

प्रथम संस्करण (हिन्दी) १९४८

प्रकाशक—किताब महल, ५६ ए, जीरो रोड, इलाहाबाद

मुद्रक—इलाहाबाद प्रेस, इलाहाबाद

दो शब्द

यह पुस्तक मेरी Banking Principles : In India नाम की पुस्तक का स्वतन्त्र अनुवाद है। कथित पुस्तक की लोक-प्रियता इसी से सिद्ध होती है कि उसके इस थोड़े से समय के अन्दर ही चार संस्करण हो चुके हैं।

बैंकिंग का विषय उन विषयों में से है जिनके ज्ञान की आवश्यकता आजकल प्रत्येक व्यक्ति को है। अतः, इस पुस्तक की बहुत आवश्यकता थी। मैंने इसमें भारतीय बैंकिंग की मुख्यमुख्य समस्याओं पर यथेष्ट प्रकाश डालने का प्रयत्न किया है और मैं यह आशा करता हूँ कि इसके पढ़ने से जनता के हृदय में इनके प्रति दिलचस्पी बढ़ेगी। इधर शिक्षा का माध्यम भी हिन्दी हो गया है। अतः, इससे अध्यापक और विद्यार्थी भी पूर्ण लाभ उठा सकेंगे।

लेखक

विषय-सूची

अध्याय	विषय	पृष्ठ
१—	विषय-प्रवेश	१
२—	अंग्रेजी बैंकिंग का इतिहास और उसकी उन्नति	१०
३—	बैंकों के भेद	२०
४—	व्यापारिक बैंकों के काम	३१
५—	व्यापारिक बैंकों के काम करने की प्रणाली	४४
६—	केन्द्रीय बैंकिंग (१)	६६
७—	केन्द्रीय बैंकिंग (२)	८९
८—	साख और साख-पत्र	१०६
९—	बैंकर का ग्राहक से संबंध	१३८
१०—	ऋण के लिए बैंकों की उपयुक्त जमानतें	१७१
११—	बैंकों का निकासगृह	१८७
१२—	भारतीय बैंकिंग	१९३
१३—	बैंकिंग की देशी प्रणाली	२११
१४—	कृषि सम्बन्धी आर्थिक व्यवस्था	२४१
१५—	उद्योग संबंधी आर्थिक व्यवस्था	२६७
१६—	व्यापारिक बैंक	२९२
१७—	इम्पीरियल बैंक आफ इण्डिया	३३२
१८—	विनिमय के बैंक	३५५
१९—	रिजर्व बैंक आफ इण्डिया	३६७
२०—	दोष और उन्हें दूर करने का उपाय	३९३
	परिशिष्ट 'अ'	४०७
	परिशिष्ट 'ब'	४०९

अध्याय १

विषय प्रवेश

बैंकिंग का विषय वास्तव में अर्थ शास्त्र के विषय का ही एक अङ्ग है। किन्तु आज-कल के आर्थिक संगठन में इसका महत्त्व इतना बढ़ गया है कि हम लोगों के लिये इस पर विशेष ध्यान देना आवश्यक हो गया है। सच बात तो यह है कि किसी देश की औद्योगिक तथा व्यापारिक उन्नति इस समय अधिकांश में उसके बैंकिङ्ग के संगठन की कुशलता पर ही निर्भर है। अतः, हम लोग यहाँ पर इसका अध्ययन पृथक् रूप से ही करेंगे।

बैंकिंग का अर्थ

‘बैंकिंग’ शब्द एक प्रकार से द्रव्य (Money) के व्यवसाय के लिये प्रयोग में आता है। अब, इस द्रव्य के व्यवसाय में विशेषतया निम्नांकित बातें सम्मिलित हैं :—(१) द्रव्य का पारस्परिक विनिमय (Exchanging of Money), (२) द्रव्य उधार देना (Lending of Money), (३) द्रव्य जमा के रूप में लेना (Depositing of Money) और (४) द्रव्य को एक स्थान से दूसरे स्थानों को भेजना (Remitting of Money)।

अधिकांश देशों में उपर्युक्त कार्य उपर्युक्त क्रम से ही आरम्भ हुये हैं। हमारे ही देश में वैदिक काल में, महाजन लोग भिन्न-भिन्न मुद्राओं (coins) को बदलने का काम किया करते थे। इसमें एक राज्य की मुद्राओं को दूसरे राज्य की मुद्राओं में बदलना और एक प्रकार की मुद्राओं को दूसरे प्रकार की मुद्राओं में बदलना दोनों ही सम्मिलित थे। साथ ही वे अपेक्षित (needy) लोगों को व्याज पर अथवा बिना व्याज के ही ऋण भी दिया करते थे। बाद में, शायद मनु के बहुत पहिले वे लोग अपने यहाँ द्रव्य को जमा के रूप में भी लेने लग गये थे और अन्त में उसको एक स्थान से दूसरे स्थानों को भेजने का काम भी करने लगे थे। इङ्गलिस्तान में भी सन् १३४४ में तृतीय एडवर्ड ने अपने यहाँ सोने और चाँदी की मुद्राओं को बदलने के लिये कुछ राजकीय महाजनों की नियुक्ति की थी। ये लोग प्रत्येक सौदे में १½ प्रति-

शत का लाभ लेते थे। साथ ही ये लोग वहाँ की मुद्राओं का अन्य देशों की मुद्राओं के साथ भी विनिमय करते थे। इसके लिये उनके यहाँ विनिमय की दूरों की एक तालिका लटकी रहती थी जिसके अनुसार ही उनको विनिमय करना पड़ता था। उनके विनिमय के लाभ में राजा का भी एक भाग रहता था। वहाँ पर साधु एडवर्ड के समय में उधार देने की भी पद्धति चालू हो चुकी थी। यहाँ तक कि धीरे-धीरे यहूदी और रूसी लोग वहाँ के मुख्य ऋणदाता (Money-lenders) बन गये थे और जब इन लोगों को देश के बाहर निकाल दिया गया तब इनका स्थान वहाँ के सर्राफों (Goldsmiths) ने ले लिया। जमा लेने का काम अवश्य ही वहाँ पर सन् १६४० के बाद ही बढ़ा। उस समय तक जनता अपना द्रव्य राजकोष में ही जमा करती थी, किन्तु इस वर्ष प्रथम चार्ल्स ने उनके अपहरण की आज्ञा निकाल दी। इसमें सन्देह नहीं कि यह आज्ञा बाद में वापस ले ली गई थी, किन्तु इससे राजकीय मर्यादा भङ्ग हो गई और लोग अपना द्रव्य राजकोष में जमा करने की अपेक्षा सर्राफों के यहाँ जमा करना अधिक पसन्द करने लगे। द्रव्य को एक स्थान से दूसरे स्थानों में भेजने के लिये पहिले तो मनुष्य काम में लाये जाते थे, किन्तु बाद में यह काम विनिमय के बिलों के द्वारा होने लगा, जिनको पहिले तो केवल व्यापारी वर्ग ही खरीदा और बेचा करते थे, किन्तु बाद में महाजन वर्ग (Bankers) भी खरीदने और बेचने लगे। आधुनिक काल में बैंकिंग के अन्दर यह सभी काम सम्मिलित हैं और कुछ और भी जिनका अध्ययन हम उचित स्थान पर करेंगे।

बैंकिंग की उत्पत्ति

उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि बैंकिंग का काम किसी न किसी रूप में भारतवर्ष में ही बहुत ही प्राचीन काल से होता आ रहा है। फ्रान्सीसी लेखक रेवलपुट का कहना है कि बैंक और बैंक नोट बेबीलोनिया में ईसा के ६०० वर्ष पूर्व भी प्रचलित थे। किन्तु बैंकिंग शब्द का पहिले-पहिल प्रयोग शायद इटली में ही मध्य काल में वेनिस के बैंक की स्थापना के साथ ही हुआ था। इस समय उस देश में बहुत से गण राज्य (city states) थे, जो आपस में लड़ा करते थे। सन् ११७१ में ऐसा हुआ कि वेनिस का राज्य अपने पड़ोसी राज्यों के साथ युद्ध

में फँसे रहने के कारण एक बड़े आर्थिक संकट में पड़ गया। जब परिषद् (Grand Council) के सामने और कोई चारा न रहा तब उसने प्रत्येक नागरिक से उसकी सम्पत्ति के एक प्रतिशत का अनिवार्य ऋण माँगा। इस पर पोंच प्रतिशत का वार्षिक व्याज भी रखा गया। ऋण दाताओं को व्याज देने का और ऋण पत्रों की लेवा-बेची का प्रबन्ध करने के लिये कमिश्नरों की भी नियुक्ति की गई। इटालियन भाषा में ऐसे ऋण के लिये 'मौन्टे' (Monte) नामक एक शब्द है। 'मौन्टे' के हिन्दी अर्थ पहाड़ है। वास्तव में इस ऋण से जो द्रव्य एकत्रित हो गया था वह पहाड़ की ही तरह दिखाई पड़ता था। 'मौन्टे' के लिये ज्वाइन्ट स्टॉक फण्ड (Joint Stock Fund) भी प्रयोग में आता था। ज्वाइन्ट स्टॉक फण्ड के हिन्दी अर्थ है सम्मिलित पूँजी कोष। वास्तव में ऋण की रकम सम्मिलित पूँजी तो थी ही। इस समय में इटली के एक बहुत बड़े भाग पर जर्मनी का अधिकार था। अतः, वहाँ पर 'मौन्टे' का जर्मन पर्यायवाची शब्द बैंक (Banck) भी प्रयोग में आने लगा। धीरे-धीरे इटली वाले इसको बैंको (Banco), फ्रान्स वाले बैंके (Banke) और अन्त में अंग्रेज इसको बैंक (Bank) कहने लगे। वेनिस के लेखों से, जिनमें उसने वेनिस के सरकारी ऋणों का वेनिस के तीन बैंकों (Bankes) से संकत किया है, यह पता लगता है कि अंग्रेज लेखक सत्रहवीं शताब्दी में भी बैंके (Banke) शब्द का ही प्रयोग करते थे। ऐसे बैंक बाद में इटली के अन्य नगरों में भी स्थापित हो गये थे। इनमें मिलन का बैंक, फ्लारेन्स का बैंक और जनोआ का सेंट जार्ज बैंक, इत्यादि थे। क्रामबैल के समय में इंगलिस्तान में भी उपर्युक्त परिस्थितियों में ही एक बैंक की स्थापना करने के लिये एक प्रस्ताव किया गया था, किन्तु जैसा कि हमको अगले अध्याय के अध्ययन से पता चलेगा, यह सन् १६९४ के पहिले सफलीभूत नहीं हो सका। इस वर्ष ऐसी ही परिस्थितियों में जिन लोगों ने वहाँ की सरकार को ऋण दिया था उन सबों का एक बैंक 'बैंक आफ इंगलैंड' के नाम से बना और उसको सरकार से एक वार्षिक आय दी जाने लगी।

इस शब्द की उत्पत्ति एक अन्य तरह से भी अनुमानित की जाती है। इसके अनुसार ऐसा कहा जाता है कि इस शब्द की उत्पत्ति 'बैंक' शब्द से है जिसका अर्थ एक ऐसी धैज है जिस पर इटली के

महाजन अपने सामने भिन्न-भिन्न प्रकार के सिकों को इस बात को दिखलाने के लिये रखते थे कि वे उनका व्यवसाय करते हैं। किन्तु मैकलित्रड अपनी पुस्तक 'बैंकिंग के सिद्धान्त और उनके प्रयोग' (Banking Theory and Practice) में इस विचार का बुरी तरह से खण्डन करता है। उसका कहना है कि यह उत्पत्ति बिल्कुल भ्रमोत्पादक है। यदि ऐसा था तो इन महाजनों को मध्यकाल में बैन्चियरी (Benchieri) क्यों नहीं कहा गया? उसने अपने कथन की सत्यता को प्रमाणित करने के लिये अन्य कई लेखकों द्वारा दिये गये प्रमाणों को भी दिया है। अन्त में वह कहता है कि यह विद्वान लेखक बहुत ही ठीक कहते हैं। बैंकों का वास्तविक अर्थ एक ढेर अथवा पहाड़ है और यह शब्द बहुत से लोगों के द्वारा एकत्रित किये गये एक सम्मिलित कोष का द्योतक है।

बैंकिंग की परिभाषा

बैंक अथवा बैंकर शब्द की अनेकों परिभाषाओं* के होते हुये भी विचित्रता तो इस बात की है कि आज तक इसकी कोई ऐसी सन्तोषजनक परिभाषा नहीं बनी है जो सर्वमान्य हो। इसका एक

* Definitions by eminent authorities on the subject:—

(1) The word bank expresses the business which consists in effecting on account of others receipts and payments, buying and selling either money of gold and silver or letters of exchange and drafts, public securities and shares in industrial enterprises—in a word—all the obligations whose creation has resulted from the use of credit on the part of states and societies and individuals—*Gautier*.

(2) No one and nobody corporate and otherwise can be a banker who does not (i) take deposit accounts, (ii) take current accounts, (iii) issue and pay cheques drawn upon himself, (iv) collect cheques crossed and uncrossed for his customers—and it might be said that even if all the above functions are performed by a person or body corporate, he or it may not be a banker or bank unless he fulfils the following conditions: (i) banking is his or its known occupation, (ii) he or it must profess to be a banker or bank and the public take him or it as such, (iii) has an intention of earning by so doing, (iv) this business is not subsidiary—*John Paget*.

मात्र कारण यही है कि बैंकिंग में अनेकों प्रकार के कार्य सम्मिलित हैं, जिससे कि उन सब का एक परिभाषा के अन्तर्गत लाना असम्भव सा है। अधिकांश देशों में तो यह विधानतः निर्धारित ढङ्ग से ही किया जाता है जिससे कि इसके वैधानिक अर्थ में लेश मात्र भी सन्देह नहीं रह जाता है। किन्तु जितने लोग अथवा जितनी संस्थायें इस काम को करती हैं वे सब विधान की पकड़ में नहीं आती। हमारे ही देश में बैंकिंग कम्पनी की एक परिभाषा सन् १९३६ के कम्पनी विधान की २७७वीं धारा में दी हुई है, किन्तु रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने इस बात की अनेकों शिकायतों की थीं कि बहुत से बैंक उस धारा के अन्तर्गत दिये हुये कामों के न करने के कारण उनको अपने सम्बन्ध में, जो सूचनाये उसको देनी चाहिये, नहीं देते थे। यही कारण था कि सन् १९४२ में उक्त धारा में निम्न आशय का एक संशोधन जोड़ा गया था— 'यदि कोई कम्पनी अपने नाम के साथ बैंक अथवा बैंकिंग शब्द का प्रयोग करती है तो चाहे उसके यहाँ चालू खातों में द्रव्य जमा किया जाता हो अथवा नहीं वह बैंकिंग कम्पनी समझी जायगी।' संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में बैंकों को संघ सरकार से अथवा किसी स्टेट सरकार से एक अधिकार पत्र प्राप्त करना पड़ता है। साथ ही उनके कार्यों को भली भाँति बता दिया गया है और उनको उन्हे विधानतः निर्धारित ढङ्ग पर करने के लिये बाध्य किया जाता है। स्थान-स्थान पर ऐसे निरीक्षक नियुक्त हैं जो उनकी

(3) A banker or bank is a person, firm or company, having a place of business where credits are opened by the deposit or collection of money or currency subject to be paid or remitted upon draft, cheque or order or where money is advanced or loaned on stocks, bonds, bullion and bills of exchange, and promissory notes are received for discount and sale—*Findlay Shirras*.

(4) Bank is an establishment which makes to individuals such advances of money or other means of payment as may be required and safely made and to which individuals entrust money or means of payment when not required by them for use—*Kinley*.

(5) A banker is one who, in the ordinary course of his business, honours cheques drawn upon him by persons from and for whom he receives money on current account—*Dr H. L. Hart*.

¶ परिशिष्ट 'अ' देखिये

देख-रेख करते हैं। किन्तु इतने पर भी अनेकों संस्थायें ऐसी बच जाती हैं जो किसी न किसी प्रकार का बैंकिंग का कार्य करती हैं और फिर भी विधान के अन्तर्गत नहीं आती हैं। इसके विपरीत इंगलिस्तान में कोई भी ऐसी वैधानिक परिभाषा नहीं बनी है। सन् १७४५ में महासभा (House of Commons) में दी गई एक वक्तृता के निम्न आशय के अंश को गिल्बर्ट ने अपनी एक पुस्तक में उद्धृत किया है—

“हम बैंकर किसको कहते हैं? इस नगर में सर्राफों का एक गुट्ट है और अधिकांश में जो बैंकर्स कहलाते हैं, इसी गुट्ट के अंतर्गत आते हैं, किंतु जहाँ तक मुझे ज्ञात है इनमें से कोई भी अपने को बैंकर नहीं कहता और न इस व्यवसाय का विधानतः कहीं वर्णन ही किया गया है। प्रचलित प्रथा के अनुसार हम ऐसे लोगों को बैंकर्स कहते हैं जिनकी दूकानें हैं, उनमें कटघरे हैं, काम करने वाले हैं, दूसरों का द्रव्य जमा करने के लिये और माँगने पर उनके वापस करने के लिए रजिस्टर हैं। जब कोई व्यक्ति ऐसी दूकान खोल लेता है तब चाहे उसके यहाँ रकम जमा होती हो अथवा नहीं, इस बात की पूछ-ताछ किये बिना ही हम उसे बैंकर कहते हैं।” तब से अब तक स्थिति बहुत ही बदल गई है। सर्राफ महाजन (Goldsmith Bankers) समाप्त हो चुके हैं। अपने को बैंक कहने वाली कम्पनियाँ स्थापित हो चुकी हैं। किन्तु यह तो अब भी सत्य है कि वहाँ पर विधानतः बैंकिंग की आज भी कोई परिभाषा नहीं है। वाल्टर लीफ कहता है “तथापि कम से कम आज तो इंगलैण्ड में सर्वसाधारण को बैंकिंग शब्द का एक बहुत ही स्पष्ट ज्ञान है। किन्तु यदि इसकी कोई परिभाषा बनाई जाय तो वह अवश्य ही उस परिभाषा से भिन्न होगी, जो अन्य किसी देश में है अथवा इसी देश में एक सौ वर्ष पहिले होती। उसने जो परिभाषा दी है वह इस आशय की है ‘बैंक वह व्यक्ति अथवा संस्था है जो सर्व-साधारण का द्रव्य चेक से माँगने पर तुरन्त ही वापस करने की शर्त पर जमा करने के लिये तय्यार रहता है अथवा रहती है।’ इस परिभाषा में जैसा कि उसने स्वयम् कहा है बैंकिंग के व्यवसाय के केवल एक ही अङ्ग का उल्लेख है। किन्तु इंगलैण्ड में तथा उन सभी देशों में जिनमें इंगलैण्ड की ही बैंकिंग के अनुरूप बैंकिंग की उन्नति हुई है और उनमें हमारा भारतवर्ष भी सम्मिलित है इसी एक काम के बहुत महत्त्वपूर्ण होने के कारण उक्त परिभाषा कम से कम आधुनिक काल में

तो अवश्य ही ठीक मानी जा सकती है। किन्तु अन्य देशों में विशेषतया यूरोपीय देशों में, जहाँ चेकों का इतना चलन नहीं है, किसी अन्य काम को लेकर इस परिभाषा को बनाना पड़ेगा। फ्रांसीसी लेखक बैंक शब्द की अपनी परिभाषाओं में विलों पर, अथवा अन्य प्रकार से ऋण देने पर अधिक महत्त्व देते हैं।

एक अन्य बात भी है जिसको कभी भी नहीं भूलना चाहिये और वह यह है कि बैंक विलों पर अथवा अन्य प्रकार से केवल उतना ही ऋण देने की क्षमता नहीं रखते जितना उनके यहाँ जमा होता है। सत्य तो यह है कि वह ऋणदाताओं और ऋण लेने वालों के बीच में केवल मध्यस्थ ही नहीं है और यदि कोई परिभाषा ऐसा बताती है तो वह सन्तोषजनक नहीं ठहर सकती है। लन्दन के सर्गफों ने जो कि इंगलैंड के सर्वप्रथम महाजन (Bankers) थे अपनी उन्नति के प्रारम्भ ही में इस बात को समझ लिया था कि उनके यहाँ जितना द्रव्य जमा किया जाता है उससे कई गुना अधिक वह ऋण दे सकते हैं। वास्तव में यही बैंकिंग के व्यवसाय की विशेषता है; यद्यपि बहुत बड़े-बड़े लेखक भी कभी-कभी इस बात को भूल जाते हैं। वे लोग जितना द्रव्य जमा हो उससे अधिक ऋण देने के सर्वथा विरुद्ध रहे हैं। वेनिस, एम्सटर्डम और हैम्बर्ग के बैंक उनमें जमा किये गये द्रव्य की सीमा के अन्दर ही अपने नोट निकालते थे। मिल ने लिखा है कि नोटों का चलन राष्ट्र के लिये हितकर है, किन्तु उनको जमा की हुई रकम से अधिक रकम में निकालना एक प्रकार की ठगी है। वास्तव में यदि आज-कल की बैंकिंग के सिद्धान्त को देखा जाय तो वह यही है और यदि मिल की बात मानी जाय तो ठग और ठगी सभी जगह प्रचलित हैं। बैंकिंग की सफलता तो उपलब्ध साधनों को कई गुना बढ़ा देने पर ही निर्भर है। इस सम्बन्ध की सारी स्थिति केवल इसी वाक्य से स्पष्ट हो जाती है कि दूसरों का द्रव्य और महाजनों की बुद्धि (The Bankers' brain and others' money) यही बैंकिंग का व्यवसाय है।

अभी यहाँ पर कुछ अन्य भ्रमोत्पादक विचारों का स्पष्टीकरण करना भी आवश्यक है। प्रथम तो यह कि ऋण देने के काम के बैंकिंग के मुख्य काम होने के साथ ही केवल यही उसके लिये यथेष्ट नहीं है। अतः, हम यह कह सकते हैं कि ऋणदाता केवल ऋणदाता होने

पर ही बैकर नहीं कहे जा सकते हैं। बैकर कहे जाने के लिये यह आवश्यक है कि वे द्रव्य को जमा के रूप में भी ले क्योंकि बैंकिंग के व्यवसाय में द्रव्य का जमा के रूप में लेना और ऋण देना दोनों सम्मिलित हैं। अकेले एक से बैंकिंग का व्यवसाय पूरा नहीं हो सकता है। दूसरी बात यह है कि साख (Credit) के उत्पादन का, जो बैंकिंग के कार्य का एक मुख्य अंग है, यह अर्थ नहीं है कि उसके लिये नोटों को चलाने के अधिकार का होना आवश्यक है। वास्तव में इसी भ्रमपूर्ण विचार के कारण इंग्लैण्ड में सम्मिलित पूँजी की बैंकिंग की बहुत दिनों तक उन्नति नहीं हो सकी। बैंक आफ् इंग्लैण्ड के अधिकार-पत्र के परिवर्तन के सम्बन्ध में सन् १७०८ में जो विधान बना था उसने उक्त बैंक को छोड़कर अन्य किसी ऐसे बैंक को, जो छः व्यक्तियों से अधिक को मिलाकर बना हो, नोटों को चलाने के काम के करने को मना कर दिया था। किन्तु उस समय के लोगों का यह विश्वास था कि नोटों को चलाने के काम को छोड़कर कोई बैंक बैंकिंग का काम कर ही नहीं सकता है। अतः, उपयुक्त मनाही के कारण उस देश में बहुत दिनों तक सम्मिलित पूँजी के किसी अन्य बैंक की स्थापना हो ही नहीं सकी। हाँ, सन् १८३३ के उस विधान में जो बैंक आफ् इंग्लैण्ड के उस वर्ष के अधिकार-पत्र के परिवर्तन के सम्बन्ध में बना था, इस बात के स्पष्टीकरण के बाद कि नोटों को चलाने के काम को छोड़कर भी बैंकिंग का व्यवसाय किया जा सकता है, लन्दन में सम्मिलित पूँजी के बैंक स्थापित किये गये। तब इन्होंने जमा लेने के और चेकों पर भुगतान देने के उस काम की उन्नति की जिसकी उन्नति स्वयं का काम करने वाले सर्राफ़ महाजन बहुत दिनों से करते आ रहे थे। कहना न होगा कि वहाँ पर च्चेकों का चलन आज-कल नोटों के चलन से भी कहीं अधिक है। लन्दन के बाहर सम्मिलित पूँजी के बैंकों की स्थापना सन् १८२६ ही से आरम्भ हो चुकी थी। उस वर्ष इस बात की घोषणा की जा चुकी थी कि वे लन्दन से ६५ मील के व्यास के क्षेत्र को छोड़कर अन्य किसी भी क्षेत्र में अपने नोट चला सकते हैं।

उपसंहार

उपसंहार में हम यह कह सकते हैं कि बैंकिंग शब्द पहिले-पहिले बारहवीं शताब्दी में ही प्रयोग में आया। हाँ, बैंकिंग का व्यवसाय किसी न किसी रूप में अवश्य ही बहुत ही प्राचीन काल से होता

आ रहा था। पहिले-पहिल यह शब्द सम्मिलित कोष के आशय को व्यक्त करने के लिये ही प्रयोग में लाया गया था। बाद में द्रव्य को जमा करने और ऋण देने के काम को, जो आधुनिक बैंकिंग के व्यवसाय के मुख्य अङ्ग माने जाते हैं, लन्दन के सराफ महाजनों ने प्रोत्साहित किया। किंतु वे द्रव्य जमा करने वालों और ऋण लेने वालों के बीच के केवल मध्यस्थ ही नहीं थे, वरन् जितना द्रव्य जमा के रूप में पाते थे उतने से कहीं अधिक द्रव्य ऋण के रूप में देते थे। चेकों के प्रयोग को भी अवश्य ही उन्होंने प्रारम्भ किया था किंतु इसकी उन्नति बाद में लन्दन के सम्मिलित पूँजी वाले बैंकों के द्वारा ही हुई। बात यह थी कि वे अपने नोट तो चला ही नहीं सकते थे, अतः, उन्होंने अपनी चेकों को चलाने के लिये उत्तरोत्तर प्रयत्न किये और वे इसमें सफल भी हो सके। उस समय से इसने इतना महत्व पा लिया है कि जब तक बैंक शब्द की परिभाषा में इसके ऊपर जोर नहीं डाला जाता, वह परिभाषा सन्तोषजनक नहीं मानी जाती। किन्तु यह उसकी परिभाषा के लिये सब जगह आवश्यक नहीं है। यह केवल इंग्लैण्ड और उन सभी देशों में बनी हुई परिभाषाओं के लिये आवश्यक है जिनके यहाँ बैंकिंग की उन्नति इंग्लैण्ड की बैंकिंग की उन्नति के सदृश्य ही हुई है। इससे यह स्पष्ट है कि बैंक शब्द की कोई भी परिभाषा सब देशों के लिये और सब समय के लिये उपयुक्त नहीं हो सकती।

प्रश्न

१. 'बैंक' शब्द के क्या अर्थ हैं ? क्या इससे केवल बैंकों के जमा, प्राप्त करने और ऋण देने के कार्यों का ही बोध होता है ?

२. आपके विचार से 'क' शब्द की क्या उत्पत्ति है ? क्या इसकी उत्पत्ति और इसका व्यवसाय दोनों समकालीन हैं ?

३. 'बैंक' शब्द की परिभाषा बताइये। आपकी परिभाषा बनाने के सम्बन्ध की कौन-कौन सी कठिनाइयाँ हैं ?

४. निम्नाङ्कित की आलोचना कीजिये:—

(अ) 'ऋणदाता बैंकर नहीं है'। (ब) 'बैंकर ऋणी और ऋणदाता के बीच का मध्यस्थ है'। (स) 'बैंकिंग का व्यवसाय नोट चलाने के अधिकार को पाये बिना नहीं किया जा सकता'। (द) 'बैंक का व्यवसाय केवल धन को साख पत्रों में और साख पत्रों को धन में परिवर्तित करने का ही है'।

अध्याय २

अंग्रेजी बैंकिंग का इतिहास और उसकी उन्नति

अधिकांश देशों की और विशेषकर भारतवर्ष की बैंकिंग के अंग्रेजी बैंकिंग पर निर्भर होने के कारण यह अत्यावश्यक हो गया है कि हम अंग्रेजी बैंकिंग के इतिहास और उसकी उन्नति का अध्ययन तो पहले ही विशेष रूप से कर लें। अतः, इस अध्याय में हम इसी पर ध्यान देंगे।

प्रारम्भ

इंग्लैण्ड में आधुनिक बैंकिंग के बीज तो लौम्बर्डों के प्रसिद्ध बैंकरो ने ही सर्वप्रथम उस समय बो दिये थे, जिस समय उन्होंने लन्दन के उस स्थान पर बसेरा डाला था जिसको आज भी हम लौम्बर्डों स्ट्रीट के नाम से पुकारते हैं। हाँ, एक के बाद दूसरे आने वाले राजाओं ने दिन-प्रति-दिन उनके कार्यों पर जो बंधन लगाये थे उनके कारण वे वहाँ पर अधिक दिनों तक नहीं ठहर सके। किन्तु जैसा डावर ने कहा है लौम्बर्डों ने यद्यपि इंगलिस्तान को छोड़ दिया, किन्तु उस व्यापार का और बैंकिंग का उत्तराधिकार, जो उन्होंने वहाँ चालू किया था उस देश को सदा के लिये धनी बनाता रहा। जो हो, आधुनिक बैंकिंग तो इंग्लैण्ड में केवल सन् १६४० के बाद ही उस समय प्रारम्भ हुई जब वहाँ के सर्राफ महाजनों ने पिछले अध्याय में दी हुई परिस्थितियों के कारण जनता के द्रव्य को जमा के रूप में लेना प्रारम्भ कर दिया। उसके स्थान में पहिले तो वे ऐसी रसीदे देते थे जिनमें उनको मांगने पर वापिस देने का वचन दिया रहता था। कहना न होगा कि इस जमा में पाये हुये द्रव्य से वे अनेकों प्रकार के लाभ कमाते थे। उस समय की मुद्राओं में उनके हाथ से ढाले जाने के कारण धातु की अवश्य ही कुछ कमी और अधिकता होती थी। नस, ये सर्राफ महाजन इसको खूब समझते थे। अतः, वे जमा में पाये हुये द्रव्य में से उन मुद्राओं को छाँटकर निर्यात (Export) करके लाभ उठा लेते थे, जिनमें अधिक धातु होती थी। इसके अतिरिक्त वे उसको ऋण में

देकर और व्यापारियों के विनिमय के बिलों को डिस्काउन्ट करके अर्थात् समय से पहिले उनका उस समय का मूल्य देकर व्याज भी कमाते थे। उनके साधनों के कारण धीरे-धीरे उनके पास बहुत से धनी ग्राहक भी आने लगे। क्रौमवेल की और अन्य राजाओं की सरकार भी उनसे ऋण लेने लगी। अतः, इस व्यवसाय के लाभदायक होने के कारण उनमें द्रव्य को जमा के रूप में लेने की प्रतियोगिता बढ़ने लगी, जिससे उन्होंने उस पर व्याज देना भी प्रारम्भ कर दिया। धीरे-धीरे उनकी रसीदें नोटों की तरह चलने लगीं और कुछ समय में ही वे सुविधाजनक रकमों में निकाली जाने लगीं। सर्राफ महाजन पास बुकों का भी प्रयोग करते थे। ये उनके लेजरों से दिन-प्रतिदिन तैयार की जाती थी। द्रव्य जमा करने वाले लोग जब चाहे तब इनको मिलान करने के लिये मंगवा लेते थे और इन्हीं के आधार पर अपने भुगतान के ड्राफ्ट (Draft) दे दिया करते थे। कुछ समय के उपरान्त ये ड्राफ्ट निर्धारित रकमों में छपने लगे और द्रव्य जमा करने वाले लोगों को उनको अपने-अपने भुगतान करने के लिये दिये जाने लगे। वे लोग इन पर हस्ताक्षर करके उन व्यक्तियों को दे देते थे जिनको उन्हें भुगतान देना होता था। इस तरह से उनको हम आज-कल की चेकों के प्रतिरूप ही कह सकते हैं। सर्राफ महाजनों के द्वारा चलाई गई इस प्रणाली को धीरे-धीरे उनके अन्य धनिक पड़ोसियों ने भी अपनाना प्रारम्भ कर दिया। अधिकांश में ये लोग शराब के अथवा कपड़े के ऐसे व्यवसायी थे, जिनका जनता में यथेष्ट मान था और जो अपनी अच्छी साख के लिये भी कुछ प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके थे। किन्तु इन्होंने चेकों के प्रयोग को अधिक बढ़ाने का प्रयत्न नहीं किया। वास्तव में बैंक आफ इंग्लैण्ड के नोट तो केवल लन्दन में ही बहुत चालू थे। उस समय उसकी शाखाएँ लन्दन के बाहर तो थीं ही नहीं, और न रेल इत्यादि साधन ही ऐसे थे कि जिनसे उनके नोट अन्य स्थानों में प्रचलित हो सकते। अतः, इन धनी व्यवसायियों के नोट उनके अपने-अपने स्थानों में चलते थे और उन्हें चेकों के प्रयोग को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं प्रतीत हुई। सत्य तो यह है कि पहिले तो लन्दन के सर्राफ महाजनों ने और फिर लन्दन के सम्मिलित पूँजी वाले बैंकों ने चेकों का प्रयोग खूब बढ़ाया।

बैंक आफ इंग्लैण्ड की संस्थापना

इस बात का संकेत तो पहिले अध्याय में ही किया जा चुका है कि यद्यपि इटली के बैंकों की तरह ही इंग्लैण्ड में भी एक बैंक की संस्थापना करने का प्रस्ताव तो क्रौमवेल के ही काल में किया जा चुका था, किन्तु उसकी संस्थापना केवल सन् १६९४ में ही हो सकी। तृतीय विलियम के सिंहासनारूढ़ होने पर महासभा (Parliament) के अधिकार बढ़ गये और उसका राष्ट्रीय आय-व्यय पर भी नियन्त्रण हो गया। इसका संचोप में यह फल हुआ कि जो राजकीय मर्यादा पहिले के राजाओं के दुर्व्यवहार के कारण भङ्ग हो गई थी वह फिर से स्थापित हो गई। सचिव मण्डल (Ministry) को द्रव्य की बहुत आवश्यकता थी और जन-सम्मति उसको पूरा करने के पक्ष में थी। इस सब का यह परिणाम हुआ कि विलियम पैटरसन की वह योजना जिससे कि वह जनता से १२ लाख पाउण्ड एकत्रित करके राज्य को देना चाहता था, सब को बहुत पसन्द आई और बैंक आफ इंग्लैण्ड की संस्थापना का बिल महासभा से पास हो कर २५ अप्रैल, सन् १६९४ को राजा द्वारा स्वीकृत भी हो गया। विज्ञापन के दस दिनों के अन्दर ही पूरा द्रव्य मिल गया और ऋण-दाताओं की बैंक आफ इंग्लैण्ड के नाम से एक संस्था बन गई। इस संस्था को उपर्युक्त ऋण पर सरकार की ओर से ८ प्रतिशत का वार्षिक व्याज और ४००० पाउण्ड प्रति वर्ष प्रबन्ध के लिये मिलने लगे। इसको १२ लाख पाउण्ड तक के नोटों को चलाने की भी आज्ञा प्रदान कर दी गई।

प्रतियोगी बैंकों पर नोट चलाने के प्रतिबन्ध

और उनका परिणाम

बैंक आफ इंग्लैण्ड की सफलता महासभा के उदार दल (Whigs) की सफलता थी। अतः, जब शक्ति अनुदार दल (Tories) के हाथ में आई तो उसने उसी प्रकार के एक भूमि बैंक (Land Bank) की संस्थापना के लिये प्रस्ताव पास कराया। किन्तु यह योजना सफल नहीं हो सकी। अस्तु, बैंक आफ इंग्लैण्ड के किसी प्रतियोगी बैंक की पुनर्स्थापना को रोकने के लिये उदार दल वालों ने पुनः शक्ति प्राप्त करने पर सन् १७०८ में उक्त बैंक के अधिकार-पत्र के

परिवर्तन के समय इस आशय का एक विधान बनाया कि जब तक उक्त बैंक आफ इंगलैण्ड काम करता रहे, इस बैंक के अतिरिक्त कोई भी ऐसा बैंक जिसमें छः से अधिक व्यक्ति सदस्य हों अपने विनिमय के बिलों और प्रण-पत्रों को इंगलैण्ड में छः महीने से पहिले माँगने पर द्रव्य देने की शर्त पर न चालू कर सके। इसका परिणाम यह हुआ कि लन्दन में और उसके समीपवर्ती स्थानों में (उस समय बैंक आफ इंगलैण्ड का आफिस केवल लन्दन में ही था) नोटों के चलाने का एक मात्र अधिकार विधानतः नहीं तो क्रियात्मक रूप से ही केवल बैंक आफ इंगलैण्ड ही के हाथ में रह गया। यह सत्य है कि छः से कम व्यक्तियों के बने हुये बैंक लन्दन में भी अपने नोट चला सकते थे। किन्तु बैंक आफ इंगलैण्ड के नोटों के राज्य द्वारा भी स्वीकृत हो जाने के कारण वे सर्राफ महाजनों के नोटों की अपेक्षा कहीं अधिक चालू थे। हाँ, लन्दन के बाहर अवश्य उनके नोट चलते थे। बैंक आफ इंगलैण्ड के नोट सन् १८३३ में विधानतः ग्राह्य (Legal Tender) भी बना दिये गये। अतः, यह स्पष्ट है कि सर्राफ महाजनों ने पहिले और अन्य सम्मिलित पूँजी वाले बैंकों ने सन् १८३३ के बाद जब वे लन्दन से ६५ मील के व्यास क्षेत्र में नोटों को न चला सकने के प्रतिबन्ध के साथ वहाँ पर स्थापित हुए, नोटों के स्थान पर चेकों का प्रयोग बढ़ाने के निरन्तर प्रयत्न किये। आवागमन के साधनों के उन्नत दशा में न होने के कारण बैंक आफ इंगलैण्ड ने अपना दफ्तर सन् १८२५ तक केवल लन्दन में ही रक्खा। अतः, तब तक उसके नोट लन्दन से बाहर इतने परिमाण में नहीं पहुँच सके कि वहाँ के महाजनों के नोट वहाँ पर न चल सकें। अतः, वहाँ के महाजनों ने वहाँ पर चेकों के प्रयोग के लिये कोई प्रयत्न नहीं किया।

प्रतिबन्ध का संशोधन

सन् १८२६ के विधान ने नोट चलाने वाले सम्मिलित पूँजी के बैंकों की संस्थापना की इस शर्त पर आज्ञा दे दी कि वे लन्दन में और वहाँ से ६५ मील के व्यास-क्षेत्र के अन्दर कहीं भी न तो अपने आफिस खोलें और न नोट चलावें। इसके फलस्वरूप देश में लन्दन के बाहर महत्वशाली बैंक खुल गये। सन् १८३३ में इन्हें लन्दन में भी इस शर्त पर अपनी शाखाएँ खोलने की आज्ञा दे दी गई कि

वे बहा पर अपने नोट न चलायें। इससे यह बैंक वहां भी खुल गये।

बैंक आफ इंग्लैंड का सन् १८४४ का विधान

अब हम बैंक आफ इंग्लैंड के सन् १८४४ के उस विधान की ओर आते हैं जिसका अंग्रेजी बैंकिंग की उन्नति में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। इस विधान के पास होने के पहिले कुछ वर्षों से इंगलिस्तान की बैंकिंग की अवस्था बहुत ही शोचनीय हो रही थी। उसमें अनेकों जोखिमों (Crises) उठानी पड़ रही थीं और एक के बाद दूसरा महाजन बराबर अपना दिवाला निकालता चला जा रहा था जिससे कि उनके नोटों को प्रयोग में लाने वाली जनता की निरन्तर हानि हो रही थी। अतः, वह उस विधान के विरुद्ध हो गई थी जिसके कारण सम्मिलित पैंजी वाले बैंकों की संस्थापना को प्रोत्साहन नहीं मिल रहा था। हम को यह तो विदित हो चुका है कि सन् १८२६ के विधान के अनुसार लन्दन के बाहर नोट चलाने वाले और सन् १८३३ के विधान के अनुसार स्वयं लन्दन में भी नोट न चला सवने वाले सम्मिलित पैंजी के बैंकों की संस्थापना की आज्ञा दी जा चुकी थी। वास्तव में यह इसी कारण वश थी। साथ ही बैंक आफ इंग्लैंड को भी इसी कारण वश बड़े-बड़े प्रान्तीय नगरों में अपनी शाखाओं के खोलने की और उनके द्वारा नोट चालू करने की मन्त्रणा मिल चुकी थी और उसने ग्लाउसेस्टर, मैनचेस्टर तथा स्वान्सी में अपनी शाखाएँ खोल भी ली थीं। इन सब बातों का एक मात्र उद्देश्य शक्तिहीन महाजनों के नोटों के चलन को कम करना था। जो हो, सन् १८४४ के विधान में इसके लिये कुछ बहुत ही स्पष्ट धारारें रख दी गईं। जहाँ तक नोटों के चलन के नियंत्रण का प्रश्न था, इस समय दो विचार-धारारें चल रही थीं, (१) करन्सी की विचार-धारा (Currency Principle) और (२) बैंकिंग की विचार-धारा (Banking Principle)। प्रथम के अनुसार केवल उतनी रकम के ही नोट चल सकते थे जितनी के मूल्य का सोना और चाँदी कोप में हो और दूसरे के अनुसार इनका परिमाण उनना हो सकता था जितने की सट्टेबाजी के लिये नहीं बरन् वास्तविक व्यापार के लिये आवश्यकता हो। बैंक आफ इंग्लैंड का सन् १८४४ का विधान प्रथम विचार-धारा के लोगों की जीत का द्योतक था। उसकी मुख्य-मुख्य धाराएँ निम्न आशय की थीं—

(१) बैंक कुल मिला कर १४० लाख पाउण्ड के नोट साख-पत्रों की जमानत पर चालू कर सकता था। कहना न होगा कि इस १४० लाख पाउण्ड की रकम में १,१०,१५,१०० पाउण्ड तो उस ऋण के ही सम्बन्ध के थे जो बैंक ने समय-समय पर^१ इंग्लैंड की सरकार को दिये थे।

(२) १४० लाख के मूल्य के उपर्युक्त नोटों के अतिरिक्त बैंक को अन्य नोटों को चालू करने का तभी अधिकार था जब उनके लिये उसके पास शत-प्रतिशत मूल्य का सोने और चाँदी^२ का सुरक्षित कोष हो। हाँ, चाँदी के कोष का मूल्य किसी समय भी सोने के कोष के मूल्य से चतुर्थांश से अधिक नहीं हो सकता था।

(३) इस विधान के पास हो जाने के बाद केवल उन्हीं लोगों का^३ नोट चलाने का अधिकार रह गया जो छः मई सन् १८४४ को नोट चला रहे थे।

(४) बैंक आफ इंग्लैंड को छोड़कर अन्य जो सहाजन अथवा बैंक नोट चलाने का अपना उपर्युक्त अधिकार रखना चाहते थे उनके लिये यह आवश्यक कर दिया गया कि वे स्टाम्प कमिश्नर के पास यह सूचित करें कि २७ अप्रैल सन् १८४४ के पहिले १२ सप्ताहों के बीच में उनके चालू नोटों के मूल्य का क्या औसत^४ था। भविष्य में उसका ४ सप्ताहों का औसत उपर्युक्त औसत से अधिक नहीं हो सकता था।

(५) यदि कोई बैंकर अपने दिवालिया हो जाने के कारण अथवा चौथी धारा को भङ्ग करने के कारण नोट चलाने के अपने अधिकार

१ बैंक सरकार को बराबर ऋण देती जाती थी। सन् १६६४ के १२ लाख पाउण्ड से बढ़कर इस समय तक यह १,१०,१५,१०० पाउण्ड हो गया था।

२ सन् १६२८ में चाँदी का सुरक्षित कोष ५५ लाख पाउण्ड का था। उस वर्ष से इसकी गणना साख-पत्रों की श्रेणी में की जाने लगी।

३ उस समय इंग्लैंड और वेल्स में इनकी संख्या २७६ थी।

४ सब का औसत मूल्य ८६,३१,६४७ पाउण्ड था।

को खो देता था तो फिर वह उसको कभी भी नहीं प्राप्त कर सकता था ।

(६) यदि कोई बैंकर नोट चलाने का पना अधिकार खो देता था तो बैंक आफ इंगलैण्ड उस खोये हुये अधिकार के दो-तिहाई मूल्य के नोटों को स्वयं अपने साख-पत्रों पर निर्धारित नोटों के परिमाण को बढ़ाकर चला^५ सकता था ।

(७) नोट चालू करने के अपने एकाधिकार के लिये और उन पर स्टाम्प लगने से मुक्त रहने के लिये बैंक को १,८०,००० पाउण्ड प्रति वर्ष सरकार को देना पड़ने लगा । १४०,००,००० पाउण्ड की रकम के अतिरिक्त अन्य नोट चलाने से बैंक को जो लाभ होता था यह सब भी उसको सरकार को देना पड़ने लगा । इसके लिये बैंक का नोट चलाने का और बैंकिंग के काम करने का ये दो भिन्न-भिन्न विभाग बनाये गये--(१) नोट चालू करने का विभाग (Issue Department) और (२) बैंकिंग विभाग (Banking Department) । इन दोनों विभागों का हिसाब-किताब भी अलग-अलग रहने लगा ।

उपर्युक्त धाराओं का एक मात्र उद्देश्य महाजनों और सम्मिलित पूँजी के बैंकों के नोट चालू करने के अधिकार को छीन लेना था । किंतु इसमें बड़ा समय लगा और अन्तिम सफलता सन् १९२१ में श्री फाक्स फाउलर कम्पनी के लायड्स बैंक से एकीकरण हो जाने पर ही मिली । हाँ, चेक करन्सी अवस्था ही इससे बड़ी उन्नत अवस्था को प्राप्त हो गई ।

सम्मिलित पूँजी के बैंकों के महाजनों का शोषण

और पारस्परिक एकीकरण

जिस समय बैंक आफ इंगलैण्ड का सन् १८४४ का विधान पास

५ इस धारा के अनुसार बैंक आफ इंगलैण्ड के साख-पत्रों पर निर्धारित नोटों का परिमाण बराबर बढ़ता गया और अन्त में सन् १९२१ में जब अन्तिम महाजन और बैंक का यह अधिकार छिन गया, यह रकम १,६७,५०,००० पाउण्ड हो गई थी ।

हुआ था उस समय इंग्लैंड में निम्न प्रकार के बैंक काम कर रहे थे :—

(१) बैंक आफ इंग्लैंड—इसका मुख्य दफ्तर लन्दन में और दूसरी शाखाएँ प्रान्तीय नगरों में थीं। इसके नोट दिन-प्रतिदिन प्रचलित हो रहे थे।

(२) लन्दन के सर्राफ महाजन—इनको नोट चालू करने का सीमित अधिकार था। किंतु ये विशेषतः चैक करेन्सी को प्रोत्साहन दे रहे थे।

(३) लन्दन के सम्मिलित पूँजी के बैंक—इनको नोट चलाने का अधिकार नहीं था। हाँ, ये भी चैक करेन्सी को प्रोत्साहन दे रहे थे।

(४) लन्दन के बाहर के महाजन—इनको नोट चलाने का सीमित अधिकार था।

(५) लन्दन के बाहर के सम्मिलित पूँजी के बैंक—इनको भी नोट चलाने का सीमित अधिकार था।

कुछ समय तक तो उपर्युक्त सभी महाजन और बैंक काम करते रहे। किन्तु बाद में उनमें एकाग्रता का भाव बढ़ा और वे शोषण (Absorption) और एकीकरण (Amalgamation) के द्वारा अपनी सख्या को तो कम करते गये लेकिन शाखाओं को फैलाते गये। इस सम्बन्ध की जेम्स डिक की तालिका, जिसको साहक्स ने भी अपनी पुस्तक में उद्धृत किया है, बड़ी ही रोचक है :

वर्ष	बैंकों की संख्या	दफ्तरों की संख्या	एक दफ्तर द्वारा सेवित व्यक्तियों की संख्या
१८८३	३१७	२,३८२	११,३१५
१८९१	२६१	३,२३१	८,९१५
१९०१	१७१	४,८७२	६,६६७
१९११	९९	६,४१३	५,६३०
१९२१	४०	८,०२२	४,७२२

यह अंक इंगलैण्ड और वेल्स के हैं और इनमें स्काच बैंक तो सम्मिलित है किन्तु अन्य विदेशी बैंकों की लन्दन स्थित शाखायें सम्मिलित नहीं हैं। वर्तमान समय में समस्त देश में एक दर्जन से अधिक बैंक नहीं हैं।

जिन कारणों से एकाग्रता का भाव बढ़ा उनका संकेत भी साइक्स ने अपनी पुस्तक में किया है। उसका कथन है कि लन्दन के सम्मिलित पूँजी के बैंकों ने लन्दन के बाहर के महाजनों का शोषण तो लन्दन के बाहर अपनी शाखाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से और सम्मिलित पूँजी के प्रान्तीय बैंकों ने लन्दन के सर्राफ महाजनों का शोषण लन्दन में अपनी शाखायें खोलने के उद्देश्य से किया। साथ ही बड़े-बड़े बैंकों का पारस्परिक एकीकरण अपने को शक्तिशाली बनाने और पारस्परिक प्रतियोगिता को दूर करने के लिये हुआ।

कहीं-कहीं ऐसी शंका की गई थी कि कहीं इस एकाग्रता का परिणाम वैकिंग के व्यवसाय में ऐसा एकाधिपत्य उत्पन्न कर देने का न हो कि वह जनता के लिये हानिकर सिद्ध हो। किन्तु ऐसा नहीं हुआ, वरन् इसके विपरीत इससे कार्य-संचालन में एकरूपता आ गई जिससे वैकिंग का व्यवसाय एक बहुत ही कुशल ढङ्ग से होने लगा और उससे सुरक्षा बढ़ गई। फिर इससे एक लाभ और हुआ और वह यह है कि इनकी बहुत कम संख्या होने के कारण जब कभी भी सारे देश में एक प्रकार की ही नीति का पालन करने की आवश्यकता पड़ी तब इन्होंने शीघ्र ही उस नीति को परस्पर तय कर लिया जिससे कि जनता बहुत से आर्थिक संकटों का बड़ी ही आसानी से सामना कर सकी।

बैंक आफ इंगलैण्ड का राष्ट्रीयकरण

आज-कल लोगों का जो सुकाव समाजवाद की तरफ हो रहा है उसके कारण मजदूर दल के इंगलिस्तान में शक्ति ग्रहण करने के समय से ही बैंक आफ इंगलैण्ड के राष्ट्रीयकरण की माँग उत्तरोत्तर बढ़ती गई। अतः, १८ फरवरी सन् १९४६ के एक विधान से इसको पूरा किया गया। उक्त विधान में मुख्यतः निम्न बातें दी हुई हैं :—

(१) बैंक के पूँजी पत्र (Capital Stocks) तत्काल ही राज-कोष के नाम हस्तान्तरित कर दिये जायें।

(२) इंग्लैण्ड का राजा बैंक के गवर्नर, डिप्टी गवर्नर और अन्य संचालकों को नियुक्त करे।

(३) राज-कोष के अधिकारी बैंक के गवर्नर के साथ मन्त्रणा करके उसका प्रबन्ध एक संचालक-मण्डल को सौंप दें।

(४) बैंक को इस बात का अधिकार है कि वह राज-कोष के अधिकारियों की इच्छा से किसी भी बैंक से कोई भी सूचना माँग ले और उसको किसी भी प्रकार की आज्ञा दे दे।

हरजाने की योजना के अनुसार बैंक के हिस्सेदारों को उनके १०० पाउण्ड के प्रत्येक हिस्सों के लिये ४०० पाउण्ड का एक प्रतिशत वार्षिक व्याज का ऐसा सरकारी साख-पत्र दिया गया जिसका भुगतान राज-कोष के अधिकारी ५ अप्रैल सन् १९६६ के बाद जब चाहें तब उसका पूरा मूल्य दे कर कर सकते हैं। हिस्सेदारों को इस प्रकार अपने हिस्सों पर वह १२ प्रतिशत व्याज मिल रहा है जो उन्हें, जिस समय बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था उसके पिछले २० वर्षों से मिल रहा था। बैंक को राज-कोष को उसके स्टाकों पर कोई लाभ नहीं वितरण करना पड़ता। हाँ, उसको उसे उतनी रकम अवश्य देनी पड़ती है जो राज-कोष उपर्युक्त सरकारी साख-पत्र पर व्याज की तौर पर देता है। हिसाब की दृष्टि से तो इस नई व्यवस्था में केवल एक बहुत ही सीधे-सादे लेखे का परिवर्तन हुआ है किन्तु वास्तव में बैंक को राज-कोष के अधिकारियों की इच्छा से अन्य बैंकों से जो किसी प्रकार की भी सूचना माँगने और उसको किसी प्रकार की भी आज्ञा देने का अधिकार मिल गया है वह सरकार के द्वारा जब भी वह चाहे तभी किसी भी राजनैतिक अथवा निर्जी कारणों से दुरुपयोग में लाया जा सकता है। इतना अवश्य है कि इस सम्बन्ध का विल जव महासभा के द्वारा पास किया जा रहा था तब उसमें सुरक्षा के आशय से कुछ संशोधन कर दिये गये थे जिनसे यह स्पष्ट हो गया है कि (अ) बैंकों से पृथक-पृथक खातों की स्थिति नहीं पूछी जा सकती, और (ब) कार्य रूप में यह अधिकार राज-कोष के अधिकारियों के कहने से नहीं, बल्कि बैंक जव उचित समझे तभी प्रयोग में लाया जा सकता है।

प्रश्न

(१) सराफ महजनों के व्यवसायिक कामों का एक संक्षिप्त विवरण

दीजिये और यह बताइये कि उन्होंने नोटों के चलन की अपेक्षा चेकों के चलन पर क्यों अधिक जोर दिया ?

(२) उस परिस्थिति का वर्णन कीजिये जिसमें बैंक आफ इंग्लैण्ड की संस्थापना हुई थी। इसको लन्दन में नोट चलाने का एकाधिकार कैसे प्राप्त हो गया ?

(३) बैंक आफ इंग्लैण्ड का सम्मिलित पूँजी की बैंकिंग का एकाधिकार कब और कैसे छिन गया ?

(४) किन परिस्थितियों में बैंक आफ इंग्लैण्ड का सन् १८४४ के विधान बना ? उसकी मुख्य-मुख्य धाराओं को बताइये और यह समझाइये कि उनका क्या प्रभाव पड़ा ?

(५) सन् १८४४ के विधान के पास होने के समय किन-किन प्रकार के बैंक इंग्लैण्ड में काम कर रहे थे ? बाद में उनका क्या हुआ ?

अध्याय ३

बैंकों के भेद

आज-कल के हमारे आर्थिक जीवन के प्रत्येक भाग में विशिष्टता (Specialisation) की जो लहर दिखाई दे रही है वह बैंकिङ्ग में भी भली-भाँति व्यक्त है। अतः, भिन्न-भिन्न आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिये भिन्न-भिन्न प्रकार के बैंक भी खुल गये हैं। किन्तु इसके यह अर्थ नहीं है कि यह विशिष्टता हर जगह पूर्ण रूप से सफल हो गई है और भिन्न-भिन्न प्रकार के बैंकों के कार्यों में पूरी-पूरी विभिन्नता है। हमको ऐसी अनेकों संस्थायें मिलेंगी जो बैंकिंग के साथ-साथ व्यापार भी करती हैं और एक प्रकार की बैंकिंग तो दूसरे प्रकार की बैंकिंग के साथ बहुत ही प्रचलित है।

व्यापारिक बैंक (Commercial Banks)

बैंकों में सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक बैंक हैं। यहाँ तक कि जब भी हम किसी विशेषण का प्रयोग किये बिना ही 'बैंक' शब्द का प्रयोग करते हैं तब वह व्यापारिक बैंक का ही द्योतक समझा जाता है। इसके अतिरिक्त हम लोग अधिकांश में व्यापारिक बैंकों के ही

संसर्ग में आते हैं। जैसा कि इसके विशेषण से विदित हो जाता है यह वैक विशेषतः व्यापारियों से ही सम्बन्ध रखता है। यह उनकी चालू पूँजी को जमा के रूप में ग्रहण करता है और उनके व्यापारिक लेन-देनों के सम्बन्ध की अस्थायी आवश्यकताओं के लिये आर्थिक सहायता प्रदान करता है। इसके यहाँ जो रकमें जमा की जाती हैं वह माँग पर देय होती हैं। अतः, यह लम्बी अवधि के लिये आर्थिक सहायता नहीं प्रदान कर सकता। इससे इस प्रकार के वैक का यह नियम रहा है कि वह लम्बी अवधि का ऋण नहीं देता और न आय पर लगाने के लिये पूँजी की ही व्यवस्था करता है। साथ ही यह व्यापार के लिये भी स्थायी तौर पर पूँजी नहीं देता बरन् व्यापार करने में जो कभी-कभी पूँजी की कमी पड़ जाती है अथवा उसमें द्रव्य लगाना पड़ता है उसकी यह व्यवस्था कर देता है। इसको व्यापार के लिये ऋण लेने वालों और सट्टे के लिये ऋण लेने वालों के बीच में भी भेद करना पड़ता है। एक व्यापारिक वैक को व्यापार के लिये ऋण लेने वालों को तो प्रोत्साहन देना पड़ता है और सट्टे के लिये ऋण लेने वालों को रोकना पड़ता है। यह किसी दशा में भी जोखिम नहीं उठा सकता और न अवसरवादी ही हो सकता है। इसके यहाँ द्रव्य जमा करने वालों का इस पर विश्वास रहता है और उस विश्वास को, इसको उनकी माँगों को पूरा करके निवाहना पड़ता है, यहाँ तक कि यदि यह उनकी एक माँग को भी नहीं पूरी कर सकता तो यह समाप्त हो जाता है। किन्तु इसके ऋण देने की क्षमता इसके यहाँ जमा किये हुये द्रव्य तक ही सीमित नहीं रहती। वैक साख (Credit) उत्पन्न करते हैं। उनके अधिकांश ऋणों का नकदी में भुगतान नहीं होता। यथा सम्भव वे उसी प्रकार से चेकों द्वारा सकारे (Honour) जाते हैं जिस प्रकार से उनके यहाँ के जमा के द्रव्य सकारे जाते हैं। इनको अनुभव से यह मालूम हो गया है कि एक तो सब लोगों की माँगें एक ही समय में नहीं आती और दूसरे जब एक तरफ इनके कोष से द्रव्य दिया जाता है तो दूसरी तरफ वह प्राप्त भी होता रहता है। इनको अपने ऊपर की सारी चेकों के लिये भी नकदी नहीं देनी पड़ती। उनमें से कुछ तो दूसरे बैंकों के द्वारा आती हैं और उन चेकों द्वारा सकार जाती हैं जो उन्हें उन्हीं बैंकों के ऊपर की अपने ग्राहकों से प्राप्त होती हैं। इससे यह स्पष्ट है कि वह उनके पास जितनी नकदी होती है उससे कहीं अधिक के मूल्य का

ऋण देने की जोखिम को ओढ़ सकते हैं। जहाँ तक यह प्रश्न है कि उनकी नकदी उनके ऋण की कितनी प्रतिशत हो, इसका उत्तर स्पष्ट शब्दों में नहीं दिया जा सकता। यह प्रत्येक बैंक के ग्राहकों की श्रेणी और उसके लागत (Investments) की श्रेणी के ऊपर निर्भर रहता है। कभी-कभी तो यह ऋतु के परिवर्तन के साथ-साथ भी परिवर्तित होता रहता है। फिर यह जनता के बैंकिङ्ग की आदत के बदलने से भी एक बहुत बड़े काल में बदल जाता है। 'तथापि बैंकों के प्रत्येक व्यवस्थापक के मस्तिष्क में उस प्रतिशत का अनुमान अवश्य रहता है जिसे उसको रखना चाहिये और जिसके कम कर देने से उसको जोखिम उठानी पड़ती है तथा बढ़ा देने से लाभ की क्षति होती है।' जिन कार्यों का विवरण ऊपर दिया जा चुका है उनके अतिरिक्त अन्य कार्यों को भी व्यापारिक बैंक करते हैं। इनका विस्तृत अध्ययन हम उचित स्थान में करेंगे। हाँ, इतना अवश्य है कि ये कार्य हर देश में समान नहीं हैं, कहीं कुछ हैं तो कहीं कुछ हैं। इनके काम करने के ढङ्गों के विषय में भी यही कहा जा सकता है। जब अंग्रेजी बैंक और विशेषतया लन्दन के बैंक लागत का व्यवसाय (Investment Banking) नहीं करते, जर्मन और फ्रान्सीसी बैंक ऐसा करते हैं। अंग्रेजी बैंक चेकों के प्रयोग पर भी बहुत जोर डालते हैं किन्तु जर्मन और फ्रान्सीसी बैंक ऐसा नहीं करते।

केन्द्रीय बैंक (Central Banks)

यद्यपि केन्द्रीय बैंकों के कार्यों की क्रमिक उन्नति तो बहुत दिनों से होती आ रही थी किन्तु इस शताब्दी के प्रारम्भ तक वे स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं हो पाये थे। प्रत्येक बैंक के व्यवस्थापक उस समय तक अपनी इच्छा के अनुसार ही मनमाने कार्य किया करते थे। बहुत से प्राचीन देशों में तो एक बैंक धीरे-धीरे बहुत ही महत्त्वपूर्ण होता जा रहा था और विशेषतः नोटों के चलाने का और सरकार के बैंकिंग के कामों के करने का एकाधिकार अथवा मुख्य अधिकार प्राप्त करता जा रहा था। ये बैंक प्रारम्भ में केन्द्रीय बैंक न कहे जाकर नोट चलाने वाले बैंक (Bank of issue) अथवा राष्ट्रीय बैंक (National Bank) कहे जाते थे। हाँ, धीरे-धीरे इनके काम और इनके अधिकार बढ़ते गये तथा इनके साथ 'केन्द्रीय' शब्द एक विशेष अर्थ के साथ प्रयोग में आने लगा। कहना न होगा कि बैंक आफ इंग्लैण्ड ही शायद

ऐसा बैंक था जिसने सबसे पहिले केन्द्रीय बैंकों का काम करना प्रारम्भ कर दिया था। अतः, केन्द्रीय बैंकिङ्ग के सिद्धान्तों की व्याख्या करने के लिये इसी की उन्नति का इतिहास सर्वत्र अध्ययन किया जाता है। प्रसङ्गवश यही बैंक इंग्लैण्ड का सम्मिलित पँजी का सर्वप्रथम बैंक भी था। उन्नीसवीं शताब्दी में भिन्न-भिन्न राष्ट्रों ने या तो अपने यहाँ के किसी पुरानी बैंक को ही नोट चलाने का एकाधिकार अथवा मुख्य अधिकार दे दिया था या किसी नये बैंक की संस्थापना करके उसको यह अधिकार दे दिया था। हाँ, नई दुनिया के सभी देश और पुरानी दुनिया के भारतवर्ष और चीन अवश्य ही ऐसे बचे थे कि जिनके यहाँ इस शताब्दी के प्रारम्भ तक कोई भी केन्द्रीय बैंक नहीं खुल सका था। यहाँ तक कि आधुनिक काल के सबसे महत्त्वपूर्ण देश अर्थात् सयुक्त राष्ट्र अमेरिका में भी सन् १९१४ तक कोई भी केन्द्रीय बैंक नहीं खुल पाया था। इस वर्ष वहाँ पर भिन्न-भिन्न स्थानों के लिये १२ केन्द्रीय बैंक खुले जिनको फेडरल रिजर्व बैंक्स (Federal Reserve Banks) कहते हैं। साथ ही इनके कार्यों के एकीकरण के लिये एक बोर्ड भी बनाया गया जिसको फेडरल रिजर्व बोर्ड (Federal Reserve Board) कहते हैं। केन्द्रीय बैंकों ने प्रथम महायुद्ध के समय में और उसके बाद भी अपने-अपने यहाँ के राष्ट्रों को इतना लाभ पहुँचाया और सहायता दी कि अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक अधिवेशन ने, जिसकी बैठक सन् १९२० में ब्रुसेल्स में हुई थी, सभी राष्ट्रों को अपने यहाँ इनको खोलने के लिये मन्त्रणा दी। अतः, तब से यूरोप में जो नये राष्ट्र बने उन्होंने और नई और पुरानी दुनिया के उन सभी राष्ट्रों ने, जिनके यहाँ उस समय तक केन्द्रीय बैंक नहीं थे अपने यहाँ उनको खोल लिया है। चीन का सेन्ट्रल बैंक और भारतवर्ष का रिजर्व बैंक क्रमशः सन् १९२८ में और सन् १९३५ में स्थापित किये गये थे। वास्तव में बैंकिङ्ग और वाणिज्य की आधुनिक परिस्थितियों के कारण प्रत्येक देश में चाहे उसके आर्थिक उन्नति की कैसी भी दशा क्यों न हो, इस बात की आवश्यकता उत्पन्न हो गई है कि वहाँ की नकदी का कोप केन्द्रित रहे और करन्सी और साख के नियन्त्रण पर किसी न किसी प्रकार की राष्ट्र की देख-रेख और यथासम्भव उसका हाथ रहे। केन्द्रीय बैंकों के कारण भिन्न-भिन्न देशों के बैंकों के बीच में पारस्परिक सहयोग और सम्यन्ध की मात्रा भी बढ़ गई है।

विनिमय के बैंक (Exchange Banks)

विनिमय के बैंकों का एक मात्र लक्ष्य विदेशी व्यापार को आर्थिक सहायता पहुँचाना और भिन्न-भिन्न देशों के पारस्परिक लेन-देनों का भुगतान करना ही है। उनकी शाखायें सारी दुनिया में फैली रहती हैं और विशेषतया व्यापारिक देशों में तो अवश्य ही रहती हैं। शायद यही कारण है कि उनको बहुत अधिक पूँजी की भी आवश्यकता पड़ती है। फिर विनिमय का व्यवसाय कुछ पेचीदा भी है और उसको करने के लिये अनुभव और कार्य-कुशलता की आवश्यकता पड़ती है। इसमें जोखिम भी यथेष्ट है। हाँ, यह इधर विनिमय मान (Exchange Standards) के चलन से अवश्य कुछ कम हो गई है। इसके पहिले स्वर्ण मान (Gold Standard) और रजत मान (Silver Standard) वाले देशों के बीच की विनिमय की दरों में बहुत परिवर्तन होते थे और उनके विनिमय के सम्बन्ध एक प्रकार से बहुत ही जोखिम के होते थे। इन सब कारणों से साधारण व्यापारिक बैंक इस काम को कर ही नहीं सकते थे। अतः, इसके लिये एक विशेष प्रकार के बैंकों की आवश्यकता पड़ी। ये बैंक निर्यात करने वाले व्यापारियों से उनके विनिमय के बिलों को खरीद लेते हैं और उन पर वसूल हुई रकम को आयात करने वाले व्यापारियों के हाथ बेच देते हैं। अधिकांश निर्यात के लिये निर्यात करने वाले व्यापारी (Exporters) उनका आयात करने वाले व्यापारियों (Importers) के ऊपर विनिमय के बिल कर देते हैं और फिर उनकी वसूली के लिये न रुक कर उनको विनिमय के बैंकों के हाथ/या तो बेच देते हैं या डिस्काउण्ट करा लेते हैं। अब, ये बैंक उन्हें या तो उनके भुगतान की तिथि तक अपने पास रखते हैं या उसके पहिले ही विदेशों में विशेषतः लन्दन और न्यूयार्क के बाजारों में, जहाँ सदैव ही उनकी माँग रहती है, बेच देते हैं। जिन देशों में उनकी शाखायें नहीं होतीं उनमें उनके अद्वितिये होते हैं। अतः, वहाँ पर वह उन्हीं के द्वारा काम करते हैं। वे उन पर अपने विनिमय के बिल करते हैं और जिनको बाहर भुगतान करना होता है वह इन्हें उन लोगों के पक्ष में लिखवाकर ले लेते हैं, जिन्हें उन्हें भुगतान देना होता है। ये बैंक अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान के बचे-खुचे भाग का भुगतान सोना, चाँदी और

साख-पत्र माँगाकर अथवा भेजकर करते हैं। अतः इस व्यवसाय से इन्हें इनका व्यापार करने का भी अवसर मिल जाता है। वे वायदे के विनिमय (Forward Exchange) का भी क्रय और विक्रय करते हैं जिससे भिन्न-भिन्न समय के विनिमय के भावों के बीच का अन्तर बहुत ही कम हो जाता है, और व्यापारियों की विनिमय की दरों के परिवर्तन से जो हानि होती है वह भी इनके अपने ऊपर जोखिम ओढ़ लेने के कारण बच जाती है। जहाँ तक इनकी स्वयं की जोखिम का प्रश्न है उसको भी ये लोग विरुद्ध सौदे करके अर्थात् क्रय के लिये विक्रय करके और विक्रय के लिये क्रय करके बचा लेते हैं। भारतवर्ष में तो नहीं किन्तु अन्य देशों में तो विनिमय के वैकों के अतिरिक्त व्यापारी बैंक भी यह व्यवसाय करते हैं। यहाँ पर विनिमय के विदेशी बैंक हैं जो इसको अपनाये हुये हैं।

औद्योगिक बैंक (Industrial Banks)

औद्योगिक बैंक कृषि के अतिरिक्त अन्य सभी उद्योग-धन्धों की आर्थिक सहायता करते हैं और उन्हें अन्य प्रकार से भी मदद पहुँचाते हैं। व्यापारिक बैंक अपने विशेष उत्तरदायित्व के कारण इस कार्य को नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त उनके पास उद्योग-धन्धों का अनुभव रखने वाले व्यक्ति भी नहीं होते। औद्योगिक बैंकों के पास लम्बी अवधि के लिये जमा की हुई रकमे रहती हैं और साथ ही उनके पास ऐसे अनुभवी व्यक्ति भी रहते हैं जो उद्योग-धन्धों के पेचीदा प्रश्नों को समझते हैं। वे उन औद्योगिक कम्पनियों के ऊपर जो उनसे सहायता प्राप्त करती हैं, उनके यहाँ अपने प्रतिनिधि रखकर अपना नियन्त्रण भी रखते हैं। जब कोई औद्योगिक कम्पनी किसी औद्योगिक बैंक से अपने हिस्सों और ऋण-पत्रों को जनता के सामने रखने में सहायता माँगती है तब वह बैंक जो पहिला काम करता है वह उसकी योजना को समझने का तथा उसका विश्लेषण करके उसके भविष्य पर दृष्टि डालने का है। कभी-कभी जब किसी कम्पनी के निकाले हुये सब हिस्से अथवा उनका वह न्यूनतम भाग जो उसके विवरणपत्र (Prospectus) में दिया रहता है जनता के द्वारा यथा समय नहीं ले लिया जाता तब यही बैंक उसको स्वयं ले लेते हैं। प्रायः नई कम्पनियों के हिस्सों की विक्री का ये लोग प्रारम्भ ही से एक प्रकार का

बीमा कर देते हैं। ये अपने ग्राहकों को उनकी रकम लगाने के सम्बन्ध में भी सलाह देते हैं और जहाँ तक होता है उनको अच्छे लागत के चुनाव में सहायता पहुँचाते हैं। इनसे कारबारियों का भी यह लाभ होता है कि वे हिस्से बेचने के भ्रमट से मुक्त हो जाते हैं। सत्य तो यह है कि ये इस काम में निपुण होने के कारण हिस्सों और ऋण-पत्रों के सम्बन्ध के विज्ञापन करने और उनको बेचने में कारबारियों से कहीं अधिक सफलता प्राप्त कर लेते हैं। जर्मनी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और जापान, इत्यादि देशों की औद्योगिक उन्नति इन्हीं बैंकों के कारण हो पाई है।

कृषि बैंक (Agricultural Banks)

कृषि की 'अपनी समस्याएँ' होती हैं। अतः, उसकी आर्थिक सहायता करने के लिये पृथक बैंक भी होते हैं। इनके दो भेद हैं— (१) एक तो वे जो लम्बी अवधि की आवश्यकताओं (Long-term needs) को पूरी करते हैं और (२) दूसरे वे जो थोड़ी अवधि की आवश्यकताओं (Short-term needs) को पूरी करते हैं। लम्बी अवधि के ऋण-भूमि में स्थायी सुधार करने के लिये, अधिक भूमि खरीदने के लिये और कृषि के अच्छे तरीकों और औजारों को प्रयोग में लाने के लिये लिये जाते हैं। और थोड़ी अवधि के ऋणों का उद्देश्य कृषकों की दिन-प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरी करने का है। इसमें बीज और खाद खरीदना, अपने खर्चें, मजदूरों की मजदूरी, सिंचाई तथा अन्य करों का भुगतान, इत्यादि सभी सम्मिलित हैं। कृषकों के पास जो जमानत (Security) रहती है और जिस अवधि के लिये उनको ऋण की आवश्यकता रहती है वह सब ऐसे हैं कि उनको व्यापारिक बैंक, विनिमय के बैंक तथा औद्योगिक बैंक सहायता कर ही नहीं सकते। अतः, इस काम के लिये भूमि-बन्धक बैंक (Land Mortgage Banks) और सहकारी बैंक (Co-operative Banks) हैं। भूमि-बन्धक बैंक तो लम्बी अवधि की और सहकारी बैंक थोड़ी अवधि की माँगों को पूरी करते हैं।

भूमि-बन्धक बैंक—ये बैंक भूमि से चालू साख-पत्र बना लेते हैं। ये शहरी और देहाती दोनों होते हैं। शहरी बैंक मकान इत्यादि बनाने में सहायता देते हैं। अतः, हम लोग यहाँ पर इनका अध्ययन

नहीं करेंगे। देहाती बैंकों की स्वयं की बहुत बड़ी पूँजी होती है। यह इनको हिस्सों अथवा ऋण-पत्रों की बिक्री से प्राप्त होती है। इनके अपनी पूँजी को रेहन पर देने के कारण उससे जो भूमि प्राप्त होती है उसकी जमानत पर यह जनता में अपने ऋण-पत्र चालू करते हैं। जब कुछ भूमि की जमानत पर चालू किये हुये ऋण-पत्रों से प्राप्त रकम अन्य भूमि के रेहन में लग जाती है तब वही अन्य भूमि फिर नये ऋण-पत्रों की जमानत के लिये काम में आ जाती है और उससे नई पूँजी प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार यह चलता रहता है। ये केवल उत्पादन के लिये ही ऋण देते हैं और जो भूमि इनके यहाँ रेहन की जाती है उसका ये बहुत होशियारी से मूल्य निर्धारित करा लेते हैं। फिर उस पर ये काफी गुंजाइश (margin) रखकर ऋण देते हैं। इनके ऋण का भुगतान वार्षिक किस्त से होता है और वह एक बहुत लम्बी अवधि में विभाजित कर दिया जाता है। उस पर उचित व्याज भी लिया जाता है। इनके द्वारा निकाले हुये ऋण-पत्रों के सुरक्षित होने के कारण वे बड़े प्रिय होते हैं और जनता में उनकी यथेष्ट माँग होती है। इनमें ट्रस्ट की और बीमे की रकमों को भी लगाने की आज्ञा दे दी गई है। भूमि और मकान, इत्यादि आसानी से नहीं बिक पाते। इसमें अनेकों वैधानिक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं। किन्तु इनसे जो चालू साख-पत्र निकाले जाते हैं वे आसानी से हस्तान्तरित किये जा सकते हैं। वे बाजारों में बिकते भी हैं। अतः, इनके कारण उपर्युक्त कठिनाई दूर हो जाती है। फ्रान्स का क्रेडिट फौन्सियर (Credit Foncier) जिसकी संस्थापना सन् १८५२ में हुई थी भूमि-बन्धक बैंकों का पिता कहा जाता है और वह जर्मनी, स्पेन, आस्ट्रिया, हंगरी और जापान के ऐसे ही बैंकों के साथ-साथ बहुत ही उन्नति कर रहा है। इंगलिस्तान का कृषिक भूमि बन्धक कारपोरेशन भी जो अब से कुछ वर्षों पहिले संस्थापित किया गया था बहुत काम कर रहा है। हमारे देश में भी ऐसे बैंकों की संख्या बढ़ती जा रही है किन्तु यह अभी तक सन्तोष-जनक नहीं है। वास्तव में इस देश के मुख्यतः कृषक देश होने के कारण और यहाँ की कृषि की अवस्था पिछड़ी होने के कारण यहाँ पर ऐसे बैंकों की बहुत आवश्यकता है।

सहकारी बैंक—ये बैंक कृषकों के स्वयम् के बैंक होते हैं। उनके दूर-दूर फैले रहने के कारण उनको थोड़े समय के लिये छोटी-छोटी

रकमों के ऋण को देना इतनी जोखिम का काम है कि उसको कोई भी आधुनिक बैंक नहीं कर सकता। इसमें सन्देह नहीं कि इसको करने के लिये महाजन हैं। वास्तव में उनका जो स्थानीय प्रभाव रहता है और वहाँ के लोगों के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध होता है उसके कारण वे लोग इसके लिये बहुत उपयुक्त हैं। किन्तु उनकी शक्ति इतनी कठिन रहती है कि वे कृषकों के मित्र नहीं बन सकते उनके लिये जोंक के समान हैं। यदि देखा जाय तो इस काम में जितनी जोखिम है उसके लिये यह उचित ही है। जहाँ तक लम्बी अवधि के ऋण का प्रश्न है उसकी जमानत के लिये तो कृषकों की भूमि है किन्तु थोड़ी अवधि के लिये तो उनके पास उनके हल, बैल तथा ओपड़ी को छोड़कर कुछ भी नहीं बचता। अतः उनको इस मामले में स्वावलम्बी होना पड़ता है और सहकारिता की शरण लेनी पड़ती है। कहना न होगा कि इसका प्रारम्भ गत शताब्दि में पहिले-पहिल जर्मनी में हुआ था। वहाँ की कृषि की दयनीय दशा का रैफेसिन के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा और उसने स्थिति को सुधारने के लिये सहकारी समितियों की संस्थापना की जो थोड़ी अवधि की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिये धन एकत्रित करने के उनके स्वयम् के संगठन हैं। अपने सम्मिलित साधनों को एकत्रित करके अपने वैयक्तिक उत्तरदायित्व के सहारे वे द्रव्य के बाजार से द्रव्य उधार लेते हैं और उसको अपने में से जिन लोगों को आवश्यकता पड़ती है उनको कम ब्याज पर देते हैं। ऋण की अदायगी प्रायः मासिक किस्तों के द्वारा होती है और वह लेने वालों के प्रण-पत्रों की जमानत पर मिलता है। फिर इन पर कुछ अन्य सहयोगी सदस्यों के हस्ताक्षर कराके इनके द्वारा बाजार से और अधिक ऋण प्राप्त कर लिया जाता है। इस प्रणाली को ईमानदारी से पूँजी बनाने की प्रणाली (Capitalisation of Honesty) कहा गया है। इसके वास्ते वैयक्तिक जमानत एक बहुत बड़ी मात्रा में बिकने योग्य जमानत में परिवर्तित हो जाती है। कृषि की थोड़े समय की आर्थिक माँग के पूरा होने के साथ-साथ इससे अन्य भी बहुत से लाभ होते हैं। इससे सदस्यों के बीच में स्वावलम्बन और मितव्ययता का भाव बढ़ता है और उनको स्वशासन की कला की शिक्षा भी प्राप्त होती है।

सेविंग्स बैंक (Savings Bank)

ये बैंक सच पूछा जाय तो बैंक नहीं हैं। वास्तव में ये साधारण

स्थिति के लोगों में मितव्ययता का प्रचार करके उनकी थोड़ी-थोड़ी बचत को एकत्रित करके सुरक्षित रखने वाले संगठन हैं। इनके ग्राहकों द्वारा जमा की हुई रकम निकाली जाने वाली रकम की अपेक्षा सम्भवतः कहीं अधिक रहती है। अतः इनको उस सबकी द्रवित दशा (liquid-state) में रखने की भी आवश्यकता नहीं रहती। इसी कारणवश इनको व्यापारिक बैंकों के समान अपनी पूँजी को केवल थोड़े समय में वापिस होने वाले ऋणों में ही लगाने की आवश्यकता नहीं रहती। किन्तु यह उतने स्वतन्त्र भी नहीं रहते। इनको विधान अपनी पूँजी को केवल कुछ सुरक्षित लागतों में ही लगाने के लिये बाध्य करता है। इनमें द्रव्य जमा करने के और उनसे निकालने के नियम भी भिन्न-भिन्न देशों में भिन्न-भिन्न हैं। प्रायः कोई भी इनके यहाँ अपना खाता खोल सकता है। प्रत्येक ग्राहक को एक पास-बुक दी जाती है जिसमें बैंक में उसका जो खाता रहता है उसकी प्रतिलिपि होती है। द्रव्य प्रायः सप्ताह में केवल एक अथवा दो बार ही निकाला जा सकता है और बड़ी-बड़ी रकमों को निकालने के लिये पहिले से कुछ समय की सूचना देनी पड़ती है। जितनी रकम इनमें जमा होती है उससे अधिक निकालने की कभी भी आज्ञा नहीं मिलती। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में अनेकों प्रकार के सेविंग्स बैंक हैं। इङ्गलिस्तान में डाकघर यह काम करते हैं और हमारे देश में भी ऐसा ही है। किन्तु यहाँ पर व्यापारिक बैंक भी अपने यहाँ ऐसे खाते रखते हैं।

निजू बैंक (Private Banks)

उपर्युक्त सभी बैंक आधुनिक काल के बैंक हैं। किन्तु इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे निजू बैंक भी हैं जो व्यापार के साथ-साथ बैंकिंग भी करते हैं। इनके काम करने के ढंग भी बहुत पुराने हैं। इङ्गलिस्तान के ऐसे सर्राफ़ महाजन तथा अन्य महाजनों के विषय में हम पहिले ही पढ़ आये हैं। हमारे देश में इनकी संख्या आज भी बहुत है। वास्तव में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ यह न पाये जाते हों। प्रायः कृषि के सारे धन्धे को और देशान्तर्गत व्यापार के एक बहुत बड़े भाग को यही आर्थिक सहायता पहुँचाते हैं। इनके सुधार की आवश्यकता तो अवश्य है किन्तु जैसा कि किसी विद्वान् ने कहा है यह हमारे आर्थिक संगठन के बहुत ही आवश्यक अङ्ग हैं और इनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता।

साथ ही इनको समाप्त कर देने से न केवल भारतवर्ष ही को वरन समस्त संसार के सभी देशों को एक बहुत बड़ी क्षति उठानी पड़ेगी। कहना न होगा कि कुछ ऐसे बैंक आज भी सभी देशों में पाये जाते हैं।

अन्य प्रकार के बैंक (Miscellaneous Banks)

लोगों की विशेष आवश्यकताओं को पूरी करने के लिये आधुनिक काल में स्थान-स्थान पर कुछ अन्य प्रकार के बैंक भी खुल गये हैं। उदाहरण के लिये इंग्लैण्ड और अमेरिका में लागत लगाने वाले बैंक (Investment Banks) हैं जिनका काम पूँजी को अनेकों प्रकार के प्रयोगों में विभाजित करना है। फिर अमेरिका में मजदूर संघों के अपने मजदूर बैंक (Labour Banks) भी हैं जिनमें उनके मजदूर अपनी बचत जमा करते हैं। हमारे ही देश में कुछ बड़े-बड़े कॉलेजों में विद्यार्थियों का द्रव्य जमा रखने के लिए विद्यार्थी बैंक (Student Banks) हैं। लन्दन के सौदागर महाजन (Merchant Bankers) और वहाँ की बिलों पर स्वीकृति देने वाली संस्थायें (Accepting Houses) एक अन्य प्रकार की ऐसी संस्थायें हैं जो एक विशेष प्रकार का काम करती हैं। आजकल व्यापार साख पर निर्भर है। किन्तु जब कोई व्यापारी विदेशों में उधार माल बेचता है तब उसको इस बात की आवश्यकता पड़ती है कि वह अपने ग्राहकों की आर्थिक स्थिति पर बराबर ध्यान रखे। अतः, यह काम उपर्युक्त सौदागर महाजनों ने अपने ऊपर ले रखा है। उनका सम्बन्ध सभी देशों से रहता है। अतः, वे भिन्न-भिन्न देशों के ऊपर किये गये विनिमय के बिलों पर भी उनकी ओर से स्वीकृति दे सकते हैं। कभी-कभी वे इसके लिये विनिमय के बैंकों की मंत्रणा भी ले लेते हैं। इनके अतिरिक्त लन्दन में कुछ डिस्काउन्टिंग संस्थायें (Discounting Houses) हैं जो सारे शहर में ऐसे विनिमय के बिलों की तलाश में रहती हैं जिनका उस समय का मूल्य वह दे देती हैं। उनके साधनों में उनकी स्वयम् की पूँजी, जनता की उन्ही शर्तों पर जमा की गई रकम जैसी अन्य बैंकों की होती है, हाँ, ऊँची दरों पर अवश्य, और कभी-कभी बैंकों से सप्ताह भर के लिये अथवा रात्रि भर के लिये (Overnight) लिये हुये ऋण सम्मिलित रहते हैं। बिलों का उस समय का मूल्य प्राप्त

करने वाले लोगों और व्यापारिक बैंकों के बीच में वे दलाली का भी काम करते हैं। ये सब थोड़े से उदाहरण हैं। संसार में सभी जगह भिन्न-भिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये अगणित प्रकार की बैंकिंग संस्थाएँ हैं।

प्रश्न

(१) 'बैंकिंग में भी विशिष्टता पाई जाती है, यद्यपि वह अभी पूरी तरह से सफलीभूत नहीं हुई है।' समझाइये।

(२) हमारे देखने में अधिकांश में किन-किन तरह के बैंक आते हैं ? उनका संक्षिप्त विवरण दीजिये।

अध्याय ४

व्यापारिक बैंकों के काम (Functions)

जैसा कि हमको ज्ञात हो चुका है व्यापारिक बैंकों का प्रारम्भ लोगों का द्रव्य जमा करने के विचार से केवल उस समय के बाद ही हुआ था जब कि लन्दन की जनता ने वहाँ के सराफ महाजनों के पास अपनी रकम जमा करना प्रारम्भ कर दिया था। उनको इस बात को समझने में भी अधिक देर नहीं लगी कि यदि वह जमा में पाये हुये द्रव्य को वापस करने के समय के पहिले प्राप्त कर सकें तो उसको उधार देकर इस व्यवसाय को बहुत ही लाभदायक बनाया जा सकता है। धीरे-धीरे उनको यह भी मालूम हो गया कि उनके प्रतिदिन के भुगतानों के लिये उन्हें प्रति दिन ही यथेष्ट रकम प्राप्त हो जाती है, अतः इस बात की आवश्यकता भी नहीं है कि उधार दी हुई रकम जमा की हुई रकम की वापसी के पहिले ही प्राप्त हो जाय। इसमें सन्देह नहीं कि उनको ऋण देने में अपनी बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता था और उचित जमानत लेनी पड़ती थी। कभी-कभी उनकी बहुत हानि भी हुई है। उदाहरण के लिये जब चार्ल्स द्वितीय ने अपने लिये हुये ऋण को लौटाने से इंकार कर दिया था। अतः, यह स्पष्ट है कि बैंकिंग के दो मुख्य काम द्रव्य उधार लेना और देना है। वस, हम यहाँ पर इन्हीं का अध्ययन करेंगे। किन्तु आज-कल के बैंक इनके

अतिरिक्त कुछ अन्य काम भी करते हैं जिससे जनता को सुविधा मिलती है।

इन तमाम कामों का हम चार शीर्षक में अध्ययन कर सकते हैं :—

- (१) जमा लेना ।
- (२) ऋण देना ।
- (३) आदृत के काम करना ।
- (४) अन्य कार्य ।

जमा लेना (Receiving Deposits)

जमा कई खातों में ली जाती है जिनमें मुख्य तो चालू खाता (Current Account) खाता है, किन्तु अन्य भी कई खाते हैं जैसे स्थायी खाता (Fixed Deposit Account), बचत का खाता (Savings Bank Account) गोलक खाता (Home Safe Account), इत्यादि। पहिले-पहिले जो जमा प्राप्त होती थी वह तो स्थायी खातों ही में होती थी। किन्तु शीघ्र ही सर्गाफ महाजनो ने यह समझ लिया कि यदि जमा में प्राप्त होने वाली रकम एक बहुत बड़ी मात्रा में है तो वह इस बात पर निर्भर रहकर कि उसमें से एक बहुत बड़ी रकम बहुत दिनों तक वापिस नहीं माँगी जायगी उस रकम को ऋण में भी दे सकते हैं। अतः उन्होंने माँग की वापिसी की शर्त पर भी जमा (Demand Deposits) प्राप्त करना प्रारम्भ कर दिया। इस तरह से चालू खातों की नींव पड़ी जिनमें से जमा करने वाले अपनी रकम को जब चाहे तब प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद चेकों का प्रादुर्भाव हुआ जिससे कि चालू खातों से रुपया निकालने में बहुत सुविधा पड़ने लगी। फिर जब चेकें अच्छा अधिकार देने वाले पुर्जों (Negotiable Instruments) की तरह जन साधारण में स्वीकृत होने लगीं और हाथों-हाथ चलने लगीं तब जमा प्राप्त करने वाली बैंकिंग की प्रणाली और भी उन्नति को प्राप्त होने लगी। यह अवश्य ही लन्दन से प्रगट हुई है। चालू खातों में साधारणतया व्याज नहीं दिया जाता, यहाँ तक कि कभी-कभी यह शर्त भी रहती है कि जमा करने वाले उसमें से न्यूनतम रकम कभी भी नहीं निकाल सकेंगे। लन्दन में तो

इन पर व्याज न देने का एक चलन ही हो गया है। बैंक इनको केवल इसीलिये रखते हैं कि उनको एक मुक्त रकम (Free Balance) मिल जाती है। यह रकम उतनी होती है कि जितने का व्याज खाता रखने के खर्च के बराबर होता है, और यह खर्च भी लेजर के पृष्ठों के चलने और चेकों के प्रयोग की संख्या पर निर्भर रहता है। यदि यह मुक्त रकम नहीं छोड़ी जाती तो फिर बैंक ग्राहकों से एक कमीशन लेता है जैसा कि हमारे देश में चलन है। यह छमाही लिया जाता है। इसको प्रासंगिक व्यय (Incidental Charges) कहते हैं। हाँ, कुछ ऐसे भी बैंक हैं जो व्याज देते हैं। इंगलिस्तान के अन्य शहरों में तो कहना ही क्या है यह लन्दन में भी है। हमारे देश में भी ऐसे अनेकों बैंक हैं।

स्थायी खातों में जो रकम जमा की जाती है वह उस अवधि के बीत जाने के पहिले नहीं निकाली जा सकती जिसके लिये वह जमा की गई थी। कभी-कभी यह पहिले से सूचना देकर भी निकाली जा सकती है। इन्हें अमेरिका में समय के लिये प्राप्त जमा (Time Deposits) भी कहते हैं। इन्हें व्याज देकर आकर्षित किया जाता है जिसकी दर जितना अधिक समय होता है उतनी ही अधिक होती है। लन्दन में यह सात दिनों की सूचना पर भी जमा किये जाते हैं, किन्तु सात दिनों की सूचना देने के पहिले इनको कम से कम एक माह तक अवश्य जमा रखना पड़ता है इनके व्याज की दर को बैंकों के जमा की दर (Bank Deposit Rate) कहते हैं। भारतवर्ष में ये तीन महीनों, छैं महीनों, नौ महीनों और एक वर्ष के लिये जमा होते हैं। कुछ बैंक एक वर्ष से ऊपर के लिये भी जमा प्राप्त करते हैं, किन्तु ऐसा बहुत कम (Time Deposits) किया जाता है।

कुछ समय के लिये जमा और मांग पर वापिस होने वाली जमा (Demand Deposits) दोनों की रकमें आपस में बदलती भी रहती हैं। जब व्यापार मन्दा हो जाता है तब चालू खातों की रकमें स्थायी खातों में चली जाती है और जब व्यापार की तेजी होती है इसका उल्टा हो जाता है। अच्छी बैंकिंग के अर्थ यह है कि जमा अधिकांश में चालू खातों में ही हो। विख्यात बैंकों ने स्थायी खातों के और व्याज देने के दोनों के विरोध में बहुत कुछ कहा है। व्यापारिक बैंक तो व्यापारियों से काम करते हैं जिनके पास स्थायी खातों में

रखने के लिये फालतू रकमें नहीं होतीं, उनको तो केवल उतनी ही पूँजी रखनी चाहिये जितनी उनके व्यापार के लिये आवश्यक है। अतः, इसको उन्हे चालू खातों में ही रखना चाहिये। निर्धारित समय के लिये जमा प्राप्त करने का काम तो लागत वाले बैंकों (Investment Bank) का है। अतः, व्यवसाय की छीना-फुपटी नहीं होनी चाहिये। किन्तु भारतवर्ष ऐसे देश में जहाँ लागत के बैंक हैं ही नहीं व्यापारिक बैंकों के इस काम को करने में कोई हानि नहीं मालूम पड़ती।

कुछ देशों में और विशेषतः भारतवर्ष में व्यापारिक बैंक बचत के खातों में भी जमा प्राप्त करते हैं। सम्पूर्ण जमा की रकम के जो अंश वर्तमान काल में इन खातों में है वह प्रथम युद्ध के पहिले के काल की अपेक्षा कहीं अधिक है। इनका एक मात्र उद्देश्य थोड़ी आय वाले लोगों में मितव्ययता का प्रचार करना है। वास्तव में यह काम भी व्यापारिक बैंकों के लिये उपयुक्त नहीं है। किन्तु वे लोग इसे बराबर करते आ रहे हैं और इसका महत्व भी इतना बढ़ गया है कि हमको अधिक नहीं तो थोड़ा सा अवश्य इसके विषय में अध्ययन कर लेना चाहिये। इन खातों की रकम एक निर्धारित सीमा के ऊपर नहीं जाने दी जाती। इनको कोई भी व्यक्ति अपने नाम में अथवा किसी अपने कमवयस्क सम्बन्धी के नाम में अथवा किसी ऐसे कमवयस्क के नाम में जिसका वह अभिभावक नियुक्त हुआ हो, खोल सकता है। इसमें जमा तो जब चाहे तब की जा सकती है किन्तु इसमें से निकाला सप्ताह में केवल एक अथवा दो बार ही जा सकता है। कुछ बैंक इसमें चेकों के प्रयोग की भी सुविधा देने लगे हैं। कहीं-कहीं इस सुविधा को प्राप्त करने के लिये एक न्यूनतम मुक्त रकम का रखना भी आवश्यक है। पांचवीं तारीख के अन्त के बीच में जिस दिन भी न्यूनतम रकम होती है उसी पर पूरे एक माह का व्याज लगाया जाता है। कहीं-कहीं, एक निर्धारित रकम से अधिक रकम निकालने के लिये कुछ दिनों की सूचना की भी आवश्यकता पड़ती है।

गोलक खाता बचत खाते ही की तरह है। इसको हमारे देश के सैन्ट्रल बैंक के अधिकारियों ने चालू किया था। इसका ध्येय बच्चों में भी मितव्ययता की आदत डालना है। जब कोई व्यक्ति यह खाता खोलता है तब उसको एक सुन्दर गोलक दे दिया जाता है जिसको वह अपने घर ले जाता है और जिसमें वह समय-समय पर अपने पैसे डालता

रहता है। जब गोलक भर जाता है तब वह उसको बैंक में वापस ले जाता है जहाँ पर उसको खोल कर उसका रुपया उसके खाते में जमा कर लिया जाता है। गोलक के स्थान पर एक सुन्दर घड़ी भी मिलती है जिसमें प्रति दिन एक आना छोड़ने से चाभी भरी जाती है। इस खाते की ही तरह व्याज लगाया जाता है।

जमा अन्य खातों में भी प्राप्त की जाती है। निजी खरचों को देने के लिये निजू खाते (Private Accounts) खोले जाते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य विशेष कामों के लिये विशेष खाते खुलते हैं। उदाहरण के लिये बच्चों के लिये बच्चों के विवाह के लिये द्रव्य एकत्रित करने के लक्ष्य से विवाह खाता (Marriage Account) खोला जाता है।

जमा के भेद (Nature of Deposits)

जमा कई प्रकार से प्राप्त होते हैं। ग्राहक नकद जमा कर सकते हैं अथवा नकदी मिलने के अपने अधिकारों को भी जमा कर सकते हैं। ये चेक, विनिमय के बिल और प्रणपत्र इत्यादि हो सकते हैं। बैंक इनका भुगतान प्राप्त करके उसको खातों में जमा कर लेता है। बैंकों के ऋण देने से अथवा विनिमय के बिलों को डिस्काउंट कर देने से भी उनको जमा प्राप्त हो जाती है। इनको सृजित जमा (Created Deposits) कहते हैं। वास्तव में आज कल सृजित जमा की रकम अन्य प्रकार से उत्पन्न हुई जमा की रकम से कहीं अधिक होती है। अतः, इस बात को सोचना कि बैंक के चिट्ठे (Balance Sheet) में जितना जमा (Deposits) दिखलाया गया है उतना उसे नकद प्राप्त हुआ है, भ्रमपूर्ण है। मैक्लिथड का कहना है कि यह रकम उस रकम की द्योतक नहीं है जो बैंक को उसका व्यवसाय चलाने के लिये प्राप्त हो चुकी है। यह तो यह बतलाती है कि बैंक ने कितना व्यवसाय किया है और उसने कितने का अपना उत्तरदायित्व (Liabilities) खड़ा कर लिया है। अतः, यह जमा की रकम जिनको बहुत से लेखक नकद प्राप्त हुई रकम समझते हैं, केवल उस साख की द्योतक हैं जो बैंकों ने उस नकद, विनिमय के बिलों और ऋण के बदले में उत्पन्न कर ली है जो उसके चिट्ठे में सम्पत्ति और पाउने (Assets) की तरफ दिखलाई गई है। जब किसी ग्राहक को थोड़े समय के लिये द्रव्य की आवश्यकता पड़ती

है तब वह बैंकर से या तो ऋण (Loan) लेने अथवा अधिक द्रव्य निकालने (Overdraft) अथवा नकद साख प्राप्त करने (Cash Credits) अथवा बिल को भुनाने (Bill Discounting) की प्रार्थना करता है। बैंकर तो यह जानता है कि द्रव्य रखने के लिये नहीं बरन् भुगतान करने के लिये मांगा जा रहा है। अतः, प्रायः वह इस शर्त पर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर लेता है कि ग्राहक सब रकम नकद न लेकर जब कभी उसको भुगतान करना होगा तब चेकें काटेगा। हम जानते हैं कि चेकों के काटने का यह अधिकार तो नकद जमा करने पर भी मिलता है, अतः, हम यह कह सकते हैं कि इसको चाहे ग्राहक स्वयम् प्राप्त कर ले अथवा बैंक उसको दे दे। जब ग्राहक नकदी जमा करता है तब वह इसे स्वयम् प्राप्त करता है और जब बैंक उसे किसी भी रूप में ऋण देता है तो बैंक उसे इसे देता है। किन्तु बैंक की इस अधिकार को देने की शक्ति उसके पास जितनी नकदी होती है उसी के अनुसार सीमित रहती है। अतः, जैसा कीन्स ने कहा है हम भी कह सकते हैं कि ऋण जमा के बच्चे हैं और जमा ऋण के बच्चे हैं १।

किन्तु बहुत से लोग उपर्युक्त बात को नहीं समझ पाते हैं और कहते हैं कि बैंक के लेखक (Clerks) जितनी चाहे उतनी साख उत्पन्न कर सकते हैं २। यदि उनमें दुर्भाव न हो तो इतनी अधिक साख उत्पन्न हो जाय कि संसार से दरिद्रता और पसीना बहाने वाली सख्त मेहनत का सदा के लिये विनाश हो जाय। वे इस बात को नहीं सोचते कि ३

1. Loans are the children of deposits and deposits are the children of loans.

2. Credit is the mere creation of the bank clerk's pen and that but for the malevolence of the wicked banker enough of it could be created to remove poverty and banish toil from the world.

3. Why the banker should be so concerned to reduce the volume of the material in which he trades and from which he earns his living if he has the power they think he has?

यदि बैंकर के पास इतनी शक्ति है तो वह उस चीज को क्यों कम करता है जिससे वह व्यापार करता है और अपनी रोटी कमाता है ।

ऋण देना (Granting Loans)

यह तो बतलाया ही जा चुका है कि बैंकर प्रायः नकद ऋण नहीं देते । अधिकांश में उनके ग्राहकों के ऋण चेक काटने के अधिकार के रूप में ही होते हैं । इनके कई रूप हैं, जैसे ऋण का रूप (Loans and Advances) जमा की गई रकम से अधिक रकम निकालने का रूप (Overdrafts) नकद साख का रूप (Cash Credits) अथवा विनिमय के बिलों के भुनाने का रूप (Bill Discounting) इत्यादि, इत्यादि । बैंकर अपनी पूंजी नहीं देते । इसके विषय में लार्ड ओवरस्टन नाम के एक प्रसिद्ध बैंकर ने कहा है “यह मेरी स्वयम् की बुद्धि है और दूसरे का द्रव्य है ।” रेकार्डो ने भी इसी आशय की बात कही थी । उसका कहना था “कोई व्यक्ति तभी बैंकर कहला सकता है जब वह दूसरों का द्रव्य उधार देता है ।” वास्तव में बैंकों के पास अपने नकद कोष को रखने और मृत स्टॉक (Dead Stock) खरीदने के बाद अपनी स्वयम् की पूंजी ऋण के रूप में देने के लिये नहीं वचती । अतः, वह इस काम के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं कर सकते कि दूसरों के द्वारा जमा किये हुये द्रव्य को इस काम में लगावे । किन्तु इन्हे उन्हें माग पर वापिस करना पड़ता है । यदि वे ऐसा नहीं कर पाते हैं तो दिवालिया घोषित कर दिये जाते हैं जिससे उनका काम ही बन्द हो जाता है । हमें यह भी ज्ञात है कि वह केवल उसी सीमा तक ऋण देते हैं । वह साख उत्पन्न करते हैं । इसमें सब में अवश्य ही बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है । बैंक व्यवस्थापक की स्थिति वास्तव में बड़ी दयनीय है । एक तरफ तो हिस्सेदार उससे अधिकाधिक लाभ कमाने की आशा रखते हैं जो जोखिम उठाये बिना हो ही नहीं सकता और दूसरी तरफ उसके व्यवसाय के ऐसा होने के कारण कि जिससे उसे रक्षा का सबसे अधिक ध्यान रखना पड़ता है वह अधिकाधिक लाभ भी नहीं उठा सकता । किन्तु यह काम बहुत कठिन नहीं है । आचार्य टाजिग (Taussig) कहते हैं “सब बातों को देखते हुये व्यापारिक बैंकों का प्रबन्ध बहुत कठिन नहीं है । उसके लिये पूर्व विचार,

साधुता, नियमपालन तथा व्यवसायियों के अच्छे ज्ञान की आवश्यकता है।”

जहाँ तक ऋण के रूपों का प्रश्न है, ऋण (Loans and Advances) तो एक तरफ ग्राहकों के नाम छोड़कर (उनके एकाउन्टों को डेबिट करके) और दूसरी ओर उनके चालू खातों में जमा करके (उनके क्रेडिट एकाउन्ट को क्रेडिट करके) दे दिया जाता है। यह व्यवसाय बहुत ही लाभप्रद है क्योंकि इसमें तो बैंकर केवल अपनी साख ही जिसे जनता केवल इसलिये मानती है कि उसका नाम बहुत प्रसिद्ध होता है ऋण के रूप में देता है। यदि वह तनिक सा भी ध्यान रखता है तो इसमें उसको लेश मात्र भी जोखिम नहीं उठानी पड़ती। बैंक हर प्रकार की जमानतों पर ऋण नहीं देते। वे केवल उन्हीं जमानतों को स्वीकार करते हैं जो आसानी से बिक सकती हैं। उनके मूल्य का भी ह्रास नहीं होना चाहिये। जार्ज रे ने कहा है कि बैंकों के लिए दोष रहित जमानतें वहीं हैं जो अन्त में भी सुरक्षित हैं, जिनका भुगतान थोड़ी अवधि के बाद ही एक निश्चित तिथि पर होने को है, जिनमें आवश्यकता पड़ने पर शीघ्र ही बिक जाने की योग्यता है और जो ह्रास की जोखिम से मुक्त है। कभी कभी ऋण लेने वालों की वैयक्तिक जमानत ही ले ली जाती है, अथवा एक संयुक्त प्रणपत्र अथवा दो नाम वाला साख पत्र ही ले लिया जाता है। इस ऋण में पूरी रकम पर व्याज लगाया जाता है।

जमा की हुई रकम से अधिक निकालने (Overdraft) का अधिकार भी केवल बैंक व्यवस्थापक से पहिले ही तै कर लेने पर प्राप्त हो सकता है। इसे प्राप्त करने के लिए ग्राहकों को उसके पास जाना पड़ता है अथवा उससे लिखा पढ़ी करनी पड़ती है। इसमें यह भी तय हो जाता है कि इस तरह से अधिक से अधिक कितनी रकम निकाली जा सकती है। फिर जितने दिनों के लिये यह सुविधा दी जाती है वह भी पहिले से ही निश्चित हो जाती है। इतना हो जाने पर बैंकर चेकों को उस निश्चित रकम तक सकारता जाता है। ऋण (Loan) और जमा की हुई रकम से अधिक प्राप्त करने (Overdraft) में एक्यह भी अन्तर है कि जब कि ऋण (Loan) में ग्राहक ऋण की पूरी रकम पर व्याज देता है जमा की हुई रकम से अधिक प्राप्त करने (Overdraft) में वह उतनी ही

रकम पर व्याज देता है जितनी दिन प्रति दिन उसके नाम पड़ी रहती है। इसके यह अर्थ हैं कि जमा की हुई रकम से अधिक प्राप्त करने (Overdraft) में ग्राहकों को ऋण (Loans) की अपेक्षा कहीं अधिक लाभ होता है। किन्तु बैंक इन पर ऊँचे दर से व्याज लगा कर ऐसा नहीं होने देते। ऋण की तरह यह भी जमानत पर अथवा विना जमानत के ही प्राप्त हो सकते हैं।

नकद साख (Cash Credit) देने की प्रणाली स्काटलैण्ड में जहाँ यह पहिले पहिल चालू हुई थी, बहुत ही प्रिय है। मैक्लिथड का कहना है कि वहाँ की उन्नति केवल इसी प्रणाली के कारण हुई है। उसका कथन है कि नाइल नदी ने जो कुछ मिश्र के लिये किया है वही नकद साख (Cash Credit) प्रणाली ने स्काटलैण्ड के लिए किया है, अर्थात् वह उत्पादन बढ़ाने वाली सिद्ध हुई है। लेवी कहता है 'स्काच बैंकों ने बहुत से दरिद्र स्काचों को केवल दो घरेलू व्यक्तियों के द्वारा लिखे हुए साख पत्रों पर ही नकद साख देकर उनको योग्यता की स्थिति में ही नहीं बरन बहुत ही महत्वपूर्ण स्थितियों में पहुँचा दिया है।' हमारे देश में भी यह प्रणाली व्यापारिक बैंकों को बहुत ही प्रिय है। किन्तु वे इसे केवल वैयक्तिक जमानतों पर ही न देकर ऐसे प्रणालियों की जमानत पर देते हैं जिनके पृष्ठ पर हिस्से अथवा अन्य साख पत्र रहते हैं अथवा रुई, पाट और चावल जैसी वस्तुये होती हैं। यदि माल बैंको के गोदामों में रख दिया जाता है तो उनके वहाँ पहुँचने पर ऋण दे दिया जाता है और उसकी जैसे जैसे वापसी होती जाती है वह छुटता जाता है। ऋण देते समय उचित छूट (Margin) रख ली जाती है। इसमें भी जमा की हुई रकम से अधिक निकालने (Overdrafts) की तरह ही जो रकम ऋणी लिये रहता है उसी पर व्याज लगता है। हाँ, दोनों में एक अन्तर यह है कि जब इसमें ऋणी के नाम का एक नया खाता जिसको उल्टा चालू खाता (Inverse Current Account) कहा जा सकता है, खोला जाता है। उसमें वही पुराना चालू खाता चलता रहता है।

विलों को भुना करके भी ऋण प्राप्त किया जा सकता है। आधुनिक व्यापार साख पर ही निर्भर है। नकद सौदे तो केवल खुदरा व्यापार में ही होते हैं। उद्योग धन्धों के सम्बन्ध के बहुत से सौदे तो साख पर होते हैं। कच्चे माल के उत्पादक उनको माल बनाने वालों

के हाथ साख पर ही बेचते हैं। ऐसे ही माल को थोक व्यापारियों के हाथ, थोक व्यापारी खुदरा व्यापारियों के हाथ साख पर ही बेचते हैं, अतः, यह आदि से अन्त तक फैला हुआ है और हम इस बात को किसी विरोध के बिना कह सकते हैं कि आज का समस्त औद्योगिक संसार साख की जंजीर से जकड़ा हुआ है। यदि यह अपने इस विस्तरण रूप में न फैला होता तो उत्पत्ति का आजकल का इतना बड़ा रूप सम्भव ही न होता। साख ने व्यापार की मशीन की चाल को बढ़ा दिया है जब कोई साख का सौदा होता है तो विक्रेता एक विनिमय का बिल तैयार करता है जिसमें वह विक्रेता से एक निश्चित अवधि के बीत जाने पर उसमें दी रकम देने की मांग करता है। भुगतान का यह तरीका बहुत ही सुविधाजनक है। प्रथम तो इसके भुगतान के बैंकों के द्वारा होने के कारण मुद्राओं और नोटों के प्रयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती। दूसरे विनिमय के बिलों से भुगतान की तारीख भी निश्चित हो जाती है और यह एक प्रकार के साक्षी का भी काम देते हैं। भुगतान के दिन यदि इसका ऊपर वाला धनी (Drawee) भुगतान नहीं करता तो वह अदालत में यह नहीं कह सकता कि उसके ऊपर ऋण नहीं चाहिये। जिस सौदे के सम्बन्ध में कोई बिल किया जाता है, उस सौदे के विषय में कोई प्रश्न उठ ही नहीं सकता। बिल स्वयं ही ऋण का द्योतक माना जाता है। तीसरे, इसका अधिकारी (Holder) इसे अपने ऋण के भुगतान में हस्तान्तरित (Transfer) कर सकता है। अन्तिम बात यह है कि आवश्यकता पड़ने पर इसके अधिकारी को इसे भुनाने से इसके भुगतान की तारीख के पहिले ही इसकी रकम मिल जाती है। वास्तव में जिन व्यापारियों के पास पूँजी तो कम है किन्तु साख पर काम करना है उनके लिए रकम पाने का यह अच्छा साधन है।

बिल भुनाने का तरीका एक ऐसा तरीका है जिसमें बैंकर किसी अन्य जमानत को लिए बिना ही ऋण दे देता है। इस स्थिति में उसके लिये केवल लिखने वाले धनी (Drawer) और ऊपर वाले धनी (Drawee) दोनों की वैयक्तिक जमानत ही रहती है। कभी-कभी इन बिलों को पहिले तो भुनाने का काम करने वाली संस्थाओं (Discounting Houses) अथवा बिलों के दलालों (Bill Brokers) से भुना लिया जाता है और फिर वे

इन्हे किसी बैंक से भुनाते हैं। ऐसी अवस्था में इन मध्यस्थों की एक और जमानत हो जाती है। भारतवर्ष में सर्राफ अथवा देशी महाजन (Indigenous Bankers) इस मध्यस्थ के काम को करते हैं। बिल पर रकम देने वाला महाजन (Banker) शेष अवधि का व्याज काटकर बिल की रकम उसके अधिकारी के खाते में जमा कर देता है और वह उसको उसमें से चेकों द्वारा धीरे-धीरे निकालता रहता है। बैंक बिलों को भुगतान की तारीख तक अपने पास रखते हैं और अन्त में ऊपर वाले धनी से उनकी रकम प्राप्त कर लेते हैं। ऊपर वाला धनी किसी बिल पर अपनी स्वीकृति देने के समय अपने बैंक को जिसका नाम वह स्वीकृति के साथ-साथ भुगतान देने के स्थान की जगह पर लिख देता है उसका भुगतान करने को सूचित कर देता है।

बिलों पर ऋण देना बैंकों के लिए बहुत ही लाभप्रद है—

(१) बिल पर मिलने वाली रकम निश्चित रहती है। वह कभी भी नहीं बदल सकती। इसके विपरीत अन्य जमानती रकमें बदलती रहती है। उनके गिर जाने से हानि भी हो सकती है।

(२) बिल की अवधि बीत जाने पर उसका भुगतान मिल जाना पूर्णतया निश्चित ही रहता है। बात यह है कि किसी बिल के खड़े रह जाने पर (Dishonour) उसके ऊपर वाले धनी की बड़ी बदनामी होती है जिसको कोई भी व्यक्ति सहन नहीं कर सकता। फिर यदि वह उसका भुगतान नहीं करता तो उस पर और जो धनी उत्तरदायी होते हैं वह उसका भुगतान कर देते हैं।

(३) किसी भी बैंक का व्यवस्थापक बिलों पर ऋण देते समय इस बात का ध्यान रख सकता है कि उनमें से कुछ बराबर भुगतान के लिये पकते रहें। इससे उसको बराबर रकम मिलती रहती है।

(४) केन्द्रीय बैंक अच्छे बिलों पर फिर से ऋण देने (Rediscounting) के लिये बराबर तैयार रहते हैं। इन पर वह अपनी बैंक-दर (Bank-rate) से व्याज लेते हैं।

(५) यदि इन्हें भुनाने की दर और व्याज की दर एक ही होती है तो भी इनके ऊपरी-मूल्य (Face-value) पर न कि जितना ऋण दिया गया है उस पर कटौती (Discount) मिलने के कारण बैंकों का लाभ ही होता है। इसके अतिरिक्त इनका यह लाभ ऋण देने

के समय ही मिल जाता है और अन्य ऋणों का व्याज कुछ समय बीतने पर मिलता है। अतः, बैंक इस रकम से भी लाभ उठा सकते हैं।

किन्तु इस व्यवसाय में भी इसे बेपरवाही से करने पर बड़ी जोखिम है। यह बात विशेषतः इसलिये है कि विनिमय के बिल कई प्रकार के होते हैं—वास्तविक (Genuine), बनावटी (Non-genuine)। इन दोनों में विभेद करना भी असम्भव सा है। वास्तविक बिल व्यापारिक सौदों के सम्बन्ध में किये जाते हैं। अतः, उनके भुगतान की तारीख तक माल के विक्रि जाने की सम्भावना होने से उनका भुगतान तो एक प्रकार से निश्चित सा ही रहता है। किन्तु बनावटी बिल तो केवल उनके धनियों की साख पर ही निर्भर रहते हैं। अतः, उनके भुगतान में सन्देह हो सकता है। कभी-कभी ये बिल केवल अपने व्यापारी मित्रों की आर्थिक सहायता करने के विचार से ही स्वीकृत कर लिये जाते हैं, और उनके भुन जाने से लिखने वाले धनी को द्रव्य तो मिल ही जाता है। लिखने वाला धनी इसके भुगतान की तारीख के पहिले ऊपर वाले धनी के पास इसकी रकम पहुँचा देने का वायदा कर लेता है। अब, यदि वह ऐसा नहीं करता तो सम्भव है कि ऊपर वाला धनी उसका भुगतान न कर सके। राजू कहता है कि यदि सहायता के सम्बन्ध के बहुत से बिल हो जायँ और लिखने वाले तथा ऊपर वाले धनियों की आशायें सफलीभूत न हों तो यह सम्भव है कि ऐसे बिलों का भुगतान न होने के कारण बैंकर की हानि हो जाय। ये बिल साख पर तो निर्भर होते ही हैं और साख का अनुचित प्रयोग कभी भी किया जा सकता है। सहायता के बिलों (Accommodation Bills) को पतंगी बिल (Kite Bills) भी कहते हैं। आशा पर किये गये बिलों (Anticipatory Bills) को अर्थ बिल (Financial Bills) भी कहते हैं। ये वर्तमान सम्पत्ति के ऊपर नहीं बरन् भविष्य में उत्पन्न होने वाली सम्पत्ति पर किये जाते हैं। ये अमेरिका में बहुत प्रचलित हैं और कृषकों को उनके दैनिक व्यय देने के लिये किये जाते हैं। ये भी बैंकों के लिये उपयुक्त नहीं हैं क्योंकि खड़ी खेती के मूल्य पर निर्भर रहना जोखिम से खाली नहीं है।

आदत के काम (Agency Services)

बैंकर अपने ग्राहकों के लिये अनेकों प्रकार के आदत के काम भी

किया करते हैं। वे उनके चेकों, विलों, प्रणपत्रों, व्याजपत्रों (Coupons) लाभ क्री बँटनी के पत्रों (Dividend-warrants) चन्दे (Subscriptions), किराये, आय कर, वीमे के प्रीमियम, इत्यादि की वसूली भुगतान और जमा करते हैं। वे उनकी तरफ से हिस्से-पत्रों, स्टकों, ऋणपत्रों, इत्यादि की स्टोक एक्सचेंज में और अन्य वस्तुओं की अन्य बाजारों में लेवा-बेची करते हैं। वास्तव में वे आदत पाने पर उनके लिये कोई भी काम कर सकते हैं। कभी-कभी तो वे इन्हे आदत लिए बिना ही केवल जमा प्राप्ति की लालच में ही किया करते हैं। किन्तु वे जब आदत का काम करते हैं तब उनके ऊपर बहुत से महत्वपूर्ण दायित्व आ पड़ते हैं।

अन्य काम (Miscellaneous Services)

अन्य कामों में बैंकों द्वारा किये जाने वाले अनेकों काम सम्मिलित हैं। वे अपने ग्राहकों की मूल्यवान सम्पत्ति, गहनों और जवाहिरात तथा मूल्यवान कागजों को सुरक्षित रखने (Safe custody) के लिये भी लेते हैं। वे सम्मति देने (Referee) का भी काम करते हैं। जब कोई व्यवसायी किसी अन्य व्यवसायी की आर्थिक स्थिति का पता लगाना चाहता है तब उसे उसके बैंकर का हवाला (Reference) दे दिया जाता है जो उसे उसके विषय में सारी सूचनाएँ दे देता है। वे अपने ग्राहकों के सम्भावित ग्राहकों की स्थिति का पता भी लगा देते हैं जिससे वे उनकी साख पर काम करने अथवा न करने का निश्चय करते हैं। वे साख-पत्र (Letters of credit) और बैंक ड्राफ्ट भी निकालते हैं। इनके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थानों को भेजी जाती हैं। किन्तु किसी बैंकर का सबसे महत्वपूर्ण काम तो यह है कि वह अपने ग्राहकों को सच्ची मित्रता और सहनशीलता सिखाता है। बैंकिंग की कार्य-कुशल प्रणाली साख के दर्जे की और समाज की व्यवसायिक सञ्चरितता की इतनी उन्नति करती है कि उन्हें साधुशीलता, विश्वासपात्रता, ईमानदारी, सत्यता और योग्यता का निर्माता कहा जाता है। किसी राष्ट्र के यहाँ जब सीधी-सादी द्रव्य प्रणाली के स्थान पर पेचीदा साख-प्रणाली चालू हो जाती है तभी हमको इस बात का पता चलता है कि उपर्युक्त गुणों के उसके जन-साधारण में कूट-कूट कर भर जाने से क्या लाभ होता है।

प्रश्न

- (१) व्यापारिक बैंकों के कामों का सक्षिप्त वर्णन कीजिये ।
- (२) बैंक किन-किन विभिन्न खातों में जमा प्राप्त करते हैं । उनमें से प्रत्येक के महत्वपूर्ण लक्षण बताइये ।
- (३) बैंकों की जमा किन-किन तरीकों से बनती है ! साथ ही यह भी बतलाइये कि वह उन्हें कहीं तक शक्ति प्रदान करती है !
- (४) 'साख की उत्पत्ति बैंक के' लेखक की लेखनी पर ही निर्भर है ।' उपयुक्त की आलोचना कीजिये ।
- (५) कीन्स का कथन है "ऋण जमा के बच्चे हैं और जमा ऋण के बच्चे हैं ।" इससे आप कहीं तक सहमत हैं ?
- (६) बैंकों के ऋण देने के सम्बन्ध में लार्ड ओवरस्टन का जो यह कथन है कि यह मेरी बुद्धि है और दूसरो का द्रव्य है उससे आप कहीं तक सहमत हैं ?
- (७) बैंकों के ऋण के जितने रूप हो सकते हैं उनका एक सक्षिप्त विवरण दीजिये । डिस्काउन्ट का व्यवसाय बैंकों की क्यों अधिक प्रिय है ?

अध्याय ५

व्यापारिक बैंकों के काम करने की प्रणाली

(Banking Operations)

व्यापारिक बैंकों के काम करने की प्रणाली में निम्न चार बातों का अध्ययन करना पड़ता है :—

- (१) बैंकों को उनकी कार्यशील पूँजी (Working Capital) कैसे प्राप्त होती है ।
- (२) बैंक अपनी कार्यशील पूँजी का कैसे उपयोग करते हैं ।
- (३) बैंक कैसे लाभ कमाते हैं ।
- (४) बैंक अपने लाभ का किस प्रकार उपयोग करते हैं ।

बैंकों को उनकी कार्यशील पूँजी कैसे प्राप्त होती है

बैंकों को उनकी कार्यशील पूँजी अनेकों ढङ्ग से प्राप्त होती है। प्रथम तो अन्य व्यापारिक सस्थाओं की तरह वह भी अपने हिस्से (Shares) निकालते हैं। किसी बैंक के सस्थापक यह निश्चय करते हैं कि उनके बैंक की रजिस्ट्री कितनी पूँजी से होनी चाहिये। सारी पूँजी बराबर-बराबर रकम के कुछ भागों में विभक्त कर दी जाती है, और प्रत्येक भाग एक हिस्सा (Share) कहलाता है। ये हिस्से जनता को क्रय करने के लिये दिये जाते हैं। कभी-कभी सब हिस्से प्रारम्भ ही में जनता के क्रय के लिये नहीं निकाले जाते, वरन् उनमें से कुछ भविष्य में निकालने के लिये रोक लिये जाते हैं। फिर, जितने हिस्से निकाले जाते हैं उन सब को जनता हमेशा ले भी नहीं लेती है। अब यदि विवरणपत्रिका (Prospectus) में दी हुई न्यूनतम पूँजी (Minimum-subscription) के हिस्सों के लिये उचित समय के अन्दर जनता के प्रार्थनापत्र नहीं आ जाते हैं तो उनकी बँटनी (Allotment) नहीं होती और बैंक भंग कर दिया जाता है। फिर, हिस्सों की पूरी रकम भी न मँगाई जाकर केवल कुछ अंशों में ही मँगाई जा सकती है। शेष रकम आवश्यकता पड़ने पर भविष्य में मँगाने के लिये छोड़ी जा सकती है। अन्तिम, यह भी सम्भव है कि सब हिस्सेदार कुल माँगी हुई रकम न दे पावे। अतः पूँजी के भिन्न-भिन्न रूप हैं और उनके भिन्न-भिन्न नाम भी हैं। जिस पूँजी से बैंक की रजिस्ट्री होती है उसको अधिकृत अथवा रजिस्टर्ड अथवा नाममात्र की पूँजी (Authorised, Registered or Nominal Capital) कहते हैं, निकाली गई पूँजी को निकाली गई पूँजी (Issued Capital), खरीदी हुई पूँजी को क्रीत पूँजी (Subscribed-Capital) माँगी हुई पूँजी को माँगी हुई पूँजी (Called up Capital) और प्राप्त पूँजी को प्राप्त पूँजी (Paid up Capital) कहते हैं। प्राप्त पूँजी और माँगी हुई पूँजी के अन्तर की रकम को बाकी पूँजी (Calls in arrear) कहते हैं। यह अन्तर अधिक दिनों तक नहीं चलता। उचित समय के व्यतीत हो जाने पर उन व्यक्तियों के हिस्सों को जप्त (Forfeit) कर लिया जाता है जो उन पर की गई माँग को नहीं दे पाते हैं और उन्हें दूसरों के नाम बेच दिया जाता है। माँगी हुई पूँजी और क्रीत पूँजी के बीच के अन्तर को हिस्सेदारों का सुरक्षित दायित्व (Reserved Liability of the Shareholders)

कहते हैं। वैयक्तिक बैंकरों (Individual Bankers) और साम्ने के बैंकरों का दायित्व तो असीमित रहता है, अर्थात् यदि उनके व्यवसाय का ऋण उनके व्यवसाय की पूँजी से नहीं पूरा हो पाता तो उसको उन्हें अपनी निजी पूँजी से पूरा करना पड़ता है। किंतु सम्मिलित पूँजी के बैंकों के सम्बन्ध में यह बात नहीं है। उनके हिस्सेदारों को केवल उनकी पूँजी की रकम को ही देना पड़ता है। यदि ध्यान से देखा जाय तो यह ठीक ही है। वैयक्तिक बैंकर और साम्ने बैंकर अपने व्यवसाय को स्वयं चलाते हैं और उसकी नीति को निर्धारित करते हैं। अतः, उनका उत्तरदायित्व भी असीमित रह सकता है। किन्तु सब हिस्सेदार तो व्यवसाय को देखते नहीं, अतः, उनका उत्तरदायित्व सीमित ही रहना चाहिये। सीमित दायित्व का सबसे पहिला विधान सन् १८५५ में इंगलिस्तान में पास किया गया था। किन्तु उस समय यह केवल अन्य व्यापारों के लिये था, बैंकिंग के लिये नहीं। अधिकांश लोगों का यह विचार था कि बैंकरों की स्थिति ऐसी दायित्वपूर्ण है और उनके पास लोगों की इतनी अधिक जमा रहती है कि उनके दायित्व को सीमित नहीं किया जा सकता। सन् १८५७ में बड़े संकट का समय आ गया और उसमें बहुत से बैंक विशेषतः स्काटलैण्ड का पश्चिमी बैंक (Western Bank of Scotland) भी फेल हो गया। अतः यह देखा गया कि धनी लोग बैंकों के हिस्से नहीं खरीदते। उनके अधिकतर हिस्से गरीबों के पास ही रहते हैं। इसलिये धनी लोगों को बैंकों के हिस्से लेने को प्रोत्साहित करने के लिये सन् १८५८ में बैंकों के हिस्सेदारों के दायित्व को भी सीमित कर दिया गया। किन्तु बहुत से बैंकों ने यह सोचकर कि कहीं ऐसा करने से उनके ग्राहकों का उनके ऊपर से विश्वास न उठ जाय, ऐसा नहीं किया। लेकिन सन् १८७८ में ग्लासगो शहर के बैंक (City of Glasgow Bank) के फेल हो जाने पर उसके हिस्सेदारों की बहुत क्षति हो जाने के कारण बैंकों के हिस्सेदारों में इतना डर समा गया कि उनके दायित्व को सीमित करना ही पड़ा। सन् १८७९ में सुरक्षित दायित्व का एक विधान पास किया गया जिसके अनुसार बैंक अपने हिस्सों के पूर्ण मूल्य (Nominal value) को इस शर्त पर बढ़ा सकते थे कि वह बढ़ा हुआ मूल्य केवल उनके दिवालिया होने पर ही आवश्यकता पड़ने पर लिया जा सकेगा। वस, यह उनका सुरक्षित दायित्व कहलाया। इसका फल यह हुआ कि

जब कि एक ओर तो हिस्सेदारों का दायित्व सीमित हो गया दूसरी ओर बैंकों में जमा करने वालों को यह विश्वास हो गया कि यदि वह फेल भी हो जायेंगे तो उनकी रकम के भुगतान के लिये कुछ रकम तो सुरक्षित दायित्व से मिल ही जायगी। तब से यह प्रथा प्रचलित है और बैंक, अपने हिस्सेदारों से उनके खरीदे हुये हिस्सों की पूरी रकम नहीं माँगते। हमारे देश में सीमित दायित्व के सिद्धान्त को सन् १८६० में माना गया था। अतः, उसके बाद ही यहाँ पर बहुत से बैंक स्थापित हुये। ऊँचे दर्जे के बैंकों की निकाली हुई पूँजी और क्रीत पूँजी में कोई अन्तर नहीं होता। बात यह है कि उनके निकाले हुये सभी हिस्सों के खरीदार मिल जाते हैं। अधिकृत पूँजी और निकाली हुई पूँजी का अन्तर इस बात का द्योतक है कि व्यवसाय के बढ़ने पर बैंक की पूँजी भी बढ़ जायगी। किन्तु इन सब में सबसे महत्वपूर्ण तो प्राप्त पूँजी ही है। वही तो बैंक की कार्यशील पूँजी का एक विशेष अङ्ग है। किन्तु यह अङ्ग अन्य अंगों की अपेक्षा-कृत बहुत ही कम होता है। एक बात और ध्यान देने की है और वह यह है कि हिस्सेदार अपनी पूँजी पर कुछ आय भी चाहते हैं। बैंकों को लाभ तो मिलता ही है, किन्तु उसमें से कुछ तो वे सुरक्षित कोष (Reserve fund) के लिये बचा लेते हैं। हाँ, शेष हिस्सेदारों में लाभ के रूप में (Dividend) बाँट दिया जाता है। सुरक्षित-कोष अन्त में हिस्सेदारों का ही होता है। अतः, वह भी पूँजी का ही एक अङ्ग माना जाता है। किसी बैंक के सब हिस्सों के विक्रि जाने के कारण और उनकी पूरी रकम मँगा लेने के कारण जब व्यवसाय के बढ़ने पर उस बैंक की पूँजी बढ़ने का कोई तरीका नहीं रह जाता तब इसी तरीके से बराबर उसकी पूँजी बढ़ती रहती है।

कार्यशील पूँजी प्राप्त करने का एक दूसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण साधन जमा प्राप्त करने का है। जैसा कि हम पहिले ही देख चुके हैं यह जमा भिन्न-भिन्न रूपों में और भिन्न-भिन्न खातों में प्राप्त की जाती है। अतः, केवल वही जमा कार्यशील पूँजी को बढ़ाती है जो नकदी के रूप में अथवा ऐसे अधिकारों के रूप में होती है, जिससे नकदी प्राप्त हो सकती है। विनिमय के विलों पर अथवा अन्य तरह से ऋणों को देकर जो जमा प्राप्त की जाती है वह कार्यशील पूँजी को नहीं बढ़ाती। पहिले प्रकार की जमा को प्रत्यक्ष जमा (Direct

deposits) और दूसरे प्रकार की जमा को अप्रत्यक्ष जमा (Indirect deposits) कहते हैं। बैंकर अपने ग्राहकों की उस रकम को भी जो उनके पास आदत के काम के सम्बन्ध में आती है, उस समय तक प्रयोग में ला सकते हैं, जिस समय तक वह आदत के काम में नहीं आ जाती। उदाहरण के लिये जब एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजने के लिए द्रव्य दिया जाता है तो जब तक वह पाने वाले को नहीं दे दिया जाता तब तक बैंकर उसको प्रयोग में ला सकता है, इत्यादि।

किन्तु बैंक के जमा का व्यवसाय या तो अधिकार का पारस्परिक विनिमय है^१ या द्रव्य और अधिकार का विनिमय है। कोई बैंक जब द्रव्य पाता है तब वह जमा करने वाले को अपनी इच्छा पर उसको निकालने का अधिकार देता है। जब उसे विनिमय के बिल, चेक, प्रण-पत्र, लाभपत्र, व्याजपत्र इत्यादि उनकी रकम वसूल करने के लिए मिलते हैं तब उसे द्रव्य वसूल करने का अधिकार मिलता है और वह उसके स्थान पर उसे निकालने का अधिकार देता है। जब उसको चन्दा, किराया, आयकर, वीमे का प्रीमियम और दूसरे सामयिक भुगतान मिलते हैं तब वह द्रव्य पाता है और जिनके लिये वह ऐसा करता है उनको इनके निकालने का अधिकार देता है। द्रव्य को इधर से उधर भेजने में भी वह द्रव्य पाता है और उसको निकालने का अधिकार देता है। जहाँ तक अप्रत्यक्ष जमा का प्रश्न है उसमें तो केवल अधिकारों का ही विनिमय होता है। दूसरे शब्दों में यह सब साख का व्यवसाय है क्योंकि ग्राहकों और बैंकों के बीच में जितने लेन-देन होते हैं उनमें सब में विश्वास की मात्रा प्रधान होती है। इसके बिना कोई किसी को द्रव्य अथवा उसको पाने का अधिकार सौंप ही नहीं सकता है।

राज के कथन के अनुसार बैंकों के जमा का व्यवसाय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें वह इधर-उधर पड़ी हुई दस, बीस, पचास और सौ-सौ की छोटी-छोटी रकमों को एकत्रित करता है। अकेले इनमें कोई आर्थिक कुशलता नहीं है, किन्तु बैंकर जब इन्हे प्रयोग में लाते हैं तब यह बड़े से बड़े काम कर डालते हैं। बेजहौट के कथन के अनुसार इंगलिस्तान के द्रव्य के बाजार के इतना धनी और महत्वशाली होने का यदि एक मात्र नहीं तो मुख्य कारण यही है कि वहाँ पर द्रव्य

१ "The whole deposit business of a Bank consists in the exchange of rights against rights or of rights against money"

की एकाग्रता पाई जाती है। लोगों की रकम जमा करना और उनको व्यापारियों और उद्योगपतियों को देना यह बैंकों की, समाज के प्रति पहिली सेवा है और इसकी कुशलता इस बात पर निर्भर है कि उन्होंने कितनी रकम जमा कर ली है और व्यापार और उद्योग-धन्धों की कितनी माँग पूरी की है। भारतीय बैंक बहुत कुशल नहीं कहें जा सकते क्योंकि न तो उन्होंने यहाँ के सर्वसाधारण की वचत को ही प्राप्त करने का प्रयत्न किया है और न वे व्यापार और उद्योग-धन्धों की माँग ही पूरी कर पाते हैं।

बैंक अपने ग्राहकों को उनके जमा के सम्बन्ध में चेक काटने के अधिकार देकर अधिकाधिक क्रय-शक्ति उत्पन्न करते हैं। यह उनकी दूसरी समाज सेवा है। राज के कथन के अनुसार जमा से उत्पन्न होने वाली करन्सी (Deposit currency) अथवा चेक करन्सी अथवा बैंकों का यह द्रव्य चाहे जिस नाम से पुकारा जाय, बहुत ही लोचप्रद (Elastic) है। वास्तव में बैंकों को उनके सम्बन्ध की किसी वैधानिक अड़चन के न होने के कारण सुरक्षा और समाज हित के विचार को ध्यान रखते हुये किसी भी रकम तक निकाला जा सकता है। अब यह सुरक्षा और समाज हित के क्या विचार हैं यह तो पहिले ही बताये जा चुके हैं। इनका उल्लंघन इस सेवा के कार्य को अहित में परिणत कर देता है। रक्षा की सीमा को पार करने से बैंक फेल हो सकते हैं और समाज हित के विचारों को त्याग देने से इतनी अधिक क्रय-शक्ति उत्पन्न हो जाती है कि उससे वस्तुओं के मूल्य अत्यधिक बढ़ जाने से समाज का अहित होता है। साख उत्पन्न करना तो आसान है किन्तु उसी के अनुपात में उत्पत्ति बढ़ाना कठिन है।

पूँजी प्राप्त करने का तीसरा साधन नोटों को चलाना है। किन्तु यह साधन अब अधिकांश बैंकों के लिये उपलब्ध नहीं है। कहना न होगा कि धात्विक-द्रव्य की तरह नोटों को चलाने के अधिकार को सदा से ही राज्याधिकार माना गया है। किन्तु जब धात्विक-द्रव्य निकालने के अधिकार का राज्य ने बराबर उपयोग किया है, तब कुछ विशेष हालतों को छोड़ कर नोटों के चलाने के अधिकार को उसने बैंकों ही को सौंप दिया है। यदि कहीं बैंक स्वयं ही अपने नोट चलाते आ रहे थे तो वहाँ राज्य ने पहिले तो उनकी सुरक्षा के लिये कुछ वैधानिक नियम बना कर उनको ऐसा करते रहने की विधानतः

आज्ञा दे दी; किन्तु शीघ्र ही उसने इस बात का अनुभव किया कि इसमें समानता लाने के लिये, अच्छे निरीक्षण के लिये और इससे उत्पन्न हुये लाभ में राज्य का हिस्सा बटाने के लिये इसका या तो किसी एक बैंक को एकाधिकार अथवा शेषाधिकार (Residuary power) देना पड़ेगा। बेरस्मिथ के अनुसार शेषाधिकार वह है जब कई बैंक नोट चलाते हैं किन्तु उनमें से एक को छोड़कर सब का यह अधिकार सीमित रहता है। वास्तव में एक मुख्य बैंक के ही नोट विशेषतः चालू रहते हैं और उसी पर अधिकांश करन्सी का दायित्व रहता है। हम को ज्ञात है कि यह सन् १८४४ में इंगलैण्ड में हुआ। हालैण्ड में यह सन् १८१४ ही में हो चुका था। फ्रान्स में यह सन् १८४८ में, जर्मनी में सन् १८७५ में, स्वीडेन में सन् १८९७ में, संयुक्त राष्ट्र में सन् १९१४ में, दक्षिणी अफ्रीका के यूनियन में सन् १९२१ में, कोलम्बिया में सन् १९२३ में, आस्ट्रेलिया में सन् १९२४ में, चिली में सन् १९२५ में, इटली में सन् १९२६ में, न्यूजीलैण्ड में सन् १९३४ में, और कनाडा में सन् १९३५ में हुआ। भारतवर्ष में बैंकों के पास नोट चलाने की यह शक्ति सन् १८६१ तक रही। उस वर्ष सरकार ने इसको अपने हाथ में ले लिया और सन् १९३५ में यह इस देश के केन्द्रीय बैंक, रिजर्व बैंक आफ इण्डिया को हस्तान्तरित कर दी गई।

जब कोई बैंक नोट निकालता है तब वह स्वयं अपनी कार्य-शील पूँजी उत्पन्न करता है। पहिले-पहिल जो नोट चलाये गये थे वह द्रव्य-की रसीदें थीं। साथ ही उनके चलाने वालों ने यह भी शीघ्र ही समझ लिया था कि जैसा जमा की रसीदों के सम्बन्ध में है वैसा ही इनके सम्बन्ध में भी है अर्थात् इन सब का भुगतान भी कभी एक साथ नहीं करना पड़ेगा। अतः, वह वास्तविक द्रव्य के एक बड़े अंश को चाहे जिस काम में लावे, उससे उनके नोटों के भुगतान में तनिक भी अड़चन नहीं पड़ेगी। जब तक किसी बैंक की साख मानी जाती थी तब तक उसके नोट नकदी ही समझे जाते थे और विधानतः ग्राह्य द्रव्य (Legal tender money) के सदृश्य ही माने जाते थे। बस, बिलों के भुनाने में और ऋण देने में भी इन्हीं नोटों का देना प्रारम्भ हो गया और लोग इन्हे सहर्ष लेने भी लगे। बैंकों के लिये भी इस बात में कोई अन्तर नहीं था कि उनके साख की उत्पत्ति का रूप नोटों का हो अथवा अप्रत्यक्ष जमा का हो। यदि इनमें कोई अन्तर था

तो वह केवल रूप का ही था। किन्तु व्यापारियों की दृष्टि में नोटों की अपेक्षाकृत जमा के अधिक लाभप्रद जँचने के कारण और जैसा कि पहिले बताया जा चुका है, नोटों के निकालने पर अधिकाधिक बन्धनों के लग जाने के कारण जमा बहुत ही महत्व पकड़ती गई यहाँ तक कि उसकी करन्सी संसार के प्रगतिशील देशों में आज नोट करन्सी से कहीं अधिक प्रचलित है। राज इन दोनों की सदृश्यता के विषय में जो कहता है उसका यहाँ पर संकेत कर देना भी शायद अनुपयुक्त न होगा। वह कहता है दोनों का प्रयोग ग्राहकों को ऋण देने में अथवा उनके प्रणपत्रों और विलों का विनिमय करने में क्रिय, जा सकता है। दोनों ही प्रणपत्रों के रूप में अथवा ग्राहकों के विलों के रूप में जनता की सेवा करते हैं। दोनों में ही बैंकों से विधानतः ग्राह्य द्रव्य माँगने का अधिकार रहता है। दोनों ही बैंकों के लिये आय के साधन हैं। बैंक के लिये दोनों माँग पर पूरा करने वाले दायित्व हैं।” आगे चलकर उसने इनके अन्तर भी बताया है—“बैंक नोट जमा की अपेक्षाकृत कहीं अधिक सुरक्षित दायित्व है। अतः, बैंक अपनी साख इनके रूप में चलाना अधिक पसन्द करता है। उद्योग-धन्यों में चाहे जितनी मन्दी क्यों न आ जाय जब तक बैंक जनता का विश्वासपात्र है तब तक उसके नोट चलते ही रहते हैं। जमा वो तो उसके ग्राहक किसी समय भी अपने दायित्व को पूरा करने के लिये प्रयोग में ला सकते हैं, किन्तु छोटे नोट बहुत दिनों तक चलते रहते हैं और प्रायः जमा के रूप में बैंकों के पास वापस आते हैं। बैंक नोट में चलन-शक्ति चेकों के अपेक्षाकृत कहीं अधिक है। जिस प्रकार चन्द्रमा गरीबों की लालटेन कहा जा सकता है उसी प्रकार बैंक नोट गरीबों की जमा कही जा सकती है। अतः, लोगों की वास्तविक माँग को पूरा करने के लिये नोटों के देने में अधिक कठिनाई नहीं पड़ती।” किन्तु यह सब सैद्धान्तिक है। वास्तव में साधारण बैंकों के पास तो अब नोट चलाने का अधिकार रह ही नहीं गया है।

बैंक अपनी कार्यशील पूँजी का कैसे उपयोग करते हैं

उपर्युक्त विवरण से यह तो, स्पष्ट ही हो गया है कि बैंकों की अधिकांश कार्यशील पूँजी माँग पर देय है। हाँ, उनके हिस्सेदारों से प्राप्त पूँजी और उनके लाभ का वह अंश जिसे वह हिस्सेदारों में न

बाँट कर सुरक्षित कोष के रूप में रख लेते हैं, अवश्य ही स्थायी होता है। किन्तु वैकिंग के व्यवसाय का अर्थ पूँजी का रख छोड़ना नहीं वरन् उसको चलायमान रखना है। बैंकों को थोड़ा-सा नकद कोष रखने के अतिरिक्त शेष सभी को ऐसी लागतों में लगा देना चाहिये जो आवश्यकता पड़ने पर उसके खाली हो जाने वाले कोष का स्थान लेने के लिये उपलब्ध हो सकें। थोड़े-थोड़े समय पर प्रायः ऐसे अवसर आते रहते हैं कि लोग अधिकाधिक द्रव्य निकाल लेते हैं। कभी-कभी तो इन अवसरों पर ग्राहक ऋण लेने भी आ जाते हैं, जिनका पूरा करना भी बैंकों के लिये बहुत ही आवश्यक है। अतः, हम अगले पृष्ठों में इस बात को समझने का प्रयत्न करेंगे कि बैंक अपनी सम्पत्ति और अपने पावने (Assets) को किस रूप में रखते हैं और उनके चुनाव में उन्हें किन-किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है।

कुशल बैंकर ऐसी व्याज लागतों को ढूँढते रहते हैं जो आसानी से वसूल हो जाती है; और भुगतान के लिये लगातार पकती रहती हैं। वह आर्थिक स्थितियों का बराबर ध्यान रखते हैं और उन्हीं के अनुसार अपनी लागतों में हेर-फेर करते रहते हैं। मोटे तौर पर इन्हें दो विभागों में बाँटा जा सकता है—(१) लाभ न देने वाली और (२) लाभ देने वाली। प्रथम में तो उनके नकदी के कोष और मृत स्टॉक के क्रय और दूसरे में मॉग पर वापिस होने वाली लागत (Call money), बिलों पर की लागत (Discounts), ऋण (Advances), बाजारू साख-पत्रों पर की लागत (Investments), और बिलों को स्वीकार करना (Acceptances), इत्यादि सम्मिलित हैं।

पहिले हम नकद कोष को ही लेते हैं :—उनको अंग्रेजी में टिल मनी (Till money) कहते हैं। इसका अर्थ बैंकों के बक्सों में और केन्द्राय बैंक में रक्खा हुआ द्रव्य है। इन दोनों को मिलाकर उनकी रक्षा की प्रथम कतार (First line of defence) बनती है। यह दिवालियापन से वचाती है। सन्नेप में यह पूर्व विधान युक्ति (Precautionary measure) है। बैंकों को यथेष्ट नकद कोष रखने और उसको निरन्तर सुदृढ़ बनाने का सदा प्रयास करते रहना चाहिए। इसके लिये उनको देर में वसूल होने वाली लागत को शीघ्र वसूल होने वाली लागत में परिवर्तित करते रहना चाहिये। जहाँ तक

यह प्रश्न है कि नकद कोष और माँग पर देय रकम (Demand liability) का क्या अनुपात रहना चाहिये यह बात जैसा कि पहिले भी कहा जा चुका है, बहुत सी बातों पर निर्भर है और परिवर्तित होती रहती है। यह निम्नाङ्कित है :—

(१) कहीं-कहीं व्यवस्थापक सभाओं (Legislatures) ने कुछ प्रतिशत निश्चित कर दिया है। इससे नवसिखियों को अवश्य सहायता मिलती है और अत्यधिक साहस करने वालों के ऊपर भी प्रतिबन्ध रहता है। किन्तु इसके अतिरिक्त यह कुछ नहीं है। वास्तव में बैंक प्रबन्धकों को विधान के द्वारा बाँधने की अपेक्षाकृत उनकी स्वयं की सचाई, बुद्धि और निर्णय शक्ति पर विश्वास करना अधिक अच्छा है। किसी वैधानिक सीमा को निर्धारित कर देने से उनके मस्तिष्क में झूठी सुरक्षा का बोध हो जाता है और वे सोचने लगते हैं कि उनको जो कुछ करना था वह उन्होंने कर दिया है। फिर यह बतलाना भी कठिन है कि यह निर्धारित प्रतिशत क्या होनी चाहिये क्योंकि भिन्न-भिन्न देशों की व्यवस्थापक सभाओं ने जो प्रतिशत निर्धारित किये हैं वे सभी एक दूसरे से बहुत ही भिन्न हैं। उदाहरण के लिये डेनमार्क में यह चालू जमा का १० प्रतिशत है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में यह भिन्न-भिन्न स्थानों में भिन्न-भिन्न है, अर्जेंटीना में यह स्थायी जमा का ८ प्रतिशत और चालू जमा का १६ प्रतिशत है, चिली में यही क्रमशः ८ प्रतिशत और २० प्रतिशत है, इक्वेडोर में यह क्रमशः १० प्रतिशत और २५ प्रतिशत और वीलिविया में क्रमशः १० प्रतिशत और २० प्रतिशत है। कुछ देशों में इस प्रतिशत में केवल बैंकों में रक्खा हुआ सुरक्षित कोष और कुछ में इसमें यह और केन्द्रीय बैंकों में भी रक्खा हुआ सुरक्षित कोष दोनों सम्मिलित हैं। हमारे देश में रिजर्व बैंक के सदस्य बैंकों (Scheduled Banks) को उक्त बैंक के पास उनकी चालू जमा का ५ प्रतिशत और स्थायी जमा का २ प्रतिशत रखना पड़ता है। उनके स्वयं के वक्कों में रखे जाने वाले कोष पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। इसके विपरीत अन्य बैंकों (Non-Scheduled Banks) को उनकी स्थायी जमा का १½ प्रतिशत और चालू जमा का ५ प्रतिशत अपने ही वक्कों में रखना पड़ता है।

(२) यह साधारणतः रखे जाने वाले प्रतिशत पर भी निर्भर रहता है। यदि किसी स्थान का एक बैंक अधिक प्रतिशत रखना

है तो उस स्थान के अन्य बैंकों को भी जनता का विश्वासपात्र बनने के लिये वैसा ही करना पड़ता है। अन्य स्थानों के बैंकों की अपेक्षा-कृत इंग्लैण्ड के बैंक बहुत कम प्रतिशत रखते हैं।

(३) किसी बैंक के नकद कोष का परिमाण उसके प्रत्येक ग्राहक की जमा के आसत के परिमाण पर भी निर्भर रहता है। वास्तव में यह उतना होना चाहिये जितना कि सबसे अधिक जमा रखने वाले ग्राहक की माँग को पूरा करने के लिये काफी हो।

(४) जिन देशों में अधिकांश भुगतान चेकों के द्वारा होते हैं उन देशों में उनकी अपेक्षाकृत कम कोष रखने की आवश्यकता पड़ती है जिनमें अधिकांश भुगतान नकदी में होते हैं।

(५) यदि निकास प्रणाली (Clearing system) बहुत ही उन्नत अवस्था को पहुँच चुकी है तो बैंकों पर की गई अधिकांश चेकों का भुगतान परस्पर ही हो जाता है। मान लीजिये 'अ' बैंक के ग्राहकों ने 'ब' 'स' 'द' बैंकों के ग्राहकों के भुगतान में 'अ' बैंक के ऊपर के चेक दिये हैं। इसी तरह से 'ब' 'स' और 'द' बैंकों के ग्राहकों ने भी अपने से अन्य बैंकों के ग्राहकों के भुगतान में अपने-अपने बैंकों के चेक दिये हैं। अब, प्रत्येक बैंक के ग्राहकों को अन्य बैंकों के ग्राहकों से उनके अपने-अपने बैंकों के ऊपर के जो चेक प्राप्त हुये होंगे उनको वे अपने-अपने बैंकों को देगे। अतः, सभी बैंकों को अन्य बैंकों से पाना और उनको देना भी होगा। अब, यदि निकास प्रणाली है तो इन चेकों का परस्पर भुगतान हो जायगा, नकदी नहीं देनी पड़ेगी। अतः, ऐसी अवस्था में बैंकों को बहुत कम नकद कोष रखना पड़ता है।

(६) जहाँ पर लोग अपने पास नकदी न रख कर बैंकों के द्वारा काम करते हैं, वहाँ पर उसके बराबर चालू रहने से जब बैंक एक तरफ उसको देते हैं तब दूसरी तरफ उसको पाते भी हैं। अतः, उनका काम कम नकदी रखने पर भी चल जाता है।

(७) यदि किसी बैंक के ग्राहक ऐसे हैं जो कभी-कभी बहुत रकम निकालते हैं जैसे बिलों के दलाल, इत्यादि तब उसको इनको पूरा करने के लिये काफी नकद कोष रखना पड़ता है।

(८) यदि किसी बैंक की लागत ऐसी है जिसकी वसूली आसानी से हो सकती है तो कम नकदी रखने से भी काम चल सकता है। जिन देशों में द्रव्य के बाजार और बिलों के बाजार बहुत उन्नत दशा

में हैं उनमें उन्हीं में लागत लगाई जाती है। अतः, आवश्यकता पड़ने पर उनकी वसूली भी हो सकती है। इंग्लैण्ड में बहुत काफी द्रव्य बिलों के और स्टॉक एक्सचेंज के दलालों को जो अपने ऋणों के लिये बहुत उच्च श्रेणी की देखनहार सिक्क्योरिटीज गिरवी रख देते हैं और उनको तीन से दस दिनों के अन्दर अथवा दूसरे ही दिन वापस करने का वायदा कर लेते हैं, दे दिया जाता है। वास्तव में यह ऋण जो बहुत ही थोड़ी अवधि के लिये अथवा दैनिक ही होते हैं एक तरह से बराबर चालू रहते हैं। इनमें माँग पर अथवा कम अवधि पर वापिस होने वाले ऋण (Money at call and short notice or Call money) अथवा रात्रि भर के लिये ऋण (Over-night money) कहते हैं। इनके अतिरिक्त बिलों के डिस्काउण्ट करने के व्यवसाय में भी जैसा कि पहिले कहा जा चुका है, बिलों में की लागत आदर्श लागत है। यदि केन्द्रीय बैंक है और आज कल तो सभी जगह केन्द्रीय बैंक है तो आवश्यकता पड़ने पर इनको उससे भुनाया भी जा सकता है।

(५) अन्तिम, यदि बैंक व्यापारिक क्षेत्र में स्थित है तो उनको उन बैंकों की अपेक्षाकृत कम नकदी रखनी पड़ती है जो कृषक-क्षेत्र में स्थित हैं। बात यह है कि जब कृषकों को बार-बार द्रव्य निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती, व्यापारियों को इसकी आवश्यकता पड़ती है।

जहाँ तक मृत स्टॉक (Dead stock) के क्रय का प्रश्न है उसमें इमारतें और उनके सम्बन्ध की अन्य चीजें जैसे फरनीचर, इत्यादि सम्मिलित है। बैंकों के लिये अपना व्यवसाय करने के लिये इनका होना अत्यावश्यक है। किसी बैंक की इमारत काफी बड़ी और भड़कीली होनी चाहिये। वह वास्तव में विज्ञापन का काम देती है। अच्छी इमारतें अच्छे ग्राहकों को आकर्षित करती हैं। वह ऐसी होनी चाहिये कि जिसमें न तो सेंध लगाई जा सके और न आग लग सके। पुराने और नये रिकार्डों को रखने के लिये उसमें विशेष कमरे होने चाहिये। किन्तु इतना होते हुये भी उसमें बहुत अधिक लागत लगा देना उचित नहीं है। राज के शब्दों में "एक बैंक के लिये ठोस

1. It is always preferable for a bank to have solid cash in its hands rather than invest it in bricks and mortar.

नकदी का होना ईंटों और चूने में लागत लगा देने की अपेक्षाकृत कहीं अधिक अच्छा है।" मृत स्टाक का विक्रय कठिन है। एक तो वह आसानी से बिकता ही नहीं और दूसरे उसके बेचने से बैंक की वदनामी भी हो जाती है। उसको तो बैंक के फेल हो जाने पर ही बेचा जा सकता है, पहिले नहीं।

अब हम बैंकों की कार्यशील पूँजी के लाभदायक प्रयोगों की ओर आते हैं। उसके एक अंश को मृत स्टाक और नकद कोष में फँसा देने के बाद प्रत्येक बैंक प्रवन्धक इस बात को सोचता है कि शेष को वह कैसे छोटी और बड़ी अवधि वाले ऋणों में लगावे। यह स्पष्ट है कि वह काफी रकम केवल छोटी अवधि वाले ऋणों में ही लगाना चाहता है। किन्तु ऐसा करने के पहिले वह यह करने का प्रयत्न करता है कि जितनी भी रकम सम्भव हो ऐसी लागत में लग जाय जिससे उसको कुछ आय भी मिले और जो काम पढ़ने पर उसी समय प्राप्त भी हो सके। कुछ देशों में भाग्यवश यह सम्भव भी है क्योंकि वहाँ पर विलों और स्टाक एक्सचेंज के दलाल बराबर ऐसा ऋण लेने की ताक में लगे रहते हैं। विलों के दलालों को तो इसकी आवश्यकता उनके क्रय के सम्बन्ध में और स्टाक एक्सचेंज के दलालों को इसकी आवश्यकता पाल्तिक् भुगतानों के बीच के दिनों में स्टाक लेने के लिये पड़ती है। ये लोग कन्सलों को (Consols), सरकारी बाण्डों को (Exchequer bonds) और लन्दन कारपोरेशन और नागरिक काउन्सिल के बाण्डों को जो आसानी से बिक जाते हैं और जिनको रखकर कोई व्यक्ति भी सुख की नींद सो सकता है, जमानत की तौर पर देते हैं। प्रो० टाजिंग के कथनानुसार बैंकों की दृष्टि से ये उनके व्यवसाय के बहुत ही सुविधापूर्ण अङ्ग हैं। इनसे कभी थोड़ी और कभी बहुत किन्तु हमेशा यथेष्ट आय हो जाती है और साथ ही यदि किसी एक बैंक को आवश्यकता पड़ती है तो ये नकदी में अकेले परिवर्तित भी किये जा सकते हैं। वे जब चाहे इनको संकट के समय अथवा किसी अन्य लाभदायक लागत में लगाने के लिये उपयोग में ला सकते हैं। फिर जनता के लाभ की दृष्टि से भी ये लाभदायक हैं। कुछ आवश्यक कार्यों के लिये हमेशा थोड़ी और निश्चित अवधि के लिये नकदी की आवश्यकता पड़ती रहती है और उसके लिये यही माँग पर वापिस होने वाले ऋण बहुत ही उपयुक्त साधित होते हैं।"

राज के कथन के अनुसार^२ इसमें बैंकर कुछ इसी तरह का असम्भव सा काम करता है कि रोटी बची भी रहती है और खाने के काम में भी आ जाती है। किन्तु ये बुराइयों से विल्कुल खाली नहीं हैं। इनसे सट्टेबाजी को प्रोत्साहन मिलता है। इसके अतिरिक्त ये साधारण समय के लिये तो अच्छे हैं किन्तु संकट काल के लिये व्यर्थ है अर्थात् जम जाते हैं (Become frozen)। ऐसे समय में इनका भुगतान मिलना कठिन हो जाता है और इनमें जो द्रव्य लगा रहता है वह ठीक उसी समय जब उसकी नकदी के रूप में एक बहुत बड़ी आवश्यकता होती है, फँसा रह जाता है। अतः, बहुत से बैंकर इनकी अच्छी सम्पत्ति में गणना नहीं करते। लार्ड गाशान ने इनके विरुद्ध कहा है।^३ तथापि ये लन्दन और न्यूयार्क में बहुत प्रचलित हैं। भारतवर्ष में ये प्रथम युद्ध के पहिले तक तो बम्बई, कलकत्ता, सद्दास और कराची तक में प्रचलित नहीं थे। किन्तु उसके पश्चात् इनका प्रयोग प्रारम्भ हो गया। यहाँ पर इनकी माँग सोने, चाँदी के और स्टाकों के वाजारे में है। यह बिना किसी जमानत के उच्चतम श्रेणी के लोगों को दिया जाता है। ऋण की मन्दी और तेजी पर इनके व्याज की दर निर्धारित रहती है। तेजी की ऋतु में यह बहुत ऊँची दर पर भी नहीं प्राप्त होती और मन्दी की ऋतु में यह $\frac{1}{4}$ प्रतिशत पर मिल जाते हैं। कुछ दिनों से यह द्रव्य सरकारी खजानों के बिलों (Treasury Bills) में लगा दिया जाता है। यह बैंकों के पारस्परिक ऋण (Inter-bank-loans) में भी लगा रहता है।

किन्तु इस प्रकार की लागत तो केवल कुछ रकम के ही लगाने के लिये उपयुक्त है। कार्यशील पूँजी के एक बहुत बड़े भाग को तो अधिक आय पाने के लिये किसी अन्य काम में लगाना पड़ता है। जैसा कि पिछले अध्याय में कहा जा चुका है, बैंक्स की दृष्टि से बिलों पर की लागत सबसे अच्छी है। यह ऋण व्यापारियों के द्वारा लिया

2 In the case of Call Money the banker seems to accomplish the impossible feat of 'Having the cake and eating it too.'

3. It is not an asset which constitutes a reserve—useful in the general interest of community at large.

जाता है। कभी-कभी बिलों के और स्टार्कों के दलाल भी इनसे लाभ उठा लेते हैं। हम जानते हैं कि बिल डिस्काउण्टिंग हाउस और बिल के दलालों से भी भुनाये जाते हैं जो आवश्यकता पड़ने पर उनको फिर बैंकों से भुना लेते हैं। बिलों के दलाल साधारणतया तो उन पर अपनी पूँजी से ही रकम देते हैं, किन्तु कभी-कभी उनको बैंकों की भी शरण लेनी पड़ती है। वे उनसे इस आशा पर ऋण ले लेते हैं कि शीघ्र ही जब उनके कुछ बिल पक जायेंगे तब वह उनको लौटा लेंगे। बिलों के वास्तविक और भूठे (Genuine and Non Genuine) होने के कारण बैंकों को जो कठिनाई पड़ती है उसको हम पहिले ही समझ आये है किन्तु जो ग्राहक अपने बिल भुनाते हैं उनके ऊपर दृष्टि रखने से यह कठिनाई भी दूर हो सकती है। प्रायः, प्रत्येक बैंक के पास कुछ ऐसे ग्राहकों के नाम रहते हैं जिनके बिलों पर वे ऋण देने के लिये तैयार रहते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक ग्राहक के नाम के आगे एक रकम लिखी रहती है जिस तक के ही उसके बिलों पर बैंक ऋण देते हैं, और यदि इस बात पर ध्यान रक्खा जाता है तो कोई डर नहीं रहता। बिलों पर ऋण देने के पहिले यह भी देख लेना चाहिये कि वह सब तरह से पूर्ण है, अर्थात् वह नियमानुसार लिखे, स्वीकृत किये और बेचान किये गये हैं। उनके लिखने वाले, ऊपर वाले और बेचान करने वाले धनियों की व्यापारिक स्थिति का भी पता लगाते रहना चाहिए क्योंकि उनका भुगतान तो इन्हीं के ऊपर निर्भर रहता है। फिर एक ही प्रकार के सौदों के सम्बन्ध के ही बिलों पर सब रकम नहीं लगा देनी चाहिये क्योंकि इससे उस व्यापार के मन्दा पड़ जाने पर रकम के फंसे रह जाने का डर रहता है। अन्तिम बात यह कि किसी बैंक को लगातार पकने वाले बिलों पर ही अपनी रकम लगानी चाहिये जिससे कि वह धीरे-धीरे मिलती भी रहे। इससे उसके ग्राहकों की मांग बराबर पूरी होती रहेगी।

अब हम मुख्य ऋण की ओर जाते हैं। वास्तव में ऋण के अन्तर्गत तो सब ही प्रकार के ऋण आ जाते हैं; यहां तक कि बिलों पर दिया जाने वाला ऋण भी आ जाता है। किन्तु मांग पर वापिस होने वाले और बिलों पर दिये जाने वाले ऋणों को बैंक मुख्य ऋण के समकक्ष नहीं गिनते और वास्तव में यह ठीक भी है, क्योंकि इनपर लगी हुई रकम तो जब चाहे तब वसूल की जा सकती है। अतः, ऋण

तो वही है जो हर समय वापिस न हो सके। ऋण भी तीन प्रकार के हैं। प्रथम तो जमा की हुई रकम से अधिक निकालने की आज्ञा (Over drafts) के रूप में, दूसरे नकद साख (Cash credit) के रूप में और तीसरे मुख्य ऋण (Loans and advances) के रूप में। ये प्रणपत्रों की, अन्य जमानतों की तथा वैयक्तिक जमानत की भी बिना पर दिये जाते हैं। सच तो यह है कि इन्हीं की वाहुल्यता पर बैंकों का लाभ निर्भर रहता है। किन्तु सुरक्षा के विचार से यह बहुत उपयुक्त नहीं है, अतः, इनके सम्बन्ध में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिये :—

(१) प्रत्येक बैंकर को नकदी का यथेष्ट कोष अपने पास रखना चाहिये। यदि यह अधिक हो जाय तो कोई हर्ज नहीं, किन्तु कम नहीं होना चाहिये।

(२) जैसा प्रायः कहा जाता है उसको अपने सारे अण्डे एक ही टोकरी में नहीं रखने चाहिये। इसके यह अर्थ हैं कि उसको अपनी ऋण देने की सारी रकम एक ही व्यक्ति को नहीं दे देनी चाहिये। जहाँ तक हो वह अधिकाधिक विस्तृत क्षेत्र में बँटी रहनी चाहिये अर्थात् न तो एक व्यक्ति ही हो, न एक तरह का व्यापार ही हो, न एक स्थान ही और न एक प्रकार की जमानत ही हो।

(३) उसको जमानतों को भी भली भाँति देख लेना चाहिये। इस विषय पर राज ने जो कुछ कहा है उसको तो हम पिछले अध्याय में देख चुके हैं। जो भी जमानत ली जाय उसको हर दृष्टि से देख लेना चाहिये। किन्तु जैसा कि एक अगले अध्याय में बताया जायगा कोई भी जमानत आदर्श जमानत नहीं है। भूमि और मकान का रेहन तो सबसे निकृष्ट है। उसको न तो आसानी से और शीघ्र से बेचा जा सकता है और न तो उसके मूल्य का कोई ठिकाना है।

(४) उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि उसको व्यापारियों के केवल चाख लेन-देन का ही प्रबन्ध करना है। उसको न तो सब तरह के न विकने वाले धन को द्रव्य के रूप में परिणत करना है और न उससे इसी बात की आशा की जाती है कि वह भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये साख ही उत्पन्न करेगा।

(५) उसको अपने पक्ष में सदा यथेष्ट गुंजाइश (Margin)

रख लेनी चाहिये । जितनी अधिक मूल्य में घट-बढ़ होने की सम्भावना हो उतनी ही अधिक यह गुंजाइश रखनी चाहिये ।

(६) व्यापारिक बैंकों का उद्देश्य केवल थोड़े समय के लिये ही साख उत्पन्न करना है । अतः, यदि वे इस नियम से लेशमात्र भी विचलित हो जाते हैं तो बड़ी आपत्ति आ जाती है । इसमें सन्देह नहीं कि यूरोप के बैंक और विशेषतया जर्मन बैंक उद्योग धंधों में भी रकम फँसा देते हैं, किन्तु उनके यहाँ की जमा और इंगलैण्ड के तथा अन्य ऐसे देशों के यहाँ की जमा में एक बड़ा अंतर है जिनकी वैकिंग इंगलैण्ड की वैकिंग की तरह की है, अतः, इसमें कोई हर्ज नहीं है । प्रत्येक बैंकर को अपने ग्राहक से यह पूछ लेना चाहिये कि उसको कितनी अवधि के लिये ऋण की आवश्यकता है और उसका जो पहिला उत्तर हो उसी को ठीक समझना चाहिये । प्रायः यह देखा गया है कि जब कोई व्यापारी अधिक दिनों के लिये ऋण माँगता है और उसको वह नहीं प्राप्त होता तब वह यह कह कर कि वह वाद में किसी अन्य जगह से ऋण प्राप्त करके बैंक को वापिस कर देगा उसको थोड़े ही समय के लिये ही प्राप्त कर लेता है । ऐसा ऋण कभी भी वापिस नहीं होता । वाल्टर लीफ ने अपनी पुस्तक में ऐसे दो ऋणों के उदाहरण दिये हैं—एक में तो किसी बीमा कम्पनी से रेहन पर ऋण लेने की और दूसरे में नये हिस्सों को बेचकर ऋण लेने की बात थी, किन्तु यह कुछ भी न हो सका । ऐसे ऋण सदा के लिये चालू रह जाया करते हैं ।

(७) ऋणों का वारम्बार का नवीनकरण भी अच्छा नहीं है । ऐसा करने से वे जाम (Freeze) हो जाते हैं । इनको खातों का पोषण करना (Nursing of Accounts) कहा जाता है ।

(८) ऋण के उद्देश्य का भी पता लगा लेना चाहिये । ऐसा कहा जाता है कि उपभोग के लिये ऋण नहीं देने चाहिये । किन्तु सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि ऋण कहाँ से वापिस किया जायगा । कभी-कभी लोग ऐसी सम्भावनायें (Prospects) लेकर आते हैं जो पूरी नहीं हो सकतीं । यदि बैंकर इन पर उधार नहीं देता तो उससे न केवल उसी की वस्तु ग्राहकों की भी वचत हो जाती है ।

(९) जो जमानते दी जायें उनके मूल्य की घट बढ़ पर भी बैंकर को दृष्टि रखनी चाहिये । यदि उसमें हास हो जाय तो उसको अन्य जमानत मंगाकर फौरन पूरा कर लेना चाहिये ।

(१०) कम व्याज की नीति भी बहुत अच्छी नहीं होती । इससे लोग अत्यधिक उधार ले लेते हैं । किन्तु व्यापार तो केवल पूँजी ही से नहीं चलता है उसके लिये अन्य साधनों की आवश्यकता पड़ती है । अतः, उनके न रहने पर जो पूँजी लगाई जाती है वह भी व्यर्थ चली जाती है ।

(११) अन्तिम बात यह है कि ऋण माँगने वाले का चरित्र बहुत अच्छा होना चाहिये । सच तो यह है कि अच्छे चरित्र से बढ़कर कोई दूसरी जमानत नहीं है । जो लोग उधार माँगते हैं उनको विश्वासपात्र होना चाहिये क्योंकि विश्वास ही तो साख की एक मुख्य चीज है । अब इस विश्वास के लिये ईमानदारी, गम्भीरता, तत्परता, न्यायपरता और व्यवस्था को पालन करने की आदत होना बहुत ही जरूरी है ।

जहाँ तक इन ऋणों के रूप का प्रश्न है उनको तो हम पहिले ही देख चुके हैं । यह जमानत पर अथवा विना जमानत के भी दिये जा सकते हैं । जहाँ तक भिन्न-भिन्न प्रकार की जमानत का प्रश्न है उनका हम आगे चल कर विस्तृत अध्ययन करेंगे । अब रह गये विना जमानत के ऋण सो वह वैयक्तिक जमानत पर दिये जाते हैं । इसमें ऋण लेने वाले के चरित्र की छान-बीन बहुत ही महत्व रखती है । उसकी कुल सम्पत्ति और ऋण वापस करने की क्षमता पर भी ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है । प्रत्येक बैंकर के कुछ ऐसे ग्राहक अवश्य होते हैं जो उसके संरक्षक की तरह होते हैं । इनको उसे किसी जमानत के विना भी ऋण देना पड़ता है । उनको जब बहुत ही आवश्यकता पड़ती है तभी वह ऋण माँगते हैं । अतः, बैंकर उनको नाराज नहीं करना चाहते । वास्तव में ऐसे ऋणों को आवश्यक बातों को ध्यान में रख कर देने से बैंकों की कमी हानि नहीं होती ।

बैंक अपनी रकम सरकारी, अर्ध-सरकारी, जनहित के लिये बनी हुई संस्थाओं और उद्योग-धन्धों सम्बन्धी साख-पत्रों में भी लगाते हैं । यदि सच पूछा जाय तो ऐसा करना उनके लिये उपयुक्त नहीं है । उनका काम तो पूँजी को चालू रखना है । उसको फँसा रखना नहीं है । किन्तु वे इस काम में अपनी रकम केवल इसी लिए लगाते हैं कि वह इसमें से आवश्यकता पड़ने पर आसानी से वसूल हो जाती है । इन पर की वार्षिक आय भी अधिक नहीं होती । वह बिलों पर तथा अन्य प्रकार

के ऋणों पर की आय की अपेक्षाकृत बहुत ही कम होती है। हाँ, इन साख-पत्रों की कीमतों के बढ़ जाने पर अवश्य लाभ हो जाता है, किन्तु यह तो सट्टेबाजी है जो बैंकिंग के व्यवसाय के विरुद्ध है। किन्तु ये स्टॉक एक्सचेंज के बाजार में किसी समय भी बेचे जा सकते हैं। अतः वसूली की दृष्टि से तो यह लागत आदर्श लागत है। सरकारी साख-पत्र जिनको स्वर्ण साख-पत्र (Gilt-Edged Securities) भी कहते हैं शायद इस दृष्टि से सबसे अच्छे होते हैं। उनके मूल्य का ह्रास भी प्रायः कम होता है। किन्तु बैंक एक ही प्रकार की लागत में अपनी सारी रकम कभी नहीं लगाते, चाहे वह सरकारी साख-पत्र की हो, चाहे किसी की भी हो। उनकी रकम तो भिन्न-भिन्न प्रकार की लागतों में लगी रहती है।

एक अन्य प्रकार का ऋण भी होता है जिसे बिलों की स्वीकृति (Acceptance business) का ऋण कहते हैं। हम तो पहिले ही देख चुके हैं कि जब विक्रेता क्रेता के ऊपर कोई बिल करता है तब क्रेता को उस पर स्वीकृति देनी पड़ती है। किंतु ऐसा भी हो सकता है कि उसकी साख इतनी व्यापक न हो कि उसके द्वारा स्वीकृति बिल पर हर बैंक ऋण देने के लिये तैयार हो जाय। ऐसी स्थिति में क्रेता का बैंक उस पर के बिल पर अपनी स्वीकृति दे देता है इसमें वह अपने ग्राहक के संकीर्ण साख के स्थान पर अपनी विस्तृत साख दे देता है। इसके लिये वह उससे प्रतिफल (Commission) भी पाता है। इस काम को पहिले पहिले यूरोप के उन बड़े-बड़े व्यापारी महाजनों ने आरम्भ किया था जिन्होंने उन्नीसवीं शताब्दी में नेपोलियन के युद्ध के समय इंगलिस्तान के द्वारा हालैंड के हराये जाने पर एम्सटरडम का जो दौर अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक क्षेत्र में था उसके समाप्त हो जाने पर लन्दन में अपनी शाखाएँ खोल ली थीं। उन्होंने शायद इस बात को समझ लिया था कि भविष्य में ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी ही अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक क्षेत्र में हालैंड की राजधानी का स्थान लेगी। कुछ बड़ी-बड़ी संस्थायें अमेरिका वालों की भी थीं। यद्यपि ये सब चालू खातों में जमा प्राप्त करने के काम को न करने के कारण अपने को बैंक नहीं कहते तथापि ये उन्हीं के सदस्य महत्वपूर्ण हैं। संसार के सभी महत्वपूर्ण देशों के लोगों से इनके सम्बन्ध हैं जिससे ये सभी स्थानों के लोगों के विषय में जानकारी रखते हैं

इससे ये उनके ऊपर किये गये विलों पर स्वीकृत भी दे सकते हैं। इनकी इतनी साख है कि इनके द्वारा स्वीकृति किये गये विलों पर सभी बैंक ऋण देने के लिये तैयार हो जाते हैं। प्रायः यह क्रेता से इस बात का वायदा करा लेते हैं कि वह इनको विलों के पकने की तारीख के तीन दिन पहिले उनकी रकम दे देंगे। आजकल के व्यापारी महाजन विनिमय के बैंकों की मन्त्रणा से भी विलों पर स्वीकृति देते हैं। प्रथम महायुद्ध के समय से अमेरिका वालों ने भी न्यूयार्क को लन्दन का प्रतियोगी बनाने के बहुत से प्रयत्न किये हैं। अतः, ऐसी सस्थाये अब वहाँ भी यथेष्ट मात्रा में खुल गई हैं। इसके अतिरिक्त यह काम अब बैंकों के हाथ में भी आ गया है। बात यह थी कि उक्त युद्ध के छिड़ने पर व्यापारी महाजनों को यूरोप के शत्रु देशों से जो कुछ पाना था वह नहीं मिल सका। अतः, उनके लिये उनके द्वारा स्वीकृत विलों का भुगतान करना कठिन हो गया। किन्तु उनकी साख को बचाना आवश्यक था। अतः, सरकारी आज्ञा से उन विलों का भुगतान बैंक आफ इंग्लैण्ड ने कर दिया। युद्ध के बाद जब यह रकम वसूल हुई तब बैंक आफ इंग्लैण्ड ही को मिली। तब से यह काम बैंक करने लगे। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में इस काम को बैंकिंग का एक व्यवसाय माना जाता है। किन्तु भारत के सम्मिलित पूँजी वाले बैंक इस काम को नहीं करते। हाँ, यहाँ के सर्राफ़ अवश्य उन व्यापारियों की दुष्टियाँ खरीद लेते हैं जिनको वे जानते हैं। अतः, इससे उन पर उनका दायित्व भी हो जाता है और इसी कारणवश उन पर बैंक भी ऋण दे देते हैं।

बैंक कैसे लाभ कमाते हैं

अब हम इस बात की ओर आते हैं कि व्यापारिक बैंक कैसे लाभ कमाते हैं। हम यह तो देख ही चुके हैं कि वे अपनी कार्यशील पूँजी को किन-किन लाभदायक प्रयोगों में लगाते हैं। वास्तव में वही उनकी आय के मुख्य साधन हैं। यहाँ पर हम उन्हें फिर दोहराये देते हैं:—

- (१) माँग पर वापिस होने वाले ऋणों पर का व्याज ।
- (२) विलों पर ऋण देने की कटती (Discount Charges) ।
- (३) ऋणों पर का व्याज ।

(४) साख-पत्रों पर की लागतों पर का ब्याज ।

(५) विलों पर स्वीकृति देने का प्रतिफल (Commission)

इनके अतिरिक्त प्रासङ्गिक मूल्य (Incidental Charges) की और आदत के तथा अन्य कार्यों के करने से जो आय होती है वह भी उनके लाभ में सम्मिलित है। हम जानते हैं कि बैंक अपने ग्राहकों की चेकों, उनके विनिमय के विलों, प्रण-पत्रों, ब्याज के पर्चों (Coupons), बंटनी पत्रों (Dividend warrants), चन्दे, किराये, आयकर और बीमा के प्रीमियम की वसूली और उनका भुगतान भी करते हैं। इनमें से अधिकांश काम तो वे निशुल्क करते हैं, किन्तु कुछ के लिये उनको प्रतिफल भी प्राप्त होता है। जैसे बाहर की चेकों को वसूल करने तथा हिस्सों, स्टकों और ऋण-पत्रों का स्टॉक एक्सचेंजों में और अन्य सामानों का उनके बाजारों में क्रय-विक्रय करने के लिये वे दलालों की दलाली के अतिरिक्त अपना प्रतिफल भी लेते हैं। फिर उनको धरोहरी (Trustees), सर्वराहकार (Administrators) और साधक (Executors) की हैसियत में काम करने पर भी उचित प्रतिफल मिलता है। इसी तरह से बहुमूल्य वस्तुओं जैसे जेवरात और जवाहिरात, लेखपत्र, इत्यादि को अपने पास रखने (Safe Custody) के लिये भी उनको प्रतिफल प्राप्त होता है। यह कार्य सचमुच बहुत ही जोखिमपूर्ण है किन्तु जोखिम लेने के बिना तो कोई काम चल ही नहीं सकता। इससे उन्हें न केवल यथेष्ट लाभ होता है बल्कि यह उनके व्यवसाय का एक मुख्य अङ्ग भी है। साख-पत्रों को रखने पर उनके ऊपर उनके ब्याज इत्यादि को और उनके पकने पर उन्हें स्वयं वसूल करने का उत्तरदायित्व भी रहता है। धन भेजने और विनिमय के व्यवसाय से भी उन्हें विशेष लाभ होता है। भारतवर्ष में प्रायः व्यापारिक बैंकों को धन भेजने से बहुत आय होती है। हाँ, विनिमय का काम वे प्रायः नहीं करते क्योंकि वह विदेशी विनिमय के बैंकों के हाथ में है।

बैंक अपने लाभ का किस प्रकार उपयोग करते हैं

लाभ के सब मद ऊपर दिये गये हैं। किन्तु यह सब लाभ हिस्सेदारों के बीच में विभक्त करने के लिये नहीं रहता। इसमें

से उन सब खर्चों को काट दिया जाता है जिनको करना प्रत्येक बैंकर के लिए आवश्यक रहता है। ये निम्नांकित हैं :—

- (१) स्थायी जमा तथा अन्य खातों पर का व्याज ।
- (२) सञ्चालकों और हिसाब निरीक्षकों का शुल्क, कर्मचारियों के वेतन, पेन्शन और प्राविडेन्ट फण्ड का खर्च ।
- (३) बैंकरों के संघों, इत्यादि के सदस्य शुल्क ।
- (४) दफ्तर सम्बन्धी खर्च जैसे छपाई, डाक खर्च, विज्ञापन खर्च, स्टेशनरी खर्च, किराया और बीमे के प्रीमियम, इत्यादि ।
- (५) प्रतिनिधियों का सफर खर्च और उनके तथा अदतियों के शुल्क ।
- (६) मृत-स्टाक और साख-पत्रों की लागत के ह्रास का प्रबन्ध ।
- (७) अप्राप्य ऋण और बैंक के कर्मचारियों द्वारा किये गये ग़वन ।

(८) आय तथा अन्य कर ।

किसी बैंक का पक्का मुनाफा (Net profit) उसके प्रबन्ध की कुशलता पर ही निर्भर रहता है। बहुधा जमा अधिक व्याज न दे कर बरन् ग्राहकों को सुविधायें देकर तथा उनकी अनेकों प्रकार की सेवायें करके प्राप्त किये जाते हैं। कम वेतन वाले कर्मचारियों को रखने से कोई लाभ नहीं होता। उनसे प्रबन्ध की वह कुशलता नहीं प्राप्त होती, जो होनी चाहिये। हमारे देश में कुछ बैंक थोड़े-थोड़े वेतन पर मैनेजर, इत्यादि रख लेते हैं जिससे ग़वन, इत्यादि बहुत होता है। अधिक वेतन वाले कर्मचारी प्रायः कम वेतन वाले कर्मचारियों की अपेक्षाकृत सस्ते पड़ते हैं। उनको अधिक काम मिल जाता है और वे उसको भली भाँति निवाह भी लेते हैं। वट्टा खाता भी कम हो जाता है और ग़वन भी नहीं होता। पक्के मुनाफे में से उसके हिस्सेदारों के बीच में एक निश्चित दर से बँटनी करने के उपरान्त कुछ सुरक्षित कोष के लिये भी रख लिया जाता है। यह कभी-कभी ऐसे वर्षों में बँटनी की दर बढ़ाने के भी काम आता है जब लाभ कम होता है। किन्तु प्रायः यह दिन प्रतिदिन बढ़ने वाले काम के साथ-साथ दिन प्रतिदिन पूँजी को बढ़ाने के उद्देश्य से भी संचित किया जाता है।

प्रश्न

(१) बैंकों की कार्यशील पूँजी कौन-कौन से साधनों द्वारा प्राप्त होती है ? उनमें से प्रत्येक का एक सक्षिप्त विवरण दीजिये ।

(२) बैंकों के जमा किस तरह के होते हैं ? इस सम्बन्ध में आप सजित जमा से क्या समझते हैं ?

(३) बैंकों की पूँजी कितने प्रकार की होती है ? हिस्सेदारों के सुरक्षित दायित्व से आप क्या समझते हैं ?

(४) 'बैंकों की जमा का सारा काम अधिकारों का पारस्परिक परिवर्तन और उनका द्रव्य के साथ परिवर्तन के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है'—इसका विश्लेषण कीजिये ।

(५) एक बैंकर जमा प्राप्त करके अपने ग्राहकों की और समाज का कौन-कौन सी सेवाएँ करता है ? क्या इससे वह समाज की कोई हानि भी कर सकता है ?

(६) 'किसी बैंक की जमा प्राप्ति का कार्य और नोटों के चलाने के कार्य दोनों एक ही प्रकार के हैं'—इसका विश्लेषण कीजिये ।

(७) कोई बैंक अपनी 'कार्यशील पूँजी' कैसे प्रयोग में लाता है ? इस सम्बन्ध में माँग पर वापिस होने वाले ऋणों से आप क्या समझते हैं ?

(८) किसी बैंकर को अपने ग्राहकों को ऋण देने के समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिये ? इसको स्पष्टतया समझाइये ।

(९) बैंकों के स्वीकृति के कार्यों से आप क्या समझते हैं ? यह कैसे प्रारम्भ हुआ ?

(१०) वे कौन-कौन से तरीके हैं जिनसे बैंकर अपना लाभ कमाते हैं ? क्या वह सभी हिस्सेदारों में विभक्त किया जा सकता है ?

अध्याय ६

केन्द्रीय बैंकिंग (१)

केन्द्रीय बैंकिंग ने एक विशिष्ट व्यवसाय (Specialised Banking) का रूप तो केवल इसी शताब्दी में ही धारण कर लिया है। इसके पूर्व यूरोप में प्रायः सभी देशों में, पूर्व में जापान और जावा में तथा अफ्रीका में मिश्र और अल्जीरिया में नोटों को

चलाने वाले और सरकार के काम करने वाले बैंक तो अवश्य स्थापित हो चुके थे, किन्तु जैसा कि तीसरे अध्याय में बताया जा चुका है उनको केन्द्रीय बैंकों के कार्यों का कोई स्पष्ट ज्ञान नहीं था। हाँ, यह व्यवसाय धीरे-धीरे अवश्य उन्नति प्राप्त कर रहा था। बैंक आफ इंग्लैण्ड से प्रारम्भ होकर अन्य सभी बैंक थोड़े बहुत ऐसे केन्द्रीय बैंकिंग के कार्य अवश्य करने लग गये थे जैसे व्यापारिक बैंकों के नकद कोष के एक बहुत बड़े भाग को अपने पास रखना, उनको विलों पर तथा अन्य जमानतों पर ऋण देना, और आर्थिक तथा साख सम्बन्धी मामलों में अपने को उत्तरदायी और मुखिया समझना इत्यादि, इत्यादि। जहाँ तक उनका जनता से व्यवसाय करने का प्रश्न था वह भी भिन्न-भिन्न बैंकों के साथ भिन्न-भिन्न था। एक तरफ तो बैंक आफ इंग्लैण्ड था जिसने यह व्यवसाय विल्कुल त्याग दिया था और दूसरी तरफ बैंक आफ फ्रान्स था जो अपने यहाँ के छोटे से छोटे व्यापारियों के साथ भी काम किया करता था। इस शताब्दी में कुछ ऐसे नियम और चलन बन गये हैं जिनसे केन्द्रीय बैंकिंग का व्यवसाय शासित हो रहा है और उसका एक विशिष्ट रूप बन गया है। हिल्टन यंग कमीशन के सामने बैंक आफ इंग्लैण्ड के शासक (Governor) ने केन्द्रीय बैंकों के कार्यों का उल्लेख कुछ निम्न आशय के शब्दों में किया था :—‘उनको वैधानिक रीति से ग्राह्य होने वाली करन्सी को बाहर निकालने वाली और अन्दर करने वाली सरिता का काम करना चाहिये। उन्हें सरकार के सम्पूर्ण नकदी को और देश के अन्य बैंकों के और उनकी शाखाओं के सुरक्षित कोष को अपने पास रखना चाहिये। वह अपनी-अपनी सरकारों के देशान्तर्गत और अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देनों को भी उनकी ओर से पूरा करते हैं। उनका यह भी कर्तव्य है कि वे अपने-अपने देश की द्रव्य की इकाई का मूल्य देश में और बाहर स्थिर रखने के उद्देश्य से अपने-अपने यहाँ की करन्सी और साख का परिमाण आवश्यकता के अनुसार घटाते और बढ़ाते रहे। जब आवश्यकता पड़े तब उन्हीं को विलों की तथा अन्य उपयुक्त जमानतों की बिना पर आकस्मिक करन्सी और साख-पत्रों को चालू करने का भी प्रवृत्ति करना चाहिये।

एस० एच० डी० काक ने, जिसको केन्द्रीय बैंकिंग के विषय में

परिमाणस्वरूप माना जाता है केन्द्रीय बैंकों के कर्तव्यों का कुछ विशेष वर्णन किया है जिसको यहाँ पर संक्षेप में दिया जाता है :—

(१) व्यापार तथा साधारण जनता की आवश्यकतानुसार करन्सी को निकालना । इसके लिये उनको नोटों के चलाने का या तो एकाधिकार अथवा आंशिक अधिकार दे दिया जाता है ।

(२) सरकार के साधारण बैंकिंग के और आदृत के कामों को करना ।

(३) व्यापारिक बैंकों के नकद कोप को रखना ।

(४) राष्ट्र के धात्विक कोष को रखना ।

(५) व्यापारिक बैंकों, बिल के दलालों तथा अन्य ऐसे ही अर्थ से सम्बन्ध रखने वाले व्यवसायियों को विनिमय के अथवा सरकारी बिलों के तथा अन्य उपयुक्त साख-पत्रों के ऊपर ऋण देना ।

(६) जब कहीं से ऋण न मिल सके तब ऋण देने के दायित्व को स्वीकार करना ।

(७) बैंकों के पारस्परिक लेन-देनों के लिये निकास-ग्रह (Clearing House) का प्रबन्ध, इत्यादि करना ।

(८) व्यापार की आवश्यकता के अनुसार और विशेषतः राज्य के द्वारा चलाई हुई द्रव्य-प्रणाली को स्थिर रखने के उद्देश्य से साख का नियन्त्रण में रखना ।

उसने केन्द्रीय बैंकों का एक अन्य आवश्यक गुण भी बताया था जो यह है कि वे साधारण व्यापारिक बैंकों के व्यवसाय भी न करें अर्थात् न तो वे प्रत्येक व्यक्ति से जमा ही प्राप्त करें और न साधारण लोगों को किसी प्रकार का ऋण दें । किन्तु यहाँ पर यह कह देना आवश्यक है कि बहुत से केन्द्रीय बैंक, जैसे फ्रान्स का बैंक, आस्ट्रेलिया का बैंक, जावा का बैंक, और मिश्र का राष्ट्रीय बैंक यह काम करते हैं । इधर कुछ दिनों से यह स्पष्ट हो गया है कि कुछ परिस्थितियों को छोड़कर जब राष्ट्र के आर्थिक हित के लिये यह आवश्यक प्रतीत हो, केन्द्रीय बैंकों को इन कामों को नहीं करना चाहिये । अतः, उपर्युक्त बैंक भी या-तो इन्हे धीरे-धीरे कम कर रहे हैं या किसी विशेष कारणवश करते जा रहे हैं । भारतवर्ष में और अर्जेन्टाइना में जहाँ, क्रमशः इम्पीरियल बैंक आफ इण्डिया और अर्जेन्टाइना राष्ट्र का बैंक कुछ केन्द्रीय कामों के साथ-साथ ऐसा करते थे

नये केन्द्रीय बैंक स्थापित किये जा चुके हैं और उन पर ऐसा करने की रोक लगा दी गई है।

अब हम ऊपर दिये हुये सब कामों को एक-एक करके लेंगे और उनका विस्तृत अध्ययन करेंगे :—

(१) कागजी मुद्रा को चलाना—प्रायः सभी जगह यह काम सबसे पहिले केन्द्रीय बैंकों को सौंप दिया गया था। हम इस बात को जानते हैं कि बैंक आफ इंग्लैण्ड इसको अपनी संस्थापना के समय से ही करता आ रहा है। इस विषय के कुछ बड़े-बड़े लेखक इसको केन्द्रीय बैंकों का एक मुख्य काम समझते हैं। सभी केन्द्रीय बैंकों के पास आजकल या तो इसका एकाधिकार अथवा शेषाधिकार है। पिछले अध्याय में यह बताया जा चुका है कि कुछ बड़े-बड़े केन्द्रीय बैंकों को यह अधिकार कब दिये गये थे। जिन केन्द्रीय बैंकों के पास इस समय इसका एकाधिकार है उनके वहाँ के अन्य बैंकों से या तो किसी समय एक दम ही उनके चालू नोटों का भुगतान करने को कह दिया गया था अथवा उनको धीरे-धीरे समाप्त करने का आदेश दे दिया गया था। हाँ, कुछ ऐसे केन्द्रीय बैंक भी हैं जिन्हें अन्य बैंकों के चालू नोटों का दायित्व कुछ शर्तों पर अपने ऊपर ही ले लेना पड़ा था। इंग्लैण्ड में, जैसा कि पहिले ही बताया जा चुका है सन् १८४४ में निजी बैंकों को अपने चालू नोटों को चालू रखने का अधिकार तो दे दिया गया था किन्तु एक ऐसी शर्त लगा दी गई थी कि जिससे उनका यह अधिकार धीरे-धीरे समाप्त होता गया। जर्मनी में नोट चलाने वाले अधिकांश बैंकों ने सन् १९३५ के बहुत पहिले ही उनके इस अधिकार पर जो बन्धन लगा दिये गये थे उनके कारण इसको वहाँ के रीश बैंक को हस्तान्तरित कर दिया था और जो बच रहे थे उन्हें भी इस वर्ष अपने इस अधिकार को उसको हस्तान्तरित करने को विवश किया गया। आजकल कुछ ही ऐसे केन्द्रीय बैंक बचे हैं जिनके पास इसका एकाधिकार नहीं है और उनमें से भी केवल संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, कनाडा और चीन ही के केन्द्रीय बैंक मुख्य हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में राष्ट्रीय बैंकों के नोटों का भुगतान तो सन् १९३५-३६ में कर दिया गया था, किन्तु इस समय भी कुछ सरकारी नोट चालू हैं, यद्यपि उनका परिमाण बहुत ही कम है। कनाडा में भी चार्टर्ड बैंकों के नोटों का परिमाण बहुत

ही कम है, अधिकांश में तो वहाँ के केन्द्रीय बैंक अर्थात् बैंक आफ कनाडा के ही नोट चालू हैं। हाँ, चीन में अवश्य उन तीनों गैर-केन्द्रीय बैंकों के जिनको नोट चलाने का अधिकार प्राप्त है सन् १९३८ के मई के अन्त में १२३.३ करोड़ चीनी डालर के नोट चालू थे और इसके विरुद्ध चीन के केन्द्रीय बैंक के केवल ४७.३ करोड़ चीनी डालर के नोट चालू थे। भारतवर्ष में सन् १९४० की जुलाई से यहाँ की सरकार ने भी रिज़र्व बैंक के नोटों के साथ-साथ जिसके पास उनको चलाने का एकाधिकार प्राप्त है अपने एक-एक रुपये के नोटों को उसी प्रकार चलाना प्रारम्भ कर दिया है जिस प्रकार ब्रिटिश राजकोप ने प्रथम युद्ध के समय एक-एक पाउण्ड और आधे-आधे पाउण्ड के नोट चलाने प्रारम्भ कर दिये थे।

नोटों के चलाने का एकाधिकार कई कारणों से केन्द्रीय बैंकिंग के व्यवसाय का एक मुख्य अंग माना जाता है। पहिली बात तो यह है कि इससे नोट करन्सी में जो आजकल की द्रव्य-प्रणाली में सभी जगह बहुत ही महत्वपूर्ण है सादृश्यता आ जाती है। दूसरे, इससे केन्द्रीय बैंकों का एक ऐसा प्रभाव उत्पन्न हो जाता है जिसकी उनको सङ्कटकाल में बहुत आवश्यकता पड़ती है। तीसरे, इससे उसको व्यापारिक बैंकों की साख उत्पन्न करने की शक्ति का नियन्त्रण करने का भी अवसर प्राप्त हो जाता है। जैसा कि आगे चलकर ज्ञात होगा उनको साख में वृद्धि करने के लिये या तो अपने यहाँ के नकदी के कोप को अथवा केन्द्रीय बैंक में अपनी जमा को बढ़ाना पड़ता है। बात यह है कि उनको अपने द्वारा उत्पन्न की गई साख का एक निश्चित प्रतिशत इन्हीं में रखना पड़ता है। अब, यदि केन्द्रीय बैंक यह समझता है कि साख की वृद्धि देश के हित में नहीं है तो वह ऐसे बैंकों की सहायता नहीं करता। और यदि वह इसका उल्टा समझता है तो ऐसा करता है। अन्तिम बात यह है कि इससे सरकार को नोटों की सुरक्षा के विचार से उनको नियन्त्रित रखने में भी बड़ी सहूलियत मिलती है। इसके विपरीत यदि यह अधिकार कई बैंकों में बँटा रहता है तो इसमें उसको कठिनाई पड़ती है।

जहाँ तक नोटों के नियन्त्रण का प्रश्न है यह कम से कम सात प्रकार से किया जा सकता है। पहिले को अंग्रेजी में फिक्स्ड फाइडुसियरी इश्यू सिस्टम (Fixed Fiduciary Issue System)

कहते हैं। इसमें एक निश्चित रकम के नोट तो सरकारी साख-पत्रों पर निकाले जाते हैं, किन्तु उसके ऊपर जो नोट रहते हैं, उनके लिये शत प्रतिशत धात्विक कोप रक्खा जाता है। इसमें लोच नहीं है जिससे धात्विक कोप के धातु की बाहरी अथवा भीतरी माँग के कारण काफी कम हो जाने पर नोटों के परिमाण को भी घटाना पड़ता है। फिर यदि करन्सी की बहुत माँग हो जाती है तो जब तक उसी मूल्य की धातु न प्राप्त हो जाय तब तक वह बढ़ाई भी नहीं जा सकती। किन्तु इसके विपरीत यह कहा जा सकता है कि यह अच्छी स्थिति में करन्सी के अत्याधिक बढ़ जाने को रोके रहता है। हाँ, सन् १९२८ से अंग्रेजी प्रणाली में इसमें कुछ लोच आ गया है। इस वर्ष वहाँ पर इस बात की आज्ञा दे दी गई थी कि कोप की आज्ञा से आवश्यकता पड़ने पर अधिक से अधिक दो वर्षों के लिये निश्चित रकम से ऊपर के नोट भी सरकारी साख-पत्रों की बिना पर चालू किये जा सकते हैं। हम ये तो जानते ही हैं कि सरकारी साख-पत्रों की बिना पर नोटों को चालू करने की जो रकम है वह वहाँ पर किस तरह से धीरे-धीरे प्रारम्भ के १२ लाख पाउण्ड से बढ़कर सन् १९२१ तक १९,७५०,००० पाउण्ड हो गई थी। किन्तु प्रथम युद्ध के समय राजकोष ने एक-एक पाउण्ड और आधे-आधे पाउण्ड के नोट भी चलाये थे। अतः, सन् १९२८ में उनका दायित्व भी बैंक को ही हस्तान्तरित कर दिया गया और सरकारी साख-पत्रों की बिना पर चालू करने के नोटों का परिमाण भी २६ करोड़ पाउण्ड कर दिया गया। तब से अब तक यह अनेकों बार बदला जा चुका है^१। अंग्रेजी प्रणाली को जापान और नारवे ने भी अपनाया है और इसमें थोड़ा-सा परिवर्तन करके तो इसे कई देशों ने अपना लिया है।

दूसरी प्रणाली वह है जिसमें नोटों के परिमाण को विधानतः निश्चित कर दिया जाता है (Fixed legal maximum of note issue)। यह सन् १८७० से सन् १९२८ तक फ्रान्स में चालू रही। लेमोइन का कहना है “यह बहुत ही कड़ी प्रणाली है और द्रव्य के आधुनिक बाजारों की आवश्यकता को पूरा करने के लिये विल्कुल ही अनुपयुक्त है। इससे मुद्रा-प्रसार के रुके रहने की कोई सम्भावना

^१ सन् १९४७ के अन्त में नोटों का परिमाण १३६.२ करोड़ पाउण्ड था और स्वर्ण कोप का परिमाण २०.४६ लाख पाउण्ड था।

नहीं रहती क्योंकि महासभा (Parliament) जब चाहती है, तब नोटों को चालू करने के परिमाण को विधानतः बढ़ा देती है।

तीसरी प्रणाली वह है जिसमें नोट सरकारी साख-पत्रों की बिना पर चालू किये जाते हैं और साथ ही बैंक की प्राप्त पूँजी और सुरक्षित कोप से अधिक नहीं हो सकते। यह प्रणाली संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में राष्ट्रीय बैंकों के नोटों के सम्बन्ध में चालू थी। इसमें भी लोच नहीं है। जैसा बरगैस ने कहा है इसमें चालू नोटों का परिमाण सदा के लिये निश्चित-सा हो जाता है और न तो वह मन्दी में घट सकता है और न तेजी में बढ़ सकता है।

चौथी प्रणाली वह है जिसमें नोटों का एक निश्चित प्रतिशत उदाहरण के लिये २५, ३०, ३३^१ अथवा ४० प्रतिशत धात्विक कोप में रक्खा जाता है और शेष इस शर्त के साथ कि आवश्यकता पड़ने पर अधिकाधिक व्याज देकर कुछ समय के लिये इस धात्विक कोप का प्रतिशत कम भी किया जा सकता है सरकारी साख-पत्रों और व्यापारिक बिलों में रक्खा जाता है। इसको सन् १८५५ में जर्मनी ने और सन् १९३३ में कुछ संशोधनों के साथ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने तथा प्रथम युद्ध के बाद कुछ अन्य देशों ने अपनाया था। इसमें यह अच्छाई है कि जब एक तरफ तो इसमें लोच है दूसरी तरफ इसमें धात्विक कोप के न मिलने पर अत्याधिक मुद्रा प्रसार नहीं हो सकती।

पाँचवीं प्रणाली वह है जिसमें चौथी प्रणाली ही की तरह नोटों का कुछ प्रतिशत तो धात्विक कोप में रक्खा जाता है किन्तु शेष के लिये कोई बन्धन नहीं रहता। हाँ, बैंक के फेल होने पर उसकी सम्पत्ति पहिले नोटों के भुगतान में और फिर अन्य भुगतानों में लगाई जाती है। इसमें बैंकों के लिये पाँचवीं प्रणाली की अपेक्षाकृत अधिक भवतन्त्रता रहती है। यह प्रणाली हालैण्ड में बहुत समय तक चालू थी, और आज कल दक्षिणी अफ्रीका के संघ में चालू है।

छठी प्रणाली अनुपातिक जमा की प्रणाली (Proportional Deposit Method) है। इसमें नोट चलाने वाले बैंकों को जितने के नोट चालू किये गये हैं उतने का एक विशेष प्रतिशत सरकारी साख-पत्रों के अथवा धातु के रूप में केन्द्रीय बैंक में जमा कर देना पड़ता है। यह प्रणाली संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में सदस्य बैंकों के नोटों के सम्बन्ध में चालू है। वहाँ पर उक्त बैंकों को एक निश्चित प्रति

शत सरकारी साख-पत्रों में लगाना पड़ता है और फिर उनको फेडरल रिजर्व बोर्ड के पास जमा कर देना पड़ता है।

सातवीं प्रणाली चौथी प्रणाली की ही संशोधन-मात्र है। इसमें एक निश्चित प्रतिशत तो धातु के रूप में रखनी पड़ती है, और कुछ किसी दूसरे देश के सरकारी साख-पत्रों में अथवा किसी विदेशी केन्द्रीय बैंक में जमा रखनी पड़ती है। भारतवर्ष में सन् १८६१ से सन् १९२० तक तो प्रथम प्रणाली (Fixed Fiduciary Issue Method) चालू थी और आजकल यह सातवीं प्रणाली एक विशेष रूप में चालू है।

अन्त में यह कह देना भी आवश्यक है कि प्रायः सभी राष्ट्रों ने केन्द्रीय बैंकों को नोट चलाने का जो एकाधिकार दे रखा है उससे उनको जो भारी लाभ होता है उसका बँटवारा करना प्रारम्भ कर दिया है। कहीं-कहीं पर तो इनके नोट चलाने से इन्हे जो लाभ प्राप्त होता है उसका और इनके दूसरे बैंकिंग के कार्यों से जो लाभ प्राप्त होता है उसका अर्थात् दोनों का हिसाब अलग-अलग रखा जाता है और नोट चलाने से जो लाभ प्राप्त होता है वह पूरा राष्ट्र को दे दिया जाता है। अन्य स्थानों में या तो हिस्सेदारों को पहले एक निश्चित प्रतिशत की बँटनी देकर शेष सब राष्ट्र का हो जाता है या सब की सब में बैंक और राष्ट्र का किसी विधान द्वारा निर्धारित तरीके पर बँटवारा होता है। बैंक आफ इंग्लैण्ड के राष्ट्रीयकरण के पहले तो उसके नोट चलाने से उसको जितना लाभ होता था वह सभी सरकार ले लेती थी और भारतवर्ष में रिजर्व बैंक के हिस्सेदारों को केवल ३½ प्रतिशत की बँटनी दी जाने के बाद उसका सारा लाभ राजकोष में चला जाता है।

(२) राज्य के साधारण बैंकिंग के और आदृत के कार्यों को करना और आर्थिक मामलों में सरकार को मन्त्रणा देना—पुराने केन्द्रीय बैंक तो यह काम उस समय भी करते थे जिस समय वह पूर्ण रूप से केन्द्रीय बैंक नहीं बन पाये थे, और नये केन्द्रीय बैंकों के तो उस विधान के प्रारम्भ ही ने जिससे वह संस्थापित हुये हैं, यह दिया हुआ है कि वह यह सब काम करेंगे।

आजकल तो केन्द्रीय बैंक इन कामों को केवल इस लिये ही नहीं कि यह राज्य के लिये सुविधाजनक और अल्पव्ययी है बल्कि इस-

लिये भी करते हैं कि इनका देश के द्रव्य के बाजारों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है और यदि वह इन्हें न करें तो उनका इन पर नियंत्रण भी न रह सके। वास्तव में एक केन्द्रीय बैंक उसकी सरकार के जो लेन-देन होते हैं उसका उसके देश के द्रव्य के बाजारों पर जो प्रभाव पड़ता है उसको तभी दूर कर सकता है जब वह राज्य के लिये बैंकर का, अदलतिये का और मंत्रणा देने का काम करता हो। केन्द्रीय बैंकों का विनिमय सम्बन्धी दायित्व भी रहता है और सरकार के इनके लेन देन इतने अधिक रहते हैं कि जब तक यह सब उनके द्वारा न सम्पादित किये जायँ तब तक वह अपने इस उत्तरदायित्व को नहीं पूरा कर सकते। केन्द्रीय बैंकों के द्रव्य के बाजारों से सीधी तौर पर सम्बन्धित होने के कारण वह सरकार को आर्थिक मामलों में भी सरकार और देश दोनों के हितों के अनुकूल मन्त्रणा दे सकते हैं।

केन्द्रीय बैंक सरकार के बैंकर की हैसियत से अपने यहाँ की भिन्न-भिन्न सरकारों की तरफ से और उनके विभागों की तरफ से पूँजी सम्बन्धी और आय-व्यय सम्बन्धी दोनों ही प्रकार के जमा प्राप्त करते हैं और भुगतान देते हैं। वह राज्य के आय की वसूली और जनता से उनके लिये ऋण की वसूली की सम्भावना पर उन्हें ऋण भी देते हैं। कोई केन्द्रीय बैंक वास्तव में अपनी सरकार को स्थायी (Permanent) ऋण नहीं देता। हाँ, कुछ केन्द्रीय बैंक अवश्य अपनी सरकार को स्थायी ऋण देने के विचार से ही संस्थापित किये गये थे। किन्तु बाद में उनको भी और अधिक ऐसे ऋण देने के लिये मना कर दिया गया। हम जानते हैं कि बैंक आफ इंग्लैण्ड की संस्थापना वहाँ की सरकार को उसकी प्रारम्भ की १२ लाख पाउण्ड की सारी पूँजी देने के लिये दी हुई थी और बाद में भी धीरे-धीरे उसने उसको इतना ऋण दिया कि वह सब मिलाकर सन् १८०० तक १४,६८६,००० पाउण्ड हो गया। किन्तु फिर सन् १८३३ में इसको घटाकर ११,०१५,००० पाउण्ड कर दिया गया जो सन् १९२८ तक रहा। इसके बाद भी इस रकम में कई बार परिवर्तन किये जा चुके हैं। बैंक आफ फ्रान्स ने भी सन् १८५७ से राज्य को स्थायी ऋण देना प्रारम्भ कर दिया था जो सन् १९२६ तक ३८०० करोड़ पाउण्ड हो गया। फिर, सन् १९२८ में यह घटाकर २० करोड़ फ्रैंक कर दिया गया। यह कमी जनता से ऋण लेकर और बैंक के स्वर्ण और विनिमय के कोप का फ्रैंक की नई विनिमय की

दर से जो पहिले की दर की केवल ३ ही रक्खी गई थी मूल्य लगाकर की गई थी। किन्तु कुछ ही समय बाद फिर उसने सरकार को ३०० करोड़ फ्रैंक का स्थाई ऋण दिया। इसके बाद सन् १९३५ से सन् १९३८ तक मे उसने उसको थोड़ी अवधि के कई ऋण दिये जिनका कुल जोड़ ५००० करोड़ फ्रैंक था। किन्तु इस वर्ष बैंक के और सरकार के बीच मे एक प्रतिज्ञापत्र लिखा गया जिससे कि बैंक के स्वर्ण और विनिमय के कोष का फिर से प्रति पाउण्ड १७० फ्रैंक के हिसाब से मूल्य लगाने से जो लाभ हुआ उससे बैंक ने सरकार को जो थोड़ी अवधि के लिये ऋण दे रखा था उसका आशिक भुगतान किया गया और बैंक का सरकार के ऊपर ३२० करोड़ फ्रैंक का स्थायी ऋण माना गया। यह केवल दो उदाहरण मात्र हैं। प्रायः प्रत्येक केन्द्रीय बैंक ने आवश्यकता पड़ने पर अपनी सरकार को अवश्य ही कुछ न कुछ स्थायी ऋण दिये है। नये ऋणों को देने के बाद बार-बार भविष्य मे ऐसा करने पर बन्धेज लगाये गये और फिर उनको तोड़ा गया। इन ऋणों को देने के अतिरिक्त केन्द्रीय बैंक अपनी-अपनी सरकार के साख-पत्र और बिल भी एक बहुत बड़े परिमाण मे खरीदकर अपने पास रखते है। संसार के दो बड़े केन्द्रीय बैंक, बैंक आफ इंग्लैण्ड और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक, प्रथम युद्ध के समय से अब तक बराबर अपनी-अपनी सरकारों की इसी प्रकार सहायता करते आ रहे है।

यहाँ पर यह बता देना भी आवश्यक है कि सरकार को ऋण देकर किसी केन्द्रीय बैंक के अपनी साख बढ़ाने से बैंकों की नकदी के कोष बढ़ जाते है और उनका साख के प्रसार पर वही प्रभाव पड़ता है जो नोटों के प्रसार पर पड़ता है। यह संसार के कई महत्त्वपूर्ण देशों मे सन् १९१४-१८ के बीच मे और उसके बाद मे हुआ था। जब कोई केन्द्रीय बैंक अपनी सरकार को ऋण देता है तब सरकार उसको जनता को या तो माल खरीद कर या उससे काम करा कर दे देती है। फिर यही बैंकों मे जमा के रूप मे प्राप्त हो जाते है जिनसे उनकी साख-पत्रों पर की लागत (Investments) विलों पर की लागत तथा ऋणों के परिमाण बढ़ा लिये जाते है।

भारतवर्ष का रिजर्व बैंक यूनियन सरकार को किसी भी सीमा तक इस शर्त पर ऋण दे सकता है कि वह तीन महीनों के अन्दर-अन्दर वापिस हो जायँ। किन्तु यह उनके साख-पत्र भी अपनी

पूँजी, अपने सुरक्षित कोष और अपने बैंकिंग विभाग के जमा के ६० प्रतिशत के मूल्य तक रख सकता है। हाँ, इनमें से जो साल भर के बाद पकने वाले हैं और जो दस साल के बाद पकने वाले हैं उनका परिमाण उसकी पूँजी और उसके सुरक्षित कोष के अलावा बैंकिंग विभाग के जमा के क्रमशः ४० प्रतिशत और २० प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता। थोड़ी अवधि वाले साख-पत्रों का परिमाण इसीलिये अधिक रक्खा गया है कि जिससे उनके मूल्य के ह्रास से उसको क्षति न उठानी पड़े और साथ ही वह जब चाहे तब उन्हें वसूल भी कर ले।

सरकार के अद्वितिये और मंत्री की हैसियत से भी केन्द्रीय बैंकों को बहुत से काम करने पड़ते हैं। वह सरकारी ऋणों का प्रबन्ध करते हैं; उनके सम्बन्ध के स्टाकों और प्रमाण-पत्रों के हस्तान्तरित होने पर जिस रजिस्टर में उनके लेखे होते हैं उनको रखते हैं; सरकारी ऋणों को निकालते हैं, उनको दूसरे ऋणों में बदलते हैं अथवा उनका भुगतान करते हैं; सरकारी बिल निकालते हैं और उनके भुगतान करते हैं, विनिमय की निकासी (Clearing) का तथा अन्य बहुत से कार्य करते हैं।

(३) व्यापारिक बैंकों के नकदी के कोष को रखना—व्यापारिक बैंकों ने अपने-अपने केन्द्रीय बैंकों में धीरे-धीरे अपने नकदी के कोष रखने प्रारम्भ कर दिये। वास्तव में यह तभी विशेष तौर पर होने लगा जब उन्होंने यह समझ लिया कि उनकी नोट चलाने की शक्ति के कारण और विशेषतः उनके देश के अन्दर बहुत ही विश्वासपात्र तथा विस्तृत क्षेत्र में चालू होने के कारण उनके यहाँ अपने खातों को रखने से उनको बहुत लाभ होगा। सच तो यह है कि केन्द्रीय बैंकों में जमा की हुई रकम उनके स्वयं के पास की रकम के ही सदृश्य है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय बैंकों से घनिष्ठ सम्बन्ध उत्पन्न हो जाने में वह अपना एक बहुत बड़ा सम्मान भी समझने लगे। इंग्लैण्ड के अठारहवीं शताब्दी के निजी बैंकों ने भी इन सब बातों को भली भाँति समझ लिया था और इसी से वह बैंक आफ इंग्लैण्ड में अपने हिस्से रखने लग गये थे। सन् १८२६ के बाद जब सम्मिलित पूँजी वाले बैंकों की संस्थापना हुई तब उन्होंने भी पूर्वोक्त चलन चालू रक्खा। दूसरे देशों में भी यही हुआ। किन्तु संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के

फेडरल रिजर्व बैंक की संस्थापना के साथ ही इस सम्बन्ध के एक नये सिद्धान्त का प्रारम्भ हुआ जो यह है कि प्रत्येक बैंक अपने यहाँ के केन्द्रीय बैंक के पास अपनी जमा का विधान द्वारा निश्चित प्रतिशत अवश्य रखें। उसके बाद जितने केन्द्रीय बैंक संस्थापित हुये हैं उनमें से प्रत्येक के विधान में यह बात दी हुई है। हमारे देश में भी जैसा एक पिछले अध्याय में बताया जा चुका है सब सदस्य बैंकों (Scheduled Banks) को उनकी माँग पर वापिस होने वाली और एक निश्चित अवधि के बीच जाने पर वापिस होने वाली दोनों प्रकार की जमा के क्रमशः ५ प्रतिशत और २ प्रतिशत का नकद कोप रिजर्व बैंक में रखना पड़ता है।

जहाँ तक किसी देश की द्रव्य सम्बन्धी और बैंकिंग सम्बन्धी स्थिति का प्रश्न है वह नकद कोप के इस प्रकार केन्द्रित होने से चाहे वह विधान द्वारा हो चाहे चलन के अनुसार हो बहुत ही अर्थपूर्ण हो जाती है। उसके तेजी और आवश्यकता के समय पर पूर्ण रूप से कार्यान्वित हो सकने के कारण उसकी विना पर साख की लोच बहुत अधिक बढ़ जाती है। यदि हम संसार के मुख्य-मुख्य देशों के बैंकों के द्वारा जो नकदी के कोप उनके यहाँ केन्द्रीय बैंकों की संस्थापना के पहिले रखे जाते थे और जो उसके बाद रखे जाते हैं उनकी तुलना करें तो हमको यह अवश्य ही ज्ञात हो जायगा कि इससे उनकी भी कमी हो जाती है। भारतवर्ष ऐसे कृषि-प्रधान देश में कृषि की ऋतु में जो अत्याधिक साख की आवश्यकता पड़ती है उसको पूरा करने के लिये बैंकों के नकदी के कोप को केन्द्रित रखना बहुत ही आवश्यक है, किन्तु यहाँ के रिजर्व बैंक की बैंक दर के बराबर एक समान रहने पर भी हम यह नहीं कह सकते कि उक्त बैंक की संस्थापना के बाद से नकदी के कोप के उसके पास केन्द्रित रहने पर भी यहाँ की अत्याधिक साख की माँग बराबर पूरी हो जाती है। किन्तु जो कुछ कठिनाई है वह जैसा कि हम आगे चलकर देखेंगे केवल इसी कारण है कि यहाँ के द्रव्य के आधुनिक बाजार और देशी बाजार के बीच में कोई घनिष्ठ सम्बन्ध नहीं है।

(४) राष्ट्र के धात्विक कोप को रखना—प्रत्येक केन्द्रीय बैंक को प्रायः विधान के अनुसार ही अपने पास यथेष्ट धात्विक कोप रखना पड़ता है। पहिले तो यह धात्विक कोप केवल नोटों के लिये ही रखना

पड़ता था किन्तु धीरे-धीरे इस बात की भी आवश्यकता प्रतीत होने लगी कि यह जमा के लिये भी होना चाहिये। सच तो यह है कि प्रायः सभी आगे बढ़े हुये देशों में आज कल जमा की बिना पर निकाले गये चेकों का प्रयोग नोटों के प्रयोग की अपेक्षाकृत कहीं अधिक बढ़ गया है। अतः, ऐसा होना आवश्यक हो गया है। किन्तु इंग्लैण्ड में और उसके साथ ही अन्य बहुत से देशों में आज भी जमा के सम्बन्ध में किसी धात्विक कोष को रखने के लिये कोई विधान नहीं है। हाँ, यह देश वैसे ही इतना अधिक धात्विक कोष रखते हैं^२ जितना कि केवल उनके नोटों के कारण नहीं होना चाहिये। फिर, यह कोष कितना होना चाहिये यह बात सदा के लिये नहीं निश्चित की जा सकती। अन्त में इसको उस विशेष केन्द्रीय बैंक के निश्चय पर ही छोड़ देना पड़ेगा। वास्तव में जो चीज अनिश्चित है वह यह है कि किसी देश की विनिमय की दर और उसकी द्रव्य-प्रणाली को स्थिर और चालू रखने के लिये कितने धात्विक कोष की आवश्यकता पड़ेगी। एक ही देश में भिन्न-भिन्न समय में और भिन्न-भिन्न देशों के बीच में यह बराबर परिवर्तित होती रहती है। जितने देश हैं उनकी सबकी आर्थिक स्थिति और प्रणाली में पारस्परिक विभिन्नता के साथ-साथ उनकी जनता की प्रकृति में भी विभिन्नता है, और वास्तव में इन्हीं सब बातों पर उनके धात्विक कोष की मात्रा की आवश्यकता निर्भर रहती है। इसमें सन्देह नहीं कि केन्द्रीय बैंकों के प्रबन्धकर्ता स्वयं ही इस बात को अपने अनुभव से सीख लेते हैं और इसी कारण इसके लिये उनको पूर्ण स्वतंत्रता दी जा सकती है। हाँ, जब कोई नया केन्द्रीय बैंक खुलता है तब अवश्य उसके प्रबन्धकर्ताओं के अनुभव-हीन होने के कारण इस बात की आवश्यकता प्रतीत होती है कि यह मात्रा निश्चित कर दी जाय।

कुछ देश अवश्य ऐसे हैं जिनकी विशेष परिस्थितियों के कारण उनको जो प्रायः आकस्मिक माँग को पूरा करना पड़ता है उसके कारण अवश्य उन्हें इसकी एक बहुत बड़ी मात्रा रखनी पड़ती है। ये निम्न प्रकार के हो सकते हैं—(१) जिनके यहाँ से कुछ थोड़ी-सी ही वस्तुओं

^२यह बात इधर कुछ दिनों से सही नहीं है।

का अत्यधिक निर्यात होता है जैसे अर्जेंटाइना, ब्रेजिल, चिली, कनाडा और न्यूजीलैण्ड। इनके मूल्यों के गिर जाने से इनकी व्यापारिक विषमता (Balance of Trade) इनके विपरीत हो जाती है जिससे इनके यहाँ के केन्द्रीय बैंकों को अत्यधिक धात्विक कोष निकालना पड़ता है। (२) वे जिनके यहाँ विदेशियों के थोड़ी अवधि के अन्दर वापिस माँगे जाने वाले कोष जमा रहते हैं जैसे ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। इनको कभी भी माँगा जा सकता है। (३) वे जिनके यहाँ की राजनीतिक परिस्थिति के गड़बड़ होने के कारण उनकी करन्सी के विनिमय मूल्य में बराबर परिवर्तन होता रहता है, जैसे फ्रान्स।

सन् १९३२ के पहिले बैंक आफ इंग्लैण्ड के पास बहुत कम स्वर्ण-कोष था। किन्तु इसके बाद उसने इसको नोटों के सम्बन्ध में और विनिमय समता कोष (Exchange Equalisation Fund) के सम्बन्ध में बहुत बढ़ा लिया था। हाँ, द्वितीय महायुद्ध के कारण इस समय फिर यह बहुत कम हो गया है, किन्तु धीरे-धीरे अवश्य बढ़ जायगा। इसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की फेड्रल रिजर्व प्रणाली में भी इसकी बाहुल्यता है। अब, केन्द्रीय बैंकों के अन्य कार्यों को लेने के पहिले यह भी कह देना आवश्यक है कि प्रायः इनके नाम में रिजर्व (Reserve) शब्द के आने के कारण जैसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के फेड्रल रिजर्व बैंक, दक्षिणी अफ्रीका का रिजर्व बैंक, पीरू का केन्द्रीय रिजर्व बैंक, न्यूजीलैण्ड और भारत के रिजर्व बैंक, इत्यादि बहुत से लोग इनके रिजर्व अर्थात् कोष रखने वाले कामों का बहुत महत्व समझते हैं।

(५) व्यापारिक बैंकों, विलों के दलालों और व्यापारियों तथा इसी प्रकार की अन्य द्रव्य से सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा लाये हुये विनिमय के बिलों, सरकारी विलों और दूसरे उपयुक्त साख-पत्रों पर इन सबको ऋण देना और (६) जब कही ऋण न मिल सके तब उसको देने के दायित्व को स्वीकार करना—व्यापारिक बैंकों, विलों के दलालों और व्यापारियों तथा इसी प्रकार की अन्य द्रव्य से सम्बन्धित संस्थाएँ प्रायः अपने केन्द्रीय बैंकों के पास ऋण के लिये तब तक नहीं जातीं जब तक उनके स्वयं के और बाहर के वह सब साधन नहीं समाप्त हो जाते जिन तक उनकी आसानी

से पहुँच हो सकती है। अतः, केन्द्रीय बैंक, जब अन्य कहीं ऋण न मिल सके तब उसको देने वाले समझे जाते हैं और क्योंकि वह यह काम प्रायः विनिमय के बिलों, सरकारी बिलों और दूसरे उपयुक्त साख-पत्रों की बिना पर करते हैं, अतः, (५) और (६) कामों को हम एक साथ ही लेते हैं। किन्तु यहाँ पर यह कह देना भी आवश्यक है कि यद्यपि बैंक आफ इंग्लैण्ड ने विनिमय के बिलों, सरकारी बिलों और दूसरे साख-पत्रों पर बहुत दिनों पहिले से ही ऋण देना प्रारम्भ कर दिया था तो भी वह जब कहीं ऋण न मिल सके तब उसको देने के दायित्व को स्वीकार करने के लिये काफी समय तक तैयार नहीं था। सन् १८२५ तक तो यह उन बिलों के अतिरिक्त अन्य बिलों को लेने के लिये तैयार ही नहीं होता था जिनको वह बराबर लेता चला आ रहा था। हाँ, उस वर्ष के अन्त में जब बैंकों और दूसरी द्रव्य-सम्बन्धी संस्थाओं के पास वह बिल नहीं रह गये जिनको वह लेने के लिये तैयार था तब उसने अवश्य इस सम्बन्ध के कुछ बन्धेज अनिच्छापूर्वक हटा दिये। इसके बाद अन्य आर्थिक संकटों के अवसरों पर भी उसने बड़ी अनिच्छा दिखलाई किन्तु सन् १८७३ के पहिले-पहिले तक जब वेजहौट की लौम्बर्ड स्ट्रीट नामक पुस्तक प्रकाशित हुई थी उसने इस दायित्व को पूर्णतया स्वीकार करना प्रारम्भ कर दिया था। अन्य केन्द्रीय बैंकों ने भी यह धीरे-धीरे ही किया। हाँ, सन् १९१३ में जब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक स्थापित हुये उस समय तक यह काम केन्द्रीय बैंकों का एक मुख्य काम समझा जाने लगा था। वास्तव में इसके महत्त्व को सब जगह समझे जाने के कारण ही हौटरे के सहित बैंकिंग के सभी बड़े-बड़े लेखकों ने केन्द्रीय बैंकों के कार्यों में से इसको बहुत ही महत्त्वपूर्ण माना है। बिलों पर ऋण देने (Rediscounting) के अर्थ साधारणतया तो विनिमय के बहुत ही अच्छे बिलों पर ऋण देने के ही हैं किन्तु इधर इसमें सरकारी बिल और अन्य साख-पत्र भी सम्मिलित हो गये हैं। वास्तव में इस व्यापकता का एक-मात्र कारण यही है कि केन्द्रीय बैंकों ने कहीं भी ऋण न मिलने पर ऋण देने के अपने दायित्व को स्वीकार कर लिया है और उसके लिये बहुत अच्छे विनिमय के बिल सदा नहीं मिलते। बैंक, इत्यादि विनिमय के बिलों के अतिरिक्त सरकारी बिलों और अन्य साख-पत्रों पर भी ऋण देते

हैं। सच तो यह है कि प्रथम युद्ध के समय से सरकारी बिलों और अन्य साख-पत्रों का परिमाण विनिमय के बिलों की अपेक्षाकृत कहीं अधिक बढ़ गया है। “बिलों पर ऋण देने का काम नोटों को चालू करने के और नकद कोप को रखने के कामों से बहुत ही सम्बन्धित है क्योंकि यह दोनों जब केन्द्रित हो जाते हैं तब केन्द्रीय बैंकों की ऋण देने की शक्ति भी अत्यधिक बढ़ जाती है। नोट चलाने के अधिकार के कारण कोई भी केन्द्रीय बैंक उससे जो हाथो-हाथ चलाने वाली करन्सी की माँग होती है उसको और नकद कोप के केन्द्रित होने के कारण उसके पास जो बिलों, इत्यादि पर ऋण देने की प्रार्थना की जाती है उसको पूरी करने में पूर्णतया समर्थ रहता है।”

किन्तु व्यापारिक बैंकों को इस सुविधा का दुरुपयोग नहीं करना चाहिये। साधारणतया तो उन्हें स्वयं के साधनों पर ही निर्भर रहना चाहिये। ‘जब कि प्रत्येक केन्द्रीय बैंक को बैंकों के संकट के समय उनकी सहायता करने के लिये तैयार रहना चाहिये और जब उन्हें कहीं से भी ऋण न मिल सके तब उन्हें ऋण देना चाहिये, इसके यह हर्गिज भी अर्थ नहीं है कि बैंकों को हर परिस्थिति में अपने केन्द्रीय बैंक से अपरिमित ऋण लेने का अटल अधिकार प्राप्त है।’ भारतवर्ष में अभी हाल तक बैंकों को इस सम्बन्ध का एक बहुत बड़ा भ्रमोत्पादक विश्वास था और यहाँ के रिजर्व बैंक को उस समय बहुत बुरा-भला कहा गया था जब उसने त्राव-ङ्कुर नेशनल क्लिन बैंक को सन् १९३८ के मध्य में जिस समय वह बड़ी कठिनाई में पड़ा हुआ था और अन्त में उसका काम बन्द हो गया था, उसको मदद नहीं दी। अन्त में बैंक के ७वीं दिसम्बर सन् १९३८ के ‘सदस्य बैंकों के बिलों पर तथा अन्य प्रकार से ऋण देने के सम्बन्ध के पत्र’ के द्वारा जो निम्न आशय का था, यह बात स्पष्ट की गई :—

“संसार के दूसरे देशों में केन्द्रीय बैंकों का जो चलन है उसके अनुसार तथा इस देश में बैंकिंग को एक उचित मार्ग पर चलाने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक अपने सदस्य बैंकों को साख देने के समय केवल उनके द्वारा लाई गई जमानतों पर ही नहीं वरन् उनके लागत की किस्मों पर और उनका व्यवसाय करने का जो ढंग है उदाहरण के लिये वह जमा आकर्षित करने के लिये व्याज की ऊँची दर तो नहीं

देते हैं, अथवा साधारण अवसरों पर जब द्रव्य के बाजारों में काफी द्रव्य रहता है तब तो वह रिजर्व बैंक से सहायता नहीं लेते हैं, अथवा वह अत्यधिक व्यापार तो नहीं करते हैं और वस्तुओं पर अथवा साख-पत्रों पर सट्टेबाजी के लिये अत्याधिक साख तो नहीं देते हैं अथवा विला जमानत प्राप्त किये तो बहुत अधिक व्यवसाय नहीं करते हैं इस पर भी विचार करेगा। इस सम्बन्ध में यह भी ध्यान रखना चाहिये कि रिजर्व बैंक विधान के अनुसार केवल अस्थायी ऋण ही दे सकता है। इस बात का निश्चय करने के लिये कि वह जो साख दे रहा है उसका किसी प्रकार का दुरुपयोग तो नहीं होगा रिजर्व बैंक उधार, लेने वाले बैंकों से कोई भी ऐसी सूचना माँग सकता है अथवा उन पर कोई भी ऐसे बन्धेज लगा सकता है जो उसकी दृष्टि में वांछनीय हैं और सहायता की प्रार्थना करने वाले किसी भी सदस्य बैंक को उपर्युक्त सूचना देनी पड़ेगी तथा बन्धेजों को मानना पड़ेगा।

किसी अन्य बैंक की तरह रिजर्व बैंक को भी कोई कारण बताये बिना भी किसी बैंक को उसके कागजों पर ऋण देने की मनाही कर देने का पूर्ण अधिकार है। किन्तु जो सदस्य बैंक उचित ढंग पर व्यवसाय करते हैं वे रिजर्व बैंक से संकट के समय अथवा आवश्यकता पड़ने पर उचित जमानत देने पर अवश्य ही सहायता पाने की आशा रख सकते हैं।

इससे यह स्पष्ट है कि कोई केन्द्रीय बैंक जब कहीं ऋण न मिले तब ऋण देने के अपने दायित्व को स्वीकार करते हुये भी अपने यहाँ के बैंकों के काम करने के स्तर को ऊँचा कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में भी इस सम्बन्ध की स्थिति अक्टूबर सन् १९३७ के एक फेडरल रिजर्व पत्र से स्पष्ट की गई थी।

(७) बैंकों के पारस्परिक लेन-देनों को निकास-गृह (Clearing house) के द्वारा निपटाना—इस काम को केन्द्रीय बैंक या तो स्वयं ही या विधान के कहने पर करने लग गये हैं। इसमें भी बैंक आफ इंगलैण्ड का ही रास्ता दिखाया हुआ है। स्प्रैंग के कथन के अनुसार इसका प्रारम्भ सन् १८५४ में हुआ था। वास्तव में बैंकों के नकद कोष को अपने पास रखने के उपरान्त बैंक आफ इंगलैण्ड के लिये इस काम को करना आवश्यक हो गया था। दूसरे केन्द्रीय बैंकों ने भी शीघ्र ही इसको प्रारम्भ कर दिया। बैंकों का यह अनुभव

है कि दूसरे बैंकों के पास उनके ऊपर के जो चेक, इत्यादि होते हैं उनकी रकम लगभग उन चेकों, इत्यादि की रकम के बराबर ही होती है जो उनके पास दूसरे बैंकों के ऊपर की होती हैं। हो सकता है कि दिन-प्रतिदिन के हिसाब में यथेष्ट अन्तर हो, किन्तु अन्त में यह बिल्कुल भी नहीं रह जाता। अतः, दिन-प्रतिदिन के हिसाब का निपटारा उनके जो खाते केन्द्रीय बैंक में होते हैं उन्हीं में जमा नाम करके कर दिया जाता है। अब, यदि इससे किसी विशेष बैंक के खाते में उतनी बाकी नहीं रह जाती जितनी विधानतः और चलन के अनुसार रहनी चाहिये तब वह बैंक अपने बिलों, इत्यादि पर केन्द्रीय बैंक से ऋण लेकर उसको पूरा कर देता है। यह क्रम बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ है। प्रथम तो इससे भिन्न-भिन्न बैंकों के पारस्परिक लेन-देन एक बहुत ही सीधे-सादे ढङ्ग से निपट जाते हैं, अर्थात् केवल उनके खातों में ही लेखे करने पड़ते हैं। दूसरे, इससे इस काम में द्रव्य के प्रयोग की बचत होती है। अन्तिम बात यह है कि इससे संकट की स्थिति में भी नकदी के न निकाले जाने की सम्भावना के कारण देश की बैंकिंग-प्रणाली बहुत ही सुदृढ़ बन जाती है।

कुछ देशों में जहाँ व्यापारिक बैंकों ने केन्द्रीय बैंकों की संस्थापना के पहिले ही अपने पारस्परिक लेन-देनों के निपटारे के लिये स्वयं ही निकास-गृहों में प्रवन्ध कर लिये थे अथवा जहाँ केन्द्रीय बैंकों ने प्रारम्भ में इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया था, जहाँ पर अब भी स्वतंत्र निकास-गृह हैं और उनके स्वयं के विधान तथा काम करने के स्थान हैं। किन्तु वहाँ भी केन्द्रीय बैंक एक तो उनके सदस्य हैं ही, साथ ही प्रत्येक निपटारे के बाद उनकी बाकी के निपटारे का भी प्रवन्ध करते हैं। अन्य स्थानों में वह प्रायः निकास-गृह के लिये स्थान देते हैं, उनके काम करने की विधि सम्बन्धी नियम बनाते हैं, उनका निरीक्षण करते हैं और अन्त में उनकी बाकी के निपटारे का प्रवन्ध भी करते हैं।

इंग्लैण्ड में लन्दन में बैंक आफ इंग्लैण्ड का स्वयं का आफिस है, और साथ ही उन ग्यारह प्रान्तीय शहरों में से जिन में निकास गृहों का प्रवन्ध है सात में भी उसकी शाखाएँ हैं। तथापि इन सभी स्थानों के निकास-गृह स्वतन्त्र हैं। हाँ, इनकी बाकी का निपटारा

अवश्य सभी जगह बैंक आफ इंगलैण्ड के द्वारा ही किया जाता है। लन्दन में जहाँ उसका आफिस है और सातों प्रान्तीय शहरों में जहाँ उसकी शाखायें हैं, यह निपटारा उक्त आफिस और उसकी शाखाओं के ऊपर जैसा हो चेकें काट करके किया जाता है। किन्तु उन चार शहरों में जहाँ उसका कोई आफिस अथवा उसकी कोई शाखा नहीं है यह उन बैंकों के लन्दन स्थित प्रधान आफिसों के बीच में उनके जो खाते बैंक आफ इंगलैण्ड के लन्दन के आफिस में है, उन्हीं पर चेक काट करके उसी तरह से होता है, जिस तरह से यह लन्दन के निकास-गृह की बाकी के सम्बन्ध में होता है।

भारतवर्ष में रिजर्व बैंक की संस्थापना के पहिले भी यहाँ के मुख्य-मुख्य स्थानों में स्वतन्त्र निकास-गृह थे और उनमें कार्य संचालन का अधिकार स्वाभाविक रूप से ही इम्पीरियल बैंक को था जो इस सम्बन्ध के सारे काम सब सदस्यों की ओर से करता था। यद्यपि रिजर्व बैंक विधान की ५८ (क) धारा के अनुसार उसको निकास-गृहों के सम्बन्ध के नियम बनाने के अधिकार हैं, तो भी उसने अभी तक इस विषय में कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझा है और पूर्वोक्त निकास-गृह पहिले की ही तरह स्वतन्त्ररूप से अपना कार्य करते आ रहे हैं। हाँ, उनमें से कुछ के कार्य-संचालन का अधिकार अवश्य इसने ले लिया है! किन्तु कलकत्ता और कानपुर जैसे दो स्थान आज भी ऐसे हैं जहाँ क्रमशः इसके आफिस और इसकी शाखा के होने पर भी इसने इस सम्बन्ध के कार्य-संचालन का कार्य दूसरों के ऊपर ही छोड़ रक्खा है। कलकत्ते में तो यह काम क्लियरिंग बैंक्स एसोसियेशन की साधारण कमेटी के द्वारा नियुक्त एक निरीक्षक के हाथ में है और कानपुर में यही इम्पीरियल बैंक के हाथ में है। किन्तु इन सभी स्थानों में सब बैंक अपनी बाक़ी का निपटारा उनके रिजर्व बैंक में जो खाते हैं उन्हीं के ऊपर चेक काट कर करते हैं। कुछ ऐसे भी स्थान हैं जहाँ न तो रिजर्व बैंक के आफिस हैं और न उसकी शाखायें हैं। अतः, वहाँ इम्पीरियल बैंक न केवल निकास-गृह सम्बन्धी कार्यों का संचालन ही करता है वरन् उसकी बाकी का भी निपटारा करता है।

(८) व्यापार की आवश्यकता के अनुसार और सरकार के द्वारा निर्धारित द्रव्य-प्रणाली को स्थिर रखने के उद्देश्य से साख का

नियन्त्रण करना—वास्तव में केन्द्रीय बैंकों का यह कार्य अन्य सब कार्यों की तुलना में सबसे महत्वपूर्ण है। इस सम्बन्ध में शा ने कहा है “किसी केन्द्रीय बैंक का एक मात्र वास्तविक और सबसे महत्वपूर्ण काम साख का नियन्त्रण करना है।” इसका एक मात्र कारण यही है कि आधुनिक काल में सब प्रकार के द्रव्य-सम्बन्धी और व्यापार-सम्बन्धी लेन-देनों के निपटारे में साख का ही भाग सबसे प्रधान हो गया है। ऐसा कहा जाता है कि ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जैसे देशों में ९० प्रतिशत मुग्तान मुद्राओं और नोटों के द्वारा न किये जाकर चेकों के द्वारा ही किये जाते हैं। ऐसा होने के कारण साख अच्छे और बुरे दोनों के लिये कार्य रूप में लाई जा सकती है, अतः, देश के हित के लिये इसका नियन्त्रण बहुत ही आवश्यक हो गया है। इसके अतिरिक्त साख को चालू करने और उसको वापिस करने के काम के वास्तविक रूप में बैंकिंग के व्यवसाय के अन्तर्गत आने के कारण उसका नियन्त्रण भी राज्य के किसी विभाग के द्वारा किये जाने की अपेक्षाकृत किसी बैंक के द्वारा ही किया जाना चाहिये और यह बहुत से बैंकों की अपेक्षाकृत एक ही बैंक के द्वारा बहुत ही सफलतापूर्वक किया जा सकता है। जहाँ तक इस नियन्त्रण के उद्देश्य का प्रश्न है इस विषय में बहुत मतभेद है। इसका चालू और जो कुछ ही दिनों के पहिले तक मुख्य उद्देश्य था वह विनिमय की दरों को स्थिर रखने का था। हमारे देश में तो यह उद्देश्य बराबर ब्रिटिश राज्य के अन्त तक रहा। किन्तु विनिमय की दर की स्थिरता के यह आवश्यक अर्थ नहीं है कि चीजों के मूल्य भी स्थिर रहेंगे। प्रायः उनमें बहुत घट-बढ़ होती रहती है। यदि हम इस बात को भली भाँति सोचें तो हमको यह विदित हो जायगा कि विनिमय के दर की स्थिरता की अपेक्षाकृत चीजों के मूल्य की स्थिरता कहीं अधिक वांछनीय है। यह तो सभी जानते हैं कि मूल्य के परिवर्तन से बहुत से परिवर्तन हो जाते हैं और आधुनिक आर्थिक संगठन विल्कुल गड़बड़ हो जाता है तथा उससे जो बेतरतीबी फैल जाती है उसके आर्थिक और सामाजिक फल बहुत बुरे होते हैं। फिर विनिमय की स्थिरता को अत्यधिक महत्व देने वाले देश प्रायः किसी एक बड़े देश के अथवा कई मुख्य देशों के आश्रित हो जाते हैं। कहना न होगा कि जब से भारतवर्ष ने स्टर्लिंग विनिमय मान को अपनाया है तब से इस देश में भी यही

हो रहा है। इसकी द्रव्य-सम्बन्धी नीति बराबर इंग्लैण्ड की द्रव्य-सम्बन्धी नीति पर ही आश्रित रही है। कहना न होगा कि इन देशों की आर्थिक स्थिति के एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होने के कारण भारतवर्ष के लिये यह बहुत ही हानिकारक सिद्ध हुआ है। विनिमय की अथवा मूल्य की स्थिरता के उद्देश्य को छोड़ कर साख के नियन्त्रण का एक उद्देश्य व्यापारिक चक्र (Business cycles) से रक्षा करना अथवा उसको बिल्कुल दूर करना भी है। अब धीरे-धीरे लोगों का यह विश्वास होता जा रहा है कि साख के नियन्त्रण का सबसे मुख्य उद्देश्य व्यापारिक कार्यों की साधारण एवं बराबर उन्नति करना और अत्यधिक तेजी तथा मन्दी को रोकना ही है।

जहाँ तक साख के नियन्त्रण के तरीकों का प्रश्न है भिन्न-भिन्न केन्द्रीय बैंकों ने भिन्न-भिन्न अवसरों पर भिन्न-भिन्न तरीकों का प्रयोग किया है। और कभी-कभी तो उनको एक ही अवसर पर साथ-साथ ही कई तरीकों का प्रयोग करना पड़ा है। इनमें से बैंक दर नीति (Bank rate policy) और बाजार में खुले तौर पर सौदा करने की प्रणाली (Open Market Operations) बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई है। किन्तु हम इनका विस्तृत अध्ययन अगले अध्याय में ही करेंगे। हाँ, किसी देश में उसका केन्द्रीय बैंक साख के नियन्त्रण में कहाँ तक सफल हो सकता है यह भी बहुत सी बातों पर निर्भर है। पहिले तो यह उसके द्रव्य के बाजार की उन्नति के स्तर और उसके और केन्द्रीय बैंक के पारस्परिक सम्बन्ध पर निर्भर है। अधिकांश देशों में द्रव्य के सुसंगठित बाजार है ही नहीं। हमारे ही देश में द्रव्य के दो बाजार हैं—एक देशी और दूसरा आधुनिक—तथा इन दोनों में कोई विशेष सम्बन्ध नहीं है। देशी बाजार आधुनिक बाजार की बहुत कम सहायता लेता है, और इसी प्रकार आधुनिक बाजार भी देश के केन्द्रीय बैंक की बहुत कम सहायता लेता है। इसके अतिरिक्त दूसरी बात यह है कि व्यापारिक बैंकों में से कितने बैंक केन्द्रीय बैंक के सदस्य हैं। तीसरे, उनके और केन्द्रीय बैंक के बीच में कैसा सहयोग है, और अन्तिम यह कि केन्द्रीय बैंक का व्यापारिक बैंकों पर तथा अन्य अर्थ से सम्बन्धित संस्थाओं पर कैसा प्रभाव है। ये भिन्न-भिन्न देशों में भिन्न-भिन्न हैं। हाँ, केन्द्रीय बैंक इस उद्देश्य से एक स्पष्ट नीति पर चल कर स्थिति का सुधार तो अवश्य ही कर सकते हैं।

केन्द्रीय बैंकों का सरकार से सम्बन्ध

केन्द्रीय बैंकों के जो कार्य हैं उनके महत्व के कारण हमको उनके और सरकार के बीच के सम्बन्ध का भी अध्ययन अवश्य ही कर लेना चाहिये। प्रायः सभी देशों की सरकारों ने अपने-अपने मुख्य बैंकों के कार्यों में किसी न किसी रूप में हस्तक्षेप करना आवश्यक समझा है। उन्नीसवीं शताब्दी में तो इस बात को विधान में ही स्पष्ट कर देने का चलन हो गया था। किंतु प्रथम युद्ध के समय सरकार के अत्याधिक हस्तक्षेप के कारण इनसे जो जनता का अहित हो गया था, उसके कारण कुछ हवा बदल गई थी। सन् १९२० में ब्रूसेल्स कान्फ्रेंस ने जो यह निश्चय किया था कि बैंकों और विशेष कर नोट चलाने वाले बैंकों पर उनकी सरकार का कोई दबाव नहीं रहना चाहिये और उनको अर्थ-सम्बन्धी मामलों में दूरदर्शी नीति का पालन करना चाहिये वह उस समय के जनमत का द्योतक है। किन्तु बहुत से स्पष्ट कारणों से अधिकांश देशों में यह बात मान ली गई है कि प्रत्येक केन्द्रीय बैंक के संचालक मण्डल की रचना में उसकी सरकार का हाथ अवश्य रहना चाहिये और इधर तो उनका राष्ट्रीयकरण भी हो रहा है।

प्रथम तो कुछ ऐसे केन्द्रीय बैंक हैं जिनकी सारी पूँजी उनकी सरकार के द्वारा ही प्राप्त हुई है, अथवा वह सरकार की और व्यापारिक बैंकों की, अथवा सरकार की, व्यापारिक बैंकों की तथा लोगों की सम्मिलित पूँजी है। भारतवर्ष के रिजर्व बैंक की पूँजी के स्वामित्व के सम्बन्ध में सन् १९२७ ही में एक बड़ा गहरा मतभेद उत्पन्न हो गया था किन्तु अन्त में जब इसकी संस्थापना हुई थी उसके पहिले ही यह बात पूर्णतया मान ली गई थी कि वह जनता के लोगों की निजी पूँजी ही होनी चाहिये। इस सम्बन्ध में यह भी कह देना आवश्यक है कि सरकार के स्वामित्व का इस समय कोई विशेष महत्त्व नहीं है क्योंकि वह अब इसके बिना भी अनेकों प्रकार से अपने-अपने केन्द्रीय बैंकों पर अपना नियन्त्रण रख सकती है। दूसरे, उनके प्रधान कार्यकर्ताओं की नियुक्ति भी सरकार के द्वारा स्वयं ही, अथवा उनके संचालक मंडल की मन्त्रणा से अथवा व्यवस्थापक सभाओं की स्वीकृति से की जाती है। यदि सरकार अपने यहाँ के बैंक की पूँजी को एकत्रित करने में कोई भी हिस्सा नहीं बँटाती है तो भी इसके यह अर्थ नहीं है

कि वह उनके संचालकों की नियुक्ति में भी हिस्सा नहीं बँटा सकती है। कुछ देशों में और उनमें भारतवर्ष भी सम्मिलित है, उनकी सरकारों को उनके केन्द्रीय बैंकों की पूँजी में हिस्सा न भी बँटाने पर उनके संचालकों की नियुक्ति में ऐसा करने का अधिकार है।

प्रश्न

(१) 'केन्द्रीय बैंकिंग ने केवल इसी शताब्दी में ही एक विशिष्ट व्यवसाय का रूप धारण कर लिया है। उपरोक्त कथन पर अपना मत दीजिये।

(२) केन्द्रीय बैंकिंग के प्रायः कौन-कौन से काम हैं? क्या यह आवश्यक है कि केन्द्रीय बैंक साधारणतः व्यापारिक बैंकों के कार्य न करे?

(३) नोटों को चलाने के एकाधिकार अथवा शेषाधिकार से आप क्या समझते हैं? ससार के मुख्य-मुख्य केन्द्रीय बैंकों ने इन अधिकारों को कब प्राप्त किया है? इस अधिकार के कौन-कौन से लाभ हैं।

(४) नोटों को चलाने का नियन्त्रण करने के लिये कौन-कौन से तरीके हैं? उनमें से प्रत्येक के विषय में उदाहरण के साथ बताइये।

(५) 'सरकार के बैंकर' के क्या अर्थ हैं? क्या केन्द्रीय बैंक अपनी सरकार को ऋण दे सकते हैं? उदाहरण देकर बताइये कि इस सम्बन्ध के बन्धेज किस प्रकार से बारम्बार तोड़े गये हैं।

(६) यह बतलाइये कि रिजर्व बैंक देश की सरकार को कहाँ तक आर्थिक सहायता दे सकती है।

(७) केन्द्रीय बैंक किन-किन तरीकों से व्यापारिक बैंकों के नकद कोष को रखते हैं? इस कार्य से कौन-कौन सुविधायें प्राप्त हो सकती हैं।

(८) राष्ट्र का धात्विक कोष प्रायः किस रूप में उसके केन्द्रीय बैंक के पास रहता है? वास्तविक रकम किस बात पर निर्भर रहती है? अपने उत्तर के सम्बन्ध में कुछ उदाहरण दीजिये।

(९) बिलों पर ऋण देने और जब कहीं ऋण न मिले तब ऋण देने के दायित्व को स्वीकार करने में क्या सम्बन्ध है? यह बताइये कि इस बाद वाले कार्य की किस प्रकार धीरे-धीरे उन्नति हुई है। भारतवर्ष के रिजर्व बैंक की इस सम्बन्ध में क्या नीति है?

(१०) निकास-ग्रह का क्या सिद्धान्त है? उससे कौन-कौन से लाभ हैं? इस सम्बन्ध में केन्द्रीय बैंकों का क्या भाग रहता है? अपने उत्तर में भारतवर्ष और इंग्लैण्ड के उदाहरण दीजिये।

(११) केन्द्रीय बैंक के द्वारा साख के नियन्त्रण से आप क्या समझते हैं ? इसका क्या उद्देश्य होना चाहिये ? इसको करने को दो मुख्य तरीके बताइये ।

(१२) किसी केन्द्रीय बैंक का उसकी सरकार से प्रायः क्या सम्बन्ध रहता है ? अपने उत्तर के सम्बन्ध में उदाहरण दीजिये ।

अध्याय ७

केन्द्रीय बैंकिंग (२)

सन् १९१४-१८ के महायुद्ध के पहिले मुख्यतः बैंक दर नीति ही के द्वारा साख नियन्त्रण किया जाता था ।

बैंक दर

बैंक दर का अर्थ—बैंक दर वह दर है जिस पर कोई केन्द्रीय बैंक सर्वोच्च कोटि के बिलों को फिर से डिस्काउण्ट (Rediscount) करने के लिये तैयार रहता है । यह हर सप्ताह में एक विशेष दिन बैंक सचालकों की एक विशेष बैठक में निश्चित किया जाता है और फिर घोषित कर दिया जाता है । जहाँ तक होता है यह एक बार निश्चित हो जाने पर फिर एक सप्ताह के अन्दर नहीं बदला जाता । आजकल यह वह दर भी है जिस पर कोई केन्द्रीय बैंक अपने सदस्य बैंकों को उनकी सर्वोच्च कोटि की जमानतों की बिना पर ऋण देने के लिये भी तैयार रहता है । यह परिवर्तन केवल इसीलिये हुआ है कि इधर बिलों की बहुत कमी हो गई है और सरकारी साख-पत्र तथा बिल बहुत बढ़ गये हैं । यह बिलों की कमी कई कारणों से हुई है जिनमें से मुख्य तो यह है कि इधर व्यापारिक बैंक प्रायः अपने ग्राहकों को उनके द्वारा जमा की हुई रकम से कहीं अधिक रकम निकालने की आज्ञा (Overdraft), नकद साख (Cash Credit) तथा जमानती ऋण (Collateral Loans) देने लगे हैं । इसके अलावा पहिले द्रव्य को एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजने के सम्बन्ध में भी बिलों का प्रयोग होता था, किन्तु अब ऐसा नहीं है । व्यापारिक बैंकों की सख्या बढ़ती जा रही है और वह इस

कार्य को अधिकाधिक अपने बैंक ड्राफ्टों के द्वारा करते हैं। यह लन्दन में भी हो रहा है और अन्य स्थानों में भी हो रहा है। इसके अलावा प्रथम महायुद्ध के पहिले लन्दन के अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान के केन्द्र होने के कारण वहाँ पर अनेकों विदेशी बिल डिस्काउण्ट होने के लिये आते थे। किन्तु उसके बाद से अन्य स्थान भी अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान के केन्द्र बन गये हैं, जिसके बिलों के डिस्काउण्ट होने का कार्य उनके बीच में बँट गया है। साथ ही संरक्षण की नीति के चालू हो जाने के कारण, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में भी कमी हो गई है जिससे यह बिल भी अब उतने नहीं निकलते जितने पहिले निकलते थे। इसके विपरीत सरकारी साख-पत्रों और बिलों का प्रयोग विभिन्न सरकारों के ऋण के परिमाण में वृद्धि हो जाने के कारण बहुत बढ़ गया है। कहना न होगा कि यह ऋण के परिमाण की वृद्धि प्रथम और द्वितीय महायुद्ध की और उनके बीच के समय की कठिनाइयों को दूर करने के हेतु ही हुई है।

साख के नियन्त्रण में बैंक दर का प्रयोग—साख के नियन्त्रण में बैंक दर का प्रयोग पहिले पहिले बैंक आफ इंग्लैंड ने सन् १८३९ में किया था। इसके पहिले बैंक दर ४ अथवा ५ प्रतिशत रहती थी। यदि बाजार की दर ४ प्रतिशत से नीचे गिर जाती थी तो बैंक अपनी दर को चार प्रतिशत से कम नहीं करता था। जिसका अर्थ यह होता था कि उसके पास डिस्काउण्ट कराने के लिये बिलों का आना रुक जाता था। बैंक को अपनी दर को ५ प्रतिशत से अधिक बढ़ाने का भी अधिकार नहीं था। बात यह थी कि उस समय वहाँ पर अन्याय ब्याज के विरुद्ध एक विधान (Usury law) था। तीन महीनों तक की अवधि पर के बिलों के लिये सन् १८३३ में इसके बंधन को हटा दिया गया था। इसके कुछ वर्ष बाद ही यह हर अवधि के बिलों पर के लिये भी हटा दिया गया। किन्तु इसके यह अर्थ नहीं है कि बैंक आफ इंग्लैंड सन् १८३९ के पहिले साख-नियन्त्रण के लिये कुछ नहीं करता था। वह दूसरे तरीकों को प्रयोग में लाता था। एक तो वह हर प्रार्थी के ऋण की रकम को सीमित करके साख का एक तरह से राशन बाँध देता था। दूसरे जिन बिलों को वह डिस्काउण्ट करने के लिये तैयार रहता था उनकी अवधि को कम कर देता था। सन् १८३९ में बैंक दर पहिले तो ५½ प्रतिशत और फिर ६ प्रतिशत कर दी गई। किन्तु इसके

साथ ही जिन विलों को वह डिस्काउण्ट करने के लिये तैयार रहता था उनकी अवधि को भी उसने ९५ दिन से घटा कर ३० दिन कर दिया था। किन्तु साख-नियन्त्रण के लिये बैंक दर नीति का अधिकाधिक प्रयोग केवल सन् १८४४ के बैंक विधान के पास हो जाने के बाद ही होना प्रारम्भ हुआ और जैसे-जैसे बैंक ने और कहीं ऋण न मिलने पर स्वयं ऋण देने का दायित्व स्वीकार कर लिया वैसे-वैसे इस दायित्व को निवाहने के लिये उसको साख-नियन्त्रण के पहिले वाले तरीकों को छोड़ना पड़ा। सन् १८४७ में जब एक संकट का समय (Crisis) उपस्थित हुआ तब बैंक को साख नियन्त्रण की इस नई नीति की परीक्षा करने का अवसर प्राप्त हुआ। किन्तु पहिले तो उसने कुछ नहीं किया और चुपचाप बैठा रहा और बाद में जब उसने इस नीति को अपनाने का प्रयत्न किया तब इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ सका। अतः, सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा और उसने सन् १८४४ के विधान के उस भाग को कुछ दिनों के लिये रद्द कर दिया जिसके द्वारा बैंक एक निश्चित रकम को छोड़कर अन्य के नोट शत-प्रतिशत स्वर्ण रक्खे बिना नहीं चालू कर सकता था। किन्तु इसके प्रयोग की आवश्यकता नहीं पड़ी। केवल इसके पास कर देने से ही संकट टल गया। सन् १८५७ और १८६६ के संकट काल के समय भी इसने शीघ्रता नहीं की, और अपनी दर को उस समय न बढ़ाकर जब साख की अत्याधिक माहृ हो रही थी केवल उसी समय ही बढ़ाया जब स्वर्ण का देश से निर्यात होने लगा। अतः, इन दोनों अवसरों पर भी सन् १८४४ के विधान के जिस भाग का ऊपर संकेत किया गया है उसको रद्द करने के लिये प्रबन्ध करना पड़ा और सन् १८५७ के संकट के समय इसको प्रयोग में भी लाना पड़ा। हाँ, सन् १८७३ में जब इसे एक कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ा तब इसने शीघ्रता की और उसमें इसको सफलता भी मिली। इसके बाद अन्य अवसरों पर भी इसने यही किया और उनमें भी यह सफल रहा। सन् १८९० में एक तरफ तो इसने अपनी दर को बढ़ाकर साख के अत्याधिक-फैलाव को रोक़ा और दूसरी तरफ़ अन्य अंग्रेजी बैंकों और अर्थ सम्बन्धी संस्थाओं के सहयोग से वारिंग्डर्स के जो फेल हो चुके थे देने को उनके पकने पर देने का विश्वास दिलाया। इससे न केवल जनता का भय दूर हो गया बल्कि बैंक की मर्यादा भी काफी बढ़ी। किन्तु धीरे-

धीरे साख-नियन्त्रण के अन्य तरीके भी प्रयोग में आने लगे जैसे लन्दन के बाज़ार में उधार लेना, किसी हद तक स्वर्ण के क्रय-विक्रय के अपने दर को बढ़ाना और घटाना तथा फ्रान्स और रूस में साख का प्रबन्ध करना और उसको स्वीकार करना। तथापि प्रथम महायुद्ध के पहिले और विशेषतः सन् १८४४ के विधान के पास हो जाने के बाद तक साख-नियन्त्रण का मुख्य तरीका बैंक दर नीति ही रहा। कहना न होगा कि अन्य केन्द्रीय बैंकों ने भी बैंक आफ इंग्लैंड के नियन्त्रण संबंधी अनुभव से लाभ उठाया किन्तु इसका और कहीं भी इतने जोर से और इतनी जल्दी-जल्दी प्रयोग नहीं हुआ। लूवेन के कथन के अनुसार जब कि बैंक आफ इंग्लैंड ने सन् १८७५ और १९०० के बीच में इसका १६७ बार उपयोग किया, बैंक आफ फ्रान्स ने केवल २५ बार और रीश बैंक (जर्मनी के केन्द्रीय बैंक) ने केवल ८४ बार इसका उपयोग किया। इसके कई कारण थे :— (१) लन्दन के स्वर्ण के एक स्वतन्त्र बाज़ार होने के कारण वह विदेशी पूँजी की लागत के लिये बहुत ही उपयुक्त स्थान माना जाता था। अतः, जब कभी कहीं भी गड़बड़ मचती थी और वहाँ की पूँजी लन्दन से निकाली जाती थी तब लन्दन में अवश्य कठिनाई उत्पन्न हो जाती थी। (२) ब्रिटिश साख की रचना की तुलना में इस समय बैंक आफ इंग्लैंड का स्वर्ण कोष बहुत ही थोड़ा रहता था। (३) ब्रिटिश पूँजी के विदेशों में लगने के कारण ग्रेट ब्रिटेन के बैंकिंग के साधनों पर बराबर बोझ पड़ता रहता था और उसका यह प्रभाव होता था कि कभी-कभी अत्याधिक लागत लग जाती थी तथा उत्पत्ति और व्यापार सीमा का उलंघन कर जाते थे जिससे सट्टेबाज़ी बढ़ जाती थी। यह केवल बैंक दर को ही बढ़ाकर और कभी-कभी तो अत्याधिक बढ़ाकर ही रोकी जा सकती थी।

बैंक दर नीति साख का नियन्त्रण तभी कर सकती है जब केन्द्रीय बैंक के डिस्काउण्ट की दर के परिवर्तन से द्रव्य के अन्य दरों में भी उसी अनुपात से परिवर्तन हो। इंग्लैंड में द्रव्य की विभिन्न दरों के बीच में एक बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध था। बैंक दर प्रायः बाज़ार के डिस्काउण्ट की दर से कुछ ऊँचा रहा करता था। यह एक प्रकार से दण्ड देनेवाली दर थी। अतः, बाज़ार वाले बैंक से उसी समय ऋण लेते थे जब उनको और कहीं ऋण नहीं मिलता था। साथ ही बैंक का यह सबसे

नीचा दर था। इस पर बैंक केवल सर्वोच्च बिलों को ही डिस्काउंट करने के लिये तैयार रहता था। निम्न श्रेणी के बिलों को डिस्काउंट करने के लिये यह और ऊँची दर लगाता था। बैंक जमानतों पर जो ऋण देता था उन पर भी इससे $\frac{1}{2}$ प्रतिशत ऊँची दर लेता था। बैंक दर के परिवर्तन पर बाज़ार के डिस्काउंट के दर में भी परिवर्तन होता था। बैंक सात दिन की सूचना की शर्त पर जो जमा प्राप्त करते थे उस पर जो व्याज देते थे उसकी दर प्रायः इस दर से $1\frac{1}{2}$ प्रतिशत कम रहती थी। सन् १९२१ में तो यह अन्तर २ प्रतिशत तक का हो गया था। माँग पर वापिस होने वाले ऋणों पर की व्याज की दर प्रायः जमा के व्याज की दर से $\frac{1}{2}$ प्रतिशत अधिक होती थी। फिर बैंक अन्य ऋणों के सम्बन्ध में अपने ग्राहकों से जो व्याज लेते थे उसकी दर बैंक दर से प्रायः एक प्रतिशत ऊँची होती थी और कम से कम ५ प्रतिशत अवश्य होती थी। कभी-कभी यह क्रम नहीं चलता था, किन्तु प्रायः यही रहता था। किन्तु अन्य देशों में यह सम्बन्ध इतना निश्चित नहीं रहता था। अतः, वहाँ की बैंक दर नीति साख-नियन्त्रण में इतनी सफल नहीं होती थी। जिन परिस्थितियों में कोई केन्द्रीय बैंक साख का नियन्त्रण कर सकता है उनका अध्ययन तो हम प्रहिले ही कर चुके हैं, और यह भी स्पष्ट है कि इंग्लैण्ड को छोड़कर किसी भी दूसरे देश में वह परिस्थितियाँ सम्पूर्ण रूप से नहीं पाई जाती।

जब सन् १९१४ में फेडरल रिज़र्व बैंकों ने कार्यान्वयन किया था तब उन्होंने बैंक आफ इंग्लैण्ड के साख-नियन्त्रण के तरीकों का अवलम्बन करना चाहा था और न्यूयार्क में एक बहुत ही उन्नत द्रव्य के बाज़ार की सस्थापना का निरन्तर प्रयत्न किया था। इसमें संदेह नहीं कि वे इसमें बहुत अंशों तक सफल भी हो गये थे। किन्तु उनके यहाँ के बैंक दर और वाज़ारू दरों का सम्बन्ध कुछ भिन्न परिस्थितियों के कारण भिन्न था। ग्रेट ब्रिटेन में बैंक बैंक आफ इंग्लैण्ड से सीधे ऋण की याचना नहीं करते थे। आवश्यकता के समय वह जो करते थे वह इस प्रकार था कि वे बिल के दलालों से और अन्य ऋण लेने वालों से अपने माँग पर वापिस होने वाले ऋणों को माँग लेते थे और साथ ही उनके बिलों को डिस्काउंट करना वन्द कर देते थे। इसका स्वाभावतः यह फल होता था कि बाज़ार वाले बैंक आफ इंग्लैण्ड से सहायता माँगते थे और वह उनसे यथोचित व्यवहार करता था। इसके

विपरीत सयुक्त राष्ट्र-अमेरिका में रिज़र्व बैंकों के सदस्य बैंक सीधे रिज़र्व बैंक के साथ काम करते थे। फिर, जब कि इंग्लैंड में बैंक आफ इंग्लैंड से ऋण प्राप्त करने का सबसे नीचा दर बैंक दर था सयुक्त राष्ट्र अमेरिका में यह बात नहीं थी। डिस्काउण्ट की दर के अतिरिक्त फेड्रल रिज़र्व बैंक अन्य बैंकों के द्वारा स्वीकृत हुये विलों के क्रय की एक अन्य दर भी घोषित करते थे जो विलों के बाज़ार की सहायता करने के और उनको बनाये रखने के उद्देश्य से डिस्काउण्ट की दर से नीची और प्रायः बाज़ार की दर के बराबर होती थी। अतः, जब कि सदस्य बैंक रिज़र्व बैंकों से ऊँचे दर पर अपने व्यापारिक साख-पत्रों को डिस्काउण्ट कराते थे बाज़ार वालों के बैंकों द्वारा स्वीकृत किये हुये विलों को वह नीची दर पर खरीद लेते थे। इसका यह फल होता था कि वहाँ पर साख-नियन्त्रण के लिये बैंक दर नीति उतनी कारगर नहीं होती थी जितनी ग्रेट ब्रिटेन में होती थी। तीसरे, जब से फेड्रल रिज़र्व बैंक स्थापित हुये हैं तब से वहाँ पर स्वर्ण कोप की वाढुल्यता रही है जिससे वह करन्सी के प्रसार के लिए काम में आता रहा है। इन सब कारणों के साथ-साथ कुछ अन्य कारण भी थे, जैसे वहाँ पर सट्टेबाज़ी की अत्यधिक सुविधा और वहाँ के लोगों का उसके प्रति अत्यधिक झुकाव। फिर, रिज़र्व बैंकों को बैंक दर निर्धारित करने की उतनी स्वतन्त्रता भी नहीं है जितनी बैंक आफ इंग्लैंड को है। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं, जब रिज़र्व बैंकों की प्रार्थना पर बोर्ड ने बैंक दर बढ़ाने की अनुमति नहीं प्रदान की।

प्रथम महायुद्ध के काल में और उसके बाद भी अनेकों अवसरों पर केन्द्रीय बैंक बैंक दर नीति का पालन केवल इसलिए नहीं कर सके कि उनको सरकार की अर्थ-सम्बन्धी आवश्यकताओं का ध्यान रखना था। किन्तु जैसे ही अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्ण मान अपना लिया गया और केन्द्रीय बैंक अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिये मुक्त हो गये वैसे ही साख-नियन्त्रण के लिये बैंक दर नीति का फिर से अधिकाधिक प्रयोग होने लगा। हाँ, साख नियन्त्रण के अन्य तरीकों जैसे बाज़ार में खुले तौर पर काम करना, अपना नैतिक प्रभाव डालना, इत्यादि की अपेक्षाकृत इसका प्रयोग घटता गया। हम इस बात को तो देख ही चुके हैं कि विलों की कमी क्यों पड़ने लगी थी और केन्द्रीय बैंक उनके स्थान पर सरकारी विलों और साख-

पत्रों की जमानत पर ऋण देने में बैंक दर का किस प्रकार प्रयोग करने लगे थे। किन्तु इससे अधिक लाभ नहीं हुआ क्योंकि कुछ अन्य परिस्थितियों में भी परिवर्तन हो चुका था और हो रहा था। एक तो द्रव्य के जितने मुख्य बाजार थे वह सब द्रवित अवस्था में थे। बात यह थी कि उनके यहाँ के केन्द्रीय बैंकों में अथवा सरकार के विनिमय सम्बन्धी खातों में इस समय काफी स्वर्ण कोप था, अतः, उसी से उनके यहाँ करन्सी का काफी प्रसार भी था। दूसरे, सरकारी विलों की रकम के बढ़ जाने के कारण इस समय केन्द्रीय बैंकों की अपेक्षाकृत सरकार का प्रभाव बाजार पर कहीं अधिक था। अन्तिम बात यह है कि जब से स्वर्णमान सारे संसार भर से हट गया है तबसे उसके स्थान पर कृत्रिम करन्सी मान चल रहा है। साथ ही आजकल अधिकांश देशों में स्वाभाविक तौर पर काम होने के स्थान में-योजनाओं के अनुसार काम हो रहा है जिससे मूल्य में, मजदूरी के दर में, उत्पत्ति में और व्यापार में द्रव्य की दरों के और साख की स्थितियों के परिवर्तन के साथ-साथ योजना के अनुसार ही परिवर्तन हो जाते हैं। वेजमैन का कथन है कि बैंक दर नीति उसी आर्थिक संगठन में सफल हो सकती है जिसमें मूल्य, मजदूरी के दर और व्याज के दर प्रायः आवश्यकता के अनुसार स्वाभाविक तौर पर ही कृत्रिम तरीकों से योजना के अनुसार नहीं बदलते रहते। किन्तु कृत्रिम करन्सी और योजनाओं की प्रणाली के अन्दर ऐसा नहीं होता। अतः, इन परिस्थितियों में बैंक दर नीति का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

किन्तु प्रायः सभी केन्द्रीय बैंक हर सप्ताह में अपने-अपने बैंक दर अब भी घोषित करते हैं। अधिकतर तो उनके विधानों में ही यह दिया हुआ है कि उनको अपने बैंक दर को निश्चित और घोषित करना पड़ेगा। इससे बैंक दर के आज भी महत्वपूर्ण होने का पता लगता है। पहिले तो इससे यह मालूम हो जाता है कि केन्द्रीय बैंक कुछ विशेष प्रकार के साख-पत्रों की जमानत पर किस दर से ऋण देने के लिये तैयार है। दूसरे, यह इस बात का भी द्योतेक है कि ऋण साधारणतः किस दर पर प्राप्त हो सकता है। तीसरे, इससे यह भी पता लगता है कि केन्द्रीय बैंक का देश की साख की स्थिति के विषय में क्या मत है। कभी-कभी तो इससे वहाँ की

साधारण आर्थिक स्थिति के विषय में भी बैंक के मत का पता चलता रहता है। गिबन के शब्दों में^१ हम यह कह सकते हैं कि बैंक दर की वृद्धि आर्थिक स्थिति के विकृत रूप की चेतावनी देती है। एडिस के कथनानुसार^२ यह व्यापारियों के लिये भयसूचक लाल रोशनी का काम करती है और उनको इस बात की चेतावनी देती है कि आगे चलकर उनके ठोकर खाकर गिर जाने की सम्भावना है। इसके विपरीत इसकी कमी हरी रोशनी की द्योतक है जो यह बतलाती है कि रास्ता बिल्कुल साफ है और व्यापार रूपी पोत सावधानी के साथ आगे बढ़ सकता है।

साख-नियन्त्रण के लिए बाज़ार में खुले तौर पर काम करना (Open market operations)—यह तो पहिले ही बतलाया जा चुका है कि बैंक आफ इंग्लैण्ड साख-नियन्त्रण के सम्बन्ध में बैंक दर नीति के साथ-साथ अन्य कई तरीकों का प्रयोग प्रथम महायुद्ध के और उसके बाद के साल के बहुत पहिले से ही करता आ रहा था। अब इन सब में से बाज़ार में खुले तौर पर काम करने की नीति (Open market policy) ही धीरे-धीरे विशेष तौर पर प्रधानता प्राप्त करती गई—यहाँ तक कि आज-कल यह बैंक दर नीति के सहायक रूप में न रह कर स्वयं ही एक स्वतन्त्र नीति से प्रयोग में आने लगी है। इस नीति के यह अर्थ है कि केन्द्रीय बैंक स्वयं ही बाज़ार में प्रत्यक्ष रूप से उन सब साख-पत्रों का क्रय और विक्रय करने लगे जिनको वह साधारण तौर पर लेता और बेचता है, चाहे वह सरकारी साख-पत्र हों, अथवा जनता के दूसरे साख पत्र हों, अथवा बैंकों के द्वारा स्वीकृत किये गये बिल हों अथवा व्यापारियों के बिल हों। लेकिन चलन यही है कि बैंक केवल

^१ 'A rise in Bank rate may be regarded as the amber coloured light of warning of a robot system of finance and economics'—Gilson

^२ 'A rise in Bank rate is a danger signal, the red light warning to the business community of rocks ahead on the course in which they are engaged. A fall in it on the other hand may be looked upon as the green light indicating that the coast is clear and that the ship of commerce may proceed on her way with caution'—Addis.

सरकारी साख-पत्रों को ही लेते और बेचते हैं। हाँ, यह लम्बी अवधि और थोड़ी अवधि दोनों के होते हैं। जनता के दूसरे साख-पत्रों को वह कुछ स्पष्ट कारणों से नहीं छूते। वास्तव में यह सम्भव भी केवल इसी लिये हो सका है कि आज-कल की सरकारों ने बहुत से ऋण ले रखे हैं। यह लम्बी अवधि और थोड़ी अवधि दोनों प्रकार के हैं। ऐसा करने में बैंक अपनी तरफ से बाज़ार में काम करता है, बाज़ार के लोग उसके पास स्वयं नहीं जाते। उनको ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। बैंक को देश के हित में ऐसा करना आवश्यक मालूम होता है।

किन्तु इस नीति का प्रभाव केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में ही पड़ सकता है। प्रथम तो यह आवश्यक है कि देश की बैंकिंग की प्रणाली बहुत ही उन्नत अवस्था को पहुँच गई हो, अर्थात् लोग अपनी वचत की रकम अपने पास न रख कर बैंकों में ही रखते हों। यदि ऐसा नहीं होता तो जब केन्द्रीय बैंक साख-पत्र बेचने लगता है तब उन्हें लोग अपने पास की रकमों से खरीद लेते हैं जिससे बैंकों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किन्तु जब उनकी वचत बैंकों में जमा रहती है तब केन्द्रीय बैंक के द्वारा बेचे गये साख-पत्रों को खरीदने के लिये लोग बैंकों से अपनी रकम निकालते हैं और बैंकों के नकद कोष में इस प्रकार से कर्जा आ जाने पर उनकी साख उत्पादन शक्ति में भी कमी आ जाती है। यही साख नियन्त्रण है। यह साख-नियन्त्रण उस समय भी नहीं हो पाता जब केन्द्रीय बैंक के द्वारा बेचे हुए साख-पत्रों को विदेशी लोग खरीद लेते हैं। दूसरे, बैंकों के नकद कोष में वृद्धि होने और कमी पड़ने पर उनकी साख उत्पादन शक्ति पर भी प्रभाव पड़ना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं होता तो साख नियन्त्रण नहीं किया जा सकता। बहुधा ऐसा होता है कि नकद की वृद्धि पर भी व्यापारिक बैंक साख नहीं बढ़ाते। तीसरे, इसमें केवल यही प्रश्न नहीं है कि व्यापारिक बैंक केन्द्रीय बैंक की लक्ष्य पूर्ति के लिये तैयार हों, बल्कि यह भी प्रश्न है कि कुछ साहसी लोग काम चलाने के उद्देश्य से ऋण लें और उनका इतना विश्वास हो अथवा उनके पास इस तरह की जमानत हो कि जिस पर बैंक उन्हें उधार दे सकें। यदि यह दोनों बातें नहीं हैं तो बैंकों की इच्छा रहने पर भी साख का प्रसार नहीं हो सकता। इसी तरह से यदि काम करने वालों की व्यापार

और सट्टे में लाभ दिखाई पड़ता है तो बैंक प्रयत्न करने पर भी शायद साख की माँग में कमी नहीं कर सकते। अन्तिम बात यह है कि बैंकों की जमा की चाल (Deposit velocity) में भी कोई परिवर्तन न हो। स्वाभाविक तौर पर तो व्यापार की वृद्धि से इसमें वृद्धि और उसकी मन्दी से इसमें मन्दी हो जाती है। किन्तु सच बात तो यह है कि उपर्युक्त में से कोई भी बात पूरी तौर से किसी देश में भी नहीं मिलती। लेकिन साधारणतया बाज़ार में खुले तौर पर काम करने की यह नीति मुख्य-मुख्य देशों में अपना प्रभाव अवश्य रखती है। इसका महत्व यह है कि यह बैंकों की नकदी के कोष बढ़ा अथवा घटा देती है और इन परिवर्तनों से द्रव्य की दरों और साख की स्थितियों में भी परिवर्तन हो जाते हैं जिससे मूल्यों और व्यापारिक स्थितियों में भी आवश्यक उलट-फेर हो जाते हैं। हाँ, यदि कहीं कोई रुकावट पड़ जाती है तो अवश्य इच्छित प्रभाव नहीं पड़ता।

जहाँ तक लन्दन का प्रश्न है वहाँ के क्रिक नामक एक बैंक अर्थशास्त्री ने यह कहा है कि बैंक आफ इंग्लैंड अपने प्रत्यक्ष काम से वहाँ के नकद कोष को घटा-बढ़ाकर वहाँ के बैंकों की जमा प्रसार और संकुचन बड़े जोरों से और जान-बूझकर कर सकता है और करता है तथा इसी तरह साख के नियन्त्रण में सफल होता है। एम० एच० डी काफ ने बैंक आफ इंग्लैंड की इस नीति के लक्ष्य के विषय में निम्न बातें बतलाई हैं :—

(१) बैंक दर का प्रभाव उत्पन्न करना अथवा बैंक दर में परिवर्तन करने के लिये स्थिति पैदा कर देना।

(२) सरकारी द्रव्य की अथवा ऋतु सम्बन्धी गति विधि से द्रव्य के बाज़ारों में जो हलचल पैदा हो जाती है, उसको रोकना।

(३) स्वर्ण के निर्यात और आयात को रोकना।

(४) नये ऋणों को निकालने और पुराने ऋणों को नये ऋणों में बदलने की अवस्था में सरकारी साख की रक्षा करना।

(५) व्यापार के पुनर्निर्माण में सहायता पहुँचाने के लक्ष्य से सस्ते द्रव्य की स्थितियों को उत्पन्न करना और उनको बनाये रखना।

संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंकों की भी खुले तौर पर बाज़ार में काम करने की नीति के लक्ष्य के विषय में यही कहा

जा सकता है। हाँ उनके कामों में और उनके इस पर जोर देने तथा इसको करने के स्तर (Standard) में अवश्य कुछ विशेष अन्तर है।

भारतवर्ष के रिजर्व बैंक को भी आवश्यकता पड़ने पर इस नीति का प्रयोग करने का अधिकार दिया गया है, और साथ ही जहाँ तक सम्भव हो सका है उन परिस्थितियों को भी उत्पन्न करने का प्रयत्न किया गया है जिनसे इसका यथेष्ट प्रभाव पड़ सकता है। किन्तु अभी तक कोई ऐसा अवसर नहीं आया जब उसने इस नीति का प्रयोग किया हो।

साख नियन्त्रण के अन्य तरीकों का प्रयोग

साख नियन्त्रण के अन्य तरीकों में से कुछ का संकेत तो हम बैंक दर नीति के सम्बन्ध में ही कर चुके हैं। वहाँ पर यह भी बतलाया जा चुका है कि सन् १८३९ के पहिले बैंक आफ इंग्लैण्ड (१) प्रत्येक प्रार्थी के ऋण की रकम को बाँध करके साख की राशनिंग कर दिया करता था, और (२) जिन विलों का डिस्काउण्ट करने को तैयार रहता था उनकी अवधि को भी घटा देता था। उसने इस वर्ष साख नियन्त्रण के लिये वास्तव में बैंक दर नीति के साथ-साथ उपयुक्त दूसरी नीति को भी अपनाया था और डिस्काउण्ट करने वाले विलों की अवधि को ९५ दिन के स्थान पर केवल ३० दिन ही कर दिया था। उसी सम्बन्ध में हम यह भी देख चुके हैं कि धीरे-धीरे बैंक ने साख नियन्त्रण के अन्य तरीकों का भी प्रयोग करना प्रारम्भ कर दिया था जैसे लन्दन के बाजार में ऋण लेना, स्वर्ण के क्रय और विक्रय की दर को एक विशेष सीमा के अन्दर बढ़ा देना और फ्रांस तथा रूस से उधार लेना अथवा स्वीकार करना। इधर हाल में कुछ अन्य तरीकों का भी प्रयोग होने लगा है। किन्तु उन सब का अध्ययन करने के पहिले हमको एक बार साख की राशनिंग के तरीके को फिर से भली-भाँति समझ लेना है। बात यह है कि इधर तानाशाही (Fascist) सरकारों ने हाल में भी इसका काफी प्रयोग किया था। वास्तव में राष्ट्रीय योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये ऐसा करना आवश्यक हो जाता है।

५। ख की राशनिंग—जर्मनी ने इसका प्रयोग सन् १९२४ में

अपने निच रैन्टैनमार्क के मूल्य के हास को रोकने के लिये किया था। फिर, वहाँ पर सन् १९२९ में भी यही प्रयोग में लाई गई थी। उस वर्ष रंग योजना के सम्बन्ध की पेरिस की वार्तालाप के कारण वहाँ से द्रव्य का निर्यात प्रारम्भ हो गया था जिससे वहाँ की करन्सी की स्थिति के बिगड़ने की सम्भावना उपस्थित हो गई थी। अतः, उसको इसी नीति के द्वारा साख का नियन्त्रण करके सम्भाला गया था। सन् १९३१ में भी वहाँ पर रीश बैंक ने साख का कोटा (Quota) बाँध करके बड़े-बड़े बैंकों को फेल होने से बचाया था। रूस में तो यह तरीका वहाँ के सरकारी बैंक की साधारण आर्थिक नीति का प्रायः एक अङ्ग ही बन गया है। कज़नलनबाम (Katzenellenbaum) का कथन है कि केन्द्रीय बैंक का बैंक दर न तो ऋण सम्बन्धी कोष की माँग और भरती (Supply) का सूचक है और न उसकी भरती को ठीक करता है। जहाँ तक रूस के सरकारी बैंक में जमा होने वाले कोष का प्रश्न है उसके सम्बन्ध में वह एक अन्य सिद्धान्त के अनुसार चलता है अर्थात् जिनको उसकी आवश्यकता होती है उनको वह एक निश्चिन्त योजना के अनुसार देता है और कभी-कभी जब उनकी माँग उसके पास के कोष की अपेक्षा-कृत अधिक हो जाती है तब वह उसको उनके बीच में एक विशेष योजना के अनुसार बाँट देता है। द्वितीय महायुद्ध के काल में प्रजातन्त्र राज्यों में भी इस तरीके का काफी प्रयोग किया गया था।

प्रत्यक्ष कार्यवाही करना और नैतिक प्रभाव डालना (Direct action and moral suasion)—वास्तव में प्रत्यक्ष कार्यवाही करने में नैतिक प्रभाव डालना भी सम्मिलित है। किन्तु एम० एच० डी काक ने इन दोनों के बीच में कुछ अन्तर दिखाने का प्रयत्न किया है। उसके कथन के अनुसार प्रत्यक्ष कार्यवाही करने के अर्थ हैं किसी व्यापारिक बैंक के विरुद्ध कुछ कड़े उपायों का प्रयोग करना और नैतिक प्रभाव डालने के अर्थ हैं उपयुक्त प्रकाश डाल कर अपने लक्ष्य को सिद्ध करना। इसमें केन्द्रीय बैंक का प्रभाव और उसकी स्थिति को समझाने की और उसी के अनुसार काम करा लेने की शक्ति का अधिक महत्व है। केन्द्रीय बैंकों ने इन तरीकों का प्रयोग किसी न किसी रूप में बैंक दर नीति और बाज़ार में खुले तौर पर काम करने की नीति को अपनाने के साथ-

साथ अथवा उनसे पृथक्-पृथक् अनेकों वार समय-समय पर किया है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में जब-जब फेड्रल रिजर्व बोर्ड ने बैंक दर में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी और विशेषकर सन् १९२८-२९ में उसने उसके स्थान पर इन्हीं तरीकों को काम में लाने के लिये इशारा किया था। किन्तु क्लार्क के कथनानुसार हम यह कह सकते हैं कि फेड्रल रिजर्व बैंकों को इनके प्रयोग का जो अनुभव हुआ है उससे यह ज्ञात होता है कि यह काफी उपयोगी नहीं सिद्ध हुये, अतः, इनका प्रयोग बहुत ही समझ बूझ कर करना चाहिए। हाँ, रीश बैंक ने भी प्रायः इनका प्रयोग किया है और वह इसमें फेड्रल रिजर्व बैंकों की अपेक्षाकृत अधिक सफल हुआ है। किंतु यह केवल इसीलिये हो सका कि उसमें बहुत कड़े उपायों को प्रयोग में लाने का भय दिखाया गया था जो कि केवल तानाशाही शासन प्रणाली ही के अन्तर्गत सम्भव है।

न्यूनतम नकदी केन्द्रीय बैंकों में रखने वाले व्यापारिक बैंकों में परिवर्तन—पाँचवें अध्याय में जब हम व्यापारिक बैंकों के नकद कोष के विषय में अध्ययन कर रहे थे तब हमने यह देखा था कि कुछ देशों में इन बैंकों को चालू जमा और स्थायी जमा का एक निर्धारित अंश अपने यहाँ के केन्द्रीय बैंकों में रखना पड़ता है। इधर केन्द्रीय बैंकों ने कभी-कभी इस अंश को घटाने बढ़ाने की शक्ति का भी प्रयोग किया है। पहिले पहिल इसका आविष्कार संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में सन् १९३३ में हुआ था और फिर इसका संशोधन वहाँ पर सन् १९३५ में किया गया था। इसके संबंध का जो विधान बना था उसके द्वारा फेड्रल रिजर्व प्रणाली के शासक मण्डल को साख के हानिकारक प्रसार और सकुचन को रोकने के लिये सदस्य बैंकों द्वारा उनके पास उनकी जमा का जो अंश जमा किया जाता है उसको घटाने बढ़ाने का अधिकार दे दिया गया है। वस्तुतः इसका प्रयोग वहाँ पर सन् १९३६ के अगस्त में किया गया था। उस वर्ष जमा होने वाले कोष का अंश पहिले से डबोड़ा कर दिया गया। उस समय शासक मण्डल ने यह कहा था कि इसकी अपेक्षाकृत कि पहिले तो यह अत्याधिक कोष साख बनने के काम में आवे और फिर उसको वापिस लिया जाय यह अधिक श्रेष्ठकर है कि इसके प्रयोग में आने के पहिले ही इसके एक अंश की उत्पादन शक्ति

को रोक दिया जाय। किन्तु स्वर्ण के बराबर आयात होने के कारण सदस्य बैंकों के कोप बढ़ते रहे और सन् १९३७ के आरम्भ में शासक मण्डल को फिर उनके द्वारा जमा किये जाने वाले कोष के अनुपात को दो किस्तों में बढ़ाना पड़ा जिससे सदस्य बैंकों को अगस्त १९३६ के पहिले जो न्यूनतम जमा रखनी पड़ती थी उससे अब दुगुनी जमा रखनी पड़ने लगी। परन्तु सन् १९३८ में इस जमा किये जाने वाले कोष का प्रतिशत नये प्रतिशत से १२½ प्रतिशत कम कर दिया गया। न्यूजीलैन्ड और स्विडेन ने भी इस तरीके का अभी हाल ही में प्रयोग किया था।

निस्सन्देह साख नियन्त्रण का यह तरीका बहुत ही अच्छा है किन्तु साथ ही इसमें कुछ कठिनाइयाँ भी हैं। प्रथम तो सब बैंकों के कोप एक साथ तथा एक ही मात्रा में नहीं घटते-बढ़ते। अतः, केन्द्रीय बैंकों के उनके यहाँ जमा किये जाने वाले अंश को घटा बढ़ा देने से भिन्न-भिन्न बैंकों पर भिन्न-भिन्न असर पड़ता है। दूसरे, यह तरीका तभी सफल हो सकता है कि जब बाज़ार में खुले तौर पर काम करने की नीति को सफल बनाने के लिये जिन परिस्थितियों का होना आवश्यक है वह सब परिस्थितियाँ इस तरीके को प्रयोग में लाने के लिये भी मौजूद हैं।

साख-पत्रों के मूल्य के उस अंश को घटाना-बढ़ाना जिसके बराबर उनकी बिना पर ऋण दिये जाते हैं—सन् १९३४ के साख-पत्र विनिमय विधान (Securities Exchange Act) के द्वारा फेडरल रिज़र्व प्रणाली को साख नियन्त्रण का एक अन्य तरीका भी बतला दिया गया है, अर्थात् साख-पत्रों के मूल्य के उस अंश को घटाना-बढ़ाना जिसके बराबर उसकी बिना पर ऋण दिये जाते हैं। जैसा कि स्पष्ट है इसका उद्देश्य साख-पत्रों की सट्टेबाज़ी को रोकना है। सन् १९३६ में मंडल (Board) ने बैंकों और दलालों के लिये यह आवश्यक कर दिया था कि वह लोग साख-पत्रों के जमानत पर अपने ग्राहकों को ऋण देते समय उनके मूल्य की कम से कम ५५ प्रतिशत की गुंजाइश अपने पक्ष में रख ले। फिर, सन् १९३७ के नवम्बर में यह घटा कर ४० प्रतिशत कर दी गई थी। द्वितीय महायुद्ध के समय यह तरीका कई अन्य देशों में भी प्रयोग में लाया गया था।

विज्ञप्ति—सभी केन्द्रीय बैंक समय-समय पर किसी न किसी रूप में अवश्य कुछ न कुछ विज्ञप्ति करते रहते हैं। किन्तु साख नियन्त्रण के लिये इसका प्रयोग जितना संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में हुआ है उतना अन्य किसी भी देश में नहीं हुआ है। वरगैस के कथनानुसार फेडरल रिजर्व प्रणाली के अफसरों के वक्तव्यों की साख नियन्त्रण के लिये कभी-कभी तो उतना ही असर पड़ा है जितना कि शायद उनके प्रत्यक्ष दवाब का पड़ता। रीश बैंक ने भी इसका काफी प्रयोग किया है।

केन्द्रीय बैंकों का व्यापारिक चक्र (Business cycles)

रोकने की शक्ति

केन्द्रीय बैंकों के साख नियन्त्रण के कार्य के सम्बन्ध में यह तो पिछले अध्याय में ही बताया जा चुका है कि इसका एक उद्देश्य व्यापारिक चक्र के प्रभाव को कम करना अथवा उसको विल्कुल रोक देना भी है। साथ ही हम वहीं पर यह भी देख चुके हैं कि आज कल तो इस साख नियन्त्रण का पहिला उद्देश्य व्यापारिक कार्यों की वरावर स्वाभाविक तौर पर उन्नति करते रहना और तेजी मन्दी (Booms and slumps) को रोकना ही है, अन्य सब बातें तो बाद में आती हैं। अब, इस बात को समझने के पहिले कि केन्द्रीय बैंक इसमें कहाँ तक सफल हुये हैं, हमको यह भी समझ लेना चाहिए कि व्यापारिक चक्र, तेजी और मन्दी (Booms and slumps) के क्या अर्थ हैं। जहाँ तक व्यापारिक चक्र के प्रयोग का प्रश्न है वह इस लिये होने लगा है कि व्यापारिक कार्यों की जो घट-बढ़ होती है वह एक प्रकार से चक्र ही की तरह की है। बैसले मिचेल ने व्यापारिक चक्र की जो परिभाषा^१ दी है वह कुछ इस आशय की है :—यह व्यापारिक कार्यों का एक क्रमिक प्रसार और संकुचन है। इसमें यह आवश्यक नहीं है कि तेजी और मन्दी का परिवर्तन एक संकट के रूप में हो। इसमें दो

1. Business cycle is any single succession of expansion and contraction of business activity, i.e. between one period of prosperity and another or between one depression and another, irrespective of whether the transition from prosperity to depression is of the nature of a crisis or merely mild recession.--Wesley Mitchell.

तेजी की भी अवधि हो सकती है और दो मन्दी की भी अवधि हो सकती है। इसी विना पर एम० एच० डी काक इसमें चार प्रकार की गतिविधि को सम्मिलित करता है, अर्थात् उत्थान (Prosperity), वापिसी (Recession), झुकाव (Depression) और पुनरुत्थान (Revival)। इतमें से उत्थान की अवधि को तेजी की अवधि (Boom period) और झुकाव की अवधि को मन्दी की अवधि (Slum period) कहते हैं। जहाँ तक इसके कारणों का प्रश्न है वह द्रव्य सम्बन्धी (Monetary) और गैर द्रव्य सम्बन्धी (Non Monetary) दोनों हैं। अतः, द्रव्य सम्बन्धी कारण तो पूरी तरह से नहीं कुछ अंशों में अवश्य ही रोके जा सकते हैं। बात यह है कि उत्थान और प्रसार के समय के बाद जो वापिसी अथवा संकट का समय आता है वह केवल अत्याधिक सट्टेबाजी के कारण ही आता है। एम० एच० डी० काक ही के कथन के अनुसार उत्थान के और व्यवसाय की वृद्धि के समय जन-साधारण में साहस और आशा की भावना स्वाभाविक रूप से ही दृष्टिगोचर होने लगती है। ऐसे समय में व्यवसाय में आसानी से लाभ बढ़ाने के लिये व्यवसायी समुदाय अपनी बिक्री और उत्पादन को भी बढ़ाता है और उसके लिये बैंकों की सहायता प्राप्त करना चाहता है। इसका फल यह होता है कि बैंक उत्पादकों और अन्य व्यवसायियों को साख देते हैं और उत्पादक और व्यवसायी भी अच्छी परिस्थितियों से प्रभावित होकर अपने ग्राहकों को साख देते हैं। अतः, पूँजी की तुलना में व्यवसाय के अनुपात की उपभोग तथा उत्पत्ति के सामान के उत्पादन और व्यापार के परिमाण की उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाती है और चारों तरफ तेजी ही तेजी (Boom) दिखाई पड़ने लगती है। अब, यह लाभ की वृद्धि का, बढ़ते हुये व्यापार और उत्पादन का, अधिकाधिक सट्टेबाजी का और भूमि, सामान तथा साखपत्रों के मूल्योत्कर्ष का क्रम सदा के लिये तो नहीं बढ़ सकता। कभी न कभी तो विपरीत परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है और विलकुल उल्टा हो जाता है। वास्तव में सट्टे को रोकना ही चाहिये। इसमें सन्देह नहीं कि बैंकों के पास जन समुदाय की भावनाओं को रोकने के साधन तो नहीं हैं किन्तु वह ऐसे साख का नियन्त्रण करके उनके कार्यान्वित होने को तो रोक ही सकते हैं। कहना न होगा कि इससे वापिसी (Recession) भी रुक जाती है।

(६) कोई बैंक अपने ग्राहकों की चेकों को किन-किन परिस्थितियों में भुगतान किये बिना ही वापिस कर सकता है ?

(७) चेकों को भुगतान किये बिना ही वापिस करने पर बैंक प्रायः कौन-कौन से लिख भेजते हैं ? उनको मली भ्रांति समझाइये ।

(८) यदि कोई बैंक किसी चेक को भुगतान किये बिना ही गलती से लौटा दे तो उसके कौन-कौन से दायित्व हैं ? अपने उत्तर के साथ-साथ उपयुक्त उदाहरण भी दीजिये ।

(९) एक स्थानीय (Domiciled) बिल के भुगतान के सम्बन्ध में किसी बैंक के कौन-कौन से दायित्व हैं ? ऐसे बिलों को किन-किन परिस्थितियों में स्तिरस्कृत किया जा सकता है ।

(१०) एक रेखाङ्कित चेक की बसूली के सम्बन्ध में उसके बसूल करने वाले बैंक को कौन-कौन से अधिकार और दायित्व हैं ? इस सम्बन्ध में उसे जो वैधानिक वचन दी गई है, उसे स्पष्ट कीजिये ।

(११) रेखाङ्कन से आप क्या समझते हैं ? उसके भिन्न-भिन्न रूपों को बताइये । रेखाङ्कन का क्या उद्देश्य है ?

(१२) बैंकर के स्वत्व (Lien) से आप क्या समझते हैं ? इस सम्बन्ध में साधारण स्वत्व और विशेष स्वत्व के अन्तर को बताइये ।

(१३) बैंकों को किन विशेष प्रकार के ग्राहकों से काम करना पड़ता है ? उनको इनसे काम करने में किन बातों का ध्यान रखना चाहिये ?

अध्याय १०

ऋण के लिये बैंकों की उपयुक्त ज़मानतें

यह तो हम पहिले ही देख चुके हैं कि बैंक केवल अच्छी ज़मानतों के आकार पर ही ऋण देते हैं। वास्तव में इनके अनेकों रूप हैं। उनकी जो जोखिमें हैं उनको समझने के लिये हमको उनमें से प्रत्येक के विषय में बहुत ही अच्छी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिये। बैंकों को किसी प्रकार की ज़मानत पर भी काम करने के

समय बहुत ही सावधान रहना चाहिये। उनको न केवल यही देखना चाहिये कि जमानतें मूल्य की पक्की और शीघ्र ही बिक जाने वाली हैं वरन् यह भी देखना चाहिये कि उन पर के अधिकार अरक्षित नहीं होंगे।

बिना जमानत के ऋण (Clean advances)

कई बार जब कोई ग्राहक बहुत ही ऊँची साख का होता है और उसकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी होती है तब उसको केवल उसकी वैयक्तिक जमानत पर ही ऋण मिल जाता है अथवा उसके खाते में से उसको जमा की हुई रकम से अधिक रकम निकाल लेने का अधिकार प्रदान कर दिया जाता है। ऐसी अवस्था में बैंकर केवल उसकी ईमानदारी, चाल-चलन और उद्यत तथा व्यापाराना ढंङ्ग पर ही भरोसा रखता है। हाँ, कभी-कभी अपनी वचत के ध्यान से वह उसके लिखे हुए प्रण-पत्र पर किन्हीं एक अथवा दो स्वतन्त्र व्यक्तियों के हस्ताक्षर भी ले लेता है, जिससे उस ऋण के सम्बन्ध की उनकी भी वैयक्तिक जमानत हो जाती है। किन्तु समय पर ऋण की वसूली न होने पर मुख्य देनदार तो ऋण लेने वाला व्यक्ति ही होता है। बैंकर को जॉमिन के प्रति अपने अधिकारों का तभी प्रयोग करना चाहिये जब उसकी पूरी रकम देनदार की स्वयं की सम्पत्ति से न वसूल हो सके। ऐसे ऋणों को बिना जमानती ऋण (Clean advances) कहा जाता है।

अब उपर्युक्त जमानत जारी रहने वाली (Continuing) और विशेष (Specific) भी हो सकती है। जारी रहने वाली जमानत की अवस्था में जमानत करने वाला व्यक्ति एक विशेष रकम तक चाहे वह कितनी बार ही क्यों न ली दी जाय, दायी रहता है और विशेष जमानत की अवस्था में वह केवल एक ही बार दी हुई रकम पर दायी रहता है। मान लीजिये कि 'अ' पाँच सौ रुपये का ऋण लेता है, और कुछ ही दिनों बाद वह २०० रु० वापिस कर देता है, किन्तु फिर १०१ रु० ले लेता है। अब, उस पर ४०० रु० की बाकी बची है। अतः, जारी रहने वाली जमानत में जमानत करने वाला व्यक्ति ४०० रु० के लिये दायी है और वह उस २०० रु० का त्ताभ नहीं उठा सकता जो 'अ' ने पहिले वापिस किये थे। हाँ, विशेष

जमानत में वह ३०० रु० के लिये दायी होगा क्योंकि २०० रु० तो 'अ' ने वापिस कर दिये थे। इस अवस्था में उससे उन १०० रु० से कोई मतलब नहीं है जो 'अ' ने वाद में फिर लिये थे। जमानत करने वाला व्यक्ति जब जमानत की रकम दे देता है तब वह उस रकम को मुख्य देनदार से वसूल कर सकता है।

अतिरिक्त जमानत (Collateral Securities)

उधार लेने वाले व्यक्तियों को उधार रकम के सम्बन्ध में प्रायः कुछ अतिरिक्त जमानत भी जमा करनी पड़ती है। अतिरिक्त जमानत किसी भौतिक पदार्थ की अथवा उनके सम्बन्ध के अधिकार-पत्रों की हो सकती है। यह जमानत वैयक्तिक जमानत के अतिरिक्त होती है और इसीलिये अतिरिक्त जमानत कहलाती है। वास्तव में इनको बेचकर ऋण की वसूली तभी की जा सकती है जब देनदार उसको वैसे ही देने से इन्कार कर दे अथवा न दे। यह अतिरिक्त जमानत स्वत्व (Lien) के अथवा गिरवी (Pledge) के अथवा रेहन (Mortgage) के रूप में हो सकती है।

स्वत्व में जमानत को अपने पास रोक रखने का अधिकार है, उसको बेचा नहीं जा सकता। हाँ, यदि ऐसा करना है तो पहिले अदालत से डिक्री प्राप्त करनी पड़ती है और फिर उस डिक्री में उस चीज को कुर्क करवाना पड़ता है और तब बेचा जा सकता है। किन्तु पूर्ण रूप से अच्छा अधिकार देने वाले पत्रों की जमानतों में जैसे देखनहार वारण्ट, शेयर वारण्ट, स्टॉक और सर्टीफिकेट, देखनहार और रजिस्टर्ड ऋण-पत्र, विनिमय के विल, प्रण-पत्र और चेकों में बैंक के स्वत्व में देनदार को उचित सूचना देकर इनको बेच लेने का भी अधिकार है। जहाँ तक अन्य अधिकार-पत्रों का प्रश्न है उनमें अवश्य यह अधिकार नहीं है। उनको केवल रोका जा सकता है।

गिरवी की हालत में बैंक को जमानतों को रोकने और फिर उचित सूचना देकर बेचने का भी अधिकार है। अतः, स्वत्व और गिरवी में पूर्ण रूप से अच्छा अधिकार देने वाले पत्रों को छोड़कर शेष में यही अन्तर है कि जब एक में जमानत की वस्तुओं को केवल रोका ही जा सकता है, दूसरे में उसको बेचा और रोका दोनों जा

सकता है। इसका यह निष्कर्ष है कि गिरवी-स्वत्व से अधिक अच्छा है।

जब जमानत अचल सम्पत्ति की दी जाती है तब उसका रेहन करवाना पड़ता है। इसमें स्वत्व और गिरवी के विपरीत जमानत को वस्तु का कब्जा लेनदार का नहीं हो जाता। वह या तो देनदार का ही रहता है अथवा देनदार जिसको चाहता है उसका रहता है। इसमें प्रायः स्वामित्व अवश्य हस्तान्तरित हो जाता है। स्वत्व और गिरवी में जैसा कि हमको मालूम है कब्जा तो प्रायः बदल जाता है किन्तु स्वामित्व नहीं बदलता। किन्तु यहाँ पर जो कुछ रेहन के विषय में कहा गया है वह केवल वैधानिक रेहन (Legal Mortgage) के लिये ही लागू है। वास्तव में रेहन कई प्रकार के होते हैं, किन्तु यहाँ पर हमें केवल वैधानिक रेहन (Legal Mortgage) और सादे रेहन (Equitable Mortgage) के विषय में ही समझना है। वैधानिक रेहन रेहननामे के आधार पर होता है जिसको लिखने के लिये एक सरकारी कागज का प्रयोग किया जाता है और जो रेहन के रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड करवाया जाता है। इसके विपरीत सादा रेहन (Equitable Mortgage) में केवल अधिकार-पत्रों को अकेले ही अथवा एक स्मरण-पत्र (Memorandum) के साथ अथवा केवल स्मरण-पत्र (Memorandum of Charge) को ही जिसके पास रेहन रक्खा जाता है उसको सौंप दिया जाता है। अतः, दोनों में यह अन्तर है कि जब कि पहिले में रेहन की सम्पत्ति का स्वामित्व जिसके पास वह रेहन की जाती है उसका हो जाता है और इसी से ऋण की अदायगी न होने पर उसको उसे बेच लेने का अधिकार रहता है, दूसरे में ऐसा नहीं हो पाता। इसमें जिसके पास रेहन रक्खा जाता है उसे पहिले अदालत की शरण लेनी पड़ती है, और उसकी आज्ञा प्राप्त करने के बाद ही वह उसको बेच सकता है। सादा रेहन (Equitable Mortgage) भारतवर्ष में केवल कलकत्ते, मद्रास, बम्बई, कराची और उन शहरों में ही किया जा सकता है जिनको गवर्नर जनरल समय-समय पर गज़ट में निकालता है। वैधानिक रेहन में भी ऋण की अदायगी के बाद रेहन रखने वाले को रेहन रक्खी हुई सम्पत्ति को फिर से स्वामित्व प्राप्त हो जाता है।

रेहन रखने वाले के इस अधिकार प्राप्ति के दावे को छुटकारे का दावा (Equity of Redemption) कहा जाता है।—

अतिरिक्त जमानतों के विभिन्न रूप

अतिरिक्त जमानते विभिन्न रूप की हो सकती हैं जो निम्ना-
द्वित है :—

(१) स्टॉक एक्स्चेञ्ज में विक्रय के पत्र

इनमें सरकार के और कम्पनियों के दोनों के पत्र आ जाते हैं। ये (अ) पूर्ण रूप से अच्छा अधिकार देने वाले हस्तान्तरित होने वाले (Fully Negotiable Convertible) और (ब) अच्छा अधिकार न देने वाले हस्तान्तरित न होने वाले (Non-negotiable Inconvertible) दोनों होते हैं। हस्तान्तरित न होने वाले स्टॉक फिर से रजिस्टर में स्वयं हस्ताक्षर करने पर हस्तान्तरित होने वाले (Inscribed) और हस्तान्तर-पत्र (Transfer deed) भरकर हस्तान्तरित होने वाले (Registered Stocks and Shares) स्टॉकों में विभाजित किये जा सकते हैं। पूर्ण रूप से अच्छा अधिकार देने वाले स्टॉक दूसरों को देकर अथवा बेचान करके हस्तान्तरित किये जा सकते हैं। हस्तान्तरित न होने वाले वह स्टॉक जो रजिस्टर में स्वयं हस्ताक्षर करने पर हस्तान्तरित किये जा सकते हैं (Inscribed) वह हैं जिनको हस्तान्तरित करने के लिये हस्तान्तरकर्ता को स्वयं कम्पनी में जाकर अथवा अपने किसी प्रतिनिधि को भेजकर कम्पनी के रजिस्टर में हस्ताक्षर करना पड़ता है। अतः, यह दूसरों को देकर अथवा बेचान करके हस्तान्तरित नहीं किये जा सकते। इसलिये इनके रेहन रखने जाने पर बैंकर को इन पर अपना पूरा अधिकार प्राप्त करने के लिये इनके मालिक से इनके हस्तान्तरित किये जाने के प्रमाण स्वरूप कम्पनी के रजिस्ट्रों में हस्ताक्षर करवा लेने चाहिये। जहाँ तक हस्तान्तर-पत्र को भरकर हस्तान्तरित होने वाले स्टॉकों (Registered stocks) का प्रश्न है उनके हस्तान्तर होने का प्रमाण उनको निकालने वाली कम्पनी एक मुहरबन्द प्रमाण-पत्र दे-

कर देती है और वह वैधानिक तौर से (Legal transfer) अथवा सादे तौर से (Equitable charge) हस्तान्तरित किये जा सकते हैं। वैधानिक तौर से हस्तान्तरित करने के लिये (Legal transfer) एक हस्तान्तर-पत्र लिखना अथवा लिखकर मोहर करवाना पड़ता है और जब उसका प्रमाण-पत्र (Certificate) हस्तान्तर-पत्र के सहित कम्पनी के पास पहुँच जाता है तब वह उसके अधिकारी के स्थान पर बैंकर का नाम दर्ज करके बैंकर को एक दूसरा प्रमाण-पत्र (Certificate) भेज देती है। इसके विपरीत सादे तौर से हस्तान्तरित करने के लिये (Equitable charge) प्रमाण-पत्र (Certificate) को जमा करने के एक स्मरण-पत्र (Memorandum of deposit) के सहित अथवा उसके बिना अथवा हस्तान्तरित करने के एक स्मरण-पत्र (Memorandum of transfer) के सहित अथवा उसके बिना तथा एक सादे हस्तान्तर-पत्र पर हस्ताक्षर करके बैंकर के पास जमा कर देना पड़ता है। जब प्रमाण-पत्र (Certificates) जमा किये जाते हैं तब उनके साथ प्रायः जमा का एक स्मरण-पत्र (Memorandum of deposit) और हस्ताक्षर किया हुआ एक सादा हस्तान्तर-पत्र (Duly Executed Blank Transfer) अवश्य रहता है। बात यह है कि जब इससे बैंकर के लिये यह सुविधा हो जाती है कि जब उसकी ऋण की रकम वसूल नहीं होती तब वह हस्ताक्षर किये हुये सादे हस्तान्तर-पत्र को भरकर स्टार्कों को कम्पनी को सूचना देकर अपने नाम से हस्तान्तरित करवा लेता है। इसके विपरीत जब केवल प्रमाण-पत्र ही जमा रहते हैं अथवा उनके साथ जमा का स्मरणपत्र भी होता है, तब उधार की रकम के न मिलने पर बैंकर देनदार को बुलवाकर उससे स्टार्कों को वैधानिक तौर से हस्तान्तरित करने को कहता है और उसके ऐसा न करने पर अदालत से उनके हस्तान्तर करने की और बेचने की आज्ञा प्राप्त करता है। कहना न होगा कि इसमें उसको बहुत असुविधा होती है। अतः इस तरह की प्रमानत प्रायः चालू नहीं है।

स्टाक एक्सचेंज में बिकने वाले पत्र

पूर्ण रूप से अच्छा अधिकार देने वाले स्टॉक—हस्तान्तरित होने वाले स्टॉक (इनको दूसरों को देकर अथवा बेचान करके हस्तान्तरित किया जा सकता है)

पूर्ण रूप से अच्छा अधिकार न देने वाले स्टॉक—हस्तान्तरित न होने वाले स्टॉक

रजिस्टर में स्वयं हस्ताक्षर करने पर हस्तान्तरित होने वाले स्टॉक (Inscribed stocks) इनको दूसरों को देकर अथवा बेचान करके हस्तान्तरित नहीं किया जा सकता । इनके अधिकारी को स्वयं अथवा किसी प्रतिनिधि से कम्पनी के रजिस्ट्रारों में हस्ताक्षर करवाने पड़ते हैं ।

हस्तान्तर-पत्र भरकर हस्तान्तरित होने वाले स्टॉक (Registered stocks and shares)

वैधानिक तौर से हस्तान्तरित होना (Legal transfer) —इसमें हस्तान्तर-पत्र भरकर कम्पनी में भेजना पड़ता है ।

सादे तौर से हस्तान्तरित होना (Equitable charge)

इसमें प्रमाण-पत्र जमा के अथवा हस्तान्तर करने के स्मरण-पत्र के साथ अथवा किसी ऐसे पत्र के बिना ही और एक सारे हस्ताक्षर किये हुये हस्तान्तर-पत्र के साथ रख दिया जाता है ।

गुण—(१) ये आसानी से और शीघ्रतापूर्वक वसूल किये जा सकते हैं ।

(२) इनकी वास्तविक बाजार कीमत आसानी से मालूम की जा सकती है ।

(३) इनकी कीमत बहुत नहीं घटती-बढ़ती ।

(४) इनके स्वामित्व में कोई भगड़ा नहीं होता । अतः, यह आसानी से बेचे जा सकते हैं ।

(५) पूर्ण रूप से अच्छा अधिकार देने वाले स्टार्कों के सम्बन्ध में यदि उनको अच्छी नीयत से और उनकी पूरी कीमत चुकाकर प्राप्त किया गया है तो बैंकर के पास उनका अच्छा अधिकार रहता है, और जब तक उसके ऋण की रकम का भुगतान नहीं हो जाता वह उनको प्रत्येक व्यक्ति के विरोध में भी अपने पास रख सकता है ।

(६) यदि बैंकर को द्रव्य की आवश्यकता पड़ती है तो वह इनको केन्द्रीय बैंक में रखकर इन पर ऋण प्राप्त कर सकता है ।

दोष—(१) जिन हिस्सों अथवा ऋण-पत्रों पर आंशिक भुगतान हुआ है उन पर कुछ और भुगतान माँगा जाने पर बैंकर को उस भुगतान को देना पड़ सकता है, क्योंकि भुगतान के न पहुँचने पर उनके जन्त हो जाने का डर रहता है ।

(२) कुछ कम्पनियों की यह शर्त होती है कि हिस्सेदार के ऊपर कम्पनी की कोई भी रकम बाकी रहने पर वह उसके हिस्से से वसूल की जायगी । यदि ऐसा है और बैंकर को यह नहीं मालूम है कि हिस्सेदार के ऊपर कम्पनी की कोई रकम चाहिये तो बाद में अपनी रकम वसूल करते समय उसको यह मालूम होने पर कि पूरी रकम वसूल नहीं की जा सकती उसे हानि हो सकती है ।

(३) जब यह पूर्ण रूप से अच्छा अधिकार देने वाली हस्तान्तरित होने वाली नहीं होती तब इनके हस्तान्तर करवाने में बड़ी कठिनाई पड़ती है । ऐसी अवस्था में बैंकर का अधिकार हस्तान्तरकर्ता के अधिकार की ही तरह का होता है, और उसके दूषित होने पर उसका अधिकार भी दूषित हो जाता है ।

सावधानियाँ—स्टॉक एक्सचेंज में बिकने वाले पत्रों की जमानतों के सम्बन्ध में यदि निम्न बातों का ध्यान रक्खा जाय तो उनके सब दोष दूर हो सकते हैं ।

(१) यथा सम्भव गुंजाइश देनी चाहिये । जब कभी भी मूल्य गिर जाय और अधिक जमानत माँग लेनी चाहिये ।

(२) आंशिक भुगतान वाले हिस्सों और ऋण-पत्रों को कभी नहीं लेना चाहिये ।

(३) अच्छा अधिकार न देने वाले पत्रों की अवस्था में पहिले से हस्तान्तर करवा लेना चाहिये ।

(४) सट्टे वाले हिस्सों को नहीं लेना चाहिये ।

[२] अच्छा अधिकार देने वाले पुरज़े

हमको यह तो ज्ञात ही है कि विनिमय के विलों को बैंकों से भुनवाया जा सकता है । अतः, जब वह ऐसा करते हैं तब उन पर उन्हें पूरे अधिकार मिल जाते हैं जिससे वे उनको बेच भी सकते हैं और दूसरों से फिर से भुना भी सकते हैं । हाँ, यदि यह गिरवी रखे जाते हैं तो बैंकर ऐसा नहीं कर सकता । उसे इन्हें इनके पकने तक अपने पास रखना ही पड़ता है । अतः, बैंकर के विचार से तो इनको उसके हाथ बेच देना ही अच्छा है, गिरवी रखना नहीं ।

गुण—(१) यदि बैंकर ने इनको अच्छी नीयत से प्राप्त किया है तो उसका इन पर अच्छा अधिकार ही रहता है ।

(२) इनका मूल्य निर्धारित रहता है ।

(३) इनको फिर से भुनाया जा सकता है ।

(४) इनके पकने पर द्रव्य का मिलना निश्चित है ।

दोष—इनके पकने पर बैंकर को इनकी बसूली करनी पड़ती है ।

सावधानियाँ—जहाँ तक हो सके इनको भुना दिया जाय गिरवी न रक्खा जाय ।

[३] माल अथवा माल के अधिकार-पत्र

जब माल बैंकर के यहाँ गिरवी रक्खा जाता है तब या तो वह उसी के गोदाम में ले आया जाता है या उधार लेने वाले के पास ही छोड़ दिया जाता है । यदि वह उधार लेने वाले के पास ही छोड़ दिया जाता है तो उसके गोदाम की तालियाँ अवश्य बैंकर को ही दे दी जाती हैं । दोनों ही स्थितियों में माल का बीमा कराना पड़ता है और उसका खर्च उधार लेने वाले को देना पड़ता है । जब माल बैंकर के गोदाम में रक्खा जाता है तब वह उसका किराया भी ले लेता है । माल के अधिकार-पत्रों को भी गिरवी रक्खा जा सकता

है। इन में जहाजी बिल्टी (Bill of lading) डाक पत्र (Dock-warrant), गोदाम वालों के प्रमाण-पत्र (Warehouse keeper's certificates) घटवारे का प्रमाण-पत्र (Wharfinger's certificate), रेल की बिल्टी (Railway Receipt), माल देने के लिये आदेश-पत्र तथा ऐसे ही कोई अन्य कागजात जो माल के स्वामित्व को हस्तान्तरित करने में काम में लाये जाते हैं सम्मिलित हैं।

गुण—(१) माल और माल के सम्बन्ध के कागजात एक प्रकार से स्वयं वास्तविक वस्तु हैं अथवा उनके प्रतिनिधि हैं, अतः, जमानत के लिये बहुत अच्छे हैं।

(२) इनके मूल्य बहुत नहीं घटते-बढ़ते।

(३) इनको बहुत आसानी से बेचा जा सकता है।

(४) इनकी जमानत पर जो ऋण दिया जाता है उसके अवश्य-मेव भुगतान होने की सम्भावना रहती है। बात यह है कि वह द्रव्य इन्हीं के क्रय के लिये लिया जाता है और इन्हीं के बिक्रय पर वापिस कर दिया जाता है।

(५) इनका मूल्य आसानी से मालूम हो जाता है।

दोष—(१) माल खराब हो सकता है।

(२) इनके मूल्य में दैनिक परिवर्तन होता है। हाँ, यह परिवर्तन बहुत अधिक नहीं होता।

(३) कभी-कभी एक ही माल कई किस्म का होता है। अतः इसमें धोखा दिया जा सकता है।

(४) कुछ माल को रखने में बहुत जगह की आवश्यकता पड़ती है।

(५) इसमें चोरी हो जाने की भी बड़ी आशंका रहती है।

(६) इनको देनदार थोड़ी-थोड़ी रकम देकर थोड़े-थोड़े परिमाण में उठाता रहता है। अतः, माल देने में गलती हो सकती है।

(७) माल सम्बन्धी अधिकार-पत्रों में जालसाजी की बड़ी गुञ्जाइश रहती है।

भारतवर्ष में इनके प्रिय न होने के कारण—(१) यहाँ पर लाइलेन्स प्राप्त गोदाम नहीं के बराबर हैं।

(२) प्रायः माल की उचित किस्में निर्धारित नहीं हैं और जहाँ पर ऐसा है भी वहाँ पर उनका उचित ध्यान नहीं रक्खा जाता।

(३) बहुत-सी जगहों में बहुत-सी चीजों के संगठित बाजार नहीं हैं। अतः, उनके मूल्य का पता लगाने में असुविधा होती है।

सावधानियाँ—(१) जिस माल के खराब हो जाने की अधिक सम्भावना है उसको नहीं रखना चाहिये और यदि वह रक्खा भी जाय तो उसका बीमा करवा लेना चाहिये। जहाँ तक माल के खराब हो जाने का डर है, सोना-चाँदी खराब नहीं होता है, अतः वह सर्वोत्तम है।

(२) माल के मूल्य का बराबर पता लगाते रहना चाहिये। वास्तव में उधार देने समय ही यथेष्ट मुझाइश रख लेनी चाहिये और यदि मूल्य बहुत कम हो जाय तो और अधिक अतिरिक्त जमानत मँगवा लेनी चाहिये।

(३) जो माल रक्खा जाय उसकी किस्म को समझ लेने के लिये एक बहुत ही अनुभवी व्यक्ति को रखना चाहिये।

(४) जब माल छोड़ा जाय तब बहुत निगाह रखनी चाहिये। जहाँ तक हो सके इसके लिये एक अलग गुमाश्ता होना चाहिये।

(५) माल सम्बन्धी कागज़ों पर उधार देने के पहिले उनकी वास्तविकता का पता लगा लेना चाहिये। साथ ही उनके वास्तविक अधिकारी की भी जाँच-पड़ताल करा लेनी चाहिये।

(६) बैंकर को वही माल लेने चाहिये जिनको वह अपने गोदाम में आसानी से रख सकता हो। यदि माल ऋणी के ही गोदाम में छोड़ दिया जाता है तो उसके गोदाम की जाँच करवा लेनी चाहिये और उसके दोषों को दूर करवा देना चाहिये। खत्तियों में कच्ची खत्तियों की तुलना में पक्की खत्तियाँ कहीं अच्छी होती हैं।

(७) सबसे आवश्यक तो यह है कि बैंकर को ऋण लेने वाले की ईमानदारी, इत्यादि का पता लगा लेना चाहिये। जो काम वह करता हो उसमें उसे होशियार होना चाहिये।

(८) बैंकर को अपने ग्राहकों के कर्मचारियों इत्यादि को उधार देते समय बहुत सावधान रहना चाहिये । प्रायः इनके अधिकार सीमित रहते हैं ।

(९) माल के गिरवी रखे जाने का प्रमाण बराबर लिखित रूप में ले लेना चाहिये ।

(१०) जहाजी बिल्टी (Bill of lading) की कई प्रतिलिपियाँ होती हैं । अतः, सबको ले लेना चाहिये जिससे जाल न किया जा सके ।

[४] जान बीमा-पत्र

बीमे का प्रस्ताव पत्र भरते समय यदि कोई बात गलत नहीं लिखी गई है तो जान बीमा-पत्र के आधार पर उसके परित्यज्य मूल्य (Surrender Value) तक की रकम बहुत ही अच्छी तरह से उधार दी जा सकती है । किन्तु बैंकों के पास प्रायः जो जमानतें रहती हैं उनमें यह बहुत अधिक मात्रा में नहीं पाया जाता । बात यह है कि बीमा कम्पनियों के स्वयं ही बीमा-पत्रों के आधार पर रकम उधार देने के लिये तैयार रहने के कारण अधिकांश में इनके आधार पर उन्हीं से ऋण ले लिया जाता है और इसमें बीमा कम्पनियों को तथा उधार लेने वाले दोनों को बहुत ही सुविधा रहती है । इनका भी वैधानिक रेहन (Legal mortgage) अथवा सादा रेहन (Equitable mortgage) हो सकता है । सादे रेहन में बीमा-पत्र दे दिया जाता है, चाहे साथ में जमा करने का स्मरण-पत्र दिया जाय अथवा नहीं । इसके विपरीत वैधानिक रेहन में एक बेची-पत्र (Deed of assignment) भी भरा जाता है जिसमें मूल धन और ब्याज के देने का वायदा रहता है और बीमा-पत्र की ऋण की अदायगी हो जाने पर छुटकारे की शर्त के साथ उसकी बेची भी रहती है ।

गुण—(१) इनका त्याज्य मूल्य आसानी से मालूम किया जा सकता है । प्रायः, इनकी पीठ पर इसको निकालने का तरीका दिया रहता है । साथ ही बीमा कम्पनी से भी इसका पता लगाया जा सकता है ।

(२) यदि बीमे का प्रतिफल बराबर चुकता होता रहता है तो इनका त्याग्य मूल्य भी बराबर बढ़ता जाता है ।

(३) यदि बीमा-पत्र स्मरण-पत्र के बिना ही जमा कर दिया जाता है तो भी ऋण लेने वाले के दिवालिया हो जाने पर पहिले बैंकर को बीमा-पत्र से ऋण की रकम वसूल करने का अधिकार रहता है और फिर उसके बाद सरकार द्वारा निर्धारित इतिकर्ता का अधिकार होता है ।

(४)-ऋण लेने वाले के एक विशेष आयु पर पहुँचने पर अथवा मर जाने पर उसका जान बीमा-पत्र स्वयं ही पक जाता है ।

(५) यदि जान बीमा-पत्र की बेची हो गई है और बीमा-कम्पनी को सूचना दी जा चुकी है तो यह पूर्ण रूप से सुरक्षित रहता है । इसमें अधिकार के खराब होने का प्रश्न नहीं उठ सकता ।

(६) आवश्यकता पड़ने पर बैंकर इसकी बेची किसी अन्य धनी के नाम भी कर सकता है ।

दोष—(१) यदि प्रस्ताव-पत्र ठीक नहीं भरा गया था तो बीमा-पत्र के पकने पर वह अवैध ठहराया जा सकता है ।

(२) यदि बीमा कराने वाले बी आयु का प्रमाण बीमा कम्पनी के द्वारा पहिले से स्वीकृत नहीं कराया जा चुका है तो बीमा कराने वाले की मृत्यु पर बैंकर को ऐसा कराने में कठिनाई पड़ सकती है ।

(३) प्रायः आत्महत्या और न्यायालय की ओर से फाँसी की सजा बीमा-पत्रों के अन्दर नहीं सम्मिलित होती ।

(४) बीमा प्रायः विधवा और बच्चों के हित के लिये करवाया जाता है । अतः, बैंक के लिये उसकी रकम लेना भलमनसाहत नहीं समझी जाती ।

(५) बीमे का मूल्य उसका प्रतिफल देने से ही बढ़ता है । अतः, यदि बीमा कराने वाला यह प्रतिफल नहीं देता तो उसको बैंक को देना पड़ सकता है ।

(६) यदि बीमा किसी अन्य व्यक्ति ने करवाया है तो जिसकी

जान का बीमा हुआ है उसकी जान में बीमा कराने वाले की 'आर्थिक दिलचस्पी' न होने के कारण बीमा अवैध सिद्ध हो सकता है।

(७) यदि बीमा-पत्र नहीं ले लिया गया है तो वह किसी और के नाम बेचा जा सकता है। वास्तव में जो व्यक्ति भी पहिले बीमा कम्पनी को बीमे की बेची की सूचना दे देता है वही उसको पाने का हकदार समझा जाता है।

सावधानियाँ--(१) बैंकर को यह बात देख लेनी चाहिये कि जिसका जान बीमा कराया गया है उसकी आयु के प्रमाण को बीमा कम्पनी ने मान लिया है।

(२) उसको यह भी देख लेना चाहिये कि बीमा कराने वाले की जिसका जान बीमा कराया गया है उसकी जान में बीमा कराने के समय आर्थिक दिलचस्पी थी।

(३) उसको सादे रेहन की अपेक्षाकृत वैधानिक रेहन पर अधिक जोर देना चाहिये।

(४) उसको इस बात को देखते रहना चाहिये कि प्रतिफल देने की रसीदें बराबर उसके यहाँ जमा होती रहती हैं और प्रतिफल बराबर दिया जाता है।

(५) उसको बीमा कम्पनी को रेहन की सूचना दे देनी चाहिये और इस बात का पता लगा लेना चाहिये कि वह पहिले से तो रेहन नहीं थी।

(६) बैंकर की दृष्टि से एक निश्चित अवधि पर अथवा यदि उससे पहिले मृत्यु हो जाय तो उस पर पकने वाला बीमा (Endowment) केवल मृत्यु पर पकने वाले बीमे (Whole life) की अपेक्षाकृत कहीं अधिक अच्छा है।

(७) कुँवारी स्त्रियों के बीमे के सम्बन्ध में उनका विवाह हो जाने पर बीमा-पत्र के ऊपर विवाह की बात लिखवा लेनी चाहिये।

(८) प्रत्येक बीमा-पत्र की सब धाराओं को अपने अधिकार और दायित्व को समझने के लिये बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिये।

अचल सम्पत्ति

जब अचल सम्पत्ति जमानत की तौर पर दी जाती है तब उसका

रेहन-नामा होता है और जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है यह रेहन-नामा प्रायः वैधानिक होता है क्योंकि सादा रेहन-नामा तो हमारे यहाँ कुछ विशेष शहरों को छोड़कर अन्य शहरों में होता ही नहीं और न उसमें सम्पत्ति के बेचने का ही अधिकार रहता है। अचल सम्पत्ति-सम्बन्धी अधिकार-पत्रों को भी भली भाँति जँचवा लेना चाहिये अन्यथा उन पर का अधिकार झूठा प्रमाणित हो सकता है। उनके मूल्य को भी भली भाँति अँकवा लेना चाहिये और उनका बीमा भी करवा लेना चाहिये।

गुण—सत्य तो यह है कि अचल सम्पत्ति में ऐसा कोई गुण ही नहीं है जिससे कि वह जमानत के तौर पर स्वीकृत की जाय, किन्तु प्रायः ऐसे ग्राहक मिलते हैं जिनके पास इनको छोड़कर और कोई चीज जमानत के तौर पर देने के लिये निकलती ही नहीं। अतः इनको स्वीकार करना ही पड़ता है।

दोष—(१) वैधानिक रेहन में तो बहुत ही खर्च पड़ता है और वह असुविधाजनक भी होता है, और सादा रेहन कुछ विशेष शहरों को छोड़कर अन्य शहरों में हो ही नहीं सकता।

(२) अचल सम्पत्ति के वास्तविक अधिकारी का पता लगाना बहुत ही कठिन है। बात यह है कि हमारे देश में हिन्दुओं और मुसलमानों दोनों के उत्तराधिकार सम्बन्धी नियम बहुत ही टेढ़े-मेढ़े हैं।

(३) अचल सम्पत्ति के मूल्य को ठीक-ठीक अँक लेना बहुत ही कठिन हो जाता है, और यह भी घटता-बढ़ता रहता है।

(४) इसको बेचने में बहुत ही असुविधा होती है, क्योंकि इसमें बहुत सी वैधानिक कार्रवाईयाँ करनी पड़ती है। फिर इनको खरीदने वाले भी मुश्किल से ही मिलते हैं और भिन्न-भिन्न व्यक्ति इनके भिन्न-भिन्न मूल्य लगाते हैं।

(५) कुछ मकान मरम्मत, इत्यादि के न होने के कारण बहुत जल्दी ही खराब हो जाते हैं।

(६) ऋण की अदायगी न होने पर जिस दिन से जमानत पर रक्खे गये मकान इत्यादि बैंक के हाथ में आ जाते हैं, उस दिन से

उसको उनमें किरायेदार रखने और उनकी मरम्मत कराने के दायित्व अपने ऊपर लेने पड़ते हैं।

(७) इनके अधिकार-पत्रों की वास्तविकता का पता लगाना बहुत ही कठिन हो जाता है।

(८) जहाँ पर जमीन पट्टे पर होती है वहाँ पर किराया न पहुँचने पर पट्टे की समाप्ति की आशंका रहती है।

(९) इसके आग से नष्ट हो जाने का डर रहता है।

सावधानियाँ—(१) अचल सम्पत्ति लेते समय ऋण लेने वाले के उस पर के अधिकार का भली भाँति से पता लगा लेना चाहिये।

(२) अधिकार-पत्रों को अच्छी तरह से जँचवा लेना चाहिये।

(३) भविष्य में मरम्मत, इत्यादि के लिये प्रबन्ध कर लेना चाहिये।

(४) पट्टे की सम्पत्ति के सम्बन्ध में किराया देने का प्रबन्ध हो जाना चाहिये।

(५) इसका आग बीमा करवा लेना चाहिये, और ऋण लेने वाले से वार्षिक प्रतिफल देने का जिम्मा भरवा लेना चाहिये।

(६) जहाँ तक हो एक रेहन के बाद दूसरा रेहन नहीं स्वीकार करना चाहिये, और यदि दूसरे रेहन की सूचना मिल जाय तो फिर और रकम उधार नहीं देनी चाहिये।

प्रश्न

(१) 'उधार' (Advances) से आप क्या समझते हैं ? चालू (Continuing) और विशेष (Specific) जमानतों को भली भाँति समझाइये।

(२) अतिरिक्त जमानत (Collateral securities) से आप क्या समझते हैं ? ये किस प्रकार की होती हैं ? इनमें से प्रत्येक के विषय में बताइये।

(३) बैंक प्रायः किस प्रकार की अतिरिक्त जमानतों को ले लेते हैं ? प्रत्येक की विशेषताओं पर छोटी-छोटी टिप्पणियाँ लिखिये।

(४) बैंक की दृष्टि से स्टॉक एक्सचेंज में बिकने वाले साख-पत्रों

की जमानत कैसी होती है ? इसके दोषों को कम करने के लिये अपने सुझाव लिखिये ।

(५) माल और माल के अधिकार-पत्रों के अतिरिक्त जमानत की तरह से प्रयोग में आने के गुण और दोषों को भली भाँति समझाइये । इनको लेने के समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिये ? भारतवर्ष में यह बहुत अधिक प्रिय क्यों नहीं हैं ?

(६) जान-बीमा-पत्रों को जमानत की तरह पर लेने में कौन-कौन से गुण और दोष हैं ? इनको लेने के समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिये ?

(७) 'अचल सम्पत्ति अच्छी जमानत नहीं है' इस बात को बैंकर की दृष्टि से समझाइये ।

(८) 'अच्छा अधिकार देने वाले पुजों को जहाँ तक सम्भव हो गिरवी की तरह से ही लेना चाहिये' इस पर अपने विचार लिखिये ।

अध्याय ११

बैंकों का निकासगृह (Clearing House)

बैंकों का निकासगृह वह संस्था है जहाँ स्थानीय बैंकों के पार-स्परिक लेन-देनों का निपटारा हो जाता है । जैसा कि छठे अध्याय में बताया जा चुका है यह काम प्रायः सभी केन्द्रीय बैंक या तो चलन के अनुसार करते आ रहे हैं या विधान ने उनको ऐसा करने के लिये बाध्य कर रक्खा है । जिन देशों में केन्द्रीय बैंकों की संस्थापना के बहुत पहिले ही से व्यापारिक बैंकों ने स्वयं ही अपने लेन-देनों का निपटारा करने के लिये प्रबन्ध कर लिया था अथवा जहाँ पर केन्द्रीय बैंकों ने इस काम को बहुत दिनों तक प्रारम्भ ही नहीं किया था वहाँ पर स्वतन्त्र निकासगृह स्थापित है और उनके स्वयं के नियम तथा काम करने के स्थान बने हुए हैं । हाँ, इतना अवश्य है कि वहाँ के केन्द्रीय बैंक भी इनके सदस्य हैं और साथ ही प्रत्येक दिन की निकासी के अन्त में बैंकों के जो शेष बचते हैं उनके निपटारे का भी प्रबन्ध वही करते हैं । अन्य देशों में तो वही निकासगृह के लिये स्थान देते हैं, वही काम करने के लिये नियम बनाते हैं, वही

उनकी निगरानी करते हैं और वही अन्त में बचे हुए शेष का निपटारा करते हैं। उपर्युक्त अध्याय में इस बात का भी संकेत कर दिया गया था कि बैंकों का अनुभव यह बतलाता है कि एक विशेष समय के अन्दर एक विशेष बैंक के ग्राहकों के द्वारा उस पर कटे हुये उन चेकों की रकम जो दूसरे बैंकों के द्वारा उसके यहाँ वसूली के लिये आती है उन चेकों का रकम के प्रायः बराबर होती हैं जो उसके पास दूसरे बैंकों के ऊपर की उसी ग्राहकों के द्वारा इसी काम के लिये आती है। वस्तुतः, बैंकों के निकासगृहों की स्थापना ही इसी सिद्धान्त के आधार पर की गई है।

काम करने का ढङ्ग

इनमें काम करने का ढङ्ग बहुत ही साधारण है। मान लीजिये कि अ, ब, स, और द नाम के चार बैंकों के बीच में निकासी का काम होना है। अब इनमें से प्रत्येक के पास जाने वाली निकासी के सम्बन्ध के विशेष तौर पर छपे हुये कागज (Summary sheets of out-clearing) रहते हैं जिनमें उन सभी चेकों और विलों, इत्यादि का लेखा कर लिया जाता है जिनकी एक बैंक को अन्य बैंकों से वसूली करनी होती है। अतः, यदि 'अ' बैंक को चेकों और ड्राफ्टों को छुट्टाने पर 'ब' बैंक के ऊपर के चेक और ड्राफ्ट मिलते हैं तो वह इन्हे उक्त कागज में 'ब' बैंक का नाम लिखकर लिख लेता है। इसी तरह से दूसरे बैंकों के ऊपर की रकमें भी अलग-अलग लिख ली जाती है। कहना न होगा कि वह प्रत्येक बैंक करता है। इसके बाद चेकों, इत्यादि को फिर से देखकर उनके अलग-अलग बण्डल बना लिये जाते हैं। फिर, इन बण्डलों को निकासगृह में ले जाया जाता है और चारों बैंकों के उनके निर्धारित स्थान में प्रत्येक दूसरा बैंक उनके ऊपर के इन बण्डलों को रख देता है। वहाँ पर इन बैंकों के कर्मचारी प्राप्त बण्डलों से उसी प्रकार के आने वाली निकासी के कागजातों (Summary sheets of in-clearing) में लेखे करते हैं जिस प्रकार इनके लेखे जाने वाली निकासी के कागजातों में पहिले किये गये थे। अब यदि 'अ' बैंक को 'ब' बैंक से जो पाना है वह उसको जो उसे देना है उससे अधिक है तब उसको उससे पाना है और यदि इसका उल्टा है तो उसको उसे देना है। अतः, प्रत्येक बैंक से अन्त में जो पाना है अथवा उसको देना है

वह एक साधारण चिट्ठे (General Balance-Sheet) में लिख लिया जाता है। इस चिट्ठे में निकासगृह के सब सदस्य बैंकों के नाम, उनके पाउने और देने के खानों के सहित छपे रहते हैं। अब, यदि किसी बैंक से पाना है तो वह पाउने के खाने में और यदि देना है तो वह देने के खाने में लिख लिया जाता है। अन्त में पाउने और देने के जोड़ों का शेष निकाल लिया जाता है, और यदि पाउना ज्यादा है तो केन्द्रीय बैंक से अपने एकाउण्ट को क्रेडिट करने (जमा करने) और यदि देना ज्यादा है तो अपने एकाउण्ट को डेबिट करने (नाम लिखने) को कह दिया जाता है। केन्द्रीय बैंक इन लेखों के दोहरे लेख निकासी के एकाउण्ट (Clearing) में करता है। अब, यदि सबका हिसाब ठीक है तो निकासी के एकाउण्ट में दोनों तरफ के लेख बराबर हो जाते हैं अन्यथा गलती ढूँढ़कर ठीक कर ली जाती है। अन्त में सब बैंक वाले अपने-अपने ऊपर की चेकों को अपने यहाँ ले जाते हैं और वहाँ पर उनकी जाँच-पड़ताल करके उनके लेखे कर लेते हैं और यदि वहाँ पर वह ठीक नहीं जँचती तो दूसरे दिन की निकासी में वह बाहर जाने वाली चेकों के साथ वापिस कर दी जाती है।

लाभ

इस सगठन से बैंकों और जनता दोनों को बहुत से लाभ हैं। बैंकों के लिये तो यह इस प्रकार से लाभदायक है कि उनको अपने कर्मचारियों को भिन्न-भिन्न बैंकों में नहीं भेजना पड़ता। केवल एक कर्मचारी निकासगृह में चला जाता है। फिर उनको व्यर्थ में नकदी में भुगतान नहीं करना पड़ता—एक तो प्रत्येक बैंक को भुगतान नहीं किया जाता, दूसरे सब बैंकों का मिलाकर भुगतान भी केवल केन्द्रीय बैंक में जो एकाउण्ट रहता है उसी में लेखा करने से हो जाता है। इससे यह भी लाभ होता है कि बैंकों को अपने पास बहुत कम नकदी रखनी पड़ती है। यह जनता के लिये भी बहुत लाभप्रद है। बात यह है कि इससे उसका बहुत कम नकदी से काम चल जाता है। फिर, इसके कारण चेकों, इत्यादि का जो प्रयोग बढ़ जाता है उससे भी जो साख की वृद्धि होती है उससे भी जनता का बड़ा लाभ होता है।

अंग्रेजी निकासगृह

जैसा कि छठे अध्याय में बताया जा चुका है, इंगलिस्तान में, लन्दन में और ग्यारह प्रान्तीय शहरों में स्वतन्त्र निकासगृह है। इनमें से लन्दन में और सात प्रान्तीय शहरों में तो जहाँ बैंक आफ इंगलैण्ड के अपने दफ्तर और शाखाएँ हैं बैंक अपनी पारस्परिक बाकी का निपटारा उनके बैंक आफ इंगलैण्ड में जो स्थानीय एकाउन्ट हैं उन पर चेकें काटकर कर लेते हैं। किन्तु उन चार शहरों में जहाँ निकासगृह तो हैं किन्तु बैंक आफ इंगलैण्ड के दफ्तर और शाखाएँ नहीं हैं ऐसा नहीं हो पाता। अतः, वहाँ पर यह काम उनके लन्दन स्थित प्रधान दफ्तर के जो एकाउन्ट बैंक आफ इंगलैण्ड में है उनके द्वारा करवाया जाता है।

लन्दन में निकासी का काम—लन्दन में निकासी का काम तीन भागों में विभक्त है। (१) शहर से सम्बन्धित निकासी (Town-clearing), (२) अन्य शहरों से सम्बन्धित निकासी (Country clearing) और (३) शहर के दूर स्थित स्थानों से अथवा बृहत् लन्दन से सम्बन्धित निकासी (Metropolitan clearing)

[१] शहर से सम्बन्धित निकासी के अन्तर्गत वह क्षेत्र आता है जो बैंक आफ इंगलैण्ड के दफ्तर से करीब है। इसकी प्रति दिवस प्रायः दो निकासी होती है, एक प्रातः और दूसरी मध्याह्न में। निकास-गृह का प्रत्येक सदस्य बैंक हर निकासी के समय प्रत्येक बैंक के ऊपर की अथवा उन बैंकों के ऊपर की चेकों के जिनके में सदस्य बैंक प्रति-निधि है प्रथम-प्रथम बण्डल बनाकर जिनको वहाँ पर चार्जेज (Charges) कहा जाता है निकासगृह के दफ्तर में भेज देता है। वहाँ पर ये आपस में बदले जाते हैं और फिर इनसे लेखे तैयार किये जाते हैं, और अन्त में जोड़, इत्यादि को ठीक करके बाकी निकाली जाती है। फिर वह साधारण चिट्ठे में प्रत्येक बैंक के नाम के आगे डेबिट (नाम) अथवा क्रेडिट (जमा) में जैसा होता है लिख ली जाती है। इसके बाद दोनों खानों को प्रथम-प्रथम जोड़कर उनकी बाकी निकाल ली जाती है। अब, प्रत्येक बैंक का केन्द्रीय बैंक में एकाउण्ट तो होता ही है। अतः, उसी एकाउण्ट में इस बाकी को डेबिट अथवा क्रेडिट करके जैसा होता है इसका निपटारा कर दिया जाता है।

[२] अन्य शहरों से सम्बन्धित निकासी के अन्तर्गत वृहत् (समूचे) लन्दन को छोड़कर इंग्लैन्ड और वेल्स में फैले हुए सभी वैकों और उनकी शाखाओं के चेकों की निकासी आ जाती है। लन्दन के बाहर जितने बैंक हैं प्रायः उन सर्वों ने लन्दन शहर में स्थित किसी न किसी बैंक को निकासी के लिये अपना प्रतिनिधि अवश्य बना रक्खा है। अतः, इनके पास उनके जो अन्य बैंकों के ऊपर के चेक, इत्यादि रहते हैं वह आ जाते हैं। इसमें भी निकासी का वही क्रम चलता है जो शहर से सम्बन्धित निकासी में चलता है। हाँ, यह निकासी प्रतिदिन केवल एक बार ही होती है और इसमें साधारण चिट्ठे से जो बाकी निकलती है वह सीधे-सीधे न निपटकर तीसरे दिन की शहर से सम्बन्धित निकासी के साधारण चिट्ठे में शामिल कर ली जाती है। इस दिने का कारण यह है कि ऊपर वाले बैंकों के प्रतिनिधि बैंक जो चेक पाने वाले बैंकों के प्रतिनिधि बैंकों से पाते हैं उन्हें वह ऊपर वाले बैंकों के पास भेजते हैं और वहाँ से उनके सकर जाने पर ही उन्हें निकासी में सम्मिलित करते हैं।

शहर से दूर स्थिति स्थानों से अथवा वृहत् लन्दन से सम्बन्धित निकासी बहुत बाद में प्रारम्भ हुई थी। इसमें उस क्षेत्र के बैंकों की चेकों की निकासी होती है जो न तो प्रथम और न दूसरे प्रकार की निकासी में सम्मिलित की जा सकती हैं। बात यह है कि वृहत् लन्दन का क्षेत्र बहुत बड़ा है। अतः, इससे लन्दन के उन बैंकों को सुविधा दी गई है जो बैंक आफ इंग्लैन्ड के दफ्तर से दूर पर स्थित हैं। ये बैंक इस क्षेत्र फल में स्थिति बैंकों की चेकों, इत्यादि को छाँटकर लन्दन शहर के अपने प्रतिनिधि बैंकों के पास भेज देते हैं जो उनको ऊपर वाले बैंकों के अपने यहाँ के प्रतिनिधि बैंकों के बडलों में शामिल कर लेते हैं। इस निकासी से सम्बन्धित साधारण चिट्ठे की बाकी भी दूसरे दिन की शहर से सम्बन्धित निकासी के साधारण चिट्ठे में शामिल कर ली जाती है। इसमें भी प्रतिनिधि बैंक प्राप्त चेकों को ऊपर वाले बैंकों के पास सकरने के लिये भेजते हैं जिसकी सूचना दूसरे दिन आ जाती है।

प्रत्येक निकासी की लौटी हुई चेक दूसरे दिन की उसी निकासी के लिये जाने वाली चेकों की निकासी में मिला दी जाती है।

एक बात और ध्यान देने की है कि शहर से सम्बन्धित और वृहत लन्दन से सम्बन्धित निकासी में चेकें और ड्राफ्ट दोनों सम्मिलित कर लिये जाते हैं किन्तु अन्य शहरों से सम्बन्धित निकासी में केवल चेके ही शामिल की जाती है ड्राफ्ट नहीं शामिल किये जाते ।

भारतवर्ष में निकासी

पाँचवें अध्याय में यह भी बताया गया था कि हमारे देश में भी रिजर्व बैंक की संस्थापना के पहिले से ही कई जगह स्वतंत्र निकास-गृह थे जिनमें कार्य की देख-रेख स्वभावतः इम्पीरियल बैंक ही अन्य सदस्य बैंकों की ओर से किया करता था । फिर रिजर्व बैंक की संस्थापना होने पर यह काम रिजर्व बैंक के पास आ गया । किन्तु फिर भी कलकत्ता और कानपुर दो ऐसे स्थान हैं जहाँ पर रिजर्व बैंक के क्रमशः दफ्तर और शाख के होने पर भी वहाँ के निकासगृहों की देख-रेख रिजर्व बैंक के जिम्मे नहीं है । हाँ, बाकी का निपटारा तो अवश्य बैंकों के जो इसके यहाँ एकाउन्ट हैं उन्हीं पर चेके काटकर होता है । जिन स्थानों में रिजर्व बैंक का दफ्तर अथवा शाख नहीं है वहाँ पर इम्पीरियल बैंक न केवल निकासगृह की देख-रेख करता है वरन् बाकी का निपटारा भी करता है । बैंकिंग प्रथा की उन्नति और चेकों के प्रयोग के आदत की वृद्धि के साथ-साथ यहाँ पर नये निकासगृहों की आवश्यकता पड़ेगी । कुछ बड़े शहरों में निकासी को लन्दन की तरह भागों में भी विभक्त करना पड़ेगा । किन्तु रिजर्व बैंक और बैंकों की संस्था इन बातों को समझती हैं । अतः, आवश्यकता पड़ने पर वह इनका प्रबन्ध करेंगी ।

अन्य देशों के निकासगृह

अमेरिका के निकासगृह बहुत लाभदायक काम करते हैं । वे जमा करने वालों को दिया जाने वाला न्यूनतम व्याज निश्चित करते हैं । साथ ही वे बैंकों को ऐसे प्रमाण-पत्र देते हैं जिनके आधार पर उन्हें ऋण प्राप्त हो सकता है, इत्यादि, इत्यादि । यूरोप में भी प्रत्येक बड़े देश में निकासगृह स्थापित है । हाँ, इनमें उतना काम नहीं होता जितना इंग्लैण्ड और वेल्स में होता है । बात यह है कि यूरोप में चेकों का चलन और रेखाङ्कन का चलन उतना नहीं है जितना इंग्लैण्ड और वेल्स में है ।

प्रश्न

(१) निकासग्रह की परिभाषा दीजिये और यह बताइये कि केन्द्रीय बैंक इस सम्बन्ध में क्या काम करते हैं। यह भी बताइये कि निकासग्रहों में किस सिद्धान्त पर काम होता है।

(२) निकासग्रह की कार्य व्यवस्था को संक्षेप में किन्तु स्पष्ट तौर पर समझाइये। अपने उत्तर के सम्बन्ध में एक उदाहरण ले लीजिये।

(३) निकासग्रह के कौन-कौन से लाभ हैं। उनका वर्णन कीजिये।

(४) इंगलिस्तान की निकासी (Clearing) का वर्णन कीजिये। लन्दन में निकासी (Clearing) का जो प्रबन्ध है उसको विस्तृत रूप में बताइये।

(५) भारतवर्ष में निकासी (Clearing) का क्या प्रबन्ध है ? उसका थोड़ा-सा विवरण दीजिये। क्या उसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है ?

अध्याय १२

भारतीय बैंकिंग

ऐतिहासिक दृष्टि

भारतवर्ष में आधुनिक बैंकिंग का प्रादुर्भाव तो अंग्रेजों के आने के साथ-साथ ही हुआ था। किन्तु इसके यह अर्थ नहीं हैं कि उसके पहिले हमारे यहाँ बैंकिंग थी ही नहीं। ऋण देने के प्रमाण तो यहाँ पर वैदिक काल में ही ईसा से कम से कम दो हजार वर्ष पहिले मिलते हैं। ऋग्वेद और अथर्व वेद में 'ऋण' शब्द बार बार आया है। फिर ऋण देने वाले महाजनों के नाम बौद्ध पुस्तकों (जातकों) में भी मिलते हैं जो विन्सेट स्मिथ के अनुसार ईसा से पाँच, छै सौ वर्ष पहिले से सम्बन्धित हैं। इसके बाद सरस्वती नगर के महाजनों ने फिरोज शाह को (१३५१-५८) बहुत काफी रकम उधार में दी थी जिसे उसने फौज के खर्च में लगाया था। इसी तरह से हमें साख-पत्रों का भी जिक्र मिलता है। भगवान कृष्ण के समय

की एक कथा प्रसिद्ध है जिसमें जूनागढ़ के नरसिंह भगत ने द्वारिका-पुरी के सेठ साँवल साह के ऊपर एक हुण्डी की थी। सम्भव है कि यह केवल कथा ही हो, क्योंकि बौद्ध पुस्तकों के और सूत्रों के समय तक हुण्डी का अन्य कहीं जिक्र नहीं पाया जाता। किन्तु कुछ शहरों के बड़े-बड़े व्यापारी साख-पत्र (Letters of credit) तो अवश्य निकालते थे। इसके अलावा जमा का काम भी होता था—यहाँ तक कि ईसा की दूसरी और तीसरी शताब्दी में मनु के समय तक यह काफी बढ़ गया था क्योंकि उसने अपनी स्मृति में जमा और गिरवी पर एक पूरा अध्याय लिखा है। साथ ही सिक्कों के विनिमय का काम भी बहुत पहिले ही होने लगा था और मुगलकाल तक तो यह बहुत ही अधिक उन्नति कर चुका था। बात यह है कि उस जमाने में बहुत से नये-नये सिक्के बनाये गये थे, जिनमे से कुछ तो एक ही नाम के थे, यद्यपि प्रत्येक का बाज़ारू दर भिन्न था। इस सब से यह स्पष्ट है कि भारतवर्ष के ऐतिहासिक काल में तो अवश्य ही यहाँ पर बैंकिंग की एक ऐसी सुघड़ प्रणाली चालू थी जो यहाँ की आवश्यकताओं के लिये पूर्ण रूप से उपयुक्त थी। हाँ, यह पश्चिमी प्रणाली से अवश्य भिन्न थी।

आधुनिक बैंकों के प्रवेश के पहिले देशी बैंकों (Indigenous Bankers) का महत्व

आधुनिक बैंकों के प्रवेश के पहिले यहाँ पर देशी बैंकों का बहुत महत्व था। उस समय के महाजनों के धनी मानी होने से उनके व्यवसाय का लाभप्रद होना तो स्वयं सिद्ध है। इसके अतिरिक्त पश्चिम के यहूदियों के विपरीत, जनता और सरकार दोनों ही उनको बहुत ही अच्छी दृष्टि से देखते थे। यहाँ तक कि औरङ्गजेब जैसा धर्मपरायण बादशाह भी उनका बड़ा सन्मान करता था। इतिहास इस बात का साक्षी है कि उसने उस समय के सबसे प्रसिद्ध महाजन मानिकचन्द को 'सेठ' की उपाधि से विभूषित किया था। उसके बाद बादशाह फर्रुखसियार ने अपने समय के महाजन फतेहचन्द को जो 'सेठ मानिकचन्द का दत्तक पुत्र था 'जगत सेठ' की पीढ़ी, दर पीढ़ी चलने वाली उपाधि प्रदान की थी। फिर इनका सम्बन्ध अंग्रेजों से भी बहुत अच्छा रहा। रेवेरेण्ड जे० लाज़ के लेख के

अनुसार क्लाइव ने सन् १७५९ में उस समय के जगत सेठ की चार दिन की आवभगत में १७४३४ रु० खर्च किये थे जिसका वेदलों उसने उसका बगाल के नवाब के विरुद्ध साथ देकर दिया था। अब, जहाँ तक इनकी व्यवसाय कुशलता का प्रश्न है उसके लिये हम सुप्रसिद्ध फ्रांसीसी यात्री जे० वी० टेवरनियर के लेख को देख सकते हैं। उसने लिखा है कि इटली के सब यहूदी जो द्रव्य और विनिमय के काम में बहुत ही दक्ष हैं, भारतवर्ष के इन महाजनों के यहाँ के काम सीखने वालों की भी मुश्किल से बराबरी कर सकते हैं^१।

देशी बैंकों की अवनति

किन्तु इनका व्यवसाय और इनकी शक्ति धीरे-धीरे कम होने लगी—यहाँ तक कि अठारहवीं शताब्दी के अन्त तक इनका महत्व बहुत ही घट गया था। इसके निम्न कारण थे :—

(१) अंग्रेजी व्यापारी इनकी लिखावट को न समझ सकने के कारण इनका प्रयोग नहीं कर सके।

(२) इनका चलन भी नहीं बढ़ा। ये अपने ही ढङ्ग प्रयोग में लाते रहे और केवल कृषि, हाथ की कारीगरी तथा देशी व्यापार ही को सहायता पहुँचाते रहे।

(३) यद्यपि बहुत दिनों तक ईस्ट इन्डिया कम्पनी ने यहाँ पर पश्चिमी बैंकों को नहीं आने दिया किन्तु अन्त में वह आ ही गये और देशी महाजनों के व्यवसाय के कुछ अंगों में उनकी होड़ करने लगे और अन्त में उनको पछाड़ दिया।

(४) मुगल साम्राज्य की अवनति के बाद जो गड़बड़ी मची थी उसके कारण भी देशी महाजनों की बहुत हानि हुई। प्रायः उन लोगों की जो रकम राजाओं, इत्यादि के यहाँ थी वह वसूल नहीं हो सकी।

(५) देशी महाजन स्वयं वेईमानी, इत्यादि करने लगे जिससे वह वदनाम हो गये और अन्त में उनका व्यवसाय गिर गया।

¹All the Jews who occupy themselves with money and exchange in the empire of the Grand Seigneur pass for being very sharp, but in India they would scarcely be apprentices to these !

(६) सन् १८३५ के बाद ब्रिटिश भारतीय रुपये के सारे देश में चल जाने के कारण उनका विनिमय का व्यवसाय भी बन्द हो गया जिससे उनकी बड़ी हानि हुई।

(७) रेलों, वाष्पयानों, डाक और तार, इत्यादि के खुल जाने के कारण व्यापारिक मार्ग और सम्बन्ध बदल गये जिससे भारतीय व्यापारियों को विदेशी व्यापारियों के लिये जगह छोड़नी पड़ी और वे लोग अंग्रेजी बैंकों को अधिक काम देने लगे।

आधुनिक बैंकों की संस्थापना

जहाँ तक ज्ञात है सबसे पहिला आधुनिक बैंक मद्रास प्रान्त में खुला था, यद्यपि अधिकांश पुस्तकों में कलकत्ते की आदती कोठियों के बैंकों (Calcutta Agency Houses) का जिक्र है। यह सरकारी बैंक था और इसका प्रबन्ध काउन्सिल के सदस्यों के हाथ में था। शायद यह सन् १६८८ में खुला था। फिर सन् १७२४ में बम्बई की सरकार ने बम्बई शहर में ऐसा ही एक बैंक खोला। इसके बाद मद्रास में कई निजू बैंक खुले और एक अन्य सरकारी बैंक भी खुला। पहिले तो ये सब बैंक जमा प्राप्त करने और एका-उष्ट रखने के लिये खोले गये थे किन्तु बाद में इन्होंने अपना नोट भी चलाना प्रारम्भ कर दिया। बंगाल में सबसे पहिले आधुनिक बैंक कलकत्ते की आदती कोठियों के द्वारा खोले गये। ये कलकत्ते की आदती कोठियाँ व्यापारिक संस्थाये थी और विशेषतः चाय और नील का काम करती थीं। बैंकिंग का तो इनका एक अतिरिक्त व्यवसाय था। अलेक्जेंडर एण्ड कम्पनी ने कुछ अन्य कम्पनियों के साथ मिलकर सन् १७७० में बैंक आफ हिन्दुस्तान खोला। बंगाल बैंक और जनरल बैंक आफ इण्डिया लगभग सन् १७८६ में खुले। इनमें से प्रथम तो किसी भी आदती कोठी से सम्बन्धित नहीं था, और १६ मार्च सन् १७८६ के कलकत्ता गजट के अनुसार उसको व्यापार करने की मनाही भी थी। जहाँ तक दूसरे बैंक का प्रश्न है, अभी तक यही ज्ञात है कि वह सारे ब्रिटिश साम्राज्य में सीमित दायित्व का सबसे पहिला बैंक था। वास्तव में इंगलिस्तान में यह सीमित दायित्व का सिद्धान्त बहुत देर में अर्थात् सन् १८५५ में लागू किया गया और वह भी बैंकों के लिये नहीं। बैंकों के लिये तो यह वहाँ पर सन् १८५७ के संकट (Crisis) के बाद माना गया

और तब भी नोट इससे अलग रखे गये। भारतवर्ष में इस सिद्धान्त को सन् १८६१ के भारतीय कम्पनी विधान में स्थान दिया गया।

जनरल बैंक आफ इण्डिया उत्तरोत्तर वृद्धि करता गया। शीघ्र ही यह सरकार का बैंक बना दिया गया। वास्तव में इसका प्रबन्ध बहुत ही अच्छे हाथों में था और इसी से इसने अपने प्रतिद्वन्द्वियों विशेषकर बैंक आफ हिन्दुस्तान तथा बंगाल बैंक को पछाड़ दिया। किन्तु सन् १७८७ में जो करन्सी के सम्बन्ध का संकट उपस्थित हुआ, उसमें इसके सम्बन्ध में अनेकों वेसिर-पैर की बातें कही गईं और अनुचित आलोचना की गई। फिर, सन् १७८८ के दुर्मित्त के बाद जब यह सरकार को ८ प्रतिशत के व्याज से ऋण न दे सका तब सन् १७८९ में इसका सरकार से सम्बन्ध विच्छेद हो गया। अन्त में ३१ मार्च सन् १७९१ को यह इच्छा से भङ्ग कर दिया गया। इस वर्ष के अन्त तक वारम्बार की माँग को पूरा न कर सकने के कारण बंगाल बैंक भी चन्द हो गया। केवल बैंक आफ हिन्दुस्तान ही बच रहा। इसने न केवल सन् १७९१ के संकट का वरन् सन् १८१९ और सन् १८२९ के संकटों का भी बड़ी सफलता से सामना किया। किन्तु अन्त में सन् १८३२ में अलेक्जेंडर ऐण्ड कम्पनी के जिससे कि यह प्रारम्भ से ही सम्बन्धित था फेल होने पर यह भी फेल हो गया। आढती कोठियों के द्वारा खोले गये अन्य बैंकों का भी यही हाल हुआ। मैसर्स पामर ऐण्ड कम्पनी के द्वारा खोला गया कलकत्ता बैंक तो सन् १८२९ में ही फेल हो चुका था। मैसर्स मैकिंटोश ऐण्ड कम्पनी से सम्बन्धित कमर्शियल बैंक आफ कलकत्ता सन् १८३३ में भंग हो गया। ये सब बैंक नोट भी निकालते थे, अतः, इनके फेल होने से न केवल इनमें रु० जमा करने वाले लोगों की ही जिनमें बहुत-सी विधवाये और बहुत से पेन्शन पाने वाले लोग भी थे वरन् नोट रखने वाले लोगों की भी बड़ी हानि हुई। यह सब यूरोपीय धन्ये थे; अतः, इनके फेल होने का दायित्व भारतीयों के सिर पर नहीं मढ़ा जा सकता।

प्रेसीडेन्सी बैंक

बैंक आफ बंगाल जो कि सर्व प्रथम प्रेसीडेंसी बैंक था सन् १८०६ में कलकत्ता बैंक के नाम से स्थापित हुआ था, और उसको सन् १८०९

में बैंक आफ बंगाल के नाम से अधिकार-पत्र प्राप्त हुआ था। इसकी संस्थापना का मुख्य उद्देश्य किसी विशेष जोखिम और असुविधा को उठाये बिना जनता की सेवा करना और आवश्यकता पड़ने पर ईस्ट इण्डिया कम्पनी की सरकार को आर्थिक सहायता देना था। इसका एक उद्देश्य मुद्रा की पूर्ति करना भी था। सन् १८२३ में इसको नोट चलाने की भी आज्ञा प्रदान कर दी गई और सन् १८३९ में इसको अपनी शाखायें खोलने और भारतीय विनिमय का काम करने की भी आज्ञा दे दी गई—विदेशी विनिमय का काम करने की आज्ञा इसको नहीं मिली। बंगाल की सरकार ने इसके कार्यों को रक्षा की सीमा के अन्दर रखने के उद्देश्य से इसके प्रबन्ध में भाग लेने के लिये इसकी पंचमाश पूँजी भी अपने पास से लगाई थी। अतः, बैंक का सेक्रेटरी प्रायः सिविल सर्विस का सदस्य होता था, और कुछ संचालकगण (Directors) भी सरकार चुनती थी।

बैंक आफ बम्बई और मद्रास भी क्रमशः सन् १८४० और १८४३ में संस्थापित हुये और इनकी पूँजी के भी कुछ हिस्सों को इनकी सरकारों ने बंगाल की सरकार की तरह ही लिया। ये भी नोट चलाते थे। तीनों प्रेसीडेंसी बैंकों को सरकार के बैंकिंग व्यवसाय को करने का एकाधिपत्य भी दिया गया था। किन्तु नोट चलाने का अधिकार इनसे सन् १८६१ में छीन लिया गया क्योंकि उस वर्ष स्वयं सरकार ने इसका एकाधिकार ले लिया। हाँ, नोट चलाने के अधिकार को छीन लेने से इनकी जो क्षति हुई थी उसकी पूर्ति के लिये सरकार की नकदी प्रेसीडेंसी शहरों में तथा अन्य स्थानों में जहाँ इनके दफ्तर और इनकी शाखायें थीं इनके पास इनसे कुछ व्याज लिये बिना ही रक्खी जाने लगी।

सन् १८६८ में एक विशेष घटना घटित हो गई जिसके फलस्वरूप सरकार का प्रेसीडेंसी बैंकों से जो सम्बन्ध था उसमें एक बड़ा भारी परिवर्तन हो गया। बात यह थी कि अमेरिका के घरेलू युद्ध के कारण रुई की कीमत बढ़ गई थी और उसमें सट्टेबाजी होने लगी थी। अतः, बैंक आफ बम्बई इसमें फँस गया जिससे उसकी बड़ी हानि हुई। इसके फलस्वरूप उसे भङ्ग कर दिया गया। किन्तु फौरन ही एक दूसरा बैंक इसी नाम से एक करोड़ रुपये की पूँजी से खोल दिया गया। पुराने

बैंक की जमा की रकम तो सब दे दी गई, किन्तु हिस्सेदारों को लगभग कुछ नहीं मिला। अतः, सरकार ने इसके बाद बैंक आफ बंगाल और मद्रास के हिस्से भी बेच दिये और फिर वह किसी भी बैंक के न तो संचालकों को चुन सकती थी और न उसके कार्यों में भाग ले सकती थी। साथ ही बैंक आफ बम्बई के फेल होने के कारणों का पता लगाने के लिये एक कमीशन की नियुक्ति की गई और उसकी रिपोर्ट निकलने के बाद सन् १८७६ में एक प्रेसीडेंसी बैंक विधान पास किया गया जिसके अनुसार इन बैंकों के कामों पर कुछ प्रतिबन्ध लगा दिये गये। संक्षेप में ये निम्नांकित थे—

(१) वे विदेशी विनिमय का काम नहीं कर सकते थे।

(२) उनको भारतवर्ष से बाहर उधार लेने और जमा प्राप्त करने की भी मनाही कर दी गई थी।

(३) वे छै महीनों से अधिक के लिये उधार नहीं दे सकते थे।

(४) उनको रेहन पर, अचल सम्पत्ति की जमानत पर, दो स्वतन्त्र व्यक्तियों से कम के द्वारा लिखे गये प्रण-पत्रों पर और माल पर जब तक कि वह माल अथवा उसके सम्बन्ध के अधिकार-पत्र उनके पास न रख दिये जायँ उधार देने की मनाही कर दी गई थी।

वे अब सरकार की नकदी का भी पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर सकते थे। बात यह थी कि प्रेसीडेंसी शहरों में सरकार के स्वयं के सुरक्षित कोष (Reserve Treasuries) खुल गये और उन्हीं में उसकी अधिकांश नकदी रक्खी जाने लगी। प्रेसीडेंसी बैंकों के पास सरकार की बहुत कम नकदी रहती थी।

यद्यपि ये बैंक जमा प्राप्त करते थे, देशी विलों को डिस्काउंट करते थे और यहाँ के सरकारी ऋण का प्रबन्ध करते थे, तो भी यह विदित हो गया था कि ये केवल प्रेसीडेंसी शहरों के लिये ही अथवा अधिक से अधिक थोड़े से बड़े-बड़े व्यापारिक शहरों के लिये भी उपयोगी थे अन्य स्थानों के लिये नहीं। वास्तव में इनमें निम्न दोष थे—

(१) इनके बीच में किसी प्रकार का एकीकरण नहीं था। वास्तव में बैंक आफ बंगाल को सारे भारतवर्ष का बैंक बनाने की माँग ईस्ट इण्डिया कम्पनी के सञ्चालक कोर्ट के सामने सन् १८३६ ही में रखी जा चुकी थी। फिर सन् १८६० और ७६ में भी यह माँग दोहराई

गई। सन् १८९८ में भी फाउलर कमीशन के सामने कुछ लोगों ने एक केन्द्रीय बैंक की संस्थापना की माँग रखी। सन् १९१३ में चैम्बरलेन कमीशन ने इस प्रश्न पर विचार करने के लिये एक अनुभवी कमेटी की नियुक्ति का सुझाव पेश किया। प्रथम महायुद्ध के समय एक केन्द्रीय बैंक की अनुपस्थिति बहुत ही खली।

(२) इन्होंने केवल उन्हीं स्थानों में अपनी शाखाएँ खोली थीं जिनमें इनको लाभ मिलने की सम्भावना थी। जिस समय इन तीनों बैंकों को एक किया गया था, उस समय सब मिलाकर इनकी केवल ५९ शाखाएँ थी।

(३) देश के व्यापार को सहायता पहुँचाने के लिये इनके पास काफी रकम नहीं थी। इनकी सब की मिलाकर केवल ३३ करोड़ रुपये की पूँजी थी, इनका सुरक्षित कोष केवल ३,७७,७९,००० रु० था और इनकी जमा की रकम इनके एकीकरण के समय सन् १९२० में ८७,०४,५३,००० रु० थी। सरकार की अधिकांश नकदी उसके कोष और उपकोष में फालतू पड़ी रहती थी।

(४) देश की व्यापारिक माँग के अनुसार यहाँ के चालू नोटों के घटने-बढ़ने के लिये कोई प्रबन्ध नहीं था, अतः, उससे व्याज और डिस्काउण्ट की दरों में बहुत कमी-बेशी होती रहती थी। सरकार का नियन्त्रण तो करन्सी पर था, और साख पर जो कुछ नियन्त्रण था वह प्रेसीडेन्सी बैंकों का था। अतः, इनमें कोई सम्बन्ध नहीं था।

(५) ऊपर जो पहिले दो बन्धन दिये हुये हैं वह केवल जोखिम से बचाने के लिये थे। किन्तु विनिमय की दर के स्थिर हो जाने पर भी जब विनिमय के काम में कोई जोखिम नहीं रह गई तब भी यह बन्धन चलते रहे। तीनों बैंकों ने लन्दन और भारतवर्ष में उधार लेने की और विदेशी विनिमय में काम करने की एक संयुक्त माँग सरकार से सन् १८७७ में पेश की थी। सन् १८९९ में बैंकों की माँगों पर विचार करने के लिये एक सभा भी हुई थी किन्तु जनता के इनके पक्ष में रहने पर भी सरकार ने कुछ भी नहीं किया। लन्दन में उधार लेने के प्रश्न को तो बराबर अच्छी तरह से विचार किये बिना ही अस्वीकृत कर दिया जाता था।

(६) ये न तो बैंकों के बैंक ही थे और न अन्य किसी जगह से उधार मिलने पर उधार देने के ही दायित्व को स्वीकार करते थे।

सच तो यह है कि यह इतने मंजबूत ही नहीं थे कि उपर्युक्त कार्य कर सकते। जो हो, इन्होंने तो उतना भी नहीं किया जितना ये कर सकते थे।

स्वतन्त्र व्यापारिक बैंक

आढ़ती कोठियों के द्वारा स्थापित किये गये बैंकों के सन् १८३३ में फेल हो जाने के बाद, यहाँ पर स्वतन्त्र व्यापारिक बैंक खुले। सन् १८६० तक ये अपरिमित दायित्व के सिद्धान्त पर रहे। इस बीच में सी० एच० कुक के अनुसार यहाँ पर लगभग १२ बैंक खुले और उनमें से लगभग आधे फेल भी हो गये। बात यह थी कि जब तक आढ़ती कोठियाँ थीं तब तक तो वे सरकारी कर्मचारियों के लिये बैंकिंग का काम करती थीं। किन्तु सन् १८२९-३२ के संकट काल के समय इनके फेल हो जाने के बाद, बड़ी कठिनाई पड़ी। अतः, उस कठिनाई को दूर करने के लिये शीघ्र ही आगरा ऐण्ड युनाइटेड सरविस बैंक तथा गवर्नमेन्ट सेविंग्स बैंक, कलकत्ता खुले। फिर आगरा सेविंग्स बैंक और अनकवेनेन्टेड सरविस बैंक स्थापित किये गये। किन्तु यह बैंक भी दीर्घ काल तक नहीं चल सके। इनके फेल होने के कारणों में सट्टेबाज़ी और जालसाज़ी मुख्य थे। बात यह थी कि उस समय के एकाउण्ट का निरीक्षण ठीक नहीं था। अच्छी बैंकिंग के लिये अच्छा एकाउण्ट निरीक्षण बहुत ही आवश्यक है। जो हो, इस काल के कुछ बैंकों ने बड़ा अच्छा काम किया।

सन् १८६० भारतीय बैंकिंग के लिये विशेष महत्व का था। उस वर्ष यहाँ पर बैंकों को सर्वप्रथम सीमित दायित्व के सिद्धान्त की सुविधा दी गई। अतः, इसके फलस्वरूप और अमेरिका के घरेलू युद्ध के कारण वहाँ से रुई का निर्यात रुक जाने से भारतीय रुई की जो कीमत बढ़ गई थी उससे यहाँ पर जो धन वृद्धि हो गई उसके फलस्वरूप, यहाँ पर विशेषतः सन् १८६४-६५ में लगभग २५ बैंक खुले। किन्तु ये सब बहुत शीघ्र ही काल कवलित हो गये। सत्य तो यह है कि जिस सट्टे के कारण ये उत्पन्न हुये थे उसकी समाप्ति पर ही यह भी समाप्त हो गये। हाँ, बैंक आफ़ अफ़र इण्डिया जो कि सन् १८६४ में खुला था अवश्य सन् १९१४ तक चला।

सन् १८६५-१९०५ का समय विश्राम का समय था। इन चालीस २६

वर्षों में बहुत कम बैंक खुले। किन्तु जो खुले उनमें से कुछ ने तों बड़ा काम किया। इलाहाबाद बैंक जो सन् १८६५ में खुला था आज तक है और पाँच बड़े बैंकों में से एक है। अलायन्स बैंक आफ शिमला सन् १८७४ में खुला था। यह बहुत ही सफल रहा और सन् १९२३ में जब फेल हुआ केवल अपने अंभाग्य ही के कारण फेल हुआ। सन् १९२१ के उसके सम्बन्ध के जो अङ्क प्राप्त हैं उनसे उसकी सुदृढ़ स्थिति का पता चलता है :—

प्राप्त पूँजी	८८ लाख रु०
सुरक्षित कोष	५३ लाख रु०
स्थायी जमा	९०० लाख रु०
चालू जमा	६७९ लाख रु०
कुल जमा	१,६२७ लाख रु०
नकद रोकेड़	४३९ लाख रु०
शाखायें	३६

अवध कमर्शियल बैंक सन् १८८१ में रजिस्टर्ड हुआ था। इसका प्रधान आफिस फैजाबाद में है। यह रिजर्व बैंक का संवस्य बैंक (Scheduled Bank) है। पंजाब नेशनल बैंक सन् १८९४ में खुला और इस समय यहाँ के पाँच बड़े बैंकों में से एक है। पिउपिल्स बैंक सन् १९०१ में खुला और सन् १९१३ में बन्द हो गया। इसका एक मात्र उद्देश्य औद्योगिक संस्थाओं को खोलना और चलाना था। किन्तु जिन परिस्थितियों में इसने इस काम को अपने ऊपर लिया था वह संतोषजनक न थीं। उद्योग धन्धे या तो थे ही नहीं या अधूरी हालत में थे। अतः, इसके प्रबन्ध संचालक ने स्वयं ही कई काम खोले और उनका प्रबन्ध किया जिसका फल वही हुआ जो वैकिंग और व्यापार को सम्मिलित करने का होता है। ऐसी हालत में वैकिंग के सिद्धान्त नहीं निभ पाते, सन् १९१० में इसकी जो स्थिति थी उसका पता नीचे दिये हुये अंकों से मालूम हो सकता है।

प्राप्त पूँजी...	११५ लाख रु०
सुरक्षित कोष	१८ लाख रु०
जमा.....	९८४ लाख रु०
नकद साख, विल, प्रणपत्र,	
जमा की हुई रकम से अधिक,	

निकाली हुई रकम ७९'३ लाख रु०

दूसरे बैंकों के यहाँ जमा २'४ लाख रु०

ड्राफ्ट की बाकी.....१'९ लाख रु०

ऋण-पत्र और दूसरी लागत ४'२ लाख रु० .

सरकारी कागज़....४'२ लाख रु०

नकद रोकड़ और बैंक में ७'१ लाख रु०

सन् १८६५ में जो बैंक फ़ेल हुए थे उससे बैंक संस्थापकों की हिम्मत टूट गई थी। जो बैंक फ़ेल हुए थे वे भारतीय और यूरोपीय दोनों प्रकार के लोगों के प्रबन्ध में थे। हम जानते हैं कि बैंक आफ बम्बई जैसा मजबूत बैंक भी अपमानित हो चुका था और प्रधानतः सन् १८६५ से सट्टे के कारण जो संकट पैदा हो गया था उसी के फल-स्वरूप सन् १८६८ में भङ्ग किया जा चुका था। किन्तु उपर्युक्त विश्राम का एक अन्य कारण भी था जिससे स्थिति बहुत कुछ स्पष्ट हो जाती है। हमको ज्ञात है कि चाँदी का मूल्य सोने में सन् १८७१-७२ के बाद गिरने लगा था। अतः, भारतवर्ष के उस समय रजतमान पर होने के कारण, चाँदी के मूल्य में जो भी कमी होती थी उसका प्रभाव रुपये के विनिमय की दर पर पड़ता था। इससे देश के विदेशी व्यापार में अनिश्चितता आ गई और उससे उद्योग-धन्यों पर भी बुरा प्रभाव पड़ा। यह स्थिति सन् १८९३ तक रही। करन्सी की कठिनाइयों ने वैकिंग पर दोहरा प्रभाव डाला। एक तो लोगों का ध्यान वैकिंग की स्थापना की ओर से हटकर द्रव्य की इकाई को स्थिर करने की ओर लग गया, और दूसरे व्यापार की अनिश्चितता से ऐसी परिस्थितियाँ और ऐसा वातावरण उत्पन्न हो गया जो बैंकों की संस्थापना के विरुद्ध था।

इसके बाद के काल में सन् १९०६-१३ का स्वदेशी आन्दोलन चला जिसके फलस्वरूप इस बीच में ९८ बैंक संस्थापित किये गये। इनमें से बहुत से बहुत छोटे थे और सन् १९१३-१९ के बीच में फ़ेल हो गये। किन्तु आजकल के बहुत से महत्वशाली बैंक भी इसी समय में चालू हुये थे। इस समय के पाँच बड़े बैंकों में से दो तो जैसा कि पहिले ही बताया जा चुका है इसके पहिले के काल में संस्थापित हो चुके थे। अन्य तीन इसी काल में खुले थे। बैंक आफ इण्डिया सन् १९०६ में रजिस्टर्ड हुआ था, बैंक आफ बरोदा सन् १९०९ में और सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया सन् १९११ में रजिस्टर्ड हुए थे। अन्य बैंकों

में से जो इस समय संस्थापित हुये थे और आज तक चल रहे हैं, ये मुख्य हैं :—इंडियन बैंक (१९०७), पंजाब एंड सिंध बैंक (१९०८) और बैंक आफ मैसूर (१९१३)। ये सभी रिजर्व बैंक के सदस्य बैंक (Scheduled Bank) हैं।

प्रथम युद्ध और युद्धोत्तर की तेजी ने बैंकिंग को एक और प्रोत्साहन दिया। सबसे पहिले टाटा इंडस्ट्रियल बैंक सन् १९१८ में खुला। इसका भविष्य बड़ा ही उज्ज्वल प्रतीत होता था। किन्तु लम्बी अवधि के काम को साधारण बैंकिंग के काम के साथ करने के कारण और अधिकांश यूरोपीय कर्मचारियों की जिनके हाथ में इसका काम था अनभिज्ञता तथा उसी से उत्पन्न साधारण जनता और भारतीय कर्मचारियों की उदासीनता के फलस्वरूप यह फेल हो गया और सन् १९२३ में सेन्ट्रल बैंक आफ इन्डिया के साथ मिला दिया गया। फिर, इन्डस्ट्रियल बैंक आफ वेस्टर्न इन्डिया, कारनानी इन्डस्ट्रियल बैंक, यूनियन बैंक आफ इन्डिया तथा अन्य कई बैंक जो आज तक चालू हैं और रिजर्व बैंक के सदस्य बैंक हैं इसी समय खुले। किन्तु बहुत से अन्य बैंक भी इसी अवधि के बीच में खुले जो केवल फेल होने वाले बैंकों की संख्या बढ़ाने के लिये ही थे। यद्यपि सन् १९१३-१९ के संकट की उग्रता कम हो गई तो भी सन् १९१९-२५ में भी बैंक फेल होते रहे। सब मिला कर इस अवधि में ५१ करोड़ ६० की पूँजी के ८४ बैंक फेल हुये जिनमें अलायन्स और टाटा जैसे सुदृढ़ बैंक भी थे।

इसके बाद आज तक बहुत से छोटे और बड़े बैंक संस्थापित हो चुके हैं। सन् १९४०-४५ के बीच में इसमें विशेष तौर पर उन्नति हुई। इसके लिये जो मुख्य कारण थे वह निम्नांकित हैं—युद्ध की परिस्थितियों के सुधर जाने के कारण विश्वास की मात्रा का बढ़ जाना, युद्ध सम्बन्धी परिस्थितियों के कारण आर्थिक लेन-देनों की वृद्धि और सरकार द्वारा मित्र राष्ट्रों की तरफ से क्रय करने के कारण करन्सी के परिमाण में अत्याधिक वृद्धि। पाँच लाख और उससे अधिक की पूँजी और सुरक्षित कराने वाले सम्मिलित पूँजी के बैंकों की संख्या सन् १९२६ के २८ से बढ़कर सन् १९४० में ५८ (४१ सदस्य बैंक और १७ साधारण बैंक) और सन् १९४७ में ९९ सदस्य बैंक हो गई थी। इसी तरह से एक लाख और पाँच लाख

के बीच वाले बैंकों की संख्या सन् १९२६ में ४७, सन् १९४० में १२० और सन् १९४५ में १७४ थी। हाँ, पचास हजार और एक लाख के बीच वाले बैंक सन् १९४० और सन् १९४५ में क्रमशः १२१ और ११४ थे अर्थात् पचास हजार से नीचे वाले बैंक इन्हीं वर्षों में क्रमशः ३३२ और २४४ थे। छोटी पूँजी वाले बैंक अब कम खुलते हैं, विशेषतः पचास हजार से कम पूँजी वाले बैंकों का खुलना तो सन् १९३६ से विधान के द्वारा ही बन्द कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त जो ऐसे बैंक हैं भी उनको अपने सुरक्षित कोष को बढ़ाकर अपनी पूँजी को बढ़ाने के लिये बाध्य किया जा रहा है।

इन वर्षों में बैंक फेल भी काफी हुये। सन् १९३१ में जिस वर्ष सब से कम बैंक फेल हुये थे यह संख्या १८ थी और सन् १९४० में जिस वर्ष सबसे अधिक बैंक फेल हुये थे यह संख्या १०२ थी। इस सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि सन् १९३६ के पहले जब भारतीय कम्पनी विधान में 'बैंक' शब्द की कोई परिभाषा थी ही नहीं, 'हाँ' पर बैंकों के फेल होने का कोई विशेष अर्थ नहीं था। बात यह थी कि उस समय तक कोई भी संस्था चाहे वह बैंकिंग का काम करती रही हो अथवा नहीं अपने को बैंक कह सकती थी। अतः, ऐसी संस्थाओं के फेल होने से यही समझा जाता था कि बैंक ही फेल हुये हैं, किन्तु वास्तव में यह बात न थी। फिर प्रायः थोड़े ही दिनों के खुले हुये और थोड़ी ही पूँजी वाले बैंक ही अधिक फेल होते थे। हाँ बैंक आफ अपर इंडिया, अलायन्स बैंक आफ शिमला, पिउपिल्स बैंक और टाटा इन्डस्ट्रियल बैंक का फेल होना अवश्य कुछ अर्थ रखता था। किन्तु सन् १९३६ से तो बैंकों के फेल होने के विशेष अर्थ हैं, यद्यपि इधर भी प्रायः कमजोर बैंक ही फेल हुये हैं। हाँ कुछ बड़े-बड़े बैंक भी फेल हुये हैं, जैसे सिवराम अय्यर बैंक, मद्रास; बंगाल नेशनल बैंक; ट्रावन्कोर-नेशनल ऐन्ड किलन बैंक; बनारस बैंक; और अभी हाल ही में ज्वाला बैंक। इनका फेल होना बहुत ही शोक की बात है, और विशेषतः इस-लिये कि यह सदस्य बैंक थे।

इम्पीरियल बैंक

यह तो पहले ही बताया जा चुका है कि सारे देश के लिये एक केन्द्रीय बैंक की आवश्यकता तो सन् १८३६ से ही प्रतीत होने लगी

थी। अतः, सन् १९२० में, उस वर्ष के इम्पीरियल बैंक विधान द्वारा तीनों प्रेसीडेंसी बैंकों का एकीकरण करके एक इम्पीरियल बैंक बनाया गया। इसकी प्राप्त पूँजी ५६२ करोड़ रु० रक्खी गई और इसको जनता के हित में काम करने के लिये कहा गया। यही कारण था कि इसके केन्द्रीय मंडल के १६ शासकों में से १० की नियुक्ति सपरिषद् गवर्नर जनरल के हाथ में रक्खी गई। इसका निर्माण निम्न भाँति होता था —

(१) सपरिषद् गवर्नर जनरल के द्वारा नियुक्त —

(अ) केन्द्रीय मण्डल की सिफारिश पर विचार करते हुये दो प्रबन्ध शासक (Managing Governors)।

(ब) भारतीय हित का प्रतिनिधित्व करने वाले चार गैर-सरकारी शासक।

(स) बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के तीनों स्थानीय मंडलों के तीन मंत्री।

(द) करन्सी संचालक (Controller of Currency)।

(२) हिस्सेदारों के द्वारा निर्वाचित—तीनों स्थानीय मंडलों के सभापति और उप-सभापति।

जिन बातों का सम्बन्ध सरकार की आर्थिक नीति अथवा उसका इसके पास जो नकद कोष रहता था उसकी रक्षा से होता था उनमें सरकार इसको कोई भी आदेश दे सकती थी। वह इसके कामों, कागजातों तथा पाउने और देने की सूची के सम्बन्ध में इससे किसी प्रकार की पूछ-ताछ भी कर सकती थी। वह इसके हिसाब की जाँच-पड़ताल करने और उस पर अपनी रिपोर्ट देने के लिये अपने निरीक्षक (Auditors) भी नियुक्त कर सकती थी। अन्तिम, नये स्थानीय दफ्तर और मण्डल खोलने के पहिले बैंक को उसकी स्वीकृति प्राप्त कर लेना भी आवश्यक था।

इस बैंक और भारत सचिव के बीच में एक समझौता भी हुआ था जिसमें यह तैयार किया था कि बैंक सरकार के सब वैकिंग के कार्य करेगा और उसके ऋण की भी व्यवस्था करेगा। साथ ही यह भी कि यह अपनी संस्थापना के पाँच वर्षों के अंदर अपनी सौ नई शाखाएँ खोलेगा जिनमें से कम से कम पचीस का स्थान स्वयं सरकार निश्चित करेगी। अब, इनके एवज में जहाँ-जहाँ इसकी शाखाएँ थीं वहाँ-वहाँ इसको सरकार

को नक़द कोष अपने पास रखने का अधिकार दिया गया था और यह अपने कोष को करन्सी के द्वारा जहाँ चाहे वहाँ कुछ प्रतिफल दिये बिना ही भेज सकता था। इसके अतिरिक्त जिन दो स्थानों में इसकी शाखाएँ थीं उनके बीच में सरकार ने करन्सी ट्रान्सफ़र (Currency Transfer) और सप्लाय बिलों (Supply Bills) को न निकालने का वचन दिया था। हाँ, इसके लिये इसने करन्सी संचालक से स्वीकृति कमीशन पर जनता को एक जगह से दूसरी जगह द्रव्य भेजने की सुविधा देना स्वीकार किया था।

फिर विधान ने यह भी निर्धारित कर दिया था कि यह बैंक बैंकिंग के कौन-कौन से काम नहीं कर सकेगा। इसके अलावा इसको अच्छी ऋतु में द्रव्य के वाज़ार की सहायता करने की क्षमता प्रदान करने के लिये सरकार के कागज़ी मुद्रा विभाग को इसको देशी बिलों और हुंडियों की ज़मानत पर १२ करोड़ ६० तक की अतिरिक्त करन्सी, पहिले चार करोड़ तक तो ६ प्रतिशत व्याज पर और शेष आठ करोड़ ७ प्रतिशत व्याज पर, उधार के रूप में दे देने का अधिकार दे दिया गया था।

किन्तु देश में एक सार्वजनिक केन्द्रीय बैंक संस्थापित करने की माँग बराबर होती रही, और अन्त में हिल्टन यंग कमीशन ने इस बैंक से प्रथम एक केन्द्रीय बैंक स्थापित करने की बहुत ही स्पष्ट शर्तों में सिफारिश की। अतः, सन् १९३४ में जो रिजर्व बैंक खोला गया वह उसी सिफारिश के फलस्वरूप था।

विदेशी बैंक

इस देश में जो बैंक खुले उनके अलावा- कुछ विदेशी बैंक भी जिनके प्रधान कार्यालय यहाँ से बाहर हैं अपनी शाखाओं के द्वारा यहाँ पर काम करते आ रहे हैं। पहिले तो सन् १८५३ तक ईस्ट इंडिया कम्पनी ने आदती कोठियाँ की सहायता से ओरियन्टल बैंकिंग कारपोरेशन को छोड़कर जो यहाँ पर सन् १८४२ में खोला गया था अन्य विदेशी बैंकों को यहाँ पर नहीं खुलने दिया। इसका एकमात्र कारण यह था कि वह यह नहीं चाहती थी कि उसके अलावा अन्य कोई संस्था भारतवर्ष के किसी प्रकार के भी व्यवसाय से लाभ उठा सके। वह यह कहती थी कि तृतीय जार्ज के शासन काल में जो ४७वाँ

लोन आफिस, निधि और चिट फण्ड

उपर्युक्त संस्थाएँ तो सभी जगह हैं। किन्तु कुछ ऐसी संस्थाएँ भी हैं जो केवल कुछ ही स्थानों में हैं, जैसे बंगाल के लोन आफिस और मद्रास के निधि और चिट फण्ड। बंगाल के लोन आफिसों को तो पहिले भूमि बन्धकों बैंकों के स्थान पर ही खोला गया था। वे जमा प्राप्त करते हैं। उनका मुख्य व्यवसाय भूमि तथा अन्य मूल्यवान् वस्तुओं की जमानत पर जमीन्दारों और कृषकों को ऋण देना है। वे वैयक्तिक जमानतों पर भी ऋण देते हैं। कुछ व्यापार और उद्योग-धन्धों को और विशेष कर चाय के धन्धे को भी आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। कुछ ऋण देने के साथ-साथ व्यापार भी करते हैं। निधि पहिले-पहिल मद्रास में चालू हुई थी। ये पारस्परिक ऋण देने वाली संस्थाएँ हैं। किन्तु अब इन्होंने आधुनिक बैंकों के कुछ कार्यों को करना प्रारम्भ कर दिया है और जमा प्राप्त करने तथा गैर सदस्यों को उधार भी देने लग गई हैं। चिट फण्ड भी कुछ लोगों की एक ढीली-ढाली समिति है जो मितव्ययता को फैलाने में बड़ी सहायक है। इसके सदस्य कुछ किस्त इसके सस्थापक के पास बराबर जमा करते जाते हैं और वह पहिली किस्त की पूरी रकम तो स्वयं अपने परिश्रम के लिये ले लेता है और शेष किस्ते एक-एक करके सब सदस्यों को बारी-बारी से दे देता है।

प्रश्न

(१) इस देश की बैंकिंग की क्रमिक उन्नति का इतिहास लिखिये और मध्यकाल में उसकी जो अवस्था थी-उसका दिग्दर्शन कराइये। बाद में इसकी अवनति के क्या कारण थे ?

(२) इस देश के आधुनिक काल के बैंकों की प्रथम स्थापना के विषयों में एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये। उनके फल होने के क्या मुख्य कारण थे ?

(३) प्रेमीडैन्सी बैंकों का एक संक्षिप्त ऐतिहासिक विवरण दीजिये और यह बताइये कि वह कौन कौन से काम नहीं कर सकते थे ? उनमें कौन-सी कमी थी ?

(४) सन् १८३३ से अब तक आधुनिक बैंकों की जो स्थापना हुई

(८) ऋणदाताओं और इण्डियन बैंकों के व्यवसाय को सुधारने के लिये अपने सुझाव दीजिए । उनके रिजर्व बैंक से सम्बन्धित हो जाने पर कौन-कौन से लाभ होंगे, यह बताइये ।

(९) रिजर्व बैंक ने इण्डियन बैंकों को अपने से सम्बन्धित करने के लिये जो नीति बरती है उस पर आपके क्या विचार हैं ?

(१०) ऋणदाताओं और इण्डियन बैंकों का इम्पीरियल बैंक तथा दूसरे व्यापारिक बैंकों से क्या सम्बन्ध है ? उसके सुधार के सम्बन्ध में अपने सुझाव रखिये ।

अध्याय १४

कृषि सम्बन्धी आर्थिक व्यवस्था

कृषि सम्बन्धी आर्थिक व्यवस्था पर हमें न केवल इसलिये विशेष ध्यान देना चाहिये कि इस देश में इस धन्धे का एक विशेष स्थान है बल्कि इसलिये भी कि इसको कुछ विशेष कठिनाइयाँ हैं । वास्तव में कृषि के तथा अन्य धन्धों के बीच में कुछ विशेष अन्तर है और सत्य तो यह है कि यही कृषि संवन्धी आर्थिक व्यवस्था के मूल में है । प्रथम तो कृषि की उपज की इकाई का संगठन प्रायः एक ही व्यक्ति के हाथ में होने से उसे जो साख प्राप्त हो सकती है वह बहुत ही संकुचित है । इसे साख पाने का आधुनिक तरीका अर्थात् संयुक्त प्रणाली उपलब्ध नहीं है । हम जानते हैं कि अन्य धन्धे वाले भविष्य को पूँजी के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं अथवा यों कहिये कि अपनी कल्पित आय की शक्ति के आधार पर द्रव्य एकत्रित कर लेते हैं । किन्तु कृषक ऐसा नहीं कर सकता । उसकी कल्पना की वास्तविकता का साधारण लोगों की दृष्टि में कोई व्यापारिक मूल्य नहीं है । अतः, उसके पास साख लेने के लिये केवल अपना व्यक्तित्व ही है । दूसरे, व्यापारिक बैंकों का संगठन भी उसके लिये उपलब्ध नहीं है । उसकी मुख्य आवश्यकता तो स्थायी पूँजी की है जिससे वह अपने खेत का विस्तार अथवा उसमें किसी प्रकार का सुधार कर ले और यह हुआ एक लम्बी अवधि का ऋण जिसका मुगतान वह एक फसल अथवा कुछ फसलों

की सहायता से नहीं कर सकता। फिर, भूमि तथा अन्य प्रकार की जो चीजें वह जमानत के तौर पर दे सकता है उन्हें कोई व्यापारिक बैंक पसन्द भी नहीं करता। हम जानते हैं कि उन्हें तो अपने को द्रवित अवस्था में रखना है जो इस प्रकार की लागतों में फँसा देने से नहीं रह सकती। अन्तिम यह है कि यहाँ पर कृषि का उद्यम आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद है ही नहीं। कृषि पर जो शाही कमीशन बैठा था उसके कथनानुसार यहाँ पर यह एक लाभप्रद व्यवसाय न होकर केवल एक जीवन निर्वाह का ढङ्ग है। इससे कठिनार्थ्य और भी बढ़ जाती हैं और ऋण की अदायगी असम्भव-सी हो जाती है। शाही कमीशन के शब्दों में कृषक ऋण में पैदा होते हैं, ऋण में रहते हैं और अपने बोझ को अपने उत्तराधिकारियों को देते हुए ऋण में ही मर जाते हैं। हमारे कृषकों का सम्पूर्ण ऋण १२०० करोड़ रुपये के लगभग है, अतः, इसके भुगतान का भी प्रश्न है। संक्षेप में कृषकों की आवश्यकतायें तीन प्रकार की होती हैं :—(अ). अल्पकालीन (Short term), (ब) मध्यकालीन (Intermediate), और (स) चिरकालीन (Long-term)। अब, हम इनकी समस्याओं और उनके हल की ओर ध्यान देंगे।

(अ) अल्पकालीन ऋण की आवश्यकता

भारत में कृषकों की अल्पकालीन ऋण की आवश्यकता उनके कृषि सम्बन्धी दैनिक व्यय के लिये उदाहरणार्थ बीज के दाम के लिये, श्रम के भुगतान के लिये और जब वह कृषि का काम करते हैं अथवा अपनी उपज बाजारों में ले जाते हैं तब वे उनके और उनके कुटुम्ब के व्यय के लिये और उनके अन्य चालू खर्चों के लिये जैसे लगान तथा व्याज के भुगतान के लिये हैं। यदि किसी के पास आर्थिक दृष्टि से उचित भूमि है तो साधारणतः उसे यह सब अपनी एक वर्ष की उपज को बेचकर दे देना चाहिये। अतः, इसमें नौ महीने लग जाते हैं। कुछ लेखक इसमें विक्रय और चलानी के व्यय भी सम्मिलित कर लेते हैं। किन्तु कृषकों का अधिक लाभ तभी हो सकता है जब यह कुछ अधिक समय तक के लिये अर्थात् तीन वर्ष तक के लिये मिल जाय। ऐसी स्थिति में यह मध्यकालीन ऋण के अन्तर्गत आ जाता है। यहाँ पर अधिकतर तो उपज गाँवों में ही बिक जाती है। अधिकांश में कृषकों

को अपनी गरीबी के कारण अपनी उपज को अच्छा मूल्य पाने के समय तक रोक रहने की शक्ति न होने के कारण उसे फौरन ही कम मूल्य पर बेच देना पड़ता है। यदि उसे उचित आर्थिक सहायता मिल जाय तो वह अपनी सब उपज एक साथ न बेचकर धीरे-धीरे बेचे जिससे उसका उचित मूल्य भी प्राप्त हो सके।

अब, हमें यह देखना चाहिये कि उधार देने वाले वर्तमान संगठन किस तरह से कृषकों की इस अल्पकालीन ऋण की आवश्यकता को पूरी करते हैं। इस सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि जो संगठन ऐसा कर रहे हैं वह प्रायः भिन्न-भिन्न प्रकार की ऋण की आवश्यकताओं में कोई भेद नहीं करते। हाँ, कुछ अपवाद अवश्य हैं जिनका अध्ययन हम उचित स्थान पर करेंगे।

रिज़र्व बैंक आफ इण्डिया

प्रथम तो सन् १९३५ से रिज़र्व बैंक आफ इण्डिया है। यह कृषि को निम्न प्रकार से आर्थिक सहायता दे सकता है :—

(अ) सरकारी कागज़ों के अथवा स्वीकृत भूमिवन्धक बैंकों के उन स्वीकृत ऋण-पत्रों के आधार पर जिनमें धरोहर रक्खी जा सकती है (Trustee Securities) और जो आसानी से बेचे जा सकते हैं, प्रान्तीय सहकारी बैंकों को और उन केन्द्रीय भूमिवन्धक बैंकों को जो प्रान्तीय सहकारी बैंकों के बराबर घोषित कर दिये गये हैं और उनके मार्फत क्रमशः सहकारी केन्द्रीय बैंकों को तथा प्रारम्भिक भूमि बन्धक बैंकों को नौ महीनों के अन्दर देय ऋण के रूप में ;

(ब) केन्द्रीय सहकारी बैंकों के उन ऋण-पत्रों के आधार पर जो कृषि-सम्बन्धी कामों को मौसमी सहायता देने के लिये तैयार किये जाते हैं, प्रान्तीय सहकारी बैंकों को नौ महीनों के अन्दर देय ऋण के रूप में अथवा डिस्काउण्ट के रूप में ;

(स) स्वीकृत सहकारी विक्रय और माल रखने वाली समितियों के उन ऋण-पत्रों के आधार पर जिन पर प्रान्तीय सहकारी बैंकों के वेचान हों और जो उपज की विक्री के लिये बने हों उन्हीं को अधिक से अधिक नब्बे दिन के लिये ऋण के रूप में अथवा यदि वह नौ महीने के अन्दर पकने वाले हों तो डिस्काउण्ट के रूप

में अथवा 'उन्हीं' के उन प्रण-पत्रों के आधार पर जिनके साथ माल रखने वाली समितियों की रसीदें हों अथवा ऐसे माल की गिरवी रखी गई हो जिसके आधार पर इन्होंने विक्रय और माल रखने वाली समितियों को नकद उधार अथवा जमा की हुई रकम से अधिक रकम निकालने दी हो इनको ऋण के रूप में ।

अब यह समझने की बात है कि जो ऋण नब्बे दिन के अन्दर वापिस किये जाने की शर्त पर दिये जाते हैं वह तो कृषि के अधिक काम में आ ही नहीं सकते । इन्हें तो प्रान्तीय सहकारी बैंक अथवा वह केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंक जो इनके बराबर घोषित कर दिये गये हैं यदि उनको तीन महीनों के अन्दर-अन्दर इनके वापिस कर देने का निश्चय है तो केवल अपनी अल्पकालीन क्षणिक माँग को पूरा करने के लिये ही प्रयोग में ला सकते हैं । इससे यह स्पष्ट है कि वह साधारणतः तो कृषि की अर्थ पूर्ति के लिये रिजर्व बैंक का सहारा नहीं ले सकते । हाँ, अत्यन्त आवश्यकता पड़ने पर थोड़े समय के लिये ऐसा कर सकते हैं । किन्तु केन्द्रीय सहकारी बैंकों के उन प्रण-पत्रों को फिर से डिस्काउण्ट कर देने की शर्त भी है जो कृषि के मौसमी कामों की सहायता करने के लिये लिखे जाते हैं अथवा ऐसा ही स्वीकृत सहकारी विक्रय और माल रखने वाली समितियों के प्रण-पत्रों के सम्बन्ध में भी है, और दोनों स्थितियों में प्रण-पत्र नौ महीनों में पकने वाले हो सकते हैं तथा सहायता प्रान्तीय सहकारी बैंकों ही को प्राप्त हो सकती है । यह अवश्य ही उपयोगी सिद्ध हो सकता है ; किन्तु जहाँ तक सहकारी विक्रय अथवा माल रखने वाली समितियों के प्रण-पत्रों का प्रश्न है वह तो यहाँ हो ही नहीं सकते क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं इस देश में तो बहुत कम सहकारी विक्रय और माल रखने वाली समितियाँ हैं । उपर्युक्त से यह भी स्पष्ट है कि रिजर्व बैंक सहायता देने के लिये केवल प्रान्तीय सहकारी बैंकों को मानता है ; केन्द्रीय सहकारी बैंकों को नहीं मानता । हम जानते हैं कि कृषक प्रारम्भिक समितियों से ऋण लेते हैं और वह केन्द्रीय बैंकों के पास सहायता के लिये जाती है । अतः, रिजर्व बैंक के केवल प्रान्तीय बैंकों को सहायता देने के कारण वह केवल इन्हीं से सहायता प्राप्त कर सकते हैं । इसमें सचमुच बहुत ही घुमाव-फिराव है, अतः, यह सुझाव रक्खा जा रहा है कि रिजर्व बैंक को

उन केन्द्रीय सहकारी बैंकों को भी सहायता देनी चाहिये जो उसके माप के अन्दर आ जायें ।

इम्पीरियल बैंक आफ इण्डिया और अन्य व्यापारिक बैंक

रिज़र्व बैंक के बाद इम्पीरियल बैंक आफ इण्डिया तथा अन्य व्यापारिक बैंक हैं । इम्पीरियल बैंक आफ इण्डिया प्रान्तीय सहकारी बैंकों को और केन्द्रीय सहकारी बैंकों को क्रमशः केन्द्रीय सहकारी बैंकों के तथा प्रारम्भिक सहकारी समितियों के प्रण-पत्रों के आधार पर नकद साख अथवा जमा की हुई रकम से अधिक निकालने के रूप में ऋण देता है । किन्तु इधर यह ऐसे ऋण कम करता जा रहा है, क्योंकि यह प्रण-पत्र प्रायः भूमि के आधार पर लिखे होते हैं और यही भूमि का आधार उपयुक्त आधार नहीं मानता । दूसरे, यह कृषि की सहायता इण्डीजेनेस बैंकों के द्वारा भी करता है क्योंकि वे कभी-कभी अपनी इण्डियों को इसके यहाँ डिस्काउंट कराते हैं अथवा उपज को गिरवी रखकर ऋण प्राप्त करते हैं । अन्य व्यापारिक बैंकों में देश के सम्मिलित पूँजी वाले बैंक आ जाते हैं । यह लगभग वैसे ही व्यवसाय करते हैं जैसा इम्पीरियल बैंक करता है । इनमें से कुछ जमींदारों को उनकी जमीन, इत्यादि के आधार पर भी ऋण देते हैं ।

साख सहकारी समितियाँ

(Credit Cooperative Societies)

अब हम साख सहकारी समितियों की ओर आते हैं । ये इस आधुनिक रूप में पहिले-पहिले सन् १८४९ में जर्मनी में खोली गई थीं । आजकल सहकारी समितियों की जो दो प्रणालियाँ हैं उनके चलाने वाले दो व्यक्ति थे जिनके नाम क्रमशः एफ० डबल्यू रैफिसेन (F. W. Raiffeisen) और फ्रिज हरमन शुल्ज डेलिश (Fritz Hermann Schulze Delitzsch) हैं । इन प्रणालियों को क्रमशः रैफिसेन और शुल्ज डेलिश प्रणालियाँ कहते हैं । प्रथम में एक ही पड़ोस के अथवा स्थान के रहने वाले बहुत से किसान अपनी इच्छा से मिल जाते हैं और पारस्परिक सहायता के लिये एक समिति बना लेते हैं । प्रत्येक सदस्य का दायित्व सीमित रहता है । समिति को जमा से, प्रवेश शुल्क से और कभी-कभी सदस्यों के पूँजी देने

से और उधार के रूप में द्रव्य मिलता है और उसे वह अपने सदस्यों को जनकी आवश्यकतानुसार उधार दे देती है। प्रबन्ध प्रायः निशुल्क होता है। केवल लेखकों को वेतन मिलता है। सब की राय से उनमें जो बहुत ही बुद्धिमान होता है वही मुख्य कार्य संचालन और देख-रेख करता है। द्वितीय में एक ही शहर में रहने वाले बहुत से कारीगर जो स्वयं अपने लिये काम करते हैं मिलकर एक समिति बना लेते हैं। इसमें हर सदस्य को एक जमानती हिस्सा मिलेना पड़ता है जो काफी ऊँची रकम का होता है। यह कई किस्तों में वसूल की जाती है जिससे वह मितव्ययता सीखते हैं। यह समिति भी जमा और ऋण के रूप में रकम प्राप्त करती है और यह ऋण की रकम उतनी ही अधिक होती है जितनी जमानती पूँजी होती है। सदस्यों का दायित्व प्रायः असीमित होता है किन्तु यह सीमित भी हो सकता है। समिति का द्रव्य सदस्यों में ऋण के रूप में बाँट दिया जाता है। प्रबन्धक को प्रतिफल के रूप में उचित रकम भी दी जाती है और लाभ की बँटनी भी होती है तथा उसका एक सुरक्षित कोष भी बनता है। दोनों प्रकार की समितियों की मुख्य-मुख्य बातें संक्षेप में तुलनात्मक रूप में दी जा सकती हैं:—

रैफिसेन समिति

(१) काम करने का क्षेत्र सीमित रहता है।

(२) पूँजी प्रायः नहीं होती। यदि वह होती भी है तो बहुत कम होती है।

(३) सदस्यों का दायित्व असीमित होता है।

(४) गैर सदस्यों को ऋण नहीं दिया जाता।

(५) ऋण प्रायः उत्पत्ति के कामों के लिये दिया जाता है।

(६) लाभ की बँटनी नहीं होती।

(७) प्रबन्ध निशुल्क होता है।

शुल्ज डेलिश

(१) काम करने का क्षेत्र विस्तृत रहता है।

(२) पूँजी प्रायः होती है।

(३) सदस्यों का दायित्व कभी-कभी सीमित होता है।

(४) गैर सदस्यों को भी ऋण दिया जा सकता है।

(५) ऋण उपभोग के लिये भी दिया जा सकता है।

(६) लाभ की बँटनी होती है।

(७) प्रबन्ध के लिये प्रतिफल दिया जाता है।

भारतवर्ष में सहकारिता का विकास

- यद्यपि भारतवर्ष में सहकारिता को प्रारम्भ करने के लिये पहिले भी प्रयत्न किये गये थे किन्तु सरकारी तौर पर यह यहाँ पर सन् १९०४ ही में प्रारम्भ हुआ। इसके सम्बन्ध के पहिले वाले सुभाष सर विलियम वैडरबर्न और जस्टिस रान्डे के थे, किन्तु उनके भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त कर लेने पर भी भारत सचिव ने उन्हें स्थगित कर दिया। फिर, सर फ्रेड्रिक निकल्सन ने सन् १८९२ में भारत सरकार को भूमि और कृषक बैंकों सम्बन्धी अपनी रिपोर्ट पेश की और रैफिसेन प्रणाली की समितियों की संस्थापना का सुभाव रक्खा। किन्तु यह भी कार्यरूप में नहीं लाया गया। तत्पश्चात् संयुक्त प्रान्त सिविल सरविस के श्री० डुपरनैक्स ने प्रयत्न किया और वह कुछ सफल भी हुये क्योंकि संयुक्त प्रान्त, बंगाल और पंजाब में कुछ समितियाँ स्थापित हुई। अन्त में सन् १९०१ में लार्ड करजन की सरकार ने एक कमेटी बनाई जिसकी सिफारिसों के फलस्वरूप सन् १९०४ का सहकारी सार्वजनिक विधान बना।

इस विधान में केवल साख सम्बन्धी समितियों के खुलने का ही प्रबन्ध था, और ग्रामीण समितियों पर नागरिक समितियों की अपेक्षाकृत अधिक जोर दिया गया था। इसके अनुसार एक ही गाँव के अथवा शहर के अथवा वर्ग के अथवा जाति के कोई दस व्यक्ति अपने को एक समिति के रूप में संगठित करने के लिये आवेदन-पत्र भेज सकते थे। अब, यदि सब सदस्यों के कम से कम ६ ग्रामीण होते थे तो वह समिति ग्रामीण साख समिति कहलाती थी, अन्यथा नागरिक कही जाती थी। प्रथम तो रैफिसेन वर्ग की थी और द्वितीय शुल्क डेलिश वर्ग की। इनके निरीक्षण, आडिट और भङ्ग करने का अधिकार सरकार को दे दिया गया था।

इस आन्दोलन ने खूब ही उन्नति की और सन् १९०४ का विधान अपर्याप्त प्रतीत होने लगा। अतः, सन् १९१२ में एक दूसरा विधान बना। इसने सन् १९०४ के विधान के दोषों को दूर किया और साख के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों से स्थापित समितियों की संस्थापना के लिये भी नियम रक्खा। इसने अभी तक समितियों का जो विभाजन था, अर्थात्, ग्रामीण तथा नागरिक उसके स्थान पर एक अन्य अधिक

वैज्ञानिक विभाजन का नियम बनाया जिसके अनुसार यह परिमित दायित्व वाली तथा अपरिमित दायित्व वाली कहलाई जाने लगीं। अन्तिम बात यह थी कि इसने केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सहकारी बैंकों की भी योजना की और इस तरह से इसका नीचे से ऊपर तक एक मजबूत संगठन बना दिया। किन्तु साख के अतिरिक्त अन्य कामों के लिये समितियाँ बनाने पर जो पहिले बन्धन था उसको सन् १९१२ के विधान के द्वारा दूर कर देने पर भी आज तक अधिकांश समितियाँ साख समितियाँ ही हैं।

सन् १९१४ में सहकारिता के सम्बन्ध में मैकलेगन कमेटी नियुक्त हुई। उसने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिये एक वर्ष लिया। उससे समितियों का पुनर्संगठन हुआ और उनके प्रबन्ध में बहुत-सा परिवर्तन हो गया। जो अयोग्य थीं वह बन्द भी कर दी गईं। ऋण की वापिसी के लिये समय पालन पर जोर दिया जाने लगा और इनके चलाने में जनता का हाथ बढ़ा दिया गया।

सन् १९१९ के सुधारों ने सहकारिता को एक हस्तान्तरित विषय बना दिया। अतः, इसके मन्त्रियों (Ministers) ने बड़ी दिलचस्पी दिखलाई और शीघ्र ही बहुत-सी समितियाँ स्थापित हो गईं। तब से लगभग प्रत्येक प्रान्त में इसके सुधार के लिये कमेटियाँ भी बनीं जिन्होंने अच्छे-अच्छे सुझाव रखे। रिजर्व बैंक की वैधानिक रिपोर्ट में भी इस सम्बन्ध में काफी प्रकाश डाला गया है और पुनर्संगठन के लिये अच्छे सुझाव रखे गये हैं।

देश में साख सम्बन्धी सहकारिता के आन्दोलन की वर्तमान स्थिति—भारतवर्ष में साख सम्बन्धी सहकारिता के आन्दोलन में (१) प्रारम्भिक सहकारी समितियाँ, (२) केन्द्रीय सहकारी बैंक, तथा (३) प्रान्तीय सहकारी बैंक हैं। एक अखिल-भारतवर्षीय सहकारी बैंक की भी आवश्यकता है किन्तु वह अभी तक नहीं बना है।

प्रारम्भिक साख सहकारी समितियाँ ग्रामीण तथा नागरिक दोनों प्रकार की हैं। इनकी संख्या क्रमशः लगभग १३ लाख तथा १८००० है। ग्रामीण सहकारी समितियों की पूँजी प्रवेश शुल्क से, हिस्सों (Shares) से, गैर सदस्यों की जमा अथवा ऋण से, केन्द्रीय और

प्रान्तीय सहकारी बैंकों और सरकार के ऋण से तथा अपने कोष से प्राप्त होती है। सब रकम काफी बड़ी है। सन् १९४२-४३ के अन्त में यह १,२१,१४,३२,००० रु० थी। यह किस प्रकार प्राप्त हुई थी यह भी जानने योग्य है :—

हिस्सों से प्राप्त पूँजी	रु० १५,७०,७९,०००
सुरक्षित तथा अन्य कोष	रु० १९,९२,२३,०००
जमा से प्राप्त पूँजी	रु० ७८,४५,३९,०००
ऋण	रु० ७,०५,९१,०००
कुल कार्यशील पूँजी	रु० १२१,१४,३२,०००

इससे यह स्पष्ट है कि सदस्यों से प्राप्त जमा मिलाकर इनकी स्वयं की पूँजी ५६ करोड़ रु० के लगभग है और उधार ली हुई पूँजी ६५ करोड़ रु० के लगभग है।

केन्द्रीय सहकारी बैंक प्रायः जिले के मुख्य शहर में स्थित हैं। इनकी संख्या लगभग ६९० है। इनका काम न केवल प्रारम्भिक समितियों को आर्थिक सहायता देना है बल्कि जिनके पास फालतू रकम है उनकी रकम जिनके पास उसकी कमी है उन्हें देना है और सबका पथ प्रदर्शन और निरीक्षण करना भी है। इन्हे प्रारम्भिक समितियाँ तथा बाहरी लोग दोनों मिलकर बनाते हैं और इनकी पूँजी इनके हिस्सों से, सुरक्षित कोष से, जमा से और ऋण से प्राप्त होती है।

प्रान्तीय सहकारी बैंक इस समय प्रायः सभी बड़े-बड़े प्रान्तों में और कुछ रियासतों में भी हैं। अधिकांश में इनका संगठन मिश्रित रूप से हुआ है, अर्थात् सदस्यता और सचालक मण्डल दोनों में जन-साधारण तथा सहकारी समितियों और केन्द्रीय सहकारी बैंकों के प्रतिनिधि हैं। इनकी कार्यशील पूँजी हिस्सों से, सुरक्षित तथा अन्य कोषों से, जनता से, समितियों से, प्रान्तीय और केन्द्रीय बैंकों से और सरकारी ऋण से प्राप्त होती है।

इसकी उन्नति सभी प्रान्तों में एक सी नहीं हुई है। बंगाल, पंजाब और मद्रास में सबसे अधिक समितियाँ हैं और बम्बई, बिहार, संयुक्त प्रान्त, मध्य प्रान्त और आसाम में इनकी संख्या बहुत कम है। सन् १९४३ में प्रारम्भिक समितियों के सदस्यों की संख्या ६९-१२ लाख थी। यदि हम एक परिवार औसतन ५ व्यक्तियों का मान लें तो यह स्पष्ट

है कि यहाँ पर इनसे ३३ करोड़ लोगों को फायदा होता है। वास्तव में और कोई ऐसी संस्था हमारे यहाँ नहीं है जिससे इतने अधिक लोगों का सम्बन्ध हो।

इस आन्दोलन के मुख्य दोष—किसी भी सहकारी समिति की सफलता उसके सदस्यों के अपने ऋण को समय पर वापिस करने पर निर्भर रहती है। बात यह है कि यह ऋण अल्पकालीन होते हैं; अतः, इनका भुगतान उपज के विक्रय के साथ-साथ हो जाना चाहिये। किन्तु यहाँ पर ऐसा नहीं हो पाता। यहाँ कृषक समितियों का सन् १९४०-४१ में १०४१ लाख रु० ऐसा बाकी था जो कभी का वसूल हो जाना चाहिये था। यदि हम इसकी तुलना पूरी कार्यशील पूँजी से करें तो यह ३४ प्रतिशत होगा। लोगों को जो ऋण दिया गया था और जो २२५० लाख रु० था उसका यह ४६ प्रतिशत है।

समितियों के अधिकांश सदस्य उनके उद्देश्यों को नहीं समझ पाते। इनकी सहायता से उनको जो अधिकार प्राप्त है और उनके जो दायित्व हैं उन्हें वे नहीं समझते। उन्होंने इनसे मितव्यता और दूरदर्शिता का पाठ भी नहीं सीखा। फिर सहकारी समितियों को अर्थ के अतिरिक्त अन्य बातों का भी सुधार करना चाहिये। उदाहरणार्थ, अच्छी प्रकार रहने का, कृषि करने का, विक्रय का, शिक्षा का, इत्यादि, इत्यादि।

केन्द्रीय और प्रान्तीय बैंकों के कार्यों में भी कुछ दोष हैं। इधर केन्द्रीय बैंकों से सम्बन्धित समितियों की संख्या बढ़ती जा रही है। रिजर्व बैंक की वैधानिक रिपोर्ट में एक ऐसे बैंक का नाम है जिससे ६८० समितियाँ सम्बन्धित थीं। जहाँ पर इतना काम बढ़ गया है वहाँ अच्छी देख-भाल नहीं हो सकती। न तो प्रान्तीय बैंकों ने और न केन्द्रीय बैंकों ही ने प्रारम्भिक समितियों के प्रति अपने कर्तव्य का पालन किया है। उन्होंने अभी तक अपना ध्यान केवल इनको आर्थिक सहायता पहुँचाने की ओर ही रक्खा है। उन्हें तो इनके उन सभी कामों की ओर ध्यान देना चाहिये जिससे इनका स्तर ऊँचा हो और आन्दोलन दृढ़ होकर बढ़ सके। फिर इनकी स्थिति भी बहुत ठीक नहीं है। प्रायः इनके साधन उतने द्रवित अवस्था में नहीं हैं जितने होने चाहिये। अन्तिम, यह अपने उधार लेने और देने के व्याज की दर

में इतना भी अन्तर नहीं रखते कि वह अपना खर्च पूरा करने के बाद कुछ सुरक्षित कोष में भी डाल ले।

सुधार के लिये सुझाव—साख-सहकारी-समितियों को केवल अल्प कालीन साख का ही प्रबन्ध करना चाहिये। अधिक-से-अधिक वह मध्यकालीन साख का भी प्रबन्ध कर सकती हैं। दीर्घ-कालीन साख का तो प्रबन्ध उनको किसी अवस्था में भी नहीं करना चाहिये। जब कभी ऋण के लिये प्रार्थना-पत्र आवे सदस्यों को इस बात का पता लगा लेना चाहिये कि वह किस काम के लिये चाहिये। सहकारी समितियों को यदि अपना उद्देश्य पूरा करना है और केवल महाजनों का स्थान नहीं लेना है तो उन्हें यह देखना चाहिये कि उनके सदस्य केवल उत्पत्ति के लिये उधार लेते हैं। इसके यह अर्थ नहीं है कि उपभोग के लिये ऋण दिया ही न जाय, किन्तु ऐसी आवश्यकता ही कम-से-कम कर देनी चाहिये। दूसरी बात जो देखने की है वह यह है कि ऋण लेने वाले में उसको वापिस करने की क्षमता है अथवा नहीं। साख सहकारी समितियों को यह भी देखना चाहिये कि उनके सदस्य अपनी आय से अधिक व्यय नहीं करते। सत्य तो यह है कि उन्होंने अभी तक इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया और इसी से उनके ऋण की वसूली नहीं हो पाती। वास्तव में ऋण का उद्देश्य उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना यह कि ऋण लेने वाला उसे फसल के बिकने के बाद और कुछ परिस्थितियों में अधिक-से-अधिक तीन वर्षों के अन्दर ही वापिस करने की क्षमता रखता हो।

फिर, जैसा कि रिजर्व बैंक की प्रारम्भिक तथा वैधानिक रिपोर्टों में कहा गया है जो ऋण वसूल नहीं हो रहे हैं उनके प्रश्न को भी लेना चाहिये। चीजों को टालने से और बार-बार समय बढ़ाने से कोई लाभ नहीं होता। जहाँ पर ऋण पुराने हो गये हैं सहकारिता का आन्दोलन काम नहीं कर रहा है और सदस्य महाजनों से फिर से ऋण लेने लग गये हैं। ऋण की वसूली न होने से साख की सरिता का बहाव रुक जाता है। अतः, इस समस्या को शीघ्र ही क्रियात्मक रूप से सुलझाना चाहिये। इन्हे इतना घटा देना चाहिये कि वह आसानी से दिये जा सकें और फिर इनका प्रबन्ध भूमि वन्धक बैंकों के द्वारा करवा देना चाहिये जो कि दीर्घ कालीन साख का प्रबन्ध करने

के लिये बने हैं। इनका अध्ययन हम आगे चलकर करेंगे। इससे जो हानि होगी उसे यह समितियाँ न छोड़ सकें तो उसका भी प्रबन्ध करना चाहिये। समस्याओं को साहस के साथ सुलभाने से ही काम चलता है। जो बातें स्पष्ट हैं उनका सामना तो करना ही चाहिये।

इन समितियों को भविष्य में अपने ऋण लेने और देने के व्याज की दर के बीच में काफी अन्तर रखना चाहिये जिससे इनके पास अच्छे कोप संचित हो जायें। जो ऋण आजकल वसूल नहीं हो रहे हैं उन्हें बट्टेखाते छोड़ने में यही कठिनाई है कि समितियों के पास काफी सुरक्षित कोप नहीं हैं। बात यह थी कि जैसा पहिले भी कहा जा चुका है उन्होंने अभी तक ऋण लेने और देने के व्याज की दर के बीच में काफी अन्तर रक्खा ही नहीं। इसके यह अर्थ नहीं है कि भविष्य में हम ऐसे ऋण देगे जो वसूल न होंगे और फिर उन्हें सुरक्षित कोप के सहारे बट्टेखाते में डाल देंगे। यह केवल उदाहरण के लिये है। सुरक्षित कोप को अनेकों कामों में खर्च किया जा सकता है। समितियों की स्थिति को सुदृढ़ बनाने का यह एक ढङ्ग है।

अन्तिम बात यह है कि किसी समिति का उद्देश्य ही यही है कि उसके सदस्यों की हर तरह से उन्नति हो। उसे कृपकों के सम्पूर्ण जीवन का ध्यान रखना चाहिये। वास्तव में सदस्यों को सहकारिता के सच्चे महत्व को समझना चाहिये। उसका उद्देश्य केवल ऋण देना ही नहीं है बरन् हर प्रकार से कृपकों के जीवन को सुधारना है। उनकी आय बढ़नी चाहिये; कृपि आर्थिक दृष्टि से लाभदायक हो जानी चाहिये। सच तो यह है कि ग्रामीण अर्थ की समस्या उसके बिना सुलभ ही नहीं सकती। जैसा कि एक लेखक ने कहा है कि जब तक हम कृपि की उत्पत्ति को इस प्रकार नहीं बढ़ा पाते कि एक औसत दर्जे के कृपक को उसके वर्ष भर के परिश्रम के बाद उसने जो कुछ व्यय किया है उससे अधिक मिल जाय तब तक हम ग्रामीण अर्थ का प्रश्न सुलभ ही नहीं पाते।

केन्द्रीय और प्रान्तीय बैंकों के भी सुधार की आवश्यकता है। जिन स्थानों में एक केन्द्रीय बैंक से बहुत ही अधिक समितियाँ सम्बन्धित हैं, वहाँ पर उन्हें तहसीलों की इकाई के अन्तर्गत लाना चाहिये। इससे निरीक्षण और नियंत्रण में सुविधा होगी। फिर, केन्द्रीय बैंकों और प्रान्तीय बैंकों दोनों को वैकिंग के नियमों के अनुसार सुसंगठित होना

चाहिये। उन्हें अपनी सम्पत्ति और पाउने को द्रवित अवस्था में रखना चाहिये। जैसा प्रारंभिक समितियों के सम्बन्ध में कहा जा चुका है उसी प्रकार इन्हे भी अपने उधार लेने और देने के व्याज की दर में काफी अन्तर रखना चाहिये। आजकल जो एक वर्ष से दूसरे वर्ष में बढ़े की रकमों को ले जाने की चाल है उसे आय बढ़ाने से ही वन्द किया जा सकता है। अन्तिम बात यह है कि केन्द्रीय सहकारी बैंकों और व्यापारिक बैंकों के बीच में सम्बन्ध बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है। केन्द्रीय सहकारी बैंक व्यापारिक बैंकों का प्रयोग उनमें अपने बचे हुये द्रव्य को लगाने के लिये और सरकारी साख-पत्रों के आधार पर ऋण लेने के लिये कर सकते हैं। इसके विपरीत व्यापारिक बैंक केन्द्रीय सहकारी बैंकों का प्रयोग उन स्थानों पर अपने बिलों की वसूली करने के लिये कर सकते हैं जिनमें उनके स्वयं के दफ्तर नहीं हैं। इस प्रकार की पारस्परिक सहायता से दोनों लाभ उठा सकते हैं।

रिजर्व बैंक ने सहकारी समितियों और बैंकों को जो द्रव्य भेजने की सुविधा दे रखी है—रिजर्व बैंक सहकारी समितियों और बैंकों से १ अक्टूबर सन् १९४० से द्रव्य भेजने के लिये निम्न रियायती व्यय लेता है :—

५००० रु० तक		५००० रु० के ऊपर	
प्रतिशत	न्यूनतम	प्रतिशत	न्यूनतम
दर	व्यय	दर	व्यय
१/१६	रु० आ० पा०	रु०	रु० आ० पा०
रु०	०—४—०	१/३२	३—२—०

२. ऋण देने वाले और इण्डीजेनस बैंकर

ऋण देने वाले और इण्डीजेनस बैंकर कृषि की जिस प्रकार आर्थिक सहायता करते हैं उसका हम अध्ययन कर ही चुके हैं। कहना न होगा कि उनके काम करने के ढङ्ग की सादगी और ऋण लेने, वालों से उनके व्यक्तिगत सम्बन्ध, उनके स्थानीय ज्ञान तथा अनुभव के कारण ऐसा भविष्य में भी बराबर होता रहेगा। निस्सन्देह, सन् १९३७ के बाद जो मन्दी चली थी, कृषक ऋण लेने वालों की जो रक्षा कर दी गई है, सहकारी समितियों के विकास, डिक्री देने में विलम्ब तथा उनमें से कुछ जो बुरा वर्ताव करते हैं उसके कारण उन सभी के ऊपर सन्देह की

दृष्टिके कारण उनकी दशा इधर बहुत बिगड़ गई है। किन्तु इधर उनका सुधार करने लिये प्रयत्न किये गये हैं और ऐसी आशा है कि वह भविष्य में अधिक लाभप्रद साबित होंगे। कृषि की आर्थिक सहायता की, किसी समस्या के हल की तथा उनके सुधार की कोई भी योजना तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक कि कृषकों के इस समय के ऋण का निपटारा और उनका भुगतान न हो जाय। आसाम, बंगाल, मध्य प्रान्त और पंजाब में ऋण के निपटारे के सम्बन्ध में विधान बन चुके हैं। इनके अनुसार वहाँ की प्रान्तीय सरकारें इसके लिये बोर्ड बना सकती हैं। उनका उद्देश्य ऋणियों और महाजनों के बीच में समझौता करा कर ऋण का निपटारा करने का है। कोई भी ऋणी अथवा महाजन उनके यहाँ इसके लिये प्रार्थना-पत्र भेज सकता है। ऐसा होने पर वह महाजन और ऋणियों से क्रमशः उनके ऋण और सम्पत्ति तथा पाउने, इत्यादि की सूचना माँगते हैं। ऋण के सम्बन्ध में उन्हें प्रमाण भी देने पड़ते हैं। जब सूचना मिल जाती है तब बोर्ड ऋणी का महाजन से समझौता कराने का प्रयत्न करता है। अब, यदि इसमें सफलता मिल जाती है तो समझौते की रकम को २०,२५ किस्तों में देने की योजना बना दी जाती है। महाजनों के बोर्ड के द्वारा किये हुये किसी निपटारे को न मानने पर उन्हें बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में बोर्ड ऋणी को एक प्रमाण-पत्र दे देता है, और महाजन के अदालत में जाने पर उसको न तो उसका स्वर्च और न ६ प्रतिशत से अधिक ब्याज मिलता है। जो महाजन निपटारे को स्वीकार कर लेते हैं उनके ऋण की अदायगी का पहिले प्रबन्ध कर दिया जाता है। निपटारे के स्वीकृति के जो लाभ और अस्वीकृति की जो हानियाँ हैं वह सब प्रान्तों में एक सी नहीं हैं। इसके अतिरिक्त कहीं-कहीं तो जैसे पंजाब में बोर्डों के सामने वकील आ सकते हैं; और कहीं-कहीं जैसे मध्य-प्रान्त, आसाम, मद्रास और बंगाल में ऐसा नहीं हो सकता। इसी तरह से मध्य प्रान्त, आसाम और बंगाल में यह है कि यदि ऋणी कोई किस्त नहीं देता तो वह लगान वसूल करने वाले विभाग के द्वारा वसूल कराई जा सकती है। ऋण के निपटारे की योजना उसका उसी समय भुगतान का प्रबन्ध कर देने पर और भी सफल हो सकती है। ऐसा जैसा कि हम आगे चलकर देखेंगे भूमि बन्धक बैंकों के द्वारा ही

सम्भव है। तब भी भिन्न-भिन्न प्रान्तों में ऋण के निपटारे के जो अंक हैं उनसे इसकी लोकप्रियता का पता लग जाता है।

कहीं-कहीं तो कृषि की उपज की कीमतों में जो कमी हो गई थी उसी के फलस्वरूप कृषि सम्बन्धी ऋणों के छुटकारे के लिये जो विधान बने थे उनके अनुसार कृषकों के ऋण बहुत कम कर दिये गये थे।

ग्रामीण दिवाले का जो विधान है उसे उन ऋणियों के सम्बन्ध में अवश्य लगाना चाहिये जिनके पास खर्च भर पैदा करने के लिये भी भूमि नहीं है और जिनकी सम्पत्ति और ऋण शोधन क्षमता इतनी भी नहीं है कि वह ऋण को बहुत अधिक घटा देने पर भी अदा कर सकें।

आजकल ऋणदाताओं और महाजनों का कृषकों के ऊपर जितना ऋण है उसका निपटारा करने और उसमें कमी करने पर तथा उसका भुगतान करने और जहाँ आवश्यकता हो उसको समाप्त कर देने के वाद और काम करने के ढङ्ग का सुधार कर देने पर वे बड़े लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। हाँ, वे अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन तीनों प्रकार के ऋण देने का प्रबन्ध नहीं कर सकते। बात यह है कि इनमें स्वाभाविक भेद है। अधिक-से-अधिक जो वह कर सकते हैं वह यह है कि वह प्रथम और दूसरे ऋण देने का प्रबन्ध कर दें। फिर, इस बात का भी प्रबन्ध करना होगा कि कृषक फिर ऋणग्रस्त न हो जायें; और यह तभी हो सकता है जब उन्हें इनसे असीमित ऋण लेने से रोक दिया जाय। संयुक्त प्रान्त के एक विधान में (Money-Lender's Bill, 1939) यह दिया हुआ है कि कोई महाजन एक वर्ष में किसी कृषक की उपज के एक चौथाई से अधिक को अपने ऋण की अदायगी में नहीं पा सकता और न ही वह ऐसा बराबर चार वर्षों से अधिक कर सकता है। इसके यह अर्थ हुये कि महाजन केवल उपज की कीमत तक का ही ऋण दे सकता है। कैलवर्ट कमेटी के सुझाव के अनुसार स्वीकृत ऋणदाताओं और महाजनों के उपज के आधार पर दिये हुये ऋणों के लिये उपज से ऋण वसूल करने का प्रथम अधिकार देना चाहिये।

(ब) मध्यकालीन ऋण की आवश्यकता

कृषि के धन्धे के सम्बन्ध के जो व्यय हैं उनके लिये ऋण की

जो आवश्यकता पड़ती है उसके अतिरिक्त कृषकों को मवेशी खरीदने के लिये और खेतों में बराबर किये जाने वाले सुधार करने के लिये मध्यकालीन ऋण की आवश्यकता पड़ती है। जैसा कि पहिले भी कहा जा चुका है, इसमें फसल को लाभ पर बेचने के लिये भी जिस सहायता की आवश्यकता पड़ती है उसको भी सम्मिलित किया जा सकता है। इन कामों के लिये जो ऋण लिया जाता है उसका भुगतान एक वर्ष के अन्दर नहीं किया जा सकता। अतः, उसके लिये एक लम्बी अवधि चाहिये जो तीन वर्ष से लेकर पाँच वर्ष तक की हो सकती है। इसके लिये कृषक जो जमानत दे सकता है, वह उसकी चला सम्पत्ति की हो सकती है, जैसे जेवरात अथवा मवेशी अथवा फसल।

मध्यकालीन ऋण देने के लिये वर्तमान संगठन और उनके

सुधार के लिये सुझाव

अल्प कालीन ऋण के लिये जो संगठन है वही प्रायः मध्य कालीन ऋण भी देते हैं। यदि हमें फसल बेचने के लिये जो सहायता चाहिये उसको हम ले तो यह वहाँ से प्रारम्भ होती है जब वह खलिहान में तैयार हो जाती है। कभी-कभी तो यह उससे पहिले भी प्रारम्भ हो जाती है; अर्थात्, उसी समय से जिस समय से कृषक इस शर्त पर ऋण लेता है कि वह उपज के तैयार होने पर उसे ऋणदाता के हाथ पहिले से निश्चित मूल्य पर बेच देगा। कहना न होगा कि न तो कृषक ही और न यह ऋणदाता ही इस उपज को बहुत दिनों तक अपने पास रख सकते हैं, अतः, वह बड़े-बड़े महाजनो के पास पहुँच जाती है। यह प्रायः अद्वितीय होते हैं; और अन्त में आर्थिक सहायता का बोझ इन्हीं के ऊपर पड़ता है। यदि इन्होंने जिससे माल पाया है उसको पहिले से ही ऋण दे रक्खा था तो यह केवल किताबी जमा-खर्च कर लेते हैं। अन्य स्थितियों में इन्हें नकदी देनी पड़ती है। हाँ, यदि यह इन्हें आदत पर रखते हैं तो इन्हें उसका कुछ प्रतिशत व्यापारी से मिल जाता है। अब, इनको भी आर्थिक सहायता की आवश्यकता पड़ती है जो निम्न संगठनों से प्राप्त होती है—

(१) दूसरे महाजनों से अथवा इम्पीरियल बैंक और सम्मिलित पूँजी के बैंकों से—जिस शर्त पर और जितनी रकम के ऋण इनसे मिल सकते हैं वह उनकी साख पर निर्भर है। कभी-

कभी तो उसे प्रण-पत्र लिखना पड़ता है, कभी-कभी हुण्डी से काम चल जाता है और कभी-कभी उसके पत्र में एक चालू खाता खोल दिया जाता है। जब ऋण सुदती हुण्डी के आधार पर किसी अन्य महाजन से प्राप्त हो जाता है तब कभी-कभी वह हुण्डी फिर किसी व्यापारिक बैंक से भुना ली जाती है।

(२) माल भरती पर ऋण—माल गोदाम में भरा रहता है; अतः, उस पर भी ऋण मिल जाता है। यदि ऋणदाता कोई महाजन ही होता है तो वह उसके ऊपर ऐसे ही ऋण दे देता है। हाँ, यदि वह इम्पीरियल बैंक अथवा कोई अन्य सम्मिलित पूँजी वाला बैंक होता है तो वह गोदाम में अपना ताला और अपने नाम की तख्ती भी लगाता है।

(३) माल की चलानी पर ऋण—यदि माल वहीं की वहीं विक्रित होता है तो उसका मूल्य नकद अथवा बाजार के चलन के अनुसार एक उचित अवधि के अन्दर मिल जाता है; और यदि वह बाहर जाता है तो भी मूल्य या तो सीधे ही प्राप्त हो जाता है या उसके लिये दर्शनी हुण्डी कर ली जाती है जो खाली हो सकती है अथवा जिसके साथ विल्टी भी हो सकती है। खाली हुण्डी होने पर विल्टी माल खरीदार के नाम करके वैसे ही उसके पास भेज दी जाती है, और जब उसके साथ विल्टी भी होती है तब वह बैंक को दे दी जाती है जो अपनी शाखा के द्वारा अथवा अपने किसी अन्य अद्वितीय बैंक के द्वारा हुण्डी की रकम वसूल करवा कर उसे माल खरीदार के नाम कर देता है। प्रायः बैंक माल भेजने वाले से हुण्डी का दाम देकर हुण्डी खरीद लेता है।

उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि आजकल का जो ढङ्ग है उसमें बड़ी अड़चने हैं जिन्हें दूर करना चाहिये। प्रथम तो कृषक अपनी उपज को अधिक दिनों तक अपने पास नहीं रख सकता जिससे उसे ऊँची कीमत नहीं मिल पाती। सहकारी समितियाँ उसके माल को लेकर उसे ऋण दे सकती हैं और फिर माल को अच्छी कीमत पर बेच सकती हैं। इससे कृषक को न केवल ऊँचे दाम ही मिल जायेंगे वरन् उसकी माल बेचने की बहुत सी मुसीबतें भी दूर हो जायेंगी। दूसरे, माल भरने की कठिनाइयाँ हैं। कृषक अपना माल मटकों में, बोरी में, चटाई के घेरों में, मिट्टी और डालियों के घेरों में, अथवा

जमीन के अन्दर की खत्तियों में रखते हैं। बाज़ार में भी यही सब चीज़ें हैं; हाँ, वह कुछ बड़ी अवश्य होती हैं। अतः, चूहों और घुन से अथवा भूमि के अन्दर की नमी से बड़ी हानि होती है। प्रारम्भ के व्यय अधिक होने के कारण अच्छे तरीकों का प्रयोग तो नहीं हो सकता; हाँ, लाइसेन्स प्राप्त गोदाम अवश्य स्थापित किये जा सकते हैं। विधानतः इन्हे हवा सम्बन्धी, मिलावट करने के विरुद्ध, माल के वर्गीकरण की और प्रबन्ध की शर्तों का पालन करना पड़ता है। इन पर सरकार का निरीक्षण और नियन्त्रण भी रहता है। गोदामों की रसीद अच्छे अधिकार-पत्र का काम देती है और इसी से ऋण के लिये जमानत का अथवा हुण्डियों के आधार स्वरूप काम देती हैं। तीसरे, अधिकांश व्यापार नकदी का होता है, जहाँ उधार होता भी है वहाँ भी केवल जमा खर्च कर लिया जाता है; साख-पत्र प्रयोग में नहीं लाये जाते। मुहती हुण्डियों का चलन बढ़ाने की आवश्यकता है। यह अच्छा अधिकार देने वाली होने के कारण सब जगह स्वीकृत हो जाती हैं और यह साख की बुनियाद का काम करती हैं। चौथे, दर्शनी हुण्डियों के आधार स्वरूप बिल्टियाँ बहुत कम होती हैं। अतः, उपर्युक्त सुधार होने से बैंक हुण्डियों के व्यवसाय को अधिक मात्रा में करेंगे।

कुछ प्रान्तों में वहाँ की सरकारें रुपया उधार देकर गोदामों के बनने में बड़ी सहायता कर रही हैं। तो भी इस काम को रिज़र्व बैंक बड़ी अच्छी तरह से अपने हाथ में ले सकता है और उसमें कृषि सम्बन्धी अन्वेषण करने के लिये जो इम्पीरियल काउन्सिल है वह भी इस सम्बन्ध की माल के छाटने और रखने की जो समस्याएँ हैं उनको हल करने में बड़ी सहायता दे सकती है। नोटों से जो लाभ होता है वह इस काम में लगाया जा सकता है। गोदामों का प्रबन्ध भी इसकी देख-रेख में हो सकता है। इससे उनकी रसीदें सर्वोच्च साख-पत्र का काम दे सकती हैं।

अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति ऋणदाता और महाजन लोग कर सकते हैं। वे अल्पकालीन ऋण के साथ-साथ मध्यकालीन ऋण भी आसानी से दे सकते हैं।

दीर्घकालीन ऋण की आवश्यकतायें

भारतीय कृषक बहुत से कामों के लिये दीर्घकालीन ऋण लेते

हैं। इनकी अवधि २० वर्ष से लेकर ३० वर्ष तक की हो सकती है। इनके उद्देश्य सहकारी समितियों के और महाजनों के पुराने ऋण का भुगतान करना, ऊसर भूमि को उपजाऊ बनाना, खेतों का सुधार करना, मकान बनवाना, कुंओं को खुदवाना, भूमि खरीदना, सिंचाई की नालियों को बनाना और मशीन, इत्यादि खरीदना हो सकते हैं। सहकारी समितियों के और महाजनों के ऋणों का भुगतान करने की आवश्यकता के विषय में पहिले ही काफी कहा जा चुका है। बढ़ती हुई जन सख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये ऊसर भूमि को उपजाऊ बनाने और खेतों के सुधार करने की भी बड़ी आवश्यकता है। कहीं-कहीं पर जहाँ सिंचाई का प्रबन्ध नहीं है वहाँ कुवों का खुदवाना भी बहुत आवश्यक हो गया है। कृषकों के लिये अच्छे मकान बनाने की भी बड़ी आवश्यकता है। फिर, कुछ खेत तो बहुत ही छोटे हैं। अतः, बगल की जमीन खरीदने की बहुत आवश्यकता है। कभी-कभी अपने परिवार के ही उन लोगों की जमीन खरीदने की आवश्यकता पड़ जाती है जो कृषि का उद्यम नहीं करना चाहते। इन्हे खरीद लेने से अपने खेत बड़े हो जाते हैं, अथवा छोटे होने से रुक जाते हैं; और दूसरे लोगों के उन्हे खरीद लेने से जो भगाड़े का डर हो जाता है वह नहीं रहता। अन्तिम बात यह है कि खेतों के एकीकरण और सुधार के फलस्वरूप मशीन, इत्यादि के प्रयोग की भी आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है। कहना न होगा कि इन सब कामों के लिये जो ऋण लिये जाते हैं उनका भुगतान जल्दी नहीं हो सकता। सच तो यह है कि इनसे उत्पन्न लाभ बहुत दिनों तक चलते हैं अथवा इनका भुगतान भी उसी अवधि के अन्दर होना चाहिये।

भूमि-बन्धक बैंक

दीर्घकालीन ऋण की प्राप्ति के लिये किसी संगठन के न होने के कारण कृषकों को अपनी इस माँग की पूर्ति के लिये महाजनों का दरवाजा खटखटाना पड़ता है और उन्हे बड़ी ऊँची दर के हिसाब से व्याज देना पड़ता है तथा अन्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जिससे कि उनके ऊपर एक बड़ा भारी बोझ लड़ता चला जा रहा है। यह सुभाष तो पहिले ही रक्खा जा चुका है कि पुराने ऋणों का निपटारा हो जाना चाहिये और उन्हे काफी घटाकर उनका भुगतान हो

जाना चाहिये। महाजन कृषकों की सब आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते। उन्हें केवल अल्पकालीन तथा मध्यकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिये। दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये भिन्न-भिन्न देशों में वहाँ की सरकारों ने भूमि संस्थाएँ स्थापित कर रखी है। इधर हमारे देश में भी कुछ भूमि बन्धक बैंक स्थापित कर दिये गये हैं, किन्तु उनकी संख्या बहुत कम है। सन् १९४२-४३ में यह २७१ थी। सदस्यों की संख्या १,१९,७८२ थी; हिस्सों की पूँजी ४९,१६,९६७ रु० थी; जनता और सरकार द्वारा लिये गये ऋण-पत्रों का मूल्य क्रमशः ३६४,०२,५५५ रु० और ७,१९,१४८ रु० था; जमा १०,९९,५५६ रु० की थी; सुरक्षित कोष और दूसरे कोष २३०६,८६० रु० के थे और ऋण ३,२३,६९, ८७८, रु० के थे तथा इस तरह से कुल कार्यशील पूँजी ७,७८,१७,९६४ रु० की थी। इसमें से जनता को ३६,१८,१३० रु० का ऋण दिया गया था और बैंकों तथा समितियों को ३८,४८,८१४ रु० का। देश के विस्तार को देखते हुये यह स्थिति बहुत ही असन्तोषप्रद थी।

यह बैंक मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं :—

(अ) नितान्त सहकारी, (ब) व्यापारिक और (स) अर्ध सहकारी (Quasi co-operative)। नितान्त सहकारी भूमि बन्धक बैंक ऋण लेने वालों के ऐसे संगठन हैं जो व्याज देकर रहन-पत्रों के आधार पर द्रव्य एकत्रित करते हैं। व्यापारिक भूमि बन्धक बैंक की हिस्सों की पूँजी होती है और वह लाभ के लिये काम करता है तथा लाभ की बँटनी करता है। अर्ध सहकारी बैंक के ऋण लेने वाले तथा ऋण न लेने वाले दोनों प्रकार के सदस्य होते हैं और वे एक बहुत बड़े क्षेत्र में काम करते हैं। इनकी हिस्सों की पूँजी होती है और दायित्व सीमित होता है।

भारतवर्ष में अधिकांश बैंक अर्ध सहकारी हैं। बात यह है कि वे कुछ ऋण न लेने वाले व्यक्तियों को भी प्रारम्भिक पूँजी प्राप्त करने और उनके व्यापारिक गुणों, संगठन करने और प्रबन्ध करने की शक्ति को पाने के उद्देश्य से अपने सदस्य बना लेते हैं।

मद्रास में सहकारी भूमि बन्धक बैंक सबसे अधिक हैं। सन् १९२५ के लगभग सीमित दायित्व के आधार पर हिस्सों की पूँजी वाले और प्राप्त पूँजी से अठगुना और दसगुना ऋण लेने की शक्ति

रखनेवाले दस बैंक वहाँ पर स्थापित किये गये थे। ऋण देने पर उनके पास जो भूमि रेहन के रूप में प्राप्त हो जाती थी उसी के आधार पर उन्हें ऋण-पत्रों को निकालने का अधिकार दे दिया गया था। सरकार ने भी कम-से-कम जनता के द्वारा क्रय किये गये ऋण-पत्रों के बराबर और एक बैंक के अधिक से-अधिक ५०,००० रु के ऋण-पत्र तथा सारे प्रान्त के अधिक से-अधिक २३ लाख के ऋण-पत्र खरीदने का वचन दिया था। किन्तु अधिकांश बैंक जनता में ऋण-पत्र बेचने में काफी सफल नहीं हुये। अतः, टाउन्सैण्ड कमेटी की सिफारिश के अनुसार एक केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंक की संस्थापना की गई जो सब बैंकों को आर्थिक सहायता देने के लिये और एक की वचत दूसरे को देने के लिये बड़ा उपयोगी सिद्ध हुआ। ऋण पत्र निकालने का काम यही करने लगा और इसमें इसको सफलता भी प्राप्त हुई। प्रान्तीय सरकार ने इन पर के सूद देने का दायित्व अपने ऊपर ले लिया। उसने १५००० रु० की मुक्त पूँजी भी दी। साथ ही उसके अनुभवी काम करने वाले भी इसे दिये गये प्रारम्भिक भूमि बन्धक बैंक अपने रेहन इसको दे देते हैं और यह उनके आधार पर ऋण-पत्र निकालता है। सन् १९४२-४३ में प्रारम्भिक भूमि बन्धक बैंकों की संख्या ११९ हो गई थी।

अन्य प्रान्तों में भी भूमि बन्धक है। सन् १९४०-४१ में पञ्जाब में १०, बम्बई में १८, बङ्गाल में १० और आसाम में ४ भूमि बन्धक बैंक थे। पञ्जाब के दो बैंक तो सारे जिले भर में काम करते थे और शेष केवल एक तहसील ही में काम करता था। मद्रास को छोड़कर अन्य प्रान्तों में केन्द्रीय बैंक नहीं हैं। अतः, वहाँ प्रारम्भिक बैंक ही अपने ऋण-पत्र निकालते हैं। वस्तुतः, एक केन्द्रीय सङ्गठन की तो सभी जगह आवश्यकता है। इन सहकारी भूमि बन्धक बैंकों के ढङ्ग भिन्न-भिन्न स्थानों में भिन्न-भिन्न है। साधारणतया तो उनके यहाँ की सरकारों ने ऋण-पत्रों के व्याज अथवा उनकी पूँजी अथवा दोनों के दायित्व को अपने ऊपर ले लिया है और कहीं-कहीं तो कुछ को खरीदा भी है। फिर, उन्होंने अपने अनुभवी कर्मचारियों का, आडिट का और नियन्त्रण का भी प्रबन्ध कर रक्खा है।

भूमि बन्धक बैंक को और भी उपयोगी बनाया जा सकता है।

प्रथम तो उनमें काम करने के ढङ्ग को एक सा किया जा सकता है। दूसरे, हर प्रान्त में एक केन्द्रीय बैंक का होना आवश्यक है। जहाँ वह नहीं खुल सकते वहाँ बन्धक, बङ्गाल और पञ्जाब की ही तरह प्रान्तीय सहकारी बैंकों की ऋण-पत्र निकालने का और प्रारम्भिक बैंकों की सहायता करने का काम दिया जा सकता है। तीसरे, जहाँ-जहाँ कृषकों की भूमि की बिक्री पर रोक है, वहाँ-वहाँ पर उसके कानून को इस प्रकार बदलना पड़ेगा कि उनको भूमि बन्धक बैंकों को आसानी से हस्तान्तरित किया जा सके। चौथे, प्रारम्भ में उनकी सफलता के लिये सरकारी सहायता की आवश्यकता पड़ेगी; अतः, वह प्राप्त होनी ही चाहिये। अन्तिम बात यह है कि रिजर्व बैंक भी उन्हें कई प्रकार से सहायता दे सकता है। अभी तक वह केवल उन्हीं केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंकों को जो प्रान्तीय सहकारी बैंकों के बराबर घोषित कर दिये गये हैं केवल आवश्यकता पड़ने पर सरकारी साख-पत्रों के आधार पर ९० दिन के लिये ऋण देने के लिये तैयार है। यदि उनके ऋण-पत्रों पर के व्याज और उनकी पूँजी का दायित्व प्रान्तीय सरकार ने अपने ऊपर ले लिया है और वह बाजार में आसानी से बिक सकते हैं तो वह उन्हें खरीद भी लेता है। फिर, वह उनके कामों का भी अध्ययन करता रहता है और समय पड़ने पर उन्हें मन्त्रणा भी देता है। उसने उनकी सहायता करने के सम्बन्ध में एक विज्ञप्ति तैयार की है और उसे केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंकों और सहकारी समितियों के प्रान्तीय रजिस्ट्रारों के पास भेजा है। इसमें ऋण-पत्रों के निकालने के सम्बन्ध में बहुत अच्छे सुझाव हैं। किन्तु बहुत से ऐसे काम हैं जो रिजर्व बैंक अभी कर सकता है। वह उनके ऋण-पत्रों को बेच सकता है। द्रव्य के बाजार से बराबर सम्बन्धित रहने के कारण वह यह जानता है कि इनके निकालने का कौन सा समय सबसे उपयुक्त है और इन पर व्याज की क्या दर देनी चाहिये। एक साधारण भूमि बन्धक बैंक की अपेक्षा इसकी शक्ति अधिक अपार है। जब यह ऋण-पत्र निकालेगा तो वह बहुत ही सुरक्षित समझे जायेंगे। इसका भूमि बन्धक बैंकों के ऊपर कुछ नियन्त्रण भी होना चाहिये। उनके हिसाब-किताब का इसी को आडिट करवाना चाहिये। इसे उनके व्यवसाय के सम्बन्ध में मन्त्रणा देनी चाहिये और उनके ऋण देने में भी नियन्त्रण रखना चाहिये। फिर, अचल

सम्पत्ति के मूल्य आंकने का काम भी बहुत कठिन है। अतः, यह इसके लिये भी अपने अनुभवी कर्मचारी दे सकता है।

भूमि बन्धक बैंक केवल कृषकों की ही सहायता कर सकते हैं। किन्तु कृषि से सम्बन्ध रखने वाले अन्य लोगों की सहायता करने का भी प्रश्न है और इनमें बड़े-बड़े भूमिपति भी हैं। अभी तक तो वह केवल उपयोग के ही लिये बड़े ऊँचे व्याज पर ऋण लेते रहे हैं। किन्तु वे उत्पादन सम्बन्धी कामों के लिये भी ऋण ले सकते हैं। उदाहरण के लिये भूमि में और कृषि के ढङ्ग में सुधार करने के लिये भी वह ऋण ले सकते हैं। अतः, ऐसी अवस्था में इन्हें कम व्याज पर ऋण मिलने का प्रबन्ध होना चाहिये। बारहवें अध्याय में बंगाल के लोन आफिसों के विषय में बताया जा चुका है। बैंकिंग सम्बन्धी अन्वेषण करने वाली बंगाल की और केन्द्रीय कमेटियों ने इनके ऊपर भी नियन्त्रण रखने के सुझाव रखे थे। आजकल थोड़ी-थोड़ी पूँजी की ऐसी बहुत सी संस्थाएँ हैं। इनका एकीकरण और सुधार होना चाहिये। इसके लिये एक अच्छे विधान की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिये अन्य प्रान्तों में भी सम्मिलित पूँजी वाले भूमि बन्धक बैंक स्थापित किये जा सकते हैं।

रिज़र्व बैंक का कृषि-साख-विभाग और कृषि की सहायता सम्बन्धी उसके कार्य

इस अध्याय में और पिछले अध्यायों में भी रिज़र्व बैंक के कृषि-साख-विभाग का कई बार उल्लेख किया जा चुका है। अतः, हमें यहाँ पर उसके कार्यों का एक साथ अवलोकन कर लेना चाहिये। इस विभाग के तीन अङ्ग हैं :—कृषि साख, बैंकिंग और अङ्क तथा अन्वेषण (Statistical and Research)। यहाँ पर हमें केवल कृषि-साख-अङ्ग का अध्ययन करना है; अन्य अंगों का अध्ययन हम आगे चलकर उपयुक्त स्थान में करेंगे।

कृषि-साख-अङ्ग के तीन कार्य हैं। प्रथम तो वह ग्रामीण अर्थ की और विशेषतः सहकारिता की समस्याओं का अध्ययन करता है और ग्रामीण ऋण से मुक्ति दिलवाने के सम्बन्ध में कानून बनवाता है। दूसरे, यह अपने कर्मचारियों द्वारा सहकारिता के आन्दोलन से निकटतम सम्बन्ध रखता है। इसके लिये यह सारे देश में इसका

अध्ययन करते हैं। उनके सुझाव बराबर छपते रहते हैं। तीसरे, यह अपनी सेवाओं को उन केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों के लिये और सहकारी तथा अन्य बैंकों के लिये देता है जो कृषि साख-सम्बन्धी समस्याओं पर इसकी राय लेना चाहते हैं।

रिज़र्व बैंक विधान की ५५ (१) धारा के अनुसार रिज़र्व बैंक पर जो दायित्व रक्खा गया था उसके सम्बन्ध में जो प्रारम्भिक और वैधानिक रिपोर्टें निकली हैं उनका उल्लेख भी किया जा चुका है। इन्हें और इण्डीजेनस बैंकों को रिज़र्व बैंक से सम्बंधित करने के लिये जो योजना तैयार की गई थी उसे तैयार करने का श्रेय उसके कृषि-साख-अङ्ग को ही है। कोदिनर के बैंकिंग यूनियन की रिपोर्ट सहकारी ग्राम्य बैंक, बर्मा में सहकारी आन्दोलन की गति विधि और भारतवर्ष में उसका उपयोग, पञ्जाब के होशियारपुर जिले की ऊना तहसील के एक गाँव पंजावर में सहकारिता प्रभृति स्मरण-पत्र भी इसी ने निकाले हैं। भिन्न-भिन्न प्रान्तों में ऋण सम्बन्धी जो भिन्न-भिन्न विधान बने हैं वह भी इसकी दोनों रिपोर्टों में दिये हुये सुझावों के आधार पर ही बने हैं। बिलों पर जो स्टाम्प कर लगता है उसमें जो कमी की गई है वह भी इसी के प्रयत्नों के फलस्वरूप है।

किन्तु यह विभाग केवल इतना ही नहीं कर सकता। भारतवर्ष में बिल के बाज़ार का विकास बहुत ही आवश्यक है। अभी तक बैंक ऋण और डिस्काउण्ट दोनों के लिये एक ही दर रखे हुये हैं। इस विभाग को उसे यह सुझाना चाहिये कि ऋण पर की व्याज की दर डिस्काउण्ट की दर से कुछ ऊँची रखनी चाहिये। इसे उसे यह भी सुझाना चाहिये कि वह सर्राफों और अन्य नागरिक महाजनों को गाँवों के महाजनों की मुदती बिलों के आधार पर आर्थिक सहायता करने के लिये प्रोत्साहित करे। ग्रामीण महाजन कृषकों को जो ऋण देते हैं उसमें भी उन्हें उनके ऊपर बिल करने के लिये कहा जा सकता है। यह बिल फसल की मुदत के होने चाहिये क्योंकि उसी की बिक्री से तो वे लोग इनका भुगतान कर सकते हैं। इस बैंक को भी अन्य केन्द्रीय बैंकों की तरह द्रव्य का व्यापार करने वाले सभी लोगों से आवश्यकता पड़ने पर सीधा काम करने का अधिकार मिला हुआ है। किन्तु इस विभाग को उसे यह समझाना पड़ेगा कि वह कम से कम कुछ दिनों तक तो यह काम साधारण रूप में भी करता

रहे। बात यह है कि बिलों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिये इसे प्रारम्भ में गाँवों में ऋण देने वाली संस्थाओं से अपना सीधा सम्बन्ध रखना पड़ेगा। दूसरे, इसे मूल्यांकन और आडिट के लिये अपने कर्मचारी रखने चाहिये। इससे सहकारी और भूमिवन्धक बैंकों को बड़ा लाभ होगा। तीसरे, इसे रिजर्व बैंक विधान का इस प्रकार संशोधन करा लेना चाहिये कि उसके अन्तर्गत देशी रियासतों के^१ सहकारी बैंक भी आ जायँ। आजकल ऐसा नहीं है। चौथे, इसे बंगाल के लोन आफिसों और मद्रास के निधि और चिट फण्ड की समस्याओं का भी अध्ययन करना चाहिये और उनको अधिक उपयोगी बनाने के लिये सुझाव रखने चाहिये। पाँचवे, इसे जैसा कि पहिले भी बताया जा चुका है बैंक को इस बात की आवश्यकता समझानी चाहिये कि वह उन केन्द्रीय बैंकों से सीधे काम करे जिनका काम करने का स्तर काफी ऊँचा है। अन्तिम बात यह है कि इसे जिस प्रकार के गोदामों का पहिले भी उल्लेख किया जा चुका है उसी प्रकार के गोदामों की संस्थापना के लिये भी प्रयत्न करना चाहिये। इससे कृषि की आर्थिक समस्या को सुलझाने में बड़ी सहायता प्राप्त होगी।

कृषि-साख और सरकार

कृषि को साख देने के लिये सरकार कृषि ऋण विधान और सुधार ऋण विधान के अन्तर्गत काम करती है। यह जो ऋण देती है वह प्रचलित भाषा में तकावी के नाम से विख्यात है। साधारणतया तो हर साल प्रत्येक प्रान्त में कुछ ही लाख रुपये बाँटे जाते हैं। हाँ, मुसीबत के समय यह करोड़ दो करोड़ तक पहुँच जाते हैं। तकावी अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों होती है। अल्पकालीन तकावी प्रायः बीज और मवेशियों के क्रय के लिये काम में आती है और उसी वर्ष की उपज से वसूल कर ली जाती है जिस वर्ष की उपज के लिये वह प्रयोग में लाई जाती है। इसके विपरीत दीर्घकालीन तकावी स्थायी सुधारों के लिये काम में लाई जाती है और कई वर्षों में किस्त से वापिस की जाती है। साधारणतया दीर्घकालीन तकावी नहीं बाँटी जाती। अल्पकालीन तकावी में कभी-कभी बीज दिये जाते हैं। जब मुसीबत पड़ती है तब तकावी बहुत अच्छी समझी जाती है।

^१ किन्तु अब देशी रियासतों की स्थिति ही बदल गयी है।

किन्तु साधारणतया तो कृषक ऊँचा ब्याज होने पर भी सरकार की अपेक्षा महाजनों से ऋण लेना अधिक अच्छा समझते हैं। निश्चय ही इसका एकमात्र कारण यह है कि तकावी के वितरण में अनेकों दोष भरे पड़े हैं। तकावी देने के पहिले बहुत सी पूछ-ताछ की जाती है जिसके लिये पटवारी और कानूनगो काम में लाये जाते हैं। उनकी सिफारिशें प्रायः सत्य नहीं होतीं। अतः, तकावी अपेक्षित लोगों को न मिलकर उन्हें प्राप्त हो जाती है जो पटवारियों को खुश कर लेते हैं। फिर, इन्हें बाँटने के केन्द्रों के बहुत कम होने के कारण कृषकों को बहुत समय तो राह चलने में ही खराब करना पड़ता है। उन्हें वहाँ पर पहुँचकर भी कई दिनों तक पड़ा रहना पड़ता है। इसमें सबमें खर्च पड़ता है। इसके अतिरिक्त यह समय पर बहुत कम मिल पाती है, और प्रत्येक व्यक्ति को जो रकम मिलती है वह उसकी आवश्यकता से बहुत कम होती है। उसे वसूल करने के तरीके भी बहुत सख्त होते हैं। अतः, इन सब बुराइयों को इन्हें सहकारी समितियों के द्वारा वितरण कराने से दूर किया जा सकता है। वास्तव में सरकार इस काम को बहुत अच्छी तरह से नहीं कर सकती।

प्रश्न

(१) कृषि सम्बन्धी अर्थ में क्या विशेष कठिनाइयाँ पड़ती हैं ? कृषकों की मँग का वर्गीकरण कीजिये और प्रत्येक वर्ग को स्पष्ट तौर पर समझाइये।

(२) रिजर्व बैंक कृषि सम्बन्धी ऋण किन-किन तरीकों पर देता है ? इसमें कौन-कौन से मुख्य दोष हैं ?

(३) इम्पीरियल बैंक आफ इण्डिया और दूसरे सम्मिलित पूँजी के बैंक कृषि की कैसे सहायता करते हैं, इसे समझाइये।

(४) सहकारी साख समिति से आप क्या समझते हैं ? दो तरह की जो समितियाँ होती हैं उनके भेद बताइये।

(५) इस देश में सहकारिता के विकास का इतिहास बताइये। इस समय उसकी क्या स्थिति है ?

(६) सहकारी साख समितियों और बैंको को उनकी पूँजी कहाँ से प्राप्त होती है ? वे उसका किस प्रकार उपयोग करते हैं ?

(७) इस देश में आजकल के सहकारिता आन्दोलन में कौन-कौन से दोष हैं ? उन्हें दूर करने के लिये सुझाव रखिये।

(८) एक ऐसी योजना बनाइये कि जिससे महाजन लोग और अच्छी तरह से कृषि की सहायता कर सकें । इस सम्बन्ध में निपटारे की कार्य-प्रणाली और उनके लाभ के विषय में बताइये ।

(९) भारतवर्ष में कृषि की विक्री को किस प्रकार आर्थिक सहायता मिलती है ? उसे सुधारने के लिये अपने सुझाव रखिये ।

(१०) समस्त भारतवर्ष में भूमि-बन्धक बैंकों की स्थापना की आवश्यकता के विषय में अपनी सम्मति दीजिये । वे किम तरह से और अधिक उपयोगी बनाये जा सकते हैं ?

(११) रिजर्व बैंक का कृषि साख विभाग कृषि के सम्बन्ध में कौन-कौन से कार्य करता है और वह देश को कैसे और अच्छी तरह से लाभ पहुँचा सकता है ? इस सम्बन्ध में यह भी बताइये कि वह यहाँ पर बिल बाज़ार स्थापित करने के लिये रिजर्व बैंक का ध्यान और किन-किन बातों की ओर आकर्षित करे ?

(१२) तत्कालीन से आप क्या समझते हैं ? इसके वितरण में कौन-कौन से दोष हैं ? क्या इसे किसी तरह से सुधारा जा सकता है ?

अध्याय १५

उद्योग सम्बन्धी आर्थिक व्यवस्था

उद्योग-धन्यों की उन्नति के लिये आर्थिक व्यवस्था का उतना ही महत्व है जितना किसी अन्य वस्तु का हो सकता है । अतः, इस सम्बन्ध में अभी तक जो कुछ भी नहीं किया गया है उससे यह स्पष्ट है कि औद्योगीकरण की आवश्यकता यहाँ पर कभी भी समझी ही नहीं गई है । वात यह है कि जब कभी भी यहाँ पर उत्पादन की वृद्धि के विषय में सोचा गया है तब कृषि के लिये ही सोचा गया है जिसका फल यह हुआ है कि उद्योग-धन्य पीछे पड़ गये हैं । द्वितीय महायुद्ध के समय में भी इस तरफ कोई विशेष वात नहीं की गई । देश की सरकार ने उसके प्रारम्भ होते ही यहाँ पर वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान के लिये एक बोर्ड बँटाल दिया था और उस पर बहुत रुपया खर्च किया था, किन्तु किसी धन्य की स्थापना के लिये कुछ

भी नहीं किया गया। जो कुछ अनुसन्धान भी हुये वे छोटे-छोटे रसायन सम्बन्धी धन्धों के सम्बन्ध में ही हुये हैं, उदाहरण के लिये औपधियाँ, प्लास्टिक और शीशे की चदरें, इत्यादि ही हैं। भारी धन्धों पर तो चाहे वह इस्त्रीनियरी से सम्बन्ध रखते हों और चाहे रसायन से कोई ध्यान ही नहीं दिया गया। अतः, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि भारतीय इसे ब्रिटिश उद्योग-पतियों तथा व्यापारियों के कारण ही बताते हैं जो हर तरीके से अपनी रक्षा का निरन्तर प्रयत्न करते रहते हैं। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि हमारी पुरानी सरकार उद्योग-धन्धों की उन्नति को छोड़कर कृषि की उन्नति की बातें क्यों करती रहती थी। कांग्रेस का रुख भी कुछ अच्छा नहीं रहा है। युद्ध के पहिले कुछ समय तक इसने जब ग्रान्तों में शक्ति ग्रहण की थी तब जो कुछ भी किया था वह कृषि की आर्थिक व्यवस्था ही के लिये किया था। फिर, हमारे नेतागण जब भी धन्धों की बात-चीत करते थे केवल घरेलू धन्धों की ही बात-चीत करते थे फैक्टरी के धन्धों की नहीं। किन्तु देश के आठ उद्योगपतियों ने भारतवर्ष के औद्योगीकरण की जो योजना बनाई थी उसमें उन्होंने बड़े पैमाने के धन्धों पर काफी जोर दिया था और इधर जब से हमने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है तब से बड़ी आशाये बँध गई है। वर्तमान सरकार की जितनी योजनाये देश की उन्नति के लिये हैं उन सब में उद्योग-धन्धों की उन्नति को पहिला स्थान दिया गया है। इधर हमारे प्रधान मन्त्री और उद्योग मन्त्री की जितनी वक्तृतायें हुई हैं उन सबसे यह अच्छी तरह से स्पष्ट होता है। किन्तु यदि अभी तक कुछ नहीं किया गया है तो उसका एकमात्र कारण यही है कि हमारी सरकार इस समय देश के विभाजन से उत्पन्न हुई समस्याओं को हल करने में लगी हुई है।

उद्योग धन्धों की आवश्यकतायें

प्रायः उद्योग-धन्धों की भी वही आर्थिक आवश्यकतायें हैं जो कृषि की हैं, अर्थात् अल्पकालीन, मध्यकालीन, और दीर्घकालीन। अल्पकालीन आवश्यकताये कच्चे माल और स्टोर्स के क्रय के सम्बन्ध की, उपज के विक्रय के सम्बन्ध की और मजदूरी देने तथा दैनिक व्यय को पूरा करने के सम्बन्ध की हैं। मध्यकालीन आवश्यकतायें भी

उपर्युक्त के सम्बन्ध की हो सकती है और उनके लिये लिये हुये ऋण का भुगतान एक वर्ष से पाँच वर्ष के अन्दर तक हो सकता है। दीर्घकालीन ऋण प्रारम्भ में तो ज़मीन की क्रय के लिये, कारखाने की इमारत बनाने के लिये और मशीन, इत्यादि लगाने के लिये तथा वाद में विस्तार और संगठन के लिये लिया जाता है। इसे अंग्रेजी में ब्लाक कैपिटल भी कहते हैं। हिन्दी में यह धिरी हुई पूँजी कही जा सकती है। दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन आवश्यकताओं अथवा धिरी हुई और कार्यशील पूँजी के बीच का अनुपात धन्धे के अनुसार भिन्न-भिन्न होता है। उत्पादन जितना ही पेचीदा होता है उतनी ही अधिक दीर्घकालीन आवश्यकताये अथवा धिरी हुई पूँजी की जरूरत पड़ती है। पाट, रुई, लोहे और स्टील, बिजली और खदान जैसे संगठित धन्धों में धिरी हुई पूँजी बहुत लगती है। ओपधियाँ, प्लास्टिक शीशे, चदरों और विशेषतः घरेलू धन्धों में इसका उल्टा है। सच्चे में यह उपज के मूल्य पर और उसके लिये जो समय लगता है उस पर निर्भर है। इनके अलावा और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कच्चे माल के खरीदने और बने हुये माल के बेचने के तरीके और मूल्य के भुगतान के तरीके, इत्यादि। जैसा कि हम आगे चलकर देखेंगे जितनी ही अधिक धिरी हुई पूँजी की आवश्यकता पड़ती है उतनी ही अधिक अर्थ की दिकत होती है।

भारतवर्ष में वर्तमान स्थिति

भारतवर्ष में वर्तमान स्थिति तनिक भी सन्तोषजनक नहीं है। अंग्रेजी व्यापारिक बैंकों का तो यह चलन है कि वे दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति करते ही नहीं। उनके यहाँ इसके लिये अलग संस्थाये हैं जैसे सिक्योरिटियों की व्यवस्था करने वाले ट्रस्ट और बैंको के औद्योगिक विभाग का कर्नलियाँ। हमारे यहाँ पर अंग्रेजी चलन के ही अनुसार औद्योगिक बैंकों की संस्थापना पर जोर दिया जा रहा है। जैसा की पहिले ही बतया जा चुका है इस सम्बन्ध में पहिला प्रयत्न टाटा औद्योगिक बैंक की संस्थापना से हुआ था। इसमें सदेह नहीं कि वह बहुत दिनों तक नहीं चल सका, किन्तु उसी तरह के कुछ अन्य बैंक भी चलाये गये थे जिनमें से इण्डस्ट्रियल बैंक आफ वेस्टर्न इण्डिया, कारतानी इण्डस्ट्रियल बैंक, रायकुट इण्डस्ट्रियल बैंक,

शिमला बैंकिंग ऐण्ड इण्डस्ट्रियल कम्पनी, लक्ष्मी इण्डस्ट्रियल बैंक, इत्यादि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। किन्तु इनमें विदेशी बैंकों की-सी प्रभावोत्पादक संस्थापन शक्ति, ज्ञान की दृढ़ता, और संगठन करने की योग्यता नहीं है। देश के विस्तृत क्षेत्र का ध्यान रखते हुये इनकी सख्या भी बहुत कम है। सन् १९१८ के औद्योगिक कमीशन ने भी सरकारी सहायता प्राप्त और एक निश्चित ढङ्ग पर काम करनेवाले औद्योगिक बैंकों की संस्थापना की सिफारिश की थी। किन्तु केवल सन् १९३६ ही में पहिले-पहिल सयुक्त प्रान्त की सरकार ने आद्योगिक 'अर्थ कमेटी' की उन सिफारिशों को मानकर जिनमें उसने बड़े और छोटे धन्धों को अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन ऋण देने के लिये एक इण्डस्ट्रियल क्रेडिट बैंक की संस्थापना करने के लिये सुझाव रखे थे इस तरह का एक बैंक स्थापित किया। इस बैंक ने सरकार से एक सम-भौता कर लिया है जिसके अनुसार १५ वर्ष तक सरकार ने इसे इसकी प्राप्त पूँजी का ४ प्रतिशत और अधिक से अधिक ६०,००० रु० वार्षिक इसलिये देने का वायदा किया है कि यह प्रतिवर्ष ४ प्रतिशत लाभ की वेंटनी कर सके। किन्तु इसका कार्य बहुत प्रसशनीय नहीं रहा है, और इसमें कोई आश्चर्य भी नहीं है क्योंकि सरकार की इतनी कम मदद के साथ कोई बैंक कुछ अधिक कर ही नहीं सकता। सन् १९३७ में बंगाल की सरकार ने वहाँ के छोटे-छोटे धन्धों की सहायता करने के लिये एक इण्डस्ट्रियल क्रेडिट कारपोरेशन की संस्थापना में हाथ बटाया था। सन् १९४० में यही बम्बई इकानमिक बोर्ड ने भी किया था। किन्तु इन्होंने भी कोई प्रसंशात्मक कार्य नहीं किया। अन्त में सन् १९४६ में एक अखिल भारतीय इण्डस्ट्रियल फिनान्स कारपोरेशन की स्थापना के सम्बन्ध में एक बिल पेश हुआ था जो अब विधान बन गया है। देखना चाहिये कि यह क्या करता है। जहाँ तक इम्पी-रियल बैंक और दूसरे व्यापारिक बैंकों का सम्बन्ध है वे दीर्घकालीन ऋण नहीं देते। वे जो कुछ सहायता करते हैं वह केवल मध्यकालीन तथा अल्पकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये ही होती हैं, और इनका अध्ययन हम आगे चलकर करेंगे।

उपर्युक्त स्थितियों में यहाँ पर दीर्घकालीन पूँजी के लिये केवल तीन ही साधन बच रहते हैं। इनमें से प्रथम तो जो यहाँ के धन्धों के प्रारम्भ करने में भी बड़ा सहायक हुआ है व्यक्तिगत है। इसमें एक

परिवार के लोग अथवा उसके कुछ मित्र ही उसकी सहायता करते हैं। इसी से मैनेजिङ्ग एजेन्सी प्रणाली का सूत्रपात हुआ, अथवा यह कहिये कि वह यही है। दूसरे, कुछ स्थानों में इन्हे जमा प्राप्त हो जाती है जो एक तरह से स्थायी ही है। अन्तिम में योजना-पत्र निकालकर जनता में हिस्से और ऋण-पत्र बेचे जाते हैं।

मैनेजिङ्ग एजेन्सी प्रणाली

यदि हम प्रथम को ले तो कुछ ऐसे व्यक्ति अथवा फर्म हैं जिनके पास अच्छी पूँजी है और जो किसी काम को चलाने के लिये प्रारम्भिक काम करते हैं, उसकी सस्थापना करते हैं, उसे आर्थिक सहायता देते हैं अथवा उसका दायित्व ले लेते हैं और प्रायः उसकी व्यवस्था करते हैं। इनके जिन्हे मैनेजिङ्ग एजेण्ट कहते हैं मुख्य काम नीचे दिये हुये हैं :—

(१) ये कम्पनी स्थापक का काम करते हैं। इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है कि एक बात जिस पर किसी औद्योगिक इकाई की सफलता निर्भर है यह है कि उसके सम्बन्ध की योजना व त अच्छी बनी हो और वह अच्छी अवस्था में आरम्भ की गई हो। इसके लिये संगठनकर्ता में एक बड़ी रचनात्मक योग्यता होनी चाहिये। भारतवर्ष में आधुनिक धन्धों को प्रारम्भ करने का श्रेय केवल दो ही वर्ग के लोगों को है। एक तो अग्रेज व्यापारी जो अग्रेजी व्यापारिक कोठियों का प्रतिनिधित्व करने के लिये आये थे और दूसरे बम्बई के और फिर अहमदाबाद तथा अन्य स्थानों के रुई के व्यापारी। जो कुछ भी उन्नति हुई है उसमें से अधिकांश का श्रेय प्रत्यक्ष रूप में अथवा अप्रत्यक्ष रूप में इन्हीं को है। इस सम्बन्ध में सर्वश्री टाटा सन्स ऐण्ड कम्पनी, एलिङ्गु यूल ऐण्ड कम्पनी, कैटिलवेल् वलेन ऐण्ड कम्पनी, करीम भाई इब्राहीम ऐण्ड सन्स लिमिटेड, विरला ब्रदर्स लिमिटेड, शा वालेस ऐण्ड कम्पनी, नौरोसजी वाडिया ऐण्ड सन्स, सी० एन० वाडिया ऐण्ड कम्पनी, वर्ड ऐण्ड कम्पनी, माटिन ऐण्ड कम्पनी, इत्यादि के नाम उल्लेखनीय हैं। इनमें से कुछ ने तो दर्जनों धन्धों को स्थापित कर दिखाया है।

(२) ये नये धन्धों के हिस्से की बिक्री की जमानत भी ले लेते हैं। विदेशों में इस काम को एक विशेष प्रकार के जमानत लेने वाले

अथवा औद्योगिक और व्यापारिक बैंक करते हैं। इनकी अनुपस्थिति में यहाँ पर यह काम मैनेजिङ्ग एजेंट करते हैं। हमारे यहाँ यदि इन लोगों ने बहुत सी कम्पनियों के हिस्से बेचने की ज़मानत अपने ऊपर न ली होती तो शायद वह काम आरम्भ ही नहीं कर सकती थीं। जब किसी नई कम्पनी के हिस्से निकाले जाते हैं और उनके बिकने की ज़मानत के किसी मैनेजिङ्ग एजेंट की कोठी के ले लेने की बात जनता के सामने आती है तो लोगों का उस पर विश्वास हो जाता है और यदि इतने पर भी लोग सब हिस्से नहीं ले लेते तो मैनेजिङ्ग एजेंट स्वयं वह सब हिस्से ले लेता है।

(३) ये इस संस्था के व्यवस्थापक का काम भी करते हैं और प्रायः इनके विस्तृत अनुभव से लाभ भी हुआ है। किन्तु अयोग्य व्यवस्था के भी उदाहरण मिलते हैं। पहिले इनके अधिकार पिता से पुत्र को मिल जाते थे, अतः, कुछ दिनों में यह अयोग्य व्यक्तियों के हाथ में पड़ जाते थे। यह बेचे तथा हस्तान्तरित भी किये जा सकते थे। अब, यह दोनों बातें सन् १९३६ के कम्पनी संशोधन विधान के अनुसार मना कर दी गई हैं। जब कम्पनी की स्थायी पूँजी में इनकी कोई दिलचस्पी नहीं होती तब इनके हिस्सेदारों की हानि कर देने का डर रहता है। अन्तिम बात यह है कि यह लोग अपने मित्रों और सम्बन्धियों को नौकर रख लेते हैं और यदि वह कार्य कुशल नहीं होते तो कम्पनी की बड़ी हानि होती है।

(४) बैंकिंग और कारबार के बीच में ये एक प्रकार का सम्बन्ध भी स्थापित कर देते हैं। बात यह है कि सन् १९२० के इम्पीरियल बैंक विधान के अनुसार बैंक को किसी व्यक्ति को अथवा सामे की फर्म की किसी हुण्डी पुर्जे पर ऋण देने के लिये उस समय तक मनाही है जिस समय तक कि उस पर कम से कम दो ऐसे व्यक्तियों अथवा फर्म के हस्ताक्षर न हों जिनके बीच में कोई सामा न हो। अतः, कम्पनी की ओर से जिस डाइरेक्टर के हस्ताक्षर होते हैं उसके अतिरिक्त मैनेजिङ्ग एजेंट के भी हस्ताक्षर लेने की प्रथा चल पड़ी है। इससे कम्पनी के ऊपर तो उसके डाइरेक्टर के हस्ताक्षर के कारण दायित्व रहता ही है किन्तु मैनेजिङ्ग एजेंट के ऊपर भी अलग से दायित्व हो जाता है। यद्यपि दूसरे बैंकों के लिये कोई ऐसा विधान नहीं है किन्तु वे भी इस बात में इम्पीरियल बैंक का ही अनुसरण

करते हैं, अतः, मैनेजिङ्ग एजेन्ट को हर हालत में हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। जब माल के ऊपर ऋण लिया जाता है तब भी मैनेजिङ्ग एजेन्ट की जमानत के लिये जोर दिया जाता है।

(५) ये औद्योगिक संस्थाओं को अर्थ सम्बन्धी सहायता भी देते हैं। यहाँ पर हिस्सों के बहुत अधिक प्रचलित न होने के कारण प्रायः धन्धों की पूँजी कम रहती है और उन्हें ऋण के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। हम यह तो देख ही चुके हैं कि बैंकों से ऋण लेने के लिये मैनेजिङ्ग एजेन्टों को अपने हस्ताक्षर देने पड़ते हैं। किन्तु इसके अतिरिक्त वे स्वयम् भी ऋण देते हैं।

ऊपर यह बताया जा चुका है कि कभी-कभी इनकी व्यवस्था खराब हो जाती है। किन्तु सन् १९३६ के कम्पनी सशोधन विधान के अनुसार मैनेजिङ्ग एजेन्टों के उत्तराधिकार और उनके अधिकारों के विक्रय तथा हस्तान्तरित होने की मनाही हो जाने के कारण अब ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, इसमें एक अन्य दोष है। इसके कारण बैंकों और धन्धों में सीधा सम्बन्ध नहीं है। इस प्रणाली के होने से अर्थ के दोहरे प्रबन्ध के कारण औद्योगिक उन्नति रुक गई है। एजेण्ट बैंकों के ऊपर निर्भर रहते हैं, कारवार के विषय में उनका विचार पुराना है और वह औद्योगिक योजनाओं की ओर यथेष्ट ध्यान नहीं देते। यहाँ के धन्धों को स्थापित करने के लिये उनमें पारस्परिक संगठन नहीं है, और इसी कारण उन्हें लाक्षणिक तथा आर्थिक अनुभव भी नहीं प्राप्त हो पाते। कहना न होगा कि किसी धन्धे का ठोसपन उसके कार्यान्वित तथा लाभप्रद होने की सम्भावना, इत्यादि का निश्चय इन्हीं के द्वारा हो सकता है। फिर इनके आर्थिक साधनों के सीमित रहने के कारण ये निश्चयात्मकरूप से लाभप्रद धन्धों को निरन्तर नहीं खोलते जा सकते। सत्य तो यह है कि इनका लागत लगाने वाली जनता से उतना सम्बन्ध नहीं हो सकता जितना बैंकों का होता है। अतः, ये एक के बाद दूसरी कम्पनी के हिस्सों को न तो बेच ही सकते हैं और न ऐसा करने की जिम्मेवारी ही ले सकते हैं। यह प्रणाली तेजी में तो सफलता प्राप्त कर लेती है, किन्तु मन्दी में ऐसा नहीं होता। उस अवस्था में जब मैनेजिङ्ग एजेण्टों को अपने कारवार को सुदृढ़ बनाने के लिये द्रव्य की आवश्यकता पड़ती है तब उन्हें द्रव्य नहीं प्राप्त हो पाता। जैसा प्रायः होता है यदि किसी मैनेजिङ्ग एजेण्ट का कोई एक कारवार

बुरी अवस्था में पड़ जाता है तब उसके अन्य कारबारों में भी दिक्कत हो जाती है। सन् १९३६ के कम्पनी संशोधन विधान में इस सम्बन्ध की कुछ वृत्त कर दी गई है। उसके अनुसार किसी कम्पनी के रुपये किसी ऐसी दूसरी कम्पनी के हिस्से लेने में अथवा उसको ऋण देने में नहीं प्रयोग में लाये जा सकते जो एक ही मैनेजिङ्ग एजेण्ट के प्रबन्ध में है। हाँ, यदि कम्पनी लागत लगाने वाली कम्पनी है तो यह रुकावट नहीं है। फिर, यदि खरीदने वाली कंपनी के सब डाइरेक्टर निर्विरोध ऐसा करने के लिये निश्चित कर देते हैं तब भी ऐसा हो सकता है। किन्तु यह स्पष्ट है कि एक कम्पनी की कमजोरी का दूसरे पर अवश्य प्रभाव पड़ेगा। अन्तिम दोष यह है कि बम्बई में सूती मिलों के हिस्सों में मैनेजिङ्ग एजेण्टों के कारण सट्टेबाजी होती है। प्रायः ऐसा होता है कि मैनेजिङ्ग एजेण्ट जिस कम्पनी को अपने हाथ में लेते हैं। प्रारम्भ में उसके अधिकांश हिस्से स्वयं खरीद लेते हैं। किन्तु कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कम्पनी को अपने हाथ में लेना चाहते हैं। अतः, जब वे यह देखते हैं कि मैनेजिङ्ग एजेण्ट की आर्थिक अवस्था कमजोर है तब वह हिस्सों की कीमत बढ़ाकर उन्हें स्वयं खरीद लेते हैं। संक्षेप में यह है कि वे तनिक सी कमजोरी देखने के साथ ही उसका लाभ उठाने के लिये तैयार रहते हैं और इससे बम्बई की सूती मिलों के हिस्सों में बड़ी सट्टेबाजी होती है। यदि मिले द्रव्य के लिये मैनेजिङ्ग एजेण्टों पर इतना निर्भर न होती तो उनके हिस्सों में इतनी सट्टेबाजी न होती और जनता की जो उससे हानि होती है वह रुक जाती। सन् १९३६ के भारतीय कम्पनी संशोधन विधान में मैनेजिङ्ग एजेण्टों की प्रणाली के दोषों को दूर करने के लिये जो व्यवस्था कर दी गई है उसका थोड़ा सा अध्ययन तो हम कर ही चुके हैं। इस सम्बन्ध की जो अन्य धारारें हैं वह निम्न आशय की हैं :—

(१) विधान के प्रारम्भ होने के बाद से कोई भी मैनेजिङ्ग एजेण्ट २० वर्ष से अधिक के लिये यह पद नहीं पा सकता।

(२) नियमावली में चाहे जो कुछ लिखा हो अथवा परस्पर चाहे जो कुछ तैयार है किन्तु इस विधान के पास होने के पहिले भी यदि कोई मैनेजिङ्ग एजेण्ट २० वर्ष से अधिक के लिये नियुक्त हुआ है तो इस विधान के पास होने के बीस वर्ष के बाद वह मैनेजिङ्ग एजेण्ट नहीं रह सकता। हाँ, उसकी फिर से नियुक्ति हो सकती है। जब किसी

मैनेजिङ्ग एजेन्ट का समय समाप्त होने को हो तो वह कंपनी से वह सब खर्च ले सकता है जो उसने उसके लिये किये हों ।

(३) यदि किसी मैनेजिङ्ग एजेन्ट ने कंपनी के संबंध में किसी ऐसे अपराध के लिये सजा पाई है जो भारतीय पिनल कोड के अनुसार दंडनीय है और जिसकी जमानत नहीं है तो कंपनी उसे निकाल सकती है । यदि मैनेजिङ्ग एजेन्ट कोई फर्म अथवा कम्पनी है तो यदि उसके किसी सोमी अथवा डाइरेक्टर ने उपर्युक्त अपराध किया है और वह ऐसा अपराध करने के ३० दिन के अन्दर नहीं निकाला जाता है तो वह अपराध उस फर्म अथवा कंपनी का समझा जायगा ।

(४) यदि कोई मैनेजिङ्ग एजेन्ट दिवालिया घोषित कर दिया जाता है तो वह भी अपने पद से च्युत कर दिया जायगा ।

(५) कोई मैनेजिङ्ग एजेन्ट उस समय तक अपना अधिकार हस्तान्तरित नहीं कर सकता जब तक कम्पनी की साधारण सभा में वह पास न हो जाय ।

(६) यदि मैनेजिङ्ग एजेन्ट ने अपने प्रतिफल को अथवा उसके किसी अंश को किसी को हस्तान्तरित कर दिया है तो उसके सम्बन्ध का दायित्व कम्पनी के ऊपर नहीं पड़ सकता ।

(७) किसी कम्पनी की इतिक्रिया होने पर मैनेजिङ्ग एजेन्ट का प्रतिफल, इत्यादि वैसे तो कम्पनी से वसूल किया जा सकता है । किन्तु यदि यह इतिक्रिया मैनेजिङ्ग एजेन्ट की भूल से हुई है तो ऐसा नहीं किया जा सकता ।

(८) इस विधान के प्रारम्भ होने के बाद किसी मैनेजिङ्ग एजेन्ट की नियुक्ति अथवा पदच्युति, अथवा उसके विषय की अन्य कोई बात तब तक नहीं मानी जा सकती जब तक वह साधारण सभा में न हो जाय ।

(९) इस विधान के प्रारम्भ होने के बाद से मैनेजिङ्ग एजेन्ट का प्रतिफल कम्पनी के नेट वार्षिक लाभ का ही एक अंश हो सकता है । हाँ, लाभ के कम होने पर कुछ न्यूनतम प्रतिफल भी दिया जा सकता है । साथ ही कुछ निश्चित आफिस अलाउन्स भी हो सकता है । इसके लिये नेट वार्षिक लाभ के अर्थ कम्पनी के उस लाभ से हैं जो सब खर्चों को, ऋण पर के व्याज को, मरम्मत, हास और सरकार से अथवा किसी अन्य संस्था से जो छूट मिली हो, उसको हिस्सों के

बेचने पर अथवा कम्पनी की कुछ या सब सम्पत्ति बेचने पर जो लाभ मिला हो उसको सबको काटकर और आय कर, अतिरिक्त कर, अथवा लाभ पर अन्य कोई कर हो अथवा ऋण-पत्रों पर के व्याज को, अथवा सम्पत्ति पर किये गये खर्चों को अथवा अन्य कोई ऐसी रकम जो लाभ में से सुरक्षित कोष अथवा अन्य किसी कोष में ले जाई गई हो उसको बिना काटे हुये बचती है।

(१०) कोई कम्पनी न तो अपने मैनेजिङ्ग एजेन्ट को ऋण दे सकती है और न उसे दिये हुए किसी ऋण की वापिसी का दायित्व ले सकती है।

(११) कम्पनी के कम-से-कम तीन चोथार्ड डाइरेक्टरों की राय के बिना कोई मैनेजिङ्ग एजेन्ट कम्पनी के साथ उसके माल की बिक्री अथवा खरीद अथवा पूर्ति के लिये कोई समझौता नहीं कर सकता।

(१२) जिस कम्पनी में कोई मैनेजिङ्ग एजेन्ट है वह किसी दूसरी ऐसी कम्पनी को जिसका वही मैनेजिङ्ग एजेन्ट है न तो कुछ ऋण दे सकती है, न उसको दिये हुये किसी ऋण का दायित्व ले सकती है, न उसके हिस्से अथवा ऋण-पत्र खरीद सकती है। हाँ, यदि कोई कम्पनी लागत लगाने वाली कम्पनी है तो यह नियम नहीं लागू होगा। इसके अतिरिक्त क्रय उस समय भी किया जा सकता है जब क्रय करने वाली कम्पनी के सब डाइरेक्टरों की राय से क्रय हुआ हो।

(१३) मैनेजिङ्ग एजेन्ट न तो कम्पनी के ऋण-पत्र निकाल सकता है और न डाइरेक्टरों के द्वारा निश्चित सीमा से अधिक लागत लगा सकता है।

(१४) मैनेजिङ्ग एजेन्ट स्वयं का कोई ऐसा व्यवसाय नहीं कर सकता जो उसी कम्पनी के व्यवसाय की तरह हो जिसका वह मैनेजिङ्ग एजेन्ट है। इसी तरह से वह उस कम्पनी की सहायक कम्पनी के व्यवसाय की तरह का भी कोई व्यवसाय नहीं कर सकता।

(१५) यदि किसी सार्वजनिक कम्पनी के मैनेजिङ्ग एजेन्ट को उसमें कुछ डाइरेक्टर नियुक्त करने का अधिकार है तो ऐसे डाइरेक्टरों की संख्या सब डाइरेक्टरों की एक तिहाई से अधिक नहीं हो सकती।

(१६) जिस कम्पनी में भी कोई मैनेजिङ्ग एजेन्ट है उसमें मैनेजिङ्ग एजेन्ट सम्बन्धी जितनी बातें हैं उनका सबका उल्लेख

एक रजिस्टर में होना चाहिये। कम्पनी के हिस्सेदार जब चाहे तब इसे देख सकते हैं।

जमा प्राप्त करना

कुछ जगहों पर मिलों में जो जमा प्राप्त होती है वह यहाँ पर पुराने समय में महाजनों के यहाँ जो जमा प्राप्त होती थी उसी का अवशेष है। बम्बई में और अहमदाबाद में जिन्होंने सर्वप्रथम मिले खोली थीं वह महाजन वर्ग के ही लोग थे और उन पर जनता का विश्वास था, अतः, उसने उनके पास अपनी जमा छोड़ दी। इस तरह से यहाँ पर रुई की मिलों में जो पूँजी लगी थी वह बहुत काफी थी और अहमदाबाद में तो यह इसलिये विशेष तौर पर था कि वहाँ के बैंक वहाँ की मिलों की अधिक सहायता नहीं करते थे। बम्बई में यह जमा छः महीने से लेकर वर्ष भर की होती थी। अतः, इसे अल्पकालीन जमा कह सकते हैं और यह बहुत कम व्याज पर मिल जाती थी। मिल मालिकों को यह बहुत ही पसन्द थी क्योंकि वह इसे रुई खरीदने के समय में तो ले लेते थे और बाद में जब आवश्यकता नहीं रहती थी नहीं लेते थे। किन्तु प्रथम महायुद्ध के बाद की तेजी के बाद जब मन्दी आई तब यह कम होने लगी और आजकल इसका कोई विशेष महत्व नहीं रह गया है। अब तो बैंक अधिक मदद करते हैं और मिले उन्हीं पर निर्भर हैं। हाँ, अहमदाबाद में आज भी यह विशेष महत्व की है और शायद भविष्य में भी रहेगी। इसके मुख्यतः दो कारण हैं। प्रथम तो अहमदाबाद की जमा सप्तवर्षीय जमा हो गई है जिसके अर्थ दीर्घ-कालीन जमा हैं। अतः, वे इस बात में तो ऋण-पत्रों की तरह के हैं, किन्तु उनमें यह अन्तर है कि इनका कम्पनी की सम्पत्ति पर वह स्वत्व नहीं है जो ऋण-पत्रों का रहता है। दूसरे, वह मिलों के लाभ के जमा हैं। प्रायः एक मिल का कोष दूसरे मिल में जमा रहता है। इस तरह से अहमदाबाद की मिलों ने एक ऐसी प्रणाली निकाल ली है जिससे उनका काम उन्हीं के लाभ से चल जाता है। किन्तु अब भी अहमदाबाद में कुछ अल्पकालीन जमा हैं जो बम्बई की अल्पकालीन जमा के सदृश्य कभी भी निकाली जा सकती हैं और इस तरह से मिलों को कठिनता पड़ सकती है। फिर जमा को मिलों

के लिये पूँजी के सदृश्य प्रयोग में लाने में एक और दोष है और वह यह है कि इससे हिस्सों और ऋण-पत्रों का जो लागत के अच्छे रूप हैं अधिक प्रचार नहीं हो पाता। तीसरे, मिलें जमा प्राप्त करके एक ऐसा काम कर रही हैं जो उनके योग्य नहीं है और यदि वह कभी इन्हें माँग पर न दे सकेंगी तो उससे जनता का विश्वास हट जायगा और वह न तो हिस्से ही खरीदेगी और न बैंकों ही में जमा करेगी। चौथे, यह प्रणाली पुरानी है। आजकल जब आधुनिक बैंक हैं जमा उन्हीं में होनी चाहिये। अन्तिम बात यह है कि बैंकों के अधिक लोकप्रिय हो जाने पर शायद यह जमा बैंकों में चली जाय, अतः, इस पर मिलों को निर्भर नहीं रहना चाहिये।

हिस्सों और ऋण-पत्रों को निकालना

अब हम हिस्सों और ऋण-पत्रों को ले सकते हैं। सारी पूँजी एक ही ढङ्ग से नहीं प्राप्त हो सकती। मिलों और लागत लगानेवाली जनता दोनों की दृष्टि से यह अच्छा है कि इसके लिये कई ढङ्ग अपनाने जायँ। यह सब ढङ्ग ऐसे होने चाहिये कि जो भिन्न-भिन्न प्रकार के लोगों को पसन्द हों। प्रथम तो सपक्ष हिस्से (Preference shares) होते हैं, दूसरे साधारण हिस्से (Ordinary shares) और तीसरे संस्थापकों के हिस्से (Founders' or Deferred shares) होते हैं। समक्ष हिस्से सराफ्त के सपक्ष हिस्से (Participating Preference shares) अथवा वर्धमान सपक्ष हिस्से (Cumulative Preference shares) अथवा साधारण सपक्ष हिस्से (Noncumulative Preference shares) हो सकते हैं। कभी-कभी स्थायी पूँजी के अंश को ऋण-पत्र निकाल कर भी इकट्ठा किया जाता है। इससे एक तरफ तो लागत लगाने वालों को व्याज मिलता रहता है और दूसरी तरफ हिस्सेदारों को इन्हें अपने लाभ में से बहुत अधिक नहीं देना पड़ता। हिस्सों और ऋण-पत्रों को निकालकर जनता से प्रत्यक्ष तौर पर पूँजी पाने के इस तरीके में हमारे यहाँ तथा अन्य देशों में भी यह दोष है कि कभी तो लोग अच्छी आशा होने के कारण इन्हें आसानी से ले लेते हैं और कभी इसके विपरीत स्थिति के कारण इन्हे नहीं लेते। इधर के इतिहास में सन् १९२०-२१ और सन् १९३५-३७ के वर्ष पहिली तरह के और बीच

के वर्ष दूसरी तरह के थे। यहाँ पर ऐसे होशियार लागत लगानेवालों की भी कमी है, जो अच्छी और बुरी योजनाओं को समझ सकें। पश्चिमी देशों में भी लोगों को इस सम्बन्ध की उचित सलाह देने के लिये कुछ संस्थाएँ हैं। अतः, भारतवर्ष में तो जहाँ शिक्षा की बहुत कमी है इनका होना बहुत ही आवश्यक है।

इम्पीरियल बैंक और दूसरे व्यापारिक बैंकों के द्वारा उद्योग-धन्धों की आर्थिक सहायता

हमको यह तो ज्ञात हो ही गया है कि भारतवर्ष में आधुनिक उद्योग-धन्धों की संस्थापना मैनेजिङ्ग एजेन्टों के कारण ही हुई है। बहुत दिनों तक तो केवल यही लोग इनको आर्थिक सहायता देते रहे। उनकी स्वयं की अच्छी आर्थिक स्थिति और साथ ही उनके मित्रों की सहायता के कारण वे लोग बैंकों की सहायता के बिना यह काम करते रहे। किन्तु धीरे-धीरे और विशेषकर जब मन्दी आई तब जनता का उन पर से विश्वास उठ गया और उन्हें अपने मित्रों की सहायता मिलनी बन्द हो गई। अतः, उन्हें बैंकों से सहायता लेने की आवश्यकता पड़ी। किन्तु इनके दायित्व ऐसे थे कि ये उन्हें दीर्घकालीन पूँजी नहीं दे सकते थे। हाँ, ये उनकी अल्पकालीन आवश्यकताओं को अवश्य पूरी कर सकते थे, किन्तु वह भी सब नहीं। बात यह है कि अल्पकालीन आवश्यकताओं के लिये भी कुछ ऐसी पूँजी होती है जो हमेशा चाहती है। अतः, वह स्थायी पूँजी का ही रूप धारण कर लेती है। कच्चे माल का; तैयार और अर्ध तैयार माल का स्टॉक एक न्यूनतम सीमा से कम रह ही नहीं सकता। अतः, इनको रखने के लिये जितनी पूँजी की आवश्यकता पड़ती है वह स्थायी ही के सदृश होती है। अतः, घिरी हुई पूँजी के साथ-साथ इसका भी प्रबन्ध करना पड़ता है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो बड़ी जोखिम का सामना करना पड़ता है। सच तो यह है कि इस देश में बहुत से लोग यह सोच लेते हैं कि उनकी सारी कार्य-शील पूँजी के, उन्हें अल्पकालीन ऋण के रूप में मिल जाने से उनका काम चल जायगा और इसी से वे सफल नहीं होते। बैंक यदि इसके लिये तैयार नहीं होते तो हमें उन्हें दोष न देना चाहिये। हमें तो यह देखना चाहिये कि वे कार्यशील पूँजी के उस भाग को देने के लिये तैयार हैं अथवा नहीं जो बराबर आती जाती है और इस तरह से

समय-समय पर बैंक को 'वापिस' की जा सकती है। किन्तु ध्यान से देखने पर यह पता लगता है कि बैंक यह भी भली प्रकार से और कम व्याज पर नहीं करते। इम्पीरियल बैंक और दूसरे बैंक या तो (अ) उनके पास वास्तविक और बिक्री योग्य जमानत को गिरवी के तौर पर रखने से या (ब) ऋण लेने वाले के ऐसे प्रण-पत्र जिसके ऊपर किसी अन्य धनी के भी हस्ताक्षर हों ऋण देने के लिये तैयार रहते हैं। किन्तु अधिकांश मिल-मालिक ऋण नहीं लेते। बात यह है कि उनके अपने माल को बैंक में गिरवी रखने से उनकी साख मारी जाती है। अतः, वे इसको पसन्द नहीं करते। यह तो पहिले ही बताया जा चुका है कि वे लोग विशेषतः अहमदाबाद में जनता से जमा प्राप्त करते हैं। अतः, उनकी साख मारी जाने से इस पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इससे उनके ऐसा न करने के दो कारण हैं। बैंकों ने प्रण-पत्रों पर जो दो धनियों के हस्ताक्षर लेने की प्रथा चला रखी है इससे मैनेजिङ्ग एजेन्टों का रहना बहुत जरूरी हो गया है। बैंक जो ऋण देते हैं उनका रूप या तो नकद साख का या जमा की हुई रकम से अधिक रकम निकालने का होता है। बैंक और ऋण लेने वाले दोनों यही रूप पसंद करते हैं। इसके दो कारण हैं। एक तो यह कि ऋण लेने वालों को उनके दैनिक ऋण पर व्याज देना पड़ता है। हाँ, हर हालत में एक न्यूनतम रकम अवश्य देनी पड़ती है। दूसरे, बैंक जब चाहे तब इस सुविधा को बन्द कर सकता है। किन्तु बिल डिस्का-उण्टिङ्ग पर अधिक जोर देना चाहिये। हाँ, इसके लिये एक तो यहाँ पर लाइसेन्स प्राप्त गोदाम होने चाहिये और दूसरे विलों के प्रयोग की आदत बढ़नी चाहिये। फिर बैंक ऋण देते समय ऋण लेने वाले की वैयक्तिक जमानत का जरा भी ख्याल नहीं करते और अतिरिक्त जमानत अवश्य माँगते हैं। वे अतिरिक्त जमानत न माँगें इसके लिये यह आवश्यक है भारतीय कम्पनी विधान की उस धारा में सशोधन कर दिया जाय जिसके अनुसार उन्हें अपनी बैलन्स शीट में जमानती और गैरजमानती ऋणों को अलग-अलग दिखाना पड़ता है। फिर यह इस तरह से भी हो सकता है कि बैंक मिल वालों की अधिक जानकारी प्राप्त करे। अन्तिम, व्याज की दर भी बहुत ऊँची रहती है। छोटे-छोटे बैंक तो १२ से १८ प्रतिशत तक लेते हैं।

वैकों के उद्योग-धन्धों की अधिकाधिक सहायता

करने के लिये सुझाव

इम्पीरियल बैंक और दूसरे बैंक, विशेषतः वह जिनकी स्थिति काफी अच्छी है, निम्न ढङ्ग से उद्योग-धन्धों की अधिकाधिक सहायता कर सकते हैं :—

(१) उन्हें पुरानी और नई दोनों प्रकार की कंपनियों के निकाले हुये हिस्सों का बीमा कर देना चाहिये। इसके लिये उनके यहाँ ऐसे अनुभवी कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी जो प्रत्येक धन्धे के विषय में जानते हों और उसके सबन्ध में अपनी सम्मति दे सकें। इससे ऐसी कंपनियाँ कम खुलेगी कि जिनका भविष्य अच्छा नहीं होगा। हमारे यहाँ जो बहुत सी कंपनियाँ असफल हो गई हैं वह उपर्युक्त व्यवस्था होने पर शायद खुलती ही नहीं, और इस तरह से उनमें लागत लगाने वालों की जो हानि हुई है वह भी अवश्य बच जाती।

(२) बैंक जिन हिस्सों का बीमा कर देंगे प्रायः उन सबको जनता ले ही लेगी। बात यह है कि इससे उसका उन पर विश्वास जम जायगा। किन्तु यदि कुछ हिस्से बच रहेंगे तो बैंकों को उन्हें लेना पड़ेगा। किन्तु यह बहुत दिनों तक उनके पास नहीं रहेंगे, क्योंकि कंपनियों की उन्नति के साथ-साथ वह विक जायँगे।

(३) बैंकों के प्रतिनिधि संचालक मंडलों में रहकर उन्हें बराबर सावधानी से काम करने के लिये कहते जायँगे।

(४) उन्हें वैयक्तिक जमानतों पर अल्पकालीन ऋण देने चाहिये।

(५) लाइसेन्स प्राप्त गोदाम अवश्य स्थापित किये जाने चाहियें। इससे तैयार माल को उनके यहाँ रखने की परिपाटी चल जायगी और उनके यहाँ की रसीदों के आधार पर बैंक ऋण दे सकेंगे।

(६) बिल भुनाने की प्रथा को उस पर कम व्याज लेकर प्रोत्साहित करना चाहिये। इससे बैंकों को वह लागत मिल जायगी जो उनके लिये बड़ी लाभप्रद है। उनके न होने के कारण इस समय वे अपनी लागत-सरकारी साख-पत्रों में लगाते हैं। कहना न होगा कि उनका यह काम नहीं है। उन्हें पहिले उद्योग-धन्धों और व्यापार

की सहायता करनी चाहिये और फिर सरकार के साख-पत्र खरीदने चाहिये। हाँ, इस संबंध में यह कहा जा सकता है कि इधर वे लोग ऐसा ही कर रहे हैं। यदि यह बातें होती रहे तो बहुत ही अच्छा है।

सरकार का कर्तव्य

कुछ लोगों का यह कहना है कि भारतवर्ष में व्यापारिक बैंकों की इस समय जो स्थिति है उसमें उन्हें उद्योग-धन्धों को दीर्घकालीन ऋण विलकुल भी नहीं देना चाहिये। उनका कहना है कि उनके स्थान पर सरकार को आगे आना चाहिये। इस सुझाव को समाजवाद के प्रचार से बड़ा प्रोत्साहन मिला है। इस संबंध में भिन्न-भिन्न प्रान्तों की सरकारों ने जो कुछ किया है वह तो हम देख ही चुके हैं। यहाँ पर हम प्रस्तावित अखिल भारतवर्षीय औद्योगिक अर्थ कारपोरेशन के विधान, काम और सभावनाओं का विशेष रूप से अध्ययन करेंगे।

उपयुक्त कारपोरेशन संयुक्तराज्य (U. K.) के एक ऐसे ही कारपोरेशन के सदृश्य है। इसका मुख्य ध्येय नये धन्धों को धिरी हुई पूँजी देना है। इसकी स्वयं की पूँजी पाँच करोड़ है जो २५००० रुपयों के २००० हिस्सों में विभाजित है जो पूर्णरूप से प्राप्त होगी। केन्द्रीय सरकार और रिज़र्व बैंक चार-चार सौ हिस्से लेगें शेष हिस्से स्वीकृत बैंकों, बीमा कम्पनियों, स्वीकृत इन्वैस्टमेंट ट्रस्ट्स और दूसरी आर्थिक संस्थाओं को दिये जायेंगे। सरकार ने पूँजी को वापिस करने और २½ प्रतिशत वार्षिक प्रतिफल (आय कर भुना) देने का दायित्व लिया है। लाभ की बँटनी अधिक से अधिक ५ प्रतिशत की हो सकेगी और वह भी पाँच करोड़ के सुरक्षित कोष के बन जाने के बाद होगी। कारपोरेशन के लाभ पर न तो आयकर लगेगा और न अतिरिक्त कर। कारपोरेशन के ग्यारह संचालकों में से दो केन्द्रीय सरकार के द्वारा नियुक्त होंगे, ३ रिज़र्व बैंक के द्वारा, तीन स्वीकृत बैंकों के द्वारा और दो-दो बीमा कम्पनियों और इन्वैस्टमेंट ट्रस्ट्स के द्वारा नियुक्त होंगे। प्रारम्भ में कारपोरेशन के चार दफ्तर होंगे, एक बम्बई में, दूसरा कलकत्ते में, तीसरा दिल्ली में और चौथा मद्रास में। कारपोरेशन अपनी पूँजी जमा प्राप्त करके और बाण्ड तथा

ऋण-पत्र निकाल करके भी बढ़ा सकता है। आकस्मिक दायित्व (Contingent Liabilities) को मिलाकर सारे ऋण की रकम उसकी प्राप्त पूँजी के चतुर्गुण से अधिक न हो सकेगी। दस वर्ष के पहिले जो जमा की रकम देय न होगी वह दस करोड़ रुपये से अधिक की न हो सकेगी।

कारपोरेशन उद्योग-धन्धों को अधिक से अधिक २५ वर्षों के अन्दर वापिस होने वाले दीर्घकालीन ऋण दे सकेगा। यह कम्पनियों के हिस्से और ऋण-पत्रों को निकालने का वीमा भी कर सकेगा, किन्तु इसे इन्हे अधिक से अधिक सात वर्षों में जनता के हाथ बेच देना होगा। यदि कोई कम्पनी बजार में ऋण लेना चाहती है तो यह कुछ निश्चित कमीशन लेकर उसकी जमानत भी कर सकेगा। यदि किसी कम्पनी को विदेशी कर्न्सी चाहिये तो इसे अन्तर्राष्ट्रीय बैंक (International Bank of Reconstruction and Development) से ऋण लेने का अधिकार दे दिया गया है। इसे किसी कम्पनी से दूसरे ऋणदाताओं की अपेक्षा अपने ऋण की वसूली का प्रथम अधिकार भी प्राप्त है।

यह स्पष्ट है कि भारतवर्ष की सरकार ने अब तक जो कुछ भी यहाँ के औद्योगीकरण के लिये किया है उसमें इस कारपोरेशन की स्थापना सबसे प्रधान है। इसके काम धीरे-धीरे बढ़ जायेंगे और यह अनुभव प्राप्त करने के बाद अवश्य ही और कार्य कुशल हो जायगा। प्रारम्भ में इसे कुछ अधिक सावधान रहना पड़ेगा। हाँ, बाद में यह कुछ ढील दे सकता है। यह बहुत ही आवश्यक है क्योंकि इसी के ऊपर इसकी जमा की प्राप्ति और ऋण-पत्रों की विक्री निर्भर होगी।

यदि प्रान्तीय कारपोरेशन न स्थापित किये गये तो यह कारपोरेशन अपने ढङ्ग का अकेला कारपोरेशन रहेगा। अतः, इसके यहाँ माँग भी अधिक रहेगी। किन्तु यदि प्रान्तीय कारपोरेशन भी स्थापित हो गये तो इसे उनके बीच में सहयोग उत्पन्न कराना पड़ेगा। प्रान्तीय कारपोरेशनों के बन जाने पर इसे उन उद्योग-धन्धों की सहायता करनी पड़ेगी जो अन्तर्प्रान्तीय हैं और अखिल भारतीय महत्व के हैं जैसे स्टील के, इञ्जीनियरिंग के और भारी रसायनों के, इत्यादि।

यद्यपि केन्द्रीय और छः प्रान्तीय बैंकिंग की कमेटियों ने सरकार

से सहायता प्राप्त प्रान्तीय औद्योगिक कारपोरेशन की संस्थापना के सुभाव रक्खे थे, किन्तु उनके विरुद्ध जो राय है उसके कारण उनकी संस्थापना असम्भव है। प्रथम तो इनका बोझ कर देने वाली जनता पर पड़ेगा। अतः, वह इसके पक्ष में नहीं हो सकती। दूसरे, यदि सरकार के पास इनके लिये धन है तो वह उसे अन्य उपयोगी कामों में लगा सकती है। तीसरे, यह भी अच्छा नहीं मालूम पड़ता कि सरकार से सहायता प्राप्त सस्था अन्य ऐसी ही सस्थाओं से प्रतियोगिता करे। किन्तु ये उन धन्धों की सहायता करने के लिये अवश्य ही स्थापित किये जा सकते हैं जो जनता के लिये अत्यन्त ही उपयोगी हैं। इन्हे सहायता देनेवाली सस्थाओं की आवश्यकता कुछ प्रान्तों में अच्छी तरह से प्रतीत हो चुकी है। मद्रास में बिजली कम्पनियों, शक्तिशायक योजनाओं और सिंचाई के कामों को सरकार ने सहायता दी है। किन्तु इसके लिये जिस ढङ्ग से काम लिया गया था वह ठीक नहीं था। पञ्जाब में भी यही हुआ था। इन जनता के उपयोगी कामों में एक विशेष बात है और वह यह है कि इनमें जो लागत लगाई जाती है उसका प्रतिफल मिलने में कुछ समय लगता है। अतः, कम्पनियों को आर्थिक सहायता देने के जो साधारण ढङ्ग हैं वह इनके लिये उपयुक्त नहीं हैं। किन्तु यदि कोई विशेष ढङ्ग अपनाया जाय तो उनसे रुपया अवश्य मिल सकता है। अतः, अर्ध एकाधिकार वाले धन्धों को आर्थिक सहायता देने के लिये सरकारी औद्योगिक कारपोरेशन की संस्थापना करना बहुत ही आवश्यक है। वैकिंग कमेटियों की सहायता के लिये जो विदेशी अनुभवों आये थे उनकी भी यही सम्मति थी। हाँ, पहिले अवश्य इनके विषय में कुछ मतभेद था किन्तु बाद में वह ठीक हो गया था। केन्द्रीय और उन छहों कमेटियों की राय के विरुद्ध जो प्रान्तीय औद्योगिक कारपोरेशन की संस्थापना के पक्ष में थी ये एक अखिल भारतवर्षीय कारपोरेशन की संस्थापना करना चाहते थे। श्री० सूबेदार तथा कुछ अन्य लोगों की भी यही सम्मति थी। सत्य तो यह है कि दोनों पक्ष की दलीले बड़ी सारगर्भित थी। प्रान्तीय कारपोरेशनों के पक्ष में निम्न दलीले थी :—

(१) उद्योग-धन्धों का विषय प्रान्तीय विषय है। अतः, इनके सम्बन्ध की सभी योजनायें प्रान्तीय सरकारों के नियन्त्रण में होनी चाहिये।

(२) केन्द्रीय सरकार के एक अखिल भारतवर्षीय कारपोरेशन की सहायता करने के अपेक्षा भिन्न-भिन्न प्रान्तीय सरकारों का अपने-अपने प्रान्तीय कारपोरेशनों की सहायता करना अधिक आसान होगा ।

(३) अखिल भारतवर्षीय कारपोरेशन के लिये पूँजी इकट्ठा करना कठिन होगा किन्तु प्रान्तीय कारपोरेशनों के लिये यही आसान होगा । बात यह है कि वह अपने प्रान्त के लोगों की प्रान्तीयता का लाभ उठा सकेंगे ।

(४) प्रान्तीय कारपोरेशन अपने-अपने प्रान्तों के उद्योग-धन्धों की आवश्यकताओं को आसानी से समझ सकेंगे । किन्तु एक अखिल-भारतीय कारपोरेशन को सारे देश के उद्योग-धन्धों की आवश्यकताओं का समझना कुछ कठिन-सा हो जायगा ।

(५) प्रान्तीय कारपोरेशनों के पास उनके अपने-अपने प्रान्तों के धन्धों को जानने वाले अनुभवी रह सकते हैं; किन्तु एक अखिल भारतीय कारपोरेशन के पास सारे देश के धन्धों को समझने वाले अनुभवी नहीं रह सकते ।

जो लोग एक अखिल भारतीय कारपोरेशन की संस्थापना के पक्ष में थे उनकी निम्न दलीले थी :—

(१) प्रान्तीय सरकारों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह प्रान्तीय कारपोरेशन संस्थापित कर सके । हाँ, केन्द्रीय सरकार की ऐसी स्थिति अवश्य है कि वह एक अखिल भारतीय कारपोरेशन स्थापित कर ले । यदि वह सारा बोझ स्वयं न भी उठा सकेगी तो उसे प्रान्तीय सरकारों की सहायता मिल सकती है ।

(२) एक अखिल भारतीय कारपोरेशन के हिस्सों और ऋण-पत्रों पर जनता का कहीं अधिक विश्वास होगा और विशेषतः जब केन्द्रीय सरकार के द्वारा ही वह संस्थापित होगा । फिर, उसके निकाले हुये साख-पत्र विदेशों में भी बिक सकेंगे । इसके अतिरिक्त उसके सचालक भी देश के किसी हिस्से से भी लिये जा सकेंगे । अतः, उसमें योग्य व्यक्तियों के रहने की विशेष सम्भावना होगी ।

(३) एक अखिल भारतीय कारपोरेशन की रकम भिन्न-भिन्न प्रकार के धन्धों में लगी होगी । अतः, सकट के समय उसको कुछ कम जोखिम रहेगी ।

(४) अखिल भारतीय कारपोरेशन की केन्द्रीय सरकार में भी आवाज़ होगी। अतः, वह यहाँ के धन्धों को उचित सहायता भी दिलावा सकेगा।

(५) अखिल भारतीय कारपोरेशन के कर्मचारी भी समस्त भारतवर्ष में से लिये जा सकेंगे। अतः, वह बहुत अनुभवी होंगे। फिर, एक प्रान्त के धन्धों को दूसरे प्रान्त के धन्धों के अनुभवी व्यक्तियों के अनुभव का भी लाभ प्राप्त हो सकेगा। इसे विदेशियों की सेवाये भी प्राप्त हो सकेगी।

(६) इस देश में इस समय बहुत से काम किये जा सकते हैं किन्तु उन सबका एक साथ लेना तो असम्भव होगा। अतः, उनमें से जो अधिक लाभप्रद है वही पहिले लिये जायेंगे।

किन्तु जैसा कि पहिले भी कहा जा चुका है अन्त में इस विषय पर सब की एक ही सम्मति हो गई और वह यह थी कि प्रत्येक प्रान्त में उसका एक प्रान्तीय कारपोरेशन होना चाहिये और उनके सबके ऊपर एक अखिल भारतीय कारपोरेशन भी होना चाहिये जो उनमें सहयोग स्थापित करेगा और अखिल भारतीय प्रश्नों को सुलझावेगा। इसके निम्न काम बतलाये गये थे :—

(१) प्रान्तीय कारपोरेशनों को उनके हिस्सों और ऋण-पत्रों को बेचने में सहायता देना।

(२) प्रान्तीय कारपोरेशनों में सहयोग उत्पन्न कराना और इस बात को देखना कि वह उपयोगी धन्धों को ही सर्व प्रथम लेते हैं।

(३) प्रान्तीय कारपोरेशनों के पथ-प्रदर्शन के लिये कुछ साधारण सिद्धान्तों को रखना।

(४) केन्द्रीय सरकार से इनके लिये सुविधायें दिलवाना।

औद्योगिक बैंकों की संस्थापना के लिये आवश्यक सुझाव

जैसा कि पहिले ही कहा जा चुका है देश के क्षेत्रफल को देखते हुये इस समय औद्योगिक बैंकों की जो संख्या है वह बहुत ही कम है। हाँ, यदि इम्पीरियल बैंक तथा अन्य व्यापारिक बैंक उन तरीकों को अपना कर यहाँ के उद्योग-धन्धों की सहायता करने लग जायें तथा अखिल भारतीय औद्योगिक अथ कारपोरेशन और प्रान्तीय औद्योगिक कारपोरेशन उद्योग-धन्धों के लाभ को दृष्टि में रखते हुये

काम करें तो अन्य औद्योगिक बैंकों की संस्थापना की आवश्यकता नहीं रहेगी। किन्तु यदि यह नहीं होता है तो औद्योगिक बैंकों की संस्थापना बहुत ही आवश्यक होगी। हाँ, ऐसी स्थिति में उनके काम बही होंगे जो इपीरियल बैंक और अन्य बैंकों के लिये बनाये जा चुके हैं। जो औद्योगिक बैंक इस समय स्थित है उन्हें भी इन्हीं ढङ्गों पर काम करना चाहिये। इस संवध में ब्रिटेन में एक कमेटी वैठी थी जिसने इस विषय में निम्न सुझाव रखे थे :—

(१) वर्तमान औद्योगिक कंपनियों को अर्थ सम्बन्धी मन्त्रणा देना।

(२) स्थायी पूँजी की प्राप्ति, उसकी रकम और उसके भेदों के विषय में मन्त्रणा देना।

(३) कंपनियों के साख-पत्रों के निकालने पर उनका वीमा करना और जब तक वह जनता के द्वारा न लिये जा सके तब तक के लिये उन्हें अल्पकालीन ऋण देना।

(४) देश तथा विदेशों में कंपनियों के दीर्घकालीन कन्ट्राक्टों को पूरा करने के लिये आर्थिक सहायता देना और स्थित कंपनियों की उन्नति के लिये भी ऐसा ही करना।

(५) नये धन्धों के लिये कंपनियाँ स्थापित करना।

(६) एकीकरण के सम्बन्ध में मध्यस्थ का काम करना और अर्थ सम्बन्धी मन्त्रणा देना तथा प्रतिस्पर्धी अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से समझौता करना ; और

(७) सब तरह के आर्थिक सहायता के काम करना।

ऐसे बैंकों की पूँजी अवश्य ही दीर्घकालीन ऋण के रूप में होगी न कि अल्पकालीन ऋण के रूप में। इन्हे व्यापारिक बैंकों से प्रति-योगिता नहीं करने देना चाहिये।

औद्योगिक कंपनियों के हिस्सों और ऋण-पत्रों को जनता में प्रचलित करने के लिये सुझाव

(१) प्रथम महायुद्ध के बाद के तेजी के काल में यहाँ पर बहुत-सी औद्योगिक कंपनियाँ खुली थी। किन्तु बाद में मन्दी के समय जब वह फेल हो गई तब जनता का इन पर से विश्वास उठ गया। अतः, लोग अपनी वचत पड़ोसियों को उधार देने, अचल सम्पत्ति में, सरकारी,

म्युनिसिपैलिटियों के और बन्दरगाहों के ट्रस्ट के साख-पत्रों में लगाना अधिक पसन्द करते हैं। यदि वर्तमान बैंक और जिनकी सस्थापना के लिये सुझाव रखे गये हैं वह नई कम्पनियों की योजनाओं को पहिले ही से समझ लिया करे तो उनके फेल होने की सम्भावना कम हो जाय और इससे जनता में उनके प्रति विश्वास उत्पन्न हो जाय।

(२) केन्द्रीय कमेटी के सामने जिन लोगों ने साक्षी दी थी उनमें से कुछ ने यह भी कहा था कि यहाँ पर लोगों का यहाँ के धन्धों पर इसलिये भी विश्वास नहीं है कि वह जानते हैं कि यहाँ की विदेशी सरकार उनकी तनिक भी सहायता न करेगी और इसी कारण वह सफल न हो सकेंगे। हमारी अपनी सरकार अब इस डर को दूर कर सकती है।

(३) हमारे यहाँ ऐसी सस्थाये भी नहीं के बराबर हैं जो यहाँ के लोगों को और विशेषकर ग्रामीण लोगों को इस प्रकार के लागत से अवगत करें। वास्तव में इस सम्बन्ध के विज्ञापन की यहाँ पर बड़ी आवश्यकता है।

(४) प्रायः लोग पढ़े-लिखे नहीं हैं और पूँजी एकत्रित करने के आधुनिक तरीकों को नहीं जानते। इनके विषय की शिक्षा देने की यहाँ पर बहुत ही आवश्यकता है।

(५) साख-पत्रों के क्रय और विक्रय में सुविधा देने के लिये यहाँ पर कोई भी संस्था नहीं है और यदि है तो वह शहरों में ही है। अतः इनके विश्वासपात्र दलालों की बड़ी आवश्यकता है।

(६) कुछ साख-पत्रों के हस्तान्तर करने में बड़ा ऊँचा स्टाम्प लगाना पड़ता है। इसे भी घटा देना चाहिये।

(७) जिन लोगों के पास थोड़ी संख्या के हिस्से होते हैं उन्हें कभी-कभी उनके बेचने में बड़ी कठिनाई पड़ती है। अतः, थोड़ी संख्या में भी हिस्सों के बेचने का प्रबन्ध होना चाहिये।

(८) हमारे यहाँ औद्योगिक कम्पनियों के साख-पत्रों की जमानत पर ऋण देने के लिये कोई भी संस्था तैयार नहीं होती। हमारे बैंक भी सरकारी साख-पत्रों ही को पसन्द करते हैं। हाँ, उनमें इधर कुछ परिवर्तन हो रहा है।

(९) जैसा अन्य देशों में है उसी प्रकार हमारे यहाँ भी हमारी सरकार सन् १९२० से यहाँ के वाजारों में से बहुत रुपया लेती है।

अतः, इससे उद्योग-धन्धों को पूँजी-नहीं मिलती। सरकार को हमेशा कम व्याज पर ऋण लेना चाहिये।

घरेलू धन्धों को आर्थिक सहायता देने के सम्बन्ध में सुझाव

घरेलू धन्धों को भी आर्थिक सहायता की आवश्यकता पड़ती है; और अब तक वह महाजनों के ऊपर ही निर्भर रहते हैं। वास्तव में उनकी लघुता और उनकी तितर-बितर होने की अवस्था के कारण बैंकों का तथा अन्य बड़े-बड़े अर्थ की व्यवस्था करने वाले लोगों का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो ही नहीं सकता। किन्तु इन्हीं कारणों से वह सहकारिता के लिये बहुत ही उपयुक्त हैं। भिन्न-भिन्न क्रमेडियों ने यही राय भी दी है। ऐसे धन्धे जर्मनी और जापान में सहकारिता की सहायता से ही फल फूल रहे हैं। अतः, कोई कारण नहीं कि भारतवर्ष में ऐसा न हो सके। किन्तु इसके लिये सहकारिता के सिद्धान्त को केवल साख के लिये ही नहीं सीमित रखना चाहिये। जैसे कृषि में वैसे ही यहाँ पर भी उसे दूसरे कामों के लिये भी प्रयोग में लाना चाहिये। हाथ से काम करने वालों और दूसरे छोटे पैमाने पर काम करने वालों को बड़े पैमाने पर काम करने वालों की प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिये सहकारिता की जो आवश्यकता है वह स्वयं सिद्ध है।

यद्यपि सन् १९०४ के सहकारिता विधान में ही नागरिक समितियों की संस्थापना की व्यवस्था कर दी गई थी तो भी ये बहुत दिनों तक नहीं खुलीं। जैसा कि पहिले भी कहा जा चुका है यह अपनी रचना और कार्य-प्रणाली में कृषक समितियों से बहुत ही भिन्न है। नागरिक सहकारी समितियाँ भी अनेकों प्रकार की होती हैं; उदाहरण के लिये कर्मचारियों की समितियाँ, उपभोक्ताओं के सहकारी स्टोर, हाथ से काम करनेवालों तथा जुलाहों की समितियाँ, दुग्ध इकाइयाँ और समितियाँ, वीमा समितियाँ, विद्यार्थी स्टोर्स, इत्यादि। किन्तु यहाँ पर हमारा विशेष प्रयोजन तो हाथ से काम करने वालों और जुलाहों की समितियों से ही है। जुलाहों पर इसलिये विशेष जोर दिया गया है कि यहाँ पर कपड़े का काम बहुत महत्वपूर्ण है। सन् १९३९-४० के अंत में वम्बई में जुलाहों की ३६ समितियाँ थी, मद्रास में यही १९१ थी और पञ्जाब में ३५० से अधिक थीं। अन्य प्रान्तों के यह अङ्क नहीं मिलते किन्तु प्रत्येक में ऐसी कुछ समितियाँ हैं अवश्य। इनके अतिरिक्त अन्य

कारीगरों की समितियाँ भी हैं जिनके संबंध के भी अङ्क प्राप्त नहीं हैं। इधर युद्धकाल में घरेलू धन्धों को जो प्रोत्साहन मिला था उसके कारण भी अब इनकी संख्या और बढ़ गई होगी। इसमें सन्देह नहीं कि आजकल की समितियाँ केवल साख की ही व्यवस्था करती हैं किन्तु वे कच्चे माल के क्रय में और तैयार माल के विक्रय में तथा औजारों, इत्यादि के रखने में बड़ी सहायक सिद्ध हो सकती हैं। इस समय महाजन लोग यह सब काम करते हैं। प्रायः सभी शहरों में कुछ घरेलू धन्धे हैं और कुछ महाजन व्यापारी जो ऊँचे दामों पर कच्चे माल देते हैं और नीचे दामों पर तैयार माल लेते हैं। यदि यह काम सहकारी समितियाँ अपने हाथ में ले ले तो अवश्य ही इन कारीगरों की दशा बहुत कुछ सुधर जाय। अतः, जितनी ही जल्दी यह किया जाय उतना ही अच्छा है।

उद्योग एक प्रान्तीय विषय है। अतः, प्रत्येक प्रान्तीय सरकार अपने सीमित क्षेत्र में इसकी उन्नति के लिये जो कुछ कर सकती थी वह करती आ रही है। इनमें से कुछ तो भिन्न-भिन्न धन्धों की आर्थिक सहायता करती हैं और इनमें छोटे पैमाने के धन्धे विशेष तौर पर महत्वपूर्ण हैं। यह सहायता थोड़े व्याज पर ऋण देने के रूप में अथवा किराये और खरीद पर मशीनरी की पूर्ति के रूप में अथवा भूमि अथवा अन्य कोई सरकारी सम्पत्ति देने के रूप में होती है। ये प्रोपेगैण्डा करती हैं, धन्धों के क्रम को क्रियात्मक रूप में दिखाती हैं और उनके सम्बन्ध की मन्त्रणा देती हैं। किन्तु जो रिपोर्टें निकली हैं, उनसे स्पष्ट है कि इन्हे अभी कोई विशेष सफलता नहीं मिली है। ये जो आर्थिक सहायता देती हैं वह बहुत कम होती है और प्रायः वास्तविक काम करने वालों को नहीं मिलती। शायद यही कारण है कि उसमें से बहुत-सा बट्टे खाते डालना पड़ता है। सत्य तो यह है कि सरकार इस काम को कर ही नहीं सकती। यदि इसको यह काम करना है तो इसे यह सहकारी समितियाँ अथवा प्रान्तीय सहकारी बैंकों के द्वारा करना चाहिये। प्रान्तीय सहकारी बैंक घरेलू धन्धे के लिये बहुत ही सिद्ध हो सकते हैं। फिर सरकार यदि धन्धों की सहायता ही करना चाहती है तो वह चाहे बड़े पैमाने के हों अथवा छोटे के, अन्य तरीकों से सहायता कर सकती है। उसकी क्रय नीति ही इस सम्बन्ध में बहुत कुछ कर सकती है।

उपसंहार

वास्तव में औद्योगिक अर्थ के विषय में कोई बात निश्चित रूप से कही ही नहीं जा सकती। देश में चतुर्मुखी उन्नति की आवश्यकता है। शुद्ध औद्योगिक बैंकों के और खुलने की जरूरत है। उन्हें जैसे सुभाव अब तक अनुभव प्राप्त करके दिये गये हैं उन्हीं के अनुसार काम करना चाहिये। इम्पीरियल बैंक और दूसरे बड़े बैंकों को उद्योग-धन्धों को आर्थिक सहायता देनी ही चाहिये। फिर, यदि आवश्यकता हो तो जनता के लिये जो उपयोगी धन्धे हैं उनकी करनेवाली संस्थाओं की आर्थिक सहायता करने के लिये प्रान्तीय कारपोरेशन भी खुलने चाहिये। जहाँ तक सरकार के उद्योग-धन्धों के प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक सहायता देने का प्रश्न है वहाँ तक यदि यह सहायता अन्य तरह की हो तो भी यथेष्ट है। औद्योगिक बैंक, व्यापारिक बैंक तथा प्रान्तीय कारपोरेशन किसी उद्योग-धन्धे को केवल उसके प्रारम्भ से उसके एक स्तर तक पहुँच जाने के काल में ही सहायक हो सकते हैं। अन्त में तो इसका बोझ जनता को ही उठाना पड़ेगा। अतः, इसके लिये हिस्सों और ऋण-पत्रों को अधिक प्रचलित करना चाहिये। हाँ, इम्पीरियल बैंक और दूसरे व्यापारिक बैंकों को इनकी अल्पकालीन आवश्यकताओं की तो अवश्य ही पूर्ति करना पड़ेगी। घरेलू धन्धों की सहायता के लिये तो सहकारी समितियों को ही प्रोत्साहन देना पड़ेगा। यथार्थ में उनकी मुक्ति तो इन्हीं के हाथ में है।

प्रश्न

(१) उद्योग-धन्धों की किस प्रकार की आर्थिक आवश्यकताएँ होती हैं ? प्रत्येक का तुलनात्मक महत्व बताइये और यह भी स्पष्ट कीजिये कि उनका पारस्परिक अनुपात किन बातों पर निर्भर रहता है ?

(२) इस देश में उद्योग-धन्धों की दीर्घकालीन आवश्यकताओं की कौन पूर्ति करता है ? उनके गुण और दोष बताइये। भारतीय औद्योगिक बैंकिंग ने अब तक इस सम्बन्ध में क्या किया है ?

(३) इम्पीरियल बैंक तथा दूसरे व्यापारिक बैंक किस तरह से यहाँ के उद्योग-धन्धों की आर्थिक सहायता करते हैं ? इनको और अधिक उपयोगी बनाने के लिये अपने सुभाव रखिये।

(४) प्रान्तीय औद्योगिक कारपोरेशनों की स्थापना के विषय में आपकी क्या सम्मति है ? इस सम्बन्ध में एक अखिल भारतीय सस्था की आवश्यकता दिखलाई दे।

(५) औद्योगिक कम्पनियों के हिस्सों और ऋण-पत्रों को जनता में अधिक चालू करने के लिये क्या करना चाहिये ? अभी तक वे यहाँ पर क्यों अधिक प्रिय नहीं हो सके हैं ?

(६) आपकी राय में यहाँ के औद्योगिक बैंकों को किस प्रकार काम करना चाहिये ? क्या आप उनकी स्थापना के पक्ष में हैं ?

(७) मैनेजिङ्ग एजेंटों की शक्ति को सीमित करने के सम्बन्ध में सन् १९३६ के भारतीय कम्पनी विधान में क्या-क्या बातें रखी गई हैं ? आपकी राय में क्या उनकी यहाँ पर अब भी आवश्यकता है ?

(८) घरेलू धन्धों को आर्थिक सहायता देने की यहाँ पर जो व्यवस्था है उसमें क्या दोष है ? उसे सुधारने के लिये अपने सुझाव रखिये ।

(९) भिन्न-भिन्न प्रान्तीय सरकारें अपने यहाँ के उद्योग-धन्धों को आर्थिक सहायता देने के लिये क्या करती हैं ? आपकी सम्मति में वे उनके लिये और किस प्रकार अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं ?

(१०) भारतीय उद्योग-धन्धों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिये एक अच्छी योजना रखिये । इस सम्बन्ध में अब तक जो कुछ किया गया है उसका भी वर्णन कीजिये ।

अध्याय १६

व्यापारिक बैंक

वैसे तो इस शीर्षक में सम्मिलित पूँजी के भारतीय बैंक, इम्पीरियल बैंक तथा विदेशी बैंक सभी आ जाते हैं, क्योंकि ये सभी अन्य कामों के साथ-साथ व्यापारिक बैंकिंग के काम भी करते हैं; किन्तु सुविधा के लिये हम यहाँ पर केवल सम्मिलित पूँजी के भारतीय बैंकों को ही लेंगे। इम्पीरियल बैंक तथा विदेशी बैंकों के विषय में हम अगले दो अध्यायों में पृथक्-पृथक् अध्ययन करेंगे। हाँ, इसमें वर्तमान औद्योगिक बैंक भी आ जायेंगे। सच तो यह है कि वह जो

कुछ औद्योगिक वैकिंग के काम करते हैं उसके साथ-साथ व्यापारिक वैकिंग के कार्य भी करते हैं। फिर, उनकी रचना भी अन्य व्यापारिक वैकों की ही तरह भारतीय कम्पनी विधान के अन्तर्गत ही हुई है। अब, क्योंकि व्यापारिक वैकों के क्रमिक विकास का तो अध्ययन हम बारहवें अध्याय ही में कर चुके हैं, अतः, यहाँ पर हम केवल उनकी वर्तमान स्थिति का ही दिग्दर्शन करेंगे।

सङ्गठन

सम्मिलित पूँजी के भारतीय वैकों का रजिस्ट्रेशन भारतीय कंपनी विधान के अनुसार ही होता है। सन् १९३७ के प्रारम्भ तक तो वे उसके साधारण नियमों के अनुसार ही चलते थे। हाँ, कुछ बातों में अब, वैकिंग कम्पनियों तथा साधारण कम्पनियों के बीच में थोड़ा बहुत अन्तर था। यह निम्नांकित थीं:—

(१) किसी साभे के वैकिंग के संगठन में साभियों की संख्या २० हो सकती है, किन्तु वैकिंग के संगठन में यह केवल १० ही हो सकती है।

(२) वैकिंग के काम करने वालों को रजिस्ट्रार के यहाँ अपने काम करने के सभी स्थानों का नाम भी भेजना पड़ता है।

(३) वैकिंग कम्पनी को रजिस्ट्रार के यहाँ नियत समय पर अपनी बैलन्स शीट अवश्य भेजनी पड़ती है और उसमें जमानत पर दिये गये ऋणों को और बिना जमानत के दिये गये ऋणों को अलग-अलग दिखलाना पड़ता है।

(४) दूसरा काम करने वाली कम्पनियों के सम्बन्ध में तो यदि कम से कम १० प्रतिशत सदस्य भी कहते हैं तो प्रान्तीय सरकार उनका निरीक्षण कर लेती है किन्तु वैकिंग का काम करने वाली कम्पनियों के सम्बन्ध में ऐसा तभी हो सकता है जब कम से कम २० प्रतिशत हिस्सेदार ऐसा करने को कहे।

किन्तु देश में यह राय थी कि वैकिङ्ग को नियन्त्रण में रखने के लिये इतना ही यथेष्ट नहीं है। केन्द्रीय कमेटी ने तो एक विशेष विधान बनाने की सिफारिश की थी। हाँ, विदेशी विशेषज्ञों ने केवल कुछ सशोधन मात्र ही करने को कहे थे। अतः, भारतीय सरकार ने

उन्हीं की राय के अनुसार सन् १९३६ में कम्पनी विधान में निम्न संशोधन किये :—

(१) बैंकिंग कम्पनी की एक परिभाषा दी। किन्तु यह सन्तोषजनक नहा है। जैसा कि पहिले ही कहा जा चुका है रिजर्व बैंक के कार्यकर्ताओं ने इस बात की शिकायत की थी कि ब्रिटिश भारत में ऐसे बहुत से गैरसदस्य बैंक थे जो उक्त परिभाषा के अनुसार बैंकों की श्रेणी में नहीं आते थे। अतः, वह रिजर्व बैंक को वह सूचना नहीं देते थे जिसको देना उनके लिये अनिवार्य कर दिया गया था।

(२) कोई बैंकिंग कम्पनी तब तक रजिस्टर्ड नहीं हो पाती जब तक वह अपने योजना-पत्र में उद्देश्यों के अन्तर्गत यह नहीं लिख देती कि वह केवल जमा प्राप्त करने के तथा बैंकिंग कम्पनी की परिभाषा में दिये हुये कामों में से कुछ अथवा सब काम ही करेगी। जो कम्पनियाँ पहिले काम कर रही थी उन्हें इस विधान के पास होने के दो वर्षों के अन्दर ही अपने गैर बैंकिंग के कार्य बन्द कर देने पड़े।

(३) उक्त विधान के पास होने के दो वर्षों के बाद से कोई बैंकिंग कम्पनी किसी भी ऐसे मैनेजिङ्ग एजेंट के द्वारा नहीं चलाई जा सकती जो बैंकिंग का काम न करता हो।

(४) कोई बैंकिंग कम्पनी तब तक अपना व्यवसाय नहीं प्रारम्भ कर सकती जब तक कि उसके इतने हिस्से न बिक जायँ कि उसके पास कम से कम पचास हजार रुपये आ जाय। संचालको को इस सम्बन्ध का एक प्रमाण-पत्र भी देना पड़ता है जिससे वह यह कहते हैं कि उन्होंने ५०,००० रु० प्राप्त कर लिया है।

(५) कोई बैंकिंग कम्पनी अपनी अग्राप्त पूँजी पर कोई ऋण नहीं ले सकती।

(६) रिजर्व बैंक के सदस्य बैंकों को छोड़कर प्रत्येक बैंक को लाभ की बँटनी करने के पहिले उससे से उस समय तक कम से कम २० प्रतिशत सुरक्षित कोष में डालना पड़ता है जिस समय तक यह सुरक्षित कोष उसको प्राप्त पूँजी के बराबर नहा हो जाता। इसे किसी सरकारी अथवा ट्रस्ट साख-पत्रों में लगाना पड़ता है अथवा रिजर्व बैंक के किसी सदस्य बैंक के पास रखना पड़ता है। जो बैंकिंग

कम्पनियाँ उस समय भी काम कर रही थीं उन पर यह नियम विधान के पास हो जाने के दो वर्षों बाद लागू होने को था ।

(७) रिज़र्व वैक के सदस्य वैकों को छोड़कर प्रत्येक वैक को अपने माँग पर देय दायित्व का कम से कम ५ प्रतिशत और अन्य दायित्व का कम से कम १३ प्रतिशत अपने पास नकदी में रखना अनिवार्य है । यदि इसका उल्लंघन किया जाता है तो कम्पनी के प्रत्येक जिम्मेदार कर्मचारी पर जितने दिन तक यह उल्लंघन रहे उतने दिन का प्रतिदिन जुर्माना लगता है ।

(८) कोई वैकिंग कम्पनी केवल अपनी सहायक कम्पनी को छोड़ कर न तो अन्य कोई सहकारी कम्पनी बना सकती है और न उसके हिस्सों को ले सकती है ।

(९) यदि कोई वैकिंग कम्पनी अपना ऋण नहीं दे सकती है तो यदि वह इस बात की प्रार्थना करती है और उसके साथ ही रजिस्ट्रार की रिपोर्ट भी है तो अदालत यह आज्ञा दे सकती है कि कुछ दिनों तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई न की जाय । रजिस्ट्रार की आज्ञा के बिना भी उसे थोड़े दिनों की छूट दी जा सकती है ।

(१०) कोई ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर कम्पनी का ऋण चाहिये उसका आडीटर भी नहीं नियुक्त किया जा सकता । न यदि किसी के आडीटर नियुक्त होने के बाद वह कम्पनी का ऋणी हो जाय तो वह कम्पनी का आडीटर ही रह सकता है । फिर, आडीटरों को उस बैठक में भी उपस्थित होने की आज्ञा दे दी गई है जिसमें उसके द्वारा आडिट किया हुआ हिसाब रक्खा जाय । ऐसी बैठक में वह हिसाब के विषय में बोल भी सकता है । यदि कोई आडीटर विधान में दिये हुये किसी नियम का उल्लंघन करता है तो उस पर १००) तक का जुर्माना लग सकता है ।

(११) प्रत्येक कम्पनी को, चाहे वह वैकिंग की हो अथवा अन्य किसी तरह की, अपने सदस्यों के रजिस्टर के साथ-साथ उनकी सूची भी रखनी पड़ती है ।

(१२) जिस एफ (F) फार्म पर कम्पनियों को अपनी बैलन्स शीट तैयार करनी पड़ती है उसमें भी वैकिंग कम्पनियों के लिये कुछ अधिक व्योरे भरने पड़ते हैं । लागत के मूल्यांकन का ढङ्ग भी लिखना पड़ता है; अर्थात् वह क्रय मूल्य अथवा बाजार मूल्य है । फार्म जी (G) में

भी उन्हें अपनी आर्थिक स्थिति के विषय में एक विशेष सूचना देनी पड़ती है और उसे बैलन्स शीट की लिपि के साथ-साथ दफ्तर में दिखलाना पड़ता है। विदेशी बैंकों को भी फार्म एच (H) में कुछ सूचनायें देनी पड़ती हैं।

(१३) प्रत्येक कम्पनी के संचालकों को चाहे वह बैंकिंग की हो अथवा अन्य किसी व्यवसाय के सम्बन्ध की हो हिस्सों के हस्तान्तरित करने के आवेदन-पत्रों पर अपनी स्वीकृति की सूचना अधिक-से-अधिक दो मास के अन्दर दे देनी पड़ती है।

फिर सन् १९४४ के एक दूसरे सशोधन में नियम व्यवस्था की गई थी :—

(१) कोई बैंकिंग कम्पनी चाहे वह ब्रिटिश भारत में गठित हुई हो अथवा बाहर किन्तु यदि भारतवर्ष में काम करती है तो इस विधान के पास होने के दो वर्ष बाद किसी मैनेजिङ्ग एजेंट के द्वारा नहीं चलाई जा सकती। न वह किसी ऐसे व्यक्ति को ही रख सकती है जिसका प्रतिफल अथवा जिसके प्रतिफल का कुछ भी अंश कमीशन के रूप में अथवा कम्पनी के लाभ के प्रतिशत के रूप में देने का निश्चय हुआ हो। न वह किसी से एक बार में पाँच वर्षों से अधिक तक उसके चलाने का कोई समझौता किया जा सकता है।

(२) जिस बैंकिंग कम्पनी का इस विधान के अनुसार सन् १९३७ की १५ जनवरी को अथवा उसके बाद संगठन हुआ है वह इस सन् १९४४ के विधान के लागू होने के दो वर्ष बाद ब्रिटिश भारत में उस समय तक व्यवसाय नहीं कर सकती जिस समय तक वह निम्न शर्तों को पूरा नहीं कर देती है :—

(१) उसकी क्रीत पूँजी उसकी अधिकृत पूँजी की आधी है, और उसकी प्राप्त पूँजी भी उसकी क्रीत पूँजी की आधी है।

(२) उसके हिस्से केवल साधारण हैं अथवा यदि सप्ला भी है तो वह इस सशोधन के पास होने के पहिले के हैं।

(३) प्रत्येक हिस्सेदार का मताधिकार उसकी पूँजी के अनुपात में है।

किन्तु एक पृथक् बैंकिंग विधान की आवश्यकता के कारण सन् १९४४ के नवम्बर में एक बैंकिंग बिल यहाँ की व्यवस्थापिका सभा में रक्खा गया और जब वह उक्त सभा के भङ्ग होने पर और दूसरी सभा

के बनने पर समाप्त हो गया। तब सन् १९४६ में एक नया विल रखा गया। किन्तु यह अभी तक स्वीकृत नहीं हो पाया है। इसकी मुख्य-मुख्य बातें यहाँ पर दी जाती हैं :—

(१) बैंकिंग की एक सीधी-साधी परिभाषा जिसका उद्देश्य इस विधान को केवल उनके ऊपर ही लागू करना है जो जमा प्राप्त करते हैं और उस जमा को सुरक्षित रखना तथा फौरन ही देने के लिये तैयार रखना है।

(२) न्यूनतम पूँजी निर्धारित करना।

(३) जोखिम दूर करने के उद्देश्य से अन्य व्यवसाय करने पर प्रतिबन्ध लगा देना।

(४) ब्रिटिश भारत के बाहर गठित और रजिस्टर्ड बैंकों के ऊपर भी नियन्त्रण रखना।

(५) भङ्ग होने पर शीघ्र ही भुगतान करवाना।

(६) आवश्यकता पड़ने पर रिजर्व बैंक को उनकी किताबें और उनके हिसाब देखने का अधिकार देना।

(७) जब कोई बैंक जमा करने वालों के हित के विरुद्ध काम करे तब केन्द्रीय सरकार को उसके विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार देना।

(८) एक विशेष प्रकार की बैलन्स शीट बनवाना और रिजर्व बैंक को जब वह चाहे तब उनसे कोई भी सूचना माँगने का अधिकार देना।

किन्तु उपर्युक्त विल के पास होने में देर मालूम पड़ने के कारण इस सम्बन्ध के कुछ फुटकर विधान पास कर दिये गये हैं। प्रथम का तो यह उद्देश्य है कि सरकार जब चाहे तब रिजर्व बैंक को किसी भी बैंक के हिसाब को देखने के लिये नियत कर सके और यदि उसकी निरीक्षण की रिपोर्ट से यह पता चले कि उसका काम जमा करने वालों के हित में ठीक नहीं चल रहा है तो उसे ठीक करने के लिये कोई भी उचित कार्यवाही कर सके। यदि आवश्यकता पड़े तो वह किसी भी बैंक को जमा प्राप्त करने के लिये मना कर सकती है अथवा रिजर्व बैंक की तालिका में सम्मिलित होने से रोक सकती है अथवा यदि वह उस तालिका में पहिले से ही सम्मिलित है तो उसे उससे निकाल सकती है। दूसरे का उद्देश्य बैंकों की बढ़ती हुई शाखाओं का नियन्त्रण और कुछ अनुचित बातों को रोकना है, जैसे उनके साधनों

को देखते हुये उनकी शाखाओं पर अतिशय व्यय और उनके यहाँ अनुभवहीन कर्मचारियों की नियुक्ति। इसके अनुसार कोई बैंक रिज़र्व बैंक की पहिले से अनुमति लिये बिना न तो कोई नई शाख खोल सकता है और न किसी को बदल सकता है। कहना न होगा कि ऐसा करने के पहिले वह यह देख लेता है कि उस बैंक की आर्थिक स्थिति कैसी है, उसका विकास कैसा रहा है, उसकी व्यवस्था कैसी है, उसकी पूँजी पर्याप्त है अथवा नहीं, उसकी आय के लिये कैसी सम्भावना है और उस शाख से जनता का हित होगा अथवा नहीं। यदि आवश्यकता पड़ती है तो सरकार की सम्मति से वह उसके हिसाब, इत्यादि का भी निरीक्षण कर लेता है। तीसरे का उद्देश्य कुछ बैंक का जो यह चलन हो गया था कि वह मुदती देखनहार प्रण-पत्र निकालते थे जो करन्सी नोट का काम करने लगे थे उसे रोकना था।

वर्गीकरण

व्यापारिक बैंक चार वर्गों में बाँटे जा सकते हैं :- (१) जिनकी पूँजी उनके सुरक्षित कोष को मिलाकर पाँच लाख रुपये अथवा उससे अधिक है, (२) जिनकी पूँजी उनके सुरक्षित कोष को मिलाकर एक लाख और पाँच लाख रुपये के बीच में है, (३) जिनकी पूँजी उनके सुरक्षित कोष को मिला कर ५०,००० और १ लाख रु० के बीच में है, और (४) जिनकी पूँजी और सुरक्षित कोष ५०,००० रु० से कम है।

पहिले वर्ग में (अ) सदस्य और (ब) गैरसदस्य बैंक हैं। सदस्य बैंकों की संख्या सन् १९४७ के अन्त में ९९ थी। इसमें इम्पीरियल बैंक और ब्रिटिश बैंक भी सम्मिलित हैं। गैरसदस्य बैंकों की संख्या सन् १९४५ के अन्त में ६८ थी। रिज़र्व बैंक विधान की ४२ (६) धारा में यह दिया हुआ है कि केन्द्रीय सरकार गजट में निकलवा करके किसी भी ऐसे बैंक का नाम रिज़र्व बैंक की दूसरी तालिका में सम्मिलित करवा सकती है जिसका नाम उसमें सम्मिलित न हो, जो ब्रिटिश भारत में व्यवसाय करता हो और (अ) जिसकी पूँजी उसके सुरक्षित कोष को मिलाकर पाँच लाख रु० से कम न हो और (ब) भारतीय कम्पनी विधान की (२) धारा की (२) उपधारा में दी हुई परिभाषा के अनुसार कम्पनी हो अथवा ब्रिटिश भारत के बाहर के किसी

विधान के अनुसार गठित कम्पनी अथवा कारपोरेशन ही और ऐसे ही उक्त तालिका में सम्मिलित बैंक को उसमें से उसकी पूँजी और सुरक्षित कोप के पाँच लाख रुपये से कम हो जाने पर अथवा उसके दिवालिया हो जाने पर अथवा किसी अन्य कारण से बैंकिंग व्यवसाय बन्द कर देने पर हटा भी सकती है। सन् १९४० के पहिले यदि किसी बैंक की आडिट की हुई बैलन्स शीट से उसकी पूँजी उसके सम्मिलित कोप को मिला करके पाँच लाख मालूम पड़ती थी तो वह बैंक उपर्युक्त तालिका में सम्मिलित कर लिया जाता था। किन्तु इस संबन्ध में सरकार को कुछ कठिनाइयाँ पड़ीं। अतः, उसने यह निश्चय कर दिया कि इस पूँजी और कोप का अर्थ वास्तविक पूँजी और कोप से है न कि उस पूँजी और कोप से है जो बैलन्स शीट में दिखाई गई है। अतः, रिजर्व बैंक ने सरकार को इस बात का पता लगाने में सहायता देने का वचन दिया है और यदि आवश्यकता पड़ती है तो वह प्रार्थी बैंक की किताबों का निरीक्षण भी कर सकता है। बस (अ) में यही बैंक है। उन्हे अपने कुछ दायित्वों को पूरा करना पड़ता है और उनके कुछ अधिकार भी हैं। (ब) में वह बैंक है जो किसी कारणवश इस तालिका में नहीं सम्मिलित हो पाये है। उनमें से कुछ तो भारतीय रियासतों में रजिस्टर्ड हुये हैं और वहीं काम करते हैं। उन्हे इस तालिका में इसलिये सम्मिलित नहीं किया जा सकता कि उनकी कोई शाख भी ब्रिटिश भारत में^१ नहीं है।

दूसरे, तीसरे, और चौथे वर्गों में केवल गैरसदस्य बैंक ही हैं। इनमें से प्रथम दो की संख्या तो सन् १९४५ में क्रमशः १७४ और ११४ थी और तीसरे की संख्या २४४ थी।

चौथे वर्ग के बैंक वही हैं जो सन् १९३६ के कम्पनी विधान के पास होने के पहिले स्थापित हो चुके थे। तब से ५०,००० रु० से कम पूँजी के बैंक चालू किये ही नहीं जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त जैसा कि पहिले भी कहा जा चुका है कम्पनी विधान की (६) धारा के अनुसार इनकी पूँजी इनके सुरक्षित कोप को मिलाकर सुरक्षित कोप के बराबर बढ़ने के कारण बढ़ रही है। अतः, इनकी संख्या उत्तरोत्तर घट रही

^१ अथवा रियासतें भारतवर्ष में सम्मिलित हो रही हैं इससे स्थिति बदल जायगी।

हैं। सन् १९३९ से सन् १९४२ तक इनकी संख्या क्रमशः ४००, ३३२, १४७ और १३३ थी। इसके बाद यह बढ़ी। किन्तु इसका कारण यही था कि अब उन सभी बैंकों को रिज़र्व बैंक को अपनी रिपोर्ट देनी पड़ती है जो 'बैंक' के नाम से पुकारे जाते हैं। सन् १९४३ से सन् १९४५ तक इनकी संख्या क्रमशः १६१, २३५ और २४४ थी। सन् १९४६ में जिन गौरसदस्य बैंकों ने रिज़र्व बैंक को अपनी रिपोर्टें भेजी थीं उनकी संख्या ६५९ थी। इसमें जो कारण ऊपर दिया हुआ है उसके अनुसार वह सभी संस्थाएँ सम्मिलित हैं जो अपने नाम के साथ-साथ 'बैंक' शब्द का प्रयोग करती हैं। किन्तु सत्य तो यह है कि इनमें से बहुतों को बैंक नहीं कहना चाहिये। वे इस नाम को केवल इसी-लिये प्रयोग में लाती हैं कि जिससे उन्हें एक प्रकार का सम्मान प्राप्त होता रहे।

वर्तमान स्थिति

द्वितीय महायुद्ध का इस देश की वैंकिंग पर काफी प्रभाव पड़ा। नई-नई संस्थाएँ खुलीं और पुरानी बढ़ गईं। इसका यह कारण नहीं था कि युद्ध से बैंकों को यहाँ के व्यापार और उद्योग-धन्धों को अधिक सहायता देने का अवसर मिला। बल्कि इसके विपरीत सरकार के उन व्यापार और धन्धों को स्वयं ही सहायता देने के कारण जो युद्ध सामग्री की पूर्ति में सहायता करते थे इनसे वह भी अवसर छिन गया जो इन्हें इसके पहिले प्राप्त था। इसके अतिरिक्त इनके उत्तरोत्तर बढ़ते हुये लाभ के कारण इनके स्वयं के पास इतनी पूँजी हो गई कि इन्हें बैंकों की सहायता लेने की आवश्यकता ही नहीं रह गई। फिर, सरकार ने भी ऐसे नियम बना दिये कि यह बहुत सी चीजों की गिरवी पर ऋण नहीं दे सकते थे। किन्तु इनकी जमा बराबर बढ़ती जा रही है और भारतवर्ष में वैंकिंग की उन्नति सदा से इसी कारण ही हुई है। युद्ध की व्यवस्था के लिये इस देश को केन्द्र बनाने का महत्त्व इस बार युद्ध के प्रारम्भ होते ही प्रतीत होने लगा था। इससे सरकार को अपनी और अन्य मित्रराष्ट्रों की ओर से यहाँ पर काफी व्यय करना पड़ा। अतः, फल यह हुआ कि यहाँ की करन्सी विशेषतः नोट करन्सी बढ़ती गई और उसी के कारण बैंकों के जमा भी बढ़ते गये। निस्सन्देह कभी-कभी युद्ध की विपरीत परिस्थितियों के

कारण जमा घटी भी; किन्तु उससे बैंकों को केवल अपनी स्थिति को दृढ़ रखने में सहायता ही मिली।

जब से युद्ध प्रारम्भ हुआ अर्थात् सितम्बर १९३९ से, तब से सदस्य बैंकों की संख्या बढ़ती ही गई। सन् १९४७ के अन्त तक में कम से कम इस अवधि के बीच में ४२ नये सदस्य बैंक बन चुके थे। निस्सन्देह, इसमें से कुछ तो यहाँ पहिले ही से काम कर रहे थे। किन्तु कुछ नये बैंक भी हैं। इस बीच में कुछ गैरसदस्य बैंक भी स्थापित हुये हैं।

सदस्य बैंकों और गैरसदस्य बैंकों की शाखाएँ भी बढ़ती रही हैं। जब सन् १९३९ में सब सदस्य बैंकों के १२५० दफ्तर थे, मार्च सन् १९४७ में यह ३५७६ थे। इधर इनकी संख्या कुछ घट गई है। उपर्युक्त में से यदि इम्पीरियल बैंक की ४४७ और विनिमय बैंकों की ८० संख्या घटा भी दें तो भी यह काफी है। यह भी बहुत सन्तोष की बात है कि इनमें से कुछ दफ्तर तो उन स्थानों में खुले हैं जिनमें पहिले कोई बैंक था ही नहीं। दफ्तरों की संख्या में यह वृद्धि नये बैंकों की स्थापना और उनके तथा पहिले से ही स्थापित बैंकों के सदस्य बैंक बन जाने के कारण और पुराने सदस्य बैंकों के अपने दफ्तरों की संख्या बढ़ा लेने के कारण हुई है। नवम्बर सन् १९४६ में जैसा कि पहिले भी कहा जा चुका है एक ऐसा प्रतिबन्ध पास हो गया है कि जिसके कारण अब रिज़र्व बैंक की आज्ञा के बिना नये दफ्तर नहीं खुल सकते हैं।

इस अवधि के बीच में सदस्य तथा गैरसदस्य बैंकों की जमा भी बढ़ गई है। सदस्य बैंकों की जमा सन् १९३९ के सितम्बर में २३६.६० करोड़ रु० थी और गैरसदस्य बैंकों की उसी दिसम्बर में १५.९६ करोड़ रु० थी। इसकी तुलना में इन दोनों की जमा क्रमशः ७६८.८२ (अप्रैल, १९४८ में) और ७८.४४ (सन् १९४६ के अन्त में) करोड़ रु० थी। निस्सन्देह, प्रथम में इम्पीरियल बैंक और विनिमय के बैंकों की जमा भी सम्मिलित है। किन्तु यह बिना किसी संकोच के कहा जा सकता है कि जो वृद्धि भी हुई है वह सभी के यहाँ हुई है।

बैंकों ने अपनी पूँजी भी बढ़ा ली है। बड़े बैंकों ने तो ऐसा जमा में पूँजी के अनुपात को बढ़ाने की दृष्टि से किया। ऐसा करने में उन्होंने बाज़ार की आर्थिक स्थिति से लाभ उठाया और अपने हिस्सों

को अधिक मूल्य पर बेचकर अपने सुरक्षित कोष को भी बढ़ा लिया। छोटे बैंकों ने ऐसा सदस्य बैंक बनने के लिये किया। सन् १९३६ के विधान की (६) धारा के अनुसार उनका सुरक्षित कोष भी बढ़ता रहा। पूँजी को इस तरह से बढ़ाने की इस प्रथा पर भी ऐतराज किये गये हैं। कहा जाता है कि जमा में पूँजी का जो अनुपात होना चाहिये उसके विषय में कोई निश्चित बात नहीं है। कम अनुपात होने से किसी प्रकार की शंका नहीं करनी चाहिये। अधिक पूँजी होने से अधिक लाभ प्राप्त करने का प्रयत्न करना पड़ता है। अतः, इससे अनुचित लागत लगाने का भी डर रहता है। नये बैंकों में भारत बैंक की पूँजी (२ करोड़ रु० से भी अधिक) पाँचों बड़े बैंकों की पूँजी से अधिक थी; हिन्दुस्तान कमर्शियल बैंक की (१३ करोड़ रु०) केवल सेन्ट्रल बैंक को छोड़कर अन्य सब बड़े बैंकों की पूँजी से अधिक और यूनाइटेड कमर्शियल बैंक की सेन्ट्रल बैंक और बैंक आफ इण्डिया को छोड़कर अन्य सब बैंकों की पूँजी से अधिक थी।

इनका नकद कोष भी बढ़ रहा है। युद्ध के पहिले यह प्रायः जमा का १० प्रतिशत रहता था, किन्तु युद्ध काल में यही प्रायः १५ प्रतिशत रहता था। शान्ति के साथ-साथ यह शायद फिर घट जाय।

इनके कार्य

सब प्रकार के जमा प्राप्त करने के साथ-साथ ये व्यापार और उद्योग-धन्धों को भी यथा-सम्भव आर्थिक सहायता पहुँचाते रहते हैं, अर्थात् नकद साख् एकाउण्ट खोलते हैं, बिलों और हुण्डियों को डिस्काउण्ट करते हैं, द्रव्य को एक स्थान से दूसरे स्थानों को पहुँचाने की सुविधा देते हैं और जनता की अन्य दूसरे प्रकार से सेवायें करते हैं। कृषि और उद्योग-धन्धों को आर्थिक सहायता देने में इनका जो हाथ रहता है उसके विषय में तो हम पहिले ही अभ्ययन कर चुके हैं। आगे के एक अध्याय में हम यह भी देखेंगे कि वह अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को कहाँ तक आर्थिक सहायता देते हैं। हाँ, यहाँ पर यह कह देना भी शायद अनुचित न होगा कि यह इस सम्बन्ध में भी कोई सन्तोषजनक काम नहीं करते। इधर इनका जो कुछ भी हाथ है वह माल को बन्दरगाहों से उसके उपभोक्ताओं तक और मण्डियों से बन्दरगाहों तक पहुँचाने के सम्बन्ध में है। इधर भी यह उतना काम

नहीं करते जितना इनको करना चाहिये। बात यह है कि विदेशी बैंकों ने अपनी शाखायें देश के भीतरी शहरों में भी खोल रखी हैं अथवा कुछ भारतीय बैंकों के मार्फत अपना काम करवा लेते हैं। अतः, इनको पूरा काम नहीं मिलता।

इनकी जमा निरन्तर और विशेषतः युद्धकाल में बढ़ती रही है। अब चूँकि अधिकतर बैंक अपनी भिन्न-भिन्न प्रकार की जमा पृथक्-पृथक् नहीं दिखलाते, अतः, इनके बीच में उसके वितरण का कोई अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता। हाँ, जहाँ तक यहाँ के पाँच बड़े बैंकों का सम्बन्ध है, उनकी स्थायी और अस्थायी जमा की रकम, अलग-अलग मालूम की जा सकती है, और जब से रिजर्व बैंक स्थापित हुआ है तब से तो सभी सदस्य बैंकों के सम्बन्ध की यह सूचना मिल सकती है। इससे यह पता लगता है कि प्रथम की अस्थायी जमा और स्थायी जमा का पारस्परिक अनुपात सन् १९१३ में १३.१ : ८६.९; सन् १९२० में ३४.८ : ६५.२; सन् १९२६ में ३३.४ : ६६.६; और सन् १९२९ में ३५.० : ६५.० था और द्वितीय का यही सन् १९३६ में ५४.६ : ४५.४; सन् १९३८ में ५४.८ : ४५.२; सन् १९४० में ५७.१ : ४२.९; सन् १९४२ में ७६.२ : २३.८; सन् १९४४ में ७२.९९ : २७.०१; और सन् १९४६ में ७१.६ : २८.४ था। यह इस बात का प्रमाण है कि अस्थायी जमा स्थायी जमा की अपेक्षाकृत उत्तरोत्तर अधिक चल रही है; और साधारणतया तो यह अच्छी बात है। किन्तु वर्तमान स्थिति में इससे केवल स्थायी जमा के कम होने का पता चलता है। हमारे यहाँ स्थायी जमा कई कारणों से कम होती जा रही है।

प्रथम तो सन् १९२० के बाद से डाकखानों के सेविंग बैंक खाते और कैश सर्टीफिकेट बहुत प्रिय होते जा रहे थे। सन् १९२० और सन् १९३९ के प्रथम के अङ्क क्रमशः २१३४ लाख और ८४४४ लाख रुपये थे और यही द्वितीय के सन् १९२० और सन् १९३६ के क्रमशः ५७५ लाख और ६५९८ लाख रुपये थे। तब से यह अवश्य कम हो रहे हैं। यह केवल इसलिये ही नहीं था कि बैंकों की अपेक्षा डाकखानों पर जनता का अधिक विश्वास था, बल्कि इसलिये भी कि बैंकों को अपेक्षाकृत ऊँचा व्याज देते हैं।

दूसरे, जान बीमा तथा भिन्न-भिन्न प्रकार के सरकारी तथा औद्योगिक कम्पनियों के साख-पत्रों में भी दिनोंदिन लागत बढ़ती

जा रही है। जो धन पहिले स्थायी जमा के रूप में लग जाता था वह अब अस्थायी जमा के रूप में आकर अन्त में इनमें लग जाता है।

भिन्न-भिन्न प्रकार की जमा पर जो व्याज की दर दी जाती है उनका भी उनके वितरण पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। किन्तु सेन्ट्रल बैंक को छोड़कर अन्य किसी बैंक के इन व्याज के दरों के विषय में कोई लेख नहीं मिलता। हाँ, प्रायः सभी बैंकों की दोनों तरह की जमा को एक साथ लेने पर उनके व्याज की औसत दर का पता चल जाता है। जहाँ तक हो चालू खाते में व्याज नहीं देना चाहिये और यही प्रथा अन्य देशों में है भी। हम जानके हैं कि लोग चालू खातों में तो जमा केवल अपनी सुविधा के विचार से करते हैं न कि वह उसे लाभप्रद लागत समझते हैं। अतः, व्याज की दर के अनुसार यह बिल्कुल नहीं घटती-बढ़ती। फिर व्याज देने का प्रभाव बैंकों के ऊपर भी अच्छा नहीं पड़ता। इससे उन्हें आय करने की आवश्यकता अनुभव होती है; अतः, वह मन्दी में लागत लगाने का प्रयत्न करते हैं जिसका फल अच्छा नहीं होता। इससे वे फेल भी हो जाते हैं। किन्तु यहाँ, विदेशी बैंक भी चालू खातों पर व्याज देते हैं। इम्पीरियल बैंक अवश्य ऐसा नहीं करता। सम्मिलित पूँजी वाले बैंकों में से कुछ को छोड़कर अन्य सभी कुछ न कुछ व्याज देते ही हैं। यह केवल इसलिये ही है कि वह जानते हैं कि वह इम्पीरियल बैंक और विदेशी बैंकों के सामने व्याज दिये बिना नहीं ठहर सकते। सन् १९३१ तक सेन्ट्रल बैंक माँग पर देय जमा पर औसतन २.०१ से २.५३ प्रतिशत तक व्याज देता था। इधर यह अवश्य कम कर दिया गया है। किन्तु स्थायी खातों पर व्याज देना एक दूसरी ही बात है। इस पर व्याज की दर के अनुसार इसकी रकम भी घटती-बढ़ती रहती है। स्थायी और अस्थायी खातों के बीच में भी यह बात है कि स्थायी खातों पर बहुत थोड़ी दर से व्याज मिलने पर लोग स्थायी खातों में जमा न करके अस्थायी खातों में ही जमा रखना अधिक पसन्द करते हैं। इधर हमारे यहाँ यही हुआ है; स्थायी जमा अस्थायी हो गई है।

स्थायी और चालू खातों में दोनों में इधर जो व्याज की दर कम हो गई है उसका प्रभाव यह पड़ा है कि लागत के स्रोत शुष्क पड़ गये हैं। यह सचमुच ही खराब है। अतः, जैसा कि आगे चलकर ज्ञात

होगा इस सम्बन्ध में बैंकों को अपनी ऋण देने की नीति को अधिक उदार बनाना पड़ेगा। आजकल वे अतिरिक्त जमानतों पर जोर देते हैं और यदि वह नहीं मिलती तो ऋण नहीं देते। इसका यह फल होता है कि उनके पास द्रव्य पड़ा रहता है; अतः, वह जमा प्राप्त करने के विषय में उदासीन हो जाते हैं।

अगले पृष्ठों की तालिका में इम्पीरियल बैंक और सात प्रधान बैंकों की सन् १९३९ से सन् १९४५ तक की भिन्न-भिन्न जमा के अङ्क दिये जाते हैं जिससे इनकी तुलनात्मक उन्नति का अनुमान किया जा सकता है—

[सहस्र रुपयों में]

बैंक का नाम	वर्ष	स्थायी	सेविंग्स	जमा चालू	अन्य	कुल जोड़
इम्पीरियल बैंक	१९३९	८७,८४,१६
	१९४०	९६,०३,१७
	१९४१	१,०८,९१,९०
	१९४२	१,६३,४६,४८
	१९४३	२,१४,५०,८०
	१९४४	२,३४,४२,००
	१९४५	२,५९,३७,४५
सेन्ट्रल बैंक	१९३९	११,६२,००		१८,२४,८२	..	२९,८६,८२
	१९४०	१०,८६,३८		२१,६३,५०	३२,५०,८८
	१९४१	१२,०३,१२		२९,२८,७८	४१,३१,९०
	१९४२	११,५१,४६		४८,१३,८८	..	५९,६५,३४
	१९४३	१४,०८,४२		६७,५५,२९	८१,६३,७१
	१९४४	१८,६१,०८		७५,८७,५८	९४,४८,६६
	१९४५	२२,५०,३३		८२,७२,५८	१०५,२३,४१

बैंक आरु इण्डिया	१९३९ १९४० १९४१ १९४२ १९४३ १९४४ १९४५ ११,०२,४३ १२,१८,५० ४९,८०,२८ ४६,८३,०४	१८,५९,५१ २२,२७,६१ २५,८६,०३ ३६,८२,३८ ५५,१३,८८ ६०,८२,७१ ५९,०१,५४
इलाहाबाद बैंक	१९३९ १९४० १९४१ १९४२ १९४३ १९४४ १९४५	६,०८,९७ ६,६२,५७ ६,२३,९६ ५,३६,२६ ७,८७,१३ ९,१४,१९ १३,३६,७७	१,५८,७४ १,५६,६१ १,३७,५९ १,६२,५० १,९१,३७ २,२३,३० २,७९,९९	३,२७,४९ ३,६८,६७ ५,३३,८० ९,८३,२६ ११,०६,५२ ११,५४,५९ १२,५५,१५	२०,९७ १,९४ २,२९ २,४१ २,५८ २,८० २,९९	११,१६,१७ ११,८९,७९ १२,९७,६४ १६,८४,४३ २०,८७,६० २२,९३,८८ २८,७४,९०

पंजाब नेशनल बैंक	१९३९ १९४० १९४१ १९४२ १९४३ १९४४ १९४५	५,५०,७५ ५,५८,७७ ६,०१,४२ ७,४९,२३ १३,०६,४४ २०,७०,७२ ३०,४४,५७	१,५९,१३ २,३८,०२ ३,७१,२२ ७,८७,५७ १३,३६,७२ १६,७८,०२ २१,८७,८९	५,१७ ६,१८ ७,६६ ९,५३ २७,०६	७,१५,०५ ८,०२,९७ ९,८०,३० १५,४६,३३ २६,४३,१६ ३७,७५,८१ ५१,५२,४६
बैंक आफ बड़ोदा	१९३९ १९४० १९४१ १९४२ १९४३ १९४४ १९४५	२,६९,७२ २,५१,७० ३,३६,१३ २,८३,०६ ५,०७,८३ ६,१५,७३ ७,८४,५५	४,३२,५९ ४,९०,८० ६,२३,८८ १०,४३,६६ १५,६६,१२ २०,२३,२६ २१,७३,२१	५,४३ ५,९९ ७,६० ८,९५ १०,१९	६,९९,१४ ७,४८,४९ ९,६०,०१ १३,२६,७२ २०,७३,९५ २६,३८,९९ २९,६७,९५

भारत बैंक	१९४३	५,२२,४०	८,६२,०६	११,२४	१३,९५,७० २०,४१,०० २६,९१,३३
	१९४४	८,८५,९२	११,५५,४२	
	१९४५	१३,४४,१५	१३,४७,१८	
युनाइटेड कमर्शियल बैंक	१९४३	३,०३,०४	९,७४,१५	१२,७७,१९
	१९४४	३,५७,०२	१३,६५,२३	१७,२२,२५
	१९४५	६,९३,३५	१६,९५,१०	२३,८८,५३

जहाँ तक व्यापार की आर्थिक सहायता करने का प्रश्न है, वह कई रूप में की जाती है। दीर्घकालीन और अल्पकालीन ऋण में से चूँकि आजकल अल्पकालीन ऋण पर ब्याज की दर बहुत अच्छी है और व्यापारिक बैंक के दायित्व अल्पकालीन होते हैं, इसलिए वह अल्पकालीन ऋण देना पसन्द करते हैं। इनमें से यदि हम मुख्य ऋण (Loans & Advances) को पहिले ले, तो जमा की तुलना में वह इतने अधिक नहीं हैं जितने कुछ अन्य देशों में पाये जाते हैं। आगे इम्पीरियल बैंक तथा पाँच बड़े बैंकों की जमा के मुख्य ऋण में सन् १९४१, १९४३ और १९४५ के अनुपात दिये गये हैं—

जमा का मुख्य ऋण में प्रतिशत

	सन् १९४१ की बैलन्स- शीट के अनुसार	सन् १९४३ की बैलन्स- शीट के अनुसार	सन् १९४५ की बैलन्स- शीट के अनुसार
इम्पीरियल बैंक	३३	१५	२४
सेन्ट्रल बैंक	४०	२८	३२
बैंक आफ इण्डिया	४०	२४	३२
इलाहाबाद बैंक	३३	३५	५०
पंजाब नेशनल बैंक	४४	३२	२६
बैंक आफ बरोदा	४८	३०	३७

इससे कोई बात निश्चित रूप से नहीं कही जा सकती। कुछ बैंकों के यहाँ यह प्रतिशत अन्य बैंकों के यहाँ की अपेक्षाकृत बड़ी हुई है। एक वर्ष और दूसरे वर्ष के प्रतिशत में भी कभी-कभी बड़ा अन्तर है। यह बहुत लोचप्रद मालूम पड़ता है और ऐसा ज्ञात होता है कि व्यापार की स्थिति के अनुसार घटता-बढ़ता रहता है। इन मुख्य ऋणों में कृषि और उद्योग-धन्धों को दिये हुये ऋण भी सम्मिलित हैं चाहे वह कितने ही कम न हों; अतः, हम यह नहीं कह सकते कि इनमें कितने व्यापार के सम्बन्ध के हैं।

हम इन ऋणों के रूप को भी मालूम कर लेना चाहिये। देश में बैंक का चलन बहुत-कम है। अतः, इनमें से अधिकांश ऋण नकदी के रूप में दिये जाते हैं। इनके लिये जो जमानते दी जाती है वह प्रायः जमीन, मकान, जेवर, सोना, चाँदी तथा सरकारी साख-पत्रों की होती है। जो हो, ऐसे ऋण देने के लिये अब बैंक कम तैयार होते हैं। जहाँ तक सम्भव होता है वह ऋण लेने वाले से अपने यहाँ एक चालू खाता खोल लेने को कहते हैं और उसमें जमा की हुई रकम से अधिक निकालने की आज्ञा दे देते हैं। प्रायः जमानत पर ३० प्रतिशत की गुस्ताइश रखी जाती है। इन सब में नकद साख के रूप का ऋण बहुत ही महत्वपूर्ण है। बात यह है कि वह बैंक और ग्राहक दोनों की दृष्टि से लाभप्रद है। बैंक तो जैसा कि हम जानते हैं—जब चाहे तब और ऋण देना वन्द कर सकते हैं और ग्राहक उनके ऊपर जितनी दैनिक बाकी निकलती है उसी पर व्याज देते हैं। इस ऋण की जमानत प्रायः व्यापार सम्बन्धी माल ही की होती है जो या तो व्यापारी के गोदाम में ही छोड़ दिया जाता है या बैंक के गोदाम में रख दिया जाता है। प्रथम स्थिति में तो बैंक उसमें अपना ताला लगा लेता है और उस पर अपने नाम की तख्ती भी टाँग देता है और द्वितीय स्थिति में वह गोदाम भाड़ा भी लेता है। दोनों स्थितियों में बीमा भी करवा लिया जाता है; अतः, उसका खर्च भी ऋण लेने वाले के ऊपर ही पड़ता है। वैयक्तिक जमानतों पर बहुत कम ऋण दिये जाते हैं और यदि वह दिये भी जाते हैं तो उनके लिये दो धनियों के हस्ताक्षर के प्रण-पत्र लिखवा लिये जाते हैं।

यदि हम डिस्काउण्टिंग को ले तो यह कहा जा सकता है कि यह बहुत चालू नहीं है। सदस्य बैंकों ने मार्च सन् १९४७ में केवल

२२.०७ करोड़ रुपयों के बिलों को डिस्काउंट कर रक्खा था। यह उनके कुल दायित्व (८६३.७४ करोड़ रुपये) की तुलना में कुछ भी नहीं है। निम्न तालिका में यह इम्पीरियल बैंक तथा अन्य पाँच बड़े बैंकों के सम्बन्ध का सन् १९४१, १९४३, और १९४५ का कुल जमा के प्रतिशत में दिया हुआ है :—

कुल जमा का बिल डिस्काउंटिंग में प्रतिशत

	वैलन्स-शीट के अनुसार		
	१९४१	१९४३	१९४५
इम्पीरियल बैंक	७.१	३.४	३.२
सेन्ट्रल बैंक	६.४	४.८	६
बैंक आफ इण्डिया	२.६	०.५	३.३
इलाहाबाद बैंक	२.१	३.७	२.५
पंजाब नेशनल बैंक	...	०.८	२.७
बैंक आफ बड़ोदा	२.३	०.४	३.५

यह बहुत ही कम है। अतः, बैंकों की दृष्टि से इसके बहुत अच्छे होने के कारण इसे बढ़ाने के लिये प्रयत्न करने चाहियें। नये बैंकों में से डिस्काउंट बैंक, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक और भारत बैंक इस व्यवसाय को काफी करते हैं।

अन्त में हम सरकारी तथा अन्य प्रकार के साख-पत्रों में लगी हुई लागत को ले सकते हैं। इस सम्बन्ध के जो अङ्क हैं उनमें एक बैंक की दूसरे बैंकों में जो स्थायी जमा रहती है वह भी सम्मिलित है। अतः, इसके सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा जा सकता। किन्तु इससे कुछ अनुमान तो लग ही सकता है।

जमा का सरकारी तथा अन्य साख पत्रों में लागत तथा
अन्य बैंकों में स्थायी जमा के रूप में प्रतिशत

	बैलन्स-शीट के अनुसार		
	सन् १९४१	१९४३	१९४५
इम्पीरियल बैंक	६४	६३	५९
सेन्ट्रल बैंक	५१	५५	६१
बैंक आफ इण्डिया	४५	५७	५६
इलाहाबाद बैंक	४९	४९	४१
पंजाब नेशनल बैंक	५१	५१	६५
बैंक आफ बड़ोदा	४८	६०	५२

लागत की बसूली की दृष्टि से सरकारी साख-पत्रों में लागत लगाना बहुत ही अच्छा है, किन्तु व्यापार की सहायता करने की दृष्टि से तो यह उतना अच्छा नहीं है। अतः, इन बैंकों को इसमें से रुपया खींच कर व्यापारियों को देना चाहिये।

सम्मिलित पूँजी के भारतीय बैंक रुपयों को एक स्थान से दूसरे स्थानों को भेजने में भी बहुत सहायता पहुँचाते हैं तथा अन्य प्रकार से भी लोगों की सेवाये करते हैं। जहाँ तक रुपयों को एक स्थान से दूसरे स्थानों को भेजने का सम्बन्ध है इसके लिये वे बड़ी ऊँची दर चार्ज करते हैं और विशेषतः उन स्थानों में जहाँ उनकी प्रतियोगिता करने वाले दूसरे बैंक नहीं हैं। अतः, उन्हें इसे कम करना चाहिये।

इनका भविष्य

इस देश में सम्मिलित पूँजी वाले बैंकों का भविष्य बहुत कुछ यहाँ की सरकार की भविष्य में सरकारी और गैरसरकारी औद्योगिक योजनाओं के प्रति जो नीति होगी उस पर निर्धारित रहेगा। वैसे तो लोग स्वतन्त्रता मिल जाने पर भी बहुत उत्साहित नहीं हैं। साम्प्रदायिक और जातीय स्थिति के विगड़ जाने के कारण भविष्य पर उन का कोई विश्वास नहीं रह गया है। फिर, लड़ाई चाहे न हो किन्तु उसके बादल तो घिरे ही हुये हैं। छोटी-मोटी लड़ाइयाँ चल भी रही

हैं। घूसखोरी और अनाचार व्यापार तथा औद्योगीकरण के रास्ते में खड़े हैं। प्रथम युद्ध के बाद बहुत से बैंक फेल हुये थे; अतः, इसी बात की आशंका इस बार भी है। जब-जब कोई बैंक अथवा बैंक की शाख किसी नये स्थान में खुलती थी तब-तब वहाँ के लोग उसे सन्देह की दृष्टि से देखते थे। यहाँ पर अब तक बैंकिंग की प्रत्येक तेजी के बाद उसकी मन्दी आयी है। किन्तु शायद इस बार ऐसा न हो। प्रथम तो जितने बैंक युद्धकाल में स्थापित हुये हैं उनमें से अधिकांश गयेष्ट पूँजी के साथ हुये हैं। हमें ज्ञात है कि सन् १९३६ के भारतीय कम्पनी विधान की (४) धारा के अनुसार जैसा कि इस पुस्तक में पहिले भी कहा जा चुका है कोई भी बैंक यहाँ पर ५०,००० रु० से कम पूँजी से स्थापित ही नहीं हो सकता था। फिर भारत के सुरक्षा सम्बन्धी नियमों के (९४ अ) नियम के अनुसार १७ मई सन् १९४३ को जो पूँजी निकालने के नियन्त्रण का आर्डिनेंस निकाला गया था उसने ऐसी कम्पनियों की-संस्थापना को रोक दिया था जिनके युद्ध के बाद चलने की कोई सम्भावना नहीं दिखाई पड़ती थी। अतः, तब से किसी भी नये बैंक के खुलने के पहिले सरकार की आज्ञा प्राप्त करने के लिये एक आवेदन-पत्र देना पड़ता है और सरकार उस पर रिजर्व बैंक की सम्मति लेकर अपनी अनुमति देती है। दूसरे, पहिले से स्थापित बैंकों ने भी अपनी पूँजी, इत्यादि बढ़ाकर अपनी स्थिति दृढ़ कर ली है। तीसरे, अब रिजर्व बैंक का भी सहायक हाथ है। सदस्य बैंकों के साथ तो इसका सम्बन्ध इधर युद्धकाल में और भी दृढ़ हो गया है। यहाँ की बैंकिंग प्रणाली के ऊपर सरकार का भी नियन्त्रण अब बहुत बढ़ गया है। चौथे, जैसा कि हम पहिले भी देख चुके हैं, बैंकों की नकद स्थिति भी अच्छी हो गई है। ये रिजर्व बैंक के पास जो कोप रखते हैं वह प्रायः न्यूनतम से अधिक रहता है। गैरसदस्य बैंकों की भी नकद स्थिति बहुत अच्छी है। अन्तिम बात यह है कि अब इन्हे उन्नति करने का बहुत अवसर मिलेगा, विशेषतः इसलिये कि भविष्य में हमारी राष्ट्रीय सरकार इनकी सहायता ही करेगी न कि इनके रास्ते में जैसा कि विदेशी सरकार पहिले किया करती थी रोड़े अटकायेगी।

ऊपर जो बातें कही गई हैं उनका प्रमाण भी अभी हाल ही में मिल चुका है। नवम्बर सन् १९४६ में बंगाल के कुछ छोटे-छोटे बैंकों

के कठिनाई में पड़ जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। किन्तु सभी के लिये यह बहुत ही प्रशंसा की बात हुई कि सकट टल गया और उससे किसी की भी हानि नहीं हुई। प्रथम तो रिजर्व बैंक ने और भारत सरकार ने व्यर्थ की बातों का खण्डन किया। दूसरे, रिजर्व बैंक ने सब बैंकों से उनके सरकारी साख-पत्रों को खरीद करके उन्हें रुपया देने की घोषणा कर दी। इसका बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा और स्थिति शीघ्र ही सम्भल गई। हाँ, कुछ गैरसरकारी बैंकों को कठिनाई उठानी पड़ी जो केवल इसलिये थी कि उनकी व्यवस्था खराब थी, उन्होंने व्यर्थ के लिये बहुत सी शाखाएँ खोल ली थीं, उन्होंने ऋण भी बिना समझे वृद्धि दे रखे थे, वे स्टाक एक्सचेंजों में सट्टेवाजी करते थे और उनके यहाँ विशेष शिक्षित कर्मचारी नहीं थे। ऐसे बैंक सचमुच हमारी बैंकिंग-प्रणाली के लिये बहुत ही शर्म की बात हैं। अतः, उन्हें आपस में अथवा बड़े-बड़े बैंकों से मिलकर अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाना चाहिये। अपनी सरकार हो जाने से हमें भविष्य पर विश्वास करना चाहिये।

उन्नति के लिये क्षेत्र

इन बैंकों की शाखाएँ लगभग १५०० शहरों में हैं। इसके यह अर्थ है कि लगभग १००० शहरों में अब भी कोई आधुनिक बैंक नहीं है। किन्तु वे व्यापार की दृष्टि से किसी महत्व के नहीं हैं। अतः, उन्हें इस समय छोड़ा जा सकता है। इस समय जो आवश्यकता है वह वर्तमान बैंकों के और उनकी शाखाओं के ठोस बनाने की है। हम जानते हैं कि इंग्लैण्ड में उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त में और इस शताब्दी के आरम्भ में यही किया गया था। वहाँ के केवल १६ बैंकों की तुलना में हमारे देश में कई सौ बैंक हैं। छोटे बैंकों को परस्पर अथवा बड़े बैंकों से मिल जाना चाहिये। कुछ शहरों में तो बैंकों की बहुत बड़ी संख्या है। उदाहरणार्थ कलकत्ते में ३८८, बम्बई में १८३, लाहौर में ९५, मद्रास में ८५, दिल्ली में ८०, अहमदाबाद में ५२, ढाका में ४७, कोयंबटूर और अमृतसर में से प्रत्येक में ४२, त्रिच-नापली में ३५। इसमें शक नहीं कि कहीं-कहीं तो वहाँ के व्यवसाय को देखते हुये इन शाखाओं की संख्या उचित जान पड़ती है। किन्तु प्रायः यह एकीकरण के द्वारा घटाई जा सकती है। इससे न केवल

प्रतियोगिता कम हो जायगी वस्तु व्यवसाय के अनुपात में खर्च भी घट जायगा। भविष्य में जितना जनता के हित में उतना ही इन बैंकों के हित में भी यह आवश्यक है कि इनमें व्यवसाय की खींच-तानी, नई शाखाओं की अनुचित संस्थापना और जमा के व्याज की दर में प्रतियोगिता बन्द हो जाय और यह तभी हो सकता है जब इनमें पारस्परिक एकीकरण हो। इनके गलाकाट-प्रतियोगिता के स्थान पर पारस्परिक सम्मिलन की नीति अपनाने से सभी को लाभ होगा। जैसा कि हम देख चुके हैं कुछ बैंक माँग पर देय जमा पर भी व्याज देते हैं। इसे रोकना चाहिये। कुछ लोग यह समझते हैं कि जमा ग्राप्ति के लिये व्याज देना जरूरी है। किन्तु ऐसा नहीं है। जरूरी तो यह है कि बैंक विश्वासपात्र बने। वैकिंग की आदत काफी बढ़ गई है। बहुत से लोगों ने सरकारी सुरक्षा के और बचत के प्रमाण-पत्रों में रुपये जमा कर अथवा लगा रखे हैं। वे सब बैंकों के सम्भावित ग्राहक हैं। अतः, वैकिंग की उन्नति के लिये बहुत बड़ा क्षेत्र है। बैंकों को ऋण और बिल डिस्काउंटिंग के सम्बन्ध में भी कुछ अधिक उदारता की नीति अपनानी चाहिये। जैसा कि पहिले भी कहा जा चुका है उनके रहने से तभी लाभ हो सकता है जब वह व्यापार और उद्योग-धन्धों में रुपया लगावे न कि केवल सरकारी साख-पत्रों को ही खरीद कर रखे। युद्धकाल में उन्होंने सरकारी साख-पत्रों में बहुत रुपया लगा दिया है। रिज़र्व बैंक जैसे जैसे उन्हें व्यापार और उद्योग-धन्धों की सहायता करने के लिये रुपयों की आवश्यकता पड़े वैसे वैसे इन्हें खरीद कर उन्हें इनसे मुक्त कर सकता है। किन्तु यह तभी सम्भव है जब युद्धोत्तर काल की योजनाओं को कार्यरूप में परिणत किया जाय। वे लागत लगाने वालों और उद्योग-धन्धों के बीच में मध्यस्थ का कार्य भी कर सकते हैं। उन्हें पहिले तो उद्योग-धन्धों की कम्पनियों के हिस्सों को खरीद लेना चाहिये और फिर उन्हें लागत लगाने वाले लोगों के हाथ बेच देना चाहिये। वे अवश्य ही ऐसा कर सकते हैं। उनके पास, विशेषतः इम्पीरियल बैंक और सात बड़े बैंकों के पास अच्छी पूँजी भी है। यदि हम इनके और औद्योगिक कम्पनियों के सञ्चालक मण्डल की ओर दृष्टि डालें तो हमें ज्ञात होगा कि बहुत से संचालक तो दोनों में एक ही हैं। अतः, उन्हें उद्योग-धन्धों का अनुभव भी है और इससे वे नये उद्योग-धन्धों की

सम्भावनाओं पर भी अपनी सम्मति दे सकेंगे। इससे उन उद्योग-धन्धों की संस्थापना भी रुक जायगी जिनकी सफलता के लिये कोई आशा नहीं की जा सकती है। बैंकों के द्वारा पास किये हुये धन्धों के हिस्से और ऋण-पत्र बड़े प्रिय हो सकेंगे और उन्हें जनता हाथों-हाथ ले लेगी। और यदि उन्हें पहिले इन्हे लेना भी पड़ेगा तो बाद में वे इन्हे जनता के हाथों बेच भी सकेंगे।

कठिनाइयाँ और दोष

भारतीय बैंक अनेकों कठिनाइयों और दोषों के होते हुये भी काम कर रहे हैं। अतः, यदि यह दूर हो जायें तो इनकी उन्नति हो सकती है।

(१) विदेशी सरकार और उसके अफसर भारतीय बैंकों को अपना काम नहीं देते थे। उनका सम्बन्ध इम्पीरियल बैंक तथा विदेशी बैंकों से रहता था। ऐसी आशा की जाती है कि हमारी राष्ट्रीय सरकार उन्हें काम देगी और सबों को देगी न कि केवल इम्पीरियल बैंक को।

(२) इन्हे बड़े-बड़े शहरों में विदेशी बैंकों की प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। अतः, वहाँ पर इनकी हानि ही होती है। केवल छोटे शहरों में ही जहाँ उनकी शाखाएँ नहीं हैं इनका व्यवसाय अधिक चलता है और लाभ प्राप्त होता है। इधर बड़े-बड़े शहरों की शाखाएँ वहाँ की अपनी हानि को पूरी करने के उद्देश्य से छोटे-छोटे शहरों में भी अपनी उपशाखाएँ खोलने लग गये हैं।

(३) अधिकांश उद्योग-धन्धे और व्यापार, विशेषतः विदेशी व्यापार, विदेशियों के आविपत्य में हैं। अतः, वे इस देश में अपने-अपने देशों के बैंकों की शाखाओं से ही सम्बन्ध रखना अधिक पसन्द करते हैं।

(४) बहुत से भारतीय व्यापारी भी विदेशी बैंकों ही में अपने हिसाब रखते हैं। वात यह है कि उनमें देश प्रेम का अभाव है। अन्य देशों में यह प्रेम बड़ा काम करता है।

(५) इम्पीरियल बैंक पहिले तो देश के मुख्य बैंक की हैसियत से और अब केन्द्रीय बैंक के एक मात्र अङ्गितिये की हैसियत से अन्य

बैंकों से बड़ी आसानी से प्रतियोगिता कर लेता है। अतः, उन्हें इसके सामने कठिनाई पड़ती है।

(६) इनके बारम्बार फेल होने के कारण इनमें विश्वास भी नहीं जम पाता है।

(७) कुछ वैधानिक बन्धनों के कारण बैंकों को अपने ऋण की वसूली में भी बहुत कठिनाइयाँ पड़ती हैं। कुछ उत्तराधिकार के नियम ऐसे हैं कि दूर-दूर के रिश्तेदार भी सम्पत्ति पर अधिकार पाते हैं; अतः, प्रायः ऐसा होता है कि जिस सम्पत्ति को बैंक जमानत के तौर पर लेता है उस पर बाद में उसको पूर्ण अधिकार नहीं मिल पाता; उसके लिये दूरी रिश्तेदार खड़े हो जाते हैं।

(८) सादे रेहन—रेहननामा लिखे बिना अथवा रजिस्ट्री कराये बिना केवल अधिकार पत्रों को दे देने से जो रेहन होता है उसके कुछ ही स्थानों में नियमित होने के कारण अन्य स्थानों में रजिस्ट्री करा के रेहन कराना पड़ता है। अतः, उसके सुविधाजनक न होने के कारण उस पर ऋण नहीं दिया जाता। इससे बैंकों का काम कम होता है।

(९) विलों की कमी होने के कारण और उनके बैंकों द्वारा स्वीकृत किये जाने की प्रथा न होने के कारण बैंकों को अपनी रकम अधिकांश में सरकारी साख-पत्रों में लगानी पड़ती है। यह अच्छी बात नहीं है। उनका होना तो तभी सार्थक हो सकता है जब वह व्यापार और उद्योग धन्धों की सहायता करें न कि सरकारी साख-पत्रों में लागत लगायें।

(१०) यहाँ बैंकों को अपने जमानत पर दिये हुये और बिना जमानत के दिये हुये ऋणों को बैलन्स-शीट में पृथक-पृथक दिखाना पड़ता है। फिर यहाँ पर इंगलिस्तान के सीड्स की तरह की और अमेरिका के दूनस और ब्रैड स्ट्रीट्स की तरह की सस्थाये नहीं हैं जो ऋण माँगने वालों की आर्थिक स्थिति के विषय में बतला सकें। अतः, यहाँ के बैंक पश्चिमीय देशों के बैंकों की तरह वैयक्तिक जमानतों पर ऋण नहीं दे पाते हैं।

(११) सभी बैंक अपना काम अंग्रेजी में करते हैं। सिर्फ कुछ ही यहाँ की भाषाओं में लिखी हुई चेकों और हस्ताक्षरों को ठीक मानते हैं। अतः, देश में अंग्रेजी जानने वाले लोगों की संख्या कम होने के कारण बैंकिङ्ग की प्रथा नहीं बढ़ पाती।

(१२) भारतीय बैंक अंग्रेजी बैंकों की तरह पर बने हुये हैं । वहुतों के खर्च बहुत बढ़े हुये हैं । उन्होंने अंग्रेजी बैंकों की कार्य कुशलता के साथ-साथ यहाँ के महाजनों की सादगी और मितव्ययता का मिश्रण नहीं किया है ।

(१३) प्रायः भोली-भाली जनता को वेवकूफ बनाने की दृष्टि से बैंकों के सञ्चालक मण्डलों में राजनैतिक और सामाजिक नेताओं को रख लिया जाता है । किन्तु एक तो न ये बैंकिंग के व्यवसाय को समझते ही हैं और न इनके पास समय ही रहता है । अतः, ऐसे बैंकों का कार्य सुचारु रूप से नहीं चलता ।

(१४) कुछ दिनों पहिले तक भारतीय बैंकों के अपने संगठन नहीं थे । इसका स्वाभाविक फल यह था कि उनमें पारस्परिक ईर्ष्या रहती थी और सहयोग का लेशमात्र भी नाम नहीं मिलता था । इधर भारतीय बैंकों का संगठन बन गया है ।

(१५) कुछ विदेशी बैंकों के बड़े-बड़े कर्मचारी प्रायः भारतीय बैंकों को बदनाम करते रहते हैं । इससे सेन्ट्रल बैंक की बड़ी हानि हुई है, किन्तु वह उन्नति करता ही जा रहा है ।

(१६) बैंकिंग शास्त्र के विशेषज्ञों की कमी है । अतः, साधारण लोग ही इस काम के लिये रखे जाते हैं । इधर बैंकों में अभ्यनुवी लोगों को रखने की काफी होड़ रही है जिससे बैंकों के कर्मचारी इधर से उधर चले जाते हैं ।

(१७) बैंकों की और उनकी शाखाओं की संख्या इधर बढ़ती रही है । अतः, उनके एकीकरण और सुदृढ़ होने की आवश्यकता है । हमारे बैंकों का और विशेषतः गैरसदस्य बैंकों का औसत डील-डौल बहुत छोटा है । अतः, उन्हें परस्पर अथवा बड़े-बड़े बैंकों से मिल जाना चाहिये ।

अतः, उपर्युक्त कठिनाइयों और दोषों को दूर करने के लिये निम्न बातें की जा सकती हैं—

(१) जैसा कि पहिले भी कहा जा चुका है देश की सरकार को सब भारतीय बैंकों को अपनाना चाहिये; केवल इम्पीरियल बैंक को ही नहीं । इसने इन बैंकों के ऊपर सुरक्षा के विचार से कुछ प्रतिबन्ध लगा दिये हैं । इनके साथ-साथ इन्हें कुछ रियायतें भी देनी चाहिये और उनमें सबसे महत्वपूर्ण रियायत यही है कि सरकार को

इन्हें अपनाना चाहिये। उसे सारे भुगतान चेकों से ही करने चाहिये और उसके नियन्त्रण में जितनी संस्थायें हैं उन सबों को भी ऐसा करने के लिये बाध्य करना चाहिये।

(२) विदेशी बैंकों के खुलने और काम करने पर प्रतिबन्ध लगा देने चाहिये। उन्हें देश के भीतरी शहरों में शाखाएँ खोलने की आज्ञा नहीं प्रदान करनी चाहिये और परिमित जमा से अधिक जमा भी नहीं लेने देनी चाहिये। इस बात के लिये भी व्यवस्था कर देना चाहिये कि उनके और भारतीय बैंकों के बीच में प्रतियोगिता न हो।

(३) इम्पीरियल बैंकों के अपरिमित साधनों के साथ भारतीय बैंकों से होड़ न करके अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को आर्थिक सहायता पहुँचाने का काम अपने हाथ में लेना चाहिये।

(४) अधिकतर शहरों में सादे रेहन की आज्ञा दे देनी चाहिये। बात यह है कि यह बैंकों के लिये बहुत ही सुविधाजनक हैं।

(५) डिस्काउण्टिंग को अधिक प्रिय बनाने के उद्देश्य से बिलों और हुण्डियों के प्रयोग को बढ़ाना चाहिये। ऐसा करने के लिये कुछ बातें करनी पड़ेंगी जिनका अध्ययन हम आगे चल कर करेंगे।

(६) बैंकों को वैयक्तिक ऋण अधिक देने चाहियें। ऐसा तभी किया जा सकता है जब वाज्जार के लोगों से अधिक सम्बन्ध बढ़ाया जाय और इसके लिये बैंक प्रबन्धकों को उसी स्थान का होना चाहिये न कि बाहर का। यह प्रायः देखा गया है कि स्थानीय प्रबन्धक बाहरी प्रबन्धकों की अपेक्षा अधिक व्यवसाय बढ़ा लेते हैं।

(७) बैंकों को उन्हीं भापाओं में काम करना चाहिये जिन्हें उनके ग्राहक जानते हैं। इससे उन्हें काम करने में सुविधा पड़ेगी और काम भी अधिक मिलेगा।

(८) उन्हें देशी महाजनों की सादगी और मितव्ययता का अनुकरण करना चाहिये। जैसा कि पहिले भी कहा जा चुका है उन्हें इनके साथ 'कमाण्डिट' सिद्धान्त पर साम्ना कर लेना चाहिये। उन्हें अपने नियमों के पालन पर भी बहुत कड़ाई नहीं करनी चाहिये। भारतीय बैंक चेकों के भुगतान करने में जो देर लगाते हैं वह तो सभी जानते हैं। ग्राहकों को किसी भी बैंक से किसी भी चेक का भुगतान लेने में बड़ा समय गँवाना पड़ता है।

(९) जो लोग बैंकिंग के सिद्धान्त को समझते हैं और उसके काम को देख-भाल सकते हैं केवल उन्हीं को बैंकों के संचालक मंडलों में लेना चाहिये । बैंकों के लिये केवल बड़े-बड़े नामों का ही आकर्षण नहीं होना चाहिये ।

(१०) अभी हाल में ही जो भारतीय बैंकिंग संघ बना है उसका प्रत्येक भारतीय बैंक को सदस्य बन जाना चाहिये ।

(११) रिजर्व बैंक की आवश्यकता पड़ने पर उन सभी बैंकों की किसी हिचकिचाहट के बिना सब प्रकार से सहायता करनी चाहिये जो सहायता पाने के योग्य है । इससे उसके ऊपर उनका विश्वास बढ़ जायेगा ।

(१२) बैंकों को विश्वविद्यालयों के स्नातकों को लेकर उन्हें विशेष शिक्षा देनी चाहिये । बैंकिंग के उन्नति के लिये ऐसा कोई काम करना बहुत ही आवश्यक है । बैंकिंग के योग्यता वाले कामर्स के स्नातक है । वे भी बड़ा काम कर सकते हैं ।

(१३) उन्हें अंग्रेजी बैंकों की तरह परस्पर एकीकरण कर लेना चाहिये ।

सम्मिलित पूँजी के मुख्य-मुख्य भारतीय बैंक सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया

सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया की संस्थापना सन् १९११ में हुई थी । इसका श्रेय मुख्यतः सोराबजी पुचकनवाला को था । वह बड़े ही योग्य व्यक्ति थे और आजीवन कम्पनी के मैनेजिङ्ग डाइरेक्टर रहे । सन् १९३८ में उनकी मृत्यु हो जाने से भारतीय बैंकिंग को साधारणतः और सेन्ट्रल बैंक को मुख्यतः बड़ा धक्का लगा । यह बैंक प्रत्येक दृष्टि से, चाहे पूँजी और सुरक्षित कोष को, अथवा जमा को अपनी शाखाओं की सख्या को अथवा बैंकिंग के व्यवसाय के किसी काम को ले लिया जाय सम्मिलित पूँजी के सब भारतीय बैंकों में प्रमुख है । सन् १९२३ इसके लिये विशेष महत्व का था । उस वर्ष इसने टाटा इण्डस्ट्रियल बैंक को अपने में सम्मिलित कर लिया था जिससे इसकी पूँजी और इसका सुरक्षित कोष मिलाकर ८० लाख रु० से २६८ लाख रु० हो गया, जमा १४ करोड़ रु० से १८ करोड़ रु० हो गई और पूँजी और सुरक्षित कोष मिलाकर जमा का ५.७ प्रतिशत से १७.१८ प्रति-

शत हो गया। बैंक ने प्रथम महायुद्ध के प्रारम्भ काल में अपनी पहिली शाख कराँची में खोली थी। युद्ध समाप्त होते-होते इनकी संख्या पाँच हो गई। सन् १९३४ में इसके दफ्तरों की संख्या ६८ थी, सन् १९३७ में यह ८९ हो गई, सन् १९३८ में यह १०१ थी, सन् १९४० में यह १३२ थी, सन् १९४३ में यह २१७ थी और सन् १९४५ में यह ३०८ थी। किसी भी भारतीय बैंक ने इतनी कठिनाइयों का सामना नहीं किया जितनी इस बैंक को करनी पड़ी है। इसकी संस्थापना के प्रथम २० वर्षों के अन्दर ही इसके ऊपर नौ आक्रमण हुये थे जिसे इसने सफलतापूर्वक सँभाला।

यह बैंक इम्पीरियल बैंक की तरह सभी प्रान्तों में है। स्थायी और अस्थायी जमा पर यह जो व्याज देता है उसकी दर अन्य बैंकों की दरों की अपेक्षाकृत कम है। सन् १९२१ से यह चालू खातों और स्थायी खातों पर दिये गये व्याज की रकम पृथक-पृथक दिखलाता है। पहिले तो स्थायी जमा पर चालू जमा से २-३ प्रतिशत व्याज अधिक दिया जाता था और फिर यह अन्तर केवल १-३-२ प्रतिशत का रह गया था। इस तरह से उपर्युक्त व्याज की दरों में कम अन्तर हो जाने से चालू खातों और बचत खातों में कुल जमा की तुलना में अधिक रकम जमा रहने लगी।

बैंक आफ इण्डिया

बैंक आफ इण्डिया सन् १९०६ में संस्थापित हुआ था। तब से इसने बड़ी उन्नति की है। अपने साधनों की दृष्टि से इस समय इसका यहाँ के सम्मिलित पूँजी के बैंकों में दूसरा स्थान है। इस बैंक पर कभी भी आक्रमण नहीं हुये। इसने बढ़ने में भी बहुत सावधानी से काम लिया है। इसकी संस्थापना से २० वर्षों तक इसकी कोई भी शाख नहीं थी। सन् १९४५ में इसके दफ्तरों की संख्या ३० थी जिनमें से ६ बम्बई में थे, ३ कलकत्ते में थे, ४ अहमदाबाद में थे, नागपुर और पूना में दो-दो थे और अन्धेरी, बन्द्रा, जमशेदपुर, राजकोट, अमृतसर, भुज (कच्छ), जूनागढ, कराँची, मद्रास, पालनपोवरावल और सूरत में एक-एक थे, इसे तरह से यह एक प्रकार से केवल बम्बई अहाते का ही बैंक है। इसने सन् १९२१ में भारतवर्ष से बाहर भी मोम्बासा में अपनी एक शाख खोलने का साहस किया था किन्तु वह दो ही वर्षों

बाद बन्द कर देनी पड़ी। यह अपने जमा के दायित्व के अनुपात में काफी पूँजी और सुरक्षित कोष रखता है।

यह जमा प्राप्त करने के लिये व्याज की दर ऊँची नहीं करता। इसकी लागत द्रवित और सुरक्षित है। इसने सन् १९०७ में ५ प्रतिशत लाभ की वॉटनी की थी और इसे धीरे-धीरे बढ़ाता रहा। सन् १९४५ में इसके लाभ की वॉटनी २२ प्रतिशत थी।

इलाहाबाद बैंक

सम्मिलित पूँजी के भारतीय बैंकों में से इलाहाबाद बैंक सबसे पुराना है। यह सन् १८६५ में इलाहाबाद में स्थापित किया गया था। सन् १९२२ में पी० एण्ड ओ० बैंकिंग कारपोरेशन ने इसे अपने में शोषण करने का प्रस्ताव रक्खा जिसे इसके हिस्सेदारों ने स्वीकार कर लिया। पी० एण्ड ओ० ने इसके १००-१०० रु० के हिस्सों के लिये जिनका पूरा मूल्य दिया जा चुका था ४३६ रु० दिये। इसके स्वामित्व के बदल जाने के साथ-साथ ही इसका प्रधान दफ्तर भी इलाहाबाद से कलकत्ते भेज दिया गया। सन् १९२७ में चार्टर्ड बैंक आफ इण्डिया, आस्ट्रेलिया एण्ड चाइना ने पी० एण्ड ओ० से इसके अधिकांश हिस्से खरीद लिये जिससे फिर इसका स्वामित्व बदल गया।

इस बैंक ने भी बड़ी सावधानी से चलने की नीति बरती है। इसकी पहिली शाख कानपुर में सन् १८८८ में खुली थी। सन् १९१७ में इसके दफ्तरों की संख्या केवल १२ थी। इसके बाद की; इसकी वृद्धि अवश्य कुछ तेज रही है। सन् १९४५ में इसके दफ्तरों की संख्या ७५ थी। नकद में जमा का अनुपात इसके यहाँ काफी रहता है। इसके अतिरिक्त इसकी लागत भी बहुत द्रवित रूप में रहती है। अधिकांश रुपया सरकारी साख-पत्रों में लगा रहता है। रक्षा के विचार से तो यह नीति अवश्य अच्छी है किन्तु देश के व्यापार, उद्योग-धन्धों और व्यवसाय को प्रोत्साहन देने के विचार से यह नीति अच्छी नहीं है।

अपने साधनों की दृष्टि से इसका स्थान यहाँ के सम्मिलित पूँजी के बैंकों में तीसरा है। यह अधिकतर सयुक्त प्रान्त और पंजाब में काम करता है। इसके लाभ की वॉटनी इधर १६ प्रतिशत के हिसाब से होती रही है।

पंजाब नेशनल बैंक

पंजाब नेशनल बैंक की रजिस्ट्री सन् १८९५ में हुई थी। यह बैंक सेन्ट्रल बैंक ही की तरह भारतीय प्रबन्धकों के ही हाथ में है। सन् १९४५ में इसके कुल मिलाकर १९७ दफ्तर थे और इनमें से अधिकांश पंजाब ही में थे। देश के विभाजन के साथ-साथ पश्चिमी पंजाब में जो दंगे हुये हैं उनसे इसकी बड़ी हानि हुई है। किन्तु इसके प्रबन्धकों ने बड़ी सावधानी से काम लिया था। उन्होंने इसका प्रधान कार्यालय तो पहिले से ही लाहौर से हटाकर दिल्ली भेज दिया था। इसके अतिरिक्त इसने पंजाब में ऋण भी कम दे रक्खा था। साधनों की दृष्टि से यहाँ के सम्मिलित पूँजी वाले बैंकों में इसका स्थान चौथा है। अन्य भारतीय बैंकों की तरह इसके ऊपर भी बड़े आक्रमण हुये हैं किन्तु इसने उन्हें भली-भाँति सँभाला है।

जमा प्राप्त करने के लिये यह ऊँची दर का ब्याज नहीं देता। किन्तु इतने पर भी अन्य बैंकों की अपेक्षाकृत इसके लाभ की दर बहुत ही कम रहती है। बात यह है कि इसके साधन प्रति शाख कम हैं—इसके यहाँ जमा तो कम है और इसकी शाखाओं की संख्या अधिक है।

बैंक आफ बड़ोदा

बैंक आफ बड़ोदा सन् १९०९ में स्थापित हुआ था। इसकी पहिली शाख सन् १९१९ में खोली गई थी। सन् १९४५ में इसके कुल दफ्तरों की संख्या ३३ थी और उनमें से अधिकांश काठियावाड़ और गुजरात में थे। यह नकद का अनुपात बहुत अधिक रखता है—प्रायः यह १५ प्रतिशत रहता है। साधनों की दृष्टि से यहाँ के सम्मिलित पूँजी के बैंकों के बीच में इसका पाँचवा स्थान है। इसके ग्रास लाभ (Gross Profit) की दर बहुत कम है। बात यह है कि जिस क्षेत्र में यह काम करता है उसमें द्रव्य बहुत है। अतः, बैंकों और महाजनों में परस्पर बड़ी प्रतियोगिता रहती है जिससे ऋण पर कम ब्याज मिलता है।

भारत बैंक

भारत बैंक की रजिस्ट्री सन् १९४२ में हुई थी। अतः, अन्य बड़े बैंकों के आगे यह अभी बच्चा ही है। किन्तु उसकी पूँजी उनमें

सबसे अधिक है। यह २ करोड ६० से भी ऊँची है। इसके दफ्तरों की संख्या भी बहुत है। सन् १९४५ में यह २१४ थी। इसके पास जमा भी अच्छी है। इस समय यहाँ के बैंकों के बीच में इसका स्थान छठा है। इसने अच्छे-अच्छे बैंकों को पछाड़ दिया है। इसकी संस्थापना के पहिले इण्डियन बैंक और मैसूर बैंक का स्थान क्रमशः छठा और सातवाँ था। इस प्रकार चलने से भविष्य में शायद यह पाँचों बड़े बैंकों में से कुछ और को पछाड़ दे और उनका स्थान ले ले।

यूनाइटेड कमर्शियल बैंक

यूनाइटेड कमर्शियल बैंक सन् १९४४ में स्थापित किया गया था। इसकी पूँजी भी सेन्ट्रल बैंक को छोड़कर पाँचों बड़े बैंकों की पूँजी से अधिक थी। यह भी होनहार बैंक मालूम होता है। सन् १९४५ में इसके ६२ दफ्तर थे।

इण्डियन बैंक

इण्डियन बैंक का स्थान यहाँ के बैंकों में छठा था। किन्तु अब यह स्थान भारत बैंक ने ले लिया है। इसकी रजिस्ट्री सन् १९०७ में हुई थी। यह अब भी दक्षिणी भारत का सबसे बड़ा बैंक है। इसका प्रधान दफ्तर मद्रास में है और इसके सब दफ्तरों की संख्या सन् १९४५ में ६३ थी। इसके अधिकांश दफ्तर सन् १९३५ के बाद खोले गये हैं। इसके अधिकांश हिस्से नट्टूकोटाई चट्टियों के हाथ में हैं। अतः, इसे उन्ही का बैंक कहा जा सकता है। अधिकांश ऋण भी उन्ही लोगों को दिया जाता है। चट्टी लोग स्वयं महाजन हैं और बैंक तथा ऋण लेने वालों के बीच में मध्यस्थ का कार्य करते हैं। यह बैंक इनके वैयक्तिक दायित्व पर ऋण देना अधिक पसन्द करता है। माल की जमानत से यह इसी जमानत को अच्छी जमानत समझता है। यही कारण है कि यह सरकारी साख-पत्रों में भी अधिक रकम नहीं लगाता। इसकी अधिकांश लागत ऋण के रूप में है। इससे इसकी कभी कोई विशेष हानि भी नहीं हुई है। दूसरे बैंक इससे इस बात का सबक सीख सकते हैं। वे भी देशी महाजनों को मध्यस्थ बनाकर काम कर सकते हैं।

बैंक आफ मैसूर

बैंक आफ मैसूर सन् १९१२ में स्थापित हुआ था। यद्यपि इसके

साधन बहुत बड़े हैं किन्तु इसको रिजर्व बैंक की तालिका में केवल सन् १९४३ में ही सम्मिलित किया गया था। इसके पहिले शायद ऐसा इसलिये नहीं हुआ था कि इसकी ब्रिटिश भारत में कोई शाख नहीं थी। इधर कई वर्षों से यह १४ प्रतिशत लाभ की वट्टनी करता आ रहा है।

अन्य बैंक

कुछ अन्य बैंक भी बड़े महत्वपूर्ण हैं, जैसे कोमिला बैंकिंग कारपोरेशन, कोमिला यूनियन बैंक, बैंक आफ जैपुर, डिस्काउण्ट बैंक आफ इण्डिया, एक्सचेंज बैंक आफ इण्डिया एण्ड अफ्रीका, हबीब बैंक, हिन्दुस्थान कमर्शियल बैंक, पञ्जाब एण्ड सिन्ध बैंक, ट्रेडर्स बैंक और यूनियन बैंक।

सदस्य बैंकों के दायित्व

यह त पहिले ही बताया जा चुका है कि कौन से बैंक सदस्य बैंक बन सकते हैं। इनके कुछ दायित्व होते हैं। प्रथम तो प्रत्येक सदस्य बैंक को रिजर्व बैंक में अपनी चालू जमा का कम से कम ५ प्रतिशत और स्थायी जमा का २ प्रतिशत बैलन्स रखना पड़ता है। इसके लिये इसे रिजर्व बैंक के उस दफ्तर का नाम बताना पड़ता है जहाँ यह अपना मुख्य खाता रखेगा। सदस्य बैंक अपने हिसाब रिजर्व बैंक के उन सभी दफ्तरों में रख सकते हैं जो ऐसे स्थान में हों जहाँ उनके भी दफ्तर हैं। यदि किसी सदस्य बैंक का दफ्तर किसी ऐसे स्थान में नहीं है जहाँ रिजर्व बैंक के दफ्तर हैं तो वह रिजर्व बैंक के किसी दफ्तर में भी अपना हिसाब रख सकता है। दूसरे, सदस्य बैंकों को रिजर्व बैंक विधान की ४२ (२) धारा में जो फार्म दिया हुआ है उसी के अनुसार अपनी स्थिति की एक साप्ताहिक रिपोर्ट रिजर्व बैंक के पास और एक केन्द्रीय सरकार के पास भेजनी पड़ती है। जहाँ के लिये रिजर्व बैंक यह समझता है कि वहाँ की भौगोलिक स्थिति के कारण साप्ताहिक रिपोर्ट नहीं आ सकती, वहाँ पर वह मासिक रिपोर्ट ही मँगा सकता है। यह रिपोर्ट उसी दफ्तर को जाती है जहाँ मुख्य खाता रहता है। यदि यह रिपोर्ट समय पर नहीं भेजी जाती अथवा उपर्युक्त न्यूनतम बैलन्स रिजर्व बैंक के पास नहीं रक्खा जाता तो सजा दी जाती है। यदि रिपोर्ट नहीं भेजी जाती तो जितने दिनों की

देर होती है उतने दिनों तक १०० रु० प्रति दिन के हिसाब से जुर्माना लगता है। और यदि उपर्युक्त न्यूनतम वैलन्स नहीं रक्खा जाता तो एक सप्ताह तक तो जितना वैलन्स कम होता है उस पर वैक दर से ३ प्रतिशत अधिक व्याज लगता है और यदि वह दूसरी रिपोर्ट भेजने की तारीख के बाद भी कम रहना है तो वैक दर से ५ प्रतिशत अधिक का व्याज लगता है। यह दोनों जुर्माने माँगने पर उसी समय देने पड़ते हैं, और इन्हे वही दफ्तर माँगता है जिसमें उस सदस्य वैक का मुख्य खाता होता है। इस जुर्माने के न देने पर वह अदालत के द्वारा भी वसूल किया जा सकता है। कुछ वैक न्यूनतम वैलन्स न रख कर व्याज दे देते थे। अतः, इस बात को रोकने के लिये रिजर्व वैक के सन् १९४० के एक विधान से रिजर्व वैक को यह अधिकार दे दिया गया है कि वह अपराधी वैक को और अधिक जमा प्राप्त करने से रोक सकता है और उन कर्मचारियों को भी सजा दे सकता है जिनकी जानकारी में यह अपराध किया जाता है।

उनके अधिकार

सदस्यों वैकों को कुछ अधिकार भी प्राप्त हैं और उनमें से मुख्य यह है कि उन्हें अच्छे विलों की डिस्काउंटिंग के रूप में अथवा अच्छे साख-पत्रों की जमानत पर ऋण के रूप में रिजर्व वैक से आर्थिक सहायता भी प्राप्त हो सकती है। कौन से विल अच्छे हैं और कौन से साख-पत्र अच्छे हैं यह बात स्पष्ट रूप से रिजर्व वैक विधान की १७ वी-धारा में दी हुई है। रिजर्व वैक की ऋण देने की नीति और जिस प्रकार की आर्थिक सहायता वह सदस्य वैकों को दे सकता है वह सब उसके ७ दिसम्बर सन् १९३८ के एक स्मरण-पत्र में दिये हुये हैं। उन्हें यहाँ पर भी बता देना उचित ही होगा। 'संसार के अन्य देशों में जो नीति बरती जाती है उसी के अनुसार और इस देश में बैंकिंग का उचित ढङ्ग से विकास करने के उद्देश्य से सदस्य वैकों को उधार देने के समय रिजर्व वैक केवल उन साख-पत्रों पर ही ध्यान नहीं देगा जिनके आधार पर ऋण माँगा जा रहा है बल्कि इन बातों पर भी ध्यान देगा कि प्रार्थी वैक की लागते साधारणतः किस प्रकार की है, उसका व्यवसाय कैसे किया जाता है। उदाहरणार्थ वह जमा प्राप्त करने के लिये व्याज को बहुत ऊँची दर तो नहीं देता, जब बाजार में रुपये

की टान नहीं रहती तब वह रिज़र्व बैंक से उधार तो नहीं लेता, अपनी शक्ति से अधिक व्यवसाय तो नहीं करता और चीजों पर तथा साख-पत्रों पर सट्टे के लिये ऋण तो अधिक नहीं देता अथवा बिना जमा-नती काम तो बहुत नहीं करता। इस सम्बन्ध में इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये कि रिज़र्व बैंक केवल अल्पकालीन ऋण ही दे सकता है। फिर इस बात का विश्वास मिल जाने के लिये कि वह जो ऋण की सुविधा दे रहा है उसका दुरुपयोग तो न किया जायगा वह मनचाही कोई भी बात पूछ सकता है अथवा किसी प्रकार की कोई भी शर्त लगा सकता है और ऋण लेने वाले बैंक को यह बात बतानी पड़ेगी तथा शर्त पूरी करनी पड़ेगी। अन्तिम यह कि अन्य बैंकों की तरह रिज़र्व बैंक भी अपने विवेक के अनुसार कोई कारण बताये बिना ही किसी बैंक के बिलों को डिस्काउंट करने की अथवा उसे साख-पत्रों पर ऋण देने की मनाही कर सकता है। किन्तु यदि सदस्य बैंक उचित ढङ्ग पर काम करते हैं तो आवश्यकता पड़ने पर उचित जमानत पर उन्हें रिज़र्व बैंक से अवश्य ही अल्पकालीन आर्थिक सहायता मिल सकती है।'

उन्हे जो दूसरा अधिकार प्राप्त है वह रियायती दर पर इंधर से उधर रुपया भेजने के सम्बन्ध का है। रिज़र्व बैंक ने १ अक्टूबर सन् १९४० को रुपया भेजने की सुविधा नाम की जो योजना घोषित की थी उसके दूसरे परिशिष्ट के अनुसार कोई भी सदस्य बैंक रिज़र्व बैंक के किसी भी दफ्तर, शाख अथवा एजेंसी में उसके किसी भी दफ्तर, शाख, उपशाख, इत्यादि का जो खाता है उसके बीच में डाक से अथवा तार से ब्रिटिश भारत^१ और ब्रह्मा में निम्न प्रकार से रुपया भेज सकता है :—

(१) (अ) रिज़र्व बैंक के दफ्तर और शाख में उसके जो खाते हैं उनके बीच में कोई भी खर्च दिये बिना १०००० रु० अथवा उससे गुणित कोई भी रकम;

(ब) अपने किसी भी दफ्तर से अथवा शाख से अथवा उपशाख, इत्यादि से यदि वहाँ रिज़र्व बैंक की कोई एजेंसी है तो उसके द्वारा रिज़र्व बैंक के

अपने मुख्य खाते में सप्ताह में केवल एक बार
५००० रु० अथवा उससे गुणित कोई भी रकम
किसी भी खर्च के बिना।

(स) मुख्य खाते ही को कोई भी रकम एक पैसा रु०
सैकड़ा के खर्च पर किन्तु न्यूनतम खर्च १ रु०
से कम नहीं मिलना चाहिये।

(द) रिजर्व बैंक में अथवा उसकी एजन्सियों में जो
दूसरे खाते हों उनके बीच में।

५००० रु० तक १ आ० प्रतिशत व्यय पर
न्यूनतम व्यय १ रु०।

५००० रु० से ऊपर दो पैसा प्रतिशत व्यय पर
न्यूनतम व्यय ३ रु० २ आ०

(२) रिजर्व बैंक के खजानों के ऊपर अन्य व्यक्तियों के पत्र में
टी० टी० और ड्राफ्ट निम्न व्यय पर दिये जाते हैं :—

५००० रु० तक १ आ० प्रतिशत व्यय पर न्यूनतम
व्यय १ रु०।

५००० रु० से ऊपर दो पैसा प्रतिशत व्यय पर न्यूनतम
व्यय ३ रु० २ आ०

तार का व्यय इसके अतिरिक्त लिया जाता है।

गैरसदस्य बैंकों के दायित्व

वैसे तो सन् १९३६ के भारतीय कम्पनी विधान में जो नियम
दिये हुये हैं उनका पालन सभी बैंकों को करना पड़ता है। किन्तु
नियत रिपोर्ट देने और न्यूनतम बैलन्स रखने के सम्बन्ध में उनके
जो दायित्व हैं उन्हें हमें यहाँ पर विशेष रूप से समझ लेना चाहिये।
सदस्य बैंकों के इनके सम्बन्ध में जो दायित्व हैं उन्हें तो हम अभी
समझ ही चुके हैं। उन्हें अपनी रिपोर्ट रजिस्ट्रार के पास नहीं भेजनी
पड़ती और उन्हें न्यूनतम बैलन्स भी अपने पास न रखकर रिजर्व
बैंक के पास रखने पड़ते हैं। जहाँ तक गैरसदस्य बैंकों का सम्बन्ध
है, जो गैरसदस्य बैंक ब्रिटिश भारत^१ में काम नहीं करते उनके ऊपर
कोई भी प्रतिबन्ध नहीं है। जो गैरसदस्य बैंक ब्रिटिश भारत^१ में

^१भारत

काम करते हैं उनमें से भी जैसा कि पहिले कहा जा चुका है बहुत से सन् १९४३ के पहिले बैंक की परिभाषा में न आने के कारण किसी भी प्रतिबन्ध को नहीं मानते थे। किन्तु सन् १९४३ से जो सस्था भी 'बैंक' शब्द अपने नाम के साथ लगाती है उसी को इन प्रतिबन्धों को मानना पड़ता है। सन् १९४४ के अन्त में ६१४ बैंक अपनी रिपोर्टें भेजते थे। सन् १९३८ के पहिले तक तो ये रिपोर्टें प्रान्तीय रजिस्ट्रारों के पास भेजी जाती थी। किन्तु उस वर्ष के फरवरी महीने से प्रत्येक रजिस्ट्रार को इन सब रिपोर्टों की एक लिपि रिजर्व बैंक के पास भेजनी पड़ती है और बैंक रजिस्ट्रार के पास एक लिपि न भेजकर तीन लिपियाँ भेजते हैं। जैसा कि पहिले भी बताया जा चुका है वे अपने चालू जमा की और स्थायी जमा की कम से कम क्रमशः ५ प्रतिशत और १३ प्रतिशत नकदी अपने पास रखते हैं। यहाँ पर यह भी कह देना आवश्यक है कि इनकी रिपोर्टें मासिक होती हैं सदस्य बैंकों की तरह साप्ताहिक नहीं और वह प्रतिमास के अन्तिम शुक्रवार की होती हैं न कि प्रति सप्ताह के शुक्रवार की।

अधिकार

१ अक्टूबर, सन् १९४० से रिजर्व बैंक ने रुपया भेजने की जो योजना घोषित की है उसके तीसरे परिशिष्ट के अनुसार उन गैर-सदस्य बैंकों को जिनके नाम रिजर्व बैंक की स्वीकृत तालिका में दिये हुये हैं और जो उपयुक्त प्रान्तीय सरकारों की सम्मति से बनी है केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों द्वारा स्वीकृत रियायती दूरों पर रुपया भेजने का अधिकार दिया गया है। सन् १९४० के अन्त में ऐसे ७५ बैंक थे। जब कि जनता के लिये ५००० रु० तक भेजने के लिये १२ आ० प्रति सैकड़ा दर है और ५६०० से ऊपर के लिये १ आ० प्रति सैकड़ा दर है, तब इनके लिये यही क्रमशः १ आ० प्रतिशत और २ पैसा प्रतिशत हैं। न्यूनतम व्यय सभी के लिये कुछ न कुछ निर्धारित है। स्वीकृत तालिका में आने के लिये इन बैंकों को निम्न शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं :—

(अ) इन्हें भारतीय कम्पनी विधान के अनुसार रजिस्टर्ड कम्पनियाँ होना चाहिये।

(व) इन्हे भारतीय कम्पनी विधान मे दिये हुये नियमों के अनुसार ब्रिटिश भारत^१ मे व्यवसाय करना चाहिये ।

(स) इनकी पूँजी इनके कोष को मिलाकर कम से कम ५०००० रु० होनी चाहिये ।

गैरसदस्य बैंकों को अपने सम्बन्ध की सभी बातों पर रिजर्व बैंक की सम्मति भी प्राप्त हो सकती है ।

१५ फरवरी सन् १९४५ से कोई भी गैरसदस्य बैंक निम्न शर्तों के साथ रिजर्व बैंक के यहाँ अपना हिसाब भी खोल सकता है :—

(१) उसे अपने व्यवसाय के विस्तार के अनुसार कम से कम कुछ बैलन्स अवश्य रखना चाहिये और यह १०००० रु० से कम तो होना ही नहीं चाहिये ।

(२) यह खाता साधारण खाता नहीं है, अर्थात् इस पर चेकें नहीं काटी जा सकतीं । हाँ, इसे रुपया भेजने के लिये और बैंकों के अन्य पारस्परिक कामों के लिये प्रयोग में लाया जा सकता है ।

प्रश्न

(१) सन् १९३६ और सन् १९४४ के भारतीय कम्पनी विधान मे बैंकिंग कम्पनियों के सम्बन्ध की कौन-कौन सी विशेष बातें दी हुई हैं ? जब तक एक पृथक् बैंकिंग विधान नहीं पास होता तब तक के लिये और कौन से नियम बना दिये गये हैं ?

(२) सम्मिलित पूँजी के बैंकों का किस प्रकार वर्गीकरण किया गया है ? सदस्य बैंकों के विषय में आप क्या जानते हैं ?

(३) सम्मिलित पूँजी के भारतीय बैंकों की वर्तमान स्थिति क्या है ? उनके कार्यों का एक विस्तृत वर्णन दीजिये और उनके सम्बन्ध की विशेषताये बताइये ।

(४) द्वितीय महायुद्ध का भारतीय बैंकिंग पर क्या प्रभाव पड़ा है ? यह प्रभाव आपकी समझ से अच्छा हुआ है अथवा बुरा ? इनके सर्वाधिक के विषय मे आप क्या सोचते हैं ?

(५) सम्मिलित पूँजी के भारतीय बैंकों की क्या कठिनाइयाँ हैं और उनके क्या दोष हैं ? उनके सुधार के लिये अपने सुझाव रखिये ।

(६) सम्मिलित पूँजी के कुछ महत्वपूर्ण भारतीय बैंकों के विषय में टिप्पणियाँ लिखिये ।

(७) सदस्य बैंकों के कौन-कौन से दायित्व और अधिकार हैं ?

(८) रिजर्व बैंक गैरसदस्य बैंकों से किस तरह से अपना सम्बन्ध रखता है ? उसने उन्हें कौन-कौन सी सुविधायें दे सकती हैं ?

अध्याय १७

इम्पीरियल बैंक आफ इण्डिया

जिन स्थितियों में इम्पीरियल बैंक स्थापित हुआ था और जिस तरह से यह बैंक रिजर्व बैंक की संस्थापना के पहिले तक काम कर रहा था उनका अध्ययन तो हम १२ वें अध्याय में ही कर चुके हैं । किन्तु कुछ अन्य बातें भी ऐसी हैं जिन्हें हमें अब समझ लेना चाहिये, और उनमें मुख्य तो यह है कि यह बैंक स्वयं ही पूर्णरूप से केन्द्रीय बैंक क्यों नहीं बनाया गया और एक नया बैंक क्यों स्थापित किया गया । अतः, पहिले हम इसी बात का अध्ययन करेंगे और फिर अन्य बातों को लेंगे ।

इम्पीरियल बैंक को पूर्णरूप से केन्द्रीय बैंक न बनाने के कारण

(१) प्रथम तो केन्द्रीय बैंक की राष्ट्रीय दृष्टि होनी चाहिये । ऐसा न होने से वह देश की आर्थिक स्थिति नहीं सुधार सकता और न वह उसमें राष्ट्रीय बैंकिंग का विकास ही कर सकता है । इम्पीरियल बैंक की कभी भी राष्ट्रीय दृष्टि नहीं रही । इसके विपरीत हिल्डन यंग कमीशन के सामने कुछ ऐसे उदाहरण रखे गये थे जिनसे यह साबित होता था कि इसने सरकारी साख-पत्रों के होते हुये भी कुछ भारतीय बैंकों को सहायता देने से इन्कार कर दिया था । एक ओर तो यह विदेशियों को ऋण देता था और दूसरी ओर भारतीयों को उसके लिये इन्कार कर देता था ।

(२) भारतीय बैंकों को यह प्रतियोगिता की दृष्टि से देखता था । उन्हें प्रायः यह यहाँ की बैंकिंग का एक आवश्यक अङ्ग न समझ कर अपना शत्रु समझता था । अतः, यदि इसे केन्द्रीय बैंक बना भी दिया जाता तो भी इसकी नीति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हो पाता ।

(३) इम्पीरियल बैंक की जो बहुत सी शाखायें थीं वह किसी केन्द्रीय बैंक के लिये अनावश्यक बोझ समझी जाती थीं, क्योंकि एक केन्द्रीय बैंक तो अपनी इनी-गिनी शाखाओं के द्वारा ही द्रव्य के वाजार को नियन्त्रण में ला सकता है। केन्द्रीय बैंक तो जितना काम अपनी उपस्थिति से ही कर लेता है उतना काम करके नहीं करता। अन्तिम यह कि बहुत सी शाखाओं के होने से इसकी सारी शक्ति उन्हीं की व्यवस्था करने में खर्च हो जाती और वह देश की वैकिंग प्रणाली को अपने नियन्त्रण में न ला सकता।

(४) बैंक के संचालक मण्डल और व्यवस्थापकों में से अधिकांश के यूरोपीय होने के कारण, इसके देश की आवश्यकताओं को समझ सकने और उनके अनुसार काम करने की विशेषतः जब ऐसा करने से उनके अपने देश की हानि होती आशा नहीं की जा सकती थी।

(५) इसे केन्द्रीय बैंक बनाने के लिये इसके कार्यों में बहुत अदला-बदली करनी पड़ती जो शायद इसके हिस्सेदार पसन्द न करते। अतः, उनके और राज्य के बीच में मनमुटाव उत्पन्न हो जाता जो एक केन्द्रीय बैंक के प्रारम्भ के लिये अनुचित होता।

(६) इम्पीरियल बैंक तो एकमात्र लाभ कमाने के उद्देश्य से ही संस्थापित किया गया था किन्तु एक केन्द्रीय बैंक को तो प्रायः देश के हित में लाभ का वलिदान कर देना पड़ता है। अतः, यह कैसे हो सकता था। हम जानते हैं कि जब तेजी रोकनी होती है तब केन्द्रीय बैंक को व्याज की दर बढ़ाकर ऋण देने से इन्कार कर देना पड़ता है। भला कोई व्यापारिक बैंक ऐसा कैसे कर सकता है। जब मन्दी रोकनी है तब इसका उल्टा करना पड़ता है। वाजार में खुले ढङ्ग से काम करने में भी यही कठिनाई है। केन्द्रीय बैंक को तेजी में साख-पत्रों को कम मूल्य पर बेचना और मन्दी में उन्हें अधिक मूल्य पर खरीदना पड़ता है।

(७) फ्रान्स में तो फ्रान्स का केन्द्रीय बैंक केन्द्रीय वैकिंग के कार्यों के साथ-साथ व्यापारिक वैकिंग के कार्य भी करता है। किन्तु हर देश में ऐसा नहीं किया जा सकता। सब देशों में एक ही सी स्थितियाँ नहीं हैं। फ्रांस के निर्यात में ऐसी वस्तुये बहुत कम हैं जिनके मूल्य बहुत जल्दी घटते-बढ़ते हैं। अतः, उनका निर्यात भी बहुत जल्दी नहीं घटता-बढ़ता। साथ ही उसका बहुत कुछ द्रव्य विदेशों में लगा

रहता है। अतः, उसकी अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में जल्दी फर्क नहीं पड़ता। इसके विपरीत भारत के निर्यात में, ऐसी वस्तुएँ अधिक हैं जिनका मूल्य बहुत घटता-वढ़ता है, अतः, उनका निर्यात भी घटता-बढ़ता रहता है। फिर, उसके यहाँ विदेशी रुपया लगा हुआ है। (हाँ, अब स्थिति बदल गई है।) अतः, इम्पीरियल बैंक को केन्द्रीय बैंकिंग के कार्यों के साथ-साथ व्यापारिक बैंकों के कार्य करने की आज्ञा नहीं दी जा सकती थी। साथ ही इसके अन्य बैंकों से प्रतियोगिता करने का भी प्रश्न था। कुछ बैंक इसके विरोध में आवाज उठा ही रहे थे। यदि इससे इसके व्यापारिक बैंकिंग के कार्य करने की शक्ति छीने बिना इसे केन्द्रीय बैंक भी बना दिया जाता तो यह बड़ा शक्तिवान हो जाता और अपने कुछ प्रतियोगी बैंकों को तो समाप्त ही कर देता। यह तो उचित ही है कि जिसके पास सबका कोष हो, उसे जनता से काम करने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिये नहीं तो वह दूसरों के द्रव्य से बहुत लाभ कमा सकता है। फिर यह बैंकों का बैंक कैसे बना सकता था। उनका प्रतियोगी होने के नाते यह उन्हें मदद ही कैसे कर सकता था और वही अपने संकट के समय इससे किसी प्रकार की सहायता पाने की आशा कैसे कर सकते थे। वह तो इसे अपना प्रतियोगी समझते थे और इसके अधिकारों को ईर्ष्या की दृष्टि से ही देखते। फिर यह बैंक करन्सी की व्यवस्था अपने हित में करता, न कि देश के हित में। अन्तिम, यह कि बहुत बोल हो जाने के कारण न तो यह केन्द्रीय बैंकिंग के कार्य और न व्यापारिक बैंकिंग के कार्य भली प्रकार से कर सकता।

(-८-) यद्यपि इसे रुपये की टान होने पर उसके व्याज की दर को बहुत बढ़ने से रोकने के उद्देश्य से अपने विलों और हुण्डियों की प्रमानत पर करन्सी विभाग से ४ करोड़ रुपया बैंक दर पर और न्यूनतम ६ प्रतिशत पर और इसके ऊपर ८ करोड़ रुपया ७ प्रतिशत पर उधार लेने का अधिकार प्राप्त था, किन्तु यह भिन्न-भिन्न समय पर भिन्न-भिन्न व्याज की दर को एक सी करने में और तेजी के समय उसे अत्याधिक बढ़ने से रोकने में सफल नहीं हो सका। इसमें सन्देह नहीं कि करन्सी के अन्तिम नियन्त्रण को तो सरकार के हाथ में रखकर और व्याज की दर के एक सीमा पर पहुँचने पर उसमें से कुछ ऋण प्राप्त कर सकने का अधिकार इम्पीरियल बैंक को देकर स्थिति को बहुत नहीं सम्भाला जा सकता था। किन्तु तो भी इम्पीरियल बैंक

व्याज की दर के अन्तर में कुछ तो कमी कर ही सकता था लेकिन इसने राष्ट्रीय हित की अपेक्षा कृत अपने ही हित का अधिक ध्यान रखकर तैजरी के समय की माँग से पूरा लाभ उठाया और करन्सी विभाग से करन्सी लेकर दर को ऊँचा उठने से नहीं रोका। यह एक उदाहरण है। सच तो यह है कि इसे जो केन्द्रीय काम मिले हुये थे उनके ही द्वारा इसने कमी ऐसी कोई बात नहीं की कि जिससे राष्ट्र का लाभ होता।

इससे व्यापारिक बैंकिंग के कामों को इससे छीन लेने के फल स्वरूप सम्भावित आशंकाये

उपर्युक्त विवरण से यह तो स्पष्ट ही हो गया है कि इम्पीरियल बैंक से उसके व्यापारिक बैंकिंग के कामों के करने के अधिकार को छीन लेने से स्थिति बहुत कुछ ठीक हो जाती। किन्तु इसका फल अन्य तरीकों से बहुत बुरा होता। ये निम्नांकित हैं :—

(१) बहुत सी ऐसी जगहें हैं कि जहाँ पर इम्पीरियल बैंक ही की अकेली शाख है। अतः, यदि उससे उसके व्यापारिक बैंकों के काम करने का अधिकार ले लिया जाता तो वहाँ के लोगों को बैंकिंग की सुविधा न रह जाती।

(२) जिन स्थानों में इसकी शाख के साथ किसी अन्य बैंक की भी शाख है वहाँ पर इसके काम न करने से उस बैंक का एकाधिकार हो जाता जिससे वह लोगों से अधिक खर्चा लेता। इससे जनता की हानि ही होती।

(३) जनता का इम्पीरियल बैंक के ऊपर विश्वास है। लोगों ने अपनी वचत उसके यहाँ जमा कर रखी है। अतः, यदि उसे जमा प्राप्त करने के लिये मना कर दिया जाता और स्थायी जमा प्राप्त करने के लिये तो उसे अवश्य ही मना कर दिया जाना क्योंकि उस पर तो व्याज दिया जाता है और इसके लिये अन्य बैंकों से प्रतियोगिता होने की आशंका रहती है तो स्थायी जमा तो अवश्य ही उसके यहाँ से निकल जाती। इस सम्बन्ध में यह याद रखना चाहिये कि रिजर्व बैंक को भी स्थायी जमा लेने का अधिकार नहीं दिया गया है। अब जो लोग इम्पीरियल बैंक में स्थायी जमा रखते हुये हैं उनमें से बहुत से शायद किसी अन्य बैंक में जमा रखते ही नहीं। उनका इसे छोड़कर

किसी पर विश्वास ही नहीं है। फिर, इसके चालू खातों की अधिकांश जमा भी निकल जाती क्योंकि यह तो प्रायः इसीलिये रखी जाती है कि इससे बैंकिंग की अन्य सुविधाये प्राप्त होती हैं। अतः, यदि इम्पीरियल बैंक वह सुविधाये न दे पाता तो उसके यहाँ से यह जमा भी निकल जाती। यदि इसकी बहुत सी शाखाये बन्द कर दी जाती तो स्थिति और भी गिगड जाती और ऐसा होना सम्भव भी था क्योंकि इतनी अधिक शाखाओं के बोझ के साथ इसको केन्द्रीय बैंकिंग के काम दिये ही नहीं जा सकते थे। अतः, जिन लोगों को इम्पीरियल बैंक से जमा निकालनी पड़ती, शायद वह उसे और कहीं जमा न करते। इससे बैंकिंग की आदत कम हो जाती।

(४) इम्पीरियल बैंक की अपनी काम करने की प्रणाली से व्यापारिक बैंकिंग का स्तर ऊँचा हो गया है। यदि यह बैंक व्यापारिक बैंकिंग के काम करना बन्द कर देता तो शायद अन्य बैंक अपना स्तर इतना अच्छा न रख सकते। उनके सामने कोई आदर्श न रह जाता।

सन् १९३४ का इम्पीरियल बैंक (संशोधन) विधान

इम्पीरियल बैंक पूर्णरूप से केन्द्रीय बैंक नहीं बनाया गया वरन् उसके स्थान पर एक नया रिज़र्व बैंक खोल दिया गया। इससे इम्पीरियल बैंक विधान में कुछ संशोधन करने पड़े जो सन् १९३४ के विधान से किये गये। इसके फलस्वरूप यह पूर्णरूप से व्यापारिक बैंक बन गया और इसके ऊपर के कुछ प्रतिबन्ध भी हटा लिये गये। १२ वे अध्याय में यह बताया जा चुका है कि अपने विधान के अनुसार यह कुछ व्यवसाय नहीं कर सकता था। अतः, इस विधान के द्वारा इसे उनमें से कुछ व्यवसाय करने की आज्ञा दे दी गई। हाँ, सब प्रतिबन्ध तो नहीं हटाये जा सके। बात यह थी कि इसकी स्थिति को तो अच्छा रखना ही था। अन्य कारणों के साथ-साथ इसका एक विशेष कारण यह भी था कि इसे उन स्थानों के लिये जहाँ इसके दफ्तर थे और रिज़र्व बैंक के नहीं थे उसका अढतिया वनाया गया है। जो हो, उक्त विधान से इसे निम्न सुविधाये प्राप्त हो गई है :—

(१) इसके लन्दन के दफ्तर में इसे सब प्रकार के व्यवसाय करने की आज्ञा मिल गई है—इसके पहिले यह वहाँ पर केवल उन्हीं लोगों के हिसाब खोल सकता था जो इसके अथवा प्रेसीडेंसी

बैंको के भारतवर्ष में ऐसा हिसाब खोलने की तारीख के पिछले तीन वर्षों में ग्राहक रहे हों।

(२) अब यह लन्दन के अतिरिक्त अन्य बाहरी स्थानों में भी अपनी शाख खोल सकता है—इसके पहिले इसकी शाख बाहर केवल लन्दन ही में थी। अन्य किसी स्थान में यह उसे खोल ही नहीं सकता था। किन्तु अब यह ऐसा कर सकता है।

(३) देश में ही पहिले से अधिक स्वतन्त्रता के साथ व्यवसाय कर सकना—अब यह यहाँ पर पहिले से अधिक स्वतन्त्रता के साथ व्यवसाय कर सकता है। जब से रिजर्व बैंक खुल गया है तब से यह उसके हिस्सों पर भी ऋण दे सकता है। इसी प्रकार यह म्युनिस्पैलिटीयों के ऋण-पत्रों पर भी ऋण दे सकता है। फिर यह देशी राजाओं के द्वारा निकाले हुये उन ऋण-पत्रों पर भी ऋण दे सकता है जिनको निकालने की स्वीकृति सपरिपद गवर्नर जनरल ने दे दी है। इसी तरह से यह सीमित दायित्व वाली कम्पनियों के द्वारा निकाले हुये ऋण-पत्रों पर भी ऋण दे सकता है। जहाँ तक माल की गिरवी पर नकद साख देने का प्रश्न है वह तो यह पहिले भी दे सकता था। किन्तु अब यदि इसके यहाँ कोई ऐसा विशेष प्रस्ताव पास हो जाय और इसका केन्द्रीय मण्डल उसे मान ले तो यह केवल माल को अपने नाम पर करवा कर भी, चाहे वह कहीं ही क्यों न रक्खा हो, नकद शाख दे सकता है। इसके अतिरिक्त जब कि पहिले यह सभी ऋण अधिक-से-अधिक केवल छै ही महीनों के लिये दे सकता था अब यह कृपि सम्बन्धी कामों के लिये नौ महीनों तक के लिये ऋण दे सकता है। अन्तिम यह कि अब यह कुछ शर्तों के साथ अचल सम्पत्तियों को भी ऋण की जमानत के तौर पर स्वीकृत कर और रख सकता है।

(४) अपना काम करने के लिये भारतवर्ष से बाहर ऋण ले सकना—अब यह अपने काम के लिये भारतवर्ष के बाहर भी ऋण ले सकता है। इसके पहिले यह ऐसा नहीं कर सकता था।

पहिले की अपेक्षाकृत अब इस पर सरकार का भी बहुत कम नियन्त्रण रह गया है। एक तो यह कि अब इसके केन्द्रीय मण्डल में सपरिपद गवर्नर जनरल केवल अपने दो ही गैरसरकारी सञ्चालक

भेज सकता है। हाँ, एक अन्य अफसर भी रहता है किन्तु वह अपना मत नहीं दे सकता। दूसरे, इसके पुराने विधान का ५४ वाँ नियम भी हटा दिया गया है जिसके अर्थ यह है कि अब सपरिषद् गवर्नर जनरल न तो इसको कोई आज्ञा दे सकता है न इससे कोई बात पूछ सकता है, न जिस रूप में चाहे उस रूप में ही इससे इसकी सम्पत्ति और पाउने तथा दायित्व को छापने के लिये कह सकता है। हाँ, अब भी आवश्यकता पड़ने पर वह इसके यहाँ अपना आडीटर भेज सकता है और उससे इसके कामों की रिपोर्ट माँग सकता है।

इम्पीरियल बैंक की कार्यकारिणी

देश के भिन्न भिन्न भागों के हित की रक्षा के लिये और उनके यहाँ की वैकिंग का व्यवसाय करने की स्वतन्त्रता देने के लिये इसके तीन स्थानीय दफ्तर रक्खे गये हैं जो पहिले के तीनों प्रेसीडेंसी बैंकों के मुख्य स्थानों में हैं। फिर प्रत्येक स्थानीय दफ्तर का एक स्थानीय मण्डल भी है। इसके लिये प्रत्येक क्षेत्र के हिस्सेदारों के नाम के पृथक-पृथक रजिस्टर हैं। कहना न होगा कि जिस क्षेत्र के स्थानीय मण्डल के सदस्यों का चुनाव होता है उसी क्षेत्र के हिस्सेदार उस चुनाव में भाग लेते हैं। प्रत्येक स्थानीय मण्डल में एक तो उसका सभापति, एक उपसभापति, एक मन्त्री और कम से कम तीन सदस्य होते हैं। इस मण्डल को केन्द्रीय मण्डल के बनाये हुये उपनियमों के अनुसार अपने यहाँ की वैकिंग का व्यवसाय चलाने का अधिकार है। साथ ही यह स्थानीय दफ्तरों में रक्खे हुये शाख रजिस्ट्रों की जाँच करते हैं। उनकी अदला-बदली की आर हिस्सों के हस्तान्तरित होने की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति देते हैं और उनके प्रमाण-पत्र तैयार करते हैं।

फिर एक केन्द्रीय मण्डल है जिसके निम्न सञ्चालक होते हैं :—

(१) स्थानीय मण्डलों के सभापति, उपसभापति और मन्त्री—सब मिलाकर नौ संचालक;

(२) प्रत्येक स्थानीय मण्डल के सदस्यों में से उन्हीं के द्वारा उन्हीं में से चुना हुआ एक-एक सदस्य—३ संचालक,

(३) एक व्यवस्था संचालक (Managing Director)—इसे केन्द्रीय मण्डल स्वयं ही मनचाही शर्तों पर अधिक-से-अधिक

पाँच वर्षों के लिये चुनता है। इसके बाद फिर भी यह प्रत्येक बार अधिक-से-अधिक पाँच वर्षों के लिये चुना जा सकता है।

(४) सपरिषद् गवर्नर जनरल द्वारा नियुक्त अधिक-से-अधिक ऐसे दो संचालक जो उसके यहाँ के अफसर न हों। ये प्रति वर्ष नियुक्त किये जाते हैं। हाँ, इनकी पुनर्नियुक्ति भी हो सकती है।

(५) केन्द्रीय मण्डल के द्वारा निर्वाचित एक उप-व्यवस्था संचालक (Deputy Managing Director);

(६) सपरिषद् गवर्नर जनरल द्वारा नियुक्त एक सरकारी अफसर।

(५) में दिया हुआ उप-व्यवस्था संचालक, (१) में दिये हुये मन्त्री और (६) में दिया हुआ अफसर—ये लोग प्रत्येक बैठक में सम्मिलित तो हो सकते हैं किन्तु अपने मत नहीं दे सकते। हाँ व्यवस्था संचालक की अनुपस्थिति में उप-व्यवस्था संचालक भी मत दे सकता है।

केन्द्रीय मण्डल बैंक के सभी कामों पर दृष्टि रखता है। फिर उसकी जितनी भी शक्तियाँ हैं उन सब का यही प्रयोग करता है। सक्षेप में यह बैंक के उन सभी कामों को करता है जिन्हे विधान के द्वारा अथवा इसने स्वयं स्थानीय मण्डलों को नहीं सौंप दिया है। अपनी और स्थानीय मण्डलों की सुविधा के लिये इसने इन सब कामों के सम्बन्ध में कुछ उपनियम भी बना लिये हैं।

समस्त हिस्सेदारों की साधारण तथा विशेष बैठकों को बुलाने के लिये भी विधान बने हुये हैं। इसी तरह से प्रत्येक क्षेत्र के हिस्सेदारों की बैठकों को भी बुलाने के लिये नियम हैं।

बैंक के करने योग्य व्यवसाय

बैंक निम्न व्यवसाय कर सकता है :—

(१) यह निम्न जमानतों के आधार पर ऋण और नकद साख दे सकता है :—

(क) स्थानीय सरकार अथवा सीलोन की सरकार के अथवा अन्य सस्थाओं के स्टाक, फण्ड तथा ट्रस्टी सिक्क्योरिटियों के और रिज़र्व बैंक के हिस्सों के आधार पर;

(ख) सरकार के द्वारा सहायता प्राप्त उन रेलों की सिक्क्यो-

रिटियों के आधार पर जिन्हे सपरिषद् गवर्नर जनरल ने लागत लगाने के योग्य मनोनीत कर दिया है उनके आधार पर;

(ग) उन ऋण-पत्रों, इत्यादि के आधार पर जिन्हे निम्न संस्थाओं ने निकाला हो :—

' ब्रिटिश भारत ' के किसी भी व्यवस्थापिका मण्डल के द्वारा पास किये गये विधान के अनुसार किसी भी संस्था के द्वारा निकाले हुये अथवा;

किसी जिला अथवा म्युनिस्पल बोर्ड अथवा कमेटी के द्वारा निकाले हुये अथवा;

किसी देशी रियासत के राजा के द्वारा निकाले हुये और सपरिषद् गवर्नर जनरल के द्वारा स्वीकृत हुये अथवा;

किसी सीमित दायित्व वाली कम्पनी के द्वारा निकाले हुये किन्तु केन्द्रीय मण्डल के द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर;

(घ.) गिरवी रखे हुये माल के आधार पर अथवा केन्द्रीय मण्डल की स्वीकृति पर एक विशेष प्रस्ताव के द्वारा पास करा कर माल को अपने नाम करा कर उसके आधार पर अथवा उनके आधार पत्रों पर जमा करा कर अथवा उन पर बेचान करा कर उनके आधार पर,

(ङ) स्वीकृत किये हुये विलों के आधार पर और पाने वाले धनियों के द्वारा बेचान किये गये प्रण-पत्रों के आधार पर और दो अथवा दो से अधिक व्यक्तियों के अथवा फर्मों के द्वारा लिखे हुये संयुक्त और पृथक प्रण पत्रों के आधार पर। दो व्यक्ति तभी पृथक-पृथक माने जायेंगे जब वह साफ़ से सम्बन्धित नहीं, और

(च) सीमित दायित्व वाली कम्पनियों के हिस्सों के आधार पर अथवा जब (क) से (घ) तक दी हुई जमानते तो पहिले दी गई है और फिर अचल सम्पत्ति अथवा उसके सबन्ध के अधिकार-पत्र दिये गये हैं तब उनके आधार पर और यदि पहिले (ङ) में दी हुई जमानत दी गई है तब केन्द्रीय

मंडल के द्वारा स्वीकृत शर्तों पर ऊपर दी हुई जमानतों के आधार पर।

भारत सचिव^१ को वगैर जमानत के भी ऋण दिया जा सकता था।

(२) यदि किसी ऋण के सम्बन्ध में कोई प्रण-पत्र, ऋण-पत्र, स्टॉक (माल), रसीद, बाण्ड (Bond), वार्षिक-भत्ता (Annuity), स्टॉक, हस्से सिन्डोरिटियाँ अथवा माल अथवा माल सम्बन्धी अधिकार-पत्र बैंक के हाथ में आ जाते हैं तो ऋण की वापिसी न होने पर वह उन्हें बेच और उनके मूल्य वसूल कर सकता है।

(३) वह कोर्ट आफ वाड्स को उनके हाथ में अथवा उनकी व्यवस्था में जो स्टेट हों उनके आधार पर उन्हें ऋण दे सकता है और उसे व्याज सहित वसूल कर सकता है। किन्तु ऐसे ऋण उस स्थान की स्थानीय सरकार की स्वीकृति पाने के बाद ही और कृषि के कामों के लिये तो नौ महीनों के लिये और अन्य कामों के लिये छः महीनों से अधिक के नहीं होने चाहिये।

(४) यह विनिमय के विलों को और दूसरी हस्तान्तरित होने वाली सिन्डोरिटियों को लिख, स्वीकृति कर, भुना, क्रय और विक्रय कर सकता है।

(५) यह प्रथम में (क) से (ग) तक में दी हुई जमानतों में अपनी लागत लगा सकता है और उन्हें वहीं पर दी हुई अन्य तरह की जमानतों में बदल भी सकता है।

(६) यह आर्डर बैंक, पोस्ट विल और साख-पत्र (Letters of credit) अथवा यही सब देखनहार और मांग पर देय शर्त के अतिरिक्त वना, निकाल और चला सकता है।

(७) यह मुद्रा के रूप में अथवा ऐसे ही सोने और चाँदी को खरीद और बेच सकता है।

(८) यह जमा प्राप्त कर सकता है और किसी भी शर्त पर हिसाब रख सकता है।

(९) यह प्लेट, जवाहिरात, अधिकार-पत्र अथवा अन्य मूल्यवान वस्तुओं को किसी भी शर्त पर धरोहर के रूप में रख सकता है।

^१भारत सरकार

(१०) यदि कोई चल अथवा अचल सम्पत्ति इसके हाथ में आ जाती है तो यह उसे बेच कर उसके मूल्य की वसूली कर सकता है। साथ ही यदि इसके पास इनके कोई अधिकार आ जाय तो उन्हें भी यह ले, रख और हर प्रकार से प्रयोग में भी ला सकता है।

(११) यह कमीशन पर कोई भी अर्थ सम्बन्धी आदती काम कर सकता है और जमानत पर अथवा बिना जमानत के ही किसी प्रकार की क्षति पूर्ति का अथवा प्रतिभू (Surety-ship) का दायित्व ले सकता है।

(१२) यह किसी भी स्टेट की साधक (Executor) की, धरोहरी (Trustee) की अथवा किसी अन्य स्थिति में व्यवस्था कर सकता है। साथ ही यह किसी सार्वजनिक कम्पनी के साख-पत्रों और हिस्सों को कमीशन पर खरीद, बेच, हस्तान्तरित कर और अपने पास रख सकता है। यह उनके मूल्य, व्याज, लाभ की बँटनी को प्राप्त भी कर सकता है। अन्तिम, वह उपर्युक्त रकम को देश में अथवा बाहर कहीं भी सार्वजनिक अथवा निज बिलों के द्वारा पहुँचा भी सकता है।

(१३) यह विदेशों में देय विनिमय के बिलों को लिख और ऐसे ही साख-पत्रों को निकाल भी सकता है।

(१४) यह विदेशों में देय विनिमय के बिलों को, चाहे वह किसी भी अवधि के ही क्यों न हों (किन्तु यदि वह कृपि के सम्बन्ध के हैं तो नौ महीनों से अधिक के बाद देय न हों और यदि अन्य किसी व्यवसाय के सम्बन्ध के हैं तो छ महीनों से अधिक के बाद देय न हों), बेच सकता है।

(१५) यह अपने व्यवसाय के लिये अपनी सम्पत्ति और अपने पाउने की जमानत पर अथवा बिना जमानत के ही द्रव्य उधार भी ले सकता है।

(१६) समय समय पर यह प्रेसीडेंसी बैंकों के पेन्शन कोष में रकम डाल सकता है।

(१७) ऊपर जिन व्यवसायों के विषय में कहा गया है उन्हें करने में अन्य जिन कामों के करने की आवश्यकता प्रसङ्गवश आ जाय उन्हें भी यह बैंक कर सकता है।

जो काम यह नहीं कर सकता है

ऊपर जो काम दिये गये हैं उनके अतिरिक्त यह बैंक अन्य काम और विशेषतः निम्न काम नहीं कर सकता —

(१) (३) और (४) में जैसा दिया हुआ है उसके अनुसार यह छः महीनों अथवा नौ महीनों से अधिक के लिये ऋण नहीं दे सकता। साथ ही ये इसके स्वयम् के स्टाक और हिस्सों पर भी नहीं दिये जा सकते। इसी तरह से (३) में जो दिया हुआ है उसके अतिरिक्त अचल सम्पत्ति अथवा उनके पत्रों की जमानतों पर भी ये नहीं दिये जा सकते।

(२) प्रत्येक व्यक्ति अथवा सामूहिक को जितने तक का ऋण देने के लिये इसकी स्वीकृत तालिका में अथवा विलों को भुनाने के लिये लिखा हुआ है उससे अधिक का ऋण नहीं दिया अथवा विल नहीं भुनाया जा सकता। हाँ, यह ऋण प्रथम में (क) से (घ) तक दी गई जमानतों पर दिया जा सकता है।

(३) किसी व्यक्ति के अथवा सामूहिक के ऐसे किसी अच्छा अधिकार देने वाले साख-पत्रों की जमानत पर न तो नकद साख ली जा सकती है न ऋण दिया जा सकता है, न उसे खरीदा अथवा भुनाया जा सकता है जो उसी शहर में देय हो जहाँ वह भुनाया जा रहा है और जिसमें कम से कम ऐसे दो व्यक्ति अथवा सामूहिक के पृथक् पृथक् दायित्व न हों जिनमें परस्पर सामूहिक सम्बन्ध नहीं है।

(४) ऐसे अच्छा अधिकार देने वाले साख-पत्रों की जमानत पर न तो नकद साख खाता खोला जा सकता है, न ऋण दिया जा सकता है, न उन्हें खरीदा जा सकता है और न उन्हें भुनाया जा सकता है जिनमें धरोहर की रकम नहीं लगाई जा सकती अथवा जो यदि कृपि की सहायता के लिये लिखे गये हैं तो नौ महीनों के बाद और जो किसी अन्य काम के लिये लिखे गये हों तो छः महीनों के बाद पकते हों।

रिज़र्व बैंक का इम्पीरियल बैंक से सम्बन्ध

रिज़र्व बैंक विधान की ४५ वीं धारा में रिज़र्व बैंक और इम्पीरियल बैंक के बीच में एक सम्बन्ध की बात लिखी हुई थी और उसके तीसरे परिशिष्ट में वह शर्तें दी हुई थीं जिनका उसमें होना आवश्यक

था। अतः, यह समझौता किया गया और सपरिषद् गवर्नर जनरल की स्वीकृति के बाद इस पर दोनों धनियों के हस्ताक्षर हुये। इसके अनुसार इम्पीरियल बैंक उन सब स्थानों में रिजर्व बैंक का अकेला अद्वितीया नियुक्त किया गया जहाँ इम्पीरियल बैंक का दफ्तर तो था किन्तु रिजर्व बैंक के बैंकिंग विभाग का कोई दफ्तर नहीं था। इम्पीरियल बैंक के रिजर्व बैंक की ओर से उन कामों के करने के प्रति फल-स्वरूप जिन्हे यह उन स्थानों पर पहिले ही से सपरिषद् गवर्नर जनरल की ओर से करता आ रहा था रिजर्व बैंक को इसे उस तमाम रकम पर जो यह उस खाते में वर्ष भर में पाता है अथवा देता है एक कमीशन देना पड़ता है। प्रारम्भ में पहिले के दस वर्षों में तो यह पहिले के २५० करोड़ रुपये पर तो १ आ० प्रतिशत था और बाकी रकम पर दो पैसा प्रतिशत था। इस अवधि के बीत जाने पर अगले पाँच वर्षों के लिये इस कमीशन का निश्चय इम्पीरियल बैंक के इस काम को करने में जो कुछ वास्तविक व्यय हुआ था उसे जाँचने के बाद करने के लिये तैय्य हुआ था। अतः, यह सन् १९४५ में हुआ। उसके अनुसार कमीशन की दर प्रथम १५० करोड़ रुपये के लिये १ आ० प्रतिशत, दूसरे १५० करोड़ रु० के लिये २ पैसा प्रतिशत तथा ३०० करोड़ रु० के ऊपर ३०० करोड़ रु० के लिये एक पैसा प्रतिशत और शेष के लिये $\frac{1}{2}$ प्रतिशत निश्चित हुआ था। साथ ही रिजर्व बैंक ने इम्पीरियल बैंक को उसके अपनी उतनी ही शाखाओं को खुली रहने देने के लिये जितनी रिजर्व बैंक के खुलने के समय थी प्रथम पाँच वर्षों तक ९ लाख रुपये प्रति वर्ष, दूसरे पाँच वर्षों तक ६ लाख रु० प्रति वर्ष और तीसरे पाँच वर्षों तक ४ लाख रु० प्रति वर्ष देने का वायदा किया था। इम्पीरियल बैंक उनमें कौनों ऐसी शाखा को बन्द करके, जो इस समझौते को करने के समय थी, कोई नयी शाखा नहीं खोल सकता। हाँ, रिजर्व बैंक किसी भी जगह पर चाहे वहाँ उस समय तक इम्पीरियल बैंक उसके अद्वितीय का काम क्यों न करता रहा हो अपनी शाखा जब चाहे तब खोल सकता है।

यह समझौता १५ वर्षों के लिये हुआ है। इसके बाद इसे कोई भी धनी ५ वर्षों की सूचना देकर समाप्त कर सकता है। साथ ही यह इस बात पर भी निर्भर है कि इम्पीरियल बैंक अपनी स्थिति बराबर अच्छी रखे। यदि रिजर्व बैंक के केन्द्रीय मंडल के विचार में किसी

समझ में यह आ जाता है कि वह ऐसा नहीं कर रहा है अथवा समझौते की शर्तों का पालन नहीं कर रहा है तब वह सपरिपद गवर्नर जनरल के पास जा सकता है और वह इम्पीरियल बैंक को इस समझौते के सम्बन्ध में अथवा सरकारी द्रव्य की अथवा रिजर्व बैंक के नोट चलाने वाले विभाग के सम्पत्ति और पाउने की रक्षा के सम्बन्ध में कोई भी आदेश दे सकता है और उसे न पालन करने पर समझौते को समाप्त कर सकता है।

इम्पीरियल बैंक से होने वाले लाभ

इम्पीरियल बैंक से अनेकों लाभ हुये हैं। वे निम्नाङ्कित हैं :—

(१) जब प्रेसीडैन्सी बैंकों को मिलाकर इम्पीरियल बैंक बना था तब प्रेसीडैन्सी बैंकों की कुल मिलाकर ५९ शाखाये थीं। इम्पीरियल बैंक तथा भारत सचिव के बीच में इस सम्बन्ध का जो समझौता हुआ था उसके अनुसार इम्पीरियल बैंक को प्रथम पाँच वर्षों के अन्दर १०० नयी शाखाओं की सस्थापना करने के लिये बाध्य किया गया था। कहना न होगा कि मार्च सन् १९२६ तक इसने अपने दायित्व को पूरा कर दिया था और कुल मिला कर १०२ नयी शाखाये खुल चुकी थी। सन् १९४७ के अन्त में इसके ४४४ दफ्तर थे। इसने बहुत से स्थानों में जब अपने दफ्तर खोले थे तब वहाँ पर कोई भी आधुनिक बैंक नहीं था। हाँ, उसके बाद कहीं-कहीं अन्य बैंकों के भी दफ्तर खुल गये हैं। किन्तु अब भी लगभग १०० के ऐसी जगह हैं जहाँ केवल इम्पीरियल बैंक के ही दफ्तर हैं। इसके यह अर्थ हैं कि इन स्थानों को केवल इम्पीरियल बैंक के ही होने के कारण बैंकिंग का लाभ मिल रहा है।

(२) इसमें जनता का विश्वास पैदा हो गया है। हम जानते हैं कि सम्मिलित पूँजी वाले बैंक बराबर फेल होते रहते हैं। अतः, लोगों का उन पर कोई विश्वास नहीं रह गया है। इम्पीरियल बैंक सन् १९३४ तक तो सरकार का भी बैंक था। अतः, लोग समझते थे कि यह फेल नहीं होगा। देश के प्रमुख बैंक अर्थात् रिजर्व बैंक के इसके अकेले अढतिये होने के कारण आज भी इसकी एक विशेष स्थिति है। इसके कारण इसमें द्रव्य जमा होता रहता था और है। फिर इसने कुछ बैंकों की तो उनके संकट के समय सहायता की ही है; अतः, इससे

इसने उन्हें फेल होने से भी बचाया है। इसका फल यह हुआ कि लोगों का उन सब पर भी कुछ न कुछ अधिक विश्वास तो अवश्य ही जमा। इससे इम्पीरियल और दूसरे बैंकों में जमा बढ़ी। जिन स्थानों में इसने अपनी शाखाएँ खोलीं उनमें बहुत कुछ जमा इसके यहाँ अवश्य आई। अतः, हम यह कह सकते हैं कि इम्पीरियल बैंक ने देश की पूँजी को चलायमान करके उसे अवश्य लाभ पहुँचाया है।

(३) जिन स्थानों में इसने अपनी शाखाएँ खोलीं वहाँ के लोगों ने इससे ऋण भी पाया। इतना ही नहीं वहाँ व्याज की दर भी बहुत कुछ कम हो गई। इसके अतिरिक्त जहाँ पर इसकी शाखाएँ नहीं हैं वहाँ पर भी उनके खुलने के डर के मारे अन्य बैंकों ने कम दर का ही व्याज लिया। केवल देशी महाजनों ही ने नहीं वरन् आधुनिक बैंकों ने भी यही किया। चूँकि इम्पीरियल बैंक के पास पहिले सरकार का द्रव्य भी रहता था, अतः, वह उसे भी प्रयोग में ला सकता था। जैसा कि हमें ज्ञात है इसे १२ करोड़ ६० की अतिरिक्त करन्सी प्राप्त कर लेने का अधिकार भी दे दिया गया था। इससे तेजी के समय व्याज की दर अवश्य बहुत कुछ बढ़ने से तो रुक ही जाती थी।

(४) इसकी शाखाओं की बहुत अधिक सख्या होने के कारण यह द्रव्य भेजने की भी बहुत सुविधा दे सकता था। केवल यही नहीं वरन् अन्य बैंक भी इसी कारण इस काम में अधिकाधिक सुविधा दे सकते थे। साथ ही द्रव्य भेजने का खर्च भी बहुत कम लिया जाता था।

(५) ऐसा सोचा गया था कि यह विलों को अधिकाधिक सख्या में डिस्काउंट करके उनका प्रयोग भी बढ़ा सकेगा। किन्तु यह नहीं हो सका। बात यह थी कि दूसरे बैंक इसे अपने विलों के विवरण नहीं बताना चाहते थे। उनका यह ध्यान था कि यह उससे लाभ उठाकर उनकी प्रतियोगिता करेगा। जो हो, यह माल पर उधार देकर, विलों को डिस्काउंट करके और मॉग पर देय ड्राफ्टों और टी० टी० को खरीद करके कृपि की उपज के व्यापार में बढ़ी सहायता करता है। इसने अपनी हुंडी की दर और बाजार के व्याज के दर में भी बहुत कुछ अन्तर भिटा दिया है। इसी तरह से इसने बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के बाजारों के व्याज की दरों के अन्तर को भी बहुत कुछ कम कर दिया है।

(६) इसने प्रान्तीय और जिला सहकारी बैंकों से भी बहुत घना सम्बन्ध उत्पन्न कर लिया है और यह उन्हें जमा से अधिक निकालने, इत्यादि की भी सुविधा देता है ।

(७) इसने अपनी बड़ी-बड़ी शाखाओं में निकासग्रह भी स्थापित कर दिये थे जिससे बैंकों को इस सम्बन्ध की सुविधा प्राप्त हो सकी । इसके फलस्वरूप बैंकों का प्रयोग भी बढ़ा ।

(८) यह सरकारी ऋण निकालता था और उसकी व्यवस्था करता था । अतः, जिन-जिन शहरों में इसकी शाखाएँ थीं उन-उन शहरों के लोग सरकारी साख-पत्रों में रुपया लगाने लगे ।

(९) इसकी शाख लन्दन में भी थी । अतः, इसके ग्राहकों को संसार के सबसे मुख्य अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से सम्बन्ध रखने का अवसर प्राप्त हो सका ।

रिजर्व बैंक की स्थापना का इसकी उपयोगिता पर प्रभाव

रिजर्व बैंक की स्थापना का इसकी उपयोगिता पर तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ा । जैसा कि पहिले ही कहा जा चुका है जनता का अब भी इस पर पूर्ण विश्वास है । सच तो यह है कि इसके अब बहुत से बन्धनों से मुक्त हो जाने के कारण यह जनता के लिये और भी उपयोगी हो गया है । अब यह अधिक दिनों तक के लिये और बहुत सी जमानतों पर ऋण दे सकता है । फिर, अब यह विनिमय का व्यवसाय भी कर सकता है ।

इम्पीरियल बैंक तथा जनता

उपर्युक्त से यह तो स्पष्ट ही है कि इम्पीरियल बैंक जनता के लिये, अपने ग्राहकों के लिये, सम्मिलित पूँजी वाले और सहकारी बैंकों के लिये तथा सरकार के लिये बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ है । यदि हम प्रथम को अर्थात् साधारण जनता को ही पहिले ले ले तो बैंकिंग के व्यवसाय के बढ़ जाने से उसको भी बहुत लाभ हुआ है । हमें यह तो ज्ञात ही है कि इसने किस तरह से अपनी नयी-नयी शाखाएँ खोल कर और सरकार का बैंक बन कर तथा जब से रिजर्व बैंक स्थापित हुआ है तब से उसका एकमात्र अद्वितीया बनकर और सबसे मुख्य तो सम्मिलित पूँजी वाले बैंकों को सहायता देकर साधारण जनता का

विश्वास अपने ऊपर जमा लिया है और उसमें बैंकिंग की आदत डाल दी है। इसके अतिरिक्त इसकी बहुत सी शाखाओं के होने के कारण इसको जो बहुत से कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ी उससे देश के बहुत से लोग बैंकिंग का काम सीख गये हैं। इस तरह से इस देश में बैंकिंग का धधा भी चल निकला है और उससे लोगों की जीविका का प्रश्न भी कुछ हल हो गया है।

इंपीरियल बैंक तथा उसके ग्राहक

सरकार की रकम के इसके पास होने के कारण और इसके उसे अपने प्रयोग में लाने के कारण यह अपने ग्राहकों को अधिक ऋण देकर और उनसे कम व्याज लेकर उनको बराबर लाभ पहुँचा सकता था। फिर आवश्यकता पड़ने पर यह सरकार के करन्सी विभाग से अतिरिक्त करन्सी लेकर तेजी और मन्दी के समय की व्याज की दर को बहुत कुछ सम कर सकता था। इसके अतिरिक्त इसकी एक शाख लन्दन में है। इससे एक तो यह लाभ है कि इसके ग्राहकों का इसके द्वारा ससार के एक मुख्य द्रव्य के बाजार से सीधा सम्बन्ध स्थापित हो सकता है। दूसरे, यह अंग्रेज व्यापारियों की स्थिति के सम्बन्ध में स्वयं पता लगा करके उसे अपने उन ग्राहकों को बता सकता है जो उनसे व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करना चाहते हैं। तीसरे, यह स्थानीय संस्थाओं के लिये लन्दन में साख उत्पन्न कर सकता है और अपने भारतीय ग्राहकों की बचत को वहाँ लगा सकता है। चौथे और अन्तिम, अपनी बहुत सी शाखाओं के होने के कारण यह अपने ग्राहकों को बैंकिंग की अधिकाधिक सुविधायें दे सकता है।

इंपीरियल बैंक तथा सम्मिलित पूँजी वाले बैंक

इम्पीरियल बैंक सम्मिलित पूँजी वाले बैंकों के बिलों को फिर से डिस्काउण्ट करके तथा उनकी अन्य प्रकार से सहायता करके उनके मित्र तथा सरकारी काम करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। किन्तु इसमें यह बिल्कुल भी सफल नहीं हो सका। उनका प्रतियोगी होने के कारण यह उनके हृदय में अपनी ओर से विश्वास नहीं जमा सकता और इसी कारणवश यह उपर्युक्त कामों में सफल भी नहीं हो सका। सम्मिलित पूँजी वाले बैंक इसलिये अपने बिल इससे नहीं डिस्काउण्ट कराते थे कि ऐसा करने से इसे उनके सम्बन्ध की

सब बातें मालूम हो जायँगी और इससे यह उनके काम छीन लेगा। साथ ही वह इससे अन्य प्रकार से भी ऋण लेने में डरते थे। उन्हें यह आशंका थी कि यह जनता से कहीं उन्हें बदनाम न कर दे। कभी-कभी तो इस पर उन बैंकों का पक्षपात करने का भी दोषारोपण किया जाता था जिनकी व्यवस्था विदेशियों के हाथ में थी। किन्तु इसने अन्य बैंकों की भी कई बार सहायता की और इससे अवश्य ही उन्हें फेल होने से बचाया। अलायन्स बैंक आफ शिमला के फेल होते ही इसने उसकी समस्त जमा का ५० प्रतिशत उसी समय देकर उसके ग्राहकों की बड़ी ही मदद की। इसने उनकी अन्य प्रकार से भी सहायता पहुँचाई। जैसा कि पहिले भी बताया जा चुका है इसने उन्हें द्रव्य भेजने की और चेकों के पारस्परिक निपटारे की भी सुविधाये दी। इसके अतिरिक्त इसने उनके सामने अपने काम करने के ढङ्ग को इतना ऊँचा रक्खा कि जो अन्य बैंकों के लिये आदर्श स्वरूप था और जिसे उनमें से कुछ ने तो अपनाने का भी प्रयत्न किया।

इम्पीरियल बैंक तथा सहकारी बैंक

जैसा कि पहले कहा जा चुका है इम्पीरियल बैंक सहकारी बैंकों को जमा से अधिक रकम निकालने की आज्ञा देकर तथा अन्य प्रकार से ऋण देकर उनकी सहायता करता है। उनसे इसका बहुत अच्छा सम्बन्ध रहा है।

इम्पीरियल बैंक तथा सरकार

इम्पीरियल बैंक तथा भारत सचिव के बीच में जैसे ही समझौता हो गया वैसे ही सरकार ने उन स्थानों पर अपने खजानों को बन्द कर दिया जिनमें इसके दफ्तर थे। फिर यह दफ्तर बराबर बढ़ते गये। अतः, जैसे-जैसे यह बड़े वैसे-वैसे ही सरकार के खजाने बन्द होते गये। इससे उसका बहुत कुछ व्यय बच गया। दूसरे, सरकार उन स्थानों के बीच में हुण्डियाँ (Currency transfers) निकालने की मंजूरी से भी बच गई जिन स्थानों में इसके दफ्तर थे। तीसरे, यह उसे अपने सभी दफ्तरों में उसकी आवश्यकता के अनुसार रुपये देने लगा। अन्तिम यह कि इसके उसके ऋण की व्यवस्था करने के कारण उसमें बहुत ही सुविधा होने लगी। छोटे-छोटे लोग भी उसमें रुपया लगाने लगे।

इम्पीरियल बैंक तथा विदेशी बैंक

इम्पीरियल बैंक की संस्थापना से विदेशी बैंकों की तनिक भी हानि नहीं हुई। जैसा कि हम पहिले से ही जानते हैं सन् १९३४ के पहिले तो यह विनिमय का व्यवसाय कर ही नहीं सकता था, अतः, इसका उनसे प्रतियोगिता करने का प्रश्न ही नहीं उठ सकता था। किन्तु इसके बाद भी जब से इसे विनिमय का व्यवसाय करने की आज्ञा मिल गई है तब से भी इसने इस व्यवसाय को करना प्रारम्भ नहीं किया है। अतः, उनकी प्रतियोगिता नहीं की। फिर, इसके व्यवस्थापकों और उनके व्यवस्थापकों के बीच में सदैव बहुत अच्छे सम्बन्ध रहते थे।

इम्पीरियल बैंक की वर्तमान स्थिति और उनके काम

इम्पीरियल बैंक अपनी संस्थापना के समय से ही बहुत ही उच्च तथा गौरवमय स्थिति में है। सन् १९३४ तक तो यह सरकार का और बैंकों का बैंक था और इसके बाद से यह देश के प्रमुख बैंक अर्थात् रिजर्व बैंक का एकमात्र अङ्गतिथी है। इससे जनता का इस पर बड़ा विश्वास जम गया है और इसी से इसके यहाँ अन्य बैंकों की अपेक्षाकृत बहुत ही अधिक जमा है। दफ्तरों की सख्या की दृष्टि से (सन् १९४७ में ४४४), पूँजी की दृष्टि से (५६२,५०,००० रुपये) सुरक्षित कोष की दृष्टि से (६ करोड़ रुपये से अधिक), जमा की दृष्टि से (२४४.७२ करोड़ रुपये) और प्रत्येक दृष्टि से यह देश के बड़े से बड़े बैंकों से भी यहाँ तक की स्वयं प्रमुख बैंक से भी बड़ा है। यदि हम किसी एक वर्ग के सब बैंकों को भी एक साथ ले ले तो शायद यह उनमें से भी कुछ से बहुत बड़ा है।

सन् १९४५ के अन्त में प्रत्येक वर्ग के बैंकों की प्राप्त पूँजी और सुरक्षित कोष, जमा, नकद कोष, लागत और ऋण में जमा का अनुपात इत्यादि नीचे दिये हुये हैं जिनसे उन सबों के बीच में इसकी तुलना की जा सकती है।

लाख रुपयों में

वर्ग	वर्ष	सं	प्राप्त पूँजी और कोष	जमा	नकद कोष	नकद में जमा का प्रतिशत	लागत	लागत में जमा का प्रतिशत	ऋण	ऋण में जमा का प्रतिशत
(१) सदस्य बैंक	१९४५	१	१९७०	२५९३७	४१६०	१६०	१५४१८	५९.४	७२९७	२८.१
(अ) इम्पीरियल बैंक	१९४५	१५	१८९५४	—	—	—	—	—	—	—
(ब) विनिमय के बैंक	१९४५	७५	३८७५	५४११५	१०५५९	१९.५	२७८५२	५१.५	२२०९१	४०.८
(स) अन्य सदस्य बैंक										
(२) गैरसदस्य बैंक और (अ) एक लाख और पाँच लाख रु० के बीच के पूँजी और सुरक्षित कोष वाले बैंक	१९४५	२४२	९५५	९००६	३०९३	३३.६	२७६६	३०.०	४३७५	४७.५
(ब) ५०,००० और १ लाख रु० के बीच के पूँजी और सुरक्षित कोष वाले बैंक	१९४५	११४	८०	७४५	२०४	२७.५	१५३	१९.३	२०.५	४१.९

३५१

इम्पीरियल बैंक आफ इंडिया

(स) ५८,००० रु० के नीचे के पूँजी और सुरक्षित कोष वाले बैंक	१९४५	२४४	४९	४१९	१२२	२९.१	५०	११.९	२८२	६७.३
(३) सहकारी बैंक										
(अ) पाँच लाख और अधिक के पूँजी और सुरक्षित कोष वाले बैंक	१९४५	५०	६९५	३४९०	३१५	९.०	—	—	१९८३	५६.८
(ब) एक लाख और ५ लाख की पूँजी और सुरक्षित कोष वाले बैंक	१९४५	३१३	६६१	२३०२	३४२	१४.९	—	—	१३८४	६०.१

इसके अपरिमित साधनों के कारण सम्मिलित पूँजी वाले बैंक इसे अपना बहुत भयानक प्रतिद्वन्दी समझते हैं। इसने बहुत सी शाखाएँ खोल ली हैं और इससे वहाँ पर उनका एकाधिपत्य जाता रहा है। इसने मण्डियों में भी अपनी उपशाखाएँ खोल ली हैं और वहाँ पर यह कृषि के व्यापार की सहायता करने में भी उनका प्रतिद्वन्दी बन गया है। इसके पहिले यह केवल छ. महीनों तक के लिये ही ऋण देता था किन्तु जैसा कि हमको पहिले ही ज्ञात हो चुका है अब यह नौ महीनों के लिये भी ऋण दे सकता है। फिर, अब यह सब तरह की जमानतों पर ऋण देता है। उदाहरणार्थ, माल, अचल-सम्पत्ति, उनके अधिकार पत्र, सिक्क्योरिटियाँ, इत्यादि। यह जो व्याज लेता है उसकी दर भी अन्य बैंकों के व्याज की दर से कम है।

अब यह विनिमय का व्यवसाय भी कर सकता है। किन्तु अभी तक इसने इस काम को प्रारम्भ नहीं किया है। अतः, इसकी विनिमय के बैंकों से कोई प्रतियोगिता नहीं पड़ी है। किन्तु यह उनसे बहुत अच्छी तरह से प्रतिद्वन्द्विता कर सकता है।

इसकी व्यवस्था बहुत कुछ गैरभारतीयों के हाथ में है। इसने भारतीयों को ऊँची-ऊँची जगहें बहुत कम दी हैं। इससे केवल इसका व्यय ही बहुत अधिक नहीं है बल्कि यह भारतीयों की दृष्टि में गिर गया है। किन्तु जैसा कि पहिले भी कहा जा चुका है विश्वास पात्रता की दृष्टि से यह उनमें बहुत ही प्रिय है।

इम्पीरियल बैंक की भविष्य के लिये नीति

इम्पीरियल बैंक की भविष्य के लिये यही नीति होनी चाहिये कि उसका दृष्टिकोण राष्ट्रीय हो। इसके कर्मचारियों को जनता की दृष्टि से यह निकाल देना चाहिये कि यह भारतीयों के प्रति उदासीन है। यदि ऊँचे-ऊँचे पदों को भारतीयों को दे दिया जाय तो शायद स्थिति बहुत कुछ सुधर जायगी और इधर सुधर भी रही है। इससे उन लोगों के लोगों से अधिक सम्बन्ध में आने से इसका व्यवसाय भी बढ़ जायगा। फिर, इससे इसके व्यय में भी कमी पड़ेगी। इसे भारतीय भाषाओं को भी प्रोत्साहन देना चाहिये। इसके अतिरिक्त इसे भारतीय बैंकों की व्यर्थ की प्रतिद्वन्द्विता नहीं करनी चाहिये। ऐसे अन्य बहुत से काम हैं जिन्हें यह कर सकता है। प्रथम तो अब ज्ञात कि इसे विनिमय

का काम करने की आज्ञा मिल गई है तब इसको इस काम को अवश्य करना चाहिये। जैसा कि आगे चलकर मालूम होगा विदेशी बैंक जिनके हाथ में इसका एकाधिपत्य है देश के हित के विरुद्ध काम करते हैं। वे अपने अपने देशों के व्यवसायियों का पक्ष करते हैं और भारतीयों के हित की अपेक्षाकृत उन्हीं के हित का अधिक ध्यान रखते हैं। कुछ ऐसे भारतीय बैंकों की बहुत बड़ी आवश्यकता है जो उनके एकाधिपत्य को तोड़ सकें और इम्पीरियल बैंक को छोड़कर कोई अन्य बैंक ऐसा कर नहीं सकता। इसे उद्योग-धन्धों की सहायता करने में भी बड़ी दिलचस्पी दिखानी चाहिये। भारतीय बैंकिंग में जो ऐसा काम करने वाले बैंकों की कमी है उसे यह बहुत ही अच्छी तरह से पूरी कर सकता है।

बैंक जो कुछ करता है उसी में बहुत कर सकता है। प्रथम तो इसे देशी महाजनों के विलों को और उदारता से डिस्काउण्ट करके उनकी कमी को पूरा करना चाहिये। इसके लिये इसे अपने डिस्काउण्ट के दर को व्याज के दर से कुछ कम रखना पड़ेगा। दूसरे, इसे देशी महाजनों के प्रति अधिक उदार होना पड़ेगा। इसे विलों और चेकों की बसूली के लिये उन पर उसी प्रकार विश्वास करना चाहिये जिस प्रकार यह दूसरे बैंकों पर करता है। जहाँ-जहाँ इसके स्वयं के दफ्तर नहीं खुल सकते वहाँ-वहाँ यह उनसे साफ़ा कर सकता है।^१

प्रश्न

(१) इम्पीरियल बैंक पूर्णरूप से केन्द्रीय बैंक क्यों नहीं बनाया गया? इस सम्बन्ध में यह भी बताइये कि इससे इसके व्यापारिक बैंकों के काम करने के अधिकार को छीन लेने से किन-किन बातों का डर था।

(२) इम्पीरियल बैंक जो काम कर सकता है, इसके जो व्यवस्थापक मण्डल हैं उनकी रचना में तथा इसके कामों में सपरिषद गवर्नर जनरल के हस्तक्षेप करने की शक्ति में, इसके सन् १९३४ के विधान से कौन-कौन से परिवर्तन कर दिये गये हैं?

(३) इम्पीरियल बैंक के केन्द्रीय मण्डल की रचना कैसे होती है? इसके स्थानीय मण्डलों के विषय में भी जो आप जानते हों उसके विषय में भी लिखिये।

^१ यह निश्चय किया जा चुका है कि इस बैंक को सरकार खरीद लेगी।

(४) अब इम्पीरियल बैंक किन-किन कामों को कर सकता है और किनको अब भी नहीं कर सकता ?

(५) इम्पीरियल बैंक और रिज़र्व बैंक में जो समझौता हुआ था उसमें कौन-कौन सी बातें थीं ? इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है ? •

(६) इम्पीरियल बैंक की संस्थापना से कौन-कौन से लाभ हुये हैं ? रिज़र्व बैंक की संस्थापना का इसकी उपयोगिता पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

(७) इम्पीरियल बैंक जनता के लिये, अपने ग्राहकों के लिये, सम्मिलित पूँजी वाले बैंकों के लिये, सहकारी बैंकों के लिये, सरकार के लिये और विदेशी बैंकों के लिये कहाँ तक उपयोगी सिद्ध हुआ है ?

(८) इम्पीरियल बैंक की वर्तमान स्थिति के विषय में अपनी सम्मति दीजिये । भविष्य में इसकी क्या नीति होनी चाहिये ?

अध्याय १८

विनिमय के बैंक

विनिमय के बैंकों के प्रधान दफ्तर भारतवर्ष के बाहर हैं । यद्यपि इनका विशेषण यह बतलाता है कि यह केवल विनिमय का ही काम करते हैं, किन्तु ऐसा नहीं है । विनिमय का व्यवसाय करने के अतिरिक्त ये साधारण व्यापारिक बैंकों के काम भी करते हैं । इसके यह अर्थ हुये कि ये माँग पर वापिस होने की शर्त पर रुपया उधार भी देते हैं, लागत लगाते हैं, अन्य प्रकार से ऋण देते हैं, व्यापारिक साख-पत्र निकालते हैं, जमा प्राप्त करते हैं और आदत के अन्य कार्य करते हैं । किन्तु विशेषतः ये विदेशी विलों को खरीदते और डिस्काउन्ट करते हैं तथा विदेशी मुद्रायें देते हैं और यही एक ऐसी बात है जिससे यह देश के अन्य बैंकों से भिन्न है । भारतवर्ष के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की सहायता करने का काम इन्हीं के हाथ में है । बात यह है कि प्रेसीडेंसी बैंक इस काम को कर ही नहीं सकते थे । अतः, इन्हे इसमें विशिष्टता प्राप्त करने का बड़ा अच्छा अवसर मिल गया । फिर इम्पीरियल बैंक भी इसे सन् १९३४ तक नहीं कर

सकता था और जैसा कि हम जानते हैं आज तक भी वह ऐसा नहीं करता। जहाँ तक सम्मिलित पूँजी वाले बैंकों का प्रश्न है उनमें से तो कोई भी कुछ दिनों पहिले तक तो इसे कर ही नहीं सकता था।

- यह काम तभी किया जा सकता है जब इसके करने वाले के साधन बहुत अच्छे हों। हाँ, अब कुछ सम्मिलित पूँजी वाले बैंक अवश्य ऐसे हैं जो इसे कर सकते हैं किन्तु विनिमय के बैंक जो इसे बहुत दिनों से करते आ रहे हैं इससे ये उनकी बराबरी नहीं कर सकते। सेन्ट्रल बैंक ने कुछ वर्षों पहिले इसे करना प्रारम्भ किया था किन्तु वह इसमें कोई विशेष उन्नति नहीं कर सका। कुछ अन्य बैंकों ने भी इसे किया था किन्तु उन्हें भी कोई विशेष सफलता नहीं मिली। जिन स्थितियों में विनिमय के बैंक यहाँ खुले थे वह तो हमें पूर्णरूप से विदित ही हैं। अब, हमें उनकी वर्तमान अवस्था को, उनके कार्य करने के तरीकों को और उनमें जो दोष हैं उन्हें दूर करने के तरीकों को देखना है।

वर्तमान स्थिति

जैसा कि पि ले भी कहा जा चुका है इस देश में जो विदेशी बैंक काम कर रहे हैं उनकी संख्या सन् १९४७ में १५ थी। उनके सब मिला कर ८० दफ्तर थे। इनमें से सबसे अधिक काम लायड्स बैंक के हाथ में था। इसके १८ दफ्तर थे। ग्रिन्डले बैंक के १४ दफ्तर थे। नेशनल बैंक आफ इण्डिया के ११ दफ्तर थे। चार्टर्ड बैंक आफ इण्डिया, आस्ट्रेलिया और चाइना के ९ दफ्तर थे। मर्केन्टाइल बैंक के ८ दफ्तर थे। इसके अतिरिक्त चार्टर्ड बैंक आफ इण्डिया, आस्ट्रेलिया और चाइना ने इलाहाबाद बैंक से सम्बन्धित होने के कारण जिसके ७५ दफ्तर थे यहाँ के बहुत कुछ काम को ले रखा था।

क्योंकि ये बैंक अपनी भारत की स्थिति के सम्बन्ध में कोई अङ्क नहीं निकालते, अतः, इनकी यहाँ की पूँजी और सुरक्षित कोष के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। सम्मिलित पूँजी वाले बैंकों और इम्पीरियल बैंक के जमा की तुलना में इनकी जमा भी कम नहीं हैं। ये माँग पर देय जमा पर भी व्याज देते हैं। अतः, भारतीय बैंकों को भी ऐसा ही करना पड़ना है जिससे हम यह कह सकते हैं कि इस दोष का दायित्व इन्हीं के ऊपर है।

नकद में इनकी जमा का २८.५ प्रतिशत रहता है।

भारतवर्ष में इनकी लागत का पता नहीं है। अतः, हम इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कह सकते।

उनके कार्य के तरीके

इसमें हमें केवल उनके यहाँ के विदेशी व्यापार को सहायता देने के तरीकों को देखना है। बात यह है कि इनके अन्य कामों के करने के तरीके तो वही हैं जो अन्य बैंकों के हैं। विदेशी व्यापार की सहायता में दो काम आते हैं (१) भारतीय बन्दरगाहों से विदेशी बन्दरगाहों और विदेशी बन्दरगाहों से भारतीय बन्दरगाहों के बीच में जो व्यापार होता है उसकी सहायता करना, और (२) भारतीय बन्दरगाहों से अन्दरूनी शहरों और अन्दरूनी शहरों से भारतीय बन्दरगाहों के बीच में जो व्यापार होता है उसकी सहायता करना। प्रथम के सम्बन्ध का सारा काम और दूसरे के सम्बन्ध का कुछ काम इन्हीं बैंकों के हाथ में है। जैसा कि पहिले भी कहा जा चुका है इनकी अन्दरूनी शहरों में बहुत सी शाखाएँ हैं और इनसे यहाँ के कुछ बैंक भी सम्बन्धित हैं। अतः, यह दूसरे प्रकार का काम उन्हीं से कराते हैं।

भारत और विदेशों के बीच के व्यापार के हिसाब का निपटारा विलों से ही होता है। जब यहाँ से माल बाहर भेजा जाता है तब विदेश में आयात करने वाले पर एक विल लिखा जाता है अथवा जब वह अपनी साख लन्दन की विल स्वीकृत करने वाली किसी कोठी में अथवा वहाँ के किसी बैंक में खोल लेता है तब यह विल उस कोठी अथवा बैंक पर ही लिखा जाता है। फिर, इसे या तो यहाँ पर काम करने वाला कोई विदेशी बैंक खरीद लेता है, अथवा उससे इसे भुना लिया जाता है। ऐसे विल की रकम प्रायः स्टर्लिंग में होती है। अतः, यह बैंक उसका मूल्य उस दिन के विनिमय की दर से यहाँ की करन्सी में देते हैं। प्रायः यह विल अधिकार पत्रों के साथ और ९० दिन के दर्शनी होते हैं। कभी-कभी विलकुल दर्शनी अथवा ९० दिनों से अधिक के दर्शनी विल भी लिखे जाते हैं। फिर, प्रायः यह स्वीकृति पर अधिकार पत्र देने की शर्त के होते हैं, भुगतान पर अधिकार पत्र देने की शर्त के नहीं होते। बात यह है कि यहाँ पर

प्रायः सभी देशों के बैंक हैं जो अपने-अपने यहाँ के लोगों का अच्छा हवाला देते हैं जिससे वह स्वीकृति पर अधिकार पत्र देने की शर्त पर आयात कर सकते हैं। फिर, जब यह लोग किसी लन्दन की कोठी अथवा बैंक के यहाँ साख खोल लेते हैं तब तो हवाले की भी आवश्यकता नहीं रहती और स्वीकृति पर अधिकार पत्र देने की शर्त के ही बिल लिखे जाते हैं। अतः, जब न तो अच्छा हवाला मिलता है और न वह लन्दन की किसी कोठी अथवा बैंक में साख ही खोल सकते हैं, तभी भुगतान पर अधिकार पत्र देने की शर्त के बिल लिखे जाते हैं; और ऐसा बहुत कम होता है। दर्शनी बिल की अपेक्षाकृत ३ महीनों की अवधि के बिलों की दर अधिक होती है। बात यह है कि उसमें उतने दिन का ब्याज भी सम्मिलित रहता है।

विदेशी बैंक खरीदे हुये अथवा डिस्काउण्ट किये हुये बिलों को माल के आयात करने वाले के अथवा जिसके यहाँ साख खुल जाती है उसके यहाँ भेज देते हैं और वहाँ पर उसकी स्वीकृति हो जाती है। इसके बाद अधिकारी बैंक इसे खुले बाज़ार में डिस्काउण्ट करा सकते हैं और इस तरह से यहाँ पर उनकी शाख ने जितना रुपया दिया है उसके बराबर का स्टर्लिङ्ग उन्हें मिल जाता है। हाँ, यदि उन्हें द्रव्य की आवश्यकता नहीं होती अथवा वह उसे अधिक लाभ के कामों में नहीं लगा सकते तो इन बिलों को अपने ही पास रखते हैं, भुनाते नहीं।

आयात की भी दो प्रकार से सहायता की जाती है। एक तो प्रायः भारतीयों के आयात करने पर और दूसरी विदेशियों के आयात करने पर होती है। पहिले में विदेशी निर्यातकर्ता इस देश के आयातकर्ता पर ६० दिनों का दर्शनी बिल लिखकर उसे किसी ऐसे बैंक से डिस्काउण्ट करा लेते हैं जिसका काम भारत में होता है। जो बैंक डिस्काउण्ट करते हैं उन्हें निर्यातकर्ता गिरवी पत्र (Letters of Hypothecation) भी दे देते हैं, जिससे वे इन बिलों के पूर्ण अधिकारी हो जाते हैं। फिर, यह उन्हें अपनी यहाँ की शाख के द्वारा यहाँ के आयातकर्ता के यहाँ भेजवा देते हैं जो उन पर अपनी स्वीकृति दे देते हैं, किन्तु उन्हें माल के अधिकार पत्र नहीं प्राप्त होते। बात यह है कि वह तो बिलों की शर्त के अनुसार केवल उनके भुगतान पर ही दिये जा सकते हैं। किन्तु उन्हें इन्हे प्राप्त करना तो आवश्यक ही रहता है, क्योंकि इनके बिना माल तो छुड़ाया नहीं जा सकता और

माल के न छुड़ाने पर क्षति (Demurrage) इत्यादि देनी पड़ती है। अतः, वह इन्हें बैंकों से धरोहर (Trust) पर ले लेते हैं, और माल पाने पर भी उन्हें धरोहर की तरह ही रखते हैं। इसके लिये ये बैंकों को धरोहर की रसीद (Trust Receipt) दे देते हैं। अतः, जब तक बिलों का भुगतान नहीं हो जाता तब तक यह माल बैंक का ही समझा जाता है। कहना न होगा कि इस सुविधा को दे करके बैंक आयात कर्ताओं से काफी लाभ उठा लेते हैं।

दूसरा तरीका प्रायः विदेशियों के सम्बन्ध में प्रयोग में लाया जाता है। बात यह है कि भारतीयों के लिये तो बहुत कम अच्छा हवाला दिया जाता है। अतः, वह लन्दन की किसी कोठी अथवा वहाँ के किसी बैंक के यहाँ साख भी बहुत कम खोल पाते हैं। जहाँ ऐसा हो जाता है वहाँ यह तरीका भारतीयों के लिये भी प्रयोग में आता है। इस तरीके में विदेशी, निर्यातकर्ता लन्दन की उस कोठी अथवा वहाँ के उस बैंक के ऊपर बिल कर लेते हैं जिसके यहाँ यहाँ का आयातकर्ता साख खोल लेता है। यह साख किसी विनिमय के बैंक के यहाँ भी खोली जा सकती है। विदेशी निर्यातकर्ता के यहाँ जब इण्डेन्ट भेजा जाता है तभी इस साख के खोलने की सूचना भी उसके यहाँ भेज दी जाती है। ऊपर वाला धनी माल के सम्बन्ध के अधिकार पत्र पा जाने पर इस पर अपनी स्वीकृति दे देता है। अतः, निर्यातकर्ता अब इसे भुना भी सकता है। आयातकर्ता बिल के पकने की तारीख के पहिले बिल का मूल्य ऊपर वाले धनी के यहाँ भेज देता है जिससे वह उचित समय पर उसका भुगतान कर देता है।

यहाँ के आयात के सम्बन्ध के बिल प्रायः स्टिलिङ्ग ही में होते हैं। जब वह यहाँ के आयातकर्ता के ऊपर लिखे जाते हैं तब उनमें लिखने की तारीख से उनके धन के वहाँ पहुँचने की सम्भावित तारीख तक का व्याज भी सम्मिलित कर लिया जाना है। यदि वह लन्दन की किसी कोठी के अथवा बैंक के ऊपर के होते हैं तब उन्हें वहाँ पर वहाँ के डिस्काउण्ट की दर पर भी भुना लिया जाता है। कहना न होगा कि यह डिस्काउण्ट की दर प्रथम तरह के बिलों में जो व्याज सम्मिलित होता है उसकी दर की अपेक्षा कम होती है। फिर डिस्काउण्ट तो केवल उसी अवधि के लिये लिये जाता है जो इनके पकने में बाकी रहती है। इस सबसे यह स्पष्ट है कि गैरभारतीय

आयातकर्ता और ऐसे भारतीय आयातकर्ता भी जो लन्दन में साख खुलवा सकते हैं अन्य भारतीयों की अपेक्षाकृत बहुत लाभ में रहते हैं। इस सम्बन्ध में यह भी है कि जिन भारतीयों की साख लन्दन में खुल जाती है उन्हें साख खोलने वाले को साख के धन का १५ से २० प्रतिशत पहिले से दे देना पड़ता है। गैरभारतीयों को ऐसा नहीं करना पड़ता। अतः, इसका यह निष्कर्ष निकलता है कि भारतीय आयातकर्ता हर हालत में गैरभारतीय आयातकर्ता की अपेक्षाकृत हानि ही में रहता है।

जैसा कि पहिले भी कहा जा चुका है, हमारे प्रायः सभी आयात और निर्यात के बिल स्टर्लिङ्ग में लिखे जाते हैं। केवल चीन और जापान से जो व्यापार होता है उसके सम्बन्ध में ही वह अन्य करन्सियों में लिखे जाते हैं। चीन से व्यापार होने पर तो वे रुपयों में और जापान से व्यापार होने पर वे येन में लिखे जाते हैं।

साधारणतया तो भारत के व्यापार की विपमता (Balance of trade) भारत ही के पक्ष में रहती है। अतः, इन बैंकों के पास स्टर्लिङ्ग बच जाता है और उसे रिजर्व बैंक खरीद लेता है। वह इनके आधार पर यहाँ नोट निकालता है। जब कभी यहाँ के व्यापार की विपमता यहाँ के विपक्ष में होती है तब विनिमय के बैंक रिजर्व बैंक से स्टर्लिङ्ग खरीद सकते हैं और रिजर्व बैंक स्टर्लिङ्ग सिक्योरिटियों को बेचकर उन्हें स्टर्लिङ्ग दे देते हैं। इससे नोट वापिस हो जाते हैं। इस सम्बन्ध में यह याद रखना चाहिये कि रिजर्व बैंक को कोई भी बैंक १०००० अथवा उससे अधिक पाउण्ड जब चाहे तब दे सकता है और इतना ही जब चाहे तब उससे ले सकता है। इधर स्टर्लिङ्ग के स्थान पर अन्य करन्सियाँ भी दी-ली जा सकती हैं।

विदेशी बैंकों के यहाँ के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की सहायता करने के तरीकों में दोष

विदेशी बैंकों के यहाँ के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की सहायता करने के तरीकों में जो दोष है वह तो ऊपर के वर्णन से स्पष्ट ही है :—

(१) हमारे निर्यात तथा आयात दोनों के बिल स्टर्लिङ्ग में लिखे जाते हैं। अतः, उनका लन्दन के द्रव्य के बाजार में भुमाया जाना

आवश्यक हो जाता है। यदि विल रुपयों में लिखे जाने लगे तो यहाँ के द्रव्य के बाज़ार को अवश्य ही काफी प्रोत्साहन मिल जाय।

(२) भारतीय आयात कर्ताओं को प्रायः विलों के भुगतान पर अधिकार-पत्र मिलने की शर्त पर आयात करना पड़ता है। यह इस कारण है कि विनिमय के वैक उनका अच्छा हवाला नहीं देते। इससे उनकी जो हानि होती है उससे तो हम अवगत हो ही चुके हैं।

(३) जिन भारतीयों की लन्दन में साख खुल जाती है उन्हें भी इसके लिये १५ से २० प्रतिशत तक की रकम पहिले से ही देनी पड़ती है। गैरभारतीय आयात कर्ताओं को ऐसा नहीं करना पड़ता।

(४) विलों के साथ जो अधिकार-पत्र होते हैं उन्हें उनकी जाँच के लिये गैरभारतीयों के तो दफ्तरों में भेज दिया जाता है किन्तु भारतीयों को इसके लिये वैकों के दफ्तरों ही में बुलाया जाता है।

(५) विदेशी वैक यहाँ के आयात कर्ताओं को अपने-अपने यहाँ के जहाज़ों से माल मँगाने के लिये विवश करते हैं।

(६) बीमे के लिये भी वह उन्हें गैरभारतीय कम्पनियों ही के यहाँ बीमा कराने को कहते हैं।

(७) विनिमय के कन्ट्रैक्टों के देर में पूरा करने पर भारतीय आयात कर्ताओं को जुर्माना देना पड़ता है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त इनमें कुछ अन्य दोष भी हैं :—

(१) यद्यपि ये लोग यहाँ पर बहुत दिनों से काम करते आ रहे हैं तो भी इन्होंने अभी तक ऊँचे-ऊँचे पदों पर भारतीयों की नियुक्ति नहीं की है।

(२) यहाँ के वैकों ने जव-जव विनिमय का काम करना प्रारम्भ किया तब-तब इन लोगों ने उन्हें असफल बनाने का प्रयत्न किया।

(३) इन्होंने अपनी शाखायें देश के भीतरी शहरों में भी खोल दी हैं जिससे यह भारतीय वैकों से अन्य कामों में भी होड़ करते हैं।

(४) इन्होंने सम्मिलित पूँजी वाले भारतीय वैकों से भी अपना सम्बन्ध स्थापित कर लिया है जिससे ये उन्हें अपने लाभ के लिये काम में लाते हैं।

विनिमय के बैंकों को लाइसेन्स देने और उन पर अन्य प्रतिबन्ध लगाने का प्रश्न

इन बैंकों के ऊपर जो उपर्युक्त बातों का दोपारोपण किया जाता था उसके कारण इनको लाइसेन्स देने और इन पर अन्य प्रतिबन्ध लगाने का प्रश्न कई बार उठ चुका है। बैंकिंग विषयक अनुसन्धान करने वाली केन्द्रीय कमेटी ने इनके सम्बन्ध में मुक्त द्वार नीति का बड़ा विरोध किया था। जरमनी, इटली, जापान, कनाडा, इत्यादि बहुत से देशों में विदेशी बैंकों को लाइसेन्स देने का चलन है। अब जब रिज़र्व बैंक है यही इन्हें लाइसेन्स दे सकता है। जो बैंक आज-कल काम कर रहे हैं उनके हित में यह कहा जा सकता है कि उन्हें तो एक निश्चित अवधि के लाइसेन्स मिल ही जाने चाहियें और यदि रिज़र्व बैंक को उनके विरोध में कोई बात न सुनाई दे तो वह इनके लाइसेन्स को फिर बदल सकता है। लाइसेन्स की शर्तों में एक शर्त यह होनी चाहिये कि यह यहाँ का हिसाब अलग रखे। इससे भारत के बैंकों में उनकी क्या स्थिति है इस बात का भी पता लग जायगा। यह सुभाव भी रक्खा गया है कि विदेशी बैंकों के फेल होने पर भारतीय जमा करने वालों की सुरक्षा का ध्यान रक्खा जाय। किन्तु इनकी ऐसी स्थिति है कि इनके फेल होने का डर ही नहीं है। हाँ, जब कभी युद्ध छिड़ जाता है तब अवश्य कुछ डर रहता है। किन्तु जैसा कि हम जानते हैं ऐसे अवसरों पर ऐसे बैंकों की सम्पत्ति देश के बाहर नहीं भेजी जा सकती। अतः, ऐसी कोई कठिनाई नहीं पड़ सकती। दूसरे, इन्हे देश के भीतरी शहरों में शाखाएँ खोलने को मना कर देना चाहिये। यदि ऐसा न किया जाय अथवा ऐसा करने पर भी यह सुभाव रक्खा गया है कि यहाँ पर यह जितनी जमा प्राप्त कर सकते हैं उस पर बन्धन लगा दिया जाय। ऐसा भी सुभाव रक्खा गया है कि कोई भी विदेशी बैंक किसी भी भारतीय बैंक को न खरीद सके। इनके ऊपर शाखाएँ न खोलने का जो प्रतिबन्ध लगाया जायगा उसे वह भारतीय बैंकों को खरीद कर तोड़ न सके इस बात को बचाने के लिये यह बहुत ही आवश्यक है। लाइसेन्स में यह भी शर्त होनी चाहिये कि किसी शाखा में एक या दो से अधिक गैरभारतीय नहीं होने चाहियें। अन्तिम बात यह है कि उनसे ये यहाँ पर जितना लाभ कमाते हैं उस सब पर आय

कर लेना चाहिये और उसको लगाने के लिये आय कर विभाग को इनके हिसाब की जाँच करने का पूरा अधिकार मिलना चाहिये।

यदि विदेशी वैकों का लाइसेन्स देने और उनके व्यवसाय पर बन्धन लगाने का निश्चय न किया जाय तो भी उन्हें स्वयं नीचे लिखे सुधार कर लेने चाहियें जिससे वह भारतीयों में अपने प्रति विश्वास पैदा कर सके। देश के स्वतंत्र हो जाने के बाद ऐसा न करने पर वे चल ही नहीं सकते हैं।

विदेशी वैकों के काम करने के सम्बन्ध में सुझाव

(१) इन्हें भारतीय आयात कर्ताओं के सम्बन्ध के वैसे ही हवाले देने चाहिये जैसे ये गैरभारतीय आयात कर्ताओं के सम्बन्ध के देते हैं।

(२) इन्हें भारतीय आयात कर्ताओं को लन्दन की विलों को स्वीकार करने वाली कोठियों और वैकों के यहाँ उनसे १५ या २० प्रतिशत पेशगी दिलाये बिना ही शाख खोलने की व्यवस्था कर देना चाहिये और यदि ये ऐसा न कर सके तो इन्हें स्वयं ही उनके ऊपर के विल स्वीकार कर लेना चाहिये।

(३) इन्हें विलों के रुपयों में लिखे जाने से कोई रुकावट नहीं डालनी चाहिये। रिजर्व वैक की वैक दर बहुत दिनों से तीन प्रतिशत है। अतः, यदि यह विल रुपयों में लिखे जाने लगे तो देश में विल बाजार अवश्य ही बन जायँ।

(४) इन्हें अपने यहाँ भारतीयों को ऊँचे-ऊँचे पद देने चाहिये। उससे न केवल इनका काम ही बढ़ जायगा बल्कि भारतीयों से अच्छा सम्बन्ध भी स्थापित हो जायगा।

(५) इन्हें भारतीय वैकों के साथ सहयोग से काम करना चाहिये और भारतीय चीजों का बहिष्कार नहीं करना चाहिये। इन्हें भारतीय बीमा कम्पनियों के साथ समझौता कर लेना चाहिये। भारतीय जहाजों के भविष्य में चलने की भी सम्भावना है। अतः, इन्हें उनकी भी सहायता करनी चाहिये।

भारतीयों के विनिमय के व्यवसाय करने के लिये सुझाव

चाहे विदेशी वैकों को लाइसेन्स दिया जाय अथवा नहीं, चाहे उन पर कोई प्रतिबन्ध लगाया जाय अथवा नहीं, चाहे वह अपने

मे सुधार करें अथवा नहीं, भारतीयों को विनिमय का व्यवसाय अपने हाथ में तो लेना ही पड़ेगा।

यद्यपि यहाँ पर बहुत से ब्रिटिश बैंक स्थापित हो चुके थे तो भी अमेरिका, जापान, फ्रान्स, डच इत्यादि के बैंक यहाँ पर स्थापित किये गये। इसका एकमात्र कारण यह है कि किसी देश के लोगों का उस देश के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में कितना हाथ रहेगा यह बस इस बात पर निर्भर है कि उनके बैंक उन देशों में हैं अथवा नहीं जिनसे उनका व्यापार होता है। यह स्वाभाविक ही है कि किसी देश के बैंक ही उस देश के लोगों को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में सहायता पहुँचा सकते हैं। जर्मन और जापानियों का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार इसी तरह से बढ़ सका था। बैंकिंग सम्बन्धी अन्वेषण करने वाली केन्द्रीय कमेटी और उसकी सहायता को आये हुये विदेशी अनुभवी व्यक्तियों ने भी यही बात कही थी। हमारा जो व्यापारिक मिशन सन् १९४६ में चीन को गया था उसने यह कहा था कि वहाँ पर भारतीय बैंकों की बड़ी आवश्यकता है।

इसके अतिरिक्त अन्य लोगों ने अन्य सुझाव भी रखे हैं। उनमें से प्रथम तो यही था कि इम्पीरियल बैंक को यह व्यवसाय करना चाहिये। इस सम्बन्ध का उस पर जो प्रतिबन्ध लगा हुआ था उसका लोग बहुत विरोध करते थे।

प्रेसीडेंसी बैंकों के ऊपर तो यह प्रतिबन्ध इसलिये लगाया था कि इस व्यवसाय में उस समय बड़ी जोखिम थी किन्तु जब से देश में विनिमयमान हो गया है तब से यह डर नहीं है। अतः, इस प्रतिबन्ध का रखना भी अनुचित था। जो हो सन् १९३४ में इम्पीरियल बैंक के ऊपर से यह प्रतिबन्ध उठा लिया गया। जैसा कि बैंक के व्यवस्था शासक ने बैंकिंग सम्बन्धी अन्वेषण करने वाली कमेटी के सामने कहा था इस काम को करने की शिक्षा का देना बहुत आसान था। किन्तु बैंक ने अभी तक ऐसा करना प्रारम्भ नहीं किया। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि बैंक की नीति के भारतीय विरोधी होने के कारण उसके ऐसा करने से भी कोई लाभ नहीं होता, वह विदेशी बैंकों से मिल जायगा।

बैंकिंग सम्बन्धी अन्वेषण करने वाली केन्द्रीय कमेटी ने एक सरकारी विनिमय के बैंक की स्थापना करने की सिफारिश की थी।

किन्तु ऐसा करने के लिये तभी कहा गया था जब इम्पीरियल बैंक इस काम को न करे। सरकारी बैंक की पूँजी सम्मिलित पूँजी वाले भारतीय बैंकों के द्वारा खरीदी जाने की बात थी और उसकी कमी के सरकार द्वारा पूरी करने की बात थी। कुछ सदस्यों की यह राय थी कि सरकार वो ही सब हिस्से लेने चाहिये। इसके अतिरिक्त वे इस बात के विरुद्ध थे कि इम्पीरियल बैंक से विनिमय के व्यवसाय को करने को कहा जाय क्योंकि उनका यह विचार था कि उसके हिस्सों के अधिकांश गैर भारतीयों के हाथों में होने के कारण वह भारतीयों के हित में काम कर ही नहीं सकता है। वह सब हिस्सों के सरकार के द्वारा खरीदे जाने के लिये इसलिये कहते थे कि विनिमय के बैंकों ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि किमी भी भारतीय बैंक को इसमें सफलता प्राप्त करने के लिये यह आवश्यक है कि उसके साथ में सरकार की पूरी सहायता हो। इस बैंक के ऊपर साधारण बैंकिंग का व्यवसाय करने की मनाही कर देने का भी सुझाव रखा गया था जिससे कि उसकी अन्य भारतीय बैंकों के किसी प्रकार की प्रतियोगिता न हो।

कुछ लोग सरकार के द्वारा विनिमय के बैंक के खोले जाने के पक्ष में नहीं थे। कमेटी के एक सदस्य श्री सूवेदार ने इस काम को रिजर्व बैंक के एक विभाग के द्वारा करवाने का सुझाव रखा था। उनके अनुसार इस व्यवसाय का हिसाब अलग रखने की और इसकी हानि को पूरा करने के लिये इसके एक अलग सुरक्षित कोष रखने की आवश्यकता थी। उनका यह विचार था कि सरकार विनिमय का बैंक न खोलेगी। फिर, वह किसी व्यवसाय को सरकार को देने के विरुद्ध थे। उनका विचार था कि रिजर्व बैंक इस काम को भली-भाँति कर सकता है।

बैंकिंग सम्बन्धी अन्वेषणा करने वाली कमेटी का एक सुझाव और था कि इस व्यवसाय के करने के लिये एक ऐसा बैंक होना चाहिये जिसका कि नियन्त्रण भारतीयों के हाथ में भी हो और उन देशों के लोगों के हाथों में भी हो जिनसे उनका व्यापार है। वे कहते थे कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार भिन्न-भिन्न देशों के लोगों के बीच में होता है। अतः, इसकी सहायता करने वाले बैंक के लिये यह आवश्यक है कि उसके नियन्त्रण में सब देशों के लोगों के प्रतिनिधियों का हाथ

हो। ऐसे बैंक की रुपयों की पूँजी भारतीयों की और अन्य करन्सियों की पूँजी विदेशियों की होती और इसका लाभ भी सभी में बँटता।

एक मत यह भी था कि जिन ब्रिटिश बैंकों के हाथ में भारतवर्ष की विनिमय की वैकिंग का काम है उन्हें अपनी रजिस्ट्री यहीं करा लेनी चाहिये और अपनी कुछ पूँजी रुपयों में कर लेनी चाहिये। साथ ही उन्हें यहाँ पर अपना एक प्रधान कार्यालय भी रखना चाहिये। इससे ब्रिटिश हिस्सेदारों का यह लाभ होता कि वह यहाँ के व्यवसाय का लाभ उठा सकते अन्यथा उन पर प्रतिबन्ध लग जायेंगे और उनका व्यवसाय बन्द हो जायगा। इसमें इस बात की भी आवश्यकता थी कि आधे से अधिक हिस्से भारतीयों के हाथ में आ जायें। किन्तु ब्रिटेन के लोगों को यह योजना क्योंकर स्वीकृत हो सकती थी।

प्रश्न

(१) विदेशी बैंकों के हाथ में विनिमय के व्यवसाय का एकाधिपत्य क्यों है ? क्या उनको विनिमय के बैंक कहना न्याय संगत है ?

(२) विदेशी बैंकों का यहाँ के मोतरी व्यवसाय में क्या हाथ है और भारतीय वैकिंग पर उनका क्या प्रभाव है ?

(३) भारत के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की आर्थिक सहायता कैसे की जाती है ? इन सम्बन्ध में जो क्रम हो उसका विवरण दीजिये ?

(४) यहाँ के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को आर्थिक सहायता देने का जो व्यवसाय है उसमें क्या दोष है उसे समझाइये ?

(५) जो विदेशी बैंक यहाँ पर काम कर रहे हैं उनके विरुद्ध कौन सी शिकायतें हैं ? उनके सुधार के लिये अपने सुझाव रखिये।

(६) विनिमय के बैंकों को लाभेन्स देने और उन पर अन्य प्रतिबन्ध लगाने के विषय में आपकी क्या राय है ? इस सम्बन्ध में अपने सुझाव रखिये। आपकी राय में इन्हे आने को किम प्रकार से सुधारना चाहिये ?

(७) भारतीयों को विनिमय के काम में कैसे भाग लेना चाहिये ? इस सम्बन्ध में आपको जो कहना हो कहिये। अन्य लोगों की भी इस सम्बन्ध में जो राय हो वह बतलाइये।

रिज़र्व बैंक आफ इण्डिया

रिज़र्व बैंक आफ इण्डिया सन् १९३४ के अपने विधान के अनुसार १ अप्रैल सन् १९३५ को स्थापित किया गया था। यह हिस्सेदारों का बैंक है और इसकी पूँजी ५ करोड़ रु० है जो १०० सौ रुपये के ५ लाख हिस्सों में बँटी हुई है। इसके सब हिस्से जनता के हाथ में हैं केवल २२००० रुपये के हिस्से सरकार के हाथ में हैं जिसे वह इसके केन्द्रीय मंडल के सन्चालकों को उनकी न्यूनतम हिस्सों की योग्यता की प्राप्ति के लिये देती है। फिर, जब यह लोग संचालक नहीं रह जाते तब ये हिस्से फिर सरकार को दे दिये जाते हैं। बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास के हिस्सेदारों के पृथक-पृथक रजिस्टर हैं। प्रत्येक क्षेत्रफल का वर्णन प्रथम तालिका में दिया हुआ है। निम्नलिखित लोगों को इसके हिस्से नहीं मिल सकते :—

(१) जो लोग भारत अथवा ब्रह्मा के निवासी नहीं हैं अथवा हिज मजेस्टी की भारतीय अथवा ब्रह्मी रिआया नहीं हैं अथवा भारत अथवा ब्रह्मा की किसी रियासत की रिआया नहीं हैं।

(२) जो लोग संयुक्त राज्य (U. K.) के अथवा हिज मजेस्टी की किसी ऐसी डोमिनियन के अधिवासी नहीं हैं जो किसी तरह से भी हिज मजेस्टी की भारतीय और ब्रह्मी रिआया के विरुद्ध कुछ करते हैं और साधारणतया भारतवर्ष अथवा ब्रह्मा में नहीं रहते हैं तथा ब्रिटिश रिआया नहीं हैं।

(३) जो कम्पनियाँ सन् १९१३ के भारतीय कम्पनी विधान के अनुसार रजिस्टर्ड नहीं हैं अथवा जो समितियाँ सन् १९१२ के सहकारी समिति विधान के अनुसार अथवा सहकारी समितियों से सम्बन्धित किसी ऐसे अन्य विधान के अनुसार रजिस्टर्ड नहीं हैं जो ब्रिटिश भारत में लागू हैं अथवा जो बैंक सदस्य बैंक नहीं हैं अथवा जो कारपोरेशन अथवा कम्पनियाँ महासभा (Parliament) के अथवा किसी अन्य ऐसे विधान के अनुसार नहीं बनी हैं जो हिज मजेस्टी की ऐसी डोमिनियनों में लागू हैं जिनकी सरकार भारतीयों और ब्रह्मियों के विरोध में कोई कानून बनाये हैं अथवा नहीं बनाये

हैं और जिसकी ब्रिटिश भारत में अथवा ब्रह्मा में कोई शाख है अथवा नहीं है।

(४) जो कम्पनियाँ अथवा सहकारी समितियाँ कम्पनियों से अथवा सहकारी समितियों से सम्बन्धित विधान के अनुसार ब्रह्मा में रजिस्टर्ड नहीं है अथवा जो ब्रह्मा बैंक रिज़र्व बैंक के सदस्य बैंक नहीं है।

बैंक की प्रत्येक साधारण बैठक में अथवा चुनाव में प्रत्येक हिस्सेदार का पाँच हिस्सों पर एक मत और अधिक से अधिक दस मत होने है। बैंक की पूँजी केन्द्रीय मण्डल की सिफारिश पर सपरिषद् गवर्नर जनरल की और केन्द्रीय व्यवस्थापक सभाओं की स्वीकृति पर घटाई अथवा बढ़ाई जा सकती है। बैंक के हिसाब बन्द होने के छः सप्ताहों के अन्दर बैंक की साधारण वार्षिक बैठक होना आवश्यक है। इसमें वार्षिक हिसाब रक्खा जाता है। सन् १९३९ तक तो इसका हिसाब दिसम्बर के अन्त में और तब से जून के अन्त में बनता है। केन्द्रीय सरकार ने ४७ की धारा के अनुसार बैंक के बैंटनी की अधिक से अधिक दर ३ प्रतिशत रखी है और इसको सस्थापना से अब तक यही दी जा रही है। लाभ का शेपाना सरकार ले लेती है।

व्यवस्था

बैंक के व्यवसाय की व्यवस्था एक केन्द्रीय मण्डल के हाथ में है जिसमें निम्न सञ्चालक है :—

(१) एक शासक (Governor) और दूसरा उसका उपशासक (Deputy Governor) जिनकी नियुक्ति केन्द्रीय मण्डल की सिफारिश पर विचार करने के बाद सपरिषद् गवर्नर जनरल करता है।

(२) चार संचालक जिनकी नियुक्ति सपरिषद् गवर्नर जनरल करता है।

(३) आठ सञ्चालक जिनका निर्वाचन भिन्न-भिन्न रजिस्ट्रारों में दर्ज हिस्सेदार करते हैं—बम्बई, कलकत्ता, और दिल्ली प्रत्येक में से दो-दो और रंगून तथा मद्रास प्रत्येक में से एक-एक।

(४) एक सरकारी अफसर जिसको सपरिषद् गवर्नर जनरल मनोनीत करता है।

फिर, प्रत्येक क्षेत्र में एक स्थानीय मण्डल है जिसका काम केन्द्रीय मण्डल को उन बातों पर सम्मति देना है जो केन्द्रीय मण्डल उनके सामने रखता है। साथ ही केन्द्रीय मण्डल ने जो काम उन्हें करने के लिये दे रखे हैं उन्हें भी वह करते हैं। इनकी रचना निम्न प्रकार से होती है :—

(१) प्रत्येक रजिस्टर में दर्ज हिस्सेदारों के द्वारा उन्हीं में से पाँच सदस्य चुने जाते हैं।

(२) केन्द्रीय मण्डल प्रत्येक क्षेत्र में से वहाँ के स्थानीय मण्डल के लिये ऐसे तीन सदस्यों को नामजद करता है जो उन स्थानों और हितों का प्रतिनिधित्व करते हों जिनका प्रतिनिधित्व निर्वाचन से न हो सका हो। इनमें कृषि के और सहकारी बैंकों के हित का विशेष-तौर पर ध्यान रखा जाता है।

केन्द्रीय मण्डल की बैठके साल में कम से कम छः बार और प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार होनी आवश्यक है।

हिस्सों का बँटवारा

विभिन्न क्षेत्रों के बीच में प्रारम्भ में निम्न भाँति से हिस्से बाँटे गये थे :—

पश्चिमी	(बम्बई रजिस्टर)	१४०,००,००० रु०
पूर्वीय	(कलकत्ता रजिस्टर)	१४५,००,००० रु०
उत्तरीय	(दिल्ली रजिस्टर)	११५,००,००० रु०
दक्षिणीय	(मद्रास रजिस्टर)	७०,००,००० रु०
ब्रह्मा	(रंगून रजिस्टर)	३०,००,००० रु०

धनी और महत्वपूर्ण प्रान्तों में अधिक पूँजी के हिस्से देकर सबों के बीच में एक प्रकार से आर्थिक न्याय करने का प्रयत्न किया गया था। फिर, बम्बई और कलकत्ते के महत्व की एक अन्य प्रकार से भी रक्षा की गई थी जा यह था कि यदि दिल्ली के क्षेत्र में कम हिस्से लिये जायें तो उनमें से ३५ लाख के हिस्से वे और ले सकते हैं। किन्तु इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ी। दिल्ली के क्षेत्र के सब हिस्से वहीं बाँटे गये।

अधिक से अधिक लोगों को हिस्से देने का प्रयत्न किया गया था।

हाँ, किसी को पाँच हिस्सों से कम हिस्से नहीं दिये गये थे। किन्तु बाद में यह हिस्से कुछ ही हाथों में आ गये। अतः, इसको रोकने के लिये सन् १९४० में यह पास किया गया कि २६ मार्च के बाद किसी भी हिस्सेदार के नाम से २०००० से अधिक के हिस्से रजिस्टर्ड नहीं किये जायेंगे। जहाँ तक क्षेत्रों के बीच में वितरण का प्रश्न है बम्बई के क्षेत्र में हिस्से बढ़ते जा रहे हैं।

इसके काम

इसके काम दो प्रकार के हैं—(१) केन्द्रीय और (२) साधारण

[१] केन्द्रीय

[१] भारतवर्ष में नोट निकालने का एकमात्र अधिकार—

इस बैंक को भारतवर्ष में नोट चलाने का एकमात्र अधिकार दिया गया है। कुछ दिनों पहिले यह ब्रह्मा में भी नोट चलाता था। ब्रह्मा के अलग होने के बाद भी जून सन् १९४२ तक यह ऐसा करता रहा किन्तु इस समय जापानी युद्ध के कारण यह काम स्वयं भारत सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। सन् १९४६ से ब्रह्मा की सरकार अपने नोट चलाने लगी है। इधर पाकिस्तान की सरकार ने भी अपने स्वयं के नोट निकालने प्रारम्भ कर दिये हैं। नोट चलाने के लिये इसका एक अलग विभाग है जिसके सम्पत्ति और पाउने बैंकिंग विभाग से अलग रखे जाते हैं। नोट के विभाग की सम्पत्ति सोने के सिक्कों और सोने में, स्टर्लिंग सिक्कोरिटियों में, रुपयों में (जुलाई सन् १९४० से रुपयों के नोट भी सम्मिलित हैं), रुपये की सिक्कोरिटियों में और व्यापारिक बिलों में रखी जाती है। इसका कम से कम ४० प्रतिशत सोने में और स्टर्लिंग सिक्कोरिटियों में रहना चाहिये और उसमें भी सोना कम से कम ४० करोड़ रुपये का रहना चाहिये। सोना २१ रु० ३ आ० १० पाई प्रति तोला के हिसाब से लगाया जाता है। स्टर्लिंग सिक्कोरिटियों में (अ) इसके बैंक आफ इंग्लैण्ड के बैलन्स (व) दो या दो से अधिक हस्ताक्षर वाले ऐसे विनिमय के बिल जो संयुक्तराज्य में लिखे और देय हों और जो अधिक से अधिक ९० दिन के अन्दर पकने वाले हों और (स) संयुक्तराज्य की पाँच वर्षों के अन्दर पकने वाली सिक्कोरिटियाँ हो सकती हैं। सपरिषद गवर्नर जनरल की

स्वीकृति से ये पहिले ले तो तीस दिन के लिये कम की जा सकती है और फिर इसी तरह से पन्द्रह-पन्द्रह दिन के लिये और भी कम की जा सकती है। किन्तु जो कुछ कमी हो उसके लिये बैंक को ढाई प्रतिशत तक की कमी के लिये सपरिपद गवर्नर जनरल को बैंक दर से एक प्रतिशत ऊपर का कर देना पड़ता है और फिर प्रत्येक ढाई प्रतिशत कमी के लिये बैंक दर से डेढ़-डेढ़ रुपये प्रतिशत ऊपर का कर देना पड़ता है। किन्तु यह किसी स्थिति में भी छः प्रतिशत से कम नहीं हो सकता। शेष सम्पत्ति रूपों में, भारत सरकार की रूपयों की सिक्को-रिटियों में और देशी विलों और प्रण-पत्रों में रहती है।

बैंक अभी तक चालीस प्रतिशत से अधिक सोने और स्टर्लिंग सिक्कोरिटियों में रखता है।

सदस्य बैंकों की नकदी रखने का अधिकार—जैसा कि पहिले भी कहा जा चुका है कि प्रत्येक सदस्य बैंकों को इसके पास अपनी चालू जमा का कम से कम पाँच प्रतिशत और स्थायी जमा का दो प्रतिशत रखना पड़ता है। इसका उद्देश्य यह है कि यह आवश्यकता पड़ने पर उसे सदस्य बैंकों की सहायता के लिये काम में ला सके। इससे यह खुले बाजार की नीति अपना कर अर्थात् सरकारी सिक्को-रिटियों और विलों को सीधे ही खरीद और बेच कर मदम्य बैंकों की जमा को घटा-वढ़ा कर उनकी साख देने की नीति को भी प्रभावित कर सकता है। ऐसा बैंक दर नीति के द्वारा भी किया जा सकता है। किन्तु बैंक ने आज तक ऐसा नहीं किया है। २८ नवम्बर सन् १९३५ से बैंक दर ३ प्रतिशत चला आ रहा है। व्यापारिक बैंकों को उधार देने की जो इसकी नीति है उसका संकेत तो पहिले ही किया जा चुका है। अन्तिम यह कि यह कृपि सम्बन्धी साख भी उन्हीं शर्तों पर दे सकता है जिनका वर्णन कृपि सम्बन्धी साख के अध्याय में किया जा चुका है।

(३) रुपये का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य स्थिर रखने के उद्देश्य से एक निश्चित दर पर स्टर्लिंग का क्रय-विक्रय करने का दायित्व—प्रथम तो जो कोई इससे लन्दन की सुपुर्दिगी के लिये तैयार स्टर्लिंग माँगे और उसका क्रय मूल्य कानूनन ग्राह्य करन्सी में दे तो

उसे इसे प्रति रुपया कम-से-कम एक सिलिंग $५\frac{१}{४}$ पे० देना अनिवार्य है दूसरे इसे प्रति रुपये अधिक-से-अधिक १ शि० $६\frac{३}{४}$ पे० के हिसाब से स्टर्लिङ्ग खरीदना भी पड़ता है। हाँ, प्रत्येक हालत में कम-से-कम दस हजार पौ० का काम होना चाहिये। इधर इस पर सरकार की निश्चित शर्तों पर किसी भी करन्सी के क्रय-विक्रय का दायित्व रख दिया गया है। इसे सरकार की विनियम की आवश्यकताओं को भी पूरा करना पड़ता है। अतः, इसके लिये पहिले तो यह प्रति सप्ताह स्टर्लिङ्ग के क्रय के लिये टेन्डर मँगाता था। किन्तु युद्धकाल से यह सीधे ही स्टर्लिङ्ग खरीदने लगा है।

(४) भारतवर्ष में सरकार का काम करने और उसके बैलन्स को बिना व्याज के रखने का अधिकार—इसके लिये अप्रैल ५ सन् १९३५ को इसके और केन्द्रीय सरकार के बीच में एक समझौता हुआ था। यह सरकार के हिसाब में रुपया प्राप्त करता है और जो उसका बैलन्स होता है उसमें से उसके हिसाब में भुगतान देता है और उसके विनियम के भेजने के और बैंकिंग के दूसरे काम कुछ चार्ज लिये बिना ही करता है। जिन स्थानों पर उसकी शाख अथवा आदत नहीं है उनमें सरकार के लगभग १३०० खजानों और उपखजानों के द्वारा यही काम होता है। यह सरकारी ऋण की भी व्यवस्था करता है और नये ऋण निकालता है। इसके लिये इसे प्रति करोड़ सरकारी ऋण पर २०० रुपया वार्षिक छमाही कमीशन मिलता है। अपने दफ्तरों, शाखाओं, आदतों, खजानों तथा उपखजानों में यह नोट विभाग का करन्सी चेस्ट रखता है। इनमें यह सरकार के काम के लिये और जनता का रुपया इधर-से-उधर भेजने के लिये काफी नोट और रुपया रखता है।

सरकारी ऋण दीर्घकालीन अथवा अल्पकालीन दोनों हो सकते हैं। रिजर्व बैंक करन्सी और फाइनेन्स की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में इसका विस्तृत विवरण देता है। दीर्घकालीन ऋण जिन कागजों के रूप में निकाले जाते हैं वे अनेकों प्रकार के होते हैं और उन सबको सरकारी सिक्कोरिटियाँ कहते हैं।

अल्पकालीन ऋण ट्रेजरी बिलों के रूप में निकाले जाते हैं और ये प्रायः तीन महीने की अवधि के होते हैं। दिल्ली को छोड़कर रिजर्व

बैंक के अन्य सभी दफ्तरों में और बैंकिंग विभाग की शाखाओं में इनके क्रय की व्यवस्था टेण्डर पर अथवा बीच वाली दर पर की जाती है। टेण्डर माँगने का जब निश्चय हो जाता है तब टेण्डर माँगने की तारीख, टेण्डर के धन, उनकी अवधि और उनकी स्वीकृति हो जाने पर उनका रुपया जिस तारीख को देना पड़ेगा वह तारीख, इत्यादि यह सब एक विज्ञप्ति के द्वारा निकाल दिये जाते हैं और मुख्य-मुख्य बैंकों को, दलालों को तथा कोठियों को भेज दिये जाते हैं। टेण्डर में बिल की शर्तें, टेण्डर देने वाला जितने के बिल लेना चाहता है, प्रति बिल वह जितना रुपया, आना और पैसा प्रत्येक १०० रु० के लिये देना चाहता है, दिये रहते हैं। ट्रेजरी बिल केवल २५०००; ५००००; १ लाख, ५ लाख, १० लाख और ५० लाख रुपयों के होते हैं। जब बीच की दर पर ट्रेजरी बिल बेचने का निश्चय होता है तब प्रायः टेण्डर की स्वीकृति की विज्ञप्ति के साथ यह विज्ञप्ति भी दे दी जाती है।

यदि और थोड़े समय के लिये रुपयों की आवश्यकता होती है तो वह रिजर्व बैंक से वेज एण्ड मीन्स के रूप में (Wages & Means Advances) ले लिये जाते हैं।

१ अप्रैल, सन १९३७ को प्रान्तीय स्वराज्य के प्रादुर्भाव के साथ-साथ ही रिजर्व बैंक का भिन्न-भिन्न प्रान्तीय सरकारों के साथ एक समझौता हुआ था। उमी वर्ष भारतवर्ष और ब्रह्मा की सरकार के बीच में भी एक समझौता हुआ था। कुछ बातों को छोड़कर जैसे अन्तर्प्रान्तीय भुगतान के सम्बन्ध में रुपया भेजने के और वेज एण्ड मीन्स के रूप में ऋण देने के सम्बन्ध में शेष सभी बातों में यह समझौते वैसे ही थे जैसा केन्द्रीय सरकार के बीच का समझौता था। स्वतन्त्र प्रान्तों को जो अधिकार प्राप्त हैं उनके अनुसार उन्हें उसी प्रकार दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन ऋण लेने का भी अधिकार है जिस प्रकार केन्द्रीय सरकार को है। हाँ, प्रान्तीय सरकारों को बैंक के पास एक कम-से-कम बैलन्स भी रखना पड़ता है जो उनके और बैंक के बीच में समय-समय पर निश्चित होता रहता है। इसमें यदि कोई कमी हो जाती है तो वह वेज एण्ड मीन्स से पूरी की जाती है। एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त में जब रुपया भेजा जाता है तब बैंक उसी दर से कमीशन लेता है जिस दर से वह कमीशन सहकारी समितियाँ और

वैकों से लेता है। उसी प्रान्त के अन्दर रुपया भेजने के लिये कोई कमीशन नहीं लिया जाता।

यह बैंक भिन्न-भिन्न सरकारों को आर्थिक समस्याओं पर अपनी सम्मति भी देता है।

(५) कुछ साधारण कामों को करने का दायित्व—उपर्युक्त काम केन्द्रीय बैंकिंग के मुख्य काम है। इनके अतिरिक्त कुछ साधारण काम भी हैं जिन्हें यह बैंक करता है। इसमें निम्न काम हैं :—(१) भिन्न-भिन्न प्रकार की करन्सी देना, (२) रुपया भेजने की सुविधा देना, (३) निकासगृह की व्यवस्था करना, (४) आर्थिक मामलों में मन्त्रणा देना, (५) बैंकिंग के अङ्क एकत्रित करके उनको जनता के सम्मुख रखना, इत्यादि।

यदि हम पहिले (१) को अर्थात् भिन्न-भिन्न प्रकार की करन्सी देने को लें तो बैंक को नोट के लिये रुपये और रुपयों के लिये नोट देना आवश्यक है। जुलाई, सन् १९४० से रुपयों में भारत सरकार के एक एक रुपये के नोट भी सम्मिलित हैं। इसे रेजगारी भा निकातनी और वापिस लेनी पड़ती है। चूँकि रुपया, रुपये के नोट और रेजगारी बनाने का अधिकार केवल सरकार को ही है, अतः, ऐसा नियम है कि सरकार बैंक की आवश्यकता के अनुसार नोटों के विनिमय में इन्हें दे और यदि यह उसके पास अधिक हों तो उससे वापिस ले ले।

अब यदि हम (२) अर्थात् रुपया भेजने की सुविधा को लें तो जैसा कि पहिले भी कहा जा चुका है इसके लिये यह अपने नोट चलाने के विभाग के दफ्तरों में, शाखाओं में, आदतों में, खजानों में तथा उपखजानों में करन्सी के बक्स रखता है और इसमें काफ़ी नोट और सिक्के रखता है जिससे सरकारी लेन देन हो सके और रुपया इधर से उधर भेजा जा सके। पहिली अक्टूबर सन् १९४० से इसने जनता का, सहकारी बैंकों का और समितियों का, सदस्य बैंकों का, कुछ गैरसदस्य बैंकों का तथा देशी महाजनों का रुपया रियायती कमीशन लेकर इधर से उधर भेजने की एक योजना निकाली है। सहकारी बैंकों के लिये सदस्य बैंकों और गैरसदस्य बैंकों के लिये कमीशन के जो दर हैं उन्हें तो हम पीछे देख ही चुके हैं। देशी महाजनों के लिये भी वही दर हैं जो गैरसदस्य बैंकों के लिये हैं।

जनता के लिये निम्न दर हैं :—

₹००० रु० तक		₹००० रु० के ऊपर	
प्रतिशत दर	न्यूनतम चार्ज	प्रतिशत दर	न्यूनतम चार्ज
२ आ०	४ आ०	१ आ०	रु० ६—४—०
ड्राफ्ट, इत्यादि के लिये			
	रु० १—०—०		
टी० टी० के लिये			
(तार खर्च अलग)			

जहाँ तक (३) अर्थात् निकासगृह की व्यवस्था का प्रश्न है, उसे इसने कलकत्ते और कानपुर को छोड़कर उन सभी स्थानों में ले लिया है जहाँ इसके दफ्तर और शाखाएँ हैं। कलकत्ते में इसकी व्यवस्था क्लिअरिङ्ग बैंकर्स असोसियेशन की साधारण कमेटी के द्वारा नियुक्त एक निरीक्षक के हाथ में है और कानपुर में यह इम्पीरियल बैंक के हाथ में है। अन्य स्थानों में भी जहाँ रिज़र्व बैंक के दफ्तर अथवा शाखाएँ नहीं हैं उन स्थानों में भी यह काम इम्पीरियल बैंक ही के हाथ में है। यद्यपि रिज़र्व बैंक की निकासगृहों के सम्बन्ध में नियम बनाने के अधिकार प्राप्त है तो भी उसने उसकी आवश्यकता नहीं समझी है और सब निकासगृह अपने-अपने नियमों के अनुसार स्वतन्त्रतापूर्वक काम कर रहे हैं।

इसके बाद (४) अर्थात् आर्थिक मामलों पर मन्त्रणा देने का काम है। जैसा कि भिन्न-भिन्न स्थानों पर बताया जा चुका है, रिज़र्व बैंक भिन्न-भिन्न सरकारों को, सदस्य बैंकों और गैरसदस्य बैंकों को, सरकारी समितियों और बैंकों को और भूमि-वन्धक सस्थाओं को आर्थिक मामलों पर मन्त्रणा देता है। संक्षेप में यह सबों को मन्त्रणा देने के लिये तैयार है।

अन्त में (५) अर्थात् बैंकिंग सम्बन्धी अङ्क एकत्रित करने और उसे जनता के सम्मुख रखने का काम है। प्रथम तो यह अपने नोट विभाग और बैंकिंग विभाग का साप्ताहिक हिसाब केन्द्रीय सरकार के पास भेजता है और उनको पत्रों में निकालता है। दूसरे, यह सदस्य बैंकों से प्राप्त सूचना को भी एक में करके उनकी एक साप्ताहिक रिपोर्ट निकालता है। फिर, इसने अब करन्सी और अर्थ सम्बन्धी वार्षिक

रिपोर्ट तथा यहाँ के बैंकों की अङ्क सम्बन्धी तालिका निकालने का काम भी अपने हाथ में ले लिया है। अन्तिम यह है कि यह अङ्कों का एक मासिक विवरण (Monthly statistical summary) और अपनी वार्षिक रिपोर्ट (Annual Report) भी निकालता है।

(२) साधारण बैंकिंग के काम

(१) बिना व्याज के जमा प्राप्त करना और उसे वसूल करना ।

(२) भारतवर्ष में ही लिखे हुये और देय विनिमय के बिलों और प्रणपत्रों का क्रय, विक्रय तथा फिर से डिस्काउण्ट करना :—ये (१) व्यापारिक लेन-देनों से (२) खेती के कामों से अथवा कृषि के विक्रय से और (३) भारत सरकार की अथवा किसी स्थानीय सरकार की अथवा किसी ऐसी रियासत की सिक्कोरिटियों को जिन्हे सपरिषद् गवर्नर जनरल ने केन्द्रीय मण्डल की सिफारिश से स्वीकार किया है रखने से अथवा उनमें लेन-देन करने से उत्पन्न होते हैं। इनमें से प्रथम का क्रय, विक्रय और फिर से डिस्काउण्ट तो तभी किया जा सकता है जब उन पर दो या दो से अधिक ऐसे हस्ताक्षर हों जिनमें से एक किसी सदस्य बैंक का है; दूसरे का तब किया जा सकता है जब एक हस्ताक्षर किसी सदस्य बैंक का अथवा किसी ग्रान्तीय सहकारी बैंक का है और तीसरे का तब किया जा सकता है जब केवल किसी सदस्य बैंक का ही हस्ताक्षर है। इनमें पकने की अवधि रियायती दिन छोड़ कर ९० दिन से अधिक की नहीं होनी चाहिये।

(३) (अ) सदस्य बैंकों से कम से कम एक लाख की बराबरी के स्टर्लिंग खरीदना और बेचना। अब कोई भी करन्सी खरीदना और बेचना।

(ब) संयुक्तराज्य में लिखे हुये अथवा उसके ऊपर किये हुये उन बिलों का क्रय-विक्रय और फिर से डिस्काउण्ट करना जो क्रय की तारीख से ९० दिनों के अन्दर पकने वाले हों। हाँ, यदि इनका क्रय-विक्रय और फिर से डिस्काउण्ट भारतवर्ष में किया जाता है तो वह सदस्य बैंक से होना चाहिये।

(स) संयुक्तराज्य के बैंकों के पास बैलन्स रखना ।

(४) भारतवर्ष में देशी राज्यों को, स्थानीय अधिकारियों को, सदस्य बैंकों को और प्रान्तीय सहकारी बैंकों की माँग पर देय अथवा अधिक से अधिक नब्बे दिन की अवधि पर देय ऋण देना । ये स्टाकों की, कोष (Funds) की और धरोहर की सिक्क्योरिटियों की जमानत पर (अचल सम्पत्ति की जमानत पर नहीं), सोने अथवा चाँदी पर अथवा उनके अधिकार-पत्रों पर, उसके द्वारा लिये जाने योग्य विलों पर और किसी सदस्य बैंक के अथवा प्रान्तीय सहकारी बैंक के उन प्रण-पत्रों पर जो माल के ऐसे अधिकार-पत्रों के आधार स्वरूप हैं और जो नकद साख लेने के लिये अथवा वास्तविक व्यापार के लेन-देनों के सम्बन्ध में जमा से अधिक रकम निकालने के लिये अथवा कृषि सम्बन्धी कामों अथवा कृषि की चीजों के विक्रय के लिये या तो उसको हस्तान्तरित कर दिये गये हैं अथवा उसके नाम कर दिये गये हैं अथवा उसके पास गिरवी रख दिये गये हैं उनकी जमानत पर ही दिये जा सकते हैं ।

(५) सपरिषद् गवर्नर जनरल को अथवा किसी ऐसी सरकार को ऋण देना जिनकी स्वयं की प्रान्तीय आय है । किन्तु यह ऋण देने की तारीख से तीन महीनों के अन्दर वापिस हो जाना चाहिये ।

(६) अपने दफ्तरों पर देय दर्शनी ड्राफ्ट देना, अथवा बैंक पोस्ट विलों को निकालना ।

(७) संयुक्त राज्य को ऐसी सरकारी सिक्क्योरिटियों का क्रय और विक्रय करना जो क्रय की तारीख से दस वर्षों के अन्दर पकने वाली हों ।

(८) भारत सरकार की अथवा किसी स्थानीय सरकार की किसी भी अवधि की सिक्क्योरिटियों को अथवा ब्रिटिश भारत के किसी ऐसे अधिकारी अथवा भारतवर्ष की किसी ऐसी देशी रियासत की सिक्क्योरिटियों को खरीदना और बेचना जिन्हें केन्द्रीय मण्डल की सिफारिश पर सपरिषद् गवर्नर जनरल ने इस योग्य स्वीकार कर लिया है । यदि उपर्युक्त अधिकारी किसी सिक्क्योरिटी के मूलधन और व्याज के भुगतान का दायित्व ले लेते हैं तो यह उन्हें भी खरीद और बेच सकता है । इन सब सिक्क्योरिटियों का सम्मिलित मूल्य किसी एक समय पर बैंक के हिस्सों की पूँजी, सुरक्षित कोष और उसके बैंकिंग विभाग के जमा

के दायित्व के $\frac{3}{4}$ से अधिक नहीं हो सकता। जो सिक्योरिटियाँ एक वर्ष के बाद पकने वाली हैं वह पूँजी तथा सुरक्षित कोष और बैंकिंग विभाग के जमा के दायित्व से $\frac{3}{4}$ से अधिक और जो सिक्योरिटियाँ दस वर्ष के बाद पकने वाली हैं वह पूँजी तथा सुरक्षित कोष और बैंकिंग विभाग के जमा के दायित्व से $\frac{1}{4}$ से अधिक की नहीं हो सकती हैं।

(९) द्रव्य को, सिक्योरिटियों को, तथा अन्य बहुमूल्य वस्तुओं को रखना तथा उनके मूल्य को व्याज, इत्यादि के सहित वसूल करना।

(१०) यदि बैंक के हाथ में कोई चल अथवा अचल सम्पत्ति उसके पाउने के सम्बन्ध में आ जाय तो उसे बेचना और उसका मूल्य वसूल करना।

(११) सपरिषद् भारत सचिव, सपरिषद् गवर्नर जनरल, अथवा किसी स्थानीय सरकार अथवा अधिकारी अथवा भारतवर्ष की देशी रियासत की तरफ से सोने अथवा चाँदी को खरीदने और बेचने के लिये, बिलों को, सिक्योरिटियों को अथवा किसी कम्पनी के हिस्सों को खरीदने, बेचने हस्तान्तरित करने अथवा सुरक्षित रखने के लिये, किसी सिक्योरिटियों के मूलधन, व्याज अथवा लाभ की बँटनी को वसूल करने के लिये, और वसूल की हुई रकम को उसके मालिक की आज्ञानुसार भारत में अथवा कहीं भी बिलों से भेजने के लिये तथा सरकारी ऋण की व्यवस्था करने के लिये अदलतिये के तौर पर काम करना।

(१२) सोने के सिक्के और सोने को खरीदना और बेचना।

(१३) किसी अन्य देश के केन्द्रीय बैंकों के यहाँ अथवा सब केन्द्रीय बैंकों के द्वारा सजित किसी अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के यहाँ एकाउण्ट खोलना, उनसे आदत के सम्बन्ध स्थापित करना, उनके अदलतिया का काम करना और अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के हिस्से खरीदना।

(१४) एक महीने के अन्दर के लिये ऋण लेना और उसके लिये जमानत देना। यह ऋण भारतवर्ष में केवल किसी सदस्य बैंक से अपनी पूँजी की रकम तक का और बाहर किसी केन्द्रीय बैंक से किसी भी रकम तक का लिया जा सकता है।

(१५) जैसा पहिले ही कहा जा चुका है उसी के अनुसार बैंक नोट बनाना और चलाना।

(१६) कोई ऐसे काम करना जो कि इसके उपर्युक्त कामों के सम्बन्ध में होने चाहिये ।

उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि यह बैंक जनता से इस तरह से काम नहीं कर सकता कि जिससे उसकी और किसी सदस्य बैंक की प्रति-योगिता हो सके । हाँ, वह ऐसा तभी कर सकता है जब उसके केन्द्रीय मण्डल की अथवा किसी ऐसे अधिकारी की सम्मति में जिसे केन्द्रीय मण्डल ने अपनी शक्ति दे दी है देश के व्यापार, व्यवसाय, उद्योग-धन्धों और कृषि के हित में साख का नियन्त्रण करने के लिये ऐसा करना आवश्यक है । इसे कुछ काम करने की मनाही भी कर दी गई है ।

यह बैंक जो काम नहीं कर सकता

(१) यह बैंक व्यापार नहीं कर सकता और न किसी व्यवसायिक, औद्योगिक तथा किसी अन्य प्रकार की संस्था में कोई सीधा हित ही उत्पन्न कर सकता है । यदि किसी ऋण की वसूली में यह उसके पास आ जाय तो इसे उन्हे शीघ्र ही बेच देना चाहिये ।

(२) यह अपने हिस्से अथवा किसी दूसरे बैंक के अथवा किसी कम्पनी के हिस्से में तो खरीद सकता है और उनकी जमानत पर ऋण ही दे सकता है ।

(३) यह अचल सम्पत्ति के और उसके अधिकार-पत्रों के रेहन पर अथवा उनकी किसी अन्य प्रकार की जमानत पर न तो ऋण ही दे सकता है और केवल अपने काम के लिये छोड़कर न किसी अचल सम्पत्ति को खरीद ही सकता है ।

(४) माँग पर वापिस होने की शर्त के अतिरिक्त यह न तो ऋण दे सकता है, न बिल कर सकता है अथवा स्वीकार कर सकता है और न चालू खातों पर व्याज ही दे सकता है ।

बैंक का संगठन

जैसा कि प्रारम्भ में ही कहा जा चुका है यह बैंक १ अप्रैल, सन् १९३५ को संस्थापित हुआ था । हाँ, इसके विधान को तो गवर्नर जनरल की स्वीकृति ६ मार्च, सन् १९३४ ही को प्राप्त हो चुकी थी, किंतु संस्थापना के पहिले बहुत कुछ काम करना था, इसी से इतनी देर लगी । १० दिसम्बर सन् १९३४ को सपरिषद् गवर्नर जनरल ने इसके

प्रथम शासक और उपशासक नियुक्त किये और तीन दिन बाद संचालकों का केन्द्रीय मण्डल बना। कहना न होगा कि यह प्रथम केन्द्रीय मण्डल भी सपरिषद् गवर्नर जनरल ने ही बनाया था। फिर, इसके हिस्से निकाले गये और इसके साथ ही अन्य प्रारम्भिक कार्य किये गये। इसमें इसके दफ्तर और शाखाओं के लिये उपयुक्त इमारतों की व्यवस्था की गई और सरकार के केन्द्रीय विभाग से तथा इम्पीरियल बैंक से इसके लिये कुछ कर्मचारी लिये गये। फिर, इसके और सरकार के और इम्पीरियल बैंक के बीच में वह समझौते हुये जिनके विषय में पहिले ही बताया जा चुका है और कार्य करने के लिये नियम बनाये गये। इनमें बैंक के साधारण नियम थे, चुनाव के नियम थे, हिस्सेदारों की बैठकों के लिये नियम थे, सदस्य बैंकों के लिये, नोटों की वापसी के लिये, खर्च के लिये और कर्मचारियों के लिये नियम थे। जिस दिन यह संस्थापित हुआ उसी दिन से इसने नोटों का, सुरक्षित कोप रखने का, स्टर्लिङ्ग क्रय का, और सिक्क्योरिटियों की व्यवस्था का काम करन्सी कन्ट्रोलर से ले लिया और सरकार के भिन्न हिसाब रखने का, सरकारी ऋण का और निकासग्रह का काम इम्पीरियल बैंक से ले लिया। ४ जुलाई, सन् १९३५ को बैंक की पहिली दर घोषित की गई और दूसरे दिन सदस्य बैंकों ने अपना जमा का आवश्यक अङ्ग इसके पास भेजा। हाँ, बैंक के अपने नोट पहिले-पहिल सन् १९३८ ही में निकल सके।

बैंक का मुख्य दफ्तर जिसे केन्द्रीय दफ्तर भी कहा जाता है अब स्थायी रूप से बम्बई में ही है। हाँ, मंत्री का विभाग शासक के साथ-साथ कलकत्ते और बम्बई दोनों में अदलता-बदलता रहता है। इस विभाग का संबंध मण्डल की और कमेटी की साधारण वार्षिक बैठकों से रहता है। यह केन्द्रीय सरकार से करन्सी और विनिमय के, भिन्न-भिन्न सरकारों के ऋण और ट्रेजरी विलों के निकालने के और उनकी व्यवस्था के और वेज और मीन्स के ऋण के सम्बन्ध के प्रश्नों पर लिखा पढी करता है। इसके अन्य विभाग मुख्य अकाउण्टेण्ट का विभाग, कृषि सम्बन्धी साख का विभाग और विनिमय के नियन्त्रण के विभाग हैं और इनमें से प्रत्येक के उपविभाग हैं। कृषि सम्बन्धी साख के उपविभागों का और कृषि सम्बन्धी साख उपविभाग के कामों का वर्णन तो पहिले ही किया जा चुका है। वैकिंग विभाग सदस्य तथा

गैरसदस्य बैंकों की समस्त समस्याओं की व्यवस्था करता है, बैंकों और सरकार को आर्थिक समस्याओं पर सम्मति देता है और आवश्यकता पड़ने पर इनके सम्बन्ध की रिपोर्टें तैयार करता है। अङ्क और आविष्कार विभाग भिन्न-भिन्न अङ्क एकत्रित करके छपाता है। यह भिन्न-भिन्न समस्याओं पर आविष्कार भी करता है। अब, केवल मुख्य अकाउण्टेण्ट का उपविभाग और विनिमय नियन्त्रण विभाग रह गये।

मुख्य अकाउण्टेण्ट का उपविभाग नोट के विभाग का हिसाब रखता है और उसका निरीक्षण करता है। यह बैंक के व्यय की व्यवस्था भी करता है, नोटों की वापसी की अपीलें सुनता है, रुपया इधर-से-उधर भेजता है और बैंक की अन्य सब प्रकार की व्यवस्था करता है। विनिमय नियन्त्रण विभाग युद्धकाल में बना था और भारत रक्षा विधान के अनुसार बैंक को जो मुद्राओं, सोना, चाँदी, सिक्कोरिटियों और विदेशी विनिमय का नियन्त्रण करने का काम दिया गया था उसे करता है। इधर इसके लिये एक पृथक् नियम बन गया है।

बैंक के दूसरे दफ्तर और शाख या तो बैंकिंग विभाग के दफ्तर अथवा शाख है या नोट विभाग के शाख है। बैंकिंग विभाग के वर्तमान दफ्तर बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, और रंगून में हैं तथा शाख कानपुर, कराँची और लाहौर में हैं। इसी तरह से नोट विभाग की शाख बम्बई, कलकत्ता, कानपुर, कराँची,^१ लाहौर,^२ मद्रास, और रंगून^३ में हैं। अप्रैल सन् १९३६ से इसका एक दफ्तर लन्दन में भी है जो भारत सरकार के रुपये के उस ऋण की व्यवस्था करता है जो लन्दन में है और यहाँ के वहाँ के हार्ड कमिशनर का हिसाब रखता है। इम्पीरियल बैंक उन सब स्थानों में जहाँ उसके दफ्तर तो हैं, किन्तु रिजर्व बैंक के दफ्तर नहीं हैं रिजर्व बैंक का अद्वितीय है। जैसा कि पहिले भी कहा जा चुका है सन् १९४७ में इम्पीरियल बैंक के ४४४ दफ्तर थे। इसके अतिरिक्त लगभग १३०० सरकारी खजाने तथा उपखजाने थे जहाँ इसके करन्सी चेस्ट थे।

१-२ कराँची और लाहौर में १ जुलाई से पाकिस्तान रिजर्व बैंक खुल गया है।

३ इधर यह रंगून में नोट नहीं निकालता है।

बैंक की सफलताये

यह क बड़ी-बड़ी आशाओं को लेकर स्थापित किया गया था। अतः हमें यहाँ पर इस बात को भी देख लेना चाहिये कि वह सब आशाये पूरी हुई अथवा नहीं। प्रथम तो इसे नोट निकालने का एकाधिकार केवल इसीलिये दिया गया था कि जिससे इसका देश की नकदी और साख पर पूरा नियन्त्रण हो। हमें यह तो ज्ञात ही है कि इम्पीरियल बैंक इसमें इसी कारणवश सफल नहीं हो सका था कि उसे यह एकाधिकार नहीं दिया गया था। किसी देश में उसकी द्रव्य प्रणाली का नियन्त्रण तभी हो सकता है जब उसकी क्रय शक्ति पर भी नियन्त्रण हो। अब, क्योंकि कुछ देशों में तो यह क्रय शक्ति केवल नोटों अथवा नोट और सिक्कों की ही होती है। अतः, नियन्त्रणकर्ता का इनके निकालने पर भी पूरा अधिकार होना चाहिये। बस, भारतवर्ष इसी तरह का देश है। हाँ, जहाँ तक नोटों और सिक्कों के तुलनात्मक महत्व का प्रश्न है वह यह है कि इधर कुछ दिनों से नोटों का चलन तो बढ़ रहा है और सिक्कों का घट रहा है। अतः, यह कहा जा सकता है कि आजकल यहाँ पर नोटों का चलन सिक्कों के चलन की अपेक्षाकृत बहुत अधिक है। अतः, नियन्त्रणकर्ता का नोटों पर अवश्य नियन्त्रण होना चाहिये। जहाँ तक जमा की करन्सी (Cheques) के नियन्त्रण का प्रश्न है वहाँ तक इसकी भी व्यवस्था की जा रही है। किन्तु इतना सब होते हुये भी यह कहा जा सकता है कि बैंक ने इस सम्बन्ध में जिस नीति का अनुसरण किया है वह देश के बहुत हित में नहीं रही है। इसके स्वयं के लिये यह बहुत भाग्य की ही बात समझनी चाहिये कि यह ऐसे समय में स्थापित किया गया था जब मन्दी का समय बीत चुका था। यदि सन् १९२७ का बिल पास हो जाता तो सन् १९२८ में बैंक स्थापित हो जाता और शायद इसने भी सरकार की ही तरह मुक्त द्वार नीति का पालन करते हुये उम समय के संकट को असहाय की दृष्टि से देखा होता और उसकी बुराई अपने ऊपर ली होती। किन्तु सन् १९३५ में भी यहाँ की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और सन् १९३६-३७ में इस सम्बन्ध में काफी वाद-विवाद था जिसमें अधिकांश सम्मति रुपये के मूल्य को घटाने (Devaluation) के पक्ष में थी।

सन् १९३८ में भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और विनिमय की बहुत माँग थी जिससे हमारा स्टर्लिंग कोप कम होता गया। किन्तु रिजर्व बैंक ने उस ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। द्रव्य की स्थिरता के सम्बन्ध में युद्धकाल में जो स्थिति रही है उसके विषय में भी कुछ कहना व्यर्थ ही है। करन्सी के पृष्ठ पर गिरे हुये मूल्य का स्टर्लिंग रखकर इसने जो ब्रिटेन के युद्ध व्यय का बोझ भारतवर्ष के ऊपर डाल कर मुद्रा-प्रसार किया था वह तो किसी से छिपा ही नहीं है। वास्तव में इसने अपने करन्सी के कोष के ऐसे रूप को एकत्रित होने दिया जिसकी अन्तर्राष्ट्रीय क्रय शक्ति समाप्त हो चुकी थी। इसके विपरीत केन्द्रीय बैंकिंग का तो यह सिद्धान्त है कि उसे अपना सम्पूर्ण कोप द्रवित स्थिति में ही रखना चाहिये। फिर, जहाँ तक विधान ने ही नोटों के सम्बन्ध के कोप के विषय में नियम बना रखे हैं उसमें रुपये के विनिमय का मूल्य स्थिर रखने का अधिक ध्यान दिया गया है। नोटों के भुगतान का उतना विचार नहीं रक्खा गया है। शायद ऐसा मान लिया गया है कि यहाँ की जनता का उन पर पूरा विश्वास है। किन्तु यह सत्य नहीं है। वास्तव में बात तो यह है कि उसका उन पर विश्वास न होने के कारण ही यहाँ पर लोगों में सोने, चाँदी को रखने का अधिक चाव है। इससे यहाँ की बैंकिंग प्रणाली की गंभीर उन्नति नहीं हो पाई है। फिर, नोटों के और बैंकिंग के विभागों के अलग-अलग होने से भी कोई विशेष लाभ नहीं हुआ है। यह तो केवल अंग्रेजी प्रणाली की ही नकल है जिसे सन् १८४४ से जब यह वहाँ पर अपनाई गई थी इधर ब्रिटिश साम्राज्य के बाहर किसी देश ने भी अपनाने की कोई आवश्यकता नहीं समझी है। वास्तव में अब करन्सी सिद्धान्त और बैंकिंग सिद्धान्त की कोई लड़ाई है ही नहीं।

जहाँ तक जमा की करन्सी के नियन्त्रण का प्रश्न है यह कहा जा सकता है कि इस सम्बन्ध की केन्द्रीय बैंक की शक्ति एक तो इस बात पर निर्भर है कि बैंक अपनी नीति से इस पर कितना प्रभाव डाल सकते हैं और दूसरे उन पर केन्द्रीय बैंक का कितना प्रभाव पड़ता है। अब, यह तो हमें ज्ञात ही है कि हमारे यहाँ बैंकों का जमा की करन्सी निर्धारित करने में तनिक भी प्रभाव नहीं है वास्तव में यह साख की उत्पत्ति पर निर्भर रहता है। यहाँ पर बाजार प्रायः बैंकों से ऋण नहीं लेता। अतः, साख की उत्पत्ति का प्रश्न ही नहीं उठता और फिर

जमा की करन्सी के निर्धारित होने का प्रश्न भी नहीं उठता। जहाँ तक रिजर्व बैंक और सदस्य बैंकों के सम्बन्ध का प्रश्न है उस पर इस समय कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि रिजर्व बैंक के उत्पत्ति के समय से ही यहाँ के द्रव्य के बाजार की स्थिति अच्छी रही है और द्रव्य काफी रहा है। परीक्षा का समय तो भविष्य में आने वाला है और जब वह आवेगा तो क्या होगा यह देखना है। हाँ, बैंक के पास इसके लिये उपयुक्त हथियार है जैसे बैंक दर नीति और बाजार में सीधे काम करना, इत्यादि।

इसे प्रत्येक बैंक के ऊपर अच्छी नीति को काम में लाने का दबाव डालना चाहिये और यह इसने अपने सात दिसम्बर १९३८ के उस स्मरण पत्र के द्वारा किया है जो सदस्य बैंकों को डिस्काउण्ट और ऋण देने के सम्बन्ध में निकाला गया था और जिसमें यह कहा गया था कि जब बैंक उन्हें ऋण देगा तो केवल इसी बात का ध्यान नहीं रखेगा कि वह कैसी जमानत दे रहे हैं बल्कि इस बात को भी देखेगा कि प्रार्थी बैंक के लागत कैसे हैं, उसके काम कैसे होते हैं, उदाहरण के लिये वह जमा प्राप्त करने के लिये अधिक व्याज तो नहीं देता है, साधारण स्थिति में भी जब बाजार में काफी रुपया रहता है तब उससे ऋण तो नहीं लेता है, और वह अपनी स्थिति से अधिक व्यवसाय तो नहीं करता है और माल और साख-पत्रों के सट्टे के लिये साख तो नहीं देता है अथवा बहुत अधिक बिना जमानती व्यवसाय तो नहीं करता है। इससे स्थिति तो बहुत कुछ सुधर गई है। फिर, यह जब चाहे तब किसी भी बैंक से कोई भी सूचना माँग सकता है और उसका निरीक्षण कर सकता है। इधर इसने गैरसदस्य बैंकों से भी कुछ सूचना लेना प्रारम्भ कर दिया है और कुछ से तो इसका सीधा सम्बन्ध भी हो गया है।

इस बैंक से यह भी आशा की जाती थी कि यह देशी महार्जनों को भी अपने नियन्त्रण में ले आवेगा और कृपि के अर्थ की मशीनरी का सुधार कर लेगा। साथ ही इससे यह भी आशा की जाती थी कि यह कृपि के और अपने कामों के बीच में निकट सम्बन्ध स्थापित करने के लिये कुछ सुझाव रखेगा। वास्तव में १५ वीं धारा से इसे ऐसा करने के लिये आवश्यक कर दिया गया था। किन्तु जैसा कि पहिले भी कहा जा चुका है इसने इस ओर सिवाय अपनी

प्रारम्भिक और वैधानिक रिपोर्टों को देने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं किया है।

इसके खुलने के पहिले तेजी और मन्दी के समय के व्याज के दरों में बड़ा अन्तर रहता था। यह तो पहिले ही बताया जा चुका है कि इम्पीरियल बैंक को इस बात का अधिकार होते हुये भी कि वह सरकार के करन्सी विभाग से आवश्यकता पड़ने पर १२ करोड़ ६० की करन्सी निकलवा ले वह इस अन्तर को दूर नहीं कर सका। किन्तु यह बैंक अवश्य इसमें बहुत कुछ सफलता प्राप्त कर सका है। इसका बैंक दूर नवम्बर सन् १९३५ से ही ३ प्रतिशत रहा है और यह तेजी के समय की करन्सी की सारी माँग को अपने बैंकिंग विभाग की नोटों की सम्यक्ति को कम करके पूरी कर लेता है। यह ऐसा कहाँ तक करना है इस बात का पता उसके नोटों की अधिक से अधिक और कम से कम रकम के बीच की अन्तर का पता लगाकर मालूम किया जा सकता है। वास्तव में यह उस १२ करोड़ रुपये से अधिक रहता है जितने का अन्तर इन दोनों समयों में मन्दी के पहिले के काल में अर्थात् सन् १९२१-२९ के बीच में इम्पीरियल बैंक की नकदी के बैलन्स में हो जाया करता था।

यह बैंक बैंकों के फेल होने को रोकने के उद्देश्य से भी स्थापित किया गया है। ऐसी आशा की जाती है कि यह आवश्यकता पड़ने पर उन बैंकों की रक्षा करेगा जो हमेशा अपनी स्थिति अच्छी रखते हैं। इसके पास जो केन्द्रित कोष हैं और नोट निकालने के अधिकार हैं उनसे यह ऐसा बहुत आसानी के साथ कर सकता है। किन्तु इसने त्राव्कोर नेशनल ऐण्ड क्लिन बैंक के सम्बन्ध में जिसके ऊपर सन् १९३८ में सकट पड़ा था ऐसा नहीं किया और वह फेल हो गया। उसके फेल होने के कुछ दिन पहिले उसने इससे आर्थिक सहायता माँगी थी और इसने उसे यह देने से इसलिये अस्वीकृत कर दिया था कि यह इसके पहिले उसके हिसाब-किताब, इत्यादि का निरीक्षण करना चाहता था। इसमें सन्देह नहीं कि यह केवल उसके बड़े-बड़े ऋणों की ही जाँच करता। किन्तु जैसा कि उक्त बैंक की तरफ से कहा गया था और वह ठीक ही था ऐसा करने से उसको वदनामी हो जाती जिससे और भी बुराई पैदा हो जानी। यहाँ पर यह कह देना भी आवश्यक है कि अब तो बैंक जब चाहें तब किसी बैंक की भी जाँच

कर सकता है। फिर, इसने उसे इसलिये भी ऋण नहीं दिया कि इस बात का भी निश्चय नहीं था कि उसके कौन से पाठने ब्रिटिश भारत के लेनदारों के ऋण के भुगतान में और कौन से देशी रियासत के लेनदारों के ऋण के भुगतान में काम में आ सकेंगे। हाँ, अब तो स्थिति बहुत ही बदल गयी है। उन रियासतों के बैंक भी इसके नियन्त्रण में आ गये हैं जो भारत के यूनियन में सम्मिलित हो गई हैं।

फिर, जैसा कि पहिले भी कहा जा चुका है इस बैंक ने युद्धकाल में इस तरह से काम किया था कि ब्रिटेन का बाहरी व्यय भारत से पूरा होता रहा और यहाँ पर मुद्रा प्रसार होता रहा जिससे यहाँ के लोगों को बड़ी कठिनाइयाँ उठानी पड़ी। इसके अतिरिक्त इसने डालर कोप का प्रयोग भी इस तरह किया कि जिससे यहाँ के लोगों की बड़ी हानि हुई। फिर, इसने ब्रिटिश साम्राज्य के और सशुक्र राष्ट्र अमेरिका के सोने के मुनाफाखोरों का अढ़तिया बन कर यहाँ पर सोना बहुत ऊँचे दामों पर बेचा। सक्षेप में यह कहा जा सकता है कि यह सरकारी आज्ञा को बड़ी अच्छी तरह से मानता रहा। इसने उसे अच्छी सलाह नहीं दी और यदि वह दी भी तो मानी नहीं गई। वास्तव में ऐसा नहीं होना चाहिये था। सरकार का अढ़तिया तो कोई भी बन सकता है, इम्पीरियल बैंक ही यह काम करता आ रहा था।

बैंक दर नीति

साख के नियन्त्रण के लिये यहाँ पर बैंक दर नीति का अख केवल इम्पीरियल बैंक के खुलने पर ही पहिले-पहिल उसको दिया गया था। किन्तु कई कारणों से यह बहुत उपयोगी नहीं सिद्ध हो सका। प्रथम तो जैसा कि पहिले भी कहा जा चुका है इम्पीरियल बैंक स्वयं ही इसे साख नियन्त्रण के लिये काम में नहीं लाना चाहता था वह तो लाभ कमाने का उद्देश्य ही सामने रखता था और इसी से यदि अपनी बैंक दर में कुछ हेर-फेर करता था तो इसी दृष्टि से करता था। फिर, इस नीति का प्रभाव तभी पड़ता है जब बैंक केन्द्रीय बैंक के ऊपर साख उत्पन्न करने के लिये निर्भर रहते हैं। किन्तु जैसा कि पहिले भी कहा जा चुका है यहाँ यह बात नहीं थी। यहाँ के बैंक तो इम्पीरियल बैंक से बहुत कम ऋण लेते थे क्योंकि न तो वह इसको अपने जिलों को ही देना चाहते थे और न इससे वैसे ही ऋण लेना

चाहते थे। विलों से इसे उनके ग्राहकों का नाम मालूम हो जाता था और ऐसा होने से इसके उन ग्राहकों का व्यवसाय अपने हाथ में ले लेने की आशंका रहती थी। जहाँ तक ऋण का प्रश्न था, ऐसा करने से उन्हें इस बात की अशंका रहती थी कि कहीं यह उन्हें वदनाम न कर दे। फिर, यह उनमें से बहुतों को तो संकट के समय सहायता भी नहीं करता था। अन्तिम बात यह कि यहाँ पर बाजार भी बैंकों से बहुत सहायता नहीं लेते थे। जहाँ तक होता था वह स्वयं अपनी आवश्यकता पूरी कर लेते थे। फिर, इनमें से प्रत्येक के व्याज की दर उसकी अपनी स्थिति के अनुसार रहती थी और उसमें भी चलन का बड़ा हाथ रहता था। द्रव्य की माँग और पूति का बहुत कम प्रभाव पड़ता था। इंगलिस्तान में जैसा कि ७ वे अध्याय में बताया जा चुका है बैंक दर और व्याज की अन्य दरों का बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है किन्तु भारतवर्ष में न तो यह पहिले ही था और न अब ही है।

फिर, हम यह भी देख चुके हैं कि विदेशों में बैंक दर वह दर है जिस पर केन्द्रीय बैंक प्रथम श्रेणी की जमानतों पर ऋण देते हैं अथवा प्रथम श्रेणी के विलों को डिस्काउंट करते हैं। किन्तु इम्पीरियल का दर केवल प्रथम प्रकार का ही दर था। हुण्डियों को डिस्काउंट करने के लिये एक दूसरा दर था जिसे डिस्काउंट दर कहते थे। अब, यह दर कभी-कभी तो बैंक दर से ऊँचा और कभी-कभी नीचा रहता था। बैंक दर सप्ताह में एक बार निर्धारित होता था और प्रायः उसके बीच में बदलता नहीं था, किन्तु हुण्डी दर बाजार की दैनिक स्थिति के अनुसार बदलता-बदलता रहता था।

हाँ, रिजर्व बैंक का बैंक दर अवश्य ऐसा है जिस पर वह प्रथम श्रेणी की जमानतों पर ऋण देने के लिये तैयार रहता है और साथ ही प्रथम श्रेणी के विलों को भी डिस्काउंट करता है। यह अवश्य ही अन्य देशों के बैंक दर की तरह है, किन्तु यहाँ स्थिति भिन्न है। जैसा कि हमें ज्ञात है हमारे यहाँ विल तथा हुण्डियाँ बहुत नहीं चलतीं। अतः, उन्हें चलाने के लिये यह आवश्यक है कि डिस्काउंट की दर व्याज की दर से भिन्न हो और कुछ कम भी हो। कहना न होगा कि यह प्रचलित प्रथा के विपरीत होगा किन्तु देश के लिये लाभप्रद होने के कारण अवश्य ही माना जाना चाहिये।

जब रिजर्व बैंक खुला था, यह सोचा गया था, कि कई कारणों से

इसका बैंक दर इम्पीरियल बैंक के बैंक दर की अपेक्षाकृत अधिक प्रभावशाली होगा। प्रथम तो सदस्य बैंकों को इसके पास अपनी स्थायी तथा चालू जमा का क्रमशः कम से कम ५ प्रतिशत तथा २ प्रतिशत अवश्य बैलन्स के रूप में रखना पड़ता है और यदि वह ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उन्हें कमी पर बैंक दर से कुछ अधिक दर के हिसाब से व्याज देना पड़ता है। इससे यह सोचा गया था कि बैंक बैंक दर से नीची दर पर ऋण नहीं देंगे और साथ ही इससे ऊंची दर पर जमा नहीं प्राप्त करेंगे। फिर इन बैंकों को इससे अपने बिलों को भुनाने में जरा भी सकोच नहीं हो सकता क्योंकि इसके उनके ग्राहकों के नाम जान लेने से उनकी प्रतियोगिता करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसके अतिरिक्त बैंकों को जब कोई ऋण न मिले तब उन्हें इससे ऋण मिलने की आशा रहती है और यह ऐसा इसलिये कर भी सकता है कि एक तो इसके पास बहुत से कोप केन्द्रित रहते हैं और दूसरे यह अपने नोट चलाता है। किन्तु इसमें एक बड़ा दोष है अर्थात् देशी महाजन इसके नियन्त्रण में नहीं हैं। वही तो यहाँ के व्यापार, उद्योग-धन्धों और व्यवसाय, इत्यादि को आर्थिक सहायता देते हैं। अतः, जो केन्द्रीय बैंक साख पर नियन्त्रण रखना चाहता है उसे इन्हें अवश्य अपने नियन्त्रण में रखना चाहिये।

साख का नियन्त्रण करने की किसी केन्द्रीय बैंक की शक्ति दो बातों पर निर्भर रहती है—एक तो यह कि बाजार वाले कहाँ तक अपने स्वयं के साधनों पर और कहाँ तक बैंकों के साधनों पर निर्भर रहते हैं और दूसरे यह कि बैंक कहाँ तक अपने ऊपर और कहाँ तक केन्द्रीय बैंक के ऊपर निर्भर रहते हैं। यहाँ पर बैंक भी साख की उत्पत्ति के लिये केन्द्रीय बैंक के ऊपर बहुत निर्भर नहीं रहते। उन्हें अपनी जमा का एक बहुत थोड़ा अंश इसके पास जमा करना पड़ता है। अतः, वह यह आसानी से कर सकते हैं। इसकी संस्थापना के समय से ही द्रव्य के बाजार की स्थिति अच्छी रही है। अतः, वे साख के लिये प्रायः इसके पास नहीं आये हैं। जैसा कि पहिले भी कहा जा चुका है कि बैंक दर प्रभावशाली अस्त्र होगा अथवा नहीं इस बात की जाँच का समय अभी नहीं आया है। किन्तु तब तक इसके सब दोष दूर हो जाने चाहियें।

खुले बाज़ार में काम करने की नीति

रिज़र्व बैंक खुले बाज़ार में भी काम कर सकता है, अर्थात् देश के व्यापार, व्यवसाय, उद्योग-धन्धों और कृषि के हित में साख नियन्त्रण करने के उद्देश्य से आवश्यकता पड़ने पर बाज़ार में प्रत्यक्ष रूप से काम कर सकता है। किन्तु ऐसा करने की आवश्यकता अभी तक नहीं पड़ी है। जो हो, हमें इसके संबन्ध के नियमों को भली-भाँति समझ लेना चाहिये ताकि हमें यह मालूम हो सके कि इसका यह अधिकार अपने उद्देश्य तक पहुँचने में कहाँ तक सफल हो सकता है।

खुले बाज़ार में काम करने की नीति का प्रभाव इस बात पर निर्भर रहता है कि केन्द्रीय बैंक इस काम के लिये कितने साधन एकत्रित कर सकता है, कितनी और किस तरह की सम्पत्ति वह रख सकता है और जिस बाज़ार में काम करना है उसका कैसा संगठन है।

रिज़र्व बैंक के पास जो साधन हैं वह (१) पूँजी और सुरक्षित कोष के, (२) सरकार की नकदी के, (३) सदस्य बैंकों की नकदी के, (४) विलों की वसूली और द्रव्य को इधर से उधर भेजने के लिये जिस सीमा तक इसका प्रयोग किया जाता है उनके और (५) नोटों के चलाने के हैं। जहाँ तक (१) पूँजी और सुरक्षित कोष का सम्बन्ध है हमें यह तो मालूम ही है कि वह १० करोड़ रुपया है। इम्पीरियल बैंक की पूँजी और सुरक्षित कोष इससे अधिक है। हाँ, इसकी पूँजी और कोष भी आवश्यकता पड़ने पर बढ़ाई जा सकती है। जहाँ तक (२) सरकारी नकदी का प्रश्न है वह तो प्रत्येक वर्ष में, माह में, दिन को बदलती रहती है। उसके पूर्ण धन और समय का खुले बाज़ार में काम करने की शक्ति पर बड़ा भारी प्रभाव पड़ सकता है। जहाँ तक (३) सदस्य बैंकों की नकदी का प्रश्न है वह भी बराबर बदलती रहती है। प्रायः बैंकों को जितनी नकदी इसके पास रखनी चाहिये उससे अधिक वे इसके यहाँ नकदी रखते हैं। किन्तु ऐसा भी होता था कि बैंक कम नकदी रखकर जुर्माना देकर काम चला लेते थे। अतः, इधर ऐसे नियम भी बन चुके हैं कि यह बैंक जब चाहे तब ऐसे बैंकों को अधिक जमा लेने से रोक दे। जहाँ तक (४) का अर्थात् इस बात का प्रश्न है कि विलों की वसूली तथा द्रव्य को

इधर से उधर भेजने के लिये इसका कहाँ तक प्रयोग किया जाता है यह तो पहिले ही बताया जा चुका है कि बैंक ने इधर द्रव्य भेजने की बड़ी सुविधाये दे दी है। किन्तु विलों के प्रयोग की आदत को बढ़ाने का अब भी प्रश्न है। प्रायः द्रव्य टी० टी० से भेजा जाता है; दर्शनी ड्राफ्ट कम प्रयोग में आते हैं। वास्तव में दर्शनी ड्राफ्टों से ही द्रव्य भेजे जाने पर ही बैंक की खुले बाजार में काम करने की शक्ति निर्भर है और इस समय इस मद में इसके पास उतना द्रव्य नहीं रहता है जितना कि इस काम में सहायता पहुँचा सकता है। जहाँ तक (५) अर्थात् नोटों को निकालने का प्रश्न है उसके सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि इसके विधान में इसको काफी लोचप्रद बना दिया गया है।

बैंक के पास जो सम्पत्ति रह सकती है वह निम्नाङ्कित हैं:—(१) संयुक्त राज्य की सरकार के वह साख-पत्र जो क्रय के दस वर्षों के अन्दर पकने वाले हों (यह कितने रुपयों के ही रखे जा सकते हैं) और (२) भारत सरकार अथवा प्रान्तीय सरकारों के कभी भी पकने वाले साख-पत्र अथवा किसी स्थानीय अधिकारी के अथवा देशी रियासत के ऐसे ही साख-पत्र (इनका मूल्य इसकी पूँजी, सुरक्षित कोष और जमा के ३ के बराबर रह सकता है)। हाँ, इनमें से १ वर्ष के बाद पकने वाले और दस वर्षों के भीतर पकने वाले साख-पत्रों का मूल्य इसकी पूँजी और सुरक्षित कोष तथा इसकी जमा के क्रमशः ३ और ३ के बराबर रह सकता है।

इससे यह स्पष्ट है कि दीर्घकालीन (१० वर्षों से अधिक के) साख-पत्र, अल्पकालीन (१ वर्ष और १० वर्षों के बीच के) साख-पत्रों से कम मूल्य के रह सकते हैं। वान यह है कि दीर्घकालीन साख-पत्रों का मूल्य कम घटता-बढ़ता है, अतः वे अधिक द्रवित होते हैं।

बैंक के पास जिनके साख-पत्र रहते हैं अथवा बाजार में मिल पाते हैं उतनी ही करन्सी का परिमाण घट-बढ़ सकता है। इस युद्ध में करन्सी इसीलिये बढ़ पाई है कि स्टर्लिङ और रुपयों दोनों के साख-पत्र प्राप्त थे। इसी तरह से इन्हे बाजार से वेचकर मुद्रा संकुचन भी किया जा सकता है।

अब, हमें उस बाजार के विषय में समझना है जिसमें बैंक काम कर सकता है। यहाँ के मुख्य स्टॉक एक्सचेंज बम्बई और कलकत्ते के

है। किन्तु इनके कुल सदस्यों की संख्या लन्दन और न्यूयार्क के स्टॉक एक्सचेंजों के सदस्यों की संख्या की तुलना में कुछ नहीं है, अतः, इनमें काम करने का उतना प्रभाव नहीं पड़ सकता है। हाँ, यह अवश्य है कि बैंक की बहुत कुछ सम्पत्ति के स्टर्लिङ्ग साख-पत्रों में होने के कारण जिनमें विदेशों में भी काम किया जा सकता है कुछ कठिनाई कम हो जाती है।

वैलन्स शीट

रिज़र्व बैंक की वैलन्स शीट दो भागों में विभक्त रहती है—(१) नोट के विभाग में और (२) बैंकिंग के विभाग में। यह सामाहिक होती है। नीचे एक नमूना दिया हुआ है:—

रिज़र्व बैंक आफ इण्डिया

(अ) जुलाई २, १९४८

नोट विभाग

(००० छोड़ करके)

रु०

रु०

दायित्व	पाउने
निकाले हुये नोट :—	सोना ४२,७१,९१
बाहर १२६९,८८,२२	स्टर्लिङ्ग साख-पत्र ११००,८०,४७
बैंकिंग विभाग में २९,६४,७३	११४३,५२,३८
	रुपये—
	भारतवर्ष के ४१,८५,७६
	रुपयों के साख-पत्र ११४,१४,८१
	देशी बिल, इत्यादि
१२९९,५२,९५	१२९९,५२,९५

सोने और स्टर्लिङ्ग साख-पत्रों का सम्पूर्ण दायित्व से अनुपात
८७ ९९५ प्रतिशत

बैंकिंग विभाग

(१०० छोड़ करके)

₹०	₹०
पूँजी ५००००	नोट २९,६४,७३
सुरक्षित कोष ५००००	रुपये ३,८८
जमा—	रेजगारी १,१०
(अ) केन्द्रीय सरकार की २१४,५१,६७	क्रय किये हुये और डिस्काउण्ट किये हुये बिल—
(ब) अन्य सरकारों की १९,१५,८९	(अ) देशी १५,००
(स) बैंकों की ७९,५९,७४	(ब) विदेशी ...
(द) अन्य ४७,८२,६०	(स) सरकारी ट्रेजरी बिल्स १,६२,५९
देय बिल्स ३,९४,०३	विदेशों में बैलन्स ३०१,४०,४०
अन्य दायित्व १४,५९,१४	सरकार के ऋण १०,००
	अन्य ऋण
	लागत ५०,८६,५२
	दूसरी सम्पत्ति ४,९९,१५
३८८,८३,०७	३८८,८३,०७

प्रश्न

(१) रिजर्व बैंक के हिस्से कौन लोग नहीं खरीद सकते ? क्या इस सम्बन्ध में किसी अन्य प्रतिबन्ध की आवश्यकता है ?

(२) रिजर्व बैंक के केन्द्रीय और स्थानीय मंडलों की रचना पर एक छोटी सी टिप्पणी लिखिये ।

(३) रिजर्व बैंक विधान के दोष बताइये और यह बतलाइये कि इस सम्बन्ध में क्या करना चाहिये ।

(४) रिजर्व बैंक के केन्द्रीय और व्यापारिक बैंकिंग के कामों का एक संक्षिप्त वर्णन दीजिये । यह कौन से विशेष काम नहीं कर सकता है ?

(५) रिजर्व बैंक की स्थापना के पहिले कौन-कौन से प्रारम्भिक काम करने पड़े थे । इसके दफ्तरों और विभागों के संगठन के विषय में आप जो कुछ जानते हो बताइये ?

(६) रिजर्व बैंक ने अब तक क्या-क्या किया है ? आपकी समझ में अब उसको क्या करना चाहिये ?

(७) आपकी समझ में रिजर्व बैंक को साख के नियन्त्रण के लिये जो अधिकार दिये गये हैं वह काफी हैं या नहीं ? इस सम्बन्ध में आपके क्या सुझाव हैं ?

(८) रिजर्व बैंक की एक कल्पित बैलन्स शीट बनाइये और उसके प्रत्येक मद को समझाइये ?

अध्याय २०

दोष और उन्हें दूर करने के उपाय

पिछले अध्यायों में भारतीय बैंकिंग के क्रमिक विकास का दिग्दर्शन कराया गया है । अब, इस अध्याय में हम उसके दोषों का और उन्हें दूर करने के उपायों का अध्ययन करेंगे ।

एक अच्छे संगठित द्रव्य के बाज़ार की कमी—हम यह तो ज्ञात ही है कि भारतवर्ष के द्रव्य के बाज़ार में निम्न संस्थायें हैं :— रिजर्व बैंक आफ इण्डिया, इम्पीरियल बैंक आफ इण्डिया, सम्मिलित पूँजी के भारतीय बैंक, विनिमय के विदेशी बैंक, साख-सम्बन्धी सह-कारी संस्थायें, भूमि-बंधक बैंक, ऋण के दफ्तर, निधि, चिट फण्ड, और ऋणदाताओं से लेकर अनेकों प्रकार के देशी महाजन जिन्हें बैंकर्स भी कहते हैं । इनके अतिरिक्त कुछ दिनों पहिले तक सरकार भी काफी भाग लेती थी । निसंदेह उसकी नीति तो अब रिजर्व बैंक

के हाथ में है, किन्तु आज भी उसके ढाकघर है जो कि बैंकिंग का काफी काम करते हैं। वह बचत और लागत के लिये जो कुछ करते हैं उसका अध्ययन तो हम कर चुके हैं। उनके अतिरिक्त वे द्रव्य को इधर से उधर भेजने की और बी० पी० से इसकी वसूली करने की सुविधा भी देते हैं।

रिजर्व बैंक की संस्थापना के पहिले इन सब के बीच में किसी प्रकार की साम्यता नहीं थी।

उन्हें एक नेता की भी आवश्यकता थी। रिजर्व बैंक की संस्थापना से यह कठिनाइयाँ तो कुछ अशों तक दूर हो गई हैं। हमें मालूम है कि गौरसदस्य बैंकों के ऊपर इसका कोई विशेष नियन्त्रण नहीं है। इसके अतिरिक्त ऋण के दफ्तर चिट फंड, निधि और ऋणदाताओं के सहित बहुत से देशी महाजन हैं जिनके ऊपर इसका बिल्कुल भी नियन्त्रण नहीं है। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि द्रव्य का भारतीय बाजार दो संगठनों को मिलाकर बना है—एक आधुनिक बैंकों का और दूसरा देशी महाजनों का, और इनसे से आधुनिक बैंकों का संगठन कुछ को छोड़कर रिजर्व बैंक के नियन्त्रण में है किन्तु देशी महाजन बिल्कुल स्वतन्त्रतापूर्वक काम करते हैं। जहाँ तक इनकी पारस्परिक साम्यता का प्रश्न है वह भी आदर्शरूप में नहीं है।

इन दोषों को दूर करने के लिये पहिले ही कुछ सुझाव रखे जा चुके हैं। इसमें देशी महाजनों को रिजर्व बैंक से सम्बन्धित करना, रिजर्व बैंक का गौरसदस्य बैंकों के ऊपर नियन्त्रण बढ़ाना और भिन्न-भिन्न वर्गों में साम्यता उत्पन्न करना सम्मिलित है।

बिल के बाज़ार का न होना

यहाँ के द्रव्य के बाज़ार का एक अन्य दोष बिल के बाज़ार का न होना है। इसके निम्न कारण हैं।

(१) भारतवर्ष के बैंक सरकारी साखपत्रों में लागत लगाना अधिक पसन्द करते हैं। रिजर्व बैंक की संस्थापना के पहिले उन्हें इस बात का विश्वास ही नहीं था कि इम्पीरियल बैंक उनकी हुण्डियों को डिस्काउंट कर देगा। उसने उनका कोई स्तर तो नहीं रक्खा था और किसी भी हुन्डी को स्तर के अनुसार नहीं है कह करके

डिस्काउण्ट करने से इनकार कर देता था। फिर, बैंक स्वयं भी उससे हुण्डियों को डिस्काउण्ट कराने के स्थान पर सरकारी साख-पत्रों के अधिधार पर ऋण लेना अधिक पसन्द करते थे क्योंकि हुण्डियों के भुनाने में उन्हें इस बात का डर रहता था कि इम्पीरियल बैंक उनके ग्राहकों का नाम जान जाने के बाद उनके प्रतिद्वन्दी होने के नाते कहीं लाभ न उठा ले। इसके अतिरिक्त यदि इम्पीरियल बैंक सरकारी साख-पत्रों के आधार पर ऋण देने को मना कर देता था अथवा वही इसके लिये इम्पीरियल बैंक के पास नहीं जाना चाहते थे तो इन्हे बाजार में बेचा जा सकता था। हाँ, रिजर्व बैंक की स्थापना से अब यह सब कठिनाइयाँ दूर हो गई हैं, किन्तु पुरानी प्रथा तो चल ही रही है। ऐसा विशेषतः इसलिये है कि रिजर्व बैंक ऋण देने में और विलों को डिस्काउण्ट करने में एक ही दर चार्ज करता है। जैसा कि पहिले भी कहा जा चुका है ऋण देने में डिस्काउण्ट करने की अपेक्षाकृत कुछ ऊँची दर चार्ज करने से डिस्काउण्ट करने का काम बढ़ जायगा। बैंक दर यहाँ पर केवल डिस्काउण्ट की दर होनी चाहिये।

सरकारी साख-पत्रों की लोकप्रियता का एक अन्य कारण उनके द्वारा काफी ऊँची आय का मिलना भी था। किन्तु अब ऐसा नहीं है।

(२) माल के अधिकार पत्रों के चालू न होने के कारण यहाँ पर व्यापारिक विलों और सहायक विलों के बीच में भेद करना असम्भव सा हो जाता है। इसके लिये गोदाम होने चाहिये और गोदामों की रसीदों को हस्तान्तरित करके माल की बिक्री होनी चाहिये जिससे उनके सम्बन्ध के जो विल हों उनके सुवृत्त के लिये यही गोदामों की रसीदें रहे। ऐसा करने से व्यापारिक विलों और सहायता के लिये किये गये विलों में भेद किया जा सकेगा।

(३) नकद साख की प्रणाली के चालू होने से भी विलों की कमी रहती है। हम यह तो जानते ही हैं कि ऋण का यह रूप भी बैंक और ऋण लेने वालों दोनों की दृष्टि में अच्छा है। किन्तु विलों के और अधिक लाभ है, अतः, उन्हें नकद साख की अपेक्षा अधिक उपयोग में लाना चाहिये।

(४) पहिले यह बिल इसलिये भी पसन्द नहीं किये जाते थे कि इन पर स्टाम्प ड्यूटी बहुत लगती थी किन्तु इधर तो यह दोप दूर कर दिया गया है ।

(५) बिल तो विदेशी है । अतः, उनमें विदेशी भाषा का प्रयोग होने के कारण वह यहाँ पर अधिक लोकप्रिय हो ही नहीं सकते । बात यह है कि हमारे यहाँ विदेशी भाषा जानने वाले लोग तो बहुत कम हैं । किन्तु हुण्डी तो यहाँ पर बहुत दिनों से चालू है । हाँ, इसकी इशारत इतनी कठिन है कि उसे याद रखना कुछ मुश्किल अवश्य है । उसे कुछ सादी बता देना चाहिये । फिर, इनके सम्बन्ध में अच्छा अधिकार देने वाले पुर्जों का विधान अवश्य लागू है किन्तु स्थानीय चलन का भी अधिक महत्व है । अतः, उनके भिन्न-भिन्न स्थानों में भिन्न-भिन्न होने के कारण उनका सबका एकीकरण हो जाना आवश्यक है ।

(६) विदेशी व्यापार के कारण जो बिल उत्पन्न होते हैं वह प्रायः स्टर्लिङ्ग में होते हैं । यदि वह यहाँ की करन्सी में हो तो यहाँ पर एक बिल का बाजार बन जाय ।

(७) यहाँ पर इंगलिस्तान की तरह पर बिलों पर स्वीकृति देने वाली कोठियाँ नहीं हैं । बैंक भी अपने ग्राहकों की ओर से बिल नहीं स्वीकार करते । यदि यह व्यवसाय बढ़ाया जाय तो भी यहाँ पर बिल का बाजार अवश्य बन जाय ।

(८) अन्य देशों में कृपि के सम्बन्ध में भी बिलों का प्रयोग होता है । इन्हे सम्भावित बिल (Anticipatory bills) कहते हैं, और यह अमेरिका में बहुत प्रयोग में लाये जाते हैं । अतः, यह यहाँ भी प्रयोग में आ सकते हैं । सहकारी गोदाम समितियाँ भी स्थापित की जा सकती हैं जो कृषकों को उनका सदस्य होने पर उपज के ऊपर ऋण दे सकती हैं । इसके लिये वे समितियाँ उन पर (कृषकों पर) बिल कर सकती हैं । फिर, ये समितियाँ उन्हें जिले की सहकारी संस्था से और वे उन्हें सम्मिलित पूँजी वाले बैंकों से अथवा रिजर्व बैंक से भुना सकती हैं । जिस तरह से सहकारी समितियाँ बिलों का प्रयोग कर सकती हैं उसी तरह से ऋण देने वाले महाजन भी उनका प्रयोग कर सकते हैं ।

करन्सी की इकाई पर अविश्वास

भारतीयों का अपनी करन्सी की इकाई पर विश्वास नहीं है। जहाँ तक हो सकता है वह अपनी वचत को सोने, चाँदी तथा भूमि की सम्पत्ति में रखते हैं। इसके कई कारण हैं। प्रथम तो उनका यह अनुभव है कि यहाँ की करन्सी का मूल्य मनमाना कर दिया जाता है। देश के अन्दर तो यह परिवर्तित हो ही नहीं सकती और इसका मूल्य दिन पर दिन गिरता ही जाता है। फिर, यहाँ के भूमिपति बड़ी मान-मर्यादा की दृष्टि से देखे जाते थे। इनका बड़ा प्रभाव है। हमारी स्त्रियों को भी गहनों का बड़ा शौक है। इसका एक आर्थिक कारण भी है। हमारे यहाँ विधवाओं को केवल उनके स्त्री धन को छोड़कर जिसमें केवल उनका गहना ही रहता है और किसी धन पर अधिकार नहीं है। बैंक बैलन्स और सब साख-पत्र मर्दों के ही होते हैं स्त्रियों को उनका उत्तराधिकार नहीं मिलता।

बैंकों पर अविश्वास

बैंकों पर अविश्वास स्थाई और अस्थायी दोनों हो सकता है। पश्चिमीय देशों में भी अविश्वास है किन्तु वह केवल संकटकाल के ही समय रहता है। भारतवर्ष में वह स्थाई भी है और ऐसे समय में भी हो जाता है। हाँ, इसमें सन्देह नहीं कि संकटकाल के लिये जो रक्षा के उपाय किये जाते हैं उनसे दैनिक रक्षा और दैनिक रक्षा के लिये जो उपाय किये जाते हैं उनसे संकटकाल के समय की रक्षा होती है। किन्तु सुविधा के विचार से इनका अध्ययन अलग-अलग ही किया जाना चाहिये।

स्थायी अविश्वास तो बैंकों के लगातार फेल होने से उत्पन्न हो जाता है। कोई भी ऐसा वर्ष नहीं होता जब कुछ बैंक फेल न होते हों। किन्तु इनका यहाँ पर उतना अधिक महत्व नहीं है जितना उन देशों में है जहाँ की बैंकिंग की प्रणाली बहुत उन्नत अवस्था को पहुँच चुकी है अथवा बैंकिंग अथवा कम्पनी के विधान अधिक सख्त हैं। सन् १९३६ के भारतीय कम्पनी विधान के सशोधन के पहिले बैंक शब्द की कोई ऐसी परिभाषा नहीं थी कि वह केवल अच्छी संस्थाओं के नाम के साथ भी लग सकता। अतः, बहुत सी सन्देह

युक्त संस्थायें बैंक ही कही जाती थीं और उनके फेल होने से बैंक का ही फेल होना समझा जाता था। तब से बैंक की परिभाषा बन गई है और उसकी पूँजी वम से कम पचास हजार रुपया होनी चाहिये। इसके अतिरिक्त उनका इतना ही सुरक्षित कोष भी होना चाहिये। किन्तु पुराने बैंक वैसे ही चल रहे हैं। इधर जो बैंक फेल हुये हैं उनकी जाँच करने पर हमें यह ज्ञात होता है कि उनमें से अधिकांश इसी तरह के बैंक थे। अतः, भविष्य में कम बैंक फेल होंगे इस सम्बन्ध में दो अन्य बातें भी हैं। एक तो प्रायः नये बैंक ही फेल होते हैं। यदि कोई बैंक बहुत दिनों तक चल जाता है तो यही उसके अच्छे प्रबन्ध का प्रमाण हो जाता है। दूसरे, यह कि प्रायः थोड़े ही पूँजी के बैंक फेल होते हैं और जब ऐसी आशा की जाती है कि सभी बैंकों की पूँजी और उनका सुरक्षित कोष एक लाख से कम न होगा तो उनका फेल होना भी कम हो जायगा।

अब हम यह देखेंगे कि प्रायः बैंक क्यों फेल हुये जिससे कि इसको रोके जाने के लिये उपाय मिल जायें।

एक तो बैंक प्रायः कानून के ढीले होने के कारण, जनता की अज्ञानता के कारण और बुरे तथा बेईमान प्रबन्धकों के कारण फेल हुये हैं। इसके जो बैंक शिकार हुये हैं उनमें पूना बैंक, पूना; अमृतसर नेशनल बैंक, अमृतसर; हिन्दुस्तान बैंक, मुलतान; शिवराम अय्यर बैंक, मद्रास; पायनियर बैंक, बम्बई और क्रेडिट बैंक आफ इंडिया जो क्रमशः १९२४, १९२३, १९१४, १९३२, १९१६ और १९१३ में फेल हुये थे विशेष तौर पर उल्लेखनीय है। क्रेडिट बैंक आफ इंडिया के व्यवस्थापक ने अपनी नियुक्ति के समय संचालकों से अपनी बैंकिंग और अकाउण्टैन्सी की अनभिज्ञता दिखलाते हुये एक मजबूत कमेटी बनाने की माँग रखी थी। बैंक के फेल होने तक भी जैसा कि उसने स्वयं कहा था उसने कुछ भी नहीं सीखा था।

इस कमी को कानूनन दूर किया जा सकता है जिसकी आवश्यकता यहाँ पर सन् १९१३-१४ के सकटकाल के समय से ही प्रतीत होने लगी थी। किन्तु यह केवल १९३६ में ही अंशतः पूरी हो सकी। इसमें इस बात का ध्यान रक्खा गया है कि जनता बैंकों के अज्ञान तथा बेईमान संस्थापकों से बच सके। यदि संचालक अथवा व्यवस्थापक और आडीटर गलत बान कहते हैं तो कई परिस्थितियों में वह जुर्म करते

है। फिर, उनके ऊपर द्रव्य के गलत उपयोग का, गलत तरीके पर रोक-रखने का और अमानत में खयानत करने का जिसमें किसी काम को करके अथवा न करके कर्तव्य विमूढ़ होने का अपराध भी सम्मिलित है अपराध लग सकता है। गलत हिसाब रखने पर भी सजा देने का नियम रखा गया है।

दूसरे, बहुत से बैंक इसलिये भी फेल हुये हैं कि उन्होंने बैंकिंग के कोष से उद्योग-धन्धों को भी आर्थिक सहायता दी थी। इनमें से लाहौर के पिउपिल बैंक और अमृतसर बैंक और टाटा इन्डस्ट्रियल बैंक के नाम जो क्रमशः सन् १९१३, १९१४ और १९२३ में फेल हुये थे विशेष उल्लेखनीय हैं। वस्तुतः, भारतवर्ष में लोग जर्मनी और जापान के तरीके पर सम्मिलित बैंकों के पक्ष में हैं, किन्तु यहाँ पर यह इसलिये सम्भव नहीं है कि यहाँ की बैंकिंग की प्रणाली अंग्रेजी बैंकिंग प्रणाली के सदृश्य विकसित हुई है और उसकी यह विशेषता है कि व्यापारिक बैंकिंग और औद्योगिक बैंकिंग अलग-अलग ही रहे।

तीसरे, बहुत से बैंक इस कारण भी फेल हुये हैं कि उनके अफसरों ने, सट्टेबाजी में भाग लिया था। ऊपर के कुछ बैंक इसलिये भी फेल हुये थे किन्तु इण्डियन स्पेशी बैंक के सन् १९१४ में फेल होने का यही एक कारण था। बैंक के प्रारम्भ से ही इस बात की खबर थी कि बैंक सट्टेबाजी में फँसा हुआ था किन्तु यह कहा जाता था कि यह गलत है और छिपाया जाता था। श्री चुन्नीलाल सरैया जो बैंक के व्यवस्था सचालक थे और जिनका नाम इससे सम्बन्धित था, बहुत ही चतुर व्यक्ति थे। वह ऊपरी सजावट में होशियार थे और वर्ष के अन्त में अच्छी बैलन्स शीट दिखला देते थे। किन्तु अन्त में एक साधारण हिस्सेदार ने जिससे इनको वैयक्तिक शत्रुता कही जाती थी इसके भंग करने की प्रार्थना हाईकोर्ट में दी। पहिले तो हिस्सेदारों और सचालकों ने इसका विरोध किया और सब ठीक मालूम पड़ने लगा किन्तु फिर श्री चुन्नीलाल का यकायक हृदय की गति रुक जाने से देहान्त हो गया और शेष सचालकों ने स्वेच्छा से बैंक की इतिक्रिया करने के लिये प्रार्थना-पत्र भेज दिया। बाद की जाँच से आरोप ठीक ही निकला।

चौथे और अन्तिम, प्रायः बैंक इस कारण भी फेल हुये हैं कि

जनता का मत किसी न किसी समय उनके विरुद्ध हो गया। उन्हें तो अभाग्य का शिकार ही समझना चाहिये। इनमें से एक तो मेरठ का बैंक आफ अपर इण्डिया था जिसकी रजिस्ट्री सन् १८६३ में हुई थी। यह सन् १९१४ तक बराबर उन्नति दिखलाता रहा किन्तु उस वर्ष यकायक फेल हो गया। इसके जमा करने वालों और हिस्सेदारों दोनों को पूरा रुपया मिला। दूसरा, शिमला का अलायंस बैंक था। सन् १८७४ में संस्थापित होकर यह सन् १९२३ तक काम करता रहा। किन्तु उस वर्ष फेल हो गया। इसको तो इस कारणवश बुरे दिन देखने पड़े कि बोल्टन ब्रदर्स ने जो इसके लन्दन के अद्वितिया थे इसके १५० लाख रुपये जो उनके ऊपर चाहिये थे नहीं दिये। इसके एक दूसरे ऋणी अर्थात् पंजाब के ट्रस्ट आफ इण्डिया की स्थिति भी अच्छी नहीं थी। बैंक के संचालकों ने अपनी सन् १९२२ की रिपोर्ट में यह बात साफ कह दी थी। अस्तु, बोल्टन ब्रदर्स वाली खबर फैलते ही जमा निकलनी प्रारम्भ हो गई और बैंक फेल हो गया, इस सम्बन्ध में त्रावनकोर नेशनल क्लिन बैंक का भी फेल होना उल्लेखनीय है। इसने सन् १९३८ में भुगतान देना बन्द कर दिया। भुगतान के समय इसकी स्थिति वैसी ही थी जैसी उस समय थी जब दो वर्ष पहिले त्रावनकोर नेशनल बैंक और क्लिन बैंक दोनों एक-दुसरे के साथ जुड़े हुए थे। इन दोनों बैंकों का पहिले का इतिहास बहुत ही उज्ज्वल था। फिर, रिजर्व बैंक की स्थापना के बाद इसका इस प्रकार फेल होना कुछ ठीक नहीं था और विशेषतः इसलिये कि यह उसका एक सदस्य बैंक था। रिजर्व बैंक ने इसकी सहायता क्यों नहीं की यह तो पहिले ही बताया जा चुका है। इधर ज्वाला बैंक भी फेल हो गया है। इसे सरकार ने जमा प्राप्त करने की मनाही कर दी थी। अतः, जनता का इस पर से विश्वास उठ गया और वह जमा निकालने लगी और बैंक फेल हो गया।

अब, हम फिर बैंकों के प्रति स्थायी अविश्वास के कारणों की ओर आते हैं। उनके लगातार फेल होने के साथ-साथ इसके अन्य कारण भी हैं। एक तो एक अच्छे बैंकिंग विधान के न होने से भी बड़ी हानि होती है। अच्छे बैंकिंग विधान से जनता का कई प्रकार से विश्वास बढ़ जाता है। प्रथम तो इनके कारण अच्छी व्यवस्था रहती है और शक्ति के साथ-साथ उसके दुरुपयोग की कम सम्भावना

होती है। इस सम्बन्ध में इधर सन् १९३६ का कम्पनी विधान पास करके जो कुछ भी किया गया था उसका उल्लेख पहिले ही किया जा चुका है। दूसरे, इससे हिसाब की ठीक विज्ञप्ति भी हो जाती है। भारतीय कम्पनी विधान में बैलन्स शीट का एक रूप दिया हुआ है जिसके अनुसार सब कम्पनियों को अपनी बैलन्स शीट बनानी पड़ती है। हाँ, वैकों को कुछ विशेष बातें दिखानी पड़ती है। किन्तु यह असन्तोषजनक ही है। उनके लिये तो बैलन्स शीट का एक प्रथक रूप ही होना चाहिये। ऊपर जिस विधान का उल्लेख किया गया है उसने भी ऐसा न किया। हाँ, पुरानी बैलन्स शीट में कुछ सुधार अवश्य कर दिये। जब बैलन्स शीट में कुछ सूचनार्थ नहीं रहती तो उसके कई प्रभाव पड़ते हैं। प्रथम तो जो बैंक अच्छे हैं उनकी अच्छी स्थिति का पता नहीं लगता। दूसरे, घुरे बैंकों के सम्बन्ध में अनभिज्ञ जनता को कुछ नहीं मालूम हो पाता। तीसरे, उपयुक्त अंक नहीं प्राप्त हो पाते। चौथे और अन्तिम यह कि अन्तिम लेखों के सम्बन्ध में कोई सद्दृश्यता न होने से तुलना करने में कठिनाई पड़ती है। उपर्युक्त के अलावा बैंकिंग के कानून का यह ध्येय होता है कि उन्हें जब कठिनाइयाँ पड़ें तब उन्हें वह दूर कर दें। वे जमा करने वालों की रक्षा करते हैं और यह कई प्रकार से हो सकती है। ऐसा इसलिये ही नहीं किया जाता कि इन लोगों की रक्षा का अधिकार अन्य व्यापारियों के लेनदारों की रक्षा के अधिकार से अधिक है बल्कि इसलिये कि किसी बैंक के फेल होने से अन्य व्यापारियों पर भी बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है।

संकट के समय जो अविश्वास पैदा हो जाता है, उसे दूर करने के लिये बहुत से सुझाव रखे जा चुके हैं। प्रथम तो सरकार को उस समय बैंकों की सहायता करनी चाहिये। किन्तु भारत की सरकार इस सम्बन्ध में बराबर हिचकिचाती रहती थी। इसका मुख्य कारण यही था कि वह विदेशी थी। सन् १९१३-१४ के बैंकिंग के संकटकाल में यद्यपि जनता बहुत कुछ कहती रही, किन्तु इसने कुछ भी न किया। हाँ, उस समय वाइसराय ने यह अवश्य कहा था कि यदि कुछ करने की आवश्यकता पड़ी तो वह कुछ ही बैंकों के सम्बन्ध में की जायगी और उसी समय के लिये होगी। सन् १९२३ में जब अलायन्स बैंक ने भुगतान करना बन्द कर दिया तब उसने इम्पीरियल बैंक को इस

बात का आदेश दिया कि वह उसका काम अपने हाथ में ले ले और उसके चालू खातों और वचत के खातों पर ५० प्रतिशत फौरन दे दे और इस तरह से उसके एक प्रधान कर्मचारी ने जो दस वर्ष पूर्व कहा था उसे पूरा किया। जिन कारणों से यह किया गया था वह भी बड़े मार्फे के थे। पहिले तो अर्थ सचिव ने यह कहा था कि यह इसलिये किया गया था कि अंग्रेजी और भारतीय द्रव्य के बाजारों में उस समय जो अच्छी स्थिति थी वह वैसी ही बनी रहे जिससे सरकार को ऋण लेने में सुविधा रहे और साथ ही उसके अच्छे बजट के कारण जो अच्छा प्रभाव पड़ा था वह भी बना रहे। किन्तु बैंक के चालू और स्थायी खातों की जमा केवल ७ करोड़ रु० थी। अतः, इतने के हित को बचाकर उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति करने की बात बड़ी विचित्र थी। अतः, इस बात को समझ कर फिर उन्होंने यह कहा कि यह इसलिये किया गया था कि यह भारतीय अर्थ और बैंकिंग के हित के लिये बहुत ही आवश्यक था और इससे अन्य अच्छे बैंकों को जो असुविधा होती वह रुक गई। अतः इस तरह से अनजाने में उन्होंने सरकार की जिम्मेदारी बढ़ा दी। किन्तु यहाँ के लोगों ने दूसरी ही बात सोची। उनका यह ध्यान था कि यह अलायन्स बैंक के अधिकांश ग्राहकों के अंग्रेज होने के कारण उनके हित की रक्षा के लिये किया जा रहा था। इस बात की परीक्षा का समय सन् १९३८ में त्रावनकोर बैंक के फेल होने के समय आया किन्तु उस सम्बन्ध में उसने कुछ नहीं किया। हाँ, यह कहा जा सकता है कि उस समय तक स्थिति बहुत कुछ बदल गई थी। प्रान्तीय सरकारों के अधिकार बढ़ाये जा चुके थे। अतः, इस संवध की जिम्मेदारी उनकी हो गई थी। इस संवन्ध में मद्रास सरकार ने जो कुछ किया वह प्रशंसनीय था। त्रावनकोर बैंक की अधिकांश शाखायें उसी प्रान्त में थीं। अतः, जो कुछ किया गया वह स्वाभाविक ही था। जब बैंक के ऊपर सकट आया तभी मद्रास सरकार ने रिजर्व बैंक से सम्मति ली और इससे जाँच कराने के लिये कहा गया। किन्तु वह समय जाँच का नहीं था। फिर, प्रधान मन्त्री ने जनता से शान्त रहने की अपील की और कहा कि वह अफवाहों में विश्वास न करे। उन्होंने यह भी घोषित किया कि अन्य बैंकों की भी जाँच की जायगी और कोई गड़बड़ी नहीं होगी। इसके दो महीने बाद उन्होंने यह विज्ञप्ति निकाली

कि वहाँ के सदस्य बैंकों की स्थिति बहुत अच्छी है और जिन लोगों ने रिजर्व बैंक से सहायता ली थी उन्होंने भी उसको वापिस कर दिया है और यदि आवश्यकता पड़ेगी तो रिजर्व बैंक फिर उनकी सहायता करेगा। यह सचमुच बड़े मार्फे की बात थी। किन्तु जब कोई ऐसा बैंक है कि जिसकी शाखायें सारे भारतवर्ष में फैली हुई हैं तब तो केन्द्रीय सरकार को उठना पड़ेगा। सन् १९४६ में बंगाल में जब बैंकों के ऊपर संकट पड़ा तब इस सम्बन्ध में रिजर्व बैंक और भारत सरकार ने जो कुछ किया उसका संकेत तो पहिले ही किया जा चुका है।

इसके अतिरिक्त जैसा कि हम कह चुके हैं केन्द्रीय बैंक भी बहुत कुछ स्थिति का सुधार कर सकता है। अब वह कहाँ तक ऐसा कर सकता है इसके विषय में भी पहिले ही बताया जा चुका है। पहिले हमारे देश में कोई केन्द्रीय बैंक नहीं था। किन्तु यह कमी रिजर्व बैंक की संस्थापना से दूर हो गई है। हाँ, जैसा कि पिछले अध्याय में बताया जा चुका है इस बैंक ने सन् १९३८ में त्रावनकोर नेशनल एण्ड क्लिलन बैंक की कुछ भी सहायता नहीं की। जो हो, हम आशा करते हैं कि भविष्य में यह अधिक सतर्कता से काम लेगा।

तीसरे, पत्रों और जनता की सम्मति का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। सन् १९३१ के संयुक्त राज्य के आर्थिक संकट के समय उन्होंने वहाँ के जमा करने वालों में एक देश प्रेम की लहर पैदा करके उनमें जो शान विश्वास पैदा कर दिया था वह बहुत ही प्रशंसनीय था। किन्तु इसके विपरीत संयुक्तराष्ट्र अमेरिका में इंग्लैण्ड के संकट के बाद जब संकट पड़ा तब वहाँ के पत्रों और जनता ने इसके विपरीत किया। भारतवर्ष में भी यही बात होती है। क्रिस्तानी और अंग्रेजी पत्र यहाँ के सम्मिलित पूँजी वाले बैंकों के विषय में बराबर झूठी अफवाहें उड़ाते रहे हैं। एक समय था जब यह पंजाब के मुख्य बैंक संस्थापक लाला हरकिशनलाल के विरुद्ध ऐसा किया करते थे। फिर, जनता यहाँ आसानी से धड़वाई जा सकती है। सेन्ट्रल बैंक के शत्रुओं के द्वारा उड़ाई अफवाहों के कारण उस पर बराबर आक्रमण होते रहे किन्तु वह उनको बराबर सम्भालता रहा।

अन्तिम बात यह है कि बैंक स्वयं इस सम्बन्ध में बहुत कुछ कर सकते हैं। उन्हें गम्भीर परिस्थिति के कारणों से बराबर अपनी रक्षा का उपाय करते रहना चाहिये और उसके प्रभाव को कम कर

देना चाहिये। यह वह अपने सम्बन्ध में अधिक प्रकाशन करके कर सकते हैं। वे जमा करने वालों के प्रतिनिधियों को अपने संचालक मंडल में लेकर उनमें विश्वास की मात्रा पैदा कर सकते हैं। चुनाव करने का अधिकार उन्हीं लोगों को दिया जा सकता है जिनका एक औसतन न्यूनतम बैलन्स रहता है और ऐसे लोगों की सूची दो या तीन वर्षों में दुहराई जा सकती है।

अन्य प्रकार की बैंकिंग की कमी

यहाँ के सम्मिलित पूँजी वाले बैंक केवल व्यापारिक बैंकिंग करने के लिये ही संस्थापित किये गये हैं। हाँ, औद्योगिक बैंकिंग का काम करने के लिये भी कुछ बैंक संस्थापित किये गये हैं किन्तु उन्हें कोई विशेष सफलता नहीं मिल पाई है। कृपि के अर्थ की कठिनाइयों को दूर करने के लिये सहकारिता निकाली गई है किन्तु इस सिद्धान्त को उद्योग-धन्धों के लिये अर्थ देने के लिये नहीं अपनाया गया है। भारतीय बैंकों ने विनिमय के व्यवसाय को बिल्कुल छोड़ रक्खा है। अतः, उनके इसको अपनाने की बहुत आवश्यकता है। सक्षेप में यह कहा जा सकता है कि व्यापारिक बैंकिंग और कृपि बैंकिंग के व्यवसाय के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के बैंकिंग के व्यवसाय पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया गया है।

अंग्रेजी प्रणाली की पूरी नकल

हमारी बैंकिंग अंग्रेजी प्रणाली की पूरी नकल है जिसके फल-स्वरूप सादगी के भारतीय आदर्श को पूरी तरह से ठुकरा दिया गया है। इसके फल-स्वरूप जो कठिनाइयाँ उत्पन्न हो गई हैं उनका तो अध्ययन हम कर ही चुके हैं। यही कारण है कि इस देश में बैंकिंग गाँवों में नहीं फैल सकी है।

विदेशी भाषा का प्रयोग

यहाँ पर बैंक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं। हम जानते हैं यहाँ के लोग पढ़े-लिखे ही नहीं हैं, अंग्रेजी जानने की बात तो दूर रही। अतः, वे उनसे काम नहीं कर पाते। अंग्रेजी भाषा के प्रयोग के कारण अंग्रेजी जानने वाले लोगों की नियुक्ति की आवश्यकता पड़ती है और उनकी संख्या बहुत कम होने के कारण उनके चुनाव में बड़ी कठिनाई पड़ती है।

विदेशियों का प्रभाव

भारतीय बैंकिंग पर विदेशियों का प्रभाव है और उनकी वास्तविक सहायुभूति भारतीयों से नहीं है। उनका उद्देश्य तो यहाँ लाभ कमाना है और यहाँ के लोगों को चूसना है। यह लोग न तो यहाँ विश्वास ही उत्पन्न कर सके हैं और न यहाँ की समस्याओं को ही सुलझा सके हैं। फिर, यह यहाँ के लोगों के साथ कोई निकटतम सम्बन्ध भी नहीं स्थापित कर सके हैं। ऐसा करना हर दृष्टि से आवश्यक है।

लोगों की कम आय

यहाँ की बैंकिंग की स्थिति इसलिये भी अच्छी नहीं है कि यहाँ के लोगों की आय बहुत कम है। उसकी धीमी उन्नति का कारण जितनी यहाँ की गरीबी है उतनी अन्य कोई बात नहीं है। जो लोग आयकर देते हैं उनकी संख्या और आय की औसत, जमा करने वालों की संख्या, और औसत जमा की जाँच करने पर यहाँ के उस क्षेत्र की संकीर्णता का अनुमान किया जा सकता है जिससे बैंकों को काम करना है। बहुत से सुशिक्षित लोग और उच्चतम समाज में रहने वालों के भी बैंको में हिसाब केवल इसीलिये नहीं है कि वह उनमें न्यूनतम बैलन्स नहीं रख सकते। फिर, ऐसा भी है कि यह बैंक न्यूनतम बैलन्स रखने का ऐसा नियम क्यों रखते हैं जिससे बहुत से लोग उनसे लाभ नहीं उठा पाते हैं। किन्तु ऐसा इसलिये किया जाता है कि इससे उन सिद्धान्तों का पालन होना है जिनका पालन होना बैंकिंग की सफलता के विचार से बहुत ही आवश्यक है। बैंक इसीलिये न्यून बैलन्स निश्चित करते हैं कि उनके सदस्यों का एक न्यूनतम स्तर हो और उससे उनको इतना लाभ भी हो सके कि वह उन्हें रखने का अपना खर्च पूरा कर लें।

बैंकिंग में शिक्षा की कमी

बैंकिंग के सिद्धान्तों और प्रयोगों की शिक्षा पाये हुये भारतीयों की भी बहुत कमी है। १९ वीं शताब्दी के अन्त तक व्यवसाय तथा बैंकिंग की शिक्षा का तो यहाँ पर पूर्णरूप से अभाव ही था। इधर कुछ वर्षों से अवश्य इसकी व्यवस्था हो गई है किन्तु अभी तक जितनी सुविधाये दी जा चुकी है लोग उनसे भी पूरा लाभ नहीं उठा

रहे हैं। इसमें सफलता मिलने के लिये बैंकों और विश्वविद्यालयों में एक प्रकार के सहयोग की बड़ी आवश्यकता है।

बैंकिंग के विधान की आवश्यकता

भारतवर्ष में बैंकिंग के एक पृथक् विधान की भी बहुत आवश्यकता है। यहाँ का कम्पनी विधान ही यहाँ के बैंकों के ऊपर लागू है। इसमें सदेह नहीं कि अब इसमें बैंकिंग के सम्बन्ध की बहुत सी धारयाँ सम्मिलित कर दी गई हैं, किन्तु यह यथेष्ट नहीं है। रिजर्व बैंक ने एक पृथक् बैंकिंग विधान बनाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव रखे हैं और इस सम्बन्ध का एक बिल भी यहाँ की वैधानिक सभा के सामने है। आशा है कि इस सम्बन्ध का एक पृथक् विधान बन जायगा।

बैंकों के संगठन की आवश्यकता

बैंकों का संगठन बहुत ही आवश्यक है। इसके उद्देश्य बैंकिंग के भिन्न-भिन्न वर्गों में अच्छे सम्बन्ध स्थापित करना, उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिये उनके एकत्रित होने का प्रबन्ध करना, पारस्परिक प्रतिद्वन्द्वता कम करना, लेक्चरों और पढ़ाई का प्रबन्ध करके बैंक के कर्मचारियों को शिक्षा देना, पुस्तकालयों और वाचनालयों को रखना और पत्रिकाएँ, इत्यादि निकाल कर बैंकिंग सम्बन्धी साहित्य निकालना है। पश्चिमीय देशों में इन्होंने अपने काम करने के ढंग में बड़ी उन्नति की है और लोगों में सदाचार पैदा कर दिया है। ये आकस्मिक भय दूर करने में बहुत ही सफल होते हैं। अतः इसलिये भी इनकी इस देश में बहुत ही आवश्यकता है।

प्रश्न

(१) भारतवर्ष की बैंकिंग की प्रणाली में कौन-कौन से दोष हैं ? इन्हें दूर करने के लिये उपाय बतलाइये।

(२) भारतवर्ष में बिल क्यों नहीं चालू है ? उन्हें अधिक चालू बनाने के लिये कौन से उपाय हैं ?

(३) इस देश में बैंकों के फेल होने के कौन-कौन से कारण हैं ? क्या इधर कुछ हालत सुधर गई है ?

(४) देश की बैंकिंग की प्रणाली में जनता का विश्वास उत्पन्न करने के लिये कौन-कौन से उपाय ह ? क्या इधर इस सम्बन्ध में कुछ किया गया है ?

परिशिष्ट 'अ'

बैंक की परिभाषा

Section 277 F of Indian Companies Act (1936)

A 'banking company' means a company which carries on as its principal business the accepting of deposits of money on current account or otherwise, subject to withdrawal by cheque, draft or order, notwithstanding that it engages in addition in any one or more of the following forms of business, namely

(1) the borrowing, raising or taking up of money, the lending or advancing of money either upon or without security, the drawing making, accepting, discounting, buying, selling, collecting and dealing in bills of exchange, hundis, promissory notes, coupons, drafts, bills of lading, railway receipts, warrant-, debentures, certificates, scrips and other instruments, and securities whether transferable or negotiable or not, the granting and issuing of letters of credit, travellers cheques and circular notes, the buying, selling and dealing in bullion and specie, the buying and selling of foreign exchange including foreign bank notes, the acquiring, holding, issuing on commission, underwriting, dealing in stock, funds, shares, debentures, debenture stock bonds, obligations, securities and investment of all kinds, the purchasing and selling of bonds, scrips or other forms of securities on behalf of constituents or others; the negotiating of loans and advances, the receiving of all kinds of bonds, scrips or valuables on deposits or for safe custody or otherwise, the collecting and transmitting of money and securities,

(2) acting as agents for governments or local authorities or for any other person or persons, the carrying on of agency business of any description other than the business of a managing agent, including the power to act as attorneys and to give discharges and receipts,

(3) contracting for public and private loans and negotiating and issuing the same ,

(4) the promoting, effecting, insuring, guaranteeing, underwriting, participating in managing and carrying out of any issue, public or private, of State, Municipal or other loans of shares, stock, debentures, or debenture stocks of any company, corporation or association and the lending of money for the purpose of any such issue ,

(5) carrying on and transacting every kind of guarantee and indemnity business ,

(6) promoting or financing or assisting in promoting or financing any business undertaking or industry, either existing or new, and developing or forming the same either through the instrumentality of syndicates or otherwise ,

(7) acquisition by purchase, lease, exchange, hire or otherwise of any property immovable or movable and any rights or privileges which the company may think necessary or convenient to acquire or the acquisition of which in the opinion of the company is likely to facilitate the realisation of any securities held by the company or to prevent or diminish any apprehended loss or liability ,

(8) managing, selling and realizing all property movable and immovable which may come into the possession of the company in satisfaction or part satisfaction of any of its claims ;

(9) acquiring and holding and generally dealing with any property movable or immovable which may form part of the security for any loans or advance or which may be connected with any such security ,

(10) undertaking and executing trusts ,

(11) undertaking the administration of estates as executor, trustee or otherwise

(12) taking or otherwise acquiring and holding shares in any other company having objects similar to those of the company ,

(13) establishing and supporting or aiding in the establishment and support of associations, institutions, funds, trusts and conveniences calculated to benefit employees of the company or the dependents or connexions of such persons, granting pensions and allowances and making payments towards insurance: subscribing to or guaranteeing moneys for charitable or benevolent objects or for any exhibition or for any public, general or useful object;

(14) the acquisition, construction, maintenance and alteration of any building or works necessary or convenient for the purposes of the company,

(15) selling, improving, managing, developing, exchanging, leasing, mortgaging, disposing of or turning into account or otherwise dealing with all or any part of the property and rights of the company;

(16) acquiring and undertaking the whole or any part of the business of any person or company, when such business is of a nature enumerated or described in this section,

(17) doing all such other things as are incidental or conducive to the promotion or advancement of the business of the company

परिशिष्ट 'ब'

इण्डीजेनस बैंकरो को रिज़र्व बैंक से सम्बन्धित
करने के लिये योजना

The Reserve Bank of India addressed in May, 1937 to the Scheduled Banks and Shroff's Association a letter containing the following conditions which must be fulfilled by the indigenous bankers wishing to be linked directly with it—

(1) They must confine their business to banking proper as defined by the Indian Companies Act. Any other business that they might be conducting should be wound up within a reasonable time.

(ii) They must maintain proper books of account, and have them audited by registered accountants. The Reserve Bank will have the right to inspect the accounts and call for any information necessary to determine the financial status of the banker

(iii) They must file with the Reserve Bank the periodical statements prescribed for scheduled banks. They must also, in the interest of their depositors, publish the returns prescribed for banking companies by the Companies Act and be liable to the same penalties for non-compliance.

(iv) The Reserve Bank will have the right of regulating the business of the bankers on banking lines, when necessary

(v) During a period of five years from the date of their registration as private bankers in the books of the Reserve Bank, they will be entitled to open an account at any of the offices of the Reserve Bank, and be otherwise subject to the same conditions as the scheduled banks except that during such period they will not be required to furnish the compulsory deposit set out in Section 42 of the Reserve Bank Act, unless any of their weekly statements discloses that their demand and time liabilities are five times more in excess of their capital in the business.

(vi) If an indigenous banker does not incorporate himself under the Companies Act, his liabilities in respect of his banking commitments will be unlimited. He should, therefore, state the amount of capital he has available for banking business (Bankers with a capital of less than two lakhs need not apply).

(vii) When required they will have to indicate—

(a) The names and the extent of interest of their business partners if any, and

(b) If any of the bankers is a member of a Hindu joint family, the names and interests of the co-sharers. In both the cases, statements will be required from the co-sharers who are prepared to take their full share in the business and its liabilities

(१११) This scheme will be a tentative one for a term of five years, but before the end of this period the Reserve Bank will frame proposals for legislation, if it thinks fit, further to co-ordinate or regulate the position of the private bankers. It is likely that such legislation would take the form of a separate Bank Act as suggested by the Banking Enquiry Committee or otherwise to standardise and co-ordinate the status of these registered private bankers on lines in consonance with the scheduled banks.

(१२) (a) If they satisfy the above conditions, they will have the privilege of rediscount with the Reserve Bank against eligible paper, the right to secure advances against government paper, and remittance facilities similar to those for scheduled banks

(b) If the Reserve Bank decides to take action on the lines here indicated, legislation will be necessary and the indigenous bankers will then be called upon to make an application in the manner which may then be prescribed
